

उत्तर प्रदेश
के
सामान्य प्रशासन
की
रिपोर्ट
१९५१ ई०

मुद्रक
अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामर्थ
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
१९५२

विषय-सूची

भाग १—सामान्य संक्षिप्त विवरण

	पृष्ठ
१—सामान्य राजनीतिक पृष्ठ-भूमि	१
२—राजनीतिक सिंहावलोकन	२
३—समाचार-पत्र और जनमत	८
४—विधान मंडल	१५
५—निर्वाचन	१६
६—खाद्य तथा रसद	१९
७—श्रम स्थिति	२१
८—सहायता तथा पुनर्वास	२१
९—भूमि संबंधी समस्याएँ	२५
१०—कृषि संबंधी स्थिति	२५
११—कृषि-विकास	२६
१२—ग्राम-सुधार	२६
१३—पशु-पालन	२७
१४—मत्स्य-पालन	२८
१५—वन	३०
१६—सिंचाई	३०
१७—व्यापार और उद्योग	३१
१८—सहकारी आंदोलन	३२
१९—नियोजन	३२
२०—विद्युत	३५
२१—सार्वजनिक निर्माण कार्य	३७
२२—परिवहन	३७
२३—शिक्षा	३८
२४—स्थानीय स्वशासन	४१
२५—जन-स्वास्थ्य	४४
२६—राज्य-राजस्व	४६
आबकारी	४६
न्यायालय तथा जेल	४७

[भाग २--विस्तृत अध्याय

पृष्ठ

अध्याय १--सामान्य प्रशासन और स्थिति

१—१९५१ ई० में सरकार के संवत्स्रगण	..	५१
२—प्रशासकीय कार्यवाहियाँ	..	५२
३—वर्ष कैसा रहा ?	..	६६

अध्याय २—भूमि-प्रशासन

४—ज़मींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था	..	६८
५—मालगुजारी, कृषि संबंधी अप्रभुग तथा नहरों के मजदूरों की वसूली	..	६८
६—कृषि आय-कर	..	६९
७—पमाइश, बन्दोंवस्त और कागजात देही सम्बन्धी कार्यवाहियाँ	.	७०
८—कागजातदेही	..	७०
९—आराजी के क्षेत्र	..	७१
१०—सरकारी आस्थान	..	७२
११—कोर्ट आफ़ वाड्स के अधीन आस्थान	..	७३
१२—माल की अदालतें	..	७४

अध्याय ३—शान्ति-व्यवस्था तथा सभायत्त शासन

१३—विधि-निर्माण-कम	...	७५
१४—गृह :—		
(क) पुलिस	..	७८
(ख) फौजदारी	..	८०
(ग) जेल	..	८१
१५—हरिजन उत्थान तथा पुनरुद्धार	..	८३
१६—बंड न्याय-व्यवस्था	..	८५
१७—बीवानी न्याय-व्यवस्था	..	८६
१८—रजिस्ट्रेशन (पंजीयन)	..	८१
१९—पंचायत राज	..	८१
२०—म्युनिसिपल बोर्ड	..	८३
२१—जिला बोर्ड	..	८५
२२—मोटीफाइड एरिया	..	९७
२३—टाउन एरिया	..	९८
		१००

अध्याय ४—उत्पादन तथा विवरण

		पृष्ठ
२७—कृषि	..	१०३
२८—कृषि इंजीनियरिंग	..	१०८
२९—सिंचाई	..	१११
३०—बिजली	..	११३
३१—वन	..	११६
३२—उद्योग—धंधे	..	११८
३३—खान और पत्थर की खानें	..	१२६
३४—श्रम	..	१२६
३५—सहकारी आंदोलन	..	१२६
३६—गन्ना विकास	..	१३४
३७—ग्राम—सुधार	..	१३५
३८—नियोजन	..	१३८
३९—उपनिवेशन	..	१४६
४०—सार्वजनिक निर्माण कार्य	..	१५४
४१—परिवहन	..	१५५
४२—खाद्य तथा रसद	..	१५८
४३—सहायता तथा पुनर्वास	..	१७१

अध्याय ५—सरकारी राजस्व तथा वित्त

४४—केन्द्रीय राजस्व	..	१७६
४५—राज्य का राजस्व	..	१७६
४६—मुद्रांक	..	१८५
४७—आबकारी	..	१८६
४८—बिक्री—कर	..	१८८

अध्याय ६—जन-स्वास्थ्य, पशुपालन तथा मत्स्य-पालन

४९—सार्वजनिक स्वास्थ्य	..	१८६
५०—राजकीय हेतु बोर्ड	..	१९४
५१—चिकित्सा :—		
(क) एलोपैथी	..	१९५
(ख) देशी	..	१९८
५२—पशु-पालन	..	२००
५३—मत्स्य-पालन	..	२०८

अध्याय ७—शिक्षा तथा कला

५४—शिक्षा	..	२०८
५५—रङ्गकी विश्वविद्यालय	..	२१५
५६—साहित्यिक प्रकाशन	..	२१६
५७—मंत्रालय और प्रसूतकाल	..	२१७
		२१८

अध्याय ८—विविध

५९—स्थानीय स्वशासन इंजीनियरिंग	२२२
६०—स्थानीय कोष लेखे	२२३
६१—निरीक्षण कार्यालय	२२४
६२—उत्तर प्रदेश तथा बिहार का शुगर कमीशन	२२५
६३—मुद्रण और लेखन-सामग्री	२२७
६४—अर्थ तथा संख्या	२२७
६५—ऐडमिनिस्ट्रेटर जनरल तथा आफिशियल ट्रस्टी का कार्यालय	२२९

टिप्पणी—रिपोर्ट के भाग १ में शीर्षक 'सामान्य संक्षिप्त विवरण' के अंतर्गत १९५१ ई० के कलेन्डर वर्ष की प्रमुख घटनाओं और साथ ही प्रशासकीय कार्यवाहियों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। भाग २ में सरकार के प्रत्येक विभाग के कार्यों का विस्तृत विवरण है और यह भाग उन विभागीय रिपोर्टों पर आधारित है, जो आलोच्य विषयों के अनुसार १९५०-५१ ई० के वित्तीय वर्ष, १९५०-५१ ई० के मालगुजारी वर्ष, १९५०-५१ ई० के कृषि वर्ष अथवा १९५० ई० के कलेन्डर वर्ष से संबंध रखती हैं। आवश्यकतानुसार १९५१-५२ ई० के बजट अंक भी कही-कही दिये गये हैं।

उत्तर प्रदेश के प्रशासन की रिपोर्ट, १९५१ ई०

भाग १

सामान्य संक्षिप्त विवरण

१—सामान्य राजनीतिक पृष्ठभूमि

विगत वर्ष विश्व के लिये जितना अधिक चिन्ताजनक था, विचाराधीन वर्ष उतना नहीं रहा। फिर भी यह वर्ष उतने ही महत्व का था जितना कि हाल में समाप्त होने वाले संकटपूर्ण तथा व्यापक घटनाओं से भरे हुए दशक का कोई भी वर्ष। संसार की बड़ी शक्तियों के बीच पारस्परिक तनातनी रही, और वास्तव में इस शताब्दि के उत्तरार्द्ध के प्रारम्भ में स्थिति आशाजनक रहने की अपेक्षा निराशाजनक ही अधिक रही। कोरिया के युद्ध की आग भीतर ही भीतर सुलग रही थी और यह कहना कठिन था कि युद्ध की अपेक्षाकृत विश्रान्ति और दीर्घ-कालीन विराम-सन्धि वार्ता के पश्चात् शान्ति की स्थापना होगी अथवा एक बड़े पैमाने पर फिर से लड़ाई की कार्यवाहियाँ शुरू हो जायगी और विभिन्न राष्ट्र एक बार फिर विश्वयुद्ध के सन्निकट आ जायेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरिया में चीन को "आक्रमणकारी" घोषित किये जाने, चीन के पीपुल्स रिपब्लिक के उक्त संस्था से बराबर पृथक् रखे जाने और सैन-फ्रांसिस्को सम्मेलन में, जिसमें सुदूरपूर्व के मामलों में महत्वपूर्ण स्वत्व रखने वाली शक्तियों में से कुछ का प्रतिनिधित्व नहीं था, जापानी शान्ति-सन्धि पर हस्ताक्षर किये जाने का परिणाम केवल यही हुआ कि समस्याएं और भी जटिल हो गयी और "युद्ध-विरति" निर्णय से जो एक आशा की भावना पैदा हो गई थी वह भी क्षीण हो गयी। भारत के लिये यह स्वाभाविक ही था कि वह किसी ऐसी कार्यविधि से अपने को अलग रखने में बड़ी सतर्कता से काम ले जो उसकी शान्ति और यथार्थवाद की नीति के मूल सिद्धान्तों के अनुरूप न हो और जहां तक जापान का संबंध था, यह समझा गया कि उस देश के साथ एक पृथक् सन्धि करना श्रेयस्कर होगा। राष्ट्रों में परस्पर अधिकाधिक शस्त्रास्त्र तैयार करने की होड़ की भयानक सम्भावनाएं निःशस्त्रीकरण कमीशन स्थापित करने से और भी स्पष्ट हो गई, यद्यपि व्यापक रूप से बिद्यमान तनातनी को देखते हुए इस बात की बहुत कम सम्भावना थी कि इस प्रकार का कमीशन कोई उपयोगी कार्य कर सकेगा। मध्य-पूर्व रक्षा-योजना के विचार ने स्पष्ट रूप धारण किया, किन्तु मिस्र में एक नाजुक स्थिति पैदा हो गयी, जिसमें आंग्ल-मिस्री विवाद से संबंधित प्रश्नों में मिस्र के शाह के अधीन नील की घाटी की एकता का प्रश्न प्रमुख था। ईरान सरकार की तेल के राष्ट्रीयकरण की नीति के प्रश्न पर ईरान सरकार और एंग्लो-ईरानियन आयल कम्पनी में पैदा होने वाले विवाद के कारण उस क्षेत्र में एक और संकटापन्न स्थिति उत्पन्न हुई। पेरिस सरकार के तिब्बत की "शान्तिपूर्ण मुक्ति" संबंधी निश्चय से यह प्रतीत होता था कि आगे चलकर इस समस्त क्षेत्र पर चीन अपना वास्तविक अधिकार कर लेगा। पड़ोसी देश नेपाल में, कभी-कभी उपद्रव होने के बावजूद अपेक्षाकृत शान्ति रही और अन्त में चलकर वहां जनप्रिय नताओं की अध्यक्षता में एक सरकार स्थापित हुई। किन्तु काश्मीर पर (जहां १९५१ ई० के अन्तिम काल में एक विधान-निर्मात्री सभा की स्थापना हुई) पाकिस्तान के आक्रमण से पैदा होने वाली समस्या अभी भी हल नहीं हो पायी थी, क्योंकि सुरक्षा परिषद् फिर इस समस्या का कोई न्यायोचित और मान्य हल निकालने में असफल रही। मध्यस्थता के सबध

में आग्ल-अमेरिकी प्रस्ताव से, जिसे भारत अस्वीकार करने के लिये विवश था, यह प्रनीत होता था कि वास्तविक स्थिति को समुचित रूप से समझ कर उसे नहीं तैयार किया गया था और इस गतिरोध की स्थिति को समाप्त करने का नया उपाय ढूँढ निकालने का भार आग चलकर राष्ट्र संघ के एक नये प्रतिनिधि, डा० फ्रैंक ग्राहम को सौंपा गया। इस बीच पाकिस्तान के जिम्मेदार क्षेत्रों ने ऐसे हल का परिचय दिया जो आश्चर्यजनक रूप से युद्धोन्मुख और पूर्णतः अनुचित था। भारत के प्रधान मंत्री की इस घोषणा से कि यदि काश्मीर पर कोई आक्रमण किया गया तो उसे भारत पर किया गया आक्रमण माना जायगा और इस बात से कि देश की सेना किसी भी धमकी का सामना करने के लिये तैयार खड़ी है, यह स्पष्ट रूप से प्रकट हो गया कि यद्यपि भारत शान्तिपूर्ण उपायों का प्रेमी है और कभी भी उनसे विरत नहीं हुआ है, फिर भी वह क़रता के सामने झुकने या युद्ध की धमकी के सामने घुटना टेकने के लिये किसी भी हालत में तैयार नहीं हो सकता। किन्तु दोनों देशों के बीच के व्यापार संबंध इस वर्ष हुए नये समझौते के फलस्वरूप और सुधर गये। दक्षिण अफ्रीका तथा लुका के भारतीयों को संबंधित सरकारों की नीतियों से पैदा होने वाली कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका के अधिकारियों द्वारा वर्ण-विभेद की नीति का परित्याग करने से बार-बार इन्कार किये जाने के कारण दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के संबंध में स्थिति विशेषरूप से असह्य हो गयी। इधर अपने देश में, सम्पूर्ण राष्ट्र आर्थिक कठिनाइयों से घिरा रहा और खाद्य का लगातार अभाव बने रहने के कारण फिर बड़े पैमाने पर उसका आयात करना आवश्यक हो गया, जिसका काफी बड़ा भाग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से प्राप्त हुआ। देश की अर्थ-व्यवस्था तथा सामान्य जवन-स्तर में सुधार करने के प्रयत्न जारी रखे गये और योजना कमिशन द्वारा तैयार की गयी एक पंचवर्षीय योजना का मसविदा भी प्रकाशित किया गया। भारतीय गणराज्य के प्रथम सामान्य निर्वाचन के सिलसिले में सर्वत्र राजनीतिक दार-वाइयों की चहल-पहल रही। इस निर्वाचन में जितनी बड़ी सख्या में मतदाताओं ने भाग लिया उसे देखते हुए यह निर्वाचन जनतंत्र के क्षेत्र में एक ऐसा महान् प्रयोग था जैसा इससे पूर्व संसार के किसी भाग में कभी भी नहीं देखा गया था। ..

२—राजनीतिक सिंहावलोकन

उत्तर प्रदेश में, १९४६ ई० में पद-ग्रहण करने के लिये आमन्त्रित मंत्रिमंडल द्वारा राज्य के शासन-प्रबन्ध की बागडोर संभालने की अवधि अब समाप्त होने जा रही थी। युद्ध के तथा, कुछ हद तक, देश-विभाजन के फलस्वरूप पैदा होने वाली कठिनाइयों के कारण इस अवधि में उन्नति प्रायः मन्दगति से हुई और विचाराधीन वर्ष की स्थिति में पिछले वर्ष से अधिक अन्तर नहीं रहा। आर्थिक संकट, जो अधिकांशतः विश्व-कारणों से पैदा हुआ था, अब भी एक गम्भीर वास्तविकता के रूप में विद्यमान था और ऊँची कीमतों तथा वस्तुओं के अभाव का भूत अब भी सारे देश पर सवार रहा। राज्य के कुछ भागों, विशेषतया पूर्वी जिलों को फिर दैवी प्रकोप का सामना करना पड़ा और वे अपनी फसलों के काफी बड़े भाग से वंचित हो गये। “कानून तथा व्यवस्था” की स्थिति, यद्यपि पहले से कुछ अच्छी थी, फिर भी अभी ऐसी नहीं थी कि चौकसी में कमी की जाती। श्रमिक वर्ग में बचनी के कुछ लक्षण बरबरे दिखाई पड़ते रहे और छात्र समुदाय के एक भाग ने भावावेश में आकर अनुशासनहीन कार्यों में अपनी मूल्यवान् शक्ति नष्ट की। फिर भी दिन-प्रतिदिन पैदा होने वाली समस्याओं का सामना करने के संबंध में की जाने वाली कार्यवाहियों के साथ-साथ विकास और पुनर्निर्माण का कार्य भी पहले की तरह चलता रहा। खाद्य-उत्पादन, सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार, विद्युत् विकास तथा राष्ट्र-निर्माण के अन्य कार्यों की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम को अन्तिम रूप से कानून का रूप दिया गया, यद्यपि समय के अनुकूल चलने में प्रत्यक्षतः अपनी असमर्थता के कारण जमींदार वर्ग ने जो विधि संबंधी विवाद खड़ा किया था उससे ऐसा प्रतीत होता था कि किसानों का मक्ति

क्षेत्रों में और अधिक दृढ़ हो गयी और जिलों के नियोजन कार्य से इसका सम्पर्क अधिकाधिक बढ़ता गया, जिसे इस वर्ष और अधिक तेजी के साथ चलाया गया। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों तथा इटावा में पाइलट योजनाओं के अन्तर्गत काफी बड़े इलाकों में रचनात्मक कार्यों की चहल-पहल रही। सामान्य निर्वाचनों के दौरान में, जिनका प्रभाव सारे प्रान्त की राजनीतिक स्थिति पर पड़ा और जिनके फलस्वरूप सत्ता प्राप्त करने के कुछ नये महत्वाकांक्षी भी सामने आये, मन्त्रिमंडल असामान्य कठिनाइयों के बावजूद जनता के सम्मुख अथक परिश्रम और अनेक उल्लेखनीय सफलताओं का रेकॉर्ड प्रस्तुत करने में सफ़र हुआ।

राजनीतिक दलों में सर्वश्रेष्ठ होने का गौरव अब भी कांग्रेस को ही प्राप्त रहा। जिन आन्तरिक मतभेदों के कारण १९५० ई० में जनतन्त्रात्मक मोर्चा बना था वे विरोधी विचार के कुछ लोगों के अलग हो जाने पर, जिनमें कुछ प्रमुख सदस्य भी सम्मिलित थे, तथा किसान मजदूर प्रजा पार्टी के बन जाने पर इस वर्ष समाप्त हो गये, किन्तु इसका कांग्रेस सस्था की प्रमुखता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष के परिवर्तन, जिसके फलस्वरूप श्री जवाहर लाल नेहरू को दल के प्रमुख का उत्तरदायित्व ग्रहण करना पड़ा तथा वर्ष के लगभग मध्य भाग में निकाले गये निर्वाचन घोषणापत्र के संबंध में व्यापक रूप से दिलचस्पी ली गयी। कांग्रेसजन आगामी निर्वाचनों की तैयारी करने के अतिरिक्त आमतेज़ पर रचनात्मक कार्यों में लग गये, जिनके लिये उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अप्रैल के अधिवेशन में काफी जोर दिया गया था। उन्होंने बिहार की खाद्यान्न की सहायता पहुंचाने के मामले में भी काफी दिलचस्पी ली और गणराज्य दिवस, राष्ट्रीय सप्ताह, स्वाधीनता दिवस तथा गान्धी जयन्ती जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कृत्यों तथा घटनाओं को यथोचित रूप से मनाने में जनता को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया।

जन कांग्रेस नामक दल, जिसे उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व कांग्रेसजनों ने पिछले वर्ष संगठित किया था, किसान-मजदूर प्रजा पार्टी के बन जाने के बाद कुछ समय तक अपना काम करता रहा। कांग्रेस तथा सरकार के विरुद्ध प्रचार करना ही इसका मुख्य कार्य था और लखनऊ में विधान भवन के सामने अप्रैल में प्रदर्शन करने के अतिरिक्त इस दल की ओर से बहुत सी सभाओं और जुलूसों का भी आयोजन किया गया। कुछ जिलों में स्थानीय कर्मचारियों, खासकर पुलिस विभाग के कर्मचारियों की कड़ी आलोचना की गयी।

नवनिर्मित किसान-मजदूर प्रजा पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा, जो अभी तक कांग्रेस में ही थे और जिन्होंने उसके कार्यों में भाग लिया था, सरकार पर भ्रष्टाचार, अयोग्यता, कुप्रबन्ध और अत्याचार के आरोप लगाये गये। कई जगहों पर पार्टी की शाखाएँ खोली गयीं और विभिन्न प्रचार सभाओं में जनता से कहा गया कि वह बड़ी तादाद में इस पार्टी में शामिल हो और कांग्रेस को वोट न दे। अहिंसात्मक तथा वैधानिक उपायों से सरकार को बदलने का समर्थन किया गया, किन्तु दो एक जगह से यह रिपोर्ट मिली कि व्यक्तिगत रूप से कुछ थोड़े से वक्ताओं ने हिंसा का भी प्रचार किया। नवम्बर के महीने में लखनऊ में हुई पार्टी की कार्यकारिणी की एक बैठक में पार्टी के निर्वाचन घोषणापत्र को अन्तिम रूप दिया गया।

सभाएँ करने और पर्व बांटने के अतिरिक्त, सदा की भांति, प्रदर्शन करना और जुलूस निकालना समाजवादी पार्टी का राज्य में मुख्य काय था। सभाओं में जो भाषण दिये गये उनमें कांग्रेस और सरकार के विरुद्ध पूर्ववत् आरोप लगाये गये और कुछ ऐसी भी रिपोर्टें मिली जिनसे यह पता चलता था कि कुछ जगहों में स्थानीय कार्यकर्ताओं ने ऐसी बातें कही जिनकी प्रवृत्ति लगभग जनता को हिंसा के लिये प्रोत्साहित करने की थी। ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी का प्रभाव बढ़ाने की पूरी-पूरी कोशिश की गयी और स्पष्टतः पार्टी को जनता में जनप्रिय बनाने के उद्देश्य से स्थानीय शिकायतों, खासकर किसानों और श्रमिकों की शिकायतों को बहुत महत्व दिया गया। कुछ स्थानों पर किसानों के प्रदर्शन आयोजित किये गये और कुछ अन्य स्थानों पर श्रमिकों को हड़ताल करने के लिये प्रोत्साहित किया गया। आगरा में एक स्थानीय

चलाया गया, जो कुछ दिनों तक चला और समझौता हो जाने पर १३ जुलाई को समाप्त हो गया, किन्तु हड़ताल के प्रति सरकार के रुख की तथा रेलवे की भावी हड़ताल के संबंध में भारत सरकार द्वारा निकाले गये आर्डिनेन्स की कड़ी आलोचना की गयी। उत्तर प्रदेशीय हिन्द किसान पंचायत तथा हिन्द मजदूर सभा की जनरल कोसिल और कार्यकारिणी समिति की बैठको के अतिरिक्त इस वर्ष हिन्द किसान पंचायत का वार्षिक अधिवेशन भी हुआ। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी समिति की कई बार बैठके हुई और एक बैठक में महिलाओं में कार्य करने के लिये महिला पंचायत सगठित करने का निश्चय हुआ। मई दिवस के अवसर पर विभिन्न जिलों में किसानों और मजदूरों की कुछ मांगों को दुहराना और संबंधित जिला मैजिस्ट्रेटों को इन मांगों का एक स्मृति-पत्र प्रस्तुत करना पार्टी का मुख्य कार्य रहा। २० मई से २७ मई तक एक 'रचनात्मक सप्ताह' भी मनाया गया, किन्तु इससे जनता में कोई अधिक उत्साह पैदा होता नहीं दिखायी दिया। २२ नवम्बर से २९ नवम्बर तक एक "किसान सप्ताह" भी मनाया गया। तीन जिलों के, जिनमें समाजवादी ३० मई को "जनवाणी दिवस" सगठित कर सके, जिला मैजिस्ट्रेटों को एक मांग-पत्र पेश किया गया, जिसमें बिना कोई प्रतिकर दिये जमींदारी का विनाश करने, भूमि का पुनर्वितरण करने तथा मूल उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने आदि की मांगें सम्मिलित थीं। राज्य भर में जिलों के सदर मुकामों पर इस दिवस को मनाने की बहुत पहले से तैयारियाँ की गई थीं। सामान्य निर्वाचनों का समय ज्यों-ज्यों निकट आता गया, प्रचार-सभाओं की संख्या बढ़ती गयी और उम्मीदवारों का चुनाव करने के कार्य के लिये जुलाई में एक पार्लमेन्टरी बोर्ड स्थापित किया गया। कुछ जगहों पर समाजवादियों ने शडचूल्ड कास्ट फेडरेशन के साथ एक 'संयुक्त मोर्चा' बनाया, किन्तु पार्टी के नेतागण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी और क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी जैसी संस्थाओं के साथ गठबंधन करने के विचार के प्रबल विरोधी मालूम पड़ते थे। कुछ जगहों से पार्टी में फूट पड़ जाने के समाचार भी मिले और बहुत से त्याग-पत्र दिये गये।

क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी की, जिसने अधिकतर पूर्वी जिलों में कांग्रेस सरकार, पूँजीपतियों, जमींदारों और सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध पुराने ढंग पर प्रचार करना जारी रखा और जिसकी कुछ सभाओं में वक्ताओं ने हिंसा का समर्थन करने में कोई संकोच नहीं किया, प्रगति को इस वर्ष धक्का पहुँचा। पार्टी की आन्तरिक फूट और अधिक बढ़ गयी, जिससे यह संस्था दो समुदायों में बँट गयी, जिनमें से एक ने कुछ समय तक दूसरे को अपेक्षा काम में अधिक मुस्तैदी दिखायी और पूर्वी जिलों में कुछ जिला किसान सम्मेलन तथा कानपुर में ६ अगस्त से १५ अगस्त तक "मूठा स्वतंत्रता सप्ताह" संगठित किया। किन्तु इस सम्पूर्ण संस्था का भविष्य वर्ष के अन्तिम दिनों में अच्छा नहीं दिखायी पड़ रहा था और इसके सदस्य नवनिर्मित बाँध पक्षी समाजवादी पार्टी में अधिकाधिक दिलचस्पी ले रहे थे, जो समस्त "बाँध पक्षी" दलों में एकता की आवश्यकता का समर्थन करती थी। कुछ स्थानों में क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिये, जिनके संबंध में पहले उन्होंने विधान मंडल की कुछ जगहों के लिये उम्मीदवार खड़े करने का निश्चय किया था, कम्युनिस्टों के साथ मिल कर काम किया।

कम्युनिस्ट पार्टी ने, जिसकी कार्यवाहियों में वर्ष के आरम्भ में कोई जोर नहीं था, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिये बाँध के महीनों में सभाओं, जुलूसों तथा पोस्टरों और पुस्तिकाओं के जरिये और कभी-कभी नाटकों और फिल्मों (सिनेमा-चित्रों) के प्रदर्शनों द्वारा, जिनमें रूसी और चीनी फिल्मों भी सम्मिलित थी, जोर-शोर से काम किया। सामान्य निर्वाचनों के संबंध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के निर्णय की घोषणा होने से पहले ही उत्तर प्रदेश के कम्युनिस्टों ने निर्वाचनों में भाग लेने का निश्चय कर लिया था और इस संबंध में एक तदर्थ समिति बना ली थी। उसने अन्त में चलकर जो अपेक्षाकृत थोड़े से उम्मीदवारों को खड़ा करने का निश्चय किया उससे यह प्रतीत होता था कि जनता पर उसका जो सीमित

प्रभाव था और उसे सफलता की जितनी आशा थी, उसे वह समझती है, किन्तु वह जनता से सम्पर्क बढ़ाने और अपनी विचारधारा का प्रचार करने का अवसर खोना नहीं चाहती थी। निर्वाचन-संबंधी कार्य के अतिरिक्त, पूर्वी जिलों में फौजदारी के मुकद्दमों में फंसे हुए कम्युनिस्ट कार्यकर्त्ताओं को बचाने के लिये हथपा इकट्ठा करना, समस्त बामपक्षी दलों का एक संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश करना, “शान्ति अपोल” पर हस्ताक्षर करा कर प्रायः वर्ष भर “शान्ति आन्दोलन” चलाना तथा सम्मेलनों का आयोजन करना इस पार्टी के कुछ खास-खास काम थे।

सदा की तरह १ मई को “मई दिवस”, २१ जनवरी को “लेनिन दिवस”, १ अगस्त को “राजबन्दी दिवस” और ७ नवम्बर को “रूसी क्रान्ति दिवस” मनाये जाने के अतिरिक्त संगठन के मृत सदस्यों की स्मृति में कुछ जगहों पर शोक सभायें आदि आयोजित की गईं। पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने छात्र-छात्राओं, किसानों और मजदूरों की ओर विशेष ध्यान दिया और कभी-कभी निम्नश्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के प्रति भी मैत्रीपूर्ण भाव व्यक्त किये। ट्रेड यूनियन की कार्यवाहियों के सिलसिले में संयुक्त मोर्चा कायम करने के उद्देश्य से गैर-साम्यवादी (कम्युनिस्ट) कार्यकर्त्ताओं को भी उत्तर प्रदेश ट्रेड यूनियन कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति दे दी गई। कई छोटी-छोटी सभाओं में सदा की तरह कांग्रेस, सरकार, स्थानीय कर्मचारियों, पूंजीपतियों और जमींदारों की आलोचना की गई और खाद्य व कपड़े की स्थिति, जमींदारी विनाश निधि, प्रिवेन्टिव डिटेन्शन ऐक्ट और विभिन्न स्थानीय मामलों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जब वक्ताओं ने वैधानिकता की आड़ छोड़कर हिंसा का प्रचार किया या यह सुझाया कि सरकार केवल क्रान्ति द्वारा ही बदली जा सकती है। निम्नकोटि के सरकारी कर्मचारियों पर, जो ड्यूटी पर थे, कई आक्रमण होने और कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं के साथ झगड़े और मारपीट किये जाने की भी रिपोर्ट मिली।

हिन्दू महासभा, राम राज्य परिषद् और भारतीय जन संघ ने अपना ध्यान अधिकतर हिन्दू सम्प्रदाय में अपन पक्ष का प्रचार करने में लगाया। यह रिपोर्ट भी मिली कि इन पार्टियों के उत्तर प्रदेश के नेताओं ने वर्ष के अंत में अपने कार्यकर्त्ताओं को यह आदेश दिया कि वे जिलों में संयुक्त पार्लियामेन्टरी बोर्ड कायम करें। लेकिन महासभा के लोगों में मुरादाबाद के इस प्रस्ताव के संबंध में बड़ा मतभेद था कि उक्त संगठन के पार्लियामेन्टरी कार्यक्रम में गैर-हिन्दुओं को भी भाग लेने दिया जाय।

महासभा के नेताओं ने अपने आन्दोलन के संबंध में कई जिलों का दौरा किया और सदस्यों को भर्ता करके इस संगठन को मजबूत बनाने का प्रयत्न किया। महासभा के वक्ताओं ने सभाओं में देश के विभाजन के लिये कांग्रेस को दोषी ठहराया। अखंड भारत के आदर्श की पुष्टि की, हिन्दू कोड बिल का विरोध किया या उन सदियों के पुनरुद्धार की माँग की जो भूतकाल में मुस्लिमों में परिणत कर दिये गये थे। मुसलमानों और पाकिस्तान के प्रति सरकार की नीति को तुष्टीकरण की नीति कहकर बहुधा उसकी आलोचना की गई। काश्मीर के प्रति अपनाई गई नीति से भी वे सहमत नहीं थे। उक्त संगठन के सदस्यों ने पाकिस्तान द्वारा, जिसके “तने हुये घूँसे” के चिन्ह से वे और भी चिढ़े हुए थे, आक्रमण किये जाने की दशा में काश्मीर की रक्षा के हेतु सरकार की पूरी सहायता करने का वचन दिया। २ सितम्बर को महासभा द्वारा मनाये गये “काश्मीर दिवस” के अवसर पर इस प्रतिज्ञा को दोहराया गया।

राम राज्य परिषद् का दावा यह था कि यही एक ऐसी संस्था है जिसका आधार धर्म है। यह संगठन अधिकतर हिन्दू कोड बिल का विरोध संगठित करने और गोधूम पर प्रतिबंध लगाने

की माँग के पक्ष में समर्थन प्राप्त करने में व्यस्त रहा। इसके अतिरिक्त महासभा की तरह इसके वक्ताओं ने भी कभी-कभी दूसरी समस्याओं की चर्चा की जिनमें आर्थिक समस्या, विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की समस्या तथा अयोध्या के बावरी मस्जिद-जन्मभूमि संबंधी विवाद सम्मिलित थे। धर्म निरपेक्ष राज्य के आदर्श की खिल्ली उड़ाई गई और यह कहा गया कि जब परिषद् की सरकार बनेगी तो भारत का संविधान धर्म शास्त्रों के आधार पर होगा। लोगो से यह कहा गया कि यदि वे वास्तव में राम राज्य कायम करना चाहते हैं तो वे परिषद् का समर्थन करें। इस बात का भी आश्वासन दिया गया कि अल्पसंख्यकों को भी उक्त राज्य में उचित स्थान मिलेगा। हिन्दू कोड बिल के विरोध में किये जाने वाले प्रदर्शन में भाग लेने के लिये कुछ स्वयंसेवक दिल्ली भेजे गये और "हिन्दू कोड बिल विरोध दिवस" मनाया गया।

भारतीय जन संघ ने भी मुख्यतया हिन्दू कोड बिल का विरोध किया और गोबध पर प्रतिबंध लगाने के लिये जोर दिया। वर्ष के उत्तरार्द्ध में यह संगठन का यम हुआ और इसने लखनऊ में प्रान्तीय कार्यालय खोलने के अलावा कई जिलों में भी अपनी शाखाएँ खोली और मुख्यतया सभाओं द्वारा जोर-शोर का प्रचार किया। इसके वक्ताओं ने कटु आलोचनाएँ की और कभी-कभी प्रधान मंत्री तथा अन्य नेताओं के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया। करो और निर्धन (कन्दोलो) को बग़ावती वर्ग के लिये हानिकर बताया गया और उनके संबंध में सरकारों की नीति की आलोचना की गई। धर्म निरपेक्ष राज्य के सिद्धान्त, वैदेशिक नीति तथा मुसलमानों और पाकिस्तान के प्रति सरकार के रुख का भी बहुधा आलोचना की गई। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कभी-कभी यह भी दावा किया कि इस संगठन का उद्देश्य हिन्दू संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करना है और उन्होंने मुसलमानों को भी सलाह दी कि वे 'भारतीय संस्कृति' अपनायें। अन्य अवसरों पर उन्होंने यह घोषणा की कि सच का उद्देश्य सभी जातियों की कठिनाइयों को दूर करना तथा उनके हकों की रक्षा करना है। राष्ट्रपति शासन की माँग की गई, ताकि "निष्पक्ष और स्वतंत्र" चुनाव हो सके और इस संबंध में कई स्थानों पर "राष्ट्रपति शासन दिवस" मनाया गया।

जन संघ के उम्मीदवारों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं का समर्थन मिलने की बात भी सुनने में आई, यद्यपि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से राजनीति से अलग रहे और पार्टी के आधार पर उन्होंने चुनाव में कोई भाग नहीं लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दैनिक कार्य शारीरिक व्यायाम, नकली (माक) लड़ाइयों और रैलियों तक ही सीमित रहा। इनमें वे रैलियाँ आदि भी सम्मिलित हैं जो महत्वपूर्ण हिन्दू त्यौहारों और विशेष अवसरों पर सगठित की गईं। कई स्थानों में ग्रीष्म तथा शरदकालीन शिविर भी संगठित किये गये। साधारणतया रैलियों के संबंध में दिये गये भाषणों में हिन्दू संस्कृति तथा संगठन की शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। कभी-कभी सरकार की आलोचना की गई और काश्मीर के मामले का भी उल्लेख किया गया। रक्षाबंधन के दिन जो रैली की गई उसमें भाग लेने वाले स्वयंसेवकों से यह कहा गया कि मातृभूमि पर आक्रमण होने की दशा में उन्हें किसी तरह का भी बलिदान करने के लिये तैयार रहना चाहिये। कभी-कभी साम्यवाद के सिद्धान्तों का भी उल्लेख किया गया और इस बात का संकेत किया गया कि सच उसके विरुद्ध मोर्चा लेने के लिये तैयार है और साथ ही उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाहियों में सरकार की सहायता करने के लिये तत्पर है।

उत्तर प्रदेश में सिख सम्प्रदाय के लोगों ने अकाली दल के पक्ष में प्रचार किया और दीवानों तथा विशेष "दिवसों" जैसे "खालसा दिवस", "वैसाखी दिवस" इत्यादि पर आयोजित सभाओं में एक पृथक् पंजाब-भारत राज्य स्थापित करने की माँग की। सितम्बर में जो यू० पी० सिख कन्वेंशन हुआ उसमें भाग लेने वालों ने एक प्रस्ताव पारित करके सिखों से यह कहा कि वे

चुनाव में कांग्रेस का विरोध करे और बाद में उत्तर प्रदेश सिख सम्मेलन के पाँचवें अधिवेशन में सिख प्रतिनिधि बोर्ड को यह अधिकार दे दिया जाय कि वह चुनाव के सिलसिले में 'अन्य प्रगतिशील पार्टियों' से समझौता कर सकता है। पंजाबी विस्थापित व्यक्तियों के लिये कुछ विशेष सुविधाओं की भी माँग की गई। विस्थापित व्यक्तियों के संगठनों ने अपनी समस्याओं की और विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया और निष्क्रान्त सम्पत्ति मुसलमानों को देने के संबंध में निष्क्रान्त सम्पत्ति अध्यादेश (इवेकुई प्रपर्टी आर्डीनेंस) में किये गये संशोधन की आलोचना की। केन्द्रीय पुरुषार्थी बोर्ड द्वारा मनाये गये 'निष्क्रान्त सम्पत्ति विरोध दिवस' के अवसर पर यह माँग की गई कि मुस्लिम निष्क्रमणार्थियों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति विस्थापित व्यक्तियों को दी जाय।

शेड्यूल कास्ट कैडरेशन और शोषित संघ ने मुख्यतया सवर्ण हिन्दुओं और सरकार के विरुद्ध अपनी शिकायतों का वर्णन किया। सवर्ण हिन्दुओं पर अत्याचार करने का दोषारोपण किया गया और सरकार के ऊपर यह दोष लगाया गया कि वह अनुसूचित जातियों और पिछड़े हुये वर्गों की समस्याओं के प्रति उदासीन है। उनके कतिपय सम्मेलनों और सभाओं में कड़ी भाषा और अपशब्दों का प्रयोग किया गया और कई अवसरों पर फेडरेशन के नेताओं ने अपने अनुगामियों से बुद्ध धर्म ग्रहण करने के लिये कहा। दोनों ही संगठनों ने आम चुनाव में अपने अपने उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिये लोगों से कहा। सितम्बर में संघ की कार्यकारिणी समिति की जो बैठक हुई उसमें "शोषित संघ" के सदस्यों में आपस में फूट पड़ गई और इसका परिणाम यह हुआ कि दो दल बन गये। इस संगठन ने हिन्दू कोड बिल का समर्थन किया।

जमायत-ए-उल-उलेमा तथा जमायत-ए-इस्लामी ने मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को उभाड़ा। इन दोनों ही संस्थाओं ने राजनीति से अलग रहने की घोषणा की थी और वे धार्मिक आधार पर अपने सम्प्रदाय के सदस्यों को संगठित करने में व्यस्त प्रतीत होती थीं। जमायत-ए-तबलीग द्वारा भी इसी प्रकार की कार्यवाहियों की गईं और पहले के ब्लाकसारों, मुस्लिम लीगियों तथा अहमदियों ने अपने मूर्ख संगठनों में फिर से जान डालने की कोशिश की। आमतौर पर मुसलमानों ने हिन्दी के प्रति सरकार की नीति की आलोचना की और उर्दू के पक्ष का समर्थन किया। इस सम्प्रदाय के कुछ व्यक्तियों ने तो ऐसी प्रवृत्ति की परिचय दिया जिसे देखते हुये यह नहीं कहा जा सकता था कि उन्हें भारत के नागरिक होने की जिम्मेदारियों का जरा भी ध्यान है और उन्होंने भारत विरोधी प्रचार भी किया। कभी कभी "इस्लाम खतरे में है" का पुराना नारा बुहराया गया और यह रिपोर्टें भी मिली कि मुसलमानों को गुप्त रूप से शास्त्रास्त्र इकट्ठा करने की सलाह दी जा रही है और उनसे कहा जा रहा है कि भारत के विरुद्ध "जिहाद" आरम्भ होने पर पाकिस्तान की सहायता करने के लिये वे तैयार रहें। यह भी सुनने में आया कि 'जिहाद' के शीर्ष ही शुरू होने का जिक्र अक्सर पाकिस्तान से आई हुई प्राइवेट चिट्ठियों में होता था। किन्तु कुछ मुस्लिम संगठनों ने, जैसे अखिल भारतीय शिया कान्फ्रेंस और यू० पी० मोमिन कान्फ्रेंस ने पाकिस्तान में 'जिहाद' प्रचार की घोर निंदा की। शिया कान्फ्रेंस ने अगस्त में अपने लखनऊ के अधिवेशन में प्रधान मंत्री के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास प्रगट किया और काश्मीर के प्रति पाकिस्तान के हल की आलोचना की। मोमिन कान्फ्रेंस की कार्यकारिणी समिति ने यह विश्वास दिलाया कि पाकिस्तान और भारत में लड़ाई छड़ने पर वे सरकार का पूरा-पूरा साथ देंगे।

"सुभाष दिवस" मनाने के अतिरिक्त फारवर्ड ब्लाक ने कतिपय स्थानों पर छोटी छोटी सभाये की। इनके अलावा उसने वर्ष में प्रायः कोई और ऐसा काम नहीं किया जिससे राज्य में उसके अस्तित्व का पता चलता। कई व्यक्तियों पर, जो इस संगठन के सदस्य थे, दो जमींदारों की हत्या के सिलसिले में फौजदारी मुकद्दमा चलाया गया। वे दोषी पाये गये और सेशनस कोर्ट ने उन्हें सजा दी।

जमींदारों ने सभायें आयोजित करके और नये अधिनियम की वैधता के सबंध में मुकद्दमा लड़ने के लिये चन्दा इकट्ठा करके जमींदारी विनाश विधायन के विरुद्ध अपने आन्दोलन को और भी तेजी के साथ चलाया तथा राज्य के विरुद्ध हजारों मुकद्दमे हाईकोर्ट में चलाये। अप्रैल में यू० पी० जमींदारों एसोसियेशन के सम्मेलन ने आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार खड़ा करने का निश्चय किया और उसने गत वर्ष जमींदारों द्वारा बनाई गई प्रजापार्टी का प्रसीडेंट और जनरल सेक्रेटरी भी चुना। बाद में प्रजा (जमींदार) पार्टी की कार्यकारिणी समिति और पार्लियामेन्टरी बोर्ड की संयुक्त बैठक में यह तय किया गया कि उम्मीदवारों का चुनाव करने के लिये एक कमेटी नियुक्त की जाय और समय समय पर प्रचार करने के संबंध में जो सभायें की गईं उनमें किसानों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया।

३—समाचार-पत्र और जनमत

उत्तर प्रदेश में जिस समस्या की ओर जनता का ध्यान सबसे अधिक आकृष्ट हुआ वह खाद्य समस्या थी। केन्द्रीय सरकार द्वारा (जनवरी में) राशन में घोटित की गई कटौती की बहुत से समाचार-पत्रों ने तीव्र आलोचना की। इन समाचार-पत्रों ने “खाद्यान्न खोज समिति” (फूडवेन्स इन्वेस्टीगेशन कमेटी) की इस सिफारिश की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि प्रतिदिन १६ आउंस राशन दिया जाय। देश के कुछ भागों की खाद्य स्थिति खराब हो जाने पर चिन्ता प्रगट की गई और जोर देकर इस बात की जरूरत बताई गई कि खाद्य उत्पादन बढ़ाने की महत्ता पर नये सिरे से ध्यान दिया जाय और “निर्यात” सम्बन्धी दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाय। कुछ समाचार-पत्रों ने जोरदार शब्दों में इस बात की सिफारिश की कि बंदरो और जगली जानवरों को नष्ट कर दिया जाय और मुनाफाखोरो, गल्ला जमा करने वालों तथा चोरबाजारी करने वालों के विरुद्ध और कड़ी कार्रवाई की जाय।

यह बात सामान्यतया स्वीकार कर ली गई थी कि सारे देश के लिये खाद्य नीति एक सी हो तथा गल्ले का “आयात” राष्ट्र के आत्म-सम्मान के विरुद्ध न समझा जाय, परन्तु भूमि सेना तैयार करने के विचार का समर्थन नहीं किया गया। वर्ष के अंत में यह सुझाव दिया गया कि खाद्य में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये सरकार को चाहिये कि वह लोगों में एक प्रकार का धार्मिक उत्साह पैदा करने में सर्वोदय के कार्यकर्त्ताओं को सब तरह का सहयोग दे। कुछ समाचार-पत्रों को इस बात का पूर्णतया विश्वास नहीं था कि वास्तव में ५० लाख टन गल्ले की कमी है। उनकी राय में खाद्य समस्या गम्भीर होते हुये भी इतनी गम्भीर नहीं थी जितनी कि वह प्रतीत हो रही थी। उनका विचार था कि वह प्रभावपूर्ण ढंग से हल की जा सकती है, यदि वास्तव में संकटग्रस्त व्यक्तियों के लिये सभी लोग त्याग करने के लिये तैयार हो।

भारत को ऋण के रूप में गेहूं देने के प्रश्न पर अमेरिका में लम्बे असें तक जो वाद-विवाद चला उससे यहां के समाचार-पत्रों की भावनाओं को सबसे अधिक चोट पहुंची। यद्यपि देश में खाद्यान्न की बड़ी संकट जरूरत थी, फिर भी अधिकतर समाचार-पत्रों का यही विचार था कि देश की स्वतंत्रता, सम्मान या उसके हितों को किसी दूसरे देश के हाथ बेचकर वहां से खाद्यान्न प्राप्त करने से बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता। खास तौर से यह कहा गया कि अपमानजनक शर्तों के साथ दान के रूप में खाद्यान्न प्राप्त करने से तो अच्छा यह होगा कि हम भूखे मर जायें। इस संबंध में सरकार ने रूस और चीन से खाद्यान्न प्राप्त करने की जो कोशिश की उसकी सराहना की गई। किन्तु इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया कि देश में जिस दर पर गेहूं और चावल की वसूली की जाती है उसमें और इन्हीं वस्तुओं के लिये देश के बाहर दिये जाने वाले मूल्य में बड़ी विषमता है।

स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव के कारण देश के राजनीतिक वातावरण में एक असाधारण उत्साह भरा हुआ था। नई नई पार्टियों का जन्म हुआ और पुरानी पार्टियों ने अपना काम जोरों के साथ शुरू किया। फिर भी सभी जगह इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रधानता थी। आचार्य कृपलानी ने जब अपना 'डिमोक्रेटिक प्रॉन्ट' तोड़ा तो यह आशा बंध चली थी कि कांग्रेस से आये हुये लोग उसमें वापस चले जायेंगे। आचार्य जी द्वारा यह 'फ्रंट' तोड़ दिये जाने पर उतना खेद नहीं प्रगट किया गया जितना कि उनके कांग्रेस से इस्तीफा देने पर किया गया। सामान्यतः यह महसूस किया जा रहा था कि आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस से अलग होने के लिये जो कारण बताये वे संबंध विच्छेद करने के लिये पर्याप्त नहीं थे। किन्तु अधिकतर समाचार-पत्रों ने जुलाई में जारी किये गये कांग्रेस के निर्वाचन-घोषणापत्र का स्वागत किया। कुछ पत्रों ने यह आलोचना की कि वह वास्तविकता से बहुत दूर है। लगभग सभी समाचारपत्रों ने कांग्रेस के नये अध्यक्ष का स्वागत किया और पार्टी के नये प्रधान श्री जवाहर लाल नेहरू की तारीफ की। जब श्री जवाहर लाल नेहरू ने कांग्रेस से निकले हुये व्यक्तियों से उसमें फिर से आ जाने की अपील की तो कई समाचारपत्रों ने यह आशा प्रगट की कि किसान-मजदूर प्रजा-पार्टी, जिसके निर्माण का स्वागत तो कम किया गया था और आलोचना अधिक हुई थी, अपने हक पर फिर से विचार करेगी।

देश की सामान्य आर्थिक स्थिति कभी भी सतोषजनक नहीं समझी गई। कभी-कभी समाचार-पत्रों ने मध्यम और निम्न वर्गों के लोगों की मुसीबतों की ओर ध्यान आकृष्ट किया और सरकार से इस बात की सिफारिश की कि वह इन वर्गों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये कार्रवाई करे। मार्च के शुरू में संसद में पेश किये गये बजट में कर लगाने के प्रस्तावों की कई समाचार-पत्रों द्वारा आलोचना की गई। उन्होंने विशेषतया तम्बाकू और मिट्टी के तेल पर ड्यूटी बढ़ाने पर आपत्ति की और सरकार से प्रार्थना की कि वह अन्य साधनों से, जैसे राजाओं की सम्पत्ति से धन प्राप्त करे। रुपये के पुनर्मूल्यन के प्रश्न पर वित्त मंत्री के इस कथन का साधारणतः समर्थन किया गया कि "रुपये के विनिमय-अनुपात में परिवर्तन करके खतरा मोल लेने का निश्चय ही यह समय नहीं है।"

कपड़े के उद्योग के संबंध में कुछ समाचारपत्रों की यह शिकायत थी कि इस उद्योग का व्यवहार बिगड़े हुये बच्चे की तरह है और कपड़े की मिलों के मालिक सरकार द्वारा दी गई किसी भी सुविधा का अनुचित लाभ उठाने के लिये सदैव तत्पर रहते हैं। कपड़े के मूल्य में जो वृद्धि की गई उस पर क्षोभ प्रगट किया गया और सरकार से कहा गया कि वह कपड़े के उद्योग-पतियों की ज्यादातियों को रोके। कुछ समाचारपत्रों ने यह लिखा कि देश में कपड़े की सप्लाई संतोषजनक न होने पर भी कच्ची रई का बाहर भेजना, चाहे वह थोड़े ही परिमाण में क्यों न हो, बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है। उनकी राय में विशेष आवश्यकता इस बात की थी कि कपड़े के उद्योग के संबंध में यथार्थवादी नीति अपनाई जाय, जिसके अनुसार अन्य बातों के अलावा मिलों को यह भी सुविधा मिले कि वे कच्ची रई उचित दर पर पा सकें। कुछ समाचारपत्रों का यह भी विश्वास था कि कपड़े की जितनी कमी है सरकार ने उससे कम अनुमान लगाया है।

पंचवर्षीय योजना के पांडुलेख का प्रकाशित होना एक महत्वपूर्ण घटना थी। कई समाचार-पत्रों ने इसका स्वागत किया और कहा कि देश की आर्थिक मुक्ति की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है तथा यह सुझाव दिया कि कम से कम उन योजनाओं को, जिनके विषय में कोई विवाद नहीं है, अविलम्ब कार्यान्वित किया जाय। आम तौर पर यह विश्वास किया जाता था कि योजना की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि देश की विशाल जनशक्ति को रचनात्मक कार्यों में लगाया जाय। तदनुसार गैरसरकारी एजेंसियों और प्रमुख व्यक्तियों का सक्रिय

सहयोग प्राप्त करने की महत्ता पर विशेष जोर दिया गया। प्रधान मंत्री के इस कथन की सराहना की गई कि उक्त योजना के संबंध में नये प्रस्ताव और नये सुझाव अब भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। यद्यपि इस योजना को वित्त-पोषित करने के प्रश्न पर दिये गये सुझावों की संख्या अधिक नहीं थी, फिर भी जो सुझाव दिये गये उनमें इस विचार का समर्थन किया गया था कि निजी पूँजी का लगाना भी इस प्रश्न को हल करने का एक उपाय माना जाय।

कंट्रोलो के प्रश्न पर परस्पर-विरोधी मत व्यक्त किये गये। किन्तु अधिकांश समाचार-पत्रों का यह विश्वास था कि कंट्रोलो के हटाने की नीति अपनाने का समय अभी नहीं आया। टैरिफ कमिशन के स्थापित किये जाने का साधारणतया सभी ने स्वागत किया। यही बात प्रशासन पर दी गई गोरवाला कमेटी (Gorawala Committee) की रिपोर्ट के संबंध में भी कही जा सकती है। केन्द्रीय सचिवालय की कार्यपद्धति के संबंध में तखमीना कमेटी (Estimates Committee) की रिपोर्ट पर जो आलोचनार्थ की गई, उनमें से एक अधिक महत्वपूर्ण आलोचना यह थी कि यदि अन्य मन्त्रालयों की बहुत अधिक धनराशि व्यय करने की प्रवृत्तियों पर वित्त मन्त्रालय का नियंत्रण ढीला कर दिया जायगा तो यह ठीक न होगा। यह सुझाव अव्यावहारिक समझा गया कि उच्च अधिकारी अपने वेतन में से उस धनराशि को अपनी इच्छा से समर्पित कर दें जो उन्हें ३,००० रु० प्रति मास से अधिक मिलती हो।

सैनिक शक्ति घटाने के निर्णय की सराहना की गई। संसद में प्रतिरक्षा मन्त्रालय (Defence Ministry) के विरुद्ध जो आरोप लगाये गये उनसे चिन्ता पैदा हो गई और यह मांग की गई कि इन आरोपों की अच्छी तरह से जाँच की जाय। कुछ समाचार-पत्रों ने प्रिविलिज डिटेन्शन (निवारक निरोध) ऐक्ट की अवधि बढ़ाए जाने की आलोचना की, किन्तु कुछ अन्य ऐसे समाचार-पत्र भी थे जिन्होंने इस कार्यवाही को न्यायोचित बतलाया। इसी प्रकार कुछ पत्रों ने हिन्दू कोड बिल की सराहना की तथा अन्य समाचार-पत्रों ने उसे एक अनुपयुक्त कानून बताया।

प्रायः सभी समाचारपत्रों ने मद्रास विधान सभा के अध्यक्ष (Speaker) के इस निर्णय (ruling) पर आपत्ति की कि समाचार-पत्रों द्वारा विधान-मंडलो की कार्यवाहियों पर की जाने वाली ऐसी टीका-टिप्पणियाँ, जिनसे मत-दान (voting) पर प्रभाव पड़ने की संभावना हो, विशेषाधिकार का उल्लंघन (breach of privileges) हैं। यह बात बड़े जोरदार शब्दों में व्यक्त की गई कि समाचार-पत्रों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे सार्वजनिक हित में न केवल संसद ही पर बल्कि जनतंत्र के किसी भी अंग पर प्रभाव डालने का प्रयत्न कर सकते हैं तथा उन्हें इस अधिकार से वंचित करने का अर्थ यह होगा कि उन्हें उनके एक मौलिक अधिकार (fundamental right) से वंचित किया जा रहा है। कुछ समाचार-पत्रों ने प्रेस बिल का यह कहकर स्वागत किया कि वह भारत के प्रेस के स्वतंत्रता-आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है तथा अन्य समाचार-पत्रों ने उसकी यह कहकर आलोचना की कि उससे सभी मौलिक अधिकारों पर आघात किया गया है।

रेल कर्मचारियों द्वारा आम हड़ताल करने की धमकी पर बहुत महीनों तक बड़ी जोरो से चर्चा होती रही। कोई भी समाचार-पत्र समाजवादी नेता, श्री जयप्रकाश नारायण की यह बात मानने को तैयार नहीं था कि ऐसी कड़ी कार्यवाही करने के लिए रेल कर्मचारियों के पास कोई उचित कारण था। यह अनुभव किया गया कि रेल कर्मचारी श्रमिक वर्ग के एक ऐसे भाग हैं जिसे काफी अच्छा वेतन दिया जाता है और एक ऐसे समय जब कि खाद्य-स्थिति इतनी गम्भीर थी तथा पाकिस्तान के साथ भारत के कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, रेल कर्मचारियों द्वारा आम हड़ताल करना, न केवल स्वयं उनके ही हितों के लिये अच्छा नहीं था, बल्कि उससे

देश भी एक बड़ी भारी विपत्ति में पड़ जाता। बहुत से समाचार-पत्रों ने सरकार को इस बात का आश्वासन दिया कि रेल कर्मचारियों की चुनौती का सामना करने में जनता उसका साथ देगी। अगस्त के महीने में हड़ताल स्थगित कर दी गई तथा नवम्बर में सरकार और रेल कर्मचारियों के फेडरेशन (Railwaymen's Federation) के मध्य एक समझौता हो गया। इन दोनों ही घटनाओं का स्वागत किया गया।

जब कभी कोई रेल दुर्घटना होती, तो प्रत्येक बार रेलवे प्रशासन की आलोचना की जाती थी। इस मत का कि ऐसी दुर्घटनाएँ साधारणतया तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों (sabotage) के फलस्वरूप होती हैं, बहुत समर्थन नहीं किया गया तथा सरकार से कहा गया कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अत्यन्त कड़ी कार्रवाही की जाय जो अपने कर्तव्यों की अवहेलना करने के दोषी पाए जायें। रेल के किराये में वृद्धि किसी ने भी पसंद नहीं की।

संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पर व्यापक रूप से चर्चा की गई। कुछ समाचार-पत्रों ने इस संबंध में सरकार पर सभी प्रकार के आरोप लगाये कि यह कुछ इरादों से प्रेरित होकर ऐसा कर रही है और यह कहा गया कि सरकार विरोधी शक्तियों को कुचलने के लिये अधिकार प्राप्त करना चाहती है। कुछ समाचार-पत्रों के विचार में वह संसद, जो उस समय मौजूद थी, संविधान में किसी "आमूल" परिवर्तन करने के अधिकार से वंचित थी। इस मत के विरुद्ध अन्य समाचार-पत्रों ने जो मत व्यक्त किया, वह यह था कि इस परिसीमा (limitation) के अधीन, कि संविधान के किसी "मौलिक" अंश में बहुत जल्दी-जल्दी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये, संसद जनतंत्र की कोई सेवा नहीं करती है, यदि वह किसी वास्तविक आवश्यकता पड़ने पर भी, किन्हीं मिथ्याभिमान के विचारों (prudish considerations) से प्रेरित होकर संविधान में संशोधन नहीं करती। जब संविधान संशोधक बिल (Constitution Amendment Bill) पारित हो गया तो कुछ समाचार-पत्रों ने इसके विपरीत दिशा में बड़ी कड़ी आलोचना की तथा प्रधान मंत्री के विरुद्ध यह आरोप लगाया कि वे "तानाशाही के लिये अपना मार्ग साफ कर रहे हैं"।

भारत सरकार द्वारा पंजाब का प्रशासन अपने हाथ में ले लिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं की गई। सभी समाचार-पत्रों ने एकमत होकर यह मत व्यक्त किया कि देश की सुरक्षा के हित में यह अत्यन्त आवश्यक है कि पंजाब राज्य का प्रशासन जिसकी स्थिति सैनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ी कुशलता के साथ किया जाय। राजस्थान में जो मन्त्रिमंडल संबंधी जटिल समस्या उत्पन्न हो गई थी, उससे यह सदेह प्रकट किया जाने लगा कि सभी भूतपूर्व रियासतें जनतंत्र संबंधी प्रयोगों के लिये तैयार हैं। सभी समाचार-पत्र भाग 'सी' कुछ राज्यों को स्वायत्त-पद (autonomous status) प्रदान करने की आवश्यकता के संबंध में संतुष्ट नहीं थे। विशेष रूप से यह सुझाव पेश किया गया कि दिल्ली अभी कुछ दिन और केन्द्रीय सरकार के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में रहे। भारत सरकार ने बम्बई के महाराजा के विरुद्ध जो कार्यवाही की उसका साधारणतया सभी ने समर्थन किया। यह आशा प्रकट की गई कि इस कार्यवाही से ऐसे सभी राजाओं को चेतावनी मिल जायगी जिनमें कोई अनुचित आकांक्षाएँ पैदा हो गई हों। अधिकांश समाचार-पत्रों ने राजाओं के संघ (Rulers' Union) की कार्यवाहियों की जोरदार शब्दों में आलोचना की। मैसूर सरकार की भी इस बात पर कुछ आलोचना की गई कि उसने उस मुकद्दमे को, जिसे चीफ जस्टिस प्वाइजनिंग केस (Chief Justice Poisoning Case) कहते हैं, बम्बई की किसी अदालत में भेजने के संबंध में दिये गए राष्ट्रपति के आदेश को कार्यान्वित करने में हिचकिचाहट दिखाई।

गांधी जयन्ती दिवस तथा राष्ट्रपिता के निधन की तीसरी वर्षगांठ क्रमशः २ अक्टूबर और ३० जनवरी को मनाई गई। दोनों अवसरों पर समाचार-पत्रों ने महात्मा गांधी के प्रति अपनी सम्मानपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पित की और यह दोहराया कि महात्माजी ने भारत तथा विश्व

के लिये क्या क्या किया है तथा इस बात की याद दिलाई और इस पर जोर दिया कि उनकी महान् शिक्षाओं का कितना महत्व है।

स्वर्गीय ठक्कर बापा, जिनकी मृत्यु वर्ष के प्रारम्भ में हुई थी तथा आचार्य बिनोबा भावे, जिनका भूमिदान यन्त्र इस बात का प्रतीक समझा जाता था कि लोग सर्वोदय कार्यक्रम को पसंद करते हैं, के कार्यों की हार्दिक प्रशंसा की गई। डाक्टर कैलासनाथ काटजू के गृह-मंत्री नियुक्त होने पर यह मत प्रकट किया गया कि इससे वैयक्तिक योग्यता समुचित रूप से स्वीकार कर ली गई और प्रशासकीय योग्यताओं का सही चुनाव हुआ है। डाक्टर जान मथाई तथा डाक्टर अम्बडकर ने कांग्रेस के विरुद्ध जो आरोप लगाये, उनकी सभी ने आलोचना की। मध्य प्रदेश के श्री डी० पी० मिश्र को, जिन्होंने प्रधान मंत्री के विरुद्ध एक लम्बा निन्दात्मक वक्तव्य दिया था, उनके विचारों के लिये बहुत कम समर्थन मिला तथा उनकी शैली की बड़ी निन्दा की गई।

वर्ष के अन्त में निर्वाचन चर्चा का मुख्य विषय बन गया। जब बड़े बड़े राजनीतिक दल खूब जोर शोर के साथ अपना प्रचार कार्य कर रहे थे, साधारणतया सभी समाचार-पत्र यह विश्वास करने को तैयार नहीं थे कि मतदाता (voter) उसी हद तक अनभिज्ञ हैं जितना कि वह अशिक्षित हैं। बहुत से समाचार-पत्रों को यह बात निश्चित सी प्रतीत होती थी कि कांग्रेस को निर्वाचन में बड़ी भारी सफलता मिलेगी, विशेषकर इन रिपोर्टों के आने के बाद कि सभी जगह श्री नेहरू को सुनने के लिये लोग बड़ी भारी सख्या में जमा हो रहे हैं। राजाओं के निर्वाचन में सम्मिलित होने का साधारणतया सभी ने स्वागत किया, किन्तु इस बात पर बड़ा जोर दिया गया कि उन्हें अन्य नागरिकों की तरह निर्वाचनों में लड़ना चाहिए, न कि उनसे पृथक् किसी वर्ग के रूप में। इस संबंध में कई समाचार-पत्रों ने सरकार से यह अनुरोध किया कि वह राजाओं के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दे।

सभी समाचार पत्रों को उस समय बड़ा हर्ष हुआ जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के सबंध में अपना निर्णय दिया तथा उसे एक वैधानिक विधान घोषित कर दिया। यह समझते हुये कि यह अधिनियम उन सभी प्रगतिशील कानूनों में, जिन्हे उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया था, सबसे अधिक प्रगतिशील कानून था, राज्य के नेताओं की, विशेषकर उसके मुख्य मंत्री की, जिन्होंने उसे विभिन्न मंजिलों (stages) से सफलतापूर्वक पारित करवाया था, सराहना की गई। जमींदारों के प्रति बहुत ही कम सहानुभूति प्रकट की गई। इन जमींदारों में से कुछ तो ऐसे थे जो अवश्यम्भावी स्थिति स्वीकार करने (inevitable) में हिचकिचा रहे थे तथा जिन्होंने एक ऐसे प्रयोजन के लिए आन्दोलन जारी रखा जिसे वे पहिले ही खो चुके थे। राज्य के बजट को सभी ने एक ऐसा सन्तुलित बजट बताया जिसमें जनता की आवश्यकताओं के प्रति जागृत होने की झलक मिलती थी। शिक्षा पर किये जाने वाले व्यय की वृद्धि, विकास-संबंधी योजनाओं की प्रगति तथा बजट में किसी नये कर के लगाये जाने के प्रस्तावों के न होने की विशेषरूप से सराहना की गई।

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के संबंध में प्रायः पूरे वर्ष काश्मीर का प्रश्न समाचार-पत्रों का मुख्य विषय बना रहा। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो झगडा था उसमें कोई समझौता होने की बहुत ही कम आशा थी, और बार बार यह सुझाव पेश किया गया कि सुरक्षा-परिषद् से काश्मीर का मामला बायस ले लिया जाय। यह प्रस्ताव कि काश्मीर में राष्ट्रमंडल (Commonwealth) की सेनाएँ रखी जाय बड़ी घृणा की दृष्टि से देखा गया तथा उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य का हार्दिक स्वागत किया गया कि काश्मीर पर किये गये किसी भी आक्रमण को भारत पर किया गया आक्रमण माना जायगा तथा कुछ समाचार-पत्रों ने यह आशा प्रकट की कि इस वक्तव्य का पाकिस्तान के शासकों के धमकी देने के रवैये पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ब्रिटन तथा अमेरिका के उन प्रस्तावों की बड़ी कटु आलोचना की गई जिनमें यह कहा गया कि काश्मीर के प्रश्न में समझौते के लिये मध्यस्थ निर्णय (arbitration)

एक सिद्धान्त के रूप में स्वीकार कर लिया जाय। समाचार-पत्रों की एक बहुत बड़ी संख्या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकार पर यह आरोप लगा रही थी कि वह ऐसा किन्हीं प्रेरणाओं (motives) से प्रेरित होकर कर रही है और यह अनुभव किया गया कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकार पाकिस्तान का काश्मीर पर कब्जा हो जाने में अपने ही हितों की बड़ती देख रही है।

जब डाक्टर फैंक ग्राहम राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि के रूप में इस उप-महाद्वीप (sub-continent) में आये तो बहुत से समाचार-पत्रों ने यह मत प्रकट किया कि काश्मीर की समस्या पर उस समय तक कोई समझौता नहीं हो सकेगा जब तक यह नहीं मान लिया जाता कि पाकिस्तान आक्रमणकारी रहा है तथा ऐसे राज्य-क्षेत्रों को जिन पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है जम्मू तथा काश्मीर की वैध हथ से स्थापित सरकार को वापस नहीं कर दिया जाता। काश्मीर राज्य की संविधान सभा (Constituent Assembly) के निर्वाचन से शेख अब्दुल्ला के राष्ट्रीय सम्मेलन की बड़ी भारी लोकप्रियता का स्पष्टतया पता चल गया और यह अनुभव किया गया कि केवल इसी बात से डाक्टर ग्राहम को संतोष हो जाना चाहिये था कि काश्मीर की जनता ने दो-राष्ट्र संबंधी उस सिद्धान्त को बिल्कुल ही नहीं माना है जिसके आधार पर पाकिस्तान का रख निर्भर था। इस बात का सबूत, यदि किसी सबूत की आवश्यकता थी, कि काश्मीर के मामले पर सभी भारतीय मुसलमान भारत सरकार के साथ हैं, उस स्मरण-पत्र द्वारा मिल गया, जिसे भारतीय मुसलमानों ने डाक्टर ग्राहम को दिया। यह बात बड़े जोरदार शब्दों में व्यक्त की गई कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधि इस स्मरण-पत्र की इस आधार पर कोई उपेक्षा नहीं कर सकता था कि उसका काश्मीर के प्रश्न के साथ कोई संबंध नहीं था। वर्ष के अंत में कुछ समाचार-पत्रों ने यह सुझाव पेश किया कि शायद काश्मीर का झगड़ा मंत्रीपूर्ण ढंग से हल हो जाय, यदि उसे पूर्णरूप से भारत और पाकिस्तान पर ही छोड़ दिया जाय। किन्तु सभी समाचार पत्र एकमत होकर काश्मीर राज्य में उसके सीमा-प्रदेशों (Frontiers) की सुरक्षा के लिये यथेष्ट सैनिक रखने की महत्ता पर जोर दे रहे थे।

भारत-पाकिस्तान व्यापार समझौते पर विभिन्न मत प्रकट किये गये। जहाँ कुछ समाचार-पत्रों ने इस पर संतोष की भावना व्यक्त की तथा यह आशा प्रकट की कि इस समझौते से दोनों देशों के मध्य आर्थिक संबंध और अधिक अच्छे हो जायेंगे, अन्य समाचार-पत्र इसके लिये अधिक चिन्तित थे कि पाकिस्तानी रुपये के अवमूल्यन से पूर्व की दर स्वीकार कर ली जाय। कुछ समाचार-पत्रों को यह आशका हुई कि कहीं इस समझौते के कारण भारत में कीमत न बढ़ जाय। निष्क्रान्त सम्पत्ति के प्रश्न के संबंध में इस बात में कोई संदेह नहीं था कि केवल दोनों सरकारों के बीच समझौते के आधार (Govt. to Govt. basis) पर ही उसका हल संभव है। पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं की दुर्दशा का बार-बार उल्लेख किया गया और कुछ समाचार-पत्रों को विवश होकर यह कहना पड़ा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य उस समय तक सच्ची मित्रता होने की कोई सम्भावना नहीं है जब तक कि पूर्वी बंगाल की सरकार अपने राज्य में गैर-मुस्लिम व्यक्तियों के प्रति अपनी नीति बदलने से इंकार करती है। भारत के विरुद्ध पाकिस्तान का लगातार प्रचार, जो उस समय अपनी चरम सीमा को पहुँच गया जब श्री लियाकत अली ख़ाँ ने अपने देश को “तना हुआ घुँसा” एक राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर दिया, हृदय पर आघात पहुँचाने वाला होने के साथ-साथ उत्तेजनात्मक भी था। किन्तु उत्तर प्रदेश में साधारणतया सभी समाचार-पत्र शान्तपूर्ण बने रहे और यद्यपि उन्होंने जुलाई के महीने में प्रधान मंत्री की इस घोषणा का स्वागत किया कि भारत के सीमा-प्रदेशों की सुरक्षा के प्रबन्ध और सुदृढ़ बनाये जायेंगे, तो भी जब अक्टूबर में रावलपिंडी की एक सार्वजनिक सभा में श्री लियाकत अली ख़ाँ अपने ही एक देशवासी द्वारा गोली से मार डाले गये, तो उन्होंने स्वेच्छा से पाकिस्तान के प्रति

खेद तथा सहानुभूति प्रकट की। सुरक्षा परिषद् में पाकिस्तान का निर्वाचित होना कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना नहीं समझी गई, यद्यपि कुछ समाचार-पत्रों ने यह अवश्य अनुभव किया कि इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ ने पाकिस्तान को उसके आक्रमण के लिए क्षमा कर दिया।

जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रेसीडेंट ने जनरल मैकआर्थर को कोरिया तथा जापान के कमान से हटा दिया तो इस पर कोई खेद नहीं प्रकट किया गया। कुछ समय तक यह प्रतीत होता था कि दूसरे विश्व युद्ध के होने का डर पूर्णतः दूर हो गया है और कुछ समाचार-पत्रों ने यह आशा प्रकट की कि जनरल मैकआर्थर के हटाए जाने के बाद संयुक्त राज्य संघ के प्रति चीन का रुख भी पहिले से बेहतर हो जायेगा। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया आशा की भावना पुनः निराशा में परिणत हो गई और उस समय भी जब केसांग (Kaesong) में सन्धि-वार्ताये चल रही थीं बहुत थोड़े ही समाचार-पत्र यह विश्वास करने के लिये तैयार थे कि कोरिया में फिर शान्ति स्थापित हो जायगी। वास्तव में समाचार-पत्रों को यह प्रतीत होता था कि कोरिया में लड़ाई बन्द होने के प्रश्न का संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा साम्यवादी चीन को सान्ध्यता प्रदान करने के प्रश्न से बहुत ही निकट संबध है तथा बहुत से समाचार-पत्रों ने खेद प्रकट किया कि इस संबध में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की नीति राष्ट्र-मंडल (Commonwealth) के देशों की नीति से भिन्न होती जा रही है।

किसी भी समाचार-पत्र ने संयुक्त राष्ट्र संघ की उस कार्यवाही का, जिससे उसने कोरिया में चीन को एक आक्रमणकारी (aggressor) घोषित कर दिया था, समर्थन नहीं किया। इसके विपरीत अधिकांश समाचार पत्र यह समझते थे कि इस विषय पर जनरल असेम्बली का प्रस्ताव अवैध, अन्यायपूर्ण तथा अनुचित था, और यह कि उसने न केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की मर्यादा ही कम कर दी है बल्कि उसने चीन को भी और अधिक हठी बना दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उस प्रस्ताव की, जिसके द्वारा चीन के विरुद्ध अवरोध (blockade) लगाया गया था, उतने ही ज़ोरदार शब्दों में निन्दा की गई, जितनी कि चीन को आक्रमणकारी घोषित करने के प्रस्ताव की की गई थी।

बहुत थोड़े ही समाचार-पत्र यह विश्वास करने के लिये तैयार थे कि जो निःशस्त्रीकरण कमिशन (Disarmament Commission) वर्ष के अंत में स्थापित किया गया था उसे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। उनके विचार से कमिशन से बहुत अधिक आशा करना, विशेषकर ऐसे समय जब कि बड़े-बड़े राष्ट्र अपनी युद्धसामग्री के उत्पादन को बड़ी शीघ्रता के साथ बढ़ा रहे थे, एक हास्यास्पद बात थी। जापान की शान्ति-सन्धि के संबंध में, जिस पर वर्ष के दौरान में सानफ्रान्सिस्को में हस्ताक्षर कर दिये गए थे, सभी समाचार-पत्रों ने भारत सरकार के रुख का समर्थन किया। यह अनुभव किया गया कि सानफ्रान्सिस्को सम्मेलन में रूस, चीन और भारत के भाग न लेने के कारण उक्त सन्धि का बहुत महत्व कम हो गया था तथा इस बात की कोई भी संभावना नहीं थी कि उससे विश्व शान्ति की स्थापना में कोई सहायता मिले। सिख और ईरान की जनता के सामने जो कठिन स्थिति थी उस पर उनके प्रति सभी न सहानुभूति प्रकट की। कुछ समाचार-पत्रों ने यह सुझाव पेश किया कि पश्चिमी शक्तियाँ (Western Powers) एक मध्य पूर्वी कमान (Middle East Command) स्थापित करने की अपनी योजना उस समय तक के लिये स्थगित कर दे जब तक कि उस क्षेत्र का वातावरण शान्तपूर्ण नहीं हो जाता। अधिकांश समाचार-पत्रों को यह प्रतीत होता था कि ब्रिटेन द्वारा ब्रिटेन तथा ईरान के तेल संबंधी विवाद को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) के समक्ष ले जाने के परिणामस्वरूप ईरान की स्थिति और भी अधिक

कटिल हो गई थी। ब्रिटेन से कहा गया कि वह यह बात अनुभव करे कि यदि उसने ईरान में सैनिक शक्ति का प्रयोग किया तो संभवतः रूस हाथ पर हाथ धरे न बैठा रहे और सारे मध्य-पूर्व में युद्ध की आग भभक उठे।

भारत सरकार की वैदेशिक नीति की, विशेषकर कोरिया और चीन से संबंधित नीति की साधारणतया सभी ने सराहना की। इस नीति की अमेरिका में जो आलोचना की गई, उसे उस राज्य के समाचार-पत्रों ने अन्यायपूर्ण बताया। इन समाचार-पत्रों को ऐसा प्रतीत होता था कि अमेरिका के आलोचक भारतीय परिस्थितियों, परम्पराओं तथा प्रेरणाओं को समझ नहीं पा रहे हैं। समाचार-पत्रों ने जोरदार शब्दों में यह बात व्यक्त की कि यद्यपि भारत भी शान्ति और सुरक्षा में दिलचस्पी रखता है तो भी वह कुछ सिद्धान्तों के खिलाफ केवल पूर्वद्वेष (prejudice) के आधार पर नहीं लड़ सकता है। थोड़े ही समाचार-पत्रों ने भारत के राष्ट्र-मंडल (Commonwealth) से मिले रहने पर आपत्ति की। ब्रिटेन में सरकार के बदल जाने के संबंध में साधारणतया सभी ने यह अनुभव किया कि अनुसार सरकार संभवतः कोई ऐसा कार्य नहीं करेगी जिससे भारत के साथ, जो उसके संबंध है, उन पर बुरा प्रभाव पड़े। जिस ढंग से चीनी लोगो ने वह कार्यवाही की, जिसे वे तिब्बत की “शान्तिपूर्ण मुक्ति (peaceful liberation)” के नाम से पुकारते हैं, उसे बहुत से समाचार-पत्रों ने पसंद नहीं किया। किन्तु अन्य समाचार-पत्रों ने यह अनुभव किया कि यद्यपि यह आवश्यक था कि सीमा-प्रदेश (बार्डर) पर सख्त निगरानी रखी जाय तथा नेपाल में राजनीतिक स्थिरता स्थापित करने में सहायता पहुंचाई जाय, तथापि इस बात का कोई कारण नहीं था कि भारत इस बात से बहुत अधिक घबड़ा जाय।

समय समय पर इस बात पर जोर दिया गया कि भारत और नेपाल एक दूसरे पर निर्भर हैं। आम तौर पर यह विश्वास किया जाता था कि नेपाली कांग्रेस तथा रानाओं के मध्य कोई स्थायी समझौता नहीं हो सकता था। नेपाल में नवम्बर के महीने में श्री एम० पी० कोइराला के अधीन जो एक नया मंत्रिमंडल बना उसका हादिक स्वागत किया गया और इस घटना को एक बहुत काफ़ी ऐतिहासिक महत्व रखने वाली घटना समझा गया।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों तथा अन्य अश्वेत जातियों के प्रति जो व्यवहार किया गया उसकी कई अवसरों पर निन्दा की गई। समाचार-पत्रों को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर मैलान जिस नीति का अनुसरण कर रहे थे उसके भयंकर परिणामों को पश्चिमी शक्तियाँ अनुभव नहीं कर सकी। कुछ समाचार-पत्रों ने लंका की सरकार द्वारा बरती गई “सीलोनोकरण” की कार्यवाही की यह कहकर निन्दा की कि वह न्याय के सभी नियमों के विपरीत है। चन्द्रनगर की जनता को फ्रान्सीसी शासन से स्वतंत्रता पाने पर बधाई दी गई। किन्तु समाचार-पत्रों ने इस बात पर क्रोध प्रकट किया कि फ्रान्स तथा पुर्तगाल भारत के कुछ भागों पर अभी भी अपना कब्जा जमाए हुए थे। कई समाचार-पत्रों ने पेरिस और लिसबन की सरकारों को यह चेतावनी दी कि उपनिवेशवाद के दिन अब समाप्त हो गए हैं और यह कि भारत, जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से छुटकारा पा लिया है, न तो फ्रान्सीसी तथा पुर्तगाली साम्राज्यवाद को सहन कर सकता था और न अब आग करेगा।

४—विधान मंडल

इस वर्ष विधान मंडल में महत्वपूर्ण कार्यवाहियाँ हुईं। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५१ ई० का पहला

अधिनियम बन गया और सामाजिक महत्व के अन्य विधयक अर्थात् यू० पी० चिल्ड्रेन्स बिल को विधान मंडल ने पारित कर दिया। इस वर्ष जो अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम बनने वे उत्तर प्रदेश राजकीय पथ-परिवहन अधिनियम, १९५० ई०, उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि अधिनियम, १९५० ई०, उत्तर प्रदेश विधान मंडल के सदस्यों का अर्हता-निवारण अधिनियम, १९५१ ई०, उत्तर प्रदेश टिड्डो विनाश अधिनियम, १९५१ ई०, उत्तर प्रदेश जरे चहाइम उत्पादन अधिनियम, १९५१ ई० तथा दूधी राबर्सगंज (जिला मिर्जापुर) कृषक ऋण उद्धार अधिनियम, १९५१ ई० थे। कुल ३४ अधिनियम बने।

आम चुनावों के लिये तैयारी में मेम्बरों के व्यस्त होने के कारण उत्तर प्रदेश विधान मंडल की बैठके पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष कम दिनों तक हुईं। पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश विधान सभा तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की क्रमशः १३८ तथा ६० बैठके हुईं, जबकि १९५१ ई० में विधान सभा की ६३ और विधान परिषद् की ३८ बैठके हुईं। विधान परिषद् का सत्रावसान केवल एक बार हुआ।

उस समय जबकि विधान मंडल के सत्र नहीं हो रहे थे, राज्यपाल महोदय ने चार अध्यादेश जारी किये, जिनका स्थान बाद में अधिनियमों ने ले लिया।

आलोच्य वर्ष में केवल एक सरकारी प्रस्ताव, जिसके द्वारा संग्रथित संपत्ति के संबंध में निष्क्रान्तों के स्वत्व को ऐसे लोगों के स्वत्वों से, जो निष्क्रान्त नहीं हैं, पृथक् करने के प्रश्न पर इस राज्य की ओर से संघ संसद् को कानून बनाने के लिये अधिकृत किया गया था, राज्य के विधान मंडल ने पारित किया। दोनों सदनो में से किसी ने भी कोई गैर-सरकारी प्रस्ताव पारित नहीं किया। माननीय मुख्य मन्त्री के प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश विधान सभा ने राज्य की खाली स्थिति पर २३ अगस्त, १९५१ ई० को विचार किया।

विधान सभा में ७ रिक्त स्थान थे और विधान परिषद् में एक रिक्त स्थान था। विधान सभा के केवल एक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये एक उपनिर्वाचन हुआ। इस विचार से कि आम चुनाव कुछ दिनों बाद होने ही वाले हैं, निर्वाचन कमीशन के परामर्श से यह निश्चय किया गया कि शेष रिक्त स्थानों की पूर्ति न की जाय और उन्हें योही रहने दिया जाय।

५—निर्वाचन

आलोच्य वर्ष के पहिले भाग में निर्वाचन सूचियों का संशोधन कार्य हो रहा था। निर्वाचन सूचियों के सम्बन्ध में दावे और आपत्तियाँ दायर करने की अवधि ३१ मार्च, १९५१ ई० तक कर दी गई, किन्तु सामान्य जनता इसमें पर्याप्त दिलचस्पी नहीं ले रही थी। दावे और आपत्तियों के मुकदमों जो दायर किये गये उनकी संख्या ४४,००० थी। निर्वाचन सूची में निर्वाचकों की संख्या ३१४ लाख थी। कई मामलों में, जैसा कि बाद में ज्ञात हुआ, उन लोगों ने भी, जो चुनाव के लिये भावी उम्मीदवार थे, अपनी निर्वाचन सूची

की जांच करने की ओर ध्यान उस समय नहीं दिया जब दावे और आपत्तियों के दायर करने का समय था कि उनके नाम निर्वाचन सूची में हैं या नहीं। जनता ने निर्वाचन सूची के सम्बन्ध में जो लापरवाही दिखाई उसने उसकी गलतियों और भूलों को सुधारने में बड़ी कठिनाई हुई। इतलिये सशोधक प्राधिकारियों के पास मूल निर्वाचन सूची में छूटे हुए नामों को सम्मिलित करने के लिये दरखास्त देने में निर्वाचन पंजीयन पदाधिकारी के अधिकारों का उदारतापूर्वक उपयोग किया गया। दाव और आपत्तियों के कारण निर्वाचकों की संख्या में कुल वृद्धि ३,६४,००० हुई। केवल कुछ को छोड़कर सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचन सूची अन्तिम रूप से अक्टूबर, १९५१ ई० के पहले पखवारे में प्रकाशित हुई। शेष निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचन सूची का प्रकाशन विलम्ब से हुआ, क्योंकि निर्वाचन सशोधक आज्ञा, १९५१ ई० का उन पर प्रभाव पड़ा। उनसे सम्बन्धित निर्वाचन सूची भी अन्तिम रूप से १ नवम्बर, १९५१ ई० को या उसके करीब प्रकाशित हुई। इसके बाद निर्वाचन सूची जनता में बिक्री के लिये उपलब्ध थी।

लोक सभा तथा राज्य की विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की आज्ञा राष्ट्रपति द्वारा मई, १९५१ ई० में जारी की गई और उसके बाद जल्दी ही सघ ससद के सामने रखी गयी। इस आज्ञा में ससद द्वारा कुछ सशोधन किये गये और जून, १९५१ ई० में उरहा अन्तिम रूप दे दिया गया। उत्तर प्रदेश लोक सभा के लिये ६६ प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों तथा राज्य की विधान सभा के लिये ३४१ निर्वाचन-क्षेत्रों में बांटा गया। प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में से ५२ एक सदस्य के क्षेत्र थे तथा शेष १७ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ से दो सदस्य चुने जाते हैं। विधान सभा के निर्वाचन-क्षेत्रों में से २६४ एक सदस्य के क्षेत्र थे और ८३ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ से दो सदस्य चुने जाते हैं। प्रत्येक दो सदस्यों के निर्वाचन-क्षेत्र में एक स्थान अनुसूचित जाति के सदस्य के लिये सुरक्षित था। चूँकि लोक सभा की एक जगह के लिये राज्य की विधान सभा में ५ जगहें थीं पुनर्विभाजन-निर्धारण इस प्रकार किया गया कि एक या दो सदस्यों के निर्वाचन-क्षेत्र विधान सभा के उतने ही सदस्यों के लिये क्षेत्र बन जाय। केन्द्रीय सरकार ने इसके बाद निर्वाचन नियम बनाये, जिनको जल्द ही अन्तिम रूप दिया जाने वाला था।

सितम्बर के बाद निर्वाचन कार्य बढ़ता गया। मुख्य चुन व अधिकारी को सहायता देने के लिये ५ प्रादेशिक निर्वाचन अधिकारी और एक सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किये गये। प्रादेशिक निर्वाचन अधिकारियों लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ, बनारस और हलद्वानी में थे। जिलों में निर्वाचन सम्बन्धी प्रबन्ध जिला अधिकारियों के अधीन थे, जो जिन्होंने अक्सर डिप्टी कलेक्टर या उसी के बराबर के पद के अधिकारियों को जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया और चुनाव के प्रबन्ध का इन्चार्ज बना दिया।

ग्रौठ मतदातार के आधार पर होने वाला यह पहला निर्वाचन था, इस कारण मतदान स्थानों (Polling Stations) के नियत करने में बड़ी कठिनाई थी। चूँकि निर्वाचन विधि के अधीन मतदाताओं को सवारी देना भ्रष्टाचार (corrupt practice) था इस कारण मतदान स्थान ऐसे स्थान पर नियत करना आवश्यक था जहाँ निर्वाचक सुगमता से पहुँच जायें। हर प्रकार से प्रयत्न किया गया कि किसी निर्वाचक को तीन मील से अधिक न चलना पड़े, किन्तु कुछ स्थानों पर भौगोलिक तथा अन्य कारणों से ऐसे नियम का कठोरता से पालन करना कठिन था। मतदान स्थानों की कुल संख्या १०,००० से

के प्रारम्भ में जोर शोर के साथ की जा रही थी, मन्दी हो गई। सूत का वितरण इस प्रकार आयोजित किया गया जिससे प्राप्य सप्लाई का अधिक परिमाण जुलहों को दिया जा सके।

लोहे और इस्पात और सीमेंट पर नियन्त्रण जारी रहा, किन्तु कोयले के चूरे की सप्लाई में उल्लेखनीय सुधार हो जाने से ईंटों पर से नियन्त्रण हटा दिया गया। दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद हालत बिगड़ गयी, यद्यपि यह आशा की जाती थी कि अन्त में स्थिति ठीक हो जायगी।

इस राज्य में लोहा और इस्पात कुल ४६,८०६ टन प्राप्त हुआ, जब कि कुल ५२,५५२ टन मिलना निश्चिन्त हुआ था। कुल २,४१,२३८ टन सीमेंट मिला, जबकि कुल २,६४,००० टन मिलने को था। कोयले की खानों से इस राज्य के लिये कुल १३,४६४ भरे हुए बैगन भेजे गये, जब कि ३०,१४४ भरपूर बगन भेजना नियत किया गया था।

अन्न और सूत के अतिरिक्त नमक, मिट्टी का तेल, जलाने की लकड़ी, औषधियां और सामान्य उपभोग की सामग्री पर नियन्त्रण रहा। यातायात के साधनों में कमी और माल को चढाने-उतारने के स्थान पर कठिनाइयों के साथ-साथ नमक पर भी नियन्त्रण रखना आवश्यक हो गया था। १९५१ ई० के पूर्वार्द्ध में विशेषतः राजपूताना के नमक के उद्गमों से माल भेजने में कमी पाई गयी और परिणामस्वरूप राज्य के काफी बड़े भाग में, विशेषकर उज्जैन जिले में जहाँ छोटी लाइन जाती है, नमक की भारी कमी हो गयी। इस कमी को विशेष गाड़ियों (रेक) को चलाकर पूरा किया गया। वर्ष के उत्तरार्द्ध में साँभर नमक के उद्गम में उत्पादन की कमी हो जाने से कठिनाइयाँ पैदा हुयी, तथापि सब प्रकार से सप्लाई का संतोषजनक प्रबन्ध किया गया और उपभोक्ताओं को नमक सस्ते दामों पर प्राप्त हुआ।

मिट्टी के तेल के सम्बन्ध में सप्लाई में सुधार हो जाने से, जो कि १९५० ई० के उत्तरार्द्ध में हुई थी, यह आशा की जाती थी कि नियन्त्रण में अन्ततः ढिलाई हो जायगी, किन्तु इसमें शिथिलता आ गयी और यह बात अधिकतर ईरान की होन वाली घटनाओं के कारण हो गयी थी। कई महीनों तक मिट्टी के तेल की कमी रही और खास कर बुन्दलखण्ड और घाघरा पार के प्रदेशों में। वर्ष के समाप्त होत समय इस स्थिति में कुछ सुधार होने लग गया था। उपभोक्ताओं को जलाने की लकड़ी सप्लाई करने का प्रबन्ध करने की समस्या स्टाक प्राप्ति में एकाएक कमी आ जाने से कठिन हो गई। १९५१-५२ ई० में अनुमानित स्टाक गिरकर ५५ लाख मन रह गया, जबकि पिछले वर्ष ८० लाख मन प्राप्त हुआ था। निजी जमींदारी जगहों को काटन में प्रतिबन्ध लगाने के फलस्वरूप नियंत्रित वन डिब्बेजनों से समस्त श्रेणों के उपभोक्ताओं ने जो मांग की उनमें वृद्धि हो गई। शक्कर के कारखानों से सबसे अधिक मांग हुई। प्राप्य सप्लाई के वितरण का आयोजन करने में सावधानी बरती गई और इस आयोजन के साथ-साथ जलाने के कोयले की सप्लाई का प्रबन्ध करके घरेलू कामों के लिए जलाने का कोयला नागरिक क्षेत्रों में सस्ते दामों पर उपलब्ध किया गया।

औषधियों और उपभोग के चुने हुए सामानों पर नियन्त्रण इस प्रकार किया गया जिससे भारत सरकार द्वारा उच्चतम निर्णीत मूल्य लागू किये जा सके। यह नियन्त्रण थोड़ा बहुत भी मालूम नहीं पड़ता था, किन्तु एक नियोजित और निर्धारित सीमा से ऊपर इन चीजों के मूल्य बढ़ने पर रोक रखने में इससे मदद मिलती थी।

नगरों में निवास-स्थान प्राप्ति संबंधी स्थिति अभी असन्तोषजनक रही और यू० पी० टम्पोरेरी कंट्रोल आफ रेंट एण्ड इविकशन ऐक्ट का पूर्ण प्रभाव, जिसके अनुसार १ जनवरी, १९५१ ई० के पश्चात् निर्मित मकानों को उक्त ऐक्ट के प्रतिबन्धों से इसलिए उन्मुक्त किया गया जिससे नये मकान बनाने में प्रोत्साहन मिलता रहे, अभी भी पूरी तरह व्यक्त होना बाकी रह गया था। इसी बीच छावनी में कई किरायेदारों को निकालने की सख्या में वृद्धि हो जाने से कठिन स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि नये विधान के अधीन यह एक केन्द्रीय विषय था और इस पर किराया और किरायेदारों की निकाल देने के संबंध में विनियम लागू नहीं होते हैं। तथापि राज्य सरकार के कहने पर भारत सरकार ने उसी विधान के आधारों पर यू० पी० कैंन्टनमेंट (कंट्रोल आफ रेंट एण्ड इविकशन) ऐक्ट बनाया, जिस पर कि राज्य के अन्य नागरिक क्षेत्रों में किराया और किरायेदारों को निकालने के नियम नियंत्रित किये जाते हैं।

आलोच्य वर्ष में नियंत्रण आदेश भंग करने के कई मामले निपटाये गये। इनमें से ३,६५३ मामले में सजाये हुई। इनफोर्समेंट स्क्वाड न विभिन्न नियंत्रण आदेशों को भंग करने के मामलों का पता लगाया, १,६५७ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और लगभग ५,३६,५६६ रु० की कीमत की वस्तुएं अपने कब्जे में की। बदनामी, भ्रष्टाचार इत्यादि के कारण १५६ सरकारी नौकर बर्खास्त या अलग किये गये और ३२ सरकारी नौकरों को अन्य प्रकार की सजाये दी गई। ४ अन्य सरकारी नौकरों ने त्यागपत्र दिये।

दिसम्बर, १९५० ई० में सरकार ने जिस कमेटी को नियंत्रण प्रशासन प्रणाली को मितःस्थयी और अच्छा बनाने के लिए कुछ युक्तियां निकालने के लिए नियुक्त किया था उसने सूती कपड़े के वितरण और अन्न वसूली के संबंध में अन्तस्मि सिफारिशें की। तथापि यह कमेटी १९५१ ई० के बाद इसलिए काम न कर सकी कि इसके कुछ सदस्य नये विधान के अधीन प्रथम आम चुनावों से संबंधित कार्यों में लगे रहे।

१—श्रम की स्थिति

श्रम की स्थिति में बड़ी हड़ताल या औद्योगिक झगड़ों के कारण कोई विशेष बात नहीं हुई। शक्कर के उद्योग में १९५१ ई० के प्रारम्भ में एक बड़ी हड़ताल संगठित की गई, किन्तु सरकार ने उस पर तुरन्त कार्रवाई की, इसका परिणाम यह हुआ कि हड़ताल प्रारम्भ होने के एक सप्ताह के भीतर यह हड़ताल समाप्त हो गयी और कारखाने काम करने लगे। ८१ बार कारखाने बन्द रहे और ७७१ बैठकियां हुईं, जिनके कारण क्रमशः ८,५४६ तथा १,३७,४५५ मजदूर बेकार हो गये। छटनी के कारण २,५७३ मजदूर काम से हटा दिये गये। इस वर्ष कुल १०५ हड़तालें हुईं, जिनमें ७४,४६२ मजदूरों ने भाग लिया और कुल ३,०५,७६२ काम के दिनों का हर्ज हुआ, जब कि पिछले वर्ष ६१ हड़तालों हुई थी और ४६,७६२ मजदूरों ने भाग लिया था और २,३२,४५० काम के दिनों का हर्ज हुआ था। कारखानों की बंदी, तालाबन्दी, छटनी, बैठकी और हड़ताल मुख्य रूप से कच्चे माल की कमी, तयार सामान का इकट्ठा होना, वित्तीय कठिनाइयों, स्थिरयन्त्रों के टूटने या अन्य कारणों से हुई। तेल की मिलें, तैयार किये गये माल के इकट्ठा होने तथा कच्चे माल की सप्लाई में कमी के कारण बन्द रहीं।

८—सहायता तथा पुनर्वास

विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वासन कार्य की राज्य की सरकार बराबर बढ़ा महत्व देती रही। १० अप्रैल, १९४८ ई० के पहिले आये हुये व्यक्तियों तथा

ऐसे व्यक्तियों, जिनके मामले नियमानुसूल थे और ऐसे भी व्यक्तियों, जिनके मामले शोचनीय थे, को रजिस्टरी की अनुमति दी गई।

जुलाई, १९५१ ई० में भारत सरकार ने शिक्षा संबंधी रियायतें देने की योजना में और संशोधन कर दिया। संशोधित योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा मुक्त देना जारी रहा, किन्तु नकद अनुदान केवल ५० प्रतिशत विद्यार्थियों को देने की व्यवस्था थी, बशर्ते कि उनके माता-पिता या अभिभावक की आय १०० रु० प्रति मास से अधिक न हो। छठी से द्वावी कक्षा के ५० प्रतिशत और द्वावी तथा १०वी कक्षा के ४० प्रतिशत विद्यार्थियों की फीस माफ की जा सकती थी और उन्हें नकद अनुदान मिल सकता था, बशर्ते कि उनके माता-पिता की आय एक निर्धारित सीमा से अधिक न हो, जो द्वावी से द्वावी कक्षा के विद्यार्थियों के सबध में १०० रु० मासिक और द्वावी तथा १०वी कक्षा के विद्यार्थियों के सबध में १५० रु० मासिक थी। हाई स्कूल के ऊपर के विद्यार्थियों को छात्र-वेतन देने में और अधिक उदारता दिखाई गई। १९५१-५२ के शैक्षिक वर्ष में २१,११६ विद्यार्थियों की फीस माफ की गई, २५,१३१ विद्यार्थियों को नकद अनुदान दिये गये तथा ४२६ विद्यार्थियों को छात्रवेतन दिये गये। अनुमान है कि इस सिमिले में कुल ११,१५,०३२ रु० का व्यय हुआ। १४ विद्यार्थियों को १८,६३० रु० तक के ऋण भी दिये गये।

विविन्न केन्द्रों में विस्थापित व्यक्तियों को व्यावसायिक और औद्योगिक ट्रेनिंग की सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था की गई। फेक्टरियों और कारखानों से ५०० अपरेंटिसों को ट्रेनिंग देने के प्रबन्ध के अतिरिक्त वर्ष के भरत गोश्रम मंत्रालय के केन्द्रों में ५९९ सीटें, कुटीर उद्योग के संचालक केन्द्र की शिबिरों और नयी उपनगरों में १,५०० सीटें (५०० छात्र-वेतन पानेवाले, २०० बिना छात्र-वेतन पाने वाले और ८०० उत्पादन कार्यकर्ता), जापानी मशीनरी ट्रेनिंग सेंटर, लखनऊ में २०० सीटें और रामपुर ट्रेनिंग तथा उत्पादन केन्द्र में १५० सीटें थीं।

कुटीर उद्योगों के डाइरेक्टर के केन्द्रों से ट्रेनिंग पाने वालों को छात्र-वेतन देने की योजना चालू की गई और भारत सरकार ने १०० राज और मिस्त्रियों को ट्रेनिंग देने के लिए एक अन्य योजना स्वीकृत की।

ऋण, नियंत्रित वस्तुओं का कोटा, बिजली इत्यादि देकर विस्थापित व्यक्तियों को व्यवसाय, वाणिज्य और व्यापार में पुनर्वासित करने में सुविधा हुई। आलोच्य वर्ष के अन्त तक १७,५०० विस्थापित परिवारों को व्यवसाय, वाणिज्य, व्यापार और उद्योग में फिर से लगाने के लिए १,१४,५५,००२ रुपये की धनराशि ऋण के रूप में दी गई और २,८९७ परिवारों को कृषि में पुनर्वासित करने के हेतु ३७,९७,९४० रुपये दिये गये। पुनर्वास वित्तीय प्रशासन ने ७२३ पार्टियों को ७४,३२,९०० रु० की धनराशि ऋण के रूप में दी।

विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए गोबिन्दपुरी, नंदा और हस्तिनापुर के तीन उपनगरों के विकास कार्यक्रम में सन्तोषजनक प्रगति रही। वर्ष के अन्त में कई कारखानों इत्यादि का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था। कुछ का निर्माण कार्य हो रहा था। यह आशा की जाती थी कि हस्तिनापुर के उपनगर में २,००० विस्थापित परिवारों के रहने की व्यवस्था हो जायगी, जिनमें से १,००० परिवार भी सम्मिलित हैं जिन्हें भारत सरकार इस राज्य के बाहर से यहां लायगी।

विस्थापित व्यक्तियों की भवन निर्माण सहकारी समितियों, स्थानीय निकायों और निजी (प्राइवेट) व्यक्तियों को क्रमशः ६,४७,५०० रु०, १६,३८,६६९ और १,५०,००० रु० की धनराशियां इस उद्देश्य से ऋण के रूप में दी गईं कि

विस्थापित व्यक्तियों को सतान बसाने में प्रोत्साहन मिले। आलोच्य वर्ष के अन्त तक राज्य सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों के लिए ६,७१८ मकान और ३,००० स्टाल बनवाये।

विस्थापित व्यक्तियों को नौकरी दिलाने के लिए प्रयत्न जारी रहे। आलोच्य वर्ष के अन्त तक २१,१७८ व्यक्तियों को नौकरी दिखाई गई थी। पश्चिमी बंगाल से जूट की खेती करने वाले ५०० परिवारों ने से, जिन्हें राज्य सरकार फिर से बसाने की राजी हो गई थी, ३०० परिवार इस वर्ष पहुंच चुके थे।

राज्य के विभिन्न भागों में रहने के मकान बन जाने से समस्त शिविर [६ को छोड़ कर जिनमें मेरठ और गुरा के आश्रम (होम) में सम्मिलित हैं], जिनमें अब तक विस्थापित व्यक्तियों की व्यवस्था थी, बन्द कर दिये गये। इलाहाबाद के आश्रम (होम) नवम्बर, १९५२ ई० में इनमें से बन्द कर दिया गया कि उस आश्रम (होम) में रहने वालों में से अधिकतर लोगों को पूर्वी पंजाब में फिरोजपुर के नये बसाये हुए आश्रम (होम) में भेज दिया गया था और बाकी को मेरठ आश्रम (होम) में भेज दिया गया था। तीन आश्रम, जिनमें कुल ४०० महिलाओं के रहने की व्यवस्था थी, इलाहाबाद, बनारस और बन्दाबन में पूर्वी बंगाल से आई हुई निराश्रित वृद्धाओं के लिए खोले गये। ऋषीकेश की इन्फर्मरी (अशान्ति के लिए आश्रम) प्रशासकीय सुविधाओं के विचार से मेरठ स्थानान्तरित कर दी गई।

देहरादून में आवासिक औद्योगिक आश्रम और चुनार में महिलाओं के लिए औद्योगिक आश्रम चालू रहे। इसके अतिरिक्त मेरठ, मथुरा, लखनऊ, बनारस, आगरा, मुरादाबाद, च दौसी, महारनपुर, हरद्वार, गाझियाबाद और कानपुर के ट्रेनिंग तथा उत्पादन केन्द्र व्यावसायिक ट्रेनिंग देने रहे। इन आश्रमों की ३३ महिलाओं में से प्रत्येक को २५० रु० का पुनर्वास अनुदान दिया गया, जिन्होंने दस्तकारी में पर्याप्त दक्षता प्राप्त कर ली थी और जो अब छोड़ने के बाद स्वतः अपने काम में ला सकी थी। १४ विस्थापित व्यक्तियों ने से अपने को १५ रु० मासिक नकद भत्ता दिया गया जिससे कि वे अपना खर्चा बर्ताना सके।

क्षयरोग से पीड़ित विस्थापित रोगियों के लिए भुवाली सेनेरीयम में १८ रोगियों के रहने की व्यवस्था के निमित्त चिकित्सा तथा स्वास्थ्य के डाइरेक्टर को २५,००० रु० की धनराशि दी गई। अन्य रोगों के उपचार के लिए राज्य के विभिन्न स्थानों के स्थानीय अस्पतालों और सेनेरीयम में प्रबन्ध करने के निमित्त १०,००० रुपये की धनराशि देने की व्यवस्था की गई।

निष्क्रान्त सम्पत्ति के राज्य सरक्षक के सगठन पर हुए व्यय को पूर्ण करने के लिए १९५१-५२ ई० के बजट में व्यवस्थित ८,६०,००० रु० की धनराशि में भारत सरकार का अग्रदान ४२६ लाख रुपये था। शेष धनराशि निष्क्रान्त सम्पत्ति की प्राप्ति से होने वाली आय के १० प्रतिशत धनराशि से पूरी की गई। राज्य में निष्क्रान्त सम्पत्ति की खोज करने वाले विशेष कर्मचारियों के जपानादिके सम्पूर्ण व्यय को भी भारत सरकार ने किया। इस कर्मचारियों ने लगभग १२,००० ऐसी सम्पत्तियों का पता लगाया।

भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच सन्धी के अनुसार जो मुसलमान फरवरी और मई, १९५० ई० के बीच पश्चिमी पाकिस्तान चले गये थे और तदुपरांत फिर सरकार से प्रोत्साहन मिलने पर हिन्दुस्तान में उधियों में वापिस आ गये थे, उन्हें अपनी उन सम्पत्ति के मिलने का अधिकार मिला गया था जिसे निष्क्रान्त सम्पत्ति के रूप में ले लिया गया था। इन सम्पत्तियों में निष्क्रान्त सम्पत्ति विभाग के सचिव को भारत सरकार ने यह अधिकार दे

दिये थे कि वह हल ही में वापिस आये हुए व्यक्तियों को निष्क्रान्त सम्पत्ति वापस दिलाने के प्रमाण पत्र दे सकता है। लैटने वाले कुछ मुसलमानों की विषम परिस्थितियों को देखते हुए सम्पत्ति वापस पाने के प्रत्येक प्रार्थना-पत्र पर १० रु० की निर्धारित कोर्ट स्टाम्प की फंस तथा कुछ अन्य प्रारम्भिक कानूनी कार्यवाहियों से, जिनमें सम्पत्ति वापस होने में बाधा पहुँच रही थी, उनको बरी कर दिया गया। आलोच्य वर्ष में सम्पत्ति वापस दिलाने के लिये ४८२ प्रमाण-पत्र जारी किये गये।

इस वर्ष इटैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) ऐक्ट, १९५१ नामक एक सेन्ट्रल ऐक्ट इस उद्देश्य से पारित किया गया जिससे कि सश्रुति निष्क्रान्त सम्पत्ति में निष्क्रान्तों के हित को गैर निष्क्रान्तों के हित से पृथक् किया जा सक। इस ऐक्ट के अधीन इस राज्य में निष्क्रान्त सम्पत्ति के बटवारे के काम को शुरू करने के लिये एक सुयोग्य अधिकारी की नियुक्ति की गयी।

भारत में छोड़ी गयी एकत्रित निष्क्रान्त सम्पत्ति से विस्थापित व्यक्तियों की क्षति पूर्ति के लिये भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में ग्राम्य और नागरिक सम्पत्ति का मूल्य निर्धारण करने के लिये एक योजना बनाई। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के कई जिलों में काम किया गया और कई जगहों, इमारतों इत्यादि का मूल्य निर्धारण सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा किया गया।

८ लाख रुपये की कुल धनराशि निष्क्रान्त सम्पत्ति के निजी खाते से भारत में निष्क्रान्त सम्पत्ति के सामान्य सरक्षक के निजी खाते में विस्थापित व्यक्तियों को भरण-पोषण का भत्ता देने के लिये सक्रमित की गयी।

७ नवम्बर को राष्ट्रपति ने डिस्प्लेस्ड परसन डेट एजस्टमेंट ऐक्ट, १९५१ ई० के सम्बन्ध में अपनी सम्मति दी, जिसमें विस्थापित व्यक्तियों द्वारा वेधकृण का समाधान करने, उनको देय कुछ ऋणों की बसली करने और कुछ अन्य सम्बन्धित मामलों की व्यवस्था थी। भारत सरकार ने इस ऐक्ट को १० दिसम्बर, १९५१ ई० से उत्तर प्रदेश में लागू किया। इस ऐक्ट से डिस्प्लेस्ड परसन (इन्स्टीटयूशन आफ सूट्स) ऐक्ट, १९४८ तथा डिस्प्लेस्ड परसन (लीगल प्रोसीडिंस) ऐक्ट, १९४६ ई० का अपखंडन हो गया। सभी सिविल जजों का अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में और जिला जजों को उन जगहों पर जहाँ सिविल जज नहीं थे उत्तर प्रदेश सरकार ने इस ऐक्ट के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार में धर्माधिकरण के अधिकारों का प्रयोग करने के निमित्त नियुक्त किया।

इस वर्ष निष्क्रान्त सरकारी नौकरों तथा पूर्व रियासतों और स्थानीय निकायों के नौकरों के पेन्शनों, पूर्वदायी कोष (प्राविडेंट फंड), वेतन के बकायों आदि के ८७४ दावे छानबीन के लिये प्राप्त हुए और २,४३६ और दावों की छानबीन की गई और भारत सरकार के सेन्ट्रल क्लेम्स आर्गनाइजेशन को अप्रैल, १९४६ ई० के अन्ताधिराज्य समझौते के (इटर डोमिनिय एग्रीमेंट) के अनुसार वापिस कर दिये गये। उसके अतिरिक्त इस राज्य के विस्थापित व्यक्तियों द्वारा पाकिस्तान में छोड़ी गयी चल सम्पत्ति के लिये कई दावों का हवाला पाकिस्तान में भारत के हाई कमिशनर को या पाकिस्तान में सम्बन्धित प्रांतों के मुख्य सचिवों को भेज दिये गये। एक अन्य अन्ताधिराज्य समझौते के अनुसार प्रार्थना किये जाने पर सरकार ने कई उन निष्क्रान्त सरकारी नौकरों इत्यादि के, जो पहिले उत्तर प्रदेश में कर्मचारी थे, सेवालेखों को पाकिस्तान संक्रमित कर दिया।

६—भूमि सम्बन्धी समस्याएं

वर्ष के दौरान में कृषि उपज के सामान महंगे बने रहे। अंशतः महंगाई के कारण और अंशतः 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन तथा किसानों को तत्काली ऋण के रूप में दी जाने वाली वित्तीय सहायता के कारण जोतो का क्षेत्रफल लगभग १ १/२ प्रतिशत बढ़ गया। १३५४ फसली से १३५८ फसली तक के पांच वर्षों की अवधि में कुल लगभग ७ प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें से १ प्रतिशत की वृद्धि अन्तर क्षेत्रों के विलयन के फलस्वरूप राज्य के प्रदेश में विस्तार होने के कारण हुई। इसी अवधि में जमीन्दारों की सीर और खुदकाईत की जमीनें भी लगभग २ प्रतिशत बढ़ गयीं।

खेतों में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी और बैलें तथा कृषि सम्बन्धी औजारों के मूल्य भी बढ़े चढ़े रहे। इन बातों से और साथ ही कृषि उपज की बिक्री से अधिक आय होने से और ट्रैक्टरों की खरीद के लिये राज्य सहायता दिए जाने से बड़े किसानों की मशीनों के द्वारा खेती करने की ओर महत्वपूर्ण प्रवृत्ति हुई।

कुछ वर्गों के उन किसानों को जिन्हें यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३६ ई० के अन्तर्गत स्थायी अधिकार नहीं प्राप्त थे, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने तथा निकट भविष्य में होने वाले जमीन्दारी प्रथा के विनाश के आधार पर एक बड़ी सख्या में होने वाली बेदखलियों को रोकने के अभिप्राय से आलोच्य वर्ष में भी टेनेन्सी ऐक्ट की धारा १७५ के अन्तर्गत गरदखीलकार काश्तकारों की बेदखली सम्बन्धी मुकद्दमों को स्थगित कर दिया गया। ६ अगस्त, १९५१ ई० को एक ऐसी विरूपित निकाली गई कि जिसके अनुसार टेनेन्सी ऐक्ट की धारा १८० के अन्तर्गत दखीलकार काश्तकारों की बेदखली से सम्बन्धित मुकद्दमों को भी स्थगित किये जाने के लिये दुबारा आदेश जारी किये गये।

जंगलों तथा पेड़ों को व्यापक रूप से और अविवेकपूर्ण ढंग से काटने को रोकने के लिये यू० पी० प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट के अन्तर्गत की गई कार्यवाहियां जारी रही। साथ ही साथ लैन्ड यूटिलाइजेशन ऐक्ट से भी लाभ उठाया गया कि कोई कृषि योग्य भूमि बिना खेती के शेष न रहे। राज्य की आर्थिक स्थिति में इन दो कार्यवाहियों के द्वारा सरकार इस बात में सामंजस्य स्थापित कर सकी कि कहाँ कृषि होनी चाहिए और कहाँ जंगल लगने चाहिए।

मार्च और अप्रैल, १९५१ ई० में राज्य के १२ जिलों में कहीं-कहीं पुराने पड़े। राज्य के सभी जिलों में टिड्डियों ने धावा किया, किन्तु जिला अल्मोड़ा को छोड़कर और कहीं भी रबी की फसल को अधिक हानि नहीं पहुंची। आरम्भ में वर्षा न होने के कारण व्यापक सूखे से खरीफ की फसल को विशेषतः पूर्वी जिलों में बहुत काफी हानि पहुंची।

१०—कृषि सम्बन्धी स्थिति

फरवरी, १९५१ ई० में ओले पड़ने के कारण कुछ जिलों में खड़ी फसल को नुकसान हुआ तथा कुछ जिलों में टिड्डियों के कारण कुछ स्थानीय क्षति हुई। मार्च के आखिरी तथा अप्रैल के पहले सुप्ताह में वर्षा और ओले पड़ने के कारण कुछ जिलों में रबी की खड़ी फसल तथा खलिहान में पड़ी फसल को क्षति हुई। जुलाई और अगस्त के महीनों में वर्षा बहुत से जिलों में औसत से कम और कुछ जिलों में अधिक वर्षा हुई। किन्तु दोनों महीनों को मिलाकर बहुत से जिलों में वर्षा औसत से कम हुई। मानसून के महीनों

मे और बाद की अपर्याप्त तथा छूटछूट वर्षा होने के कारण खरीफ की फसल और विशेषकर धान की फसल को बहुत क्षति हुई। नेपाल तराई के कुछ भागों में तथा गोडा, बस्ती, गोरखपुर का वह भाग, जो नेपाल की सीमा पर है और जहाँ धान पैदा होता है, वहाँ खरीफ की फसल का बीना तथा देर से पकने वाले धान के पौधों को रोपने का काम न किया जा सका। जमीन में नमी के कारण, विशेषकर गैर सिंचाई के क्षेत्रों में रबी की फसल के लिये पंती को तैयार करने का काम भी सन्तोषजनक नहीं था। रबी का फसल के क्षेत्र में भी थोड़ा कमि हुई। आलोच्य वर्ष में पिछले वर्ष के क्षेत्र और पैदावार में तुलना में क्षेत्र तथा पैदावार दोनों में गन्ना, मक्का और गेहूँ में कृति हुई और चना, बाजरा तथा गन्ना में कमि हुई। चा और कपास के क्षेत्र में कमि न हुई हुए भी पिछले वर्ष की अपेक्षा प्रत्येक फसल का क्षेत्र अधिक था। धान के सम्बन्ध में उपज में कमी हुई और धान कलन में थोड़ी देर हुई।

११—कृषि विभाग

कृषि विभाग के तानने और उत्पादन बढ़ाने का समस्या का सर्वप्रथम स्थान रहा। १३,००,६२० रु० की धनराशि बिना व्याज के ऋणों के रूप में और ३७,०४,७४६ रुपये की धनराशि का अनुदान राज सहित तकावी के रूप में किसानों को दिये जान और उनको प्रोत्साहन मिलाने के फलस्वरूप १,१४,६२६ एकड़ भूमि जोती गयी। लगभग १४,२२,७१७ मन की रबी के फसल के बीज और ३,३२,३५३ मन खरीफ के फसल के बीज किसानों में बाँटे गये और इसके अतिरिक्त ६१,५४६ मन खली, ५,२१,३०० मन कृत्रिम खाद, १६,८३२ मन सनई के बीज हरी खाद के लिये और ६,२५,४१,४५० मन मिलवा खाद बाँटी गयी। फसलों की प्रतियोगिता प्रारम्भ करने से प्रतियोगिता की भावनाएं अच्छी पैदा हुयी और लगभग ६०,००० किसानों ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया। पौधा संरक्षण सेवा और विभिन्न अनुसंधान प्रकल्पों की कार्य करते रहे।

१२—ग्राम-सुधार

मुख्य कार्यालय के स्थान (Headquarters) में ग्राम-सुधार विभाग ने सहकारी समितियों की रजिस्ट्रार तथा ग्राम सुधार अधिकारी और सहायक ग्राम सुधार अधिकारी तथा सहायक (Assistant) रजिस्ट्रार के संयुक्त शासनाधिकार के अधीन रह कर काम किया। ग्राम सुधार विभाग के बाकी कर्मचारियों को सहकारी विभाग (Co-operative Department) में खपाने की क्रिया जारी रही और साल की समाप्ति पर वह पूर्णता के समीप पहुँच चुकी थी।

महिला हितकारी योजना का स्थान विभाग के कार्यक्रम में महत्वपूर्ण रहा। देहाती नारियों की सेवा के लिये उसे "समग्र ग्राम सेवा" के आधार पर पुनर्संगठित किया गया। योजना के उद्देश्यों में माता और छोटे बच्चे (Mother and Child) का प्रबोध (Enlightenment) देने, माता और बच्चे का कल्याण साधन और आर्थिक भलाई करने के उद्देश्य भी थे। गत वर्ष की भाँति १२ जिलों में यह काम होता रहा और इस योजना की मानहती में ३ मंडल संगठनकर्ताओं (Zonal organisers), १२ जिला संगठनकर्ताओं और २०० ग्राम सेविकाओं ने काम किया। हर एक जिले में ३ से ५ तक केन्द्रों में अधिक जटकर (concentrated) प्रयत्न किये गये। आलोच्य वर्ष में सरकार ने व्यायाम परिषद् के सचिव के टेक्निकल (Technical)

सहायक शरीर व्यायाम निरीक्षक (Superintendent of Physical culture), इलाहाबाद के पक्षों को महिला हितकारी योजना के अन्तर्गत कर दिया, ताकि देहाती हस्तियों में शरीरों के शारीरिक संवर्द्धन के काम में आसानी हो। आलमबाग, लखनऊ में एक बालबारी और प्रौढ़ शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र आरम्भ किया गया और ५ सड़ियों के प्रशिक्षण के लिये २० ग्राम सेविकाओं को उसमें भर्ती किया गया।

देहाती क्षेत्रों में पानी की कमी और यातायात की दिक्कत को दूर करने तथा पंचायतघरों और बीज भण्डारों के बनाने और सरम्मत करने की ओर भी ध्यान दिया गया है। आलोच्य वर्ष में निर्माण सम्बन्धी कार्य जिला विकास समितियों (District Development Associations) द्वारा हो रहा था, किन्तु बाद को उन्होंने अपना कार्य जिला नियोजन समितियों को सुपुर्द कर दिया। देहाती में जल की व्यवस्था (supply) में सुधार करने के हेतु तीन लाख रुपये की और पंचायतघरों तथा बीज भण्डारों के बनाने एवं सरम्मत के लिये तीस हजार रुपये की रकम सरकार ने सज्जूर की।

१३—पशु-पालन

पशु-पालन विभाग ने विभिन्न दिशाओं में और अधिक प्रगति की। राज्य में परन्तु चिकित्सालयों का प्रबन्ध करने और पशु रोगों को फैलने से रोकने के लिये २६८ वेटरिनरी असिस्टेंट सर्जन और ८६४ स्टाफ नर्स थे। सकल पशु चिकित्सा यूनिट मेरठ भेज दी गयी, जहाँ उसका उपयोग जिलों में पशुधन की प्रगढ़रूप से नस्लकशी करने और सुदूर भागों में पशु चिकित्सा पहुंचाने के लिये किया गया।

बायोलाजिकल प्रोडक्ट्स सेक्शन ने रोग से बचने के दो पदार्थो अर्थात् रिडरपेस्ट गोड टिस्पू वैक्सीन (डेसिकेटेड) तथा हेमोराजिक सेप्टीसीमिया वैक्सीन (दोनों अग्रवास और ब्रोथ वैक्सीन) को काफी मात्रा में तैयार किया और उनकी सप्लाई में वृद्धि की। १९५१ ई० में इन वैक्सीनों की क्रमशः कुल १०,६१,७०० और २५,७२,७५० मात्राये फोल्ड कर्मचारियों को दी गई। वर्ष समाप्त होते समय इस सेक्शन में रानीखेत डिजीज वैक्सीन, फाउल पाक्स वैक्सीन और फाउल कालरा वैक्सीन तैयार करने का कार्य भी आरम्भ किया गया।

फंजाव आई० ए० आर० आई०, नई दिल्ली और विभिन्न सैनिक और अन्य केन्द्रीय सरकारी दुग्धशाला फार्मों से ३०० से अधिक विशुद्ध नस्ल के सांड खरीदे गये। देशी पशुधन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये स्वीकृत स्तर के सांड पैदा करने के हेतु राज्य पशुधन नस्लकर्ता फार्म (स्टेट ल इवस्टाक ब्रीडिंग फार्म) में विभिन्न नस्लों के २,४४२ पशु और विशुद्ध नस्ल को भेरी रखी गई। निजी तौर से उपयोग करने वालों को ३० रु० प्रति सांड की दर से ६०० विशुद्ध नस्ल के सांड सप्लाई किये गये। जिला मेरठ और छाता (जिला मथुरा) में प्रमुख ग्राम कार्य (की विलेज वर्क) जारी रखा गया और १४ अन्य प्रमुख ग्राम कार्य क्लार्क (की विलेज वर्क क्लार्क) स्थापित किये गये, जिनका वित्त-पोषण भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर ५०:५० प्रतिशत के हिसाब से किया। मेरठ, लखनऊ, देवरिया, गाजीपुर और महेवा (इटावा) में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र संतोषजनक कार्य करते रहे और जश्रिय हो गये। बाबूगढ़ (मेरठ), साधुरीकुण्ड (मथुरा), भरारी (झांसी) और बैरी (प्रतापगढ़) फार्मों के कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का नियन्त्रण हटाकर पशुपालन विभाग के अधीन कर दिया गया।

विशुद्ध नस्ल की साहीवाल गायों के एक गल्ले के रखरखाव के लिए बैती के पशु फार्म के मालिक को ३६,००० रुपये का आवर्तक अनुदान दिया गया। इस विभाग के लिये विशुद्ध नस्ल के सिधो सांड-बछेड़ा उत्पन्न करने के संबंध में एग्रिकलचरल इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद के साथ किये गये प्रबन्ध जारी रहे।

आलोच्य वर्ष में भद्रुक (लखनऊ) के सरकारी डेरी फार्म में १५,९७१ मन दूध, ८,३६८ पौंड मक्खन, २८ मन घी तैयार हुआ और सेन्ट्रल डेरी फार्म, अलीगढ़ में कुल ३,२५,६६३ पौंड दूध, १,५७,१०६ पौंड मक्खन, १,५२,६३२ पौंड घी और ३,१२,८४५ पौंड सुवर वाड़ों से प्राप्त होई वाली वस्तुएं तैयार की गईं। बजट में निजी डेरी फार्मों के लिये तकावी ऋण के रूप में ७५,००० रु० के अनुदान की व्यवस्था की गई और ऋण स्वीकृति सम्बन्धी नियमों के अंतिम रूप से बन जाने के उपरान्त ५ प्रार्थियों को यह अनुदान दिया गया।

निजी गौशालाओं में (जिन्हें १९४८, १९४९ तथा १९५० ई० में विशुद्ध नस्ल की २४६ हरियाना गायें दी गई थीं) प्रतिदिन के हिसाब से ४५ मन दूध पैदा किया गया। इन गौशालाओं द्वारा पैदा किये गये ४ विशुद्ध नस्ल के सांड पशुपालन विभाग ने खरीदे।

एटा, मैनपुरी, बिजनौर, मथुरा, सहारनपुर, इटावा और कानपुर के नये चुने गये जिलों में घोड़ों तथा खच्चरों के नस्लकशी की कार्यवाहियां जारी रही। वर्ष समाप्त होने के समय इन जिलों में क्रीमती सरकारी सांड-घोड़ों के लिए उपयुक्त अस्तबलों का निर्माण कार्य चालू रहा।

कूच से खरीदे गए ५ कठियावाड़ी घोड़ियां और २ काठियावाड़ी सांड-घोड़े तथा एक काठियावाड़ी बछड़ा मुरादाबाद से सांड-घोड़ों के डिपो में पाले गये। १९५१ ई० में राज्य के बाड़ों में ४३ सांड-घोड़े और ८ सांड-गधे थे।

फुलाही (इलाहाबाद), रतनपुर (फतेहपुर), भुलावन (गोरखपुर) और शिवपुरी (बनारस) के सांड-मेढा केन्द्रों में पहिले की ही तरह कार्य होता रहा और वहां स्थानीय भेड़ों के बाल काटने, उनकी नहलाने और पेरासाइटिसाइड्स (parasitocides) से भिगाने की सुविधाएं भी दी गयीं। पूर्व की भांति सरकारी भेड़ों के फार्म, उरई, डेरी डिमान्स्टेशन फार्म, मथुरा और माधुरी-कुंड (मथुरा) तथा बाबूगढ़ (मेरठ) के यंत्रीकृत राज्य फार्मों में विशुद्ध नस्ल की बीकानरी भेड़ों के गल्ले रखे गये। गढ़वाल जिले में ग्वालडम और पीपलकोटी के सरकारी भेड़ों के फार्म में रामपुर-विशेर की ३ मादा भेड़े रखी गईं। पीपलकोटी (जिला गढ़वाल) के सरकारी भेड़ों के फार्म में रखने के लिए १० विशुद्ध नस्ल के मेरिनो मादा भेड़े और ४ विशुद्ध नस्ल के मेरिनो नर भेड़ों के अमेरिकी से आयात करन के प्रबन्ध में शीघ्रता बरती गई। १९५१ ई० में विभाग ने देशी भेड़ों की नस्ल सुधारने के लिए १५० सांड भेड़े सप्लाई किये।

इटावा जिले के चाकरनगर क्षेत्र में जमुनापारी बकरियों और बकरो के रखरखाव के संबंध में राज्य सहायता देने की योजना चालू रही। उरई के भेड़ों के फार्म, एटा के पशु क्वारन्टाइन स्टेशन और माधुरीकुंड (मथुरा) के यंत्रीकृत राज्य फार्म में भी जमुनापारी बकरियों की यूनियो का रखरखाव किया गया। मथुरा के डेरी डिमान्स्टेशन फार्म में, जो बरवारी बकरियां रखी जाती थीं, वे मिशन फार्म, एटा को स्थानान्तरित कर दी गईं।

आलोच्य वर्ष में राज्य में निजी रूप से सुअरों की नस्लकशी करने वाले व्यक्तियों को विशुद्ध नस्ल के ५४ मिडिल हवाई यार्कशायर सुअर दिये गये।

लगभग ३८,४६६ अंडे, जिनसे बच्चे पैदा हो सकते हैं, ९,४९० बड़ी मुर्गियां और २,०७२ मुर्गी इत्यादि के बच्चे विकास संबंधी कार्य के लिए दिये गये और ५१,४५९ अंड और १,५५८ मुर्गियां इत्यादि खाने के लिए बँची गयीं।

समस्त पशुओं के मेलों और प्रदर्शनियों में चार्ट और नमूने दिखाये गये तथा अन्य प्रदर्शन भी किये गये। विभाग ने आगरे में राज्य के पशुधन संबंधी द्वितीय प्रदर्शनी के अतिरिक्त अन्य जिलों में एक दिन वाली क पशु-प्रदर्शनियों और प्रादेशिक पशु-प्रदर्शनियों का आयोजन किया।

वर्ष में राज्य में खाल उतारने वाले चार दलों ने दो ग्रामीण क्षेत्रों में और दो शहरी क्षेत्रों में काम किया। इन दलों ने १०६ ग्रामीण खाल उतारने वाले और १०६ कसाइयों को क्रमशः मरेपशुओं की खाल उतारने और वध किये गये पशुओं की खाल उतारने की ट्रेनिंग दी। इसके अतिरिक्त ग्रामीण खाल उतारने वालों को मरे पशुओं की उतारी गयी खाल सिझाने और उसको उपयोगी बनाने में प्रयोग करने के लिये उन्नत प्रकार के औजारों के १२२ सेट और ७० कीनिया किस्म के लकड़ी के ढ़ाचे दिये गये।

पिछले वर्ष की भांति पशुपालन विभाग के नियंत्रण में १२ यंत्रीकृत सरकारी फार्म थे। इनका कुल क्षेत्रफल १६,२५५ एकड़ था, जिसमें से १२,००० एकड़ भूमि में खेती की गई। आलोच्य वर्ष में इन फार्मों में ७३,३०६ मन अनाज, ६४,३०६ मन सूखा चारा, २,६६,६६३ मन हरा चारा, १३,७०५ मन सब्जियाँ और १,१७,४६१ मन गन्ना पैदा किया गया। विभिन्न फार्मों में जितने पशुओं का रखरखाव किया गया, उनकी संख्या ४,५१७ थी। फार्मों में पशुओं को रखने का मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत संघ के अन्य भागों से प्राप्त किये गये पशु यहां के जलवायु तथा वातावरण के आदी हो जाय और तदनन्तर उनका उपयोग देशी नस्ल के पशुओं का सुधार करने के लिए किया जाय। बाबूगढ, माधुरीकुंड और भरारी के फार्मों में बकरियों और भेड़ों का भी रख रखाव किया गया। बाबूगढ, भरारी और मझरा फार्मों में बड़े पैमाने पर सुर्गियां उत्पन्न करने का कार्य किया गया और इन फार्मों से जनता को सुर्गियां और अंडे भी सप्लाई किये गये।

उत्तर प्रदेश पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन कालेज, मथुरा में १५३ छात्र थे। आलोच्य वर्ष में इस कालेज से १५ स्नातकों का पहला बैच निकला। राज्य पशुधन अनुसन्धानशाला पशुधन संबंधी तात्कालिक महत्वपूर्ण समस्याओं को सुलझाती रही।

१४—मत्स्य-पालन

आलोच्य वर्ष में २५२ तालाबों में, जिनका क्षेत्रफल ३०८ एकड़ था, मछलियां रखी (स्टाक की) गई। 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के अधीन भारत सरकार ने तालाबों में मछलियों को स्टार्क करने तथा उनकी विकास योजना की राज्य-सहायता व्यय के ५०:५० प्रतिशत के आधार पर दिया।

कुमायूं के पहाड़ी क्षेत्रों के उच्चतर अक्षांशों में 'ट्राउट' नामक मछलियों का विकास करने के विचार से टेहरी-गढवाल जिले में 'कलदियानी हैचरी' को वन विभाग से ले लिया गया। भिररकार्य नामक मछलिया जो ऊटकमंड से लाई गई थी भुवाली हैचरी में सफलतापूर्वक पाली गई और इस नये किस्म की छोटी छोटी (Fingerlings) मछलियां कुमायूं पहाड़ियों के पानी में स्थान-स्थान पर डाली गई।

मत्स्य-पालन खोज प्रयोगशाला (Fishes Research Laboratory), लखनऊ में खोज तथा प्रयोग जारी रहे और रामपुर, बतारस, भुवाली (नैनीताल) और मिर्जापुर में चार खोज-उप-स्टेशन स्थापित किये गये। एक नये प्रकार की मछली अर्थात् 'दार्जिलिंग महासीर' को बंगाल के पहाड़ी प्रदेश से भुवाली

फिश काम में प्रयोग के लिए लाया गया। खोज का काम करने वाले कर्मचारियों ने कई तालाबों में मछलियों के स्टार्किंग का काम भी शुरू किया और आलोच्य वर्ष में १०२ एकड़ पानी स्टार्क किया गया।

१५—वन

नहरों के किनारों और तडकों के रास्तों पर स्थित पेड़ों को नुकसान से बचाने के निवार से इस वर्ष राज्य विधान मंडल ने भारतीय वन (उत्तर प्रदेश संशोधक), विधेयक, १९५१ ई० पारित किया।

लैंड मैनेजमेंट मॉकिल ईधन तथा चारे की रिजर्व की व्यवस्था के लिये रेल की भूमि, नहरों के किनारों, तडकों के किनारों और नजूल की भूमि जैसी राजकीय भूमि पर पेड़ लगाता रहा। कुछ नहरों के किनारों पर शहस्रत के पेड़ लगाये गये।

बहराइच जिला में खाद्यान्नों के अभाव के कारण सड़क को दूर करने के लिये वन विभाग ने पेड़ों के लगाने की योजना आरम्भ की। इस योजना के अंतर्गत इस क्षेत्र के बहुत से आदिमियों को काम मिला। इस विचार से राजस्थान सरकार अपने राज्य में चारे के अकाल का सामना कर सक, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने वनों से ४ लाख मन पुआल देना मंजूर किया।

राज्य में भूमि-परक्षण संबंधी कोई कानून बनाने के प्रश्न पर निवार करने के लिये भूमि अधिग्रहण बोर्ड ने एक उपसमिति नियुक्त किया।

आलोच्य अवधि में बनारस फारेस्ट डिब्बिजन में वन-बन्दीनस्स को कार्य-वाहियां आरंभ की गईं।

१६—सिंचाई

पिछले साल में ६०,१७,६७३ एकड़ के मुकाबले १३६,३१,४०० एकड़ भूमि की उपलेखनीय सिंचाई हुई। वर्षान होने से पानी की लड़ो सांग को पूरा करने में प्रयत्न और सिंचाई के लिये सुलभ पानी के सुविधापूर्वक वितरण ही सिंचाई के दोषों में वृद्धि के कारण है। सरकार सिंचाई की सहायता से होने वाले फायदों की कुल कीमत १८० करोड़ रु० आकाई गई और इसके अलावा किसानों पर बांधे गये लगानों की रकम ५४०८ रु० करोड़ हो गई।

साल के अंत में सिंचाई की नहरें कुल २६,०७३ मील थीं। साल के दौरान में १,२०८ मील लम्बी नई कुल्या बनाई गई। साल के अंत में सरकारी नल-कपा की संख्या २,३५१ थी, जिनसे १०५४ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हुई। इनमें से साल के दौरान में १३७ तैयार हुए, जिनमें बिजली लगा दी गई।

आलोच्य वर्ष में नीचे लिखे निर्माणकार्य या तो पूरे हो गये या हो रहे थे :—

(१) गंगा और यमुना नहरों में नई कुल्या का निर्माण और मौजूदा का विस्तार,

(२) नहर गंगा की पानी फेंकने की सामर्थ्य (discharge capacity) को ८ हजार से बढ़ा कर साठ दस हजार कुसेक्स (cusecs) कर देने के योजना संबंधी कार्य,

(३) सोलनी जल-प्रणाली (adueduct) की सतह को नीचा करना और उसकी बगली दीवारों को दृढ़ करना ताकि उससे गंगा नहर में अधिकतर जल पहुंचाया जा सके।

(४) घनौरी रेगुलेटर (Regulator) में लगे हुए पुरानी धाल के कपाटों को बदलना,

(५) कनखल कस्ब के बचाव के निमित्त गंगा नदी में एक बांध का निर्माण,

(६) पश्चिमी जिलों में ६००, २०० और ५० नल-कूप बनाने की योजना के अंतर्गत नल-कूपों का निर्माण,

(७) बंदेलखंड में ललितपुर, सपरार और कबराई जिलों की परियोजनाओं (Projects) के संबंध में निर्माण कार्य,

(८) बांदा जिले में रंगवां बांध का निर्माण,

(९) इलाहाबाद जिले में बेलन नहर परियोजना (Project) के सम्बन्ध में निर्माण कार्य,

(१०) बेतवा नहर प्रणाली में ३१० मील नई कुल्या और विस्तारों का निर्माण,

(११) कुथोंद शाखा को फिर से बनाना,

(१२) झासी, हमीरपुर, बांदा, इलाहाबाद, और सिजापुर जिलों में बन्धियों का बनाना,

(१३) चम्पारन, अहमौर, माताटीला और अर्जुन परियोजनाओं (Projects) के सम्बन्ध में निर्माण कार्य,

(१४) गोरखपुर, बस्ती और देवरिया जिलों में १०० नलकूपों का निर्माण,

(१५) शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर और गोंडा जिलों में ३४० नल-कूपों का निर्माण ।

पूर्वी जिलों में आगामी १५ सालों में कई हजार नलकूप के बनाने के एक अंश के सम्बन्ध में आजमगढ़ जिला से चार खोज (exploratory) नलकूप यह निश्चय करने के लिये बनाये गये कि इस हल्के में किस प्रकार के नलकूप अत्यंत उपयुक्त होंगे ।

सारवा नहर में २ हजार मील नई कुल्या के बनाने और विस्तार करने का काम हो रहा था । उसमें से साल की समाप्ति तक १,४७५ मील कुल्या और विस्तार निमित्त किये जा चुके थे और वे काम वे रही थीं । मुख्य सारवा नहर और उसकी शाखाओं का सामर्थ्य में २ हजार कुसेक (cusecs) की वृद्धि कर देने का काम भी प्रारम्भ किया गया, ताकि सुलभ होने पर नदी का पानी अधिकतर मात्रा में काम में लाया जा सके ।

अम्बोड़ा, सन्तोषाल, गढ़वाल और देहरी-गढ़वाल के जिलों में पिछड़े हुये हल्कों को, जिनको अन्न की कमी चिर काल से सता रही है, सहायता पहुंचाने के लिए लगभग ११२ मील लम्बी सिंचाई की ४१ छोटी कुल्या बनाई जा रही थीं । साल के अन्त तक ६३ मील कुल्या वस्तुतः बन गई थीं और सिंचाई के लिये खोल दी गयी थीं ।

१७—ज्यापार और उद्योग

आलोच्य वर्ष की एक उल्लेखनीय बात यह थी कि औद्योगिक उत्पादन में हर तरह से वृद्धि रही । कुछ बड़े उद्योगों के सम्बन्ध में उत्पादन १९४८ ई० के बाद इस वर्ष अधिकतम हुआ ।

उत्पादन में सुधार हो जाने का मुख्य कारण यह था कि परिवहन की सुविधायें कुछ अच्छी हो गयी थीं । गन्ना, कच्ची कपास और कच्चा जूट जैसे कच्चे माल मिलने लग गये थे और मालिकों तथा मजूरों के बीच साधारणतः सन्तोषजनक सम्बन्ध रहे ।

१९५१ ई० के प्रथम चार महीनों में कीमतें बढ़ रही थीं, किन्तु जुलाई के बाद कीमतें कम होने लग गयी थीं और इस वर्ष में लगभग २९ प्वाइन्ट की गिरावट दिखाई पड़ी ।

तथापि रहन सहन के व्यय में वृद्धि हो गयी, क्योंकि कीमते बढ़ गयी थी और मांग और माल की प्राप्य सप्लाई और सेवाओं के मध्य बड़ा भारी अन्तर हो गया था। औद्योगिक कच्चे माल की कीमतों में भारी वृद्धि हो गई थी।

१८—सहकारी आन्दोलन

१९५०-५१ ई० के सहकारी वर्ष में मुख्यतया पिछले वर्षों में किये गये समस्त सहकारिता सम्बन्धी कार्यों की प्रगति का एकत्रीकरण किया गया।

वर्ष के अन्त में विभिन्न प्रकार की ३५,००० समितियाँ थीं, जिनके सदस्यों की संख्या २८ लाख थी। कुल मिलाकर समितियों की वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक थी और उनका ग्रान्ड कैपिटल (निजी पूँजी) (७८२ करोड़ रुपये) वर्किंग कैपिटल (कार्यवाहक पूँजी) (लगभग २३ करोड़ रुपये) का लगभग एक-तिहाई था।

संस्थाएँ उत्पादन की ओर अधिक ध्यान देने और अर्थ सम्बन्धी अन्य कार्यवाहियों में वृद्धि करने की नीति का निरन्तर अनुकरण करती रही। आलोच्य वर्ष में समितियों ने मुख्यतः जो कार्य किये, वे थे—वित्तीय व्यवस्था करना, बीज, खाद तथा खेतों के औजारों की सप्लाई करना, सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं तथा कुटीर उद्योग के लिये कच्चे माल की व्यवस्था करना, आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करना और उनका वितरण करना, चीनी के कारखानों को गन्ना सप्लाई करना, शुद्ध दूध तथा दूध से बनी चीजें सप्लाई करना, औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन तथा विक्रय करना, जोतों की चकबन्दी करना, भूमि उपनिवेशन तथा सहकारी कृषि सम्बन्धी कुर्य और शहरी में मकानों का निर्माण करना।

१९५०-५१ ई० में राज्य में जो प्रमुख सहकारी समितियाँ कार्य करती रही वे ये थी—य० पी० को-ऑपरेटिव बैंक, य० पी० को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट तथा मार्केटिंग फेडरेशन, केन्द्रीय सहकारी (General Co-operative) बैंक और बैंकिंग यूनियन (६६), डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फेडरेशन (५०), डेवलपमेंट और मार्केटिंग यूनियन (१,५६७), गन्ना समितियाँ (१०५), कृषि ऋण समितियाँ (२६,३६०), अकृषि ऋण समितियाँ (६४६), दुग्ध समितियाँ (६ केन्द्रीय, २०३ प्राथमिक), घी समितियाँ (११ केन्द्रीय, ६३१ प्राथमिक), कपड़ा समितियाँ (३६ केन्द्रीय, ५८१ प्राथमिक), जोत चकबन्दी समितियाँ (४८२), सहकारी कृषि समितियाँ (३२), भूमि उपनिवेशन समितियाँ (६७), भवन निर्माण समितियाँ (१६७) और उपभोक्ता समितियाँ (५०८)।

१९—नियोजन

नियोजन और विकास (Planning and Development) विभाग का पुनर्स्थापन, १९५० में हुआ था। अपने उसी रूप में वह पूरे साल भर सरकार के मुख्य कार्यालय और जिलों में काम करता रहा। राज्य नियोजन बोर्ड (State Planning Board) की मार्च और नवम्बर महीने में दो बैठकें हुईं, जिनमें उसने राज्य नियोजन समिति (State Planning Committee) की बनाई हुई द्वितीय और पंचवर्षीय योजनाओं (Plans) पर विचार किया तथा उपयुक्त परिष्कारों का सुझाव दिया।

नव-निर्मित जिला नियोजन समितियों (Planning Committees) ने नियोजन विभाग के बताये हुए आधार पर बनाये गये कार्यक्रम के अनुसार जिले में काम किया। ब्लाक नियोजन समितियों की सलाह से विकास कार्य के अपने वार्षिक नियोजन (Plans) बनाने को जिला नियोजन समितियों से कहा गया। जिले में नियोजन की विशेष बातें यह थीं :—

(१) सरकारी और गैरसरकारी संगठनों तथा कार्यकर्त्ताओं का एकीकरण।

(२) ग्राम नियोजन (Village Plans) को आत्म-सहायता के सिद्धांत पर कार्यान्वित करना, और

(३) कृषि, पशुपालन-सहकारिता (Co-operation), सार्वजनिक स्वास्थ्य और पंचायती राज में प्रशिक्षित बहुप्रयोजन कार्यकर्त्ता का उद्विकास। लगभग ५० प्रतिशत जिले में विभिन्न विकास विभागों (Development Depots) के दफ्तर एक ही भवन में रखे गये। उपयुक्त स्थान के अभाव के कारण बाकी जिले में भी ऐसा ही प्रबन्ध कर देने के प्रस्ताव को स्थगित करना पड़ा। अधिकांश जिले में बहुप्रयोजन कार्यकर्त्ताओं को थोड़े दिनों तक जाब ट्रेनिंग (Job Training) दी गई। कर्मचारियों के पथप्रदर्शन के लिये एक्सटेंशन मैनुअल (Extension Manuals) के रूप में उपयुक्त साहित्य तैयार किया गया। कार्यक्रम में १८ बातें थीं—सड़कों और मकानों का बनाना, ग्राम आरोग्य दिक्षा और स्वच्छता, पशुपालन, शिक्षा और मनोरंजन, किसानों और बागबानी, सहकारिता और बुटीर उद्योग। प्रत्येक जिले में स्थानीय उत्साह के अनुरूप ही तरकीबें हुईं।

समग्र ग्राम सेवा के आदर्श के अनुसार गांवों को संगठित करने के उद्देश्य से कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण के लिये प्रादेशिक शिक्षण केन्द्र की योजना (Regional Training Centres Scheme) चालू रही। जिला नियोजन अधिकारियों (Planning Officers) के नियंत्रण में रखे गये विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और उन उम्मीदवारों की, जो ग्राम पंचायतों के सेक्टरियों के रूप में काम करते, ट्रेनिंग की व्यवस्था के लिये यह निश्चय हुआ कि योजना को फिर से संगठित किया जाय और दो केन्द्रों की कक्षाएँ तोड़ दी जायँ। चार क्षेत्रीय शिक्षण केन्द्रों में कार्य की परिसीमित कर दिया गया। इन चारों केन्द्रों में पंचायत राज का काम सिखाने के लिये एक अतिरिक्त शिक्षक नियुक्त किया गया। प्रांतीय रक्षक दल के पुनर्संगठन के साथ, उसके कार्यकर्त्ताओं को ग्राम कल्याण कार्यक्रम की शिक्षा देना जरूरी हो गया और २ केन्द्रों से मुक्त शिक्षकों के एक सेट को इस काम में लगा दिया गया। योजना के पुनर्संगठन के बाद छठे जूथे का प्रशिक्षण आरम्भ हुआ। इस जूथ में १२० उम्मीदवार थे, जो गांव पंचायतों के सेक्टरियों का काम करने के लिये चन गये थे।

गाजीपुर का रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (Regional Training Institute) भी अपना काम करता रहा। प्रथम वर्ष वर्ग (First Year Class) ४५ और द्वितीय वर्ष वर्ग ३५ छात्रों से प्रारम्भ हुआ। इंस्टीट्यूट से सलग्न कृषि फार्म (Farm) से साल भर में १०,००० रुपये से अधिक की आमदनी हुई। व्यावहारिक उत्थान कार्य के लिय छात्र चुने हुए गांवों में सप्ताह में दो बार जाते रहे। उन्होंने सोख लेने वाले गड्ढे (Soakage Pits) बनाये, नालियों और

और गलियों की सफाई की और बालियों को पढ़ाने के लिये दर्ज खले। अपन शिक्षात्मक दौरे में वे इटावा और गोरखपुर के पाइलेट प्रोजेक्ट (Pilot Project) क्षेत्रों तथा कानपुर, नैनी और किछा (नैनीताल) की कृषि संस्थाओं को देखने भी गये।

इटावा के पाइलेट प्रोजेक्ट न सफलतापूर्वक कार्य करने का दूसरा साल पूरा किया। प्रायः दो सौ गावों में योजना (Project) का कार्य-क्षेत्र रहा। कृषि, पशुपालन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक शिक्षा, नारी कल्याण, सहकारिता, पंचायत कार्य और घरों तथा रास्तों के सुधारों के कार्यों में काफी उन्नति हुई। एक एकड़ जमीन में ४२ मन से अधिक गेहूँ और ३८६ मन से अधिक आलू पैदा होने की रिपोर्ट मिली। दूसरी फसलों की पैदावार में भी वृद्धि हुई। उत्कृष्ट (improved) गेहूँ से पूरा क्षेत्र पाट दिया गया और दूसरे जिले तथा इटावा के अन्य हल्कों को भी १५,००० मन उत्कृष्ट गेहूँ के बीज दिये गये। किसानों को लागत पर तरकारियों के लगभग १२ हजार छोटे पौधे (बेदन), ४२ पाउण्ड तरकारियों के बीज और १,२०० फल तथा ४,१६० इमारती लकड़ी के पौधे बेचे गये। तीन नलकूप और चार पाताल कूप (Artesian Wells) उक्त क्षेत्र में बनाये गये और सहकारिता के आधार पर संचालित हुए। यमुना नदी के कछार के तीर खोज निकाली गई पाताल पट्टी (Artesian Zone) प्रकृति की एक अमूल्य देन है। कल्टिवेटर (Cultivator) हल, माड़ने का यन्त्र (Thresher), बीज बोने का यन्त्र (Seed Drill), फसल काटने का यन्त्र (Reaper) इत्यादि का इस्तेमाल अधिकता से हुआ और महेबा के देहाती कारखानों की लोकप्रियता बढ़ी। रोग-निवारक टीके लगाकर पशु रोगों को मिटाने और अच्छी नस्ल के पशु मुहब्बत करके पशुओं को नस्ल सुधारने, कृत्रिम रूप से गाम्बिन करने (artificial insemination) और बधिया करने के कार्यक्रम में बराबर उन्नति हुई। पशु महामारी (Rinderpest) तो प्रायः मिट ही गई और रक्तस्राव रोगाणु रक्तता (Haemorrhagic Septicaemia) नाम मात्र की रह गयी। गाँववासियों को १२४ सफेद मुग दिये गये और ७२ तालों में मछलियाँ रक्खी गईं। सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में चेचक के निवारण के लिये अनुविद्ध टीका (saturated vaccination) लगाया गया और हैजा तथा खुजली के नाश के भी उपाय किये गये। साथ ही आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुधार की भी चेष्टा की गई। प्रौढ साक्षरता, नारी कल्याण इत्यादि के कार्यक्रम को जोरों के साथ चलाया गया और जनता ने इसका स्वागत किया। आलोच्य वर्ष में दो नये सेकेण्डरी (Secondary) स्कूल, चार नये मिडिल (Middle) स्कूल और ११ प्रारम्भिक स्कूल चलते रहे। इनको गाँववालों ने चलाया और साज-सामान के लिये उन्होंने ६० हजार रुपये दिये। इमारत की पूरी लागत भी, जो लगभग एक लाख रुपये थी, उन्होंने दी। ४० गाँवों में स्वयंसेवकों की मेहनत से ५१ मील लम्बी कच्ची सड़क बनायी गई। वार्षिक किसान मेलों में १५ हजार से ऊपर लोग आये।

प्रोजेक्ट (Project) हल्के के समस्त सहकारी संघों (Co-operative unions) के अपने ईंटों के भट्टे थे और उन्होंने गाँव वालों को बीज, खाद, औजार (implements), कपड़ा तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुएँ (consumers goods) तथा दवाइयाँ सप्लाई की। १९५१-५२ ई० में विक्रय घन ५ लाख ८०

से अधिक था, जिसमें लगभग ४३,००० रु० का शुद्ध लाभ हुआ। इटावा पाइलट प्रोजेक्ट सम्बन्धी पाक्षिक समाचार देने वाले "मन्दिर से" नामक पत्र के लगभग एक हजार चन्दा देने वाले ग्राहक थे।

गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया और गाजीपुर में पाइलट नियोजन (Pilot Projects) के अन्तर्गत जो काम हुआ वह उससे भिन्न था जो इटावा में हुआ। इटावा में जो अनुभव हुआ उससे इन जिलों में कुछ कार्यों को तेजी और कफायत से करने में सहायता मिली। महिला कल्याण केन्द्र और ग्रामीण सहयोग वर्ग काफी लोकप्रिय सिद्ध हुए।

सब जिलों में नियोजन समितियों (Planning Committees) के बन जाने पर कुमायूँ सुधार बोर्ड तोड़ दिया गया। किन्तु यह अनुभव किया गया कि अल्मोड़ा, गढ़वाल, देहरा और नैनीताल के जिला नियोजन अधिकारी और कुछ गैर-सरकारी सज्जनों की समय-समय पर सभाओं का होना इस क्षेत्र के नये उपयोगी होगा और इन पहाड़ी जिलों के सामान्य मामलों पर सहाय देने के लिये एक तदर्थ कमेटी का बनाना वाछनीय होगा।

कुमायूँ के यात्री ब्यूरो (Tourists Bureau) ने अरुण कार्य अधिक जोर-शोर से किया। केवल इसी देश के ही नहीं, अपितु विदेशीय यात्रियों में भी कुमायूँ पहाड़ों की सैर करने की इच्छा पैदा करने के अभिप्राय से रेल, स्टेशनों, पुस्तकालयों, होटलों, क्लबों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों और नई दिल्ली में स्थित विदेशीय दूतावासों में विज्ञापनों, पोस्टरों आदि द्वारा प्रचुर प्रचार का प्रबन्ध किया गया। आलोच्य वर्ष में ब्यूरो ने रेलगाड़ियों और बसों में पहले और दूसरे दर्जे के लगभग ४०० यात्रियों के लिये जगहों (Berths) का रिजर्व करने का बन्दोबस्त किया। यात्रियों की सुविधा के लिये अवभतिरहुत रेलवे का एक टिकटघर नैनीताल में खुलवाने का भी काम ब्यूरो ने किया। पहाड़ी जिलों के अनेक सनोहर स्थानों की व्यवस्थित सैर के कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिये गैर-सरकारी व्यक्तियों को राज्य-सहायता देने के निमित्त ५,००० रुपये मन्जूर किये गये।

१ अप्रैल, १९५१ ई० से व्यायाम परिषद् (Council of Physical Culture), उत्तर प्रदेश को शिक्षा विभाग के प्रशासन से हटाकर नियोजन विभाग (Planning Department) के नियन्त्रण में कर दिया गया। एकीकरण के विचार से महिला कर्मचारियों को महिला कल्याण योजना के संचालक (Director of Women's Welfare Scheme) के अधीन कर दिया गया। राज्य में व्यायाम सम्बन्धी कार्यवाहियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक अखाड़ों, खेल-कूद समितियों तथा जिला नियोजन समितियों को १,३२,४०० रु० के अनुदान दिये गये।

२०—विद्युत्

विद्युत् शाखा में, जो फरवरी, १९५० ई० में सिंचाई शाखा से अलग कर दी गई थी, १ जनवरी, १९५१ ई० से एक अलग चीफ इंजीनियर क चार्ज में रखी गयी। सारदा हाइडल सर्किल में रूरल लाइनों के बनाने और खातिमा में बिजली पैदा करने के लिये दो नये डिबीजन स्वीकृत किये गये। इस प्रकार विद्युत् शाखा में कुल मिलाकर १४ डिबीजन और ३३ सब-डिबीजन हो गये।

विद्युत् शाखा ने आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित बड़े निर्माण-कार्य किये :—

गंगा हाइड्रल सर्किल—

- (१) हरदुआगज स्टीम स्टेशन का विस्तार ।
- (२) मोहम्मदपुर पावर हाउस का निर्माण (विद्युत्-गृह) ।
- (३) रामपुर पावर हाउस (विद्युत्-गृह) का निर्माण ।
- (४) मोहम्मदपुर सालवा ६६ के० वी० डबल सर्किट लाइन का निर्माण ।
- (५) सुमेरा-चन्दौसी तथा मुरादाबाद सब-स्टेशनों के बीच ६६ के० वी० की डबल सर्किट लाइन का निर्माण ।
- (६) ६१६ राज्य ट्यूब-वेलो का विद्युत्करण ।
- (७) साल बल्लाओ के स्थान पर इस्पात के बने खम्भे का लगाया जाना ।
- (८) चितौर और निरगाजनी में ६६ के० वी० के मेन सब-स्टेशनों का विस्तार ।

सारदा हाइड्रल सर्किल—

- (१) खातिमा पावर हाउस का निर्माण ।
- (२) सारदा हाइड्रोएलेक्ट्रिक ट्रान्समिशन तथा ट्रान्सफार्मेशन लाइनों का निर्माण ।
- (३) गोरखपुर राज्य ट्यूबवेल विद्युत्करण योजना का कार्यान्वित किया जाना ।
- (४) आजमगढ विद्युत् स्पलाई कारोबार की स्थापना ।
- (५) सोहवल स्टीम स्टेशन और फेड़वाड विद्युत् स्पलाई योजना का विस्तार ।

लार्भग १ करोड़ रुपये लागत के बड़े निर्माण कार्य किये गये । आलोच्य वर्ष में १,१४,५०,००० रु० का अनुमानित राजस्व प्राप्त हुआ, जो निम्नलिखित है :—

(१) गंगा हाइड्रल ग्रिड (रामपुर और टेहरी-गढवाल के विलीनीकृत राज्यों को मिला कर)	... १,१०,००,०००
(२) सोहवल पावर हाउस	... " २,००,०००
(३) गोरखपुर पावर हाउस	... २,००,०००
(४) आजमगढ पावर हाउस	... ५०,०००

जहाँ तक कानपुर विद्युत् स्पलाई प्रशासन का संबंध है विद्युत् उत्पादन और राजस्व में वृद्धि होती रही । वर्तमान स्थिर यंत्रों में सुधार करने के लिये जो अनुसंधान किया गया, उससे स्थिर यंत्र में ३७,००० किलोवाट बिजली का भार-वहन करने की क्षमता आ गयी, जबकि पिछले वर्ष बिजली का भार-वहन करने का इसकी अधिकतम क्षमता ३१,००० किलोवाट थी । उपभोक्ताओं की संख्या २३,२५२ से बढ़कर २३,६३१ हो गयी । वर्तमान तथा संभावित उपभोक्ताओं की समस्त माँग पूरा करना संभव नहीं था । किन्तु यह आशा की गयी कि १६५२ ई० में रीवरसाइड पावर हाउस में विद्युत् उत्पादक स्थिर-यंत्र में १५,००० किलोवाट यंत्र के चालू हो जाने से कुछ सौ किलोवाट का अतिरिक्त भार-वाहन करना सम्भव हो जायगा ।

२१—सार्वजनिक निर्माण कार्य

आलोच्य वर्ष में सार्वजनिक निर्माण विभाग के संरक्षण में ८,४४२ मील पक्की और ६,२२३ मील लम्बी कच्ची सड़के थीं, जब कि १९५० ई० में क्रमशः ८,२६२ और ६,२१३ मील लम्बी पक्की और कच्ची सड़कें थीं।

प्रथम चरण के कार्यक्रम के अपूर्ण निर्माण-कार्यों के लिए लगभग एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। यह रुपया राज्य की पक्की सड़कों को और अधिक बढ़ाने में उपयोग किया गया।

आलोच्य वर्ष में कोई बड़ा निर्माण कार्य नहीं शुरू किया गया, किन्तु विधान मंडल के सदस्यों के लिए निवास-स्थानों का निर्माण किया गया। लखनऊ के महात्मा गांधी मेमोरियल अस्पताल का विस्तार किया गया और प्रिटिंग प्रेस (लखनऊ) की इमारत पूरी की गई। सहायता तथा पुनर्वासि संबंधी कार्य के सिलसिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बहुत से वार्डर बनवाये और हस्तिनापुर उपनगर के निर्माण का भार भी इसी विभाग पर रहा।

आलोच्य वर्ष में राबर्ट्सगंज के सरकारी सीमेंट के कारखाने का निर्माण कार्य चालू रखा गया और वहाँ बहुत सी इमारतें खड़ी की गईं।

विभाग के गवेषण स्टेशन (Research) ने, जो अब पूर्णरूप से सुसज्जित था, सड़क और इमारतों के निर्माण से संबंधित समस्याओं पर अनुसंधान करना जारी रखा।

२२—परिवहन

वित्तीय कठिनाइयों के कारण रोडवेज सेवाओं का विस्तार प्रायः नगण्य रहा। पिछले वर्ष की तरह वर्तमान सर्विगो के स्थायीकरण और कर्मशाला (वर्कशाप) संगठन को खूब उन्नत करने की ओर विशेषरूप से ध्यान दिया गया। आलोच्य वर्ष में यू० पी० स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट ऐक्ट, १९५० ई० प्रचलित किया गया।

वित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई० के प्रथम ६ महीने में टूट-फूट का खर्च और पूंजी की लागत पर व्याज को सम्मिलित करके कुल खर्च पूरा करने के बाद आमदनी १८,१५,८६० रुपया थी।

मृत्यों के और अधिक बढ़ जाने से गाड़ियों तथा कल-पुर्जों को प्राप्त करने में कठिनाइयाँ होती रहीं। अस्तु, किराये वही चालू रहे जो १९४९ ई० में थे।

पहिले की तरह यह विभाग मुसाफिरो के आराम के लिये यथासंभव सब कुछ करता रहा। बसें निश्चित समय के अनुसार चलती रहीं और समय की अच्छी पाबन्दी की गई।

वर्ष के अन्त में नगर बस सर्विसें लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस और बरेली में चलती रहीं।

वर्ष के अन्त तक रोडवेज के प्रत्येक आठ रीजनो में वर्कशॉप्स के निर्माण का पहिला दौर पूरा किया गया। कानपुर का सेन्ट्रल वर्कशाप बड़ी बड़ी मरम्मतों का सभी काम करता रहा, जिसमें गाड़ियों की बाड़ी बनाने के अतिरिक्त गाड़ियों और बैटरियों की अच्छी खासी मरम्मत सम्मिलित थीं। इस वर्कशाप ने 'धूल से बचने वाली' गाड़ियाँ बनाने, उनकी डिजाइनों तथा उनकी बाड़ी को उन्नत करने का अच्छा काम किया। आटोमोबाइल इंजिनियरिंग में उम्मीदवारों की ट्रेनिंग देने की वह योजना, जिसे १९५० ई० में अंतिम रूप दिया गया था, इस सेन्ट्रल वर्कशाप में चालू की गई।

सरकार की कर्मकारों के कल्याणवर्द्धन की नीति के अनुसार रनिंग स्टाफ के कुछ श्रेणियों के लोगों को यूनिफार्म की व्यवस्था, विशेष भत्तों, इनामों और मानदण्डों की स्वीकृति जैसी विशेष कार्यवाहियों की गई।

इस वर्ष समस्त सरकारी गाड़ियों की जाँच करने की योजना के अन्तर्गत चार टेक्निकल इंस्पेक्टरों की सहायता से एक मोटर वेहिकल्स आफिसर ने काम आरम्भ किया।

रीजनल ट्रान्सपोर्ट आफसरों के अधीन मोटर वेहिकल्स अधिनियमों के केन्द्रीकृत प्रशासन की प्रणाली सफलतापूर्वक चलती रही। टेक्निकल इंस्पेक्टोरेट भी फिटनेस (Fitness) के प्रमाण-पत्र देने में होशियारी से काम करता रहा। मोटर वेहिकल्स ऐक्ट के उपबन्धों को प्रचलित करने का कार्य इंफोर्समेंट स्क्वाड करते रहे।

पावर अलकोहल उद्योग के हित में उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की राशनिंग सितंबर, १९५१ ई० तक जारी रखी गई। वर्ष भर पेट्रोल की सप्लाई संतोषजनक रही।

लखनऊ का हिन्दू प्राविशियल फ्लाइंग क्लब तथा इलाहाबाद और कानपुर में स्थित उसके केन्द्र ए-१ और बी लाइसेंसों के लिये पाइलटों को ट्रेनिंग देते रहे। इस क्लब के तत्वावधान में कानपुर में एक अखिल भारतीय एयर रैली हुई, जिसमें भारत के लगभग सभी फ्लाइंग क्लबों ने भाग लिया। भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने इस क्लब को काफी वित्तीय सहायता दी। राज्य सरकार ने १९५१-५२ ई० के लिये इस क्लब को कुल ५ लाख रुपये दिया।

२३—शिक्षा

पिछले सालों में जितने प्रारम्भिक स्कूल सरकार ने खोले थे और नवम्बर, १९५० ई० में जिला बोर्डों के सिपुर्व कर दिये थे, वे सभी आलोच्य वर्ष में उन्हीं (जिला बोर्डों) के ही अधिकार में रहे। ६ से ११ साल तक की उम्र के लड़कों के लिये ८६ म्युनिसिपैलिटियों में शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त रही तथा २४ नवनिर्मित म्युनिसिपैलिटियों में भी इस व्यवस्था को चालू करने का प्रबन्ध हो रहा था। २३ अनुविद्ध (saturated) जिलों में प्रारम्भिक शिक्षा के लिये काफ़ी सुभीते सुलभ थे और वस्तुतः कुछ जिला बोर्डों के किन्हीं देहाती क्षेत्रों में ऐसी शिक्षा लड़कों के लिये अनिवार्य थी। प्रारम्भिक पाठशालाओं की कुल संख्या दो हजार से ऊपर थी और शिक्षकों तथा पाठकों की संख्या बढ़कर यथाक्रम ७० हजार और ८ लाख हो गई।

८७ अन्य म्युनिसिपैलिटियों में लड़कियों के लिये प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। १० म्युनिसिपैलिटियों और २ जिलों के कुछ भागों में भी यह योजना चालू थी।

रामपुर को छोड़ कर, सभी जिलों में कार्यशील सचल प्रशिक्षक टुकड़ियों (squads) ने नामेल स्कूलों के साथ साथ प्रारम्भिक स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग दी। एच० टी० सी० (H.T.C.) और जे० टी० सी० (J.T.C.) की प्रशिक्षा ११,५०० से अधिक शिक्षकों ने पाई।

जूनियर हाई स्कूलों की पुनर्संगठित नई योजना के अधीन लगभग १ लाख विद्यार्थियों के पहले जल्ये में इस साल परीक्षा दी। विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ती के साथ ही अध्यापन कार्य में भी उन्नति हुई। सामान्य विज्ञान (General Science) की शिक्षा ११२ और स्कूलों में दी जाने लगी, जिससे ऐसे स्कूलों की कुल संख्या ३३७ हो गई। स्कूलों के लिये तीन लाख से अधिक अनुदान दिया गया, ताकि वे सामान्य विज्ञान के अध्यापकों की

तनख्वाहें दे सकें और साज-सामान (furniture equipment) इत्यादि खरीद सके। सात सरकारी नार्मल स्कूलों में, लड़कियों के १२ सरकारी जूनियर हाई स्कूलों में तथा लड़कों के १५ सरकारी आदर्श (Model) स्कूलों में सामान्य विज्ञान की शिक्षा देने के सुभीते के लिये ५० हजार की एक और अनावर्तक (non-recurring) रकम मंजूर की गई। इसके सिवाय इन हर एक सरकारी स्कूलों में उक्त विषय के एक एक अल्प शिक्षक की व्यवस्था की गई। सभी नार्मल स्कूलों में कृषि का विषय अनिवार्य कर दिया गया। लड़कियों के नार्मल स्कूलों में कृषि, विद्या के स्थान पर गृह, कला (House Craft) की शिक्षा दी गई।

लड़कों की १६६ और लड़कियों की १० संस्थाओं में ग्यारहवां दर्जा चालू कर दिया गया। इंटरमीडियेट, कक्षाओं से युक्त और रहित संस्थाओं की यथाक्रम संख्या ५०६ और १,०६० थी। गैर-सरकारी संस्थाओं में अधिक व्यय के कारण भौतिक विज्ञान (Physics), रसायन विद्या (Chemistry), कृषि-विद्या, जीव-विद्या (Biology) और गणित विद्या जैसे विषय आम तौर पर नहीं पढ़ाये गये। इसलिये कुछ सरकारी स्कूलों में इनके पढ़ाने की व्यवस्था की गई। औद्योगिक रसायन विद्या (Industrial Chemistry) और कुम्हारी की शिक्षा देने का प्रबन्ध सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल, इलाहाबाद में किया गया और केवल औद्योगिक रसायन विद्या का बनारस में। उत्तर प्रदेश बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडियेट की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की (बनारस और अलीगढ़ विश्वविद्यालयों तथा प्रयाग महिला विद्यापीठ सरीखी अन्य संस्थाओं की तत्सम परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को छोड़कर) संख्या यथाक्रम १,१०,५८१ और ४१,१०६ थी।

इलाहाबाद, लखनऊ और आगरा विश्वविद्यालयों को कुल २६,०७,६०० रुपये के अनुदान दिये गये। उत्तर प्रदेश के कालेजों और विश्वविद्यालयों के डिग्री और पोस्ट-ग्रेजुएट (उत्तर-स्नातक) दर्जों में छात्रों की संख्या इस वर्ष २६,८२६ थी, जब कि पिछले साल उसकी संख्या २४,१४१ ही थी। ६ नये डिग्री कालेजों को आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने की अनुमति दी गई। ज्ञानपुर और नैनीताल में २ नये डिग्री कालेज खोले गये।

कॉन्स्ट्रक्टिव ट्रेनिंग कालेज (Constructive Training College), जो इलाहाबाद के विभिन्न भवनो में स्थित था, वहाँ से हटाकर लखनऊ में एक ऐसे समुचित सरकारी भवन में बसा दिया गया जहाँ आसानी से उसका विस्तार हो सके। कालेज ने स्नातक और उपस्नातक (Graduates and Under-Graduates), दोनों तरह के शिक्षकों को अध्यापन कला की शिक्षा दी। लखनऊ स्थित सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल के, जो उस (Constructive Training College) की अभ्यासशाला (Practising School) थी, नवे दर्जे में औद्योगिक रसायन विद्या (Industrial Chemistry), कृषि विद्या, जिल्दसजी, ठठरी-शिल्प (Metal Craft), कताई और बुनाई जैसे विषयों को इस साल आरम्भ किया गया।

इलाहाबाद का मनोविज्ञान ब्यूरो (Bureau of Psychology) मनोविज्ञान के संबंध में पथप्रदर्शन करता रहा। उत्तर प्रदेश के पाँचों शिक्षा-क्षेत्रों में एक एक मनोवैज्ञानिक केन्द्र चालू करने के विचार से ५ मनो-विज्ञानविदों और ५ सहायक मनोवैज्ञानिकों को उच्च कोटि के मनोविज्ञान के काल्पनिक और व्यावहारिक पहलुओं की व्यापक (intensive) प्रशिक्षा

दी गई। नौ अनुसन्धान-निबन्ध (Research Papers) भी प्रकाशित किये गये।

इलाहाबाद के सरकारी केन्द्रीय पेडागॉजिकल इंस्टीट्यूट (Pedagogical Institute) ने जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों के लिये गणित विज्ञा, हिन्दी, भूगोल, सामान्य विज्ञान और अंग्रेजी की छोटी पुस्तिकाएं (hand books) भी तैयार कीं। गैर सरकारी सस्थाओं में, जिनमें गर-सरकारी प्रशिक्षण (Training) कालेज भी सम्मिलित हैं, काम करने वाले प्राच्य भाषाओं और हिन्दी के शिक्षकों के लिये उसने 'रिफ्रेशर कोर्स' (Refresher Courses) भी चलाये। इंस्टीट्यूट ने प्रारम्भिक स्कूलों, बेसिक स्कूलों, विज्ञान की शिक्षा, नकशा देखना आदि की पाठ्य पुस्तकों (curriculum) के सबब में पाँडित्यपूर्ण निबन्ध (papers) प्रकाशित किये।

इलाहाबाद के व्यायाम-शिक्षा कालेजर्न, जो राज्य भर में इस प्रकार की एकमात्र संस्था है, आलोच्य वर्ष में ५४ पुस्तकों और १२ महिनाओं की व्यायाम शिक्षण में निपुण बनाया। इलाहाबाद स्थित महिलाओं के लिए गृह-विज्ञान और हस्तकौशल (Home Science and Crafts) के कालेज ने, जो सन् १९४८ ई० में स्थापित हुआ था, १३२ छात्राओं की शिक्षा दी।

इलाहाबाद का 'नर्सरी ट्रेनिंग कालेज', जिसमें अभ्यास के लिये एक नर्सरी स्कूल (शिशु शाला) भी संलग्न है, छोटे बच्चों की शिक्षा देने और सम्भालन की विशिष्ट योग्यता की प्रशिक्षा प्रशिक्षकों को देता रहा, ताकि उनमें (छोटे बच्चों में) अपने भावों को व्यक्त करने की शक्ति और व्यक्तित्व का विकास हो।

समस्त राज्य के देहाती क्षेत्रों में सरकार ने १,३१७ पुस्तकालयों (जिनमें महिलाओं के लिये ४० पुस्तकालय शामिल हैं) और ३,६०० वाचनालयों का प्रबन्ध किया तथा पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं आदि की खरीद के लिये ७५,००० रु० की रकम दी। उपदेशात्मक चल-चित्रों (films) और चल-चित्र पट्टियों (film strips) को बनाने के लिये एक चल-चित्र विभाग (Film Section) भी चलाया गया। चल-चित्र विभाग में देहाती क्षेत्रों, मेलों इत्यादि में प्रस्थापन (publicity) और सुनाने, दिखाने (audio-visual) के कार्य के हेतु प्रोजेक्टरों (projectors), प्रकाश फैलाने वाले यन्त्र, रेडियो-सेटों (radio sets), लाउडस्पीकरों (loudspeakers) इत्यादि से सुसज्जित ५ सिनेमा गाड़ियाँ (cinema-vans) थीं।

शरीर और मन से दुर्बल बच्चों की शिक्षा के लिये कई स्कूलों को चालू रखा गया और नवम्बर, १९५१ में एक नया सरकारी स्कूल बरेली में खोला गया।

उत्तर प्रदेश शिक्षा कोर (Education Corps) और राष्ट्रीय कैडेट कोर (National Cadet Corps) दोनों लुशलता से काम कर रहे। लखनऊ में एक सैनिक प्रदर्शन (Military Rally) भी किया गया था।

शिक्षा-सम्बन्धी तिमाही पत्रिका "शिक्षा" सक्रियतापूर्वक चलती रही और शिक्षा विभाग के कार्यों और अन्वेषणों के प्रस्थापन (publicity) में बहुत सहायक हुई।

अतिरिक्त विद्वत्पूर्ण साहित्यिक तथा वैज्ञानिक कृतियों के लिये ३१ ग्रंथकारों को कुल मिलाकर २५,७०० रु० के पारितोषिक दिये गये। पीडित तथा विषम परिस्थिति के ग्रंथकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

गैरसरकारी शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों की स्थिति में सुधार करने तथा एक स्कूल से दूसरे स्कूल में उनके अनियमित स्थानांतरण को रोकने के अभिप्राय से उनके लिये पहले जो सरकारी वेतन-क्रम (mandatory scales) नियत किये गये थे वे चालू रहे। १९५१ ई० में शिक्षकों को उनकी १० वर्ष की सेवा पर एक वेतन-वृद्धि के हिसाब से (दो वेतन-वृद्धियाँ तक) अग्रिम वेतन-वृद्धियाँ दी गईं। क्षयरोग से ग्रस्त हो जाने की स्थिति में शिक्षकों तथा उनके आश्रितों के लिये चिकित्सालय में रखकर चिकित्सा की व्यवस्था करने के प्रयोजन से शिक्षा विभाग के लिये एक क्षय रोग के चिकित्सालय की योजना प्रारम्भ की गई। उक्त योजना के लिये १५ लाख रुपये की धनराशि इकट्ठा की गई।

उत्तर प्रदेश के ऐसे ऐतिहासिक स्मारकों, स्थलों, भग्नावशेषों इत्यादि की, जिनका कोई राष्ट्रीय महत्व न हो, सामान्य रूप से पड़ताल करने तथा उनकी रक्षा और उनके रख-रखाव में सुभीता करने के अभिप्राय से एक सूची तैयार करने के लिये एक पुरातत्व शास्त्रज्ञ अधिकारी की नियुक्ति की गयी। इस उद्देश्य के लिये ५०,००० रु० की व्यवस्था की गयी।

२४—स्थानीय स्वशासन

आलोच्य वर्ष के अन्त में राज्य में ३५,६१९ गांव सभाएं और ५,४१४ पंचायती अदालतें थीं। पंचायतो, जिन्हें विकास सम्बन्धी कार्यवाहियों में महत्वपूर्ण भाग लेने को कहा गया, क काय में वृद्धि हो जाने के कारण असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसरों की नियुक्ति की आवश्यकता हुई। प्रायः सभी जिलों में पंचायत सेक्टरियों के लिये शिक्षण शिविर खोले गये और उन्हें जो ट्रेनिंग दी गयी उसमें टीके लगाना, (हंजे की) सुइया लगाना, कृषि के उन्नत ढंग, सहकारी समितियों का संगठन इत्यादि करना भी सम्मिलित था। इन ट्रेनिंग पाने वालों ने ट्रेनिंग पाने की अवधि में सड़कों का निर्माण किया, गांव साफ किये और मिलवा खाद रखने के गड्डे बनाये।

पंचायतो ने अपने सोलह-पुत्री कार्यक्रम की ओर समुचित ध्यान दिया और पंचायतघरों और गांधी चबूतरे के निर्माण कार्य पर विशेष जोर दिया गया। इस वर्ष ४६८ पक्के, ६३४ कच्चे पंचायतघर बनाये गये। अन्तर्ग्राम्य व्यापार और यातायात में सुधार करने के लिये पंचायतों ने ६० मील पक्की और १,०२८ मील कच्ची सड़कें बनायीं।

शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य किन्तु लगातार प्रगति रही। पंचायतो ने लड़कें और लड़कियों के लिये ७१० पाठशालाएँ, ६२० प्रौढ़ पाठशालाएँ, १०,८६६ वाचनालय और ५,६३२ पुस्तकालय स्थापित किये और गांव सभाओं के लिये ६६६ रेडियो सेट की व्यवस्था की। इन निकायों ने समय समय पर साक्षरता सम्बन्धी जो आन्दोलन किये उसके परिणामस्वरूप ५८,५७६ पन्च साक्षर बनाये गये।

१०७ मील कच्ची और ३६ मील पक्की गन्दे पानी की नालिया बनायी गयीं और ग्राम्य-स्वच्छता में सुधार करने के उद्देश्य से स्वच्छता आन्दोलन का संगठन किया गया। थोड़ी सी गांव सभाओं ने छोटी-मोटी बीमारियों के लिये औषधियाँ सप्लाई कीं। कुछ जगहों में ग्रामीणों के लाभ के लिये पंचायतों ने स्थानीय वृद्ध और हकीमों की सेवाओं का उपयोग किया। इस वर्ष ७,३३५ लेम्प पोस्ट लगाये गये। कई पंचायतों ने खेल-कूद और शारीरिक सम्बर्द्धन कार्यों में बहुत दिलचस्पी दिखलाई और कई जगहों में खेल के मैदानों की व्यवस्था की गई।

“अधिक अन्न उपजाओ” आन्दोलन के सम्बन्ध में पंचायतो ने १,६३,८८८ बैलवा खाद के गड्डे तैयार किये और कई नाले, नदरे, ताजाब और कुएं बनाये

और इसके अतिरिक्त बहुत बड़े परिमाण में उन्नत प्रकार के बीजों का वितरण किया और गांव के किसानों को ऐसे ढंग अपनाए का प्रोत्साहन दिया जिससे उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिली।

जन्म-मरण के रजिस्टर ठीक से रखे गये और नियन्त्रित वस्तुओं का वितरण सन्तोषप्रद ढंग से किया गया। हरिजन उत्थान और नशाबन्दी की ओर भी ध्यान दिया गया।

पन्चायती अदालतों ने २,७१,९३५ मुकदमों की सुनवाई की। इनमें से ८७,१६८ मामले आपसी समझौते से तय किये गये, १३,०४१ मामलों में पन्चायती अदालतों के निर्णय के खिलाफ अपील करना ठीक समझा गया। तथापि केवल ५,४८४ मामलों में ही नजरसानी की गयी।

म्यूनिसिपैलिटीयों की संख्या ११७ से बढ़कर ११६ हो गयी। वर्ष में बलरामपुर के म्यूनिसिपल बोर्ड को वित्तीय कुप्रबन्धता के कारण अवकांत कर दिया गया और आगरा, मन्सूरी, टांडा, बहराइच, गोरखपुर, लखनऊ और रामपुर की म्यूनिसिपैलिटिया (जो रामपुर राज्य के उत्तर प्रदेश में विलीनीकृत होने के पूर्व भूतपूर्व रामपुर राज्य प्रशासन द्वारा अवकांत कर दी गयी थी) अवकांत रही। हाल के वर्षों में नवस्थापित कुछ म्यूनिसिपैलिटीयों की दशा में प्राचीन टाउन एरिया समिति अथवा नोटीफाइड एरिया समिति म्यूनिसिपैलिटी के कार्यों का सम्पादन करती रही और अन्य म्यूनिसिपैलिटियाँ सम्बन्धित जिला मैजिस्ट्रेट के अधिकार में रही। यू० पी० म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ ई० की धारा ३० की व्यापकता को स्पष्ट करने तथा किसी बोर्ड की अवकान्ति अर्थात् अवधि को बदलने, संशोधित करने या बढ़ाने के विषय में मूल आदेशों में निर्दिष्ट राज्य सरकार के अधिकारों के सम्बन्ध में संदेह दूर करने के लिये १९५० ई० में जो अध्यादेश जारी किया गया था, उसके स्थान पर उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज अनुपूरक अधिनियम, १९५१ ई० बनाया गया।

यू० पी० म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ ई० की धारा ३३६-क में, जैसा कि यू० पी० म्यूनिसिपैलिटीज (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, १९४८ ई० द्वारा निर्दिष्ट की गयी थी, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था थी कि अन्तरवर्ती काल में, जब तक कि उक्त ऐक्ट के अन्तर्गत प्रथम बोर्डों का निर्माण न हो जाय, राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा इस बात का निर्देश कर सकती है कि निर्दिष्ट सीमित अवधि में निर्दिष्ट अनुकलनी, परिवर्तनों तथा संशोधनों की पाबन्दी के साथ उक्त ऐक्ट लागू होगा। हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया कि चूंकि ऐक्ट में अनुकलन, परिवर्तन अथवा संशोधन का अधिकार एक विधायी अधिकार है, अतः इसे राज्य सरकार को नहीं सौंपा जा सकता। तदनुसार किसी मध्यवर्ती कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से यू० पी० म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ ई० में राज्य सरकार द्वारा किये गये अनुकलनों, परिवर्तनों तथा संशोधनों की विधायी स्वीकृति देने के लिये उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज (अनुपूरक तथा वैध) अधिनियम, १९५१ ई० कानून बनाया गया।

म्यूनिसिपैलिटीयों को विभिन्न योजनाओं के लिये ५३,०४,५०० रु० का अग्रिम ऋण दिया गया। इन ऋणों में वे ऋण भी सम्मिलित थे, जो जल-कल के निर्माण कार्यों, विस्थापित व्यक्तियों के लिये गृह-योजनाओं, विद्युत्करण योजनाओं, गन्दे पानी के निकास की नालियों की योजनाओं और लखनऊ में सरकारी कर्मचारियों के लिये बार्डों का निर्माण करने की योजना के सम्बन्ध में थे और इनमें वे ऋण भी सम्मिलित थे जो म्यूनिसिपैलिटीयों को वित्तीय कठिनाइयों

को दूर करने अथवा उनके कर्मचारियों के लिये सशोधित वेतन-क्रम लागू करने की निमित्त दिये गये थे।

विभिन्न म्यूनिसिपल बोर्डों को कुल मिलाकर ३,५६,०६४ रु० के सहायक अनुदान भी दिये गये। ये अनुदान २५,०६,४०० रु० की उस धनराशि के अतिरिक्त थे जो उनको सड़कों के सुधार के लिये उत्तर प्रदेश सड़क कोष से दी गयी थी। राज्य स्वास्थ्य बोर्ड ने नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों और तीर्थ स्थानों की सफाई की दशा में सुधार करने के लिये ५,५०,००० रु० का सहायक अनुदान दिया। शहरी क्षेत्रों में अनाथालयों को भी वित्तीय सहायता दी गयी।

म्यूनिसिपल बोर्ड शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं को राज्य सरकार के आदेशानुसार बढ़ाते रहे। बोर्डों ने शहरी इलाकों में लोक स्वास्थ्य और सफाई में भी सुधार करने के प्रयत्न किये।

संसद और राज्य विधान मंडल के सामान्य निर्वाचनों के कारण १९४४ ई० में म्यूनिसिपल निर्वाचनों के आधार पर बनाये गये। वर्तमान म्यूनिसिपल बोर्डों का कार्यकाल ३१ अक्टूबर, १९५२ ई० तक पुनः बढ़ाना पड़ा। अक्टूबर, १९४८ ई० से बोर्डों का कार्यकाल समय समय पर बढ़ाया जाता रहा और बोर्डों में जो कतिपय आकस्मिक रिक्तियाँ हुईं वे सामान्य निर्वाचनों के निकट होने के कारण भरी नहीं गयीं। किन्तु इस बात को देखते हुए कि आलोच्य वर्ष में इन निर्वाचनों को और स्थगित करना पड़ना, बोर्डों को आदेश जारी किये गये कि वे उप-निर्वाचनों का आयोजन अविलम्ब करें। तदनुसार कई म्यूनिसिपैलिटियों में उपनिर्वाचन किये गये और आकस्मिक जगहें भरी गयीं। किन्तु ये उपनिर्वाचन विस्तृत मताधिकार के आधार पर नहीं किये गये।

रामपुर तथा टेहरी-गढवाब की विलीनीकृत रियासतों में डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का निर्माण आलोच्य वर्ष में स्थगित कर दिया गया और इन क्षेत्रों का विकास कार्य नियोजन समितियों के सुपुर्दे कर दिया गया और उनको क्रमशः १,००,००० रुपये तथा ६०,००० रुपये के अनुदान दिये गये।

उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में अब भी वित्तीय कठिनाइयाँ रही। उनमें से अधिकतर कर्जदार थे और उनके द्वारा किये गये साधारण व्यय उनकी साधारण आय से अधिक थे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अमले को संशोधित वेतनक्रम के अनुसार वेतन देने के लिये १२,१६,६०० रु० का सरकारी ऋण दिये जाने के बावजूद, इस संबंध में बोर्ड पूरे तौर से अपने कर्तव्यों का पालन न कर सके। विभिन्न प्रयोजनों के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को १३,०७,१६६ रुपये के अन्य ऋण तथा अनुदान दिये गये। शिक्षा पर विशेष रूप से व्यय होता रहा, किन्तु यद्यपि परिस्थितियों के अन्तर्गत बोर्डों ने यथासंभव सब कुछ किया, फिर भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त होने को बाकी है। वित्तीय कठिनाइयों के कारण कुछ जिलों में बहुत से प्राइमरी स्कूलों को आलोच्य वर्ष में बन्द कर देना पड़ा।

बहुत से जिलों में डिस्ट्रिक्ट बोर्डों ने बहुत से पुल-पुलियाँ और कच्ची सड़कें बनवाईं। इन निकायों द्वारा व्यवस्थित सड़कों की हालत आमतौर पर अच्छी नहीं थी। कुछ बोर्डों ने कुछ नये स्कूलों के लिये और दूसरी इमारतें भी बनवाईं। सड़कों के सुधार के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को ४,००,००० रुपये के सरकारी अनुदान दिये गये।

सरकारी अनुदानों की सहायता से पहाड़ी जिलों में पाइप लाइन लगाने तथा पानी सप्लाई योजना में और अधिक प्रगति हुई। अन्य बोर्डों ने या तो

नये कुएं बनवाये या जहा-जहां आवश्यक थ, पुराने कुओ की मरम्मत कराई और उनमें सुधार करवाये ।

करो की वसूली सतोषजनक नहीं रही । कर अदा न करने वालों में अधिकतर मजदूर, रेल के कर्मचारी और कुछ विभागों के सरकारी नौकर थे । स्थिति सुधारन के विचार से यह निश्चय किया गया कि इस संबंध में बोर्डों को और अधिक अधिकार दिये जायं । यह मामला भारत सरकार के पास भेजा गया जिससे चिट्ठा बाँटते समय इस प्रकार की वसूली में सुविधा के लिये पेंमेंट आफ़ वेजेज ऐक्ट में उपयुक्त व्यवस्था कर दी जाय ।

अपनी आय के साधनों को बढ़ाने के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्डों ने कुछ मामलों में अत्यधिक दरों पर लाइसेंस फीस लगा दी और आय-कर के किस्म का कर लगा दिया । इन निकायों को इस संबंध में आवश्यक आदेश दिये गये कि वे इस प्रकार के कर न लगाएं, क्योंकि ऐसा करने के वे अधिकृत नहीं थे और दूसरे यह संभावना थी कि उनके ऐसा करने पर अदालतों में आपत्ति की जायगी ।

स्थानीय निकायों की सहायक अनुदान समिति की रिपोर्ट तैयार की गई और वर्ष के अन्त में सरकार उस पर विचार कर रही थी ।

अलीकोट वर्ष में एक नया टाउन एरिया बनाया गया और तीन टाउन एरिया कमेटियां अवकान्त की गईं । जिला नियोजन समितियों ने इन निकायों को इन उपनगरों के विकास के लिये यथासंभव सभी सहायता तथा टेक्निकल सलाह दी । कुछ जिलों में, मुख्यतः वर्तमान सड़कों को पक्का करने, नालियों की प्रणाली में सुधार करने और बाजारों, अस्पतालों, औषधालयों और पुस्तकालयों की उपयुक्त व्यवस्था करने के लिये एक पंचवर्षीय कार्यक्रम चलाया गया । नालियों और सड़कों के सुधार के संबंध में सरकार ने १,०६,८०० रुपये के ऋण तथा अनुदान दिये । पिथौरागढ़ (अल्मोड़ा जिला) और टनकपुर (नैनीताल जिला) टाउन एरियाओं के बीच सरकार द्वारा निर्मित खुले मौसम में चलने वाली सड़क स्थानीय जनता के लिये अधिक सहायक सिद्ध हुई ।

कई टाउन एरियाओं में कुओं को विसर्जित करने, टीका और सुइयों लगाने के लिये उचित व्यवस्था की गयी और कुछ अन्य टाउन एरियाओं में धात्रियों की भी व्यवस्था की गयी । कतिपय टाउन एरिया समितियों ने विशुद्ध पानी की सप्लाई के लिये हाथ से चलाये जाने वाले पम्प लगाये ।

भोलाई में बन्ध का निर्माण कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा था और इस बात की आशा की गयी कि निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर मिर्जापुर में राबर्ट्सगंज टाउन एरिया में पानी की सप्लाई की समस्या हल हो जायगी । कुछ समितियों ने सार्वजनिक सड़कों पर बिजली की रोशनी का भी प्रबन्ध किया ।

२५-जन-स्वास्थ्य

सब बातों को देखते हुये राज्य में लोगों का स्वास्थ्य संतोषजनक रहा और वर्ष में किसी भीषण महामारी का प्रकोप नहीं हुआ । इस उद्देश्य से कि हेजा न फैलने पाये, कुछ प्रमुख मेलों में जाने के लिये अनिवार्य रूप से टीका लगाने की व्यवस्था की गयी और यह उपाय उपयोगी सिद्ध हुआ ।

उत्तर प्रदेश में १२ वर्ष की आयु से कम के अल्प-पोषित तथा कु-पोषित बच्चों और प्रतीक्षिकाओं तथा धात्रियों को निशुल्क वितरण के लिये यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेन्स इमर्जेंसी फंड ने, जो लगभग ४,६०,००० पाँड का मशखन निकाला हुआ दूध का पाउंडर दिया था, उसका पूर्ण उपयोग किया गया । यूनाइटेड नेशन्स इमर्जेंसी फंड ने राज्य में जच्चा-बच्चा केन्द्रों के लिये जच्चा-बच्चा

था शिशु-स्वास्थ्य सबंधी सज्जा और जच्चा-बच्चा उपयोगी औजारों के थैले भी सप्लाई किये। यूनाइटेड नेशन्स आर्गनाइजेशन, नैनीताल तराई में हिमज्वर (मलेरिया) नियंत्रण प्रदर्शन योजना और बी० सी० जी० टीका आंदोलन में, अधिक परिमाण में सप्लाईयो, मोटरगाड़ियो तथा सज्जाओं की व्यवस्था करके, सहायता देता रहा। राज्य सरकार न हिमज्वर नियंत्रण तथा बी० सी० जी० टीका-कार्यक्रमों के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय विशासों के साथ कार्य करने के लिये कई टीमों की व्यवस्था की और उनकी सम्मति के अनुसार क्षय रोग को कम करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से छीका लगाने के लिये फील्ड में काम करने वाले बी० सी० जी० कर्मचारिवर्ग की सख्या में वृद्धि की।

औषधियों के उत्पादन तथा उसकी विक्री पर और कड़ा नियंत्रण रक्खा गया और अन्य राज्यों में उप-प्रमाण की औषधियों के तैयार होने तथा उत्तर प्रदेश में उनके बचे जाने के संबंध में वहां के नियंत्रक अधिकारियों के साथ सम्पर्क बढ़ाया गया।

नवस्थापित इन्डस्ट्रियल हेल्थ आर्गनाइजेशन ने अनेक फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया तथा फैक्ट्रियों में खतरनाक जगहों पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परीक्षा की और कार्य सम्बन्धी परिस्थितियों तथा स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न मामलों में सुधार करने के लिये सिफारिशें कीं। उक्त आर्गनाइजेशन ने पेशे के 'रोगों' से संबंधित परिस्थितियों की ओर भी विशेष ध्यान दिया।

दाइयों के काम तथा धात्रियों के यहाँ रजिस्टर्ड असामान्य रोगियों की परिचर्या पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से ग्रामीण जच्चा-बच्चा केन्द्रों का लगाव अस्पतालों से कर दिया गया।

१९५०-५१ ई० में क्षय रोग की सीलों की विक्री से २,३६,४०० रु० से अधिक इकट्ठा हुआ और यह निणय किया गया कि सरकार, जो धनराशि पहिले ही से दे रही थी, उसके अङ्गिरिक्त यह धनराशि भी स्थानीय क्षय रोग योजनाओं के संबंध में व्यय की जाय। भारत में लोगों को क्षय रोग की शिक्षा देने के उद्देश्य से (अक्टूबर, १९५० ई० में) क्षय रोग की सीलों की विक्री की एक योजना प्रारम्भ की गयी। इस योजना के अधीन प्रत्येक व्यक्ति से १ आना मूल्य की एक सील खरीदन के लिय कहा जाता है और लेन-देन के समय रोग के संबंध में कुछ उपयोगी बातों की सूचना भी दी जाती है।

इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की उत्तर प्रदेश शाखा और लखनऊ के म्युनिसिपल बोर्ड ने मिल कर जनता को गृह-व्यवस्था के संबंध में सुझाव देने के लिये प्रयोगात्मक आधार पर लखनऊ में कार्य प्रारम्भ किया। इस संबंध में राज्य सरकार ने भी १०,००० रु० का एक प्रतीक अनुदान दिया। महिलाओं और पुरुषों के लिये अलग-अलग क्लिनिकों की स्थापना की गयी और वहाँ शरीर तत्व संबंधी बातों तथा गर्भाधान नियंत्रण के सिद्धान्तों की विस्तारपूर्वक व्याख्या की गयी। इन क्लिनिकों में लागत मूल्य पर विक्री के लिय साहित्य तथा सामग्री भी उपलब्ध थी। दिसम्बर, १९५१ ई० के अन्त तक ६ महीने में १,००० से अधिक व्यक्तियों को सुझाव दिया गया। इस योजना को राज्य के दो अन्य बड़े नगरों में प्रसारित करने के लिये निर्णय किया गया।

आबादी के कूड़ा-कुरकट से तैयार की गयी कृषि संबंधी मलवा-खाद में विगत वर्ष के परिमाण से ८ प्रतिशत की वृद्धि हुई। कतिपय प्रारम्भिक कठिनाइयों के कारण कसाई बाड़े की बेकार चीजों से रक्त प्राशित खाद (blood meal manure) तैयार करने की योजना अधिक प्रगति नहीं कर सकी और कानपुर के म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा केवल ३०० मन खाद तैयार की गयी। यह खाद शीघ्र ही बिक गयी।

ग्रामीण स्वास्थ्य के छोटे निर्माण कार्यों के लिये स्टेट हेल्थ बोर्ड द्वारा ५,६०,००० रु० का सहायक अनुदान दिया गया।

हरिजनो के लिये कुएँ बनाने की दशा में और ऐसी योजनाओं की भी दशा में, जहाँ विशेष परिस्थितियों में इस प्रकार की रियायत की आवश्यकता प्रतीत हो, निर्माण कार्य की आधी लागत तक की सहायता देने का सामान्य नियम शिथिल कर दिया गया।

स्टेट हेल्थ कौंसिल की दो बैठके हुई और उन बैठकों में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य प्रशासन, संक्रामक रोगों के अस्पतालों, जैविकीय पदार्थों के प्रमापण तथा चिकित्सा अनुसंधान को प्रारम्भ करने और उस पर नियंत्रण रखने के लिये राज्य सगठन की स्थापना से संबंधित नीति की विभिन्न बातों पर विचार किया गया।

२६—राज्य-राजस्व

१९५०-५१ ई० के बजट में ५ लाख रुपये का अनुमानित बजट ठीक ही निकला, यद्यपि आय तथा व्यय दोनों ही में ३७ लाख रुपये की कमी हुई।

१९५१-५२ ई० के मूल बजट में आशा की जाती थी कि ६,१२६ लाख रुपया आय होगी और ६,१५१ लाख रुपया व्यय होगा और इस प्रकार २५ लाख रुपये की कमी होगी।

१९५१-५२ ई० के संशोधित अनुमान तखमीने में आय घट कर ५,६६५ लाख रुपया हो गयी और व्यय ५,७०६ लाख रुपया। इस प्रकार ४१ लाख रुपये की कमी हुई, जिससे रेवेन्यू रिजर्व फंड से रुपया संकलित करके पूरा किया गया।

मूल बजट में १,६७९ लाख रुपया पूंजी व्यय घटकर संशोधित बजट में १,५३९ लाख रुपया हो गया। यह कमी मुख्यतः इसलिये हुई कि राज्य सरकार ने अमोनियम सल्फेट फैक्टरी के लिये पूंजी की लागत के रूप में ९० लाख रुपये की जो व्यवस्था की थी उसका उद्घोष नहीं किया गया और यह कि सीमेन्ट फैक्टरी प्रोजेक्ट से सम्बन्धित निर्माण कार्यों की प्रगति धीमी रही।

सरकार की आशा थी कि १९५१ ई० में बाजार से ४०० लाख रुपया ऋण मिल जायगा, किन्तु वास्तव में २०३ लाख रुपया ही मिल सका। ५०० लाख रुपये के ट्रेजरी बिलों के जारी करने का पहले जो विचार था वह आवश्यक नहीं समझा गया और तदनुसार कोई ट्रेजरी बिल नहीं जारी किये गये।

२७—आवकारी

शराबबन्दी के सम्बन्ध में राज्य सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यद्यपि आलोच्य वर्ष में इस योजना को और आगे बढ़ाना अच्छा नहीं समझा गया। मद्यनिषेध की प्रगति बढ़ाने के लिये प्रगाढरूप से प्रयत्न किये गये और पैदल सफर का प्रयोग, जिसके द्वारा पिछले वर्षों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुये थे, नये क्षेत्रों में चालू किया गया।

इलाहाबाद और मिर्जापुर जिलों के निर्दिष्ट क्षेत्रों और बुन्देलखण्ड रीजन को छोड़ कर, जहाँ देशी शराब की पहले की दरें बहुत कम थीं और जहाँ शराब अधिक पी जाने लगी, देशी शराब पर महसूल ज्यों का त्यों रहा। ३१ मार्च, १९४९ ई० में अफीम खाना निषिद्ध करने की भारत सरकार की नीति के अनुसार अफीम की निकासी का मूल्य २४० रु० ७ आना प्रतिसेर से बढ़ाकर २८० रु० प्रतिसेर कर दिया गया, जिससे कि उसकी खपत कम हो जाय।

यह अनुमान किया गया कि देशी शराब की खपत १.६ प्रतिशत घट गई और भांग की खपत २.७४ प्रतिशत बढ़ गयी। यह आशा की जाती थी कि अफीम और गांजा की खपत क्रमशः २१.४ प्रतिशत और ४१.४ प्रतिशत गिर जायेगी। अफीम की खपत में कमी की आशा इसलिये की जाती थी कि इसकी निकासी के मूल्य में वृद्धि हो गयी थी और दूसरे यह कि भारत सरकार ने इसका कोटा कम कर दिया था। गांजा की खपत में कमी की आशा इसलिये की जाती थी कि वह बहुत बड़ी तादाद में चोरी से नेपाल से मगाया जाता था। इस प्रकार चोरी से गांजा लाने को रोकने के सम्बन्ध में भारत सरकार ने कार्यवाहियों की। कुल अनुमानित-राजस्व ६६३२० लाख रुपये से घटकर ६४३.६४ लाख रुपये रह गया अर्थात् २.६ प्रतिशत की कमी हो गयी। चालानों की कुल संख्या २४६ प्रतिशत घट गई और उनकी संख्या ८,३१६ रह गयी। इनमें से १,४८४ मुकदमे कच्ची शराब बनाने के थे, जबकि पिछले वर्ष मुकदमों की संख्या २,१११ थी।

१ अप्रैल, १९५१ ई० से डिरेक्ट स्ट्रिट का बिक्री शुल्क १२ आना प्रति बल्क गैलन से बढ़ाकर २ रुपया प्रति बल्क गैलन कर दिया गया। इस वर्ष विदेशी शराब की फुटकर बिक्री की लाईसेंस फीस भी १०० प्रतिशत बढ़ा दी गयी।

उत्तर प्रदेश में नीरा की बिक्री की योजना बनाई गयी और लखनऊ में एक दूकान खोली गई। यह निश्चय किया गया कि इस योजना को अन्य क्षेत्रों में चलाने के पहिले इस शहर में इसका काम देख लिया जाय।

राज्य में भट्टियों की संख्या १६ से बढ़कर १६ हो गई। इनमें से १२ करीब करीब पूर्णरूप से पावर अलकोहल के उत्पादन में लगी हुई थीं। रामपुर जिला और मुरादाबाद जिला के एक भाग को छोड़कर पावर अलकोहल योजना सारे उत्तर प्रदेश में चालू कर दी गयी। आबकारी कमिशनर शीरे के कंट्रोलर के रूप में कार्य करते रहे। चूंकि पावर अलकोहल उद्योग एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्योग है और पावर अलकोहल तैयार करने में शीरा एक मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिये शीरा जमा करने और उसके उपयोग पर प्रभावपूर्ण नियन्त्रण रखना आवश्यक था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण नियम, १९५१ ई० १ दिसम्बर, १९५१ ई० से प्रचलित किया गया। इस सिलसिले में भारी काम को संभालने के लिये कुछ अतिरिक्त अमले की स्वीकृति भी दी गयी।

२८—न्यायालय तथा जेल

आलोच्य वर्ष में कुछ ऐसी आवश्यक कार्यवाहियाँ की गयीं जिससे हाईकोर्ट तथा अधीनस्थ दीवानी अदालतों में मुकदमों का फैसला और जल्दी हो सके और बकाया कामों में कमी हो सके। भारत सरकार ने हाई कोर्ट के लिये जजों की स्वीकृत संख्या २० से बढ़ाकर २४ कर दिया और डिस्ट्रिक्ट तथा सेशन जजों के कैडर को बढ़ाकर ३० से ३७ कर दिया। इस कैडर में रामपुर, एटा और मथुरा में डिस्ट्रिक्ट जजों के तीन पद, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार का एक पद, डिप्टी लोगल रिमेम्बरेंसर का एक पद तथा डिपुटेशन रिजर्व के लिये दो पद सम्मिलित किये गये। यह भी आवश्यक समझा गया कि सिविल और सेशन जज के कैडर को बढ़ा कर १५ से ४५ कर दिया जाय और सिविल तथा सेशन जजों के २५ अस्थायी पदों को स्थायी कर दिया जाय।

एटा और मथुरा में डिस्ट्रिक्ट जजों के दो नये पदों के बन जाने से बहुत दिनों से अलग नयी जजों के लिये जनता की जो मांग थी वह पूरी हो गयी। सिविल तथा सेशन जजों का कैडर बढ़ाने का निश्चय इसलिये किया गया कि

सिविल तथा सेशन जजों के पदों पर अस्थायी रूप से मुन्सिफ बहुत दिनों तक काम करते रहे और मुन्सिफों की जगहों पर जो काम करते रहे उससे उनकी अदालतों में मुकदमों के निपटारे की अवधि बढ़ती जाती थी। सिविल तथा सेशन जजों के पदों पर मुन्सिफों के अस्थायी रूप से काम करने के फलस्वरूप मुन्सिफों के कैंडर में रिक्त स्थानों की पूर्ति अब की जा सकती थी।

सरकार ने यह भी आदेश जारी किये कि सम्मनों की तामील समय पर और शीघ्र हो और नकल शीघ्र दे दी जाय करे। नकल के मुकदमों की कार्यक्षमता बढ़ाने के विचार से विभिन्न जजों के नकल मुकदमों के लिये और अधिक टाईपराइटरों की व्यवस्था की गई और जहाँ आवश्यक था वहाँ नकलनवीसों की संख्या बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया गया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को भी आवश्यक आदेश दिये गये कि नकल देने में जल्दी की जाय और जमानत की दरखास्तें जल्द निपटाई जाय।

इसी बीच जुडिशियल रिफार्म्स कमेटी ने न्याय-व्यवस्था के प्रश्न पर विचार किया। इसके फलस्वरूप कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर में प्रस्तुत की और कार्यविधि में सरलता, अनिवार्यक गवाही को कम करने, विभिन्न वर्गों को अदालतों के सगामि तथा अतिछाही अधिकार-क्षेत्रों को दूर करने के सम्बन्ध में सिफारिशों की। वर्ष के अन्त में यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन रही।

कुमायूं डिवीजन तथा पहिले की आंशिक रूप से पृथक् किये गये क्षेत्रों की विशेष समस्याओं की जांच करने और इन क्षेत्रों की न्याय-व्यवस्था को राज्य के अन्य क्षेत्रों में प्रचलित न्याय-व्यवस्था के स्तर पर लाने की एक योजना बनाने के लिये सरकार ने जो कमेटी नियुक्त की थी, उसने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसकी सिफारिशों पर विचार करना आरम्भ किया गया।

आलोच्य वर्ष में मथुरा और एटा के लिये दो नये जजों के नियुक्त हो जाने के कारण इस राज्य में वर्तमान डिवीजनों की संख्या में दो नये सेशन डिवीजनों की वृद्धि हो गई। बरेली, कुमायूं और लखनऊ सेशन डिवीजनों में अतिरिक्त जिला और सेशन जजों के अस्थायी न्यायालय और राज्य के २६ जिलों में सिविल और सेशन जजों के अस्थायी न्यायालय इस उद्देश्य से स्थापित किये गये ताकि फौजदारी के अधिक कार्य को निपटाने में सुविधा हो सके। इन अस्थायी न्यायालयों ने कुल मिलाकर २४ साल ११ महीने और २३ दिन काम किया, जबकि पिछले वर्ष २५ साल ७ महीने और ६ दिन काम किया था।

मथुरा और आगरा के लिए दो नयी जजों बन जाने के परिणामस्वरूप दीवानी न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र में कुछ परिवर्तन हुए। इस वर्ष २६ स्थायी और ३ अस्थायी जिला जजों के न्यायालय और १५ स्थायी और ३६ दीवानी और सेशन जजों के न्यायालय काम करते रहे। अतिरिक्त जिला जजों की संख्या तीन ही बनी रही। इस वर्ष २३ अतिरिक्त दीवानी जजों के अतिरिक्त दीवानी जजों के ४२ स्थायी तथा २ अस्थायी न्यायालय कार्य करते रहे। ६१ स्थायी और ३ अस्थायी मुन्सिफों के न्यायालय और इसके अतिरिक्त ३३ अतिरिक्त मुन्सिफों के न्यायालय भी कार्य करते रहे। स्थायी स्माल काजेज न्यायालय की संख्या १२ थी जिनमें से २ स्थान रिक्त रखे गये। आलोच्य वर्ष में गांव मुन्सिफ का कोई न्यायालय नहीं था। सिविल जजों ने मुकदमों की पूरी कार्य-

वाहियां करने के बाद कुल २,३३४ नियमित मामले और मुन्सिफों ने कुल २१,१२६ मामले निपटाये। स्माल काजेज कोर्ट ने ८,५१७ मामले निपटाये। इन्सालवेन्सी ऐक्ट के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग ४२ सिविल जजों ने किया। बाराबकी और अल्मोड़ा में अवैतनिक मुन्सिफों के न्यायालय कार्य करते रहे। इन न्यायालयों द्वारा निर्णीत मुकदमों की संख्या ४६४ से घटकर २४७ हो गई। दण्ड विधि संग्रह की अनुसूची १ के आर्डर ५ के नियम ३ के अन्तर्गत व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होने वाले पक्षों की संख्या १०,५५२ से बढ़कर १३,५७१ हो गयी। इसमें से ७,१८६ से पृथक्ताछ की गयी। तामील करने वाले समनो की संख्या बढ़कर ६,६५,५५७ हो गई। जिन समनो को दण्ड विधि संग्रह की अनुसूची १ के आर्डर १६ के नियम ८ के अधीन पक्षों ने स्वतः तामील किया उनकी संख्या बढ़कर २,००,०४६ हो गई।

आलोच्य वर्ष में जेलों की दैनिक औसत आबादी में कुछ कमी हुई। जेलों में अनुशासन तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थिति आमतौर पर संतोषजनक रही। बहुत सी ईमारतों में कुछ आवश्यक सुधार किये गये और ज़नक्री मरम्मत की गई तथा कुछ जेलों में पानी की सप्लाई की व्यवस्था में सुधार किये गये। तीन और जेलों में तथा कुछ क्वार्टरों में बिजली का प्रबन्ध किया गया। बन्दियों को कुछ और अधिक आराम देने तथा सुविधा पहुंचाने के लिये कुछ महत्वपूर्ण सुधार किये गये। अनेक जेलों में बन्दियों के मनोरंजन के लिये नाटको, प्रदर्शनियों तथा सिनेमा की व्यवस्था की गई और तीन जेलों में बन्दियों के लिये जलपान-गृह खोले गये। दैवी विपदाओं के कारण खेती खराब हो गयी, परन्तु जेलों के उद्यानों का रखरखाव बहुत अच्छा रहा। ११ जेलों में खेती के फार्मों की स्वीकृति दी गयी। उद्योगों के सम्बन्ध में आमतौर पर उन्नति हुई।

२९—शान्ति और व्यवस्था

अपराधों की संख्या, जो पिछले वर्ष स्वतन्त्रता प्राप्त करने के समय से १६५० ई० में सबसे कम थी, १६५१ ई० में और भी कम हो गयी। मुकदमा चलाने वाली शाखा का पुनर्संगठन और कुछ जिलों में तफ्तीश करने वाले अमला का वाच एन्ड वार्ड स्टाफ से अलग करने का कार्य वर्ष में पूरा हो गया और पाठ्य विषय समिति की सिफारिशों को जो विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुछ नये विषयों को सम्मिलित करने तथा शिक्षा के उन्नत तरीके इत्यादि के सम्बन्ध में थी और जिनको कार्यान्वित करने में कोई वित्तीय कठिनाई नहीं थी, कार्यान्वित किया गया।

पुलिस में अशिक्षित सिपाहियों की प्रतिशत संख्या को कम करने के सम्बन्ध में निश्चित कार्यवाही की गयी। इसके फलस्वरूप सम्पूर्ण पुलिस की संख्या में से अशिक्षित सिपाहियों की संख्या करीब १४ प्रतिशत कम हो गयी। तफ्तीश विभाग ने और उन्नति की।

विभिन्न सम्प्रदायों के पारस्परिक सम्बन्ध प्रायः काफी अच्छे रहे और प्रत्यक्षरूप से उनके बीच मनमुटाव के कोई कष्टदायक लक्षण दृष्टिगोचर नहीं हुए। सीमा के उस पार देश में युद्धोन्माद के प्रदर्शन की इस देश में बहुत कम गम्भीर मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया हुई। हां, मुसलमान सम्प्रदाय के एक छोटे से वर्ग में कुछ घबड़ाहट अवश्य थी और यह रिपोर्ट मिली कि

यह घबड़ाहट उन पत्रों के कारण और भी बढ़ गयी जो पाकिस्तान में रहने वाले उनके मित्रों या रिश्तेदारों ने भेजी थी तथा जिनमें उन्होंने युद्ध अवश्यम्भावी बताकर मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाने के लिये लिखा था। लगभग सभी बड़े और छोटे त्योहार शान्तिपूर्वक बीत गये और कुछ जगहों पर होली तथा ईद के अवसरो पर विभिन्न सम्प्रदायों के लोग आपस में भ्रातृ भाव से मिले। साम्प्रदायिक किस्म की घटनाएं होली में एक बार बरेली जिले में और मुहर्रम के मौके पर बाराबंकी तथा बहराइच जिलों में हुई। इन घटनाओं के सम्बन्ध में अधिकारियों ने तुरन्त और प्रभावपूर्ण ढंग से कार्रवाई की। स्थानीय महत्व के मामलों जैसे चोरी से पशु वध करना, मस्जिद के सामने बाजा बजाना आदि के सिलसिले में समय समय पर अलग अलग जगहों में जो तनज़नी दृष्टिगोचर हुई उसके सम्बन्ध में भी अधिकारियों ने इसी प्रकार तुरन्त ही और प्रभावपूर्ण ढंग से कार्रवाई की। आलोच्य वर्ष बड़ी ही शान्ति के साथ बीता तथा लोगों में मेलजोल रहा और राज्य में आम चुनाव के पहिले स्थिति पिछले आम चुनाव की तुलना में बहुत ही संतोषप्रद थी। पिछले आम चुनाव में तो उत्तर प्रदेश एक प्रकार से साम्प्रदायिक उन्माद का क्रीड़ास्थल बन गया था।

भाग २

विस्तृत अध्याय

अध्याय १—सामान्य प्रशासन और स्थिति

१९५१ ई० में सरकार के सदस्यगण

सुहामान्य श्री हारमस जी पेरोशा मोदी इस वर्ष भी राज्यपाल के पद पर कार्य करते रहे ।

इस वर्ष मन्त्रि परिषद् के सदस्यों में कुछ परिवर्तन हुए । वर्ष के प्रारम्भ में माननीय मुख्य मन्त्री सहित मन्त्रियों की संख्या १० थी । ४ जन, १९५१ ई० को माननीय मुख्य मन्त्री के सभा सचिव श्री चरण सिंह मन्त्रि परिषद् के सदस्य के रूप में सम्मिलित किये गये । इस प्रकार मन्त्रिमंडल में मन्त्रियों की संख्या बढ़कर ११ हो गई । अगस्त के प्रारम्भ में माननीय श्री केशवदेव मालवीय और माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी के पद रिक्त हो गये और तदुपरान्त उसी महीने में श्री अली जहीर और सभासचिव श्री हरगोविंद सिंह मन्त्रि परिषद् के सदस्यों के रूप में सम्मिलित किये गये और उन्हें क्रमशः (क) न्याय और श्रम तथा (ख) उद्योग और सहयोग विभाग दिये गये । अक्तूबर में माननीय श्री लाल बहादुर ने, जिनके पास पुलिस और परिवहन विभाग थे, अपना मन्त्रिपद रिक्त कर दिया और माननीय शिक्षा मन्त्री ने पुलिस विभाग और माननीय माल मन्त्री ने परिवहन विभाग का कार्य संभाला । इन प्रबन्धों के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री ने वित्त विभाग का काम संभाला और अन्य माननीय मंत्रियों के कार्य विभागों का भी फिर से निर्धारण हुआ । वर्ष के अन्त में मन्त्रिमंडल के सदस्य और उनमें से प्रत्येक के कार्य-विभाग (पोर्टफोलियो) निम्नलिखित थे :—

क्रम- संख्या	माननीय मन्त्री के नाम	वैभागिक कार्य-विभाग (पोर्टफोलियो)
१	माननीय प० गोविंद वल्लभ पन्त, विधान सभा के सदस्य, मुख्य मन्त्री	सामान्य प्रशासन तथा वित्त
२	माननीय हाफिज मोहम्मद इब्नाहीम, वि० स० स०	यातायात
३	माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द, वि० स० स०	शिक्षा तथा पुलिस
४	माननीय श्री हुकुम सिंह, वि० स० स०	माल, वन और परिवहन
५	माननीय गिरधारी लाल, वि० स० स०	आबकारी, जेल, रजि-स्ट्रेशन, स्टाम्प और हरिजन सहायक

क्रम- संख्या	माननीय मंत्री के नाम	वैभागीक कार्य-विभाग (पोर्टफोलियो)
६	माननीय श्री आत्माराम गोविंद खेर, वि० स० स०	स्वशासन
७	माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त, वि० स० स०	स्वास्थ्य और रसद (सिविल सप्लाइज)
८	माननीय श्री चरण सिंह, वि० स० स०	कृषि, पशुपालन तथा सूचना
९	माननीय श्री सैयद अली जहीर, वि० प० स०	न्याय तथा श्रम
१०—	माननीय श्री हरगोविंद सिंह, वि० प० स०	उद्योग तथा सहकारिता

अगस्त, १९५१ ई० में माननीय मुख्य मंत्री के सभा सचिव, श्री जगन प्रसाद रावत, ने त्यागपत्र दिया। तदनन्तर सितम्बर में श्री जगमोहन सिंह नेगी, वि० स० स० को माननीय मुख्य मंत्री का सभा सचिव नियुक्त किया गया।

इस वर्ष के अन्त में निम्नलिखित सभा सचिव अपने अपने पद पर कार्य करते रहे—

(१) श्री मंगला प्रसाद, वि० स० स०	} माननीय मुख्य मंत्री से सम्बद्ध
(२) श्री जगमोहन सिंह नेगी, वि० स० स०	
(३) श्री लताफत हुसैन, वि० स० स०	} माननीय यातायात मंत्री से सम्बद्ध
(४) श्री वहीद अहमद, वि० प० स०	

२—प्रशासकीय कायवाहियां

कानून तथा
व्यवस्था

इस वर्ष इस राज्य में सामान्य आपराधिक स्थिति संतोषजनक रही और विधि तथा व्यवस्था की दृष्टि से इस राज्य में अपेक्षाकृत अधिक शान्ति बनी रही। बरेली जिले में होली के अवसर पर दोनों जातियों में मुठभेड़ हो गई और हाासी म दगा हो गया, जिनके संबंध में पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी। ये ही दो घटानाएँ उन थोड़ी सी घटनाओं में से थी जिनके कारण सार्वजनिक शान्ति भंग हुई। इस वर्ष की एक सर्माचीन और उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि बहूत सी दशाओं में गाँव के लोगों ने डाकुओं का सामना किया और कानून भंग करने वालों को पकड़वाने में पुलिस की सहायता की। कुख्यात डाकुओं के गिरावों को भग करने में भी पर्याप्त सफलता मिली।

नपाल की
स्थिति

भारतीय सेना की सहायता करने के लिये, जो नेपाल सरकार की प्रार्थना पर भारत सरकार ने सीमा पार के आतंकवादी तत्वों का सामना करने के

लिये भेजी थी, प्रांतीय सशस्त्र पुलिस दल को आदेश दिया गया। नेपाल सेना के साथ फरवरी में कार्यवाहियाँ प्रारम्भ की गयी और बहुत से कानून भंग करन वालों को उनके नेता डा० के० आई० सिंह के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जुलाई में प्रांतीय सशस्त्र पुलिस दल के यूनिटों को डा० के० आई० सिंह की, जो नेपाल में पुलिस की हिरासत से निकल भागे थे, फिर से पकड़ने की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में नेपाली सेना की सहायता करने के लिये बुलाया गया।

प्रिवेन्टिव डिटेन्शन (अमेन्डमेंट) ऐक्ट, १९५१ के बन जाने से केन्द्रीय प्रिवेन्टिव डिटेन्शन ऐक्ट, १९५० (निवारक निरोध अधिनियम) एक साल के लिये और बढ़ गया। उसकी प्रक्रिया में भी कुछ परिवर्तन किये गये और मूल अधिनियम के उपबन्धों को नजरबन्दों के पक्ष में और अधिक उदार बना दिया गया। सशोधित अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि नजरबन्दी के सब मामलों को ऐसे एडवाइजरी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें तीन सदस्य हों और उनमें से सब के सब न्यायाधीश होने चाहिए। इस राज्य में उक्त बोर्ड में दो हाई कोर्ट के न्यायाधीश और एक जिले के न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) थे। इस वर्ष के प्रारम्भ होने के समय विचाराधीन मामलों की संख्या ५ थी और वर्ष के भीतर एडवाइजरी बोर्ड (परामर्शदात्री बोर्ड) के पास ४५ मामले भेजे गये। उक्त बोर्ड ने ३२ मामलों में नजरबन्दी के आदेशों का अनुमोदन किया और १६ मामलों में ये आदेश बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर निरस्त किये गये।

कानूनों का निर्माण

१९५० ई० के अन्त में यू० पी० में सार्वजनिक शांति बनाये रखने का (रद्द करने) विधेयक, १९५० ई० को विधान मंडल में प्रस्तुत किया गया और जनवरी में पारित किया गया। इस अधिनियम को रद्द करके सरकार ने स्वेच्छा से ऐसे कुछ विशेष अधिकारों को छोड़ दिया, जो उसे विभाजन के बाद के उद्देगकारों दिनों में साम्प्रदायिकताजन्य संकट को निवारण करने के लिये ग्रहण करने पड़े थे।

इस वर्ष जिला अधिकारी डिवीजनों के कमिशनरो, भूमि-व्यवस्था कमिशनर तथा माल बोर्ड के कामों को फिर से निर्धारित करने की एक नई योजना के अनुसार महत्वपूर्ण प्रशासकीय परिवर्तन किये गए।

माल बोर्ड
डिवीजनों के
कमिशनरों
तथा भूमि-
व्यवस्था
कमिशनर
(लैंडरिफार्म
कमिशनर) के
कार्यों का
पुनर्संरगठन

इस योजना के प्रचलित होने से पूर्व जिला अधिकारी जिला प्रशासन के विषय में डिवीजन के कमिशनरो और माल बोर्ड द्वारा सरकार से सम्बद्ध थे। इस प्रणाली के अनुसार काम को निपटाने में दोहरी कार्यवाही करनी पड़ती थी और देर भी लगती थी। इससे यह अनुभव किया गया कि जिला प्रशासन का उत्तरदायित्व पूर्णतः जिला अधिकारियों से ही निहित होना चाहिए न कि उनके और सरकार के बीच के मध्यवर्ती और उनमें युग पद या संयुक्त रूप से। जिला अधिकारियों को स्थल के आसन्न अधिकारियों के रूप में दिन-प्रति दिन के मामलों को निपटाने के लिये पूर्णतः उत्तरदायी बनाने और ऐसे मामलों में कमिशनरो और माल बोर्ड को उनके दायित्व से मुक्त करने और बाद के इन दोनों प्राधिकारियों को माल की अदालतों के काम का निरीक्षण और जिले का सामान्य प्रशासन तथा अपील और पुनरीक्षण के न्यायालय के काम

सौंपने के प्रश्न पर अन्ततः विचार प्रारंभ किया गया। इस प्रश्न पर भली प्रकार से विचार करने के बाद सितम्बर, १९५१ ई० में एक योजना बनायी गयी और उसके सम्बन्ध में उसी महीने में जारी की गई आज्ञाओं द्वारा उसे कार्यान्वित किया गया।

(१) सित-
म्बर, १९५१
ई० तक की
स्थिति

किये गये परिवर्तनों को उपयुक्त रूप से समझने के लिये यह आवश्यक है कि इन आज्ञाओं से प्रभावित होने वाले प्राधिकारियों द्वारा सितम्बर, १९५१ ई० तक किये गये कामों और प्रयोग किये गये अधिकारों को ध्यान में रखा जाय।

१९२२ ई० से पूर्व माल बोर्ड रेवेन्यू ऐक्ट, टेनेन्सी ऐक्ट और अन्य सम्बद्ध अधिनियमों के अधीन उच्चतम न्यायाधिकरण के रूप में काम करता था जिसके सामने कमिश्नरों की आज्ञाओं तथा डिगिरियों के विरुद्ध अपीलें और पुनरीक्षण किये जा सकते थे और कमिश्नर अपने स्थान पर कलेक्टरों और प्रथम श्रेणी के असिस्टेंट कलेक्टरों से ऊंचे न्यायालय थे। माल बोर्ड को विशेषतः भू-राजस्व-प्रशासन के क्षेत्र में और कोर्ट आफ वार्ड्स बन्दोबस्त तथा स्टाम्प के विषय में प्रशासन, पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण के विस्तृत अधिकार भी दिये गये थे। इन मामलों में कमिश्नरों का सरकार के साथ सीधा सम्बन्ध न होकर माल बोर्ड के द्वारा था।

बोर्ड आफ रेवेन्यू अमेंडमेंट ऐक्ट, १९२२ ई० ने माल बोर्ड को कोर्ट आफ वार्ड्स के प्रशासन से सम्बद्ध मामलों को छोड़ कर उसके सभी कार्यकारी अधिकार से वंचित करके उसे मुख्यतः एक न्यायिक निकाय (Judicial Body) में परिवर्तित कर दिया। अब कमिश्नरों का, जो पहले राजस्व प्रशासन के मामलों में माल बोर्ड के अधीन वस्तुतः प्रादेशिक अधिकारी थे, सरकार के साथ सीधा सम्पर्क हो गया।

१९३२ ई० में कार्यकारी आज्ञाओं के द्वारा कुछ मामलों में बोर्ड की कार्यकारी अधिकार दुबारा दिये गये। राजस्व प्रशासन सम्बन्धी विशेषतः भू-अभिलेख, तकावी और सरकारी आस्थानों जैसे गैर-अदालती किस्म के कुछ मामले माल बोर्ड को फिर से दे दिये गये। इस प्रकार से वह फिर सरकार और जिला अधिकारियों के बीच के काम निपटाने के सम्बन्ध में दो मध्यवर्तियों में से एक का प्रतिनिधित्व करने लगा। कोर्ट आफ वार्ड्स एक स्वतन्त्र निकाय के रूप में स्थापित किया गया। डायरेक्टर आफ लैंड रिकार्ड्स (भू-अभिलेख-संचालक) का पद तोड़ दिया गया और माल बोर्ड भू-अभिलेख-संचालक के रूप में प्रस्थापित किया गया। इस प्रकार माल बोर्ड अपने प्रशासकीय क्षेत्र में प्रायः विभागाध्यक्ष के रूप में काम करने लगा और कमिश्नर कुछ मामलों को छोड़कर, जिनमें वे सरकार से सीधे ही पत्र-व्यवहार करते थे, अधिकांश मामलों में बोर्ड के द्वारा ही सरकार से पत्र-व्यवहार करने लगे।

१९५७ ई० में सत्ता हस्तान्तरण के साथ ही माल बोर्ड के विधान तथा कर्तव्यों में आमूल परिवर्तन हो गया। बोर्ड के सीनियर मेम्बर के पद का नाम ऐडमिनिस्ट्रेटिव मेम्बर रखा गया और उसे सभी प्रशासकीय मामलों की देखरेख करनी पड़ती थी। कानूनी मामलों को निपटाने के लिये बोर्ड के अस्थायी जूडिशियल मेम्बरों की नियुक्ति की गई। कृषि-आयकर अधिनियम (Agricultural Tax Act) के पास हो जाने पर माल बोर्ड को इस अधिनियम का प्रशासन भी सौंप दिया गया।

डिवीजनो के कमिश्नरों के सम्बन्ध में यह निश्चित किया गया कि उन्हें अपील सम्बन्धी अदालती काम से मुक्त कर दिया जाय और १९४२ ई० से एडीशनल (अतिरिक्त) कमिश्नरों के पद बनाये गये। अगस्त, १९४७ ई० के बाद डिवीजनों के कमिश्नरों की संख्या १० से घटाकर ५ कर दी गई और प्रत्येक कमिश्नर के अधीन दो-दो माल की डिवीजनें रख दी गयीं।

जमींदारी विनाश की योजना के सूत्रपात के बाद भूमि-व्यवस्था कमिश्नर की अध्यक्षता में एक पृथक् संगठन बनाया गया।

सितम्बर, १९५१ ई० में विभिन्न प्राधिकारियों के प्रमुख कर्तव्य फिर से नियत किये गये जिनका व्योरा नीचे दिया जाता है :—

सितम्बर, १९५१ ई० से पूर्व की भांति माल बोर्ड के दो भाग होंगे। एक भाग में प्रशासकीय सदस्य (एडमिनिस्ट्रेटिव मेम्बर) होगा और दूसरे भाग में न्यायिक सदस्य (जुडिशियल मेम्बर) होंगे। प्रशासकीय सदस्य (एडमिनिस्ट्रेटिव मेम्बर) का नियन्त्रण कमिश्नरों, जिला अधिकारियों, संयुक्त मैजिस्ट्रेटों (ज्वाइंट मैजिस्ट्रेटों), डिप्टी कलेक्टरों तथा अधिकारियों पर होगा। कमिश्नर प्रशासकीय अधिकारी तथा माल सम्बन्धी अपीलों की अदालत दोनों रूपों में सीधे उसके अधीन रहेगा। वह सरकार की ओर से यह सुनिश्चित करने के लिये एक एजन्सी की व्यवस्था करेगा कि जिले के कार्यालयों में प्रशासन का दैनिक कार्य कुशलता के साथ चलता रहे और यह कि जिले के अधिकारी और उनका अमला आचरण तथा कार्य सम्बन्धी नियमों का उन आदेशों के अनुरूप पालन करें जिनकी उनसे आज्ञा की जाती है। उसके निदेशानुसार प्रत्येक कमिश्नर जिला कार्यालयों तथा अपन क्षेत्राधिकार की अदालतों का निरीक्षण करने के लिये उत्तरदायी होगा। समय समय पर निरीक्षण करके प्रशासकीय सदस्य (एडमिनिस्ट्रेटिव मेम्बर) इस बात को सुनिश्चित कर देगा कि कमिश्नर उचित तथा बर्पास्त निरीक्षण-कार्य करते हैं। वह प्रत्येक वर्ष कमिश्नरों द्वारा किये गये काम के सम्बन्ध में भी रिपोर्ट भेजेगा। प्रशासकीय कर्तव्यों के अतिरिक्त वह विभिन्न अधिनियमों द्वारा प्रदत्त माल बोर्ड के पूरे अधिकारों का भी प्रयोग करेगा। बोर्ड के न्यायिक सदस्य (जुडिशियल मेम्बर) पूर्ववत् केवल माल सम्बन्धी अपीलों को ही सुनवाई करेंगे और वे कोई भी प्रशासकीय कार्य नहीं करेंगे।

(२) सित-
म्बर, १९५१
ई० में किये
गये परिवर्तन
(क) माल
बोर्ड

प्रशासकीय सदस्य (एडमिनिस्ट्रेटिव मेम्बर) के निदेशानुसार कमिश्नर अपने अधिकार क्षेत्र के तहसीलदार के स्तर से ऊंचे जिले के कार्यालयों तथा अदालतों के निरीक्षण के लिये उत्तरदायी होगा। वे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों, इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तथा प्राविशियल सिविल सर्विस के अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों के सम्बन्ध में बोर्डों के प्रशासकीय सदस्य (एडमिनिस्ट्रेटिव मेम्बर) के पास अपनी वार्षिक गुप्त रिपोर्टें सरकार के पास अप्रसारित करने के लिये भेजेंगे। विधि तथा नियमों में तद्विषयक व्यवस्था होने पर, कमिश्नर ऐसे मामलों की, जो उनके पास आये, अपीलों तथा पुनरीक्षणों की सुनवाई करता रहेगा। स्वयं कमिश्नर द्वारा दी हुई आज्ञाओं के विरुद्ध अपीलें तथा पुनरीक्षण आजकल की तरह, माल बोर्ड को किये जायेंगे। यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट तथा यू० पी० इनकम्बर्ड स्टैट्स ऐक्ट के अधीन होने वाली अपीलों, जैसा न्यायिक

(ख) डिवी-
जनों के
कमिश्नर

माल-कार्य, जो आजकल एडीशनल कमिश्नरों द्वारा किया जाता है, धीरे धीरे कमिश्नरों के हाथ में वापस चला जायगा। कमिश्नर स्थानीय निकायों से सम्बन्धित अपने कार्यभार से यथासंभव मुक्त कर दिये जायेंगे और वह अब नियत प्राधिकारियों के हाथ में चला जायगा। आर्म्स ऐक्ट और उसके अधीन बने नियमों तथा पुलिस विनियमों से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में कमिश्नर का काम अब जिला अधिकारियों द्वारा किया जायगा। कमिश्नरों का जेल प्रशासन सम्बन्धी कार्यों और एक्साइज मैनुअल के अधीन व उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों से अब कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा। सरकारी अपीलें दायर करने के सम्बन्ध में जिला अधिकारियों द्वारा की गई सिफारिशों की छानबीन करने के काम से भी वे मुक्त कर दिये जायेंगे। कोर्ट आफ वाट्स मैनुअल के अधीन सभी मामलों में कोर्ट आफ वाट्स कमिश्नरों के द्वारा कार्यवाही करने के बजाय सीधे ही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से व्यवहार करेगा। मालगुजारी का निर्धारण, उसकी वसूली और उसमें छूट, नहर-कर तथा अन्य विविध करों की वसूली सम्बन्धी राजस्व प्रशासन के कुछ कार्य, जो अब तक कमिश्नरों द्वारा किये जाते थे, अब भूमि-व्यवस्था कमिश्नर द्वारा किये जायेंगे। सरकारी आस्थानों के प्रबन्ध से सम्बद्ध मामलों में कमिश्नर निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण के कार्यों से मुक्त कर दिया जायगा।

(ग) भूमि-
व्यवस्था
कमिश्नर

भूमि-व्यवस्था कमिश्नर निम्नलिखित कार्य करेंगे :—

(क) रेवेन्यू मैनुअल (अध्याय १ से ८ तक) में उल्लिखित पर्यवेक्षण सम्बन्धी कार्य;

(ख) नहर-कर तथा अन्य विविध करों की वसूली का पर्यवेक्षण;

(ग) सरकारी तथा कुर्क किये हुए आस्थानों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में जिला अधिकारियों द्वारा सरकार को भज हुए कागजों के सम्बन्ध में कार्रवाई;

(घ) भू-अभिलेख सचालक के रूप में काम;

(ङ) प्रादेशिक परिवर्तनों (territorial changes) बटवारों, चक्र-बन्दियों, दाखिल खारिजों, पैमाइशों तथा बन्दोबस्तों के सम्बन्ध में कार्य, और

(च) तहसीलदारों तथा नायब-तहसीलदारों के सम्बन्ध में ऐसे कार्य, जो पहले डिवीजनो के कमिश्नरों द्वारा किये जाते थे।

उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (यू० पी० हायर जुडिशियल सर्विस) के पदों के लिये भर्ती करने और उक्त पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में नियम बनाने का काम प्रारम्भ किया गया और उसकी प्रगति संतोषप्रद रही। वर्ष के अन्त में नियमों पर अन्तिम रूप से विचार किया जा रहा था। इस वर्ष उस समय तक के लिये जब तक कि इन नियमों को अन्तिम रूप न दे दिया जाय, इस सेवा के अधिकारियों का वेतन तदर्थ स्वीकृत वेतन के टाइम-स्केल में नियत करने की रीति के सम्बन्ध में कुछ आज्ञायें जारी की गई थीं। इस सेवा के सदस्यों (केडर) की संख्या भी नियत की गई। नई सेवा में सम्मिलित डिस्ट्रिक्ट तथा सेशन जजों के ३० स्थायी पदों और सिविल तथा सेशन जजों के १५ स्थायी पदों में, डिस्ट्रिक्ट तथा सेशन जजों के ७ अतिरिक्त पद और सिविल तथा सेशन जजों के ३० और पद, जिनमें से अधिकांश अस्थायी रूप से चल रहे थे बढ़ा दिये गये। १ जुलाई, १९५१ ई० से उत्तर प्रदेश उच्चतम न्यायिक सेवा (यू० पी० हायर जुडिशियल सर्विस) के सदस्यों (केडरों) की संख्या,

जिसमें मथुरा, एटा, रामपुर के तीन नये जजों के पद भी सम्मिलित हैं, निम्न प्रकार से निश्चित की गयी थी :—

डिस्ट्रिक्ट तथा सेशन जज	३७
सिविल तथा सेशन जज	४०
छुट्टियों के लिये सुरक्षित	..	.	५
योग	८२

उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (यू० पी० हायर जुडिशियल सर्विस), डिस्ट्रिक्ट तथा सेशन जजों के पदों की पूर्ति के प्रयोजन से, जो पहले इंडियन सिविल सर्विस के यू० पी० केडर में सम्मिलित थे, १९४९ ई० में प्रचलित की गई थी और १५ अगस्त, १९४७ ई० से ही सप्रभाव हो गयी थी। उस समय ८००-५०-१,०००-६०-१,३००-५०-१,८०० रुपये का अस्थायी वेतन-क्रम अर्थात् इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का उच्च वेतन-क्रम नई सेवा में आने वाले डिस्ट्रिक्ट तथा सेशन जजों के पदों पर काम करने वालों के लिये स्वीकृत किया गया था।

नई सेवा की रचना से पूर्व अर्थात् १४ अगस्त, १९४७ ई० तक डिस्ट्रिक्ट तथा सेशन जजों के सब पद, जिनकी संख्या ३० थी जिसमें यू० पी० सिविल सर्विस (जुडिशियल ब्रांच) के अधिकारियों की पदोन्नति के लिये सुरक्षित ९ पद और सिविल तथा सेशन जजों के १५ स्थायी पदों में से ४ पद सम्मिलित थे, इंडियन सिविल सर्विस के यू० पी० के केडर पर आधारित हुआ करते थे और सिविल तथा सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट तथा सेशन जज के पदों पर नियुक्त किये जाने वाले सिविल सर्विस (जुडिशियल ब्रांच) के अधिकारियों को क्रमशः इंडियन सिविल सर्विस के छोटे और बड़े वेतन-क्रमों के अनुसार वेतन दिया जाता था। १५ अगस्त, १९४७ ई० से इंडियन सिविल सर्विस तोड़ दी गई और उसके स्थान पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रखी गई, किन्तु भारत सरकार ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के केडर में कोई न्यायिक पद न रखने का निश्चय किया। उन्होंने राज्य सरकार के राज्य की न्यायिक सेवा (Judicial Service) को पूर्ण रूप से प्रांतीय सेवा बना लेने का परामर्श दिया और तदनुसार उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (यू० पी० हायर जुडिशियल सर्विस) अस्तित्व में आई।

अबध चीफ कोर्ट के इलाहाबाद हाईकोर्ट में मिल जाने पर सरकार ने यह निश्चय किया कि यू० पी० सिविल सर्विस (न्याय शाखा) के दोनों अबध तथा आगरा के कैंडरों को मिला कर एक कर दिया जाय। इस वर्ष उक्त दोनों कैंडरों के अधिकारियों की अपारस्परिक ज्येष्ठता को कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार इस एक प्रस्तावित कैंडर में निर्धारित करने का प्रश्न सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन रहा।

यू० पी०
सिविल सर्विस
(न्याय शाखा)

यू० पी० सिविल सर्विस (न्याय शाखा) के सम्बन्ध में भर्ती करने के विषय पर सरकार ने विभिन्न स्थानों से प्राप्त इस आशय के सुझावों को स्वीकार कर लिया कि इस सम्बन्ध में अपेक्षित अर्हता में विधि की उपाधि (ला की डिग्री) के साथ-साथ कम से कम कुछ समय तक का वकालत का अनुभव भी सम्मिलित

हो। मुंसिफो की भर्ती के लिये अब तक नियमों में विधि की उपाधि की ही अर्हता नियत की गई थी। अब यह निश्चय किया गया है कि भविष्य में उक्त सेवा में भर्ती होने के लिये प्रार्थना-पत्र देने वालों के लिये यह आवश्यक होगा कि उन्होंने वस्तुतः कम से कम ३ वर्ष तक बकालत की हो। भर्ती के सम्बन्ध में अधिकतम आयु की सीमा २७ वर्ष से बढ़ा कर २८ वर्ष कर दी गई है।

इस वर्ष कुछ और परिवर्तन करने का भी निश्चय किया गया है। यू० पी० सिविल सर्विस (न्याय शाखा) के पदों पर नियुक्त तथा उसके सदस्यों की सेवा की शर्तों से सम्बद्ध दो नियमावलियों का संशोधन किया गया और उनको मिलाकर एक ही नियमावली बनाई गई और यह आज्ञा दी गई कि यह नियमावली बाद में निश्चित किये जाने वाले किसी दिनांक से लागू की जाय। ऊपर के अनुच्छेदों में वर्णित उपबन्धों के अतिरिक्त निम्नलिखित उपबन्ध संशोधित नियमावली की मुख्य विशेषताये हैं :—

(१) यू० पी० सिविल सर्विस (न्याय शाखा) में केवल मुंसिफ और सिविल जज के पद ही रहेंगे, क्योंकि सिविल तथा सेवान्स जज के पद अब उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (यू० पी० हायर जुडिशियल सर्विस) के कैंडिडेटों में हैं।

(२) इस सेवा में भर्ती होने के लिये महिलाये भी पात्र होगी।

(३) इस सेवा का वेतन क्रम ३५०-३५०-३७५-२५-४००-प्रगुणता अगल-३०-७००-प्रगुणता अगल-५०-८५० रु० होगा।

न्यायिक
अधिकारी

सरकार ने न्यायिक अधिकारियों के ६० पदों को १ अप्रैल, १९५१ ई० से स्थायी करने का निश्चय किया था और पब्लिक सर्विस कमीशन से इस राज्य के सभी न्यायिक अधिकारियों का सदृशन करने के लिये और उनमें से स्थायीकरण के निमित्त ६० व्यक्तियों को चुनने के लिये प्रार्थना की गई थी। कमीशन के परामर्श पर स्थायी पदों पर ६० अधिकारियों को स्थायी करने की आज्ञा जारी की गई और शेष अधिकारी अस्थायी आधार पर काम करते रहे। साथ ही न्यायिक अधिकारियों को नियत वेतन न देकर उनके लिये वेतन का एक टाइम स्केल (अर्थात् ३००-२५/२-४००-प्र० अ०-२५/२-५००) रूपाय निश्चित किया गया और कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार नये वेतन-क्रम से उनका वेतन उनके सेवा-काल के आधार पर नियत किया गया।

विशेष मैजि-
स्ट्रेट

आलोच्य वर्ष में दो विशेष मैजिस्ट्रेट, एक कानपुर में और दूसरा मेरठ में, विशेष पुलिस स्थापना से सम्बद्ध कुछ मामलों में कार्यवाही करने के लिये नियुक्त किये गये।

सचिवालय
पुनर्संग-
ठन

सचिवालय में काम काफी रहा। १९५० ई० में नान-गजटेड कर्मचारियों पर सचिवालय प्रशासन विभाग के नियन्त्रण का विकेंद्रीकरण करने और सरकार के सेक्रेटारियों के पास इस काम को सौंपने के लिये जो प्रस्ताव किये गये थे उन्हें १ जनवरी, १९५१ ई० से कार्यान्वित किया गया। यह भी निर्णय किया गया कि १ जनवरी, १९५२ ई० से जमादार और चपरासियों पर उक्त विभाग का नियन्त्रण भी विकेंद्रित किया जाय।

स्टेनोग्राफरी
के नये
स्थायी पद

१ अप्रैल, १९५१ ई० से सचिवालय स्टेनोग्राफरों के १६ पद स्थायी कर दिये गये। इन पदों की भर्ती पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश द्वारा लिये गये योग्यता-परीक्षा (Qualifying Examination) के परीक्षाफल के आधार पर की गई थी।

सरकार की सामान्य नीति के अनुसार यह भी निर्णय किया गया कि बनारस और टहरी-गढवाल की भूतपूर्व रियासतों के ६ अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी रूप से सचिवालय में ले लिया जाय। ये व्यक्ति सचिवालय में इन रियासतों के उत्तर प्रदेश में विलीनीकरण के पश्चात् अस्थायी पदों पर काम कर रहे थे।

विलीनीकृत रियासतों के कर्मचारियों को सचिवालय में सम्मिलित करना

सरकार को इस बात से कुछ चिन्ता हुई कि क्लर्क तथा अपर श्रेणी के कर्मचारि वर्ग अपनी कथित शिकायतों को अभिव्यक्त करने के लिये कुछ समय पूर्व से ऐसे उपायों का सहारा लेते रहे हैं, जो नियमों के अधीन अनुज्ञेय नहीं हैं अथवा जो परम्परागत रीति से प्रतिकूल हैं। यह भी देखा गया कि सरकारी नौकरो के कुछ सगठनों ने अपनी मांगों पर जोर डालने के लिये प्रेस तथा राजनीतिक सगठनों की सक्रिय सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। यह सरकारी अनुदेशों तथा नियमों के प्रतिकूल था। इस स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से अप्रैल, १९५१ ई० में समस्त विभागाध्यक्षों तथा कार्यालयों के अन्य प्रधानाध्यक्षों को विस्तृत आदेश जारी किये गये, जिनमें सरकारी नौकरो का ध्यान आवेदन-पत्र देने के सम्बन्ध में निर्धारित कार्यविधि की ओर आकर्षित किया गया और उक्त विभागाध्यक्षों तथा प्रधानाध्यक्षों से यह कहा गया कि वे उन सरकारी नौकरो की स्थाओं के पदाधिकारियों को, जिनसे उनका संबंध है, इस बात की सूचना दे दें।

सरकारी नौकरो तथा सेवाओं से सम्बन्धित मामले

निर्वाचनों के अवसर पर सरकारी नौकरो के पूर्ण्यता निष्पक्ष रहने की आवश्यकता पर जोर डालने के अभिप्राय से अप्रैल, १९५१ ई० में सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों में एक संशोधन किया गया, जिसमें इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि पूरे समय का कोई भी सरकारी नौकर विधान सभा के किसी भी निर्वाचन, चाहे वह भारत में या अन्य कहीं हो अथवा म्यूनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या अन्य स्थानीय निकायों के किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में न तो मतदानाथ प्रचार करेगा न उसमें हस्तक्षेप करेगा, न अपना प्रभाव डालेगा और न उक्त निर्वाचनों में भाग ही लेगा।

यू० सी० सिविल (जानपद सेवा) सर्विस (कार्यपालिका शाखा), यू० पी० पुलिस सर्विस तथा यू० पी० एकाउन्ट्स सर्विस (लेखा सेवा) की भर्तों भिन्न-भिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर न करके, जैसा कि पहले किया जाता था, सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर करने की योजना वर्ष में चालू की गयी। इस योजना के अन्तर्गत प्रथम सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा दिसम्बर, १९५१ ई० में लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गयी।

राज्य सेवाओं के लिये भर्तों

सरकार को लोक सेवा आयोग (Public Service Commission) ने १९४९-५० ई० की अपनी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट भेजी और उस रिपोर्ट में आयोग ने जिन जिन प्रमुख बातों की ओर सरकार का ध्यान बिलाया था, उन समस्त बातों की सरकार ने जांच की।

लोक सेवा आयोग

आयोग ने अलग से कतिपय उन बातों को ओर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जो सरकारी पदों के लिये आयोग द्वारा व्यक्तियों के चुनाव की कार्यविधि के सम्बन्ध में थी। आयोग ने जो सुझाव दिये थे उनके अनुसार नियुक्त

करने वाले समस्त प्राधिकारियों को निम्नलिखित आधार पर अनुदेश जारी किये गये:—

(क) किसी सेवा या पद पर नियुक्ति की शर्तें और उपाधियां सर्वप्रथम आयोग के परामर्श से तै की जानी चाहिए और एक बार जब उन्हें इस प्रकार तै तथा विज्ञापित कर दिया जाय, तो उनको कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, जब तक कि उनमें बाद में संशोधन न हो और उस संशोधन की विधिवत् घोषणा न कर दी जाय।

(ख) यदि आयोग उस अभ्यर्थी के संदर्शन (इंटरव्यू) की इच्छा प्रगट करे, जिसकी किसी वैभागिक चुनाव समिति ने किसी पद या सेवा में नियुक्ति के लिये सिफारिश की है, तो प्रशासक विभाग में सरकार के पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना आयोग के समक्ष इस प्रकार के अभ्यर्थी के उपस्थित होने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाय।

इलाहाबाद में
अफसरों का
ट्रेनिंग स्कूल

जूनियर इक्जीक्यूटिव अफसरों को ट्रेनिंग देने के अभिप्राय से स्थापित अफसरों का ट्रेनिंग स्कूल जनवरी, १९५१ ई० में कार्य करने लगा। इस स्कूल में ३४ डिप्टी कलेक्टर थे, जिन्हें तीन महीने तक प्रारम्भिक पाठ्यक्रम की ट्रेनिंग दी गई। दूसरी बार जुलाई में इस स्कूल में प्रारम्भिक तथा अन्तिम ट्रेनिंग के सम्मिलित पाठ्यक्रम के लिये २५ डिप्टी कलेक्टरों को भर्ती किया गया। यह ट्रेनिंग तीन महीने तक रही और सितम्बर में समाप्त हुई। तीसरी बार दिसम्बर में इस स्कूल में प्रारम्भिक ट्रेनिंग के त्रैमासिक पाठ्यक्रम के लिये २५ डिप्टी कलेक्टर भर्ती किये गये। इस राज्य के सिविल सर्विस सेवा के अफसरों के अतिरिक्त, मध्यभारत सरकार के ११ अफसरों और भोपाल, सरकार के २ अफसरों को भी वर्ष में इस सस्था में ट्रेनिंग लेने की अनुमति दी गई।

वैभागिक परी-
क्षाएँ तथा
जूनियर अफ-
सरों की ट्रेनिंग

वैभागिक परीक्षाएँ लेने का कार्य लोक सेवा आयोग से इलाहाबाद में नवस्थापित अफसरों के ट्रेनिंग स्कूल को हस्तान्तरित कर दिया गया और तदनुसार वर्ष में दो वैभागिक परीक्षाएँ मई तथा जून के महीने में स्कूल में ली गयीं।

वैभागिक परीक्षाओं में जूनियर आई० ए० ए० और पी० सी० ए० अफसरों के फर्ल तथा न्यायिक एव ट्रेजरी ट्रेनिंग के सम्बन्ध में उनकी स्थिति का सविस्तर पर्यावलोकन किया गया और यह देखा गया कि अधिकांश अफसरों ने न तो पूर्णतया अपनी वैभागिक परीक्षाएँ पास की और न निर्धारित ट्रेनिंग ही प्राप्त की थी, यद्यपि वे कहीं अधिक समय से सेवा में थे। इस असंतोषजनक स्थिति को सुधारने के लिये समस्त जिला अफसरों को अनुदेश जारी किये गये, जिनमें उनसे यह कहा गया कि इस प्रकार के जितने अफसर उनके अधीन कार्य कर रहे हैं उन सभी के मामलों पर वे विचार करे और उनमें जो कमियाँ रह गयी हैं उनको शीघ्र दूर करन की कार्यवाही करे।

घूसखोरी और
भ्रष्टाचार का
मूलोच्छेदन

१—सेवार्थी (सर्विसेज) से घूसखोरी तथा भ्रष्टाचार दूर करने के सम्बन्ध में सरकार ने जो पहले कार्यवाहियाँ की थी, वे १९५१ ई० में भी जारी रही। गुप्तचर विभाग, तफतीश शाखा (Investigation Branch) उन शिकायतों की जांच करती रही, जो विभिन्न प्राधिकारियों या सरकार द्वारा उसके पास भेजी गयी थीं। केवल ऐसे महत्वपूर्ण मामले, जिनपर स्थानीय प्राधिकारी पर्याप्त रूप से कार्यवाही नहीं कर सके, इस विभाग को सौंप गये।

जिला भ्रष्टाचार-निरोधक समितियां भी अपना कार्य करती रहें और १९५१-५२ ई० के वित्तीय वर्ष में विज्ञापन तथा प्रचार पर व्यय करने के लिये प्रत्येक समिति को ५०० रुपये का अनुदान फिर से दिया गया ।

यू० पी० डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स (एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल) रूल्स, १९४७ [संयुक्त प्रान्तीय अनुशासकीय (प्रशासकीय अधिकरण), नियम १९४७] के अधीन स्थापित प्रशासकीय न्यायाधिकरण (Tribunal) का कार्य वर्ष भर होता रहा और इस अवधि में ४ नये मामले इस न्यायाधिकरण के पास भेजे गये । निम्नलिखित आंकड़ों से प्रगट होगा कि न्यायाधिकरण ने काम प्रारम्भ करने के समय से आलोच्य वर्ष के अन्त तक कितना काम किया :—

प्रशासकीय
न्यायाधिकरण
(Tribunal)

न्यायाधिकरण के पास विचार और निर्णय

के लिये भेजे गये मामलों की संख्या	३६
निर्णीत मामलों की संख्या	२५
वापस लिये गये मामलों की संख्या	२
विचाराधीन मामलों की संख्या	..	.	९

निर्णीत किये गये २५ मामलों में ३६ सरकारी नौकर अन्तर्ग्रस्त थे, जिनमें से १९ व्यक्ति बरखास्त किए गए, १ को छोड़ दिया गया, ७ व्यक्तियों को अन्य प्रकार के दण्ड दिये गये और ९ को बरी कर दिया गया ।

टहरी-गढवाल, बनारस और रामपुर की रियासतें जो स्वाधीनता प्राप्ति के सिलसिले में १९४९ ई० में उत्तर प्रदेश में विलीन हो गई थीं और वे रियासतें (४९७ गांव), जो प्राविसेज एन्ड स्टेट्स (एजंजेशन आफ एन्क्लेव्स) आर्डर, १९५० के अन्तर्गत प्राप्त कर ली गई थीं, सभी प्रकार से शेष उत्तर प्रदेश की तरह प्रशासित होती रही । विलीनीकरण के पूर्व विलीन क्षेत्रों में, जो रियासतें दी गयी थीं, वह भी जारी रखी गयी ।

विलीनीकृत
रियासतें तथा
अन्तर-क्षेत्र
(१) प्रशासन

इसी प्रकार पहले के शासक केन्द्रीय सरकार से अपनी निजी थैली की राशि बराबर पढ़ते रहे और विलयन सम्बन्धी इकरारनामे में निश्चित किये गये निजी विशेषाधिकारों इत्यादि का उपयोग करते रहे ।

(२) शासकों
की निजी-
थैलियाँ

विलीनीकृत क्षेत्रों के कर्मचारिवर्ग के सम्बन्ध में विलयन सम्बन्धी इकरारनामे के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाहियों की गई । सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये सामान्य अनुदेशों के अनुसार उन्हें उत्तर प्रदेश सेवा में उनके निवास-स्थान वाले क्षेत्रों तथा अन्य जिलों में यथासंभव अधिक से अधिक संख्या में खपाने के लिये प्रयत्न किये गये । ऐसे कर्मचारियों को भी खपाने के लिये विचार किया गया, जिनमें काम के लिये शिक्षा सम्बन्धी आवश्यक योग्यता तो नहीं थी, किन्तु वे अन्यथा उपयुक्त थे । ऐसे व्यक्तियों को जिनमें आवश्यक योग्यता नहीं थी और जिनकी अस्थायी सेवा लगभग एक वर्ष की थी तथा उन व्यक्तियों को, जिनके लिये उपयुक्त जगह उपलब्ध न हो सकीं, सरकार द्वारा बनाई गयी नियमावली के अनुसार प्रतिकर देकर नौकरी से

(३) विलीनी-
कृत क्षेत्रों का
कर्मचारिवर्ग

हटा दिया गया। यह नियमावली सिविल सर्विस विनियमों के अन्तर्गत छटनी किये गये व्यक्तियों पर सामान्यतः लागू होने वाली नियमावली की अपेक्षा अधिक उदार थी। विलयन के बाद से भूतपूर्व टेहरी-गढ़वाल, बनारस तथा रामपुर रियासतों के जिन व्यक्तियों के सम्बन्ध में कार्यवाहियाँ की गईं हैं उनकी संख्या निम्नलिखित तालिका में दी गयी है :

रियासत का नाम	वेतन पाने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या	उन कर्मचारियों की संख्या जिनको नौकरी दी गई	नौकरी से हटाये गये कर्मचारियों की संख्या
टेहरी-गढ़वाल	२,१४९	१,८१४	३३५
बनारस	२,२७२	१,५६२	७१०
रामपुर	५,१४८	३,६५६	१,४९२

(४) शासकों के सम्बन्धियों तथा अन्य व्यक्तियों को भत्ता

इन इकरारनामों के अनुसार शासकों के सम्बन्धियों तथा अन्य निर्दिष्ट व्यक्तियों को भत्ता देना जारी रखा गया। टेहरी-गढ़वाल की राजमाता का भत्ता उनके पति श्री नरेन्द्रशाह की मृत्यु हो जाने के कारण १५,००० रु० से बढ़ाकर २४,००० रु० प्रतिवर्ष कर दिया गया।

(५) टेहरी-गढ़वाल की नान-इंडियन स्टेट्स फोर्स यूनिट

टेहरी-गढ़वाल की नान-इंडियन स्टेट्स फोर्स यूनिट तोड़ दी गई। उसके कर्मचारियों को यथासंभव पुलिस विभाग में रख लिया गया। ऐसे शेष व्यक्तियों को, जिनको उपर्युक्त रूप से काम पर न लगाया जा सका, नौकरी से अलगा कर देना पड़ा, किन्तु उन्हें नियमों के अनुसार प्रतिकर की स्वीकृति दी गई।

(६) धर्मार्थ इत्यादि के लिये अनुदान

रामपुर में परम्परागत धर्मार्थ तथा उत्सवों के लिये सरकारी अनुदान ४०,००० रु० प्रतिवर्ष से बढ़ाकर ५०,००० रु० कर दिया गया। बनारस में रामलीला इत्यादि के लिये बनारस के महाराजा को दिया जाने वाला अनुदान जारी रखा गया और टेहरी-गढ़वाल के मंदिरों तथा विलीनीकृत अन्तर्क्षेत्रों को धर्मार्थ कार्यों तथा सेवा के प्रशासन के लिये दिया जाने वाला अनुदान जारी रखा गया।

भूतपूर्व अन्तर्क्षेत्रों के मंदिरों तथा अन्य धार्मिक संस्थाओं और पुजारियों को, जो धर्मार्थ भुगतान उनके शासकों द्वारा दिया जाता था, वह आलोच्य वर्ष में सरकार द्वारा दिया गया। इस प्रकार की धार्मिक संस्थाओं के प्रबन्ध के लिये न्यास बनाने का प्रश्न भी विचाराधीन रहा।

(७) टेहरी-गढ़वाल के मन्दिर का न्यास

टेहरी-गढ़वाल के विलयन के इकरारनामे में यह व्यवस्था भी की गयी थी कि टेहरी-गढ़वाल के मन्दिरों और श्री बद्रीनाथ तथा केदारनाथ के पवित्र मन्दिरों के प्रबन्ध के लिये एक न्यास बनाया जाय और टेहरी-गढ़वाल के महाराजा उस प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष हों। इस न्यास के बनाने के सम्बन्ध में महाराजा से प्रस्ताव मांगे गये और वर्ष के अन्त तक उनकी प्रतीक्षा की जा रही थी। न्यास के न बनने तक मन्दिरों को अलग-अलग अनुदान दिये गये।

रामपुर की रियासत में एक पुस्तकालय था जो पहले किनाबखाना सरकारी रियासत रामपुर के नाम से प्रसिद्ध था और बाद में उसका नाम रजा पुस्तकालय पड़ गया। विलयन के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार करते हुए भारत सरकार इस बात से सहमत थी कि नशाब रामपुर पुस्तकालय के प्रबन्ध तथा प्रशासन के लिये एक न्यास बनावे जिससे भारत के सभी नागरिक तथा ज्ञानवृद्धि में आरूढ़ अन्य सच्चे ज्ञानार्थी इससे लाभ उठा सकें और पुस्तकालय की भी सुरक्षा और उसका विकास, परिचर्जन तथा सुधार होता रहे। इसके अनुसार रजा पुस्तकालय न्यास बनाया गया और उत्तर प्रदेश सरकार ने पुस्तकालय के रख-रखाव के लिये अनुदान दिया।

(८) रजा पुस्तकालय न्यास

पहाड़ी जिलों और मैदान के कुछ जिलों में नर-भक्षी चीते और तेंदुओं द्वारा पहुंचाई गई हानि के कारण मानव जीवन के खतरे को प्रभावकारी ढंग से रोकने के लिये बढ़ी हुई दर पर पारितोषिकों की स्वीकृति दी गयी, ताकि जंगली जानवर और उनके बच्चों को मार दिया जाय। भेड़ियों और लकड़बाघों का आतंक, जो १९५० ई० की ग्रीष्म ऋतु में सहसा बढ़ गया था, १९५१ ई० की ग्रीष्म ऋतु में इस राज्य के कुछ जिलों में फिर से होने लगा। लखनऊ, इलाहाबाद, मथुरा, फर्रुखाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, और मिर्जापुर के जिलों में इन जानवरों को नष्ट करने के लिये आवश्यकतानुसार पारितोषिक देने की स्वीकृति दी गयी।

जंगली जान-वरों को नष्ट करने के लिये पारितोषिक

इस वर्ष उत्तर प्रदेश में सिनेमा-घरों की संख्या लगभग ३०० रही। भारत सरकार ने १५ जनवरी, १९५१ ई० से सिनेमेटोग्राफ (सेकेन्ड अमेंडमेंट) एक्ट, १९४९ ई० लागू किया। उसी दिनांक से सिनेमेटोग्राफ (सेन्सरशिप) रूल्स, १९५१ जारी किये गये और फिल्म सेन्सर का एक केन्द्रीय बोर्ड बनाया गया, जिसका क्षेत्राधिकार संघ के सम्पूर्ण प्रदेश पर था और जिसे प्रतिबन्धित और आम जनता के प्रदर्शन के लिये फिल्मों को प्रमाणित करना पड़ता था। इस नये विधान के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश सिनेमा परामर्शदात्री समिति की उपयोगिता समाप्त हो गई और वह २४ जनवरी, १९५१ ई० से भंग कर दी गयी। भारत सरकार के फिल्म डिवीजन ने पूर्ववत् शर्तों पर स्वीकृत फिल्मों की सप्लाई जारी रखी।

सिनेमा फिल्मों का प्रदर्शन

पुराने नियमों को, जो १९३० ई० में जारी किये गये थे, अकारण करते हुए उत्तर प्रदेश, सिनेमेटोग्राफ रूल्स, १९५१ ई० १ फरवरी, १९५१ ई० से लागू किये गये। ये नियम मनोरंजन के स्थानों को, जो अधिकाधिक लोकप्रिय होते जा रहे थे, अधिक अच्छे आदर्शों पर रखने के लिये बनाये गये थे। नये नियमों का भलीभांति स्वागत किया गया। आम जनता की यह राय रही कि इन नियमों को उक्त स्थानों में सफाई की अधिक अच्छी दशाएँ करने तथा जनता को और अधिक आराम पहुंचाने और उसकी सुरक्षा के लिये बनाया गया था।

इस वर्ष इंटरटेनमेंट तथा बॉटिंग टैक्स कमिशनर के अधीन एक असिस्टेंट इंटरटेनमेंट एंड बॉटिंग टैक्स कमिशनर तथा २७ टैक्स-इंस्पेक्टरों ने कार्य किया। १९५१ ई० में एंडीशनल-इंटरटेनमेंट टैक्स इंस्पेक्टरों के २५ पद और बनाये गये, परन्तु पब्लिक सविस कमीशन द्वारा सिफारिश किये गये उम्मीदवारों की सूची देर से मिलने के कारण इन स्थानों को न भरा जा सका। मनोरंजन और बाजी लगाने के कर से लगभग ९०,००,००० रु० की कुल आमदनी हुई और कर की उगाही

मनोरंजन और बाजी लगाने का कर

पर लगभग १,२५,६०० रु० व्यय हुआ। आलोच्य वर्ष में मनोरंजन कर अधिनियम तथा नियमों (Entertainment Tax Act and Rules) के निदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ १७५ मुकदमे चलाये गये। इनमें से ९४ मुकदमों में सजा हुई और केवल ६ मुकदमे ऐसे थे जिनमें अपराधी छोड़ दिये गए। शेष मुकदमों की सुनवाई वर्ष समाप्त होने तक पूरी नहीं हो पाई थी। जिन ९४ मुकदमों में सजाये दी गयी उनमें ७,४१६ रु० के जुर्माने किये गये थे और उनमें से ७६ मुकदमों का जुर्माना वसूल किया गया। ८^{वाँ} मामले में चेतावनी दी गयी और शेष १० मामले में लाइसेंस या तो रद्द कर दिये गये या स्थगित कर दिये गये।

छात्रवृत्तियां
तथा अशदान

पहिले की तरह सरकार ने प्रिन्स आफ वेल्स मिलिटरी कालेज, देहरादून और जालंधर तथा अजमेर के किंग जार्ज मिलिटरी कालेजों में इस राज्य के पढ़ने वाले उपयुक्त उम्मीदवारों को कुछ छात्रवृत्तियां दीं। ७५० रु० वार्षिक की एक छात्रवृत्ति प्रिंस आफ वेल्स मिलिटरी कालेज, देहरादून में पढ़ने वाले इस राज्य के एक छात्र को २० जनवरी, १९५१ ई० तथा १ अगस्त, १९५१ ई० से आरम्भ होने वाली अवधियों में स हार अवधि के लिये दी गयी। पांच पांच रुपये की २० और १२ छात्रवृत्तियां साल में ९ महीने के लिये क्रमशः अजमेर और जालंधर के किंग जार्ज मिलिटरी कालेजों के कैडेटों को भी दी गयीं। सरकार ने भारतीय नौ सेना के कमीशन पदों में भर्ती के संबंध में तीन मामलों में ५८ पौंड प्रति व्यक्ति और दो मामलों में प्रत्येक व्यक्ति के लिये ११६ पौंड की धनराशियां उनके माता-पिता या संरक्षकों द्वारा दिये जाने वाले खर्च के मद में भी दिया।

१९५१ ई०
की जनगणना

फरवरी और मार्च के महीनों में 'समस्त राज्य में प्रति दस वर्ष में की जाने वाली जनगणना का कार्य चालू रहा। ९ फरवरी, १९५१ ई० और १ मार्च, १९५१ ई० के प्रांति काल तक जनगणना होती रही और मार्च के पहले तीन दिनों में उसकी वास्तविक रूप से फिर से जांच की गई। सरकार ने यह पहिले ही त कर लिया था कि जनगणना संबंधी कार्यवाहियों में प्रशंसनीय सेवाओं के लिये चार्ज सुपरिन्टेण्डेंटों, सुपरवाइजर्स और गिनने वालों को पदक, सनद और प्रमाणपत्र देकर उनकी सेवाओं को मान्यता दी जाये और गजटेट स्टाफ के संबंध में प्रशंसा-सूचक पत्र जारी किये जाये। अच्छे और प्रशंसनीय काम को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने यह तय किया कि जनसंख्या की कार्यवाहियों के समय सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये गये किसी भी अच्छे काम का उल्लेख उनके काम और चालचलन की सामयिक रिपोर्ट में कर दिया जायगा। इस संबंध में जनगणना के कार्यों को कराने वाले सुपरिन्टेण्डेंटों और डिस्ट्रिक्ट अफसरों को आवश्यक आदेश द दिये गये। सब संबंधित व्यक्तियों के सहयोग से जनगणना संबंधी सभी कार्य सफलतापूर्वक समाप्त हो गये।

नागरिकों का
राष्ट्रीय रजि-
स्टर बनाने की
तैयारी

भारत सरकार के सुझाव पर जनगणना संबंधी कार्यों के साथ ही नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने की तैयारी प्रारंभ हो गई और डिस्ट्रिक्ट अफसरों को यह आदेश दिये गये कि उनको यथासंभव शीघ्रता से पूरा कर लिया जाय तथा किसी भी दशा में वित्तीय वर्ष के अन्दर ही उनको समाप्त कर दिया जाये। यह रजिस्टर दहाती और नागरिक

दोनों ही क्षेत्रों में घर वालों के लिये बनाया गया और इसका उद्देश्य यह था कि समाज-अर्थशास्त्र तथा जन्म-मरण के आंकड़ों (Demographic) संबंधी जाँचों का कार्य भी शुरू कर दिया जाये। यह भी आशा की जाती थी कि निर्वाचन संबंधी सूचियाँ बनाये रखने से सम्बद्ध अधिकारियों को ऐसे आयु समूहों को जानने में आसानी होगी जो वर्ष-प्रति-वर्ष वोट देने के अधिकारी होते जायेंगे और इस प्रकार उन्हें निर्वाचन सूचियों को अद्यतन (up-to-date) रूप से तैयार करने में सहायता मिलेगी। यह तै हुआ कि इस रजिस्टर की तैयारी का व्यय भारत सरकार और राज्य सरकार ५० : ५० के आधार पर बाँट ले।

राज्य की राजभाषा से अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों की संख्या और भी कम होती गई। जिनके लिये भर्ती के समय साक्षरता अनिवार्य थी उनमें २ प्रतिशत से भी कम हो गयी। सरकारी कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग और अधिक बढ़ाने के संबंध में कार्यवाहियाँ होती रही और बहुत बड़ी संख्या में सरकारी कार्यालयों में प्रयोग में आने वाले फार्मों का हिन्दी में अनुवाद किया गया। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, १९५१ ई० पारित किया गया और इस वर्ष के अन्त में लागू किया गया।

राज्य-भाषा

अनुवाद विभाग में हिन्दी विधिक शब्दावली का संकलन-कार्य तथा सचिवालय के बाहर प्रयुक्त प्रपत्रों का अनुवाद होता रहा।

१९४२ ई० के आंदोलन के सिलसिले में राजनीतिक पीड़ितों को जो क्षति पहुँची उसके लिये उन्हें ३०,५१८ रुपये का प्रतिकर दिया गया। एक सौ पेंतालिस व्यक्तियों को माह्वारी पेंशन के रूप में ३,२२८ रु० ८ आ० (जिसमें महंगाई भत्ता भी शामिल है) की धनराशि स्वीकृत की गई। पेंतीस व्यक्तियों को इकमुट्ठ अनुदान स्वीकृत किये गये, जिसकी धनराशि १५,२५० रु० होती है।

राजनीतिक
पीड़ितों को
सहायता

प्रार्थना-पत्र विभाग में कुल २०,५४९ प्रार्थना-पत्र और शिकायतें प्राप्त हुईं, जब कि १९५० ई० में उनकी संख्या २४,७४४ थी। प्रत्येक प्रार्थना-पत्र और शिकायत पर तत्संबंधी विषय पर समय समय पर दी गयी आज्ञाओं का ध्यान रखते हुए विचार किया गया। आलोच्य वर्ष में जितने प्रार्थना-पत्र और शिकायतें प्राप्त हुईं उनमें से १३,४१० सचिवालय के विभागों, वैभागीक अध्यक्षों, या अन्य संबंधित अफसरों के पास उचित कर्मवाही के लिये भेज दी गयी, जब कि १९५० ई० में उनकी संख्या १४,२९२ थी और २,७८० प्रार्थना-पत्र प्रार्थियों को स्थानीय अधिकारियों के पास भेजने के लिये वापस कर दिये गये या उन्हें सीधे जवाब दे दिया गया, जब कि १९५० ई० में इस प्रकार १,५८८ प्रार्थना-पत्र वापस किये गये थे। जिस किसी प्रार्थना-पत्र या शिकायत के लिखने वाले के हस्ताक्षर की सच्चाई पर सन्देह हुआ उसके लेखक से कहा गया कि वह आरोपों को प्रमाणित करें और यह स्वीकार करें कि प्रार्थना-पत्र या शिकायत उसने लिखी है। इस प्रकार के अधिकतर प्रार्थना-पत्र या शिकायतें वास्तव में झूठे नाम से दी गयी प्रमाणित हुईं। निक्षिप्त या नष्ट किये गये प्रार्थना-पत्रों की कुल संख्या ४,३५९ थी।

प्रार्थना-पत्र
और शिकायतें

हमेशा की तरह प्रार्थना-पत्र और शिकायतें विभिन्न विषयों से संबंधित थीं। कृषि संबंधी झगड़ों और जमींदारों तथा उनके काश्तकारों के बीच के

के झगड़ों के संबंध में पहिले ही की तरह सबसे अधिक शिकायतें आईं और आलोच्य वर्ष में प्राप्त कुल शिकायतों में से उनकी संख्या लगभग ४८ प्रतिशत थी ।

कुछ किस्म के प्रार्थना-पत्रों और शिकायतों की संख्या कम हो गयी, वे ये हैं—(१) विभिन्न सुविधाओं जैसे भरण-पोषण, भत्ते, ऋण आदि के लिये विस्थापित व्यक्तियों की दरखास्तें (कुल संख्या की लगभग ४५ प्रतिशत), (२) राजनीतिक पीड़ितों के प्रार्थनापत्र या शिकायतें (कुल प्राप्त संख्या का लगभग ४ प्रतिशत) और (३) स्थानीय पुलिस की ज्यादाती और अष्टाचार के विरुद्ध तथा डकैती और फौजदारी संबंधी शिकायतें (लगभग ८५ प्रतिशत) ।

इस प्रकार की शिकायतों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई जैसे, (१) निष्क्रांत संपत्ति संबंधी शिकायतें, (२) मकान मालिकों और किरायेदारों के विरुद्ध शिकायतें और (३) चोरबाजारी, महंगाई और कंट्रोल के खिलाफ शिकायतें । गांव पंचायतों के सदस्यों के खिलाफ अष्टाचार, पक्षपात आदि के आरोपों की शिकायतों में (कुल संख्या का लगभग ६५ प्रतिशत) और रियासतों तथा अन्तरक्षेत्रों के विलीनीकरण के फलस्वरूप प्राप्त प्रार्थना-पत्रों या शिकायतों में (जो अधिकतर पिछले कमचारियों की नौकरी समाप्त करने से सम्बन्धित थीं) काफी वृद्धि हुई ।

कुल प्रार्थनापत्र में से ८ प्रतिशत प्रार्थना-पत्र नौकरी दिलाने के सम्बन्ध में थे । इस किस्म के प्रार्थना-पत्रों में कोई विशेष कमी बेशी नहीं हुई । उपर्युक्त किस्म के प्रार्थना-पत्रों या शिकायतों से भिन्न प्रार्थना-पत्रों और शिकायतों की संख्या कुल प्रार्थना-पत्रों तथा शिकायतों की संख्या की १० प्रतिशत थी । वर्ष के अन्तिम तीन महीनों में ११ शिकायतें सरकारी गजटेटेड अफसरों के विरुद्ध आईं और उन पर सितम्बर, १९५१ ई० में जारी किये गये आदेशों के अनुसार कार्रवाई की गई ।

३—वर्ष कैसा रहा ?

पहली जनवरी से मार्च, १९५१ के तीसरे सप्ताह तक सविराम, हल्की और छिटपुट वर्षा होती रही । मार्च के अन्तिम सप्ताह तथा अप्रैल के पहले सप्ताह में विस्तृत वर्षा हुई । अप्रैल के दूसरे सप्ताह से जून के तीसरे सप्ताह तक का मौसम प्रायः सूखा रहा । जून के अन्तिम सप्ताह में वर्षा प्रारम्भ हो गई । जुलाई के पहिले सप्ताह तक विस्तृत वर्षा हुई । उसके बाद महीने के शेष भाग में सविराम छिटपुट वर्षा हुई । अगस्त में अन्तिम सप्ताह को छोड़कर राज्य भर में विस्तृत वर्षा हुई । सितम्बर के पहले पक्ष में भी व्यापक वर्षा हुई, किन्तु सितम्बर के दूसरे पक्ष से दिसम्बर के अन्त तक का मौसम वस्तुतः सूखा रहा । राज्य में विशेषतः पूर्वी भागों में मामली से भी कम वर्षा हुई ।

सूखे से क्षति

वर्षा ऋतु में वर्षा की कमी और उसके अनियमित वितरण के कारण खरीफ की फसलों को दूर-दूर तक हानि पहुंची । विशेषतः पूर्वी जिलों में दुर्भाग्यवश रबी की फसलों की बुवाई और उनके अकुरित होने पर भी किसी हद तक सूखे का बुरा असर पड़ा । अहमोड़ा, बहराइच, गोंडा, बस्ती, आजमगढ़, मिर्जापुर और प्रतापगढ़ के जिलों के कुछ क्षेत्रों में कमी की स्थिति पदा हो गई और सरकार ने उक्त जिलों के

करने के लिये ७,०६,६५२ रु० की धनराशि स्वीकृत की। सूखे के कारण जो कमी की स्थिति पड़ा हो गई थी उसके सम्बंध में बच्चों, बुढ़ों तथा लाचार व्यक्तियों को, जिनके पास निर्वाह का कोई अन्य साधन नहीं था, निःशुल्क सहायता के रूप में देने के लिये ७६,१०० रु० की धनराशि स्वीकृत की गई।

पिछले वर्ष जितनी भूमि में खरीफ की फसल बोई गई थी उसका कुल क्षेत्रफल २,४३,८०,१०० एकड़ था जो १३५८ फसली में बढ़कर २,५३,३६,६१६ एकड़ हो गया। इसका कारण यह था कि परती भूमि के अधिक क्षेत्र में खेती की गई थी और यह भी कि खरीफ की फसल की बुवाई के समय ऋतु अनुकूल थी। दीर्घकालीन सूखे तथा रबी की बुवाई के समय मिट्टी में नमी की कमी होने के कारण रबी की फसलों की खेती कम भूमि में की गई और उसका क्षेत्रफल १३५७ फसली के २,२६,३८,४७५ एकड़ से घटकर १३५८ फसली में २,१६,६१,६१४ एकड़ रह गया। इस राज्य में १६५०-५१ (१३५८ फसली) में कुल खेती की भूमि का शुद्ध क्षेत्रफल ३,८५,७१,१७० एकड़ था, जब कि पिछले वर्ष उक्त क्षेत्रफल ३,८२,४२,७०० एकड़ रहा था। इससे ३,२८, ७० एकड़ या (०.६ प्रतिशत) की वृद्धि पाई गई।

फसल तथा
खेती किए
गए क्षेत्र

सितम्बर से दिसम्बर, १६५० ई० तक सूखा पड़ने के कारण इस राज्य में सिंचाई की मांग बढ़ गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि कुल सिंचाई हुआ क्षेत्र, जिसमें नहरो तथा ट्यूबवेलों द्वारा सींची हुई भूमि का क्षेत्रफल भी सम्मिलित है, पिछले वर्ष १३५७ फसली के १,०८,०२,६६३ एकड़ से बढ़कर १,१८,८४,१६२ एकड़ हो गया। आलोच्य वर्ष में कुल १३,३६१ पक्के कुएं बनाये गए (जबकि पिछले वर्ष उनकी संख्या ६,३७६ थी), किंतु बहुत से पुराने पक्के कुओं को काम में न लाने के कारण उनकी संख्या में वस्तुतः ६,१३० की ही वृद्धि हुई।

सींचा गया
क्षेत्र

रबी १३५८ फसली के सम्बन्ध में मालगुजारी की छूटों और मुस्तवियों के लिये क्रमशः ६१,३६७ रु० तथा ३,६७६ रु० की धनराशियों की स्वीकृति दी गई, जबकि खरीफ १३५६ फसली के लिए ४,६६,५५६ रु० तथा ८८,२६२ रु० की धनराशियाँ स्वीकृत की गई थीं। अग्नि तथा बाढ़ों के प्रकोपों के संबंध में भी ४६,८३७ रु० की धनराशि निर्मूल्य सहायता के रूप में दिये जाने के लिये स्वीकृत की गई थी।

छूटें

इस वर्ष राज्य के प्रायः प्रत्येक जिले में एक या दो बार टिड्डियों के दलों का आगमन हुआ। फसलों को पहुंची हुई हानि का नगदी में तखमोना ६,१६,२६४ रु० लगाया गया। इस आतंक का निवारण करने के लिए सरकार ने प्रभावशाली उपायों से काम लिया और इस प्रयोजन के लिये ३२,००० रु० तथा २,३६,००० रु० की धनराशियाँ क्रमशः डिबीजनों के कमिश्नरों तथा कानपुर में सरकार के कोटाणु विशेषज्ञ को काम में लाने के लिये दी गईं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को टिड्डियों का विनाश करने तथा उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने के सम्बन्ध में अधिकार देने के प्रयोजन से टिड्डि विनाश अधिनियम (Locust Destruction Act) पास किया गया। उक्त अधिनियम द्वारा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को यह भी अधिकार दिया गया कि वे आक्रांत क्षेत्रों के निवासियों को इस हानिकारक कीट के विनाश के संबंध में कुछ विशेष काम करने तथा आज्ञाओं का पालन करने के लिये आदेश दे सकें।

टिड्डियाँ

मूल्य

आलोच्य वर्ष में सभी मुख्य खाद्यान्न जैसे गेहूं, जौ, चना, ज्वार, मक्का और चावल राशनिंग व्यवस्था के अधीन रहे।

चना, ज्वार और मक्का के मूल्यों के चढ़ाव-उतार को छोड़कर, जिनके भाव १० रु० ११ आने तथा १६ रु० प्रति मन के बीच में घटते-बढ़ते रहे, सभी मुख्य खाद्यान्नों के भाव रुके रहे।

अध्याय २--भूमि-प्रशासन

४--जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था

जमीन्दारी विनाश कोष की वसूली का काम रबी की फसल में मई से जुलाई के मध्य तक जारी रहा। संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपाजर्जन) ऐक्ट, १९४९ ई० के अनुसार जो रुपया किसानों द्वारा जमा किया गया था, ३१ दिसम्बर, १९५१ ई० को ३२,९३,१२,३०३ रुपया था (जो लक्ष्य का २१.०६ प्रतिशत था)। किसानों को लगान में आधी छूट और बेदखलियों से पूर्ण मुक्ति के रूप में जो विशेषाधिकार दिए गए थे उसके अतिरिक्त युक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपाजर्जन) ऐक्ट, १९४९ ई० के अधीन घोषणा-पत्र (Declaration) प्राप्त कर लेने पर उन्हें अपनी भूमि के सम्बन्ध में संक्रम के अधिकार भी दिये गये।

उत्तर प्रदेश जमीन्दारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अनुसार जमीन्दारी प्रथा का विनाश, जिसके सम्बन्ध में २४ जनवरी, १९५१ ई० को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी थी, जमीन्दारों द्वारा उक्त अधिनियम की वैधता पर मतभेद प्रकट करते हुए मुकदमे दायर किये जाने के कारण स्थगित कर दिया गया। १० मई, १९५१ ई० को हाई कोर्ट ने निर्णय दिया और यह घोषित किया कि उक्त अधिनियम संविधान के अधिकारान्तर्गत ही है। इस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जो अपीलें दायर की गई थीं वे वर्ष के अन्त में विचाराधीन थी।

भूमि-सम्बन्धी स्थिति पूरे वर्ष भर संतोषजनक रही और जमीन्दारों तथा किसानों के पारस्परिक सम्बन्ध में तनातनी बढ़ने के कोई लक्षण प्रकट नहीं हुए। जमीन्दारों ने भूमि का प्रबन्ध करने या लगान की वसूली में किसी कठिनाई का अनुभव नहीं किया।

किसानों की सामान्य आर्थिक स्थिति तथा उनकी वित्तीय स्थिति में स्थिरता बनी रही।

५--मालगुजारी, कृषि सम्बन्धी अग्रजृण तथा नहरों के महसूलों की वसूली

मालगुजारी के अन्तर्गत सम्पूर्ण मांग ७०९.९२ लाख रुपये थी, जबकि पिछले वर्ष यह मांग ७०५.७८ लाख रुपये (संशोधित) थी। यह वृद्धि अंशतः इस वर्ष विलीनीकृत बनारस राज्य की मालगुजारी की मांग, जिसका कि पिछले वर्ष हिसाब नहीं लगाया गया था, सम्मिलित करने और अंशतः कछार महालो के अल्पकालीन बन्दोबस्त लागू करने तथा राज्य के कुछ जिलों में माल गजारी की उत्तरोत्तर वृद्धि करने से हुई। कुल मांग में से ६९२.३०

इस वर्ष ऐक्ट संख्या १२, १८८४ ई० और ऐक्ट संख्या १९, १८८३ ई० के अधीन वास्तव में क्रमशः ६९.३१ लाख रुपये और ५७.४८ लाख रुपये दिये गये, जबकि पिछले वर्ष क्रमशः ४०.९१ लाख और ३९.४५ लाख रुपये दिये गये थे। दोनों ऐक्टों के अधीन विलंबित की जाने वाली धनराशि का हिसाब लगाने के बाद कुल ७३.०७ लाख रुपये वसूल होने को थे। दी जाने वाली धनराशियों में जो वृद्धि हुई उसका कारण यह है कि 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अधीन कृषि सम्बन्धी औजारों, ट्रैक्टरों इत्यादि की खरीदने और खेती को कृषियोग्य बनाने की मांग अधिक बढ़ गई थी। ऐक्ट १२ के अधीन ३० प्र० के पूर्वी जिलों में, जहाँ सूखा पड़ जाने से बहुत नुकसान हुआ, कच्चे कुएं खोदने, बीज तथा बैल खरीदने के लिये अक्टूबर से दिसम्बर, १९५१ ई० के बीच की अवधि में २९.४८ लाख रुपया तकावी के रूप में बांटना पड़ा।

शरह दखलदार की कुल मांग, जिसमें पिछले वर्ष के बकाये सम्मिलित हैं, ४७३.५१ लाख रुपये से बढ़ कर ५५६.१२ लाख रुपये हो गई। नाममात्र की और वसूल न होने वाली शेष धनराशियों का हिसाब करने के बाद वसूल होने योग्य शुद्ध मांग ५४५.७५ लाख रुपये थी, जिसमें से ५४३.६८ लाख रुपये वसूल किये गये। इस प्रकार वर्ष के अन्त में केवल २०७ लाख रुपये की धनराशि शेष रह गई। शरह मालिकाना के कारण जो मांग हुई वह ६७,००९ रुपये से बढ़कर ८१,८०० रुपये हो गई और लगभग यह सम्पूर्ण धनराशि वसूल कर ली गई थी।

नहर के महसूल

६—कृषि आय-कर

१ अक्टूबर, १९५१ ई० से कृषि आय कर के प्रशासन का कार्य माल बोर्ड से भूमि व्यवस्था कमिशनर के यहाँ संक्रमित किया गया।

१९५१-५२ ई० (१३५८ फसली) में दिसम्बर, १९५१ ई० के अन्त तक कृषि आयकर को कुल निर्धारित धनराशि १,२२,२०,५९६ रु० थी, जबकि १९४८-४९ ई० में यह धनराशि १,०७,१०,७८३ रु०, १९४९-५० ई० में १,१३,६२,११८ रु० और १९५०-५१ ई० में १,०९,६०,००९ रु० थी। इस वर्ष १३५८ फसली के लिये १०,८६५ मे से १०,५८५ मामले ऐसे थे जिनमें अधिनियम की धारा १५ (३) के अधीन नोटिस जारी किये गये और वे निपटायें गये। केवल २८० मामले शेष बच गये थे। यह अनुमान लगाया गया था कि १३५८ फसली के लिये निर्धारित किये गये कर की धनराशि इन शेष मामलों को निपटाने के पश्चात् १,२५,००,००० रु० तक पहुँच जायेगी। १३५५ फसली और १३५७ फसली के बीच कर-निर्धारण सम्बन्धी मामलों की कार्यवाही इस वर्ष पूरी कर दी गई और अधिकतर निर्धारित कर वसूल किया गया। आयकर लगने से छूट गई धनराशियों पर भी कृषि आय-कर अधिनियम की धारा २५ के अधीन समुचित कार्यवाही की गई।

१३५८ फसली के लिये सम्पूर्ण निर्धारित कर में से २०,६९,४०३ रु० वसूल किया गया था। कर निर्धारण की धनराशि में जो वृद्धि हुई उसका मुख्य कारण यह था कि ऐसे उपाय किये गये जिनसे किसी को भी कर लगने से बच जाने का अवसर न मिल पाये।

कृषि आय-कर कमिशनर की अदालत में इस वर्ष १,१०५ अपीलें दायर की गयीं। ये अपीलें उन १,३७२ अपीलों के अतिरिक्त हैं जो १९५० ई० से विचाराधीन हैं। कुल अपीलों में से १,१५३ अपीलें कमिशनर ने निपटा दी थीं और आलोच्य वर्ष के अन्त में १,३२४ अपीलें अनिर्णीत रह गईं।

१९५० ई० में कृषि आय-कर बोर्ड के यहां अनिर्णीत ४५ पुनरीक्षण के मामले थे। १९५१ ई० में ३१० मामले दायर किये गये जिसके फलस्वरूप कुल मामले ३५५ हो गये। आलोच्य वर्ष में बोर्ड ने इन मामलों में २३५ पर निर्णय दे दिया और वर्ष के अन्त में १२० मामले बचे रह गये।

कर के प्रसाशन पर जो न्यय होता आ रहा है वह वर्ष भर की कुल आय का लगभग २ प्रतिशत है।

७—पैमाइश, बन्दोबस्त और कागजातदेही

सम्बन्धी कार्यवाहियां

आलोच्य वर्ष में राज्य में बन्दोबस्त सम्बन्धी कोई कार्यवाही नहीं की गई और जिला देहरादून के परगना जौनसार बाबर, जिला मरठ के परगना हस्तिनापुर और जिला रामपुर की तहसील शाहाबाद में पैमाइश तथा कागजातदेही संबंधी कार्यवाहियां जारी रहीं। जिला टेहरी-गढ़वाल में कागजातदेही सम्बन्धी कार्यवाहियों को समाप्त करने के सम्बन्ध में भी कुछ काय किया गया।

८—कागजातदेही

आलोच्य वर्ष में कागजातदेही कर्मचारिवर्ग के जमींदारी विनाश कोष आन्दोलन, जनगणना, पशु तथा ट्रैक्टर गणना और मतदाता सूची तैयार करने में लगे रहने के कारण कागजातदेही के कार्यों में कई प्रकार की बाधाएँ रही। इसका परिणाम केवल यह ही नहीं हुआ कि कागज-पत्र ठीक से न रखे जा सकें, बल्कि कागजातदेही के काम की कई शाखाओं के अनुसूचित कार्यक्रम में रुकावटें भी आईं। बहुत से निर्धारित सामयिक विवरणपत्र समय पर न दिये जा सके और समय-समय पर जिलों की जहाँ से ये विवरणपत्र नहीं आये थे और अधिक समय देना पड़ा। जहाँ आवश्यक समझा गया सुपरवाइजर कानूनगोओं द्वारा कागजातों की जाँच-पड़ताल के अनुसूचित कार्य में भी ढिलाई करनी पड़ी।

कागजातदेही के तीन असिस्टेंट डाइरेक्टरों ने कई जिलों का दौरा किया और कागजातदेही के कार्य का निरीक्षण किया।

सब बातों को देखते हुए नक्शों की दशा संतोषजनक रही, यद्यपि उनमें बहुत कुछ सुधार किया जा सकता था। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता था कि नक्शों को सुधारने के कार्य में पहिले से भी अधिक ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि खाद्यभक्षों के वर्तमान बढ़े हुए मूल्यों और 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के फलस्वरूप परती भूमि के कई भूखंडों (प्लॉटों) में खेती की जाने लगी है। इस्तमरारी बन्दोबस्त वाले बनारस डिवीजन में दोबारा पैमाइश और कागजातों का संशोधन उस डिवीजन के नक्शों और कागजातों में सुधार करने का एकमात्र उपाय समझा गया, किन्तु राज्य में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम द्वारा राज्य की भौतिक अधिकार प्रणाली (Land Tenure System) में प्रस्तावित परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष यह मामला स्थगित कर दिया गया।

१० पटवारी उम्मीदवारों के साथ-साथ ४० कानूनगो उम्मीदवार, जिन्हें नवम्बर, १९५० ई० में कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल में प्रविष्ट किया गया था, सितम्बर, १९५१ ई० की अंतिम परीक्षा में सफल हुए। पब्लिक

सर्विस कमीशन द्वारा ली गयी प्रतियोगिता परीक्षा तथा पटवारियों में से चुनाव के आधार पर नवम्बर, १९५१ ई० में इतने ही उम्मीदवार कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल में भर्ती किये गये, तथापि बाद में सरकारी आदेश के अनुसार कुल संख्या बढ़ा कर ५१ कर दी गयी।

१—आराजी के क्षेत्र

१९५०-५१ (१३५८ फसली) में राज्य में जोतों के क्षेत्रफल में ६,३६,८९१ एकड़ की वृद्धि हुई और वह ४,४५,०९,६६२ एकड़ हो गया, अर्थात् उसमें १५ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका कारण यह था कि खाद्यान्नों की महंगाई तथा 'अधिक अन्न' उपजाओ' आन्दोलन के कारण नौतोड़ भूमियों में भी खेती की गयी।

मुख्यतः मौरूसी अधिकारों के दिये जाने के कारण सीर का क्षेत्र ४२,३८,९२० एकड़ से घटकर ४२,२६,३८२ एकड़ रह गया। मुख्य रूप से जमींदारी प्रथा का विनाश निकट होने के कारण खुदकाश्त के अधीन कुल क्षेत्र ३१,६७,८९४ एकड़ से बढ़कर ३२,०९,९६२ एकड़ हो गया। साकितुलमिलिकयत काश्तकारों के अधीन क्षेत्र में ६,१९६ एकड़ की कमी हुई (अर्थात् ८,३८,८०६ एकड़ से ८,३२,६१० एकड़ हो गया)। यह कमी अंशतः काश्तकारों के बिना उत्तराधिकारियों के मर जाने और अंशतः उनके द्वारा जमीन के समर्पित कर दिये जाने के कारण हुई। दखीलकार काश्तकारों के अधीन कुल क्षेत्र १,०८,३२,०५० एकड़ से बढ़कर १,१०,५०,९४५ एकड़ हो गया। इसका मुख्य कारण बनारस, रामपुर तथा देहरी-गढ़वाल की रियासतों के विलयन और अंतर्देशों का उत्तर प्रदेश में विलीनीकरण है।

सीर तथा खुदकाश्त के क्षेत्रों के किसानों को उठाने और नौतोड़ भूमि में खेती किये जाने के परिणामस्वरूप मौरूसी काश्तकारों के अधीन क्षेत्र में २,५०,९१३ एकड़ की वृद्धि हुई (अर्थात् १,७८,६६,९६१ एकड़ से १,८१,१७,८७४ एकड़ हो गया)। गैरदखीलकार असामियों के अधीन क्षेत्र, नौतोड़ भूमि में खेती किये जाने के कारण, ४,११,६५२ एकड़ से बढ़कर ४,३०,६१३ एकड़ हो गया जो क्षेत्र असामियों के पास मौरूसी थे उसमें भी ४३,०६९ एकड़ की वृद्धि हुई (अर्थात् ३,३३,५४५ एकड़ से ३,७६,६८४ एकड़ हो गया)। यह वृद्धि जमींदारों द्वारा जमीन को कम लगान पर उठाने के कारण हुई। बागदारों के क्षेत्रों में जो ६,१९६ एकड़ की वृद्धि हुई वह जमींदारों द्वारा नए पट्टे दिये जाने के कारण हुई।

मुख्यतः लगान पर उठाई हुई भूमि में वृद्धि होने के कारण नगदी लगान की माँग में २३.१९ लाख रुपये की वृद्धि हुई। एक बड़ी संख्या में बटाई लगानों को नकदी लगानों में बदलने के फलस्वरूप अनाज के रूप में लगान की माँग में ७६,८६६ रु० की कमी हुई। सायर उपज का मूल्य अधिक होने के कारण सायर के अधीन लगान की माँग में ६,४९,७९५ रु० की वृद्धि हुई। आलोच्य वर्ष में लगान की कुल माँग में २६.९२ लाख रु० की वृद्धि हुई और वह १९,११,०५,२९६ रु० हो गई।

पिछले वर्ष के आँकड़ों की तुलना में इस वर्ष कुल वसूली में, जिसमें बकाया भी सम्मिलित है, ४१,६८,३२३ रु० अर्थात् ४.४ प्रतिशत कमी हुई। इसका कारण अंशतः यह था कि पटवारियों के जमींदारी विनाश, जन्मगणना तथा निर्वाचन संबंधी कार्यों में लगे रहने के कारण और अंशतः प्राप्तियों के सियाहों में पूरे तौर से सही आँकड़े देने में उदासीन रहने के कारण इंदराज न हो सके।

लगान संबंधी
माँग

१०—सरकारी आस्थान

१९५१ ई० में उत्तरप्रदेश में ५३० सरकारी आस्थान थे। इन आस्थानों में रामपुर तथा बनारस की भूतपूर्व रियासतों की सरकारी संपत्तियाँ भी सम्मिलित थीं।

कृषि संबंधी
विकास

कृषि की दृष्टि से वर्ष संतोषजनक रहा, यद्यपि पाला पड़ जाने के कारण तराई तथा भावर के सरकारी आस्थानों में रबी की फसल और ढूँधी में फसलों को, जहाँ कि वर्षा कम हुई थी, क्षति पहुँची।

तराई और भावर में जूट तथा कपास की खेती प्रारम्भ की गई। ४५,००४ एकड़ क्षेत्र नये बसने वालों को दिये गये, जिनमें से अधिकांश ने खेती करनी प्रारंभ कर दी। ४,२५० एकड़ से अधिक भूमि राज्य ट्रैक्टरों से जोती गई और परती जमीन का बहुत बड़ा क्षेत्र ट्रिजो ट्रैक्टरों द्वारा, जिनकी संख्या १७५ थी, कृषि योग्य बनाया गया। फलस्वरूप जोती गई भूमि का क्षेत्रगत वर्ष के १,६४,७४६ एकड़ से बढ़ कर १,८५,७४१ एकड़ हो गया। रामपुर की भूतपूर्व रियासत का एक बड़ा क्षेत्र, जो कि बेकार पड़ा था, कृषि योग्य बनाया गया।

लगभग ६,८०० बीघे भूमि भू-हीन व्यक्तियों को गढ़वाल, भावर सरकारी आस्थान में खेती करने के लिये दी गयी।

तराई तथा भावर सरकारी आस्थानों के बीज गोदाम ने कृषकों को १४,६६६ मन उन्नत प्रकार के बीजों की सप्लाई की। लगभग १,२६० मन उर्बरक और ६७६ कृषि संबंधी औजार भी कृषकों को रियायती दरों पर बेचे गये।

खेतिहरों को ३३,३२५ रु० के व्यय पर काँटेदार तार सप्लाई किये गये, ताकि वे जंगली जानवरों से अपने खेत की रक्षा कर सकें।

तराई और भावर में जंगली हथियों के उत्पात को दूर करने के लिये 'खेदा' कार्यक्रमों को करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा था और इस संबंध में उड़ीसा सरकार के एक वन पदाधिकारी की सेवाएँ प्राप्त की गयीं।

उद्योग-बंधे

सरकार एक प्रशिक्षित कताई अध्यापक की देखरेख में हल्द्वानी के ऊन-कताई केन्द्र को चलाती रही। कोटवाग में भी एक निजी केन्द्र खोला गया, जिसने अच्छे प्रकार के बहुत से ऊनी-कम्बल तैयार किये। जनता को १ मन ऊन, ४ ब्रॉक्स और १२० तकलियाँ रियायती दरों पर बेची गईं। घरेलू उद्योग-बंधों, जिनमें फल संबर्द्धन तथा मधु-मक्खी पालन विशेष उल्लेखनीय हैं, के विकास के लिये भी कार्यवाहियाँ की गयीं।

यातायात,
भवन, कुएं
आदि

वर्ष में एक पब्लिक-चिकित्सा, आवासिक क्वार्टरों, कतिपय सड़कों, पुलियों तथा कुओं इत्यादि का निर्माण किया गया और भवनों तथा नहरों की मरम्मत की गई।

घर और कुएं इत्यादि बनाने के लिये तराई तथा भावर सरकारी आस्थानों में खेतिहरों को या तो मुफ्त या रियायती दरों पर ३,७८८ रु० मूल्य का चूना सप्लाई किया गया।

इन आस्थानों में एक ट्यूबवेल की बंधन क्रिया, जो गत वर्ष प्रारम्भ कर दी गयी थी, पूरी हो गयी और अन्य ट्यूबवेल का कार्य हाथ में ले लिया गया।

वर्ष में तीन पाताल-तोड़ कुओं का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया। इसके अतिरिक्त हाथ के ६ नये पम्प लगाये गये और बहुत से पुराने पम्पों की मरम्मत की गयी।

दूधी सरकारी आस्थान में लगभग २०,४२८ ह० व्यय पर सात नई बन्धियां बनायी गयी। १७ बंधियों की मरम्मत भी की गयी। कुओं का निर्माण-कार्य चालू था और दूधी में आवासिक गृहों की अत्यधिक कमी को दूर करने के लिये क्वार्टरों का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया।

गढ़वाल-भावर आस्थान में पीछे के पानी की कमी को देखते हुए १६,००० ह० की तलमोती लागत पर तल्ला-सुखरों में पानी की सप्लाई के लिये एक योजना स्वीकृत की गई।

तराई तथा भ.वर सरकारी आस्थानों में ११२ स्कूल थे। इन शिक्षा संस्थाओं की दशा सामान्य रूप से सतोषजनक रही। विद्यार्थियों की संख्या गत वर्ष की ४,६३६ की अपेक्षा ४,०७४ थी।

मलेरिया रोकने के लिये उपनिवेशन विभाग के मलेरिया-निरोधक यूनिटों, विश्व-स्वास्थ्य संगठन मलेरिया-नियंत्रण प्रदर्शन टीम और आस्थानों के जन-स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा आस्थान भर में प्रपाड़ एवं व्यापक रूप से आन्दोलन चलाये गये। किछा की मलेरिया-निरोधक यूनिट ने २५ प्रतिशत डी० डी० टी० से २,५७,०६,३०४ वर्ग फीट क्षेत्र में छिड़काव किया। विश्व-स्वास्थ्य-संगठन-मलेरिया नियंत्रण प्रदर्शन टीम ने २१,०३९ घरो के आँगन या उसके आसपास के क्षेत्र के ४७,३६,५३१ वर्ग मीटर में टेक्निकल ग्रेड की डी० डी० टी० छिड़का, जिसमें शत प्रतिशत या तो घुलनशील पाउडर के रूप में प्रयोग किया गया या केन्द्रीभूत द्रवपदार्थ के रूप में। इस टीम ने १,५०० वर्ग मील में आबाद १,१०० गाँवों की सेवा की, जिनकी जनसंख्या १,३०,००० से लेकर १,४०,००० तक थी।

दूधी में चेचक के कारण ३७ मौते हुईं। अन्य स्थानों में चेचक की बीमारी छुट-पुट थी, किन्तु समय से टीका लग जाने के कारण बीमारी का फैलना बन्द हो गया। गढ़वाल-भावर में महामारी के रूप में हैजा फैला, जिसके फलस्वरूप ७६ मौते हुईं, किन्तु प्रभावपूर्ण हैजा-निरोधक उपायों द्वारा उसे शीघ्रता से दबा में कर लिया गया।

• ११—कोर्ट आफ वार्ड्स के अधीन आस्थान •

इस वर्ष ऐसे आस्थानों की संख्या, जिनका प्रबंध कोर्ट आफ वार्ड्स के अधीन था, १६४ थी, जबकि गत वर्ष उनकी संख्या १६० थी। वर्ष के दौरान नौ जो आस्थान मुक्त किए गए थे उनमें कांथ आस्थान (मुरादाबाद) सबसे बड़ा आस्थान था और उसकी कुल आमदनी १.११ लाख ह० थी और जो आस्थान कोर्ट आफ वार्ड्स द्वारा हाथ में लिए गए थे उनमें केवल कुरबार आस्थान (मुस्तानपुर) महत्वपूर्ण था। इसकी कुल आमदनी १.१६ लाख रुपये थी और यह आस्थान रानी भुवनश्वरी देवी द्वारा कोर्ट आफ वार्ड्स की धारा १० के अंतर्गत प्रार्थना किए जाने पर लिया गया था। यह आस्थान ऋण-परिशोध-क्षम (solvent) था।

आलोच्य वर्ष में चालू वर्ष के लगान तथा सायर की माँग की वाजिबुल अदा शुद्ध धनराशि पिछले वर्ष के ६४१५ लाख रुपये से बढ़कर ६६.१२ लाख ह० हो गई। चालू वर्ष की तथा बकाये की दोनों प्रकार की माँगों की कुल वसूलियाँ ६७.६६ प्रतिशत थी, जबकि पिछले वर्ष १००.०५ प्रतिशत वसूली हुई थी। प्रतिशत में कमी का कारण यह था कि वर्ष के दौरान में मुक्त किए गए आस्थानों

पानी की
सप्लाई

शिक्षा

स्वास्थ्य

कोर्ट आफ
वार्ड्स के
प्रबंध में
आस्थान

वसूलियाँ

के संबंध में माँग तो पूरे वर्ष भर के हिसाब में शामिल कर ली गई थी, परन्तु वसूलियाँ केवल आस्थानों के मुक्त किए जाने वाली तिथि तक ही हिसाब में शामिल की गई थी।

प्रबंध सम्बन्धी
[व्यय]

मालगुजारी, करों (Rates) और अबबाब के सरकारी मूतालबे, जिसकी धनराशि ३४७ लाख ६० थी, पूरे पूरे वसूल हो गए। इस वर्ष प्रबंध-सम्बन्धी व्यय १५४० प्रतिशत था जबकि पिछले वर्ष यह १५३८ प्रतिशत था।

सुधार कार्य

संरक्षितों और उनके आश्रितों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होता रहा। जमींदारी प्रथा का विनाश निकट ही सम्पन्नकर संरक्षितों को अपनी काश्त शुरू करने तथा उसे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस काम में सुविधा देने के अभिप्राय से उनमें से कई व्यक्तियों के लिए ट्रैक्टर खरीदे गए। यह एक प्रसन्नता की बात है कि उनमें से अनेक व्यक्ति बहुत ही तत्परता के साथ खेती करने लगे।

संरक्षितों तथा उनके आश्रितों की शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया गया। ऋण चुकाने की योजनाओं के अनुसार ऋण चुकाने के लिए किस्तें दी गईं। कृषि संबंधी सुधार कार्यों तथा जन हितकारी कार्यों पर एक अच्छी धनराशि व्यय की गई। माल और दीवानी के मुकदमों की संख्या कम रही।

लेखा-परीक्षा]

इस वर्ष कोर्ट आफ वार्ड्स के अधीन सभी आस्थानों के लेखों की जाँच की गई। सामान्यतः उन्हें संतोषजनक पाया गया। कुछ मामलों में, जिनमें अनियमितताएं पाई गईं, उससे संबंधित व्यक्तियों के साथ उचित कार्रवाई की गई और इस दृष्टि से कार्यवाहियों की गई कि उक्त प्रकार की अनियमितताएं दुबारा न हो सकें।

१२—माल की अदालतें

क्रांति आराजी
संबंधी मुकदमे

राज्य में यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट के अधीन दायर किए गए मुकदमों की संख्या १९५० ई० की संख्या ३,४९,३३४ से कुछ बढ़कर १९५१ ई० में ३,५०,२६५ हो गई। विविध मुकदमों की संख्या १,०६,२८५ से बढ़कर १,१०,६८६ हो गई। बकाया लगान के लिए दायर किए गए मुकदमों की संख्या भी १,०६,६७० से कुछ बढ़कर १,०८,२५७ हो गई। बेदखली की नालिशों की संख्या ६०,२८१ से घटकर ५१,८०९ रह गई। जिन मुकदमों में बेदखली की आज्ञाएं दी गई थी उनकी संख्या १५,४६९ से बढ़कर २३,०६० तक हो गई और जिस क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ा वह १६,३१५ एकड़ से बढ़ कर १९,३५३ एकड़ हो गया।

टेनेन्सी ऐक्ट
के आरम्भिक
मुकदमों का
निपटारा

वर्ष के प्रारम्भ में यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट के अधीन कुल मिलाकर ५,०८,५३७ नालिशें और प्रार्थना-पत्र निर्णय के लिए थे और वर्ष भर में इनमें से ३,५६,७९९ मुकदमों का निपटारा किया गया।

दाखिल-
खारिज

उत्तर प्रदेश में हुक मालिकाना के संबंध में दर्ज किए गए दाखिलखारिज के मुकदमों की कुल संख्या १,४२,५७४ से कुछ बढ़कर १,४३,३२८ हो गई। केवल उत्तराधिकार संबंधी मुकदमों की संख्या में वृद्धि हुई और वह १,०६,७९१ से बढ़कर १,१५,४७० हो गई। भूमि छुड़ाने (redemption) के मुकदमों की संख्या ८,९४३ से घटकर ७,३१८ रह गई और वैयक्तिक हस्तांतरण (private transfer) के मुकदमों की संख्या ९,७९६ से घटकर ५,४६४ रह गई। अन्य सभी प्रकार के मुकदमों की संख्या १०,४८६ से घटकर ९,४४९ हो गई।

इस वर्ष बंटवारा संबंधी प्रार्थना-पत्रों की संख्या ३४७ थी, जिनमें से ४ पूरे बंटवारे और ३४३ अधूरे बंटवारे के संबंध में थे। १९५० ई० के उत्तर प्रदेश कायदा (विशेषाधिकार उपार्जन) (संशोधन) और प्रकीर्ण निदेश संबंधी अधिनियम [U. P. Agricultural Tenants (Acquisition of Privileges) (Amendment) and Miscellaneous Provisions Act of 1950] की धारा १० के अधीन कार्यवाहियाँ स्थगित रहीं।

यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट के अंतर्गत कलेक्टरों की अदालतों में की गई अपीलों की संख्या ३,८६० से बढ़कर ४,२३० हो गई। निर्णय के लिए अपीलों की कुल संख्या ५,७७० थी, जिनमें से ४,३०४ निर्णय की गई और ४२५ ऐसी अपीलों को मिलाकर, जो ३ महीने से अधिक पुरानी थीं, कुल १,४६६ अपीलों शेष रह गई।

बंटवारा

अपीलें और
पुनरीक्षण
(नजरसानी)

यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट के अंतर्गत कमिश्नरों द्वारा फैसला की जाने वाली अपीलों की संख्या २६,०५० से बढ़कर ३२,५२५ हो गई। इनमें से १५,७५६ अपीलों पर निर्णय हुआ और वर्ष के अंत में १८,७६२ विचाराधीन अपीलों (जिनमें ४ संक्रमित की गईं) अपीलों सम्मिलित नहीं हैं) शेष रह गई। ४११ प्रतिशत अपीलों के संबंध में नीचे की अदालतों के निर्णय या तो उलट दिए गए या उनमें संशोधन किया गया या उन्हें नीचे की अदालतों में वापस भेज दिया गया। यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के अंतर्गत कमिश्नरों द्वारा फैसला की जाने वाली अपीलों की संख्या १,६१० थी, जिनमें से ८५६ का निर्णय किया गया और वर्ष के अंत में ७५४ विचाराधीन अपीलें शेष रह गईं। माल-बोर्ड में ६,६८१ अपीलों और पुनरीक्षण के मालले निर्णय किये गये और वर्ष के अंत में ११,६८३ अपीलें विचाराधीन रह गईं।

रानीखेत (जिला अजमेर) के आनरेरी असिस्टेंट कलेक्टर की अदालत को छोड़कर राज्य के आनरेरी असिस्टेंट कलेक्टरों की अन्य सभी अदालतों ने १ अप्रैल, १९४७ ई० से काम करना बंद कर दिया था। इस वर्ष केवल एक आनरेरी असिस्टेंट कलेक्टर रानीखेत में कार्य करता रहा और उसने २६३ मुकदमों का निर्णय किया।

आनरेरी
असिस्टेंट
कलेक्टर

अध्याय ३—शांति-व्यवस्था तथा स्वायत्त शासन

१३—विधि निर्माण-क्रम

उत्तर प्रदेश विधान मंडल ने बहुत से बिल पारित किये जो गवर्नर महोदय या राष्ट्रपति महोदय द्वारा, जैसा कि कानून द्वारा अपेक्षित है, स्वीकृत किये जाने के पश्चात् निम्नलिखित विधेयक बन गये :—

- (१) १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १, १९५१ ई०)।
- (२) १९५० ई० का उत्तर प्रदेश राजकीय पथ-परिवहन (State Road Transport) अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २, १९५१ ई०)।
- (३) १९५० ई० का उत्तर प्रदेश सिंचाई संबंधी (आकस्मिक अधिकार) अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ३, १९५१ ई०)।
- (४) १९५० ई० का कानपुर अर्बन एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (अमेंडमेंट ऑफ कांस्टीट्यूशन) (कार्यवाही संबंधीकरण) अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ४, १९५१ ई०)।

(५) १९५० ई० का उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीयों का (अनुपूरक) अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५१ ई०)।

(६) १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (पूरक) अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ६, १९५१ ई०)।

(७) १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण (संशोधन और अधिकार को जारी रखने का) अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ७, १९५१ ई०)।

(८) १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पूरक) अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ८, १९५१ ई०)।

(९) १९५० ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट एण्ड एक्विशन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ९, १९५१ ई०)।

(१०) मोटर वेहिकल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५० ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १०, १९५१ ई०)।

(११) १९५० ई० का उत्तर प्रदेश मेन्टेनेन्स आफ पब्लिक ऑर्डर ऐक्ट का (निर्वातन) अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ११, १९५१ ई०)।

(१२) १९५० ई० का उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १२, १९५१ ई०)।

(१३) १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १३, १९५१ ई०)।

(१४) १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (अनुपूरक और वेधोकरण) अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १४, १९५१ ई०)।

(१५) १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विधियों की प्रवृत्ति के प्रसार (Extension of Application) का अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १५, १९५१ ई०)।

(१६) उत्तर प्रदेश शर्करा और चालक मद्यसार उद्योग, श्रमिक कल्याण और विकास निधि अधिनियम, १९५० ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १६, १९५१ ई०)।

(१७) उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट एण्ड इक्विशन (अमेन्डमेंट) विधान, १९५० ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १७, १९५१ ई०)।

(१८) १९५१ ई० का इंडियन फ्लेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १८, १९५१ ई०)।

(१९) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों का अनर्हता निर्धारण अधिनियम, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १९, १९५१ ई०)।

(२०) उत्तर प्रदेश टिड्डी बिनाश अधिनियम, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २०, १९५१ ई०)।

(२१) रामपुर में बेदखली के बाद और व्यवहार रोकन का अधिनियम, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २१, १९५१ ई०) ।

(२२) उत्तर प्रदेश काँस उन्मूलन अधिनियम, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २२, १९५१ ई०) ।

(२३) उत्तर प्रदेश काश्तकार (विशेषाधिकार उपाजन) (संशोधन) और प्रकीर्ण निदेश अधिनियम, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २३, १९५१ ई०) ।

(२४) उत्तर प्रदेश विनियोग पुरक अधिनियम, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २४, १९५१ ई०) ।

(२५) इडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २५, १९५१ ई०) ।

(२६) उत्तर प्रदेश राज भाषा अधिनियम, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २६, १९५१ ई०) ।

(२७) उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन और विविध उपबन्ध) अधिनियम, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २७, १९५१ ई०) ।

(२८) कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २८, १९५१ ई०) ।

(२९) रेलजस एन्डाउमेंट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २९, १९५१ ई०) ।

(३०) उत्तर प्रदेश जरे चहारम विनाश अधिनियम, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ३०, १९५१ ई०) ।

(३१) उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजिशन (कन्ट्रीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ३१, १९५१ ई०) ।

(३२) दूधो राबर्ट्सगंज (जिला मिर्जापुर) कृषक ऋण उद्धारक अधिनियम, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ३२, १९५१ ई०) ।

(३३) उत्तर प्रदेश शरणार्थियों को फिर से बसाने (के लिये ऋण देने) का संशोधक अधिनियम, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ३३, १९५१ ई०) ।

(३४) उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अधिनियम, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ३४, १९५१ ई०) ।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल ने उत्तर प्रदेश चिल्ड्रेन बिल, १९५० ई० भी पारित किया। वर्ष समाप्त होने के पश्चात् राष्ट्रपति इस पर अपनी अनुमति देगे।

उस अवधि में, जबकि विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा था, राज्यपाल महोदय ने नीचे दिये गये अध्यादेश प्रख्यापित किये :—

(१) उत्तर प्रदेश टिड्डी विनाश अध्यादेश, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १, १९५१ ई०) ।

(२) रामपुर में बंदखली के बाढ़ और व्यवहार रोकने का अध्यादेश, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २, १९५१ ई०) ।

(३) उत्तर प्रदेश कास्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) (संशोधन) अध्यादेश, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० ३, १९५१ ई०) ।

(४) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों का अनर्हता निवारण अध्यादेश, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० ४, १९५१ ई०) ।

१४—गृह.

(क) पुलिस

शान्ति और
व्यवस्था

कुछ घटनाओं को छोड़कर, जिनमें कि अप्रैल, १९५१ ई० में झांसी शहर में छ दंगा-फसाद, बाराबकी और बहराइच जिलों में मुहर्रम के त्योहार पर व बरेली जिले में होली के अवसर पर छोटे-मोटे साम्प्रदायिक झगड़ शामिल हैं, बाकी राज्य भर में लगभग पूरे साल शान्ति और व्यवस्था सन्तोषजनक रही ।

जुर्म (अपराध)

बिगड़ी हुई आर्थिक दशाओं तथा गुंडे-बदमाशों की हरकतों के कारण कठिनाइयों के होते हुये भी सामान्यतया अपराध सम्बन्धी स्थिति पर नियन्त्रण रहा ।

पिछले वर्ष की सुधरी स्थिति ही नहीं कायम रखी गई (जबकि स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद से जुर्म के आंकड़े सबसे कम रहे), बल्कि ऐसे सच्चे मामलों की संख्या में वास्तव में कमी हुई, जो पुलिस को रिपोर्ट किये गये । उन दो वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े ये हैं :—

वर्ष	डकैतियां (जिनमें वे डकैतियां शामिल हैं जिनमें हत्यायें भी हुई) ।	लूटमार	हत्यायें	दंगे	नकबजनी
१९५०	२७९	५७५	१,६०४	३,७३८	२४,७६२
१९५१	८१७	५४४	१,५६९	३,३८२	२१,८८०

डकैत-गिरोहों
के विरुद्ध
कार्रवाई

खालोच्य वर्ष में डकैतों के बहुत से गिरोहों का नाश किया गया । इनमें से कुख्यात गिरोह ये थे :—जिला आगरा में चरना का गिरोह, मेरठ में छुट्टन कहार, नजरू रंगार, हुकुम सिंह और देवी सिंह; बुलन्दशहर में जहांगीरी; बदायूं में नब्बू और जालिम; नैनीताल में मजहीर; बदायूं में डूंगर कहार, मुरादाबाद में मोहन खांगी; इटावा में बाबू दिल्ली वाला; कानपुर में मस्तान शाह, फर्रुखाबाद

में सोने लाल, प्रतापगढ़ में हुबलाल पासी, आजमगढ़ में काशी चमार और गोरखपुर में वस्मीनाथ के गिरोह। चरना के गिरोह से पुलिस की ७२ घंटे मूठभेड़ हुई, जिसमें ११ डाक मारे गये और चार रायफिलें तथा ६ बन्दूकें पकड़ी गईं। राय सिक्खों और वीक सिक्खों का अन्तर्राज्य गिरोह, जो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून, मेरठ, बुलन्दशहर और मथुरा में उधम मचाये हुये था, उसे भी पुलिस ने तहस-नहस कर दिया। पंजाब के इस गिरोह के लोग बड़े दिलेर और अमानुषिक थे।

इन विभिन्न गिरोहों का मुकाबिला करने में पुलिस के एक सब-इन्स्पेक्टर, प्राविशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी के एक कम्पनी कमान्डर तथा ८ कांस्टेबुलों की मृत्यु हुई (जिनमें से एक चरना के गिरोह का सामना करते समय मारा गया था)।

इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों के लोगो ने डाकुओं तथा अपराधियों का मुकाबला करने में बड़ी सहायता की। इसके भी स्पष्ट प्रमाण मिले कि उनमें आत्म-विश्वास की भावना बढ़ रही है।

कुछ बड़े जिलों में अभियोग शाखा के संगठन तथा वाच ऐण्ड वार्ड अमले से तफतीश करने वाले अमले को अलग करने का कार्य पूरा किया गया। स्काट-लैंड (इंग्लैंड) की तरह लखनऊ और कानपुर में इन्फार्मेशन रुम्स खोले गये और सब जिलों में डिस्ट्रिक्ट क्राइम रेकार्ड सेक्शन कायम किये गये।

आलोच्य वर्ष में अपराध तफतीश शाखा ने दो सौ इकतीस मामले हाथ में लिये और ९० प्रतिशत मामलों में कामयाबी प्राप्त की। इनमें से खास-खास मामले-ये थे :—

इलाहाबाद बैंक को धोखा देने का मामला जिसमें हाई कोर्ट ने ५ वर्ष की सख्त सजा और २४,००० रु० का जुर्माना कायम रक्खा; बनारस की १५ तेल की मिलों के मामले, जिसमें अभियुक्तों को सजाएं दी गईं और कुल ४,७६,००० रु० का जुर्माना किया गया; औरतों का व्यापार करने के अन्तर्राज्य मामले (उत्तर प्रदेश, बम्बई और मद्रास), जिनमें ८ व्यक्तियों को लम्बी सजाएं दी गईं और जुर्माना किया गया और रेल हत्या कांड (१२ डाउन) जिसमें अभियुक्त को सैद्धान्तिक अदालत ने सजा दी।

फिगर प्रिन्ट ब्यूरो और साइंटिफिक सेक्शन में काम बहुत बढ़ गया। फायर आर्म सेक्शन में जिन चीजों की जांच की गई उनकी संख्या १९५० ई० की ९०९ से बढ़ कर १९५१ ई० में २,०७८, क्वेश्चनड डाक्यूमेंट सेक्शन में ९६० से ४,८९३ और फोटोग्रैफिक सेक्शन में ५,४५६ से ७,६६३ हो गई। व्यक्तिगत लोगों का या ऐसे विभागों का काम करने, जिन्हें फीस देनी पड़ती है, से होन वाली इस विभाग की आय भी बढ़ गई। फिगर प्रिन्ट ब्यूरो और फोटोग्रैफिक सेक्शन की क्रमशः ८,८३३ रु० और ६,२८५ रु० आलोच्य वर्ष में अम्नदनी हुई।

अपराध तफतीश विभाग के मुख्यालय में स्पेशल ब्रांच (विशेष शाखा) के अफसरों और कर्मचारियों के लिये तथा जिलों के तफतीश करने वाले अफसरों और डिस्ट्रिक्ट क्राइम रेकार्ड सेक्शन के इन्चार्ज सब-इन्स्पेक्टरों के लिये ट्रेनिंग के कोर्सों का संगठन किया गया। प्रशिक्षण का स्तर बढ़ाने के विचार से सब पाठ्य-विषयों का पाठ्यक्रम भी संशोधित किया गया।

गांव वालों
में नया जोश

जिला कार्य-
कारी दल

अपराध तफ-
तीश विभाग

**प्राविशियल
आर्म्ड कांस्टे-
बुलरी**

वर्ष के आरम्भ में पी० ए० सी० की ७७ कम्पनियां थी, जिनमें से १७ उत्तर प्रदेश के बाहर ड्यूटी दे रही थीं। वर्ष के अन्त में कम्पनियों की संख्या ७१ थी और इनमें से पांच उत्तर प्रदेश के बाहर (हैदराबाद) रही थी। पी० ए० सी० के दल, जो अन्य राज्यों को दिये गये थे, के कार्य और आचरण की बड़ी सराहना की गई। विभिन्न राज्यों के उच्च अधिकारियों का एक बोर्ड, जो अगस्त, १९५१ ई० में हैदराबाद गया उसकी राय में पी० ए० सी० का कार्य देश के दूसरे ऐसे ही दलों के लिये आदर्श रूप था।

आलोच्य वर्ष में ५० कम्पनियों की आठ बटालियन स्थायी कर दी गईं।

**बेतार के तार
का उप-विभाग
(वायरलेस
टेलीग्राफी
सेक्शन)**

अग्रेंटिसो की दो बँचों की ट्रेनिंग समाप्त होने से बेतार के तार के उपविभाग (वायरलेस टेलीग्राफी सेक्शन) के लोगो की संख्या पिछले वर्ष की ६०४ से बढ़ कर ६४६ हो गई। परन्तु सैक्शन की स्वीकृत संख्या ७९० थी। ५२ आपरेटरो को उच्च श्रेणी का पाठ्य-क्रम पढाया गया।

सेक्शन द्वारा भेजे गये सन्देशो की १९५० ई० की संख्या ३,६९,९६५ से बढ़ कर ३,७९,५४९ हो गई।

**प्रान्तीय रक्षक
दल**

प्रान्तीय रक्षक दल ने उपयोगी सहायता कार्य किया और गांवों में डकैतों का संगठित रूप से सामना करने में विशेष रूप से भाग लिया। पुनर्संगठन के पश्चात् इस दल ने विकास सम्बन्धी कार्यवाहियों में भाग लिया और विभिन्न विकास योजनाओं के चलाने के लिये जिले के समस्त कर्मचारिगण के साथ-साथ काम किया।

विविध

पुलिस कर्मचारी रचनात्मक कार्यों में बराबर हाथ बटाते रहे, जैसे अपने विभाग की इमारतों का मामूली मरम्मत, पेड़ लगाना आदि। उन्होंने बहुत सी जगहों में पलस्तर लगाने, पोताई करने और खपरैलों को ठीक करने का कार्य किया और पुलिस लाइनो और थाने के कम्पाउण्डों में हजारों की संख्या में फल और छायादार पेड़ लगाये।

(ख) फौजदारी

**फौजदारी के
मामलों का
निपटारा
जाना**

फौजदारी मुकदमों को शीघ्रता से निपटाने के लिये मैजिस्ट्रेटों को अनुदेश जारी किये गये। उनसे निवेदन किया गया कि वे सेशन को अदालत में मुकदमा भेजने के पूर्व समस्त सबूत पक्ष के गवाहों (prosecution witnesses) की साक्ष्य अभिलिखित कर ले और विशेष परिस्थितियों में कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (दण्ड विधि संहिता) की धारा २१९ के अधीन अतिरिक्त साक्ष्य अभिलिखित कर ले। मैजिस्ट्रेटों से यह भी कहा गया कि वे सप्ताह में कुछ दिन किसी विशेष थाने या थानों के मुकदमों के काम (case work) के लिये नियत कर दें, जिससे प्रभारी (इन्चार्ज) सब-इन्स्पेक्टर बुलाये गये सब गवाहों को उस दिन अदालत में ला सकें और इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाय कि सभी गवाह निश्चित दिन पर अपनी गवाही देने के लिये उपस्थित हो जायें। सरकारी नौकरो विशेषतः मैजिस्ट्रेटों और पुलिस अधिकारियों के गवाहों के लिये नियत तारीख पर उपस्थित होने की वांछनीयता पर पुनः जोर दिया गया।

**सब-रजिस्ट्रार,
मैजिस्ट्रेट और
अवैतनिक
मैजिस्ट्रेट**

वह योजना, जिसके अधीन योग्य सब-रजिस्ट्रारों को फौजदारी मुकदमों को निपटाने के सम्बन्ध में दूसरी श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के अधिकार प्रदान किये गये थे, उपयोगी सिद्ध हुई और उसे इस वर्ष बढ़ाया गया। कुछ जिलों में फौजदारी मुकदमों को निपटाने के लिये अतिरिक्त अवैतनिक मैजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये।

१९५१ का कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेशीय संशोधन) ऐक्ट, जिसके द्वारा कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा ४९८ तथा ५२८ का संशोधन किया गया है, इस वर्ष पारित किया गया। जमानत के प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में सेशन जज द्वारा प्रयोग किये जाने वाले अधिकार अभी तक किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रयोग नहीं किये जा सकते थे और चूंकि कई सेशन जज कुछ जिला के सदर मुकामों (हेडक्वार्टर्स) में स्थायी रूप से अपना इजलास नहीं लगा सके, इसलिये इन जिलों के मुकदमा लड़ने वालों को काफी असुविधा उठानी पड़ी। संशोधित धारा ४९८ के अधीन अतिरिक्त सेशन जजों और सहायक सेशन जजों को जमानत के प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में सेशन जज के अधिकारों का प्रयोग करने का प्राधिकार देकर मुकदमा लड़ने वालों को सुविधा दी गई। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा ५२८ में किये गये संशोधन से सेशन जज को सेशन डिवीजन के अतिरिक्त जजों की अदालतों से किसी भी मुकदमे या अपील को डिवीजन में कार्य-वितरण का उपयुक्त प्रबन्ध करने के उद्देश्य से लेने या उनका प्रत्यावर्तन करने का अधिकार मिल गया। अब तक वह उन्हीं मुकदमों या अपीलों को वापस ले सकता था या उनका प्रत्यावर्तन कर सकता था जिन्हें उसने स्वयं अतिरिक्त सेशन जज के सुपुर्द किया हो।

कोड आफ
क्रिमिनल
प्रोसीजर (दण्ड
विधि संहिता
का संशोधन

पब्लिक गैम्बलिंग ऐक्ट, १८६७ की धारा ३ और ४ बस्ती, हमीरपुर, आगिरा, झांसी, बांदा, इटावा और रामपुर जिलों के कुछ क्षेत्रों में भी लागू की गई। उक्त ऐक्ट की धारा ३, ११, १३-क और १४, १६ मुरा और जालौन जिलों के कुछ क्षेत्रों में लागू की गई।

१८६७ ई०
का पब्लिक
गैम्बलिंग
ऐक्ट

रेलगाड़ियों में बिना टिकट यात्रा करने की रोकथाम योजना का कार्य संतोषजनक ढंग से होता रहा और इस वर्ष यह योजना और व्यापक बनाई गई।

बिना टिकट
रेल यात्रा
करने की
रोकथाम

• (ग) जेल

जेल के कैदियों की प्रतिदिन की औसत संख्या में थोड़ी कमी हुई और आलोच्य वर्ष में यह संख्या २९,०६४ थी। पहली जनवरी, १९५१ ई० को कैदियों की संख्या ३०,३२२ थी और ३१ दिसम्बर, १९५१ ई० को २९,२८३। कैदियों में अनुशासन और उनके स्वास्थ्य की दशा वर्ष भर संतोषजनक रही।

कैदियों की
संख्या, स्वा-
स्थ्य और
अनुशासन

वर्ष में कई महत्वपूर्ण सुधार किये गये और कैदियों को नई सुविधायें प्रदान की गईं। नवजवान कैदियों को जुनाइल (अल्पवयस्क) जेल, बरेली तथा रिफारमेटरी (सुधारक) स्कूल, लखनऊ में भेजने के नियमों में संशोधन किया गया। देहरादून, बदायूँ, रायबरेली और सेन्ट्रल जेल, नैनी में रेडियो लगाये गये। उच्च श्रेणी की महिला कैदियों के साथ हिरासत में रखे गये बच्चों के भोजन के परिमाण में संशोधन किया गया और चावल के भोजन में नमक का परिमाण बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश के जेलों में कैदियों और कर्मचारियों के लिये निम्नलिखित अतिरिक्त छुट्टियां मंजूर की गयीं :—

सुधार

बाराकफात, शिवरात्रि, राम-नवमी, जन्माष्टमी और जन-तन्त्र दिवस।

वित्तीय संकट और व्यय में कमी करने के कारण इमारत बनाने के कार्य-क्रम में कमी की गई। कर्मचारियों के कई क्वार्टरों तथा तीन सुपरिन्टेण्डेंटों के बंगलों में सुधार और परिवर्तन किये गये। कुछ क्वार्टर और एक

• इमारतें
बिजली और
पानी

रसोईघर बनाया गया और एक जेल में एक बगीचे की कच्ची चहारदीवारी को पक्का किया गया। एक दूसरे जेल में मुख्य दीवाल की ऊंचाई में वृद्धि की गई।

एक जेल में एलेक्ट्रिक मोटर पम्प लगाया गया और एक दूसरे जेल में एक नया कुआं खोदा गया। लखनऊ में आदर्श जेल तथा जिला जेल में दो ट्यूबवेल बनाये गये। तीन जेलों में बिजली दी गई और १२ क्वार्टरों में भी बिजली लगाई गई।

जेल उद्योग

जेल के उद्योगों में कुछ विकास हुआ और जनता में बिक्री के लिये अधिक सामान तैयार करने के विचार से जेल के अधिक कैदियों को काम पर लगाया गया। समय से ऊन के न मिलने के कारण कम्बल बनाने के काम में बाधा पड़ी। मूँज घास के आघात तथा सूत के भ्रष्ट करने में भी थोड़ी कठिनाई हुई।

जेल में खेती

मौसम के अनुकूल न होने के कारण रबी और खरीफ दोनों फसलों को नुकसान हुआ। बाहर काम करने वाले कैदियों की कमी बनी रही, तथापि जेल के बगीचों का इन्तजाम ठीक से होता रहा।

• ११ जिलों में कृषि फार्म की स्वीकृति दी गई।

सुधार और पुनर्वास सम्बन्धी कार्य

रिफारमेटरी (सुधारक) स्कूल तथा जुवेनाइल (अल्पवयस्क) जेल की प्रतिदिन की औसत आबादी क्रम से ७१ और ११८ थी। जुवेनाइल (अल्पवयस्क) जेल के २९ लड़कों को बाहर कार्य करने की सुविधा दी गई थी और वर्ष में उन्होंने ६,९७१ रु० १३ आना पैदा किया। जुवेनाइल (अल्पवयस्क) जेल के १४ तथा रिफारमेटरी (सुधारक) स्कूल के ८९ लड़कों ने विभिन्न उद्योगों में अर्हता (qualification) प्राप्त की। उन्होंने क्रम से २,३८९ रु० ९ आना ६ पाई तथा ५,६१९ रु० ७ आना ६ पाई पैदा किया। रिफारमेटरी (सुधारक) स्कूल के लड़कों ने स्कूल के बाहर बन्द बजाकर के १६० रु० कमाया।

ट्रेनिंग

जेल के डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल को यू० एन० ओ० की फेलोशिप मिली और वे ६ महीने की ट्रेनिंग के लिये इंग्लैण्ड गये। जेल ट्रेनिंग स्कूल के १९५१-५२ के सेशन में ४ डिप्टी-जेलर तथा ४० वार्डर ट्रेनिंग के लिये भेजे गये। विभिन्न राज्यों के ९ बाहरी कैदियों को भी ट्रेनिंग के लिये दाखिल किया गया। कई प्रसिद्ध शिक्षा विशेषज्ञ, जिनमें यू० एन० ओ० के डाक्टर वाल्टर सी० रेकलेस भी सम्मिलित है, स्कूल में गये। डाक्टर वाल्टर सी० रेकलेस अपराध विज्ञान के विशेषज्ञ है और उन्होंने विभिन्न विषयों पर व्याख्यान दिया। इन व्याख्यानों को विभिन्न राज्यों के अधिकारियों ने भी सुना।

स्थापना

कम्पाउण्डरों के कैडर को २९ से बढ़ाकर ५१ कर दिया गया। सेंट्रल जेलों में हेडवार्डर के पदों को चुनौत द्वारा भर्ती का पद घोषित किया गया और जेलों के इन्स्पेक्टर जनरल को इन पदों की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियुक्ति अधिकारी बनाया गया।

कुछ जेलों में नाटक खले गये, प्रदर्शनियां सगठित की गईं और सिनेमा दिखाये गये। सेंट्रल जेल, नैनी और जिला जेल, फतेहगढ़ तथा उन्नाव में कैदियों के लिये कैंटीन खोले गये।

१५—हरिजन उत्थान तथा पुनरुद्धार

शिक्षा

१९५१ ई० में हरिजन सहायक विभाग की कार्यवाहियों में विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ। अनुसूचित जातियों के पिछड़े हुए वर्गों तथा मोमिन में शिक्षा प्रसार के लिये ३० लाख की धनराशि खर्च हुई थी, जब कि गत वर्ष इसके लिये १७ लाख रुपये खर्च किये गये थे। वर्तमान सुविधायें, जिनमें फीस माफ करने तथा छात्र-वेतनों की व्यवस्था सम्मिलित थी, दी जाती रही। एक विशेष बात यह थी कि डिग्री तथा पोस्ट-ग्रेजुएट कक्षाओं में पढ़ने वाले हरिजन विद्यार्थियों को छात्र-वेतन दिये गये। आलोच्य वर्ष में १,३३६ विद्यार्थियों (हरिजन ७००, पिछड़े वर्गों के सदस्य ६३६) को इंटरमीडियेट डिग्री और पोस्ट-ग्रेजुएट कक्षाओं में छात्र-वेतन दिये गये। इन कक्षाओं में अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के बच्चों को क्रमशः ७०,५२० रु० तथा ३१,५९२ रु० तक की अनावर्तक सहायता दी गई। प्रारंभिक कक्षाओं, जूनियर हाई स्कूल तथा हाई स्कूल कक्षाओं में बहुत से छात्र-वेतन दिये गये और उनके अतिरिक्त ४७,९२० रु० की अनावर्तक सहायता भी दी गई।

हरिजनों के लिये लड़कों तथा लड़कियों की रात्रि तथा दिन की पाठ-शालाओं, छात्रावासों, पुस्तकालयों आदि की सदा की भांति विभाग से सहायक अनुदान मिले और आलोच्य वर्ष में उनकी संख्या ३४५ से बढ़कर ३८४ हो गई। प्रत्येक पुस्तकालय को पुस्तकों खरीदने के लिये २०० रु० का अनुदान दिया गया।

शिक्षा सम्बन्धी सुविधा के कारण प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल तथा हाई स्कूल की कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या बहुत जल्दी बढ़ गई। विश्व-विद्यालय में भी उनकी संख्या १९५१ ई० में ६८८ हो गई, जबकि १९५० ई० में केवल ४८४ थी।

उत्तर प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग या रिसेटिलमेंट तथा इम्प्लायमेंट डायरेक्टरेट द्वारा संचालित विभाग के विभिन्न व्यावसायिक तथा शिल्प शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं में ८०० विद्यार्थियों को छात्र-वेतन मिलता था। ये छात्र-वेतन कारीगरों के छोटे दर्जों के ८ रु० प्रतिमास से लेकर कुछ उच्च श्रेणी के टेक्निकल ट्रेनिंगों के लिये १२५ रु० मास तक हैं। विभाग के टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, बकशी का तालाब (लखनऊ जिला) में ८६ लड़कों को ९ कलाओं में निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इस केंद्र पर ४० रु० प्रतिमास छात्र-वेतन दिया जाता था तथा निःशुल्क निवास-स्थान की भी व्यवस्था थी। एक हरिजन विद्यार्थी को अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये राज्य सहायता दी गई।

शिल्प सम्बन्धी
प्रशिक्षण

वर्ष के दौरान में सफ़ाई इत्यादि की अच्छी व्यवस्था के लिये प्राप्त ३.७ लाख रुपये के उपयोग का प्रबन्ध किया गया। विभाग ने इस धनराशि में से २०,००० रु० सीधे हरिजनों की बस्तियों में कुएं बनवाने तथा उनकी मरम्मत कराने में व्यय किया और २.७ लाख रुपया ४७ जिलों की जिला नियोजन समितियों को इसी उद्देश्य से व्यय करने के लिये दिया गया। वर्ष में पानी पीने के लिये बनाये गये कुओं की संख्या ५,२४९ और मरम्मत किये गये कुओं की संख्या ९,६४७ थी। ६०,००० रु० की एक दूसरी धनराशि फैजाबाद,

सफ़ाई, पानी
की व्यवस्था
इत्यादि

गोरखपुर, बिजनौर, आगरा, मथुरा, सहारनपुर, आजमगढ़, बलिया, इटावा, गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ तथा नैनीताल नामक १४ जिलों को हरिजनो के लिये घर बनवाने तथा उनकी मरम्मत करने के लिये दिया गया। इसमें वह सहायता भी सम्मिलित है जो उन हरिजनों को दी गई थी जिनके घर अग्नि तथा बाढ़ जैसी आपदाओं से नष्ट हो गये थे। बलिया में हरिजनो के बार्डरों के निर्माण के लिये अंशदान के रूप में वहाँ के म्यूनिसिपल बोर्ड को १०,००० रु० की धनराशि दी गई। इटावा में सामुदायिक केन्द्र के विकास के लिये ३०० रु० का अनुदान भी दिया गया।

छूत-छात का उन्मूलन

हरिजनो के साथ अच्छा व्यवहार हो, इस सम्बन्ध में जिला हरिजन सहायक उप-समितियों ने बड़ा कार्य किया। सरकार ने इन समितियों को ५०,००० रु० की धनराशि दी, जिससे कि वे कल्याण-कार्य पर अपने खर्च को पूरा कर सकें। विज्ञापन-पत्रों, सिनेमा स्लाइडों, समाचार-पत्रों में विज्ञापनों तथा प्रदर्शिनियों और मेलों में विशिष्ट दूकानों द्वारा छूत-छात उन्मूलित करने तथा हरिजनो को दूसरे नागरिकों के समान सामाजिक दर्जा देने की आवश्यकता पर जनता की शिक्षा देने के प्रयत्न किये गये। यू० पी० रिमूवल आफ सो गल डिस्पेविलिटीज ऐक्ट, १९४७ को कार्यान्वित करने पर भी जोर दिया गया।

दूसरी एजेन्सियों द्वारा कार्य

कई गैरसरकारी संस्थाओं को आर्थिक सहायता दी गई जिससे वे हरिजन-उत्थान सम्बन्धी कार्य कर सकें। इनमें हरिजन आश्रम, इलाहाबाद; सरवेन्ट्स आफ इंडिया सोसाइटी, इलाहाबाद तथा कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल, कौसानी (अल्मोड़ा) सम्मिलित हैं। स्वर्गीय मंशी ईश्वर शरण द्वारा स्थापित हरिजन आश्रम, हरिजनो के लिये एक अस्पताल, एक औद्योगिक स्कूल, एक हायर सेकेंडरी स्कूल तथा एक छात्रावास चलता रहा और उनको २७,००० रु० का अनुदान दिया गया। सरवेन्ट्स आफ इंडिया सोसाइटी ने जिला मिर्जापुर के दूधी क्षेत्र में बसने वाली आदिवासी जातियों में शिक्षा प्रसार के लिये २२ स्कूलों को चलाया। इन जातियों के लिये कल्याणकारी कामों में सरकार का कुल २०,००० रु० व्यय हुआ। कौसानी की संस्था में निवास की व्यवस्था थी। यहाँ अन्य जातियों की लड़कियों के साथ हरिजनों की लड़कियों को शिक्षा दी जा रही थी, जिससे वे आत्म-निर्भर और समाज की सभ्य जग बन सकें।

उद्धार कार्य

सरकार ने सिद्धांत रूप से "उत्तर प्रदेश अपराधशील जातियों की जांच समिति" की यह सिफारिश कि "क्रिमिनल ट्राइव्स ऐक्ट" निर्वर्तित कर दिया जाय, मान लिया। यह प्रयत्न किया गया कि ऐक्ट के निर्वर्तित होने की अवधि तक इसका पालन जितना संभव हो उतनी उदारता से किया जाय। गोरखपुर के डोमों, साहबगंज के ससियों, कांथ के भाटों को अपराधशील जातियों की सूची से अलग किया गया तथा उनको प्रतिबन्ध-मुक्त घोषित किया गया। अपराधशील जातियों के सुधार तथा पुनर्वासन की योजना चालू रही और यह देखा गया कि सरकार ने जो विकास सम्बन्धी कार्यवाहियाँ की थी उनसे अपराधशील जातियों के लोगों का बहुत सुधार हुआ और वे कृषि तथा जीवन पालन के अन्य अच्छे साधनों को अपनाने की ओर आकर्षित हुए। कन्यानपुर की बस्ती की आबादी १,०९८ थी और वहाँ बसने वाले व्यक्ति या तो कृषि-कार्य में या बस्ती के सिलाई के कारखाने में या कानपुर के विभिन्न कारखानों में नौकरी कर रहे थे। फजलपुर और मुरादाबाद की बस्तियों की जनसंख्या १,२६९ थी और इन बस्तियों के सदस्यों को भी अधिकतर कृषि-कार्य में लगाया गया।

मुजफ्फरनगर, कांथ और साहबगंज तीनों उपनिवेशों में भी बसने वालों के पास पर्याप्त कृषि भूमि थी और वे लोग यह उपयोगी कारोबार करते रहे।

गोरखपुर और लखनऊ की बस्तियाँ गैर-सरकारी प्रबन्ध में नहीं। गोरखपुर में बंमने वाले डोमो को प्रतिबन्ध-मुक्त कर दिया गया, किन्तु बस्तियाँ पूर्व की भाँति उनके लिये सुविधाओं की व्यवस्था करती रहीं। गोडा में बरवारों के लिये २६,००० रु० की लागत पर एक नये उपनिवेश की स्थापना की गयी।

अपराधशील जातियों के बच्चों को शिक्षा के लिये विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई। बाउरिया उपनिवेश में एक मिडिल स्कूल था और प्रत्येक बस्ती में एक प्राइमरी स्कूल था। इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी गई और छात्र-वैतन तथा पुस्तकों की भी व्यवस्था की गई। पृथक्कीकरण योजना, जिससे काफी लाभ हुआ, जारी रही। बच्चों को हानिकार पारिवारिक वातावरण से दूर रखने के लिये गोरखपुर में एक विशेष छात्रावास की व्यवस्था की गई। अपराधशील जातियों की पंचायतें उनकी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिये पूर्ववत् प्रयत्न करती रही।

१६ — दंड न्याय-व्यवस्था

मथुरा और एटा के लिये अलग सेशन डिवीजन कायम करने के फलस्वरूप एसे डिवीजनों की संख्या १९५० ई० में २९ से बढ़कर आलोच्य वर्ष में ३१ हो गई। भारी फौजदारी कार्य निपटाने के लिये बरेली, कुमायूँ और लखनऊ के सेशन डिवीजनों में अतिरिक्त जिला तथा सेशन जजों के अस्थायी न्यायालय और राज्य के २९ जिलों में दीवानी तथा सेशन जजों के अस्थायी न्यायालय कायम किये गये। इन अस्थायी न्यायालयों ने कुल मिलाकर २४ साल ११ महीना २३ दिन की अवधि तक काम किया, जबकि पिछले वर्ष इन्होंने २५ साल ७ महीना ६ दिन की अवधि तक काम किया था।

भारतीय दंड विधान के अधीन जितने अपराधों की रिपोर्ट की गयी उनकी कुल संख्या विगत वर्ष की १,०४,३२५ की तुलना में इस वर्ष घट कर १,०२,७२७ रह गयी। किन्तु रिपोर्ट किये गये अपराधों की कुल संख्या में वृद्धि हुई। शीर्षक “झुंठी गवाही और सरकारी न्यायाधीशों के विरुद्ध अपराध”, “सार्वजनिक शान्ति के विरुद्ध अपराध”, “उपघात तथा सदीष बल प्रयोग एवं आक्रमण”, “अपहरण, बलात् अपहरण, इत्यादि” और “दंड्य न्यासभंग (क्रिमिनल ब्रीच आफ ट्रस्ट)” के अधीन अपराधों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि दिखाई पड़ी। दंडविधि सप्रह के अधीन और विशेषतया स्थानीय विधियों के अधीन मामलों की (जिनमें पिछले वर्ष के विचाराधीन मामले भी सम्मिलित हैं) रिपोर्ट की गयी। उनकी संख्या २,९३,८१९ से बढ़ कर ३,१३,६१३ हो गयी।

७,२२,६२३ व्यक्तियों पर मैजिस्ट्रेटों के समक्ष मुकदमा चल रहा था। इनमें से २,०९८ मर गये, भाग गये या दूसरे राज्यों को भेज दिये गये, ३,२६,८५१ को छोड़ दिया गया या निर्दोष ठहराया गया; २,५४,२०८ को दंड दिया गया; २१,४५३ को सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया गया और आलोच्य वर्ष के अंत में १,०९,८४३ व्यक्तियों पर मुकदमा चल रहा था।

वे व्यक्ति
जिन पर
मुकदमा चल
रहा था

भारतीय दंड विधान के अधीन ३,१६,१२६ व्यक्तियों का चालान किया गया। उनमें से १,६०,०६८ व्यक्तियों को निर्दोष ठहराया गया या छोड़ दिया गया; ४८,१८६ को दंड दिया गया; १,१२४ मर गये, भाग गये या दूसरे राज्यों को भेज दिये गये और वर्ष के अंत में ७६,७४५ व्यक्तियों पर मुकदमा चल रहा था। दंड विधि संग्रह तथा विशेष और अन्य स्थानीय विधियों के अधीन अपराधों के लिये ४,११,४३८ व्यक्तियों का चालान किया गया। इनमें से १,५१,३१२ को या तो निर्दोष ठहराया गया या छोड़ दिया गया; २,१६,८७५ को दंड दिया गया; १,०७० मर गये, भाग गये या दूसरे राज्यों को भेज दिये गये और वर्ष के अंत में ३६,१८१ व्यक्तियों पर मुकदमा चल रहा था।

निर्णीत
मुकदमों

इस वर्ष निर्णीत मुकदमों की संख्या ३,०६,६३५ थी, जबकि पिछले वर्ष इनकी संख्या २,८७,६१२ थी। यह वृद्धि मुख्यतया वैतनिक विशेष मैजिस्ट्रेटों, अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों, सबडिवीजनल मैजिस्ट्रेटों और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में हुई। अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों ने १,४७,३२६ व्यक्तियों के मुकदमों का निर्णय किया, जबकि पिछले वर्ष १,३२,७२२ व्यक्तियों के मुकदमों में निर्णय हुआ था। आलोच्य वर्ष में ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या, जिनके मुकदमों में निर्णय हुआ था, ६,११,६३८ थी।

गवाह

मैजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में जितने गवाहों ने बयान दिया उनकी संख्या ४,६४,२७४ से बढ़ कर ५,११,०२८ हो गयी तथा सेशन जजों के न्यायालयों में यह संख्या ५५,३४१ से बढ़कर ५८,२३० हो गयी। मैजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में उन गवाहों की संख्या, जो न्यायालयों में उपस्थित तो हुये, किन्तु बयान लिये बिना ही उन्हें छोड़ दिया गया, ५५,६७४ से घटकर ५५,७७७ हो गयी तथा सेशन के न्यायालयों में यह संख्या ६,६६५ से बढ़कर ६,७६६ हो गयी।

असेसरों की
सहायता से
मुकदमों पर
विचार

असेसरों की सहायता से जिनने व्यक्तियों के मुकदमों पर विचार किया गया उनकी संख्या १८,८४७ से बढ़कर १६,२७६ हो गयी।

जुरी द्वारा
मुकदमों
पर विचार

जुरी की सहायता से मुकदमों पर विचार किये जाने का ढंग पहिले की भांति इलाहाबाद, बनारस, बरेली, फैजाबाद, कानपुर और लखनऊ जिलों में जारी रहा। जिन व्यक्तियों के मुकदमों का इन्होंने फैसला किया उनकी संख्या इन जिलों के सेशन कोर्टों में १,०८४ से घट कर ८८४ हो गयी।

मुकदमों की
अवधि

मैजिस्ट्रेटों के सभी न्यायालयों में मुकदमों की औसत अवधि २३ दिन बनी रही। किन्तु सेशन के न्यायालयों में यह ६७ से बढ़कर ११० दिन हो गया।

अभियोगों का
परिणाम
और दंड

मैजिस्ट्रेटों तथा सेशन दोनों के न्यायालयों में दंड पाने वाले व्यक्तियों में से ३५,१६७ को कारावास का दंड मिला, २,०८,७६८ पर जुर्माने किये गये और १२४ को बेंत लगाये गये। इसके अतिरिक्त ३३,६०६ व्यक्तियों से जमानतें माँगी गयीं।

• ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या, जिन्हें सेशन के न्यायालयों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया (ऐसे व्यक्तियों को सम्मिलित करके, जिनके मुकदमों पिछले वर्ष से विचाराधीन थे), ३४२ से बढ़कर ४०५ हो गई। इनमें से ६८ व्यक्तियों के दंडों की पुष्टि की गई, १०३ को अपील पर छोड़ दिया गया, ७७ के दंड हाईकोर्ट से संशोधित कर दिये गये और एक व्यक्ति मर गया। वर्ष के अंत में १२६ व्यक्ति

फासी पाने वाले व्यक्तियों की संख्या २२ से घट कर ११ हो गयी ।

ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जिनको आजन्म कारावास का दंड दिया गया, ५८३ से बढ़ कर ८१३ हो गई । इसी प्रकार जिन व्यक्तियों को कठोर कारावास का दंड दिया गया उनकी कुल संख्या २४,१३३ से बढ़ कर २६,४३८ हो गयी ।

सेशन के न्यायालयों द्वारा लगाये गये जुर्माने की कुल धनराशि १,७६,६७४ रु० से बढ़ कर २,५७,४७६ रु० हो गयी । मैजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में यह ५१,६५,८६८ रुपया से बढ़ कर ६१,०२,५८६ रु० हो गयी ।

ऐसे लोगों की कुल संख्या, जिनसे शान्ति बनाये रखने के लिये मुचलके लिये गये, ३०,५८५ से घट कर २४,७७८ हो गई । गोंडा में शान्ति बनाये रखने के संबंध में मुचलका लिये जाने वाले व्यक्तियों की सबसे अधिक संख्या २,८८६ थी । ऐसे लोगों की कुल संख्या, जिनसे सद्व्यवहार बनाये रखने के संबंध में मुचलके लिये गये, ६,०७० से घट कर ८,३२६ हो गई । सद्व्यवहार बनाये रखने के संबंध में मुचलके लिये गये व्यक्तियों की सबसे अधिक संख्या कानपुर (७०६), आगरा (६२८) और सहारनपुर (४०२) के जिलों में थी ।

शान्ति बनाये रखने तथा अच्छे व्यवहार करने के लिये मुचलके

पहली बार अपराध करने वालों की कुल संख्या, जिन्हें या तो चेतावनी देकर या यू० पी० फर्स्ट अफेन्डर्स प्रोवेशन ऐक्ट, १९३८ ई० के अधीन छोड़ दिया गया, ६,२१६ से बढ़ कर ७,३५६ हो गई । ऐसे अपराधियों की संख्या, जो प्रोवेशन अफेन्डर्स की देख-रेख में रखे गये, १६८ से बढ़ कर २२८ हो गयी ।

पहली बार अपराध करने वाले तथा अल्पवयस्क

हाईकोर्ट में अपील करने वालों की संख्या ८,१८७ से बढ़ कर ८,६८२ हो गयी । सरकारी अपीलों की संख्या, जिनमें पिछले वर्ष की विचाराधीन अपीलों भी सम्मिलित हैं, १५२ थी, जबकि १६५० ई० में उनकी संख्या १०२ थी । इनमें से ५ स्वीकार कर ली गयीं, २० खारिज कर दी गयीं और वर्ष के अंत में १२७ विचाराधीन रह गयीं । अन्ध न्यायालयों के समक्ष अपील करने वालों की संख्या ४७,६३७ थी, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या ४१,५२४ थी ।

अपीलों

१७—दीवानी न्याय-व्यवस्था

(क) उच्च न्यायालय

१९५१ ई० में उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीशों की संख्या २० थी । एक न्यायाधीश की मृत्यु तथा दूसरे के अवकाश ग्रहण कर लेने से उनके रिक्त स्थानों पर दो नये न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई ।

उच्च न्यायालय के समक्ष फैसले के निमित्त नम्बरी अपीलों की कुल संख्या १३,०६६ थी, जबकि गत वर्ष उनकी कुल संख्या १२,७५७ थी । इस वर्ष दायर की गई अपीलों की संख्या २,६८८ से बढ़ कर ३,६६४ हो गई । इन्तदाई डिप्रियों के विरुद्ध की गयी अपीलों की संख्या ५२० से बढ़ कर ६६७ हो गई और अपील की डिप्रियों के विरुद्ध की गई अपीलों की संख्या २,४२२ से बढ़ कर २,६२५ हो गई । इस न्यायालय के किसी एक ही जज द्वारा किये गये फैसलों के विरुद्ध की गयी अपीलों की संख्या ६४ से बढ़ कर १०२ हो गई ।

अपीलों

सब प्रकार की अपीलों की कुल संख्या जिनका फैसला इस वर्ष इस न्यायालय ने किया, ३,७३५ से घट कर २,२६४ हो गई। इन्तर्दाई डिग्रियों के विरुद्ध की गई अपीलों की संख्या, जिनका फैसला इस न्यायालय ने किया, ३६१ से बढ़ कर ४२७ हो गई और अपील की डिग्रियों के विरुद्ध की गई अपीलों की संख्या, जिनका फैसला किया गया, ३,३३६ से घट कर १,८३४ हो गई। फिर भी एक ही जज द्वारा किये गये फैसलों के विरुद्ध की गई अपीलों की संख्या ३८ से घट कर ३३ हो गई।

इस वर्ष के अन्त में विचाराधीन नम्बरी अपीलों की कुल संख्या १०,८०५ थी जब कि गत वर्ष के अन्त में उनकी संख्या ९,०२२ थी। पांच वर्ष से विचाराधीन अपीलों की संख्या ३१ दिसम्बर, १९५१ ई० को १,७४८ थी।

पूरी बेच के पास फैसले के लिये भेजे गये मुकदमों

पूरी बेच के पास फैसले के लिये भेजे गये मुकदमों की संख्या १०० थी, जिनमें ८३ मुकदमों ऐसे भी सम्मिलित हैं जो पिछले वर्ष से विचाराधीन थे। इनमें से ३८ मुकदमों का फैसला कर दिया गया और वर्ष के अन्त में ६२ विचाराधीन थे। इंडियन बार कौन्सिल्स ऐक्ट (ऐक्ट संख्या ३८, १९२६ ई०) के अन्तर्गत इस न्यायालय के पास फैसले के लिये एडवोकेटों के ध्यावसायिक दुराचरण संबंधी १० मुकदमों भेजे गये। इस वर्ष इन सब का फैसला कर दिया गया।

शेष काम

उच्च न्यायालय में बकाया काम में वृद्धि विभिन्न कारणों से हुई, जिनमें दायर किये गये फौजदारी के मुकदमों की संख्या में वृद्धि तथा दायर किये गये आदेश लेख संबंधी मुकदमों की पेचीदगी सम्मिलित हैं। आदेश लेख संबंधी मुकदमों में आम तौर से काफी समय लगा और प्रायः उनको ऐसी पूरी बेच के पास भेजना पड़ता था जिनमें तीन या पांच जज रहते थे। जमींदारी विनाश अधिनियम के विरुद्ध आदेश लेख प्रार्थना-पत्रों के संबंध में, जिनकी सुनवाई पांच जजों वाली पूरी बेच ने की, लगभग दो महीने लग गये। बकाया काम इकट्ठा हो जाने के संबंध में अन्य कारणों के साथ-साथ ये कारण भी थे कि न्यायालय के दिन प्रतिदिन कार्यों से संबंध न रखने वाले अन्य कार्य के लिये जजों की तैनाती की गई और उनकी जगह पर रखने के लिये आदमी न मिल सके, यहां तक कि एक जगह पर तो लगभग ६ महीने तक कोई व्यक्ति न मिल सका और उसकी पूर्ति न हो सकी।

(ख) दीवानी अदालतें

क्षेत्राधिकार

मथुरा तथा एटा के लिये दो नई जजों की स्थापना के फलस्वरूप उच्च न्यायालय के अधीनस्थ दीवानी अदालतों के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में कुछ परिवर्तन हुआ। मथुरा और एटा की नई जजों क्रमशः २२ और २३ सितंबर, १९५१ ई० से कार्य करने लगी।

नालिशों

राज्य की अधीनस्थ अदालतों में दायर की गयी नालिशों की कुल संख्या (जिनमें ऋणग्रस्त सम्पत्तियों के ऐक्ट के अधीन हुई नालिशें सम्मिलित नहीं हैं, किन्तु एग्रीकल्चर रिलीफ ऐक्ट की धारा १२ और ३३ के अधीन दी हुई दरखास्तें सम्मिलित हैं) १,०४,००० से घट कर १,०२,७८८ रह गयी। अचल संपत्ति के संबंध में की गयी नालिशों की संख्या २२,८३२ से बढ़ कर २३,१३८ हो गई, जब कि अधीनस्थ अदालतों में दायर की गई नालिशों की कुल मालियत ९,०९,३०,९३८ से घट कर ८,५४,११,२७७ रह गयी। मालियत के गिरने का कारण यह था कि दायर की गई नालिशों की संख्या में कमी हो गई थी।

जिन इन्तदाई नालिशो का फैसला किया गया उनकी संख्या में ९,५९० की कमी हुई (यह सख्या पिछले वर्ष के १,५३,६५९ से घटकर १,४४,०६९ हो गई)। ऐसे मुकद्दमो की संख्या, जिनका फैसला मुन्तकिली के अतिरिक्त अन्य ढंगों से किया गया, १,१८,७१३ से घटकर १,१३,३९१ रह गयी और ऐसी नालिशों की कुल संख्या, जिनका फैसला अदालतो को करना था, २,३६,३०७ से घट कर २,२७,५५१ रह गयी। ऐसी नालिशों की संख्या, जिनका फैसला पूरी सुनवाई के बाद किया गया, ३२,०७४ थी, जबकि पिछले वर्ष उनकी संख्या ३१,७६६ थी। ऐसी नालिशो की संख्या, जिनका फैसला पूरी सुनवाई न करके अन्य ढंगों से किया गया और जिनमे ऐसी नालिशो की संख्या भी सम्मिलित है, जिनका फैसला संक्रमण करके हुआ, १,११,९९५ थी। ऐसी इन्तदाई नालिशो की कुल संख्या, जिनका फैसला डिस्ट्रिक्ट जजो ने पूरी सुनवाई के बाद किया, १०० से घटकर ५३ रह गई। सिविल जजों द्वारा निपटाई गयी नम्बरी और खफीफा अदालतो की नालिशो की कुल संख्या २६,७३८ थी, जबकि १९५० ई० मे उनकी संख्या २६,४५४ थी और ऐसी नालिशों की संख्या, जिनका फैसला पूरी सुनवाई के बाद किया गया, ४,१३६ से बढ़कर ४,६६२ हो गई। ऐसी नालिशों की संख्या, जिनका फैसला मुन्सिफों ने किया, ९४,९७८ से घट कर ८१,९८२ रह गई। इनमें से २३,०२४ नालिशो का फैसला पूरी सुनवाई के बाद किया गया, जब कि ऐसी नालिशो की संख्या पिछले वर्ष २१,७५५ थी। ऐसी नालिशो की कुल संख्या में, जिनका फैसला खफीफा अदालतों ने किया, ५,८५३ की कमी हुई और जिन दूसरी अदालतो को खफीफा अदालतो के अधिकार प्राप्त थे उनके द्वारा फैसला किये गये मुकद्दमो की कुल संख्या में ३,०३९ की कमी हुई। इन अदालतों में दी हुई जिन दरखास्तो के सबध में डिगरी इजरा की गई उनकी संख्या ३३ थी। राज्य की ऐसी दरखास्तो का प्रतिशत ४५ से बढ़कर ४७ हो गया।

मुन्सिफो की अदालतो में पूरी सुनवाई के बाद जिन मुकद्दमो का फैसला किया गया उनकी औसत अवधि ३२७ दिन पर स्थिर रही। सिविल जजो की अदालतों में यह अवधि २६३ दिन से बढ़ कर ३५४ हो गई और डिस्ट्रिक्ट जजों की अदालतों में यह अवधि ४१९ दिन से बढ़कर ७४९ दिन हो गई। राज्य में पूरी सुनवाई के बाद जिन कुल मुकद्दमो का फैसला किया गया उनकी औसत अवधि २७७ दिन थी, जबकि पिछले वर्ष यह अवधि २६७ दिन थी। अवधि में वृद्धि इस कारण हुई कि दीवानी का काम करने वाले अफसरो की कमी थी।

ऐसी अपीलो की कुल संख्या, जिनमे माल की अपीलें भी सम्मिलित हैं और जो अधीनस्थ अदालतो में दायर की गई, १२,९१६ से बढ़ कर १३,७७१ हो गई। फैसले के लिये ऐसी अपीलो की कुल संख्या ४६,१६९ थी, जिनमें से २९,१४८ अपीलो का फैसला किया गया। इनमे १४,६०७ ऐसी अपीलें भी सम्मिलित हैं जो मुन्तकिल करके निपटाई गईं। सुनवाई के लिये आई हुई नम्बरी दीवानी अपीलो की संख्या में ४५५ की कमी हुई और वह ४१,९३५ रह गई। इनमें से १३,२०० अपीलो का फैसला मुन्तकिल न करके, अन्य ढंगो से किया गया और १३,३१८ अपीलो का फैसला उनको मुन्तकिल करके किया गया। मातहत अदालतो में माल संबंधी अपीलो की संख्या ४,२३४ थी। ऐसी अपीलो की संख्या जिनका फैसला मुन्तकिली के अतिरिक्त अन्य ढंगो से किया गया, १,३४२ थी और ऐसी अपीलो की संख्या जिनको मुन्तकिल करके निपटाया गया १,२८९ थी। ऐसी अपीलो की संख्या, जो सिविल प्रोसेजर कोड की अनुसूची १ के आर्डर ४१ के नियम ११ के अधीन अधीनस्थ अदालतो में सरसरी तौर से सुनवाई करके खारिज कर दी गई, ९४ से बढ़कर १०६ हो गई।

अपीलें

दिवाला

इन्स्टालमेन्सी ऐक्ट के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग ४२ दीवानी जजों ने किया। अधीनस्थ अदालतों में दिवाला संबंधी मुकद्दमों की संख्या में ६ की कमी हो गई और उनकी संख्या १,०६४ रह गई। बरी किये गये दिवालियों की संख्या ९७ से बढ़कर २१४ हो गई।

रिसीवरों द्वारा वितरित कुल धनराशि में ६८,१३५ रुपये की वृद्धि हुई और वह २,२३,४७४ रुपये हो गई और रिसीवरों के पास जो धनराशि रह गई उसमें ६४,३८७ रुपये की वृद्धि हुई और वह ६,७१,३९१ रुपये हो गई।

डिग्रियों का इजरा

मातहत अदालतों के समक्ष डिग्रियों की इजरा के लिये पेश की गई दरखास्तों की कुल संख्या ८७,७६४ से बढ़ कर ९८,५७८ हो गई। डिग्रियों की इजरा के लिये पेश की गई दरखास्तों की कुल संख्या आलोच्य वर्ष में ६७,८३१ थी, जब कि पिछले वर्ष यह संख्या ६३,१८८ थी। निपटाई गई दरखास्तों की संख्या में ७,६६३ की वृद्धि हुई (वह १९५० के ५७,३८५ से बढ़कर ६५,०४८ हो गई)। इसके अतिरिक्त ६,८६२ दरखास्तों का फंसला उनकी सुन्तकिल करके किया गया।

आनरेरी मुन्सिफ

आलोच्य वर्ष में बाराबकी और अल्मोड़ा में आनरेरी मुन्सिफों की अदालतें काम करती रही। इन अदालतों ने जिन मुकद्दमों का फंसला किया उनकी संख्या ४६४ से घटकर २४७ रह गयी।

फरीकों और गवाहों का बयान

ऐसे फरीकों की संख्या, जिनको सिविल प्रोसीजर कोड की अनुसूची १ के आर्डर ५ के नियम ३ के अन्तर्गत अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया गया, १०,५५२ से बढ़ कर १३,५७१ हो गई। इनमें से ७,१८९ फरीकों के बयान अदालतों में लिये गये। बुलाये गये गवाहों की संख्या २,०१,४४२ से बढ़ कर २,१३,६३१ हो गई। ऐसे गवाहों की संख्या, जिनका बयान लिये गये, १,१५,१६२ थी।

सम्मन तामील करने वाला अमला

ऐसे सम्मनों की संख्या, जिनको सम्मन तामील करने वालों ने तामील किया, ९,३०,९५७ से बढ़ कर ९,६५,५५७ हो गई। ऐसे सम्मनों की संख्या जिनको सिविल प्रोसीजर कोड की अनुसूची १ के आर्डर १६ के नियम ८ के अधीन फरीकों ने स्वयं तामील किया, २,००,०४६ थी, जब कि १९५० ई० में यह संख्या १,६५,६५८ थी।

विचाराधीन मिसिले

वर्ष के अन्त में विचाराधीन मुकद्दमों की कुल संख्या में पिछले वर्ष की अपेक्षा ८३४ की वृद्धि हुई, अर्थात् वे ८३,४८२ थे। ऐसे मुकद्दमों की संख्या, जो एक वर्ष से अधिक तक विचाराधीन रहे, २५,५७९ से बढ़कर २६,७४३ हो गई। ऐसे मुकद्दमों की कुल संख्या, जो ६ महीने से अधिक तक विचाराधीन रहे, ४१,२७२ थी। तमाम विचाराधीन अपीलों की कुल मिसिलों की संख्या १७,३७१ से घटकर १७,०२१ रह गयी। इनमें से १५,४१७ नम्बरी अपीलें थीं और १,६०४ माल संबंधी अपीलें थी। एक वर्ष से अधिक विचाराधीन अपीलों की संख्या में ५७३ की कमी हुई (१९५० ई० के ४,९६४ से घटकर ४,४२१ रह गयी)। डिगरी इजरा कराने की दरखास्तों की विचाराधीन मिसिलों की संख्या में २,३७६ की वृद्धि हुई और वह २६,६६८ थी। ३ महीने से अधिक विचाराधीन दरखास्तों की संख्या ११,६९७ से बढ़कर १२,९५६ हो गई।

विभिन्न अधीनस्थ अदालतों में विचाराधीन बहुत से मुकद्दमों की संख्या में वृद्धि होने से काम बढ़ गया और दीवानी का बहुत सा काम जमा हो गया।

ज्ञान) में अक्सरों की कमी थी। अक्सरों के न मिलने के कारण मुन्सिफों और सिविल जजों (जिनमें खफीफा के जज भी सम्मिलित हैं) की कुछ जगहों को खाली रखना पड़ा। औद्योगिक अदालतों, डिटन्शन बोर्ड आदि जैसे अन्य कार्यों तथा फौजदारी के काम की भरमार के कारण डिस्ट्रिक्ट जज भी दीवानी के काम की ओर उचित रूप से ध्यान न दे सके।

१८-रजिस्ट्रेशन

रजिस्ट्रेशन विभाग का संबंध मुख्य रूप से चल तथा अचल संपत्तियों से संबंधित लेखों के रजिस्ट्रेशन से उसी प्रकार रहा जैसा कि पहिले था।

१९५१-५२ ई० में इस विभाग की आय लगभग २५ लाख रु० और व्यय लगभग १३.५ लाख रु० था, जब कि गत वर्ष की आय २७ लाख रु० और व्यय १३ लाख रु० था।

राज्य में रजिस्ट्रेशन कार्यालयों की संख्या २४१ थी, जिसमें पदेन डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारों के रूप में कार्य करने वाले डिस्ट्रिक्ट जजों के कार्यालय भी सम्मिलित थे। व्यय में मितव्ययता लाने के उद्देश्य से ८ कार्यालयों को, जहाँ काम कम हो गया था, तोड़ दिया गया। वर्ष में सब-रजिस्ट्रार के पदों की भर्ती का कार्य स्थगित कर दिया गया। यह निर्णय उस निर्णय के अनुसार किया गया, जो गत वर्ष ५६ वैभागिक सब-रजिस्ट्रारों के कार्यालयों को, जैसे और जब सब-रजिस्ट्रारों के कैंडर में जगहें खाली हों, कुछ समय के सब-रजिस्ट्रारों के कार्यालयों में बदलने के संबंध में किया गया था। इन कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन क्लर्क इनचार्ज अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त सब-रजिस्ट्रार के रूप में भी कार्य करेंगे। राजस्व में कमी होने को रोकने के उद्देश्य से शुल्कों और महसूलों की वृद्धि जाँच की गयी और अधिक क्षमता लाने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया गया।

लगभग ४९ सब-रजिस्ट्रारों को, जो वकालत पास थे, उनके सामान्य कर्तव्यों के अतिरिक्त द्वितीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेट का भी कार्य सौंपा गया। गत वर्ष ऐसे सब-रजिस्ट्रारों की संख्या, जो इस प्रकार द्वितीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर रहे थे, ३५ थी।

१९-पंचायत राज

सोलह-सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में, जिसमें विभिन्न रचनात्मक कार्यवाहियों सम्मिलित हैं, पंचायतों ने और अधिक प्रगति की। इन रचनात्मक कार्यवाहियों को करने के अतिरिक्त उन्होंने कृषि, पशुपालन, सहकारिता, चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य विभागों के विकास संबंधी कार्यों में भी सहयोग दिया। पंचायती अदालतों के स्तर पर सुधार क्षेत्र समितियाँ बनाई गईं और गाँव सभाओं के प्रधान और उप-प्रधान इन समितियों के सदस्य मनोनीत किये गये और पंचायतों के सेक्रेटरी इन समितियों के सेक्रेटरी नियुक्त किये गये। प्रत्येक तहसील से एक प्रधान जिला योजना समिति में भी मनोनीत किया गया। विकास संबंधी विभिन्न कार्यवाहियों के लिये पंचायत सेक्रेटरियों को ट्रेनिंग देने की सरकार द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की गयी। राज्य के लगभग प्रत्येक जिले में ट्रेनिंग कैम्पों का संगठन किया गया और टीका लगाने, साँड़ों को बधिया करने, मिलवा खाद के गड्डे तैयार करने, कृषि के उन्नत ढंगों, सहकारी समितियों संगठित करने आदि की प्रशिक्षण

रचनात्मक
कार्य

इन कार्यों से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने गाँव में क्षेत्रिक कार्यवाहियाँ करने में प्रशिक्षण पाने वालों का हाथ बढ़ाया।

पंचायतों के कार्य में वृद्धि को देखते हुए सरकार ने जिलों में सहायक पंचायत अफसरों की नियुक्ति की।

पंचायतों की कार्य-पद्धति के संबंध में प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के विचार से आलोच्य वर्ष में बिहार और पेप्सू के प्रतिनिधि इस राज्य में आये और जो सफलता प्राप्त हुई थी उस पर उन्होंने बड़ा संतोष प्रकट किया।

पंचायतघर और सड़के

सोलह-सूत्री कार्यक्रम का पहला काम पंचायतघरों का निर्माण जारी रहा और इस प्रयोजन के लिये धनो जमींदार और गरीब किसान दोनों ही ने अधिक संख्या में इसके लिये भूमि और घरों का बड़ी उदारता के साथ दान किया। अकेले मुजफ्फरनगर जिले में ४१ पंचायतघर दान में प्राप्त हुए। पंचायतों द्वारा १९५१ ई० में ४९८ पक्के और ६३४ कच्चे पंचायतघर बनाये गये। ६० मील पक्की और १,०२८ मील कच्ची सड़के भी बनाई गईं। बहुत से स्थानों में गाँव वालों ने स्वेच्छा से मजदूरी का काम किया और इस प्रकार सड़के बनाने में पंचायतों ने लाखों रुपये की बचत की। अल्मोड़ा, नैनीताल और टेहरी-गढ़वाल के जिलों ने इस दिशा में विशेष प्रयास किया।

शिक्षा

ग्रामीणों की शिक्षा की ओर बराबर ध्यान दिया गया। पंचायतों ने वर्ष के अन्त तक लड़के और लड़कियों के लिये ७१० नये स्कूल और प्रौढों के लिये ६२० स्कूल खोले। इसके अतिरिक्त १०,८९६ वाचनालय और ५,९३२ पुस्तकालय थे। समय-समय पर जो साक्षरता आन्दोलन चलाया गया उसके फलस्वरूप साक्षर बनाये गये पंचों की संख्या ५८,५७६ थी और गाँव-सभाओं के लिये पंचायतों द्वारा ६६६ रेडियो सेटों की व्यवस्था की गई। गाँव के लोगो ने पुस्तकालयों के लिये बड़ी उदारतापूर्वक पुस्तकें दान दीं। केवल झांसी जिले में ही गाँव सभाओं को २०,००० पुस्तकें दान में प्राप्त हुईं।

सफाई व्यवस्था तथा रोशनी

सफाई व्यवस्था सम्बन्धी अवस्था में सुधार करने का प्रयास भी जारी रहा। आलोच्य अवधि में ३६ मील पक्की और १०७ मील कच्ची गन्दे पानी के निकास की नालियाँ पंचायतों द्वारा बनाई गयीं। हँजा, प्लेग, चेचक आदि महामारियों को फैलने से रोकने के लिये प्रत्येक संभव उपाय किये गये। मामूली बीमारियों का इलाज करने के लिये सरकार द्वारा दिये गये दवाइयों के बक्से का पूर्ण उपयोग किया गया। दवाइयों के खाली बक्सों को पुनः भरने का व्यय हमेशा की तरह पंचायतों द्वारा उठाया गया। कुछ पंचायतों ने वैद्य और हकीमों को वित्तीय सहायता भी दी। पंचायत राज विभाग ने समय-समय पर ऐसे अनुदेश जारी किये, जो चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी मामलों में पंचायतों के लिये लाभकारी समझे गये। पंचायत राज विभाग गाँव वालों के लाभ के लिये घरेलू चिकित्सा पर पुस्तिकाओं आदि की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रहा था। जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों की देख-रेख करने के अतिरिक्त पंचायतों ने जन्म और मृत्यु के रजिस्टर भी रखे।

रात में गाँव वालों की असुविधा दूर करने के विचार से आलोच्य वर्ष में लगभग ७,३२५ रोशनी के नये खम्भे गाड़ गये।

अन्न-उत्पादन

लगभग सभी पंचायतों ने अधिक अन्न उत्पादन कार्य में सक्रिय भाग लिया। १९५१ ई० में १,९३,८८८ मिलवां खाद के गड्ढे तैयार किये गये जिनसे लाखों टन खाद प्राप्त हुई और पंचायतों ने बहुत से किसानों को विभिन्न फसल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया। पंचायतों ने नाले,

नहरों और कुयों भी खोदे और काफी जमीन कृषि योग्य बनाई। कृषि विभाग द्वारा दिये गये उन्नत बीज बहुत बड़ी मात्रा में किसानों को बांटे गये और कुछ स्थानों में पंचायतों ने अपने खुद के बीज गोदाम स्थापित किये। पंचायतों ने सामूहिक आधार पर कृषि के आधुनिक औजार खरीदे। १ नवंबर की मृग की खेती का अधिक प्रचार करने का सफल प्रयास किया गया और अच्छी पैदावार हुई।

पंचायतों की अन्य कार्यवाहियों में नियन्त्रित वस्तुओं जैसे चीनी, सीमेंट, कपड़ा आदि का वितरण सम्मिलित है। बहुत काफी संख्या में पंचायतों ने खेलकूद तथा शारीरिक सम्बर्धन कक्षाओं में बड़ी दिलचस्पी ली। कुछ पंचायतों ने खेल के अपने मैदान बनाये जहाँ गांव वालों ने फुटबाल, कबड्डी, जालीबाल आदि खेलकूदों में भाग लिया। गांव वालों द्वारा खोले गये खेलकूद के बलबों को पंचायतों का संरक्षण प्राप्त था और समय-समय पर खेलकूद के टूर्नामेंट संगठित किये गये।

पंचायतों की
अन्य कार्य-
वाहियाँ

हरिजन उद्धार तथा मद्यनिषेध का कार्य जारी रहा। न्याय प्रशासन के क्षेत्र में पंचायतों अदालतों को काफी सहायता मिली। उन्होंने कुल २,७१,९३५ मुकदमों की सुनवाई की और ८७,१६८ मामलों में पंच लोग समझौता कराने में सफल हुए। पंचायती अदालतों द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध १३,०४१ अपीलें की गईं, किन्तु ५,४८४ मामलों में ही नज़रसानी की इजाजत दी गई।

पंचायती
अदालतें

२०-म्युनिसिपल बोर्ड

म्युनिसिपैलिटीयों की संख्या १९५० ई० में ११७ से बढ़कर वर्ष के दौरान में ११९ हो गई। जालौन नोटीफाइड एरिया १ जनवरी, १९५१ ई० को म्युनिसिपैलिटी में परिवर्तित कर दिया गया और विलीनीकृत अन्तर्क्षेत्रों में चरखारी की म्युनिसिपैलिटी उत्तर प्रदेश में म्युनिसिपैलिटीयों से संबंधित विधि के अधीन १ मार्च को स्थापित की गयी। इस वर्ष बलरामपुर की म्युनिसिपैलिटी वित्तीय कुप्रबंध के कारण अधिकारच्युत कर दी गई और आगरा, मंसूरी, टांडा, बहराइच, गोरखपुर तथा लखनऊ की म्युनिसिपैलिटीयों अधिकारच्युत सस्थाओं के रूप में कार्य करती रहीं। रामपुर की म्युनिसिपैलिटी भी, जो रामपुर राज्य के उत्तर प्रदेश में विलीन हो जाने के पूर्व विगत रामपुर राज्य प्रशासन द्वारा अधिकारच्युत कर दी गयी थी, इस वर्ष अधिकारच्युत रही।

म्युनिसि-
पैलिटीयों
की संख्या

हाल के वर्षों में स्थापित कुछ नयी म्युनिसिपैलिटीयों की दशा में पुरानी टाउन एरिया समिति या नोटीफाइड एरिया समिति म्युनिसिपैलिटी का कार्य करती रहीं और अन्य म्युनिसिपैलिटीयों की दशा में सम्बन्धित जिला मैजिस्ट्रेट नयी म्युनिसिपैलिटीयों के इन्चार्ज बने रहे।

विगत वर्ष यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ ई० की धारा ३० के अधिकारों को स्पष्ट करने और किसी बोर्ड के अधिकारच्युत रहने के संबंध में मूल आदेशों में निर्दिष्ट अवधि को बदलने, संशोधित करने या बढ़ाने के निमित्त राज्य सरकार के अधिकार के संबंध में संदेह दूर करने के लिये एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था। आज्ञोच्च वर्ष में उक्त अध्यादेश के स्थान पर उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (पूरक) अधिनियम, १९५१ ई० का परिनियम पुस्तक में समावेश किया जायगा।

कानून
बनाना

यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज (अमेडमेन्ट) ऐक्ट, १९४८ ई० द्वारा निर्दिष्ट यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ ई० की धारा ३३६-ए० में अन्य

बातों के साथ-साथ इस बात की भी व्यवस्था की गई थी कि उक्त ऐक्ट के अधीन प्रथम बोर्डों के निर्माण तक कार्य चालू रखने के अभिप्राय से राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा यह निदेश कर सकती है कि उक्त अधिनियम निर्दिष्ट परिमित अवधि में ऐसे अनुकूलनो, परिवर्तनो तथा परिष्कारों के साथ लागू होगा जैसा कि निर्दिष्ट किया जाय। हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि चूंकि उक्त ऐक्ट के इस अनुकूलन, परिवर्तन अथवा संशोधन में विधान बनाने के अधिकार बरतने का प्रश्न उठता है, इसलिये इसे राज्य सरकार को समर्पित नहीं किया जा सकता। तदनुसार अन्तरिम कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट में किये गये अनुकूलनों, परिवर्तनों तथा परिष्कारों को विधायी स्वीकृति देने के लिये उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (अनुपूरक तथा वैधकरण) अधिनियम, १९५१ ई० लागू किया गया।

ऋण

विभिन्न योजनाओं के लिये म्युनिसिपैलिटीयों को कुल मिलाकर ५३,०४,५०० रु० के ऋण दिये गये थे। इन ऋणों में जलकलौ (वाटरवर्क्स) के लिये १६,०३,००० रु० के ऋण, उद्वासित व्यक्तियों के लिये गृह-निर्माण योजनाओं के संबंध में ११,७२,४०० रु० के ऋण, विद्युत्करण योजनाओं के लिये १,०३,१०० रु० के ऋण, लखनऊ में सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों के निर्माण के सम्बन्ध में ८,००,००० रु० के ऋण, पानी निकास की नालियों की योजनाओं के लिये ३,५३,१०० रु० के ऋण, वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिये २०,००० रु० के ऋण तथा संशोधित वेतन-क्रमों को लागू करने के लिये २५,००० रु० के ऋण सम्मिलित थे। सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनवाने के संबंध में लखनऊ के म्युनिसिपल बोर्ड को ८,००,००० रु० का ऋण दिया गया। सरकारी कर्मचारियों के लिये निवास-स्थान की व्यवस्था करने के संबंध में म्युनिसिपल बोर्ड को सब से पहली बार साधून के रूप में काम में लाया गया।

सहायक अनुदान

इस वर्ष विभिन्न म्युनिसिपल बोर्डों को कुल मिलाकर ३,५६,०६४ रु० के सहायक अनुदान दिये गये। उनको उत्तर प्रदेश सड़क कोष से २५,०६,४०० रु० की एक दूसरी धनराशि सड़कों के सुधार के निमित्त दी गयी। राज्य स्वास्थ्य बोर्ड ने भी नागर तथा ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई और तीर्थ स्थानों की सफाई या स्वास्थ्य संबंधी दशाओं को सुधारने के लिये ५,५०,००० रु० के सहायक अनुदान दिये। नगरी के अनाथालयों को भी कुल मिला कर १,००० रु० के सहायक अनुदान दिये गये। इसके अतिरिक्त उन्हें २,५०० रु० की और धनराशि मुख्य मन्त्री के अपनी इच्छा से दिये जाने के लिये नियत धनराशि में से दी गई।

शिक्षा, जन-स्वास्थ्य और सफाई व्यवस्था

म्युनिसिपल बोर्ड राज्य सरकार के इस निर्णय पर कि शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार किया जाय, ध्यान देते रहे। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में जन-स्वास्थ्य और सफाई सम्बन्धी व्यवस्था में सुधार करने का भी प्रयत्न किया।

चुनाव

वर्तमान म्युनिसिपल बोर्डों का कार्यकाल, जो ९ वर्ष बीत जाने के उपरान्त १९४४ ई० में किये गये चुनावों के आधार पर बनाय गये थे, संसद तथा राज्य विधान मंडल के संधारण चुनावों के कारण ३१ अक्टूबर, १९५२ तक फिर बढ़ाना पड़ा। बोर्डों की यह अवधि अक्टूबर, १९४८ ई० से समय-समय पर बढ़ाई जाती रही थी और म्युनिसिपल बोर्डों के सदस्यों

की बहुत सी आकस्मिक रिक्तियों की पूर्तियां साधारण चुनाव सन्निकट होने के कारण नहीं की गई। फिर भी इस बात को देखते हुए कि आलोच्य वर्ष में साधारण म्युनिसिपल चुनावों को फिर से स्थगित करना पड़ा, बोर्डों को यह आज्ञा दी गई कि वे बिना और विलम्ब किये उपचुनाव कर लें। इन आज्ञाओं के फलस्वरूप बहुत सी म्युनिसिपैलिटियों में उपचुनाव किये गये और आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति की गयी। ये उपचुनाव विस्तृत मताधिकार के आधार पर नहीं किये जा सके। म्युनिसिपल बोर्डों के निर्वाचकों को वयस्क मताधिकार के आधार पर मत प्रदान करने का अवसर अभी तक नहीं मिला है।

२१-जिला बोर्ड

रामपुर तथा देहरी-गढ़वाल की विलीनीकृत रियासतों में फिर जिला बोर्डों का बनाया जाना स्थगित करना पड़ा, क्योंकि इन क्षेत्रों की स्थिति अभी ऐसी नहीं हो सकी थी कि वहाँ निकाये बनाई जा सकती। तथापि इन क्षेत्रों के विकास का कार्य नियोजन समितियों को सौंप दिया गया और रामपुर को १,००,००० रु० और देहरी-गढ़वाल को ९०,००० रु० के अनुदान दिये गये जिससे वे इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यय पूरा कर सकें।

रामपुर तथा
देहरी-गढ़वाल

राज्य के जिला बोर्डों की वित्तीय स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। ३४ बोर्डों की साधारण आय से साधारण व्यय अधिक हुआ। बताया गया है कि बहुत से बोर्ड ऋणग्रस्त हैं। संशोधित वेतनक्रमों को कार्यान्वित करने में इन निकायों के आय साधनों पर बड़ा भारी भार पड़ा और इस प्रयोजन के निमित्त १२,१९,६०० रु० का ऋण दिये जाने पर भी बोर्डों की कठिनाई दूर न हो सकी। बाराबंकी में संशोधित वेतनक्रम कार्यान्वित न किये जा सके और धन की कमी के कारण फैजाबाद में २६ प्राइमरी पाठशालाएँ बन्द कर देनी पड़ीं।

बोर्डों की
वित्तीय स्थिति

सामान्य प्रयोजनों के लिये जिला बोर्डों को १,००,००० रु० की धनराशि अन्य ऋणों के रूप में दी गई। पर्वतीय जिलों में साफ पानी की उचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में, सड़कों के सुधार और बाढ़ से बर्बाद सड़कों की मरम्मत के लिये क्रमशः ८१,०७५ रु०, ४,००,००० रु० तथा १,००,००० रु० के अनुदान दिये गये। अनावतक अनुदानों में मथुरा के जिला बोर्ड पुल निर्माण के लिये ३१,७०० रु० का अनुदान और ठेके तथा अन्य आकस्मिक व्ययों के शीषक के अन्तर्गत कुल मिलाकर २३,३०० रु० का अनुदान भी सम्मिलित है। आवर्तक अनुदानों में "ठेके" अंशदान के लिये ५,७१,१२१ रु० की धनराशि भी सम्मिलित है।

ऋण तथा
अनुदान

बोर्डों का सबसे अधिक व्यय शिक्षा की मद पर हुआ, किन्तु यद्यपि इन परिस्थितियों में उन्होंने प्रत्येक संभव उपाय किये, तथापि वांछित लक्ष्य अभी नहीं प्राप्त हुआ। कुछ बोर्डों में पाठशालाओं और विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई, किन्तु व्यय में जो आनुपातिक वृद्धि हुई उससे अपेक्षित कार्यक्षमता मिलना असंभव था।

शिक्षा

हमेशा की तरह दूसरी सबसे बड़ी मद सड़कों पर व्यय हुई और उनमें सुधार करने के लिये ४,००,००० रु० का अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ। बोर्ड अपनी वित्तीय स्थिति के कारण स्वतंत्र रूप से ठोस कार्य न कर सके। बड़ी सड़कों का प्रांतीयकरण किये जाने से स्थानीय निकायों का व्यय-भार कम हो जाने और परिणामस्वरूप शेष सड़कों की स्थिति सुधर जाने की जो आशा की गयी थी वह पूरी न हो सकी और यद्यपि मुजफ्फरनगर, मथुरा, नैनीताल, खीरी, सीतापुर, झांसी तथा शाहजहांपुर के कई पुलिसियाँ और पुल

सड़कें तथा
ईमारतें

बनाये गये और उनमें से कुछ जिलों में थोड़ी सी कच्ची सड़कों भी बनाई गईं, आमतौर पर जिला बोर्ड की सड़कों की हालत खराब ही रही।

देहरादून में ग्रामीणों की सहायता से ५ सड़कों का निर्माण कार्य विशेष-रूप से उल्लेखनीय है।

इमारतों के संबंध में बोर्डों ने अधिक ठोस कार्य किया। फँजाबाद में १९ जूनियर हाई स्कूलों की और १५ बेसिक प्राइमरी स्कूलों की इमारतों की मरम्मत की गई और ३ नई इमारतें बनाई गईं। बदायूँ बोर्ड ने एक जूनियर हाई स्कूल और त्वार प्राइमरी स्कूलों को बनाने की स्वीकृति दी और मुजफ्फरनगर में ३ स्कूली इमारतों का पुनर्निर्माण किया गया और ३९ अन्य स्कूलों की इमारतों की मरम्मत की गई। हरदोई में विस्थापित व्यक्तियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण कार्य हाथ में लिया गया और इस वर्ष ऐसे ०६ क्वार्टर और १५ दुकानें बनाई गईं और इसके अतिरिक्त ३ प्राइमरी पाठशालाओं के लिये इमारतें बनाई गईं। जिला नैनीताल के निर्माण कार्य की उल्लेखनीय बात यह थी कि जनता क प्रयास से १,००,००० रु० से अधिक लागत की पाठशालाओं की इमारतें बनाई गईं और बोर्ड ने इस काम के लिये केवल भवन निर्माण की सामग्री दी। मथुरा बोर्ड ने २ ऐलोपैथिक तथा तीन आयुर्वेदिक औषधालय और ३ कांजीहाउस की इमारतें बनवाई और देहरादून में जित औषधालय की इमारत का कार्य पहिले ही प्रारंभ हो चुका था उसको पूरा किया गया।

चिकित्सा
संबंधी सहा-
यता तथा
जन-स्वास्थ्य

कुछ जिलों में थोड़े से औषधालयों और अस्पतालों के निर्माण तथा विस्तार और वैद्य तथा हकीमों को आर्थिक सहायता देन के अतिरिक्त जन-स्वास्थ्य या चिकित्सा संबंधी क्षेत्र में कोई विशेष कार्यवाही नहीं हुई।

पानी की
सप्लाई

इसी प्रकार पर्वतीय जिलों को छोड़कर, जहाँ कि भौगोलिक स्थिति के कारण, माँग की गयी थी, कहीं भी पानी ले जाने के लिये नल नहीं बिछाये गये। अन्य जिलों में वर्तमान कूप प्रणाली जारी रही। जहाँ आवश्यक था सुधार किया गया। पहाड़ों में अत्मोडा और नैनीताल के जिलों में दो नई योजनाएँ पूरी की गयीं और नैनीताल में कई पाइप लाइनें बनाई गईं।

महसूलों की
वसूली

हमेशा की तरह बोर्डों की मुख्य कठिनाई (यह उन कारणों में से एक कारण है जिससे बोर्डों की वित्तीय स्थिति कमजोर रहती है) कर वसूली में सफलता का न मिलना है। प्रायः प्रत्येक जिले में हैसियत और जायदाद कर (सरकस्टान्सेज ऐंड प्रापर्टी टैक्स), जहाँ यह कर लिया जाता है, की बकाया रकम में बढ़ती होती गयी। दूसरी ओर कर वसूली का व्यय कर की वसूली में कमी होने के साथ-साथ बढ़ता गया। कहा जाता है कि मुख्यतया रेलवे के और कुछ अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारी कर न देने के दोषी थे। चूँकि रेलवे कर्मचारियों के वेतन पर पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट लागू होता है और वेतन वितरण के समय यह संभव नहीं है कि इनके वेतन में यह रकम काटी जा सके, अतएव भारत सरकार से प्रार्थना की गई कि पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट में ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे कि उनके वेतन में से काटे जाने वाले जिला बोर्डों के हैसियत तथा जायदाद कर को वेतन वितरण प्राधिकारी वेतन से काटी जाने वाली रकम में सम्मिलित कर सकें। वर्ष के अन्त में यह प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन था।

वित्तीय स्थिति संतोषप्रद न रहने के कारण अपनी आय बढ़ाने के इच्छुक कुछ बोर्डों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ऐसे उपाय किये जिनका करना वैध नहीं था। इन उपायों में अत्यधिक दर से लाइसेंस फीस लगाना और बिक्री कर के समान ही कर लगाना शामिल था। इन स्थानीय निकायों को पहिले ही कर के रूप में लाइसेंस फीस न लेने के लिये निर्देश जारी कर दिये गये थे, किन्तु कहीं-कहीं की छबियों से पता चलता है कि ये फीस इसी प्रकार वसूल की जा रही हैं। यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। यह महसूस किया गया है कि जिला बोर्डों को इस प्रथा का अनुसरण न करने के लिये नये निर्देश जारी करना वांछनीय है, ताकि उन्हें अशोभनीय स्थिति का सामना न करना पड़े। संबंधित बोर्डों पर इस बात के लिये जोर दिया गया कि 'बिक्री कर लगाना अनुचित है।

बोर्डों द्वारा
करों का
लगाया जाना

इस वर्ष स्थानीय निकायों की सहायक अनुदान समिति की रिपोर्ट पूरी की गई और उसे सरकार के सामने प्रस्तुत किया गया। समिति ने स्थानीय निकायों की आय बढ़ाने के निमित्त जिन उपायों की सिफारिश की थी उनकी वर्ष के अन्त में जांच की जा रही थी।

सहायक अनु-
दान समिति
की रिपोर्ट

२२-नोटीफाइड एरिया

समथर (जिला झांसी) के नोटीफाइड एरिया को सम्मिलित करके राज्य में नोटीफाइड एरिया की संख्या ३८ थी। समथर, जो इस राज्य में अन्त-क्षेत्रों के विलयन के अवसर पर आया, इससे पहिले एक नगरपालिका थी। यह नगर छोटा था और इसका उत्तर प्रदेश की स्थानीय स्वशासन रचना में एक नोटीफाइड एरिया के रूप में विलीनीकरण किया जाना था। इस वर्ष जालौन की नोटीफाइड एरिया एक नगरपालिका के रूप में परिवर्तित कर दी गयी। जिला गोंडा में कर्नलगज की तथा जिला बहराइच में नानपारा की नोटीफाइड एरिया की दो समितियाँ अवकांत (under supersession) रहीं। भुवाली तथा मिथिष नीमसार की दो अन्य समितियों के प्रशासन के विरुद्ध शिकायत आई और वर्ष के अन्त में उनके मामलों की जांच की जा रही थी।

इस वर्ष आठ नोटीफाइड एरिया की समितियों को विशेषतः सड़को तथा नालियों जैसे नागरिक निर्माण कार्यों के लिये ४१,००० रु० की धनराशि का अग्रऋण दिया गया। जिन समितियों को लाभ पहुंचा वे गंगोह (जिला सहारनपुर), करवी (जिला बांदा), बादशाहपुर (जिला जालौन), अहौरा (जिला मिर्जापुर), खुदौली (जिला बाराबंकी), सरधना और बागपत (जिला मेरठ) और भुवाली (जिला नैनीताल) की समितियाँ थी। टहरी-गढ़वाल के नये जिले की (टहरी, नरेन्द्रनगर और देवप्रयाग) तीन नोटीफाइड एरिया को सरकार से १४,७५० रु० के सहायक अनुदान के रूप में सहायता प्राप्त हुई। ये अनुदान सामान्य प्रयोजनों के लिये दिये गये थे, क्योंकि अभी समितियों को करोड़ों प्राप्त होने वाली अपनी आय को बढ़ाना था और अपनी वित्तीय स्थिति को दृढ़ करना था। देवप्रयाग नोटीफाइड एरिया की सीमायें बहुबाजार तथा जिला गढ़वाल के कुछ अन्य क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित करने के प्रयोजन से बढ़ाई गई। यह कारवाई स्थानीय जनता की निरंतर माँग के कारण की गयी थी। इस सीमा-विस्तार के कारण उत्पन्न हुई प्राविधिक कठिनाई को दूर करने के लिये टहरी-गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को गढ़वाल के अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अधिकार निहित कर दिये गये।

२३-टाउन एरिया

सामान्य

इस वर्ष बिजनौर जिला के सहनपुर में एक नया टाउन एरिया बनाया गया। तीन टाउन एरिया कमेटियां अर्थात् गोपागंज (जिला आजमगढ़), नौतनवां (जिला गोरखपुर) और फरहा (जिला मैनपुरी) अवकांश कर दी गयी और एक टाउन एरिया कमेटी, फरीदपुर (जिला बरली) के सेम्बरों ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया।

आमतौर से टाउन एरिया कमेटियों का महत्व बढ़ गया और उनमें से कई ने केवल मौलिक कर्तव्यों की ओर ही ध्यान न देकर विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करके अपने कार्यक्षेत्र को बढ़ाया। वित्तीय कठिनाइयों का ध्यान रखते हुए राज्य सरकार ने उनको यथासंभव सभी सुविधायें प्रदान की।

विकास,
सड़कों और
नालियां

जिला नियोजन समितियों ने भी इन एरियाओं के विकास कार्य में दिलचस्पी ली और योजनायें तथा सुझाव देकर टाउन एरिया कमेटियों की सहायता की। बुलन्दशहर की जिला नियोजन समिति की ओर से जिला की टाउन एरिया कमेटियों ने एक पंचवर्षीय विकास योजना, जिसमें सड़को, नालियों तथा बाजारों का सुधार, बस के अड्डे, पार्क, खेल-कूद के मैदान, औषधालयों, अस्पतालों और पुस्तकालयों की व्यवस्था का कार्य सम्मिलित था, आरंभ की गयी। ८,४६७ रुपये की अनुमानित लागत पर दादरी टाउन एरिया में सीमेंट की दो सड़कों पर काम वास्तव में आरम्भ किया गया। गुलौरी, जहांगीराबाद और शिकारपुर के टाउन एरियाओं में तारकोल की सड़के बनाने का प्रस्ताव था। शिकारपुर टाउन एरिया कमेटी ने ११,०७१ रु० ५ आना की लागत पर सड़क और नालियां बनाने का कार्यक्रम आरंभ किया और इसके लिये सरकार ने ४,००० रुपये का अनुदान दिया। अतर्रा (जिला बांदा) के टाउन एरिया कमेटी ने भी सड़क बनाने का एक बड़ा कार्यक्रम आरम्भ किया, जिसमें २५,००० रु० का व्यय था, लेकिन काम १३,००० रुपये से पूरा किया गया। नौतनवा टाउन एरिया कमेटी (गोरखपुर) ने नालियां बनाने की योजना का कार्य ५८,३०९ रुपये के अनुमानित व्यय पर आरम्भ किया और कमेटी ने लागत का अपना हिस्सा अर्थात् २९,१५२ रुपये जमा कर दिये। सरकार ने इसके लिये १०,००० रु० मंजूर किया था। ६५,००० रुपये लागत की नाली बनाने की एक दूसरी योजना जहांगीराबाद की टाउन एरिया कमेटी ने आरंभ की। इस योजना को सरकार ने मंजूर किया और इस टाउन एरिया कमेटी ने भी लागत का अपना हिस्सा अर्थात् ३३,००० रुपये जुदा कर दिया।

सरकार ने खुले मौसम में प्रयोग की जाने वाली एक सड़क बनाया, जो जिला अल्मोड़ा के पिथौरागढ़ टाउन एरिया और नैनीताल के टनकपुर को मिलाती है।

इसके फलस्वरूप इन क्षेत्रों में यातायात साधनों की समस्या की समस्या बहुत कुछ हल हो गयी।

ऋण तथा

इस वर्ष टाउन एरिया कमेटियों को सड़कों तथा नालियों के लिये

ऋग की इस धनराशि में से निम्नलिखित टाउन एरिया कमेटियों ने सब से अधिक पाया —

मोथ टाउन एरिया कमेटी	..	१०,००० रु०
रामपुर टाउन एरिया कमेटी	..	४,७०० रु०
मिरानपुर टाउन एरिया कमेटी	..	१०,००० रु०

निम्नलिखित टाउन एरिया कमेटियों ने इस अनुदान का सब से अधिक भाग पाया—

शिवपुरी टाउन एरिया कमेटी	..	५,००० रु०
छिबरामऊ टाउन एरिया कमेटी	..	५,००० रु०
जलालाबाद टाउन एरिया कमेटी	..	५,००० रु०
मन्दावर टाउन एरिया कमेटी	..	५,००० रु०

इस वर्ष इन कमेटियों ने जन-स्वास्थ्य संबंधी जो कार्यवाहियाँ की वह संतोषजनक रही। बहुत सी कमेटियों ने टीका लगाने की व्यवस्था की और स्थानीय वैद्यों को अनुदान भी दिये गये और उन्होंने गरीबों को मुफ्त दवा बाँटी। इस सबध में जहाँगीराबाद (बुलन्दशहर) और मोदीनगर (मेरठ) की टाउन एरिया कमेटियों ने ठोस कार्य किया। सार्वजनिक कुँग्रों को विसंक्रमित किया गया और निजी कुँग्रों को साफ़ तथा विसंक्रमित करने के लिये लोगों को पोर्टेडियम परमेगनेट दिया गया।

जन-स्वास्थ्य

कुछ क्षेत्रों में पीने का साफ़ पानी देना स्थानीय निकायों का विशेष कार्य रहा, किन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण केवल कुँए खोदने का काम ही आरंभ किया जा सका। पाँच टाउन एरिया कमेटियों ने हँड पंप की व्यवस्था की। पानी सफ़ाई करने की समस्या को हल करने के विचार से मिर्जापुर जिला में राबर्ट संगंज टाउन एरिया के निकट भेलाई में सरकार ने एक बाँध का निर्माण आरंभ किया।

कुछ टाउन एरिया कमेटियाँ अपने अधिकार-क्षेत्र की सार्वजनिक सड़कों पर बिजली की रोशनी की व्यवस्था भी कर सकीं। अन्य टाउन एरिया कमेटियाँ बिजली न मिलने के कारण यह सुविधा न पहुँचा सकीं। इस बात का प्रयत्न जारी रखा गया कि यथासंभव अधिक से अधिक क्षेत्र को यह सुविधा दी जा सके।

बिजली लगाना

खाद की मात्रा बढ़ाने के विचार से कम्पोस्ट (मिलवा) खाद बनाने तथा कूड़ा-करकट से खाद तैयार करने की संभावना को जाँच करने के लिये भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक अफसर राज्य के विभिन्न भागों में गया। उसने यह सुझाव रखा कि इस संबंध में मथुरा जिला की कुछ टाउन एरिया कमेटियों के वर्तमान सधनों का प्रसार किया जाय और स्थानीय अफसरों से इस मामले पर विचार करने के लिये कहा गया। चौहारपुर (जिला देहरादून) में और इटावा जिला की कुछ टाउन एरिया कमेटियों में यह कार्य सफलता से होता रहा, जिससे संबंधित स्थानीय निकायों को भी कुछ आमदनी होती रही।

‘अधिक अन्न
उपजाओ’
अभियोग

२४—कानपुर विकास (डेवलपमेंट) बोर्ड

कानपुर विकास (डेवलपमेंट) बोर्ड ने गलीज उपयोग योजना का पहला दौर चार महीने की अवधि में पूरा कर लिया। वर्ष में बोर्ड ने जो अन्य मुख्य कार्य किया। उनमें विस्थापित व्यक्तियों के लिये १५० मकानों और रसोईघर तथा बरामदे से युक्त एक कमरे वाले ८६ क्वार्टरों का निर्माण, १०४ क्वार्टरों सहित एक केन्द्रीय पार्क, पलश लैंड्रीन और पानी की सप्लाई के प्रबंध से युक्त जलकल की बस्ती का काम पूरा किया जाना, मास्टर प्लान के अंतर्गत बेनाबाबर रोड, ग्रांड ट्रंक रोड और कालपी रोड को मिश्रित करने वाली १०० फीट चौड़ी सड़कों का निर्माण, २८ सड़कों पर डामर बिछाना, अन्य दो सड़कों को पुनः पक्की करना और महात्मा गांधी सड़क पर नवाबगंज से फूलबाग तक ट्रैफिक पुलिस के खड़े होने के लिये १० स्थलों का निर्माण करना सम्मिलित है। वर्ष के अंत में महात्मा गांधी सड़क को कर्नलगज तथा परेड के बीच अधिक चौड़ी करने का काम हाथ में ले लिया गया था।

बोर्ड द्वारा इसकी उपविधियों का कड़ाई के साथ लागू किये जाने के परिणाम-स्वरूप अहातों के सुधार के संबंध में बोर्ड की सफलता प्राप्त हुई और ४३,००० रु० की तखसीनी लागत पर पाखानों, पेशाबघरों, पगडंडियों, पक्की नालियों, पानी के बंबों इत्यादि की व्यवस्था करने के लिये अहातों के ५१ स्वामी तैयार किये गये, १७ अन्य अहातों का ३०,००० रु० की लागत का सुधार कार्य बोर्ड द्वारा स्वयं किया गया, जिसमें सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्राप्त किया गया १०,००० रु० सम्मिलित है।

पुराने कानपुर क्षेत्र का विकास कार्य भी, जिसमें मध्यम श्रेणी के लोगों के लिये ५०० गृहों के प्लॉटों की व्यवस्था है, प्रारम्भ किया गया। इस क्षेत्र में ८६,००० रु० की लागत पर सड़कों के बनाने का काम पूरा किया गया। मध्यम तथा निम्न मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के लिये नारायणपुरवा क्षेत्र में २०० अन्य प्लॉटों (भूमिखंडों) की व्यवस्था की गई थी और नारायणपुरवा में स्थानीय निकायों तथा सरकारी विभागों के कर्मचारियों को रियायती दरों पर देने के लिये ३५० प्लॉट (भूमिखंड) बनाये गये थे। कारखाना क्षेत्र के टी० और पी० प्लॉटों में तथा सोसायटी नाला योजना के संबंध में विकास कार्य चालू था।

गृह-निर्माण के संबंध में ६८७ भवनों के नक्शों, जिनमें २,५५० किराए के मकानों की व्यवस्था है, के लिये द्वितीयकृत की गई थी। वर्ष के अंत में बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जनता के कुछ व्यक्तियों द्वारा ५४६ मकान बनाए जा चुके थे और अन्य २७६ के संबंध में निर्माण कार्य चालू था।

नगर में पानी सप्लाई का प्रबंध सुचारु रूप से चल रहा था, जिसमें प्रतिदिन अधिक से अधिक २,७०,००,००० गैलन पानी की सप्लाई होती थी। पानी की सप्लाई को अप्रॉइनेन्स फंड्री तक पहुंचाने की योजना का काम प्रारंभ कर दिया गया था और उसी प्रकार से पानी की सप्लाई को चकरी हवाई अड्डे तथा छावनी क्षेत्र तक पहुंचाने के प्रस्ताव प्रगति के विभिन्न स्तरों पर थे।

बोर्ड के संरक्षण में दो पौवशालाएं थीं। लगभग ४० विभिन्न प्रकार के पेड़ लगाने गए और मौसमी फूलों तथा तरकारियों की बेहिन जनता के हाथ नाममात्र के मूल्य पर बेची गईं। ४०० नए पेड़ लगाए गए और ३ नए पार्क बनाए गए।

मकानों का निर्माण कार्य पूरा किया और नगर के एक सबसे अधिक गंदे स्थान छितवापुर पजावा क्षेत्र में, जिसमें अब तक सब नालियाँ कच्ची थी, जमीन के नीचे गंदे पानी की नालियों का एक जाल सा बिछा दिया, अंत में कच्ची नालियाँ हटा दी गईं। ट्रस्ट का प्रस्ताव था कि सड़कें, गलियाँ और सतह की नालियाँ बनाकर छितवापुर पजावा क्षेत्र का और अधिक सुधार किया जाय।

ट्रस्ट के अन्य उल्लेखनीय कार्यों में विस्थापित व्यक्तियों के क्वार्टरों से होकर विक्टोरिया पार्क तक जाने वाली सड़क और कान्यकुब्ज तथा जुबली कालेजों तक जाने वाली सड़कों, निशातगंज और बागशेरगंज में कई सड़कों का निर्माण, मेरिस मार्केट में फ्लश लैट्रीन का निर्माण, पानी की सप्लाई का डाली-गंज तक बढ़ाने और पानी निकास की सुविधा औद्योगिक क्षेत्रों को प्रदान किये जाने के कार्य सम्मिलित हैं।

मुख्यतया वस्तुओं के महंगे होने के कारण इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की योजनाओं के कार्यों में प्रगति बहुत संतोषजनक नहीं रही। रेन्ट कण्ट्रोल एण्ड इविकशन अफसर के परामर्श से विस्थापित व्यक्तियों के लिये ट्रस्ट द्वारा बनवाये गये क्वार्टरों के किराए को निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा किया गया और यह निर्धारित किराया पूर्वं निश्चित किराये से काफी कम था। अवधि के भीतर अदायगी के लिये लोगों को प्रलोभन देने के विचार से ऐसे भुगतान पर बढ़ा देने की प्रणाली भी चलाई गई। पुनर्वासित व्यक्तियों की बस्ती में पानी की स्वतंत्र रूप से सप्लाई सुरक्षित करने के विचार से एक ट्यूबवेल लगाया जा रहा था और बिजली सप्लाई करने के लिये सर्विस लाइन की और आगे बढ़ा दिया गया था। ट्रस्ट ने विस्थापित व्यक्तियों के हेतु क्वार्टरों के निर्माण के लिये ३ एकड़ ६८६ वर्ग गज और भूमि नियत की।

मास्टर प्लान का कार्य समाप्त हुआ और पाँच अन्य योजनाओं के संबंध में पैमाइश तथा नक्शे बनाने का काम हाथ में लिया गया।

भेलूपुरा नामक स्थान के एक स्वतः पूर्ण नगर की विकास-योजना और नीचीबाग शांतिग सेन्टर योजना, जो बनारस इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा गृह निर्माण तथा सामान्य विकास के प्रयोजन से बनाई गई थी, के संबंध में इस वर्ष स्वीकृति दी गई और वे प्रगति के विभिन्न स्तरों पर थी। भोजबीर क्षेत्र की एक तीसरी गृह निर्माण योजना अभी प्रकाशित नहीं हुई थी। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के निकटवर्ती क्षेत्र की प्रस्तावित दुकान तथा आवासिक गृह योजना के संबंध में होने वाली पैमाइश का काम चालू था।

ट्रस्ट ने दो उद्यानों का विकास कार्य पूरा किया, एक घोड़ा घाट में और दूसरा त्रिपुरा भैरवी में और तिलभांडेश्वर तथा देवनाथ नामक स्थानों के दो उद्यानों के संबंध में भूमि प्राप्त करने की कार्यवाहियाँ चल रही थीं। ६ सड़कों की योजनाओं के संबंध में भूमि प्राप्त करने की कार्यवाहियाँ भी चल रही थी या चलाई जाने वाली थीं। इसके अतिरिक्त काशी रेलवे स्टेशन और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बीच में एक १०० फीट चौड़ी सड़क द्वारा सोना सबंध स्थापित करने के हेतु एक एक्सप्रेस रोड स्कीम बनाई गई और इसकी सूचना प्रकाशित की गई। इस संबंध में जो आपत्तियाँ प्राप्त हुईं उन पर वर्ष के अंत में विचार किया जा रहा था।

आलोच्य वर्ष के अंत में आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के हाथ में कई योजनाएँ थी जो प्रगति के विभिन्न स्तर पर थी, जिनमें ३ गृह निर्माण

इलाहाबाद

बनारस

आगरा

की योजनाएं, ५ विकास योजनाएं, ३ सड़कों की योजनाएं तथा एक विविध योजना सम्मिलित हैं।

गृह निर्माण संबंधी योजनाओं में महात्मा गांधी रोड की गृह निर्माण योजना, जिसमें ७४ एकड़ भूमि की आवश्यकता है, आपत्तियों के लिये विज्ञप्त की गई। इस संबंध में श्रीर आगे की जाने वाली कार्यवाहियाँ उस समय तक के लिये स्थगित कर दी गईं जब तक कि भरतपुर के महाराजा की कुछ भूमि की प्राप्त करने के प्रश्न पर निर्णय न हो जाय।

वर्ष के अंत में वलोचपुरा गृह निर्माण योजना के संबंध में, जो विस्थापित व्यक्तियों के लिये बनाई गई थी, सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही थी और विस्थापित व्यक्तियों की सिविल लाइन की योजना के संबंध में हाई कोर्ट द्वारा स्थगन आज्ञा होने के कारण इसका काम रोक देना पड़ा।

पाँच विकास योजनाओं में कंधारी रोड विकास योजना को छोड़ कर कोई भी ऐसी योजना न थी जिसके काम में सरकार की स्वीकृति हो जाने के बाद कोई प्रगति हुई हो। इस योजना के संबंध में भूमि प्राप्त की गई थी और विकास कार्य कुछ आगे बढ़ाया गया। जैपुर गृह निर्माण योजना के संबंध में जो आपत्तियाँ प्राप्त हुई थी उनकी सुनवाई इस संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व (representations) प्राप्त होने के बाद रोक दी गई थी।

सड़कों (street) की तीन योजनाओं के संबंध में सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गई।

ट्रस्ट ने राजमंडी रेलवे स्टेशन को किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने के लिये रेलवे के अधिकारियों से निवेदन किया और इस संबंध में उक्त अधिकारियों द्वारा उस स्थान का निरीक्षण किया गया।

नगर तथा ग्राम संविधायन

पहले की भांति नगर तथा ग्राम संविधायन विभाग के कर्त्तव्यों में स्थानीय प्राधिकारियों को उप-नगर विस्तार इत्यादि से संबंधित योजनाओं को बनाने में परामर्श देना तथा पथ-प्रदर्शन करना, गाँवों के लिये योजनाएं बनाना, नए उप-नगरी अथवा बस्तियों के विकास की योजनाएं बनाना, कस्बों तथा गाँवों की पारस्परिक सहयोग योजनाएं बनाना, बाढ़ तथा अग्नि प्रकोप जैसी आकस्मिक आपत्तियों द्वारा नष्ट हुए क्षेत्रों के लिये उत्तम प्रकार के नक्शे तथा गृह निर्माण योजना बनाना, सरकारी विभागों के भवनों के संबंध में बड़े आकार की इमारतों के लिये स्थान नियत करने और स्थानीय प्राधिकारियों को गृह-निर्माण तथा सड़क बनाने की योजनाओं अथवा प्रमुख सार्वजनिक भवनों को बनाने के संबंध में परामर्श देने का काम सम्मिलित है। यह स्थानीय प्राधिकारियों को स्थापत्य संबंधी मामलों में भी परामर्श देता था।

आलोच्य वर्ष में ३ मास्टर प्लान तैयार किये गये, जिनमें से दो इलाहाबाद तथा अल्मोडा के लिये और एक गौचर (जिला गढ़वाल) के आदर्श नगर तथा बाजार के लिये था। गृह निर्माण की ६ बड़ी योजनाएं, विस्थापित व्यक्तियों के लिये २२ योजनाएं, सहकारी समितियों के लिये ८ नक्शे, स्थानीय निकायों के लिये १० योजनाएं, चीनी की मिलों के मजदूरों की बस्तियों के लिये १७ नक्शे, सामाजिक तथा नागरिक जांच पड़ताल की ३ योजनाएं, स्थापत्य संबंधी ३१ योजनाएं और ६ विभिन्न योजनाएं भी तैयार की गईं।

गृह-निर्माण संबंधी ६ बड़ी योजनाओं में आगरे की नया आगरा तथा जैपुर की गृह-निर्माण योजना, बनारस की भोजपूरी विकास योजना, लखनऊ की नदी किनारे पर गृह-निर्माण योजना, कानपुर की जल-कल भूमि पर गृह निर्माण योजना और मिर्जापुर की सेटलर्स कालोनी योजना सम्मिलित हैं। मेरठ,

शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, बरेली, रामपुर, काशीपुर, हलद्वानी, हाथरस, हस्तिनापुर, फैजाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, खुरजा, मुरादाबाद, फरीदपुर, शामली, खतौली, गोला गोकर्ननाथ और बुलन्दशहर के नगरों में विस्थापित व्यक्तियों के संबंध में योजनाएं तैयार की गईं। स्थानीय निकायों के लिये बनाई गई १० योजनाओं में से ६ योजनाएं कानपुर विकास बोर्ड और लखनऊ तथा आगरा के इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों के लिये बनाई गई थी। इलाहाबाद, अल्मोड़ा तथा हरद्वार के नगरों के लिये सामाजिक तथा नागरिक (CIVIC) जांच-पड़ताल की गई।

विभाग ने ५ रिपोर्टें भी तैयार की, जिनमें से दो आदर्श भवन निर्माण उपविधि तथा प्रादेशिक नियमों के संबंध में थी। दूसरी रिपोर्ट का उद्देश्य यह था कि आवासिक क्षेत्रों में भवन निर्माण के मामले में होने वाली वैयक्तिक स्वैच्छाचारिता पर प्रतिबंध लगाने के आवश्यक साधनों की व्यवस्था की जाय।

अध्याय ४—उत्पादन तथा वितरण

२७—कृषि

जनवरी, १९५१ ई० में थोड़े से जिलों में औसत से कम वर्षा हुई और अन्य जिलों में हल्की बौछारे हुई। फरवरी के प्रथम सप्ताह में बहुत से जिलों में औसत से कम बौछारे हुई और थोड़े से जिलों में औसत वर्षा हुई। फरवरी के दूसरे सप्ताह में कई जिलों में हल्की बौछारे हुई। कुछ जिलों में ओलों से खड़ी फसल को थोड़ी सी हानि पहुंची और कई जिलों में स्थान स्थान पर बिड़ुयो ने हानि पहुंचाई। मार्च के दूसरे और तीसरे सप्ताह में थोड़े से जिलों में हल्की बौछारे आईं, किन्तु चौथे सप्ताह में अधिकांश जिलों में औसत से कम वर्षा हुई और थोड़े से जिलों में भारी वर्षा हुई। इस महीने में प्रायः सभी जिलों में कुल वर्षा औसत से अधिक हुई। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में अधिकांश जिलों में कहीं कहीं हल्की बौछारे आईं और शेष महीने में कई जिलों में हल्की बौछारें आईं। मार्च के अन्तिम सप्ताह और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में कई जिलों में खड़ी और खलिहानों में काटकर रखी हुई फसल को वर्षा और ओलों से क्षति पहुंची। मई के प्रथम और चतुर्थ सप्ताह में कई जिलों में औसत से कम वर्षा हुई। जून के प्रथम तीन सप्ताहों में अधिकांश जिलों में हल्की बौछारें आईं और बाकी जिलों में औसत से कम वर्षा हुई। महीने के अन्तिम सप्ताह में कुछ जिलों में भारी वर्षा हुई और शेष जिलों में औसत से कम वर्षा हुई।

१९५१ ई०
में वर्षा और
सामान्य
स्थिति

इस वर्ष मानसून बहुत कम थी और इस राज्य में औसत से कम थी। जुलाई और अगस्त के महीने में बहुत से जिलों में औसत से कम वर्षा हुई और थोड़े से जिलों में जोर की वर्षा हुई, किन्तु अधिकांश जिलों में दोनों महीनों में कुल वर्षा औसत से कम रही। सितम्बर के प्रथम सप्ताह में बहुत से जिलों में वर्षा औसत से कम हुई और कुछ जिलों में जोर की वर्षा हुई। सितम्बर के दूसरे सप्ताह में कई जिलों में जोर की वर्षा हुई और शेष समस्त जिलों में औसत से कम वर्षा हुई। किन्तु इसके तीसरे और चौथे सप्ताह में कुछ दिनों में केवल हल्की बारिश हुई और बाकी जिलों में बारिश हुई ही नहीं। अक्टूबर में कई जिलों में कहीं कहीं केवल हल्की बारिश हुई और बाकी जिलों में वर्षा न हुई और इस प्रकार राज्य भर में वर्षा औसत से कम हुई। नवम्बर के प्रथम तीन सप्ताहों में तो राज्य भर में कहीं भी वर्षा नहीं हुई, तथापि चतुर्थ

सप्ताह में बहुत से जिलों में हल्की बौछारें आईं और शेष जिलों में वर्षा बिलकुल नहीं हुई। दिसम्बर में राज्य भर में कहीं भी वर्षा बिलकुल नहीं हुई।

वर्षा ऋतु में और उसके बाद वर्षा के अभाव में और अपर्याप्त होने से राज्य में खरीफ की फसलों और विशेषतः धान की काफी क्षति पहुंची। नेपाल तराई के समीप कुछ भागों और गोडा, बस्ती और गोरखपुर जिलों के कुछ क्षेत्रों में, जो नेपाल की सीमा पर हैं और जहां मुख्यतया धान पैदा होता है, खरीफ की फसल का बोया जाना और देर से होने वाले धान के पौदों के रोपने का काम न हो सका। भित्री में नमी की बहुत कमी होने के कारण रबी की फसल के लिए खेत विशेषकर न सींचे जाने वाले क्षेत्रों में सन्तोषपूर्ण ढंग से नहीं तैयार किये जा सके और कुछ कम क्षेत्रों में रबी की फसल बोई गई थी।

१९५०-५१ ई० में फसलों का क्षेत्रफल तथा उत्पादन गन्ना गुड़ चावल ज्वार	१९५०-५१ ई० में गन्ना का क्षेत्रफल २५,०७,६४५ एकड़ था, जिसमें गत वर्ष की अपेक्षा क्षेत्रफल में १९.४ प्रतिशत वृद्धि हुई और गुड़ की कुल पैदावार २९,०६,४६९ टन हुई और इस प्रकार इसमें १०.४ प्रतिशत वृद्धि हुई। चावल का क्षेत्रफल ९३,१६,०२९ एकड़ था और उसमें गत वर्ष के चावल के क्षेत्रफल की अपेक्षा ३.२ प्रतिशत वृद्धि हुई, किन्तु १९५०-५१ ई० में कुल उत्पादन २०,०८,६९६ टन था, जो कि गत वर्ष की अपेक्षा १९.६१ प्रतिशत कम था। यह कमी सूखा, जिससे फसल को भारी क्षति पहुंची, पड़ने के कारण बतलाई जाती है। ज्वार (जो कि २३,३२,००२ एकड़ था) के क्षेत्रफल में ०.७ प्रतिशत नाम मात्र की कमी हुई, किन्तु बाढ़ के कारण फसलों को नुकसान पहुंचने से उत्पादन में ८३ प्रतिशत की कमी हुई अर्थात् वह ४,२१,२८४ टन रही। बाजरा के क्षेत्रफल में ४.२२ प्रतिशत और उत्पादन में ४.४९ प्रतिशत कमी हुई, क्षेत्रफल और उत्पादन के आंकड़े क्रमशः २५,६६,२६२ एकड़ और ४,४७,४८३ टन हैं। मक्का का क्षेत्रफल २०,४३,६३६ एकड़ था अर्थात् गत वर्ष से ७.०९ प्रतिशत ज्यादा था और कुल पैदावार ६,४०,९०१ टन थी। इस प्रकार इसमें १८.६ प्रतिशत वृद्धि हुई। गेहूं के क्षेत्रफल में ०.२४ प्रतिशत और कुल पैदावार में १२.७६ प्रतिशत वृद्धि हुई। क्षेत्रफल और कुल पैदावार क्रमशः ८२,२१,०६१ एकड़ और २९,१४,७८४ टन थी। जहां तक जौ का संबंध है क्षेत्रफल में २.७५ प्रतिशत कमी हुई अर्थात् ४५,६८,६३८ एकड़ था, किन्तु कुल पैदावार में ८.४ प्रतिशत वृद्धि हुई अर्थात् १६,३४,८३५ टन थी। चने का जहां तक सम्बन्ध है क्षेत्रफल और कुल पैदावार क्रमशः ६२,४५,७०९ एकड़ और १४,६३,५७८ टन थी, जिससे गत वर्ष की अपेक्षा क्रमशः ६.१६ और २.४ प्रतिशत की कमी प्रदर्शित होती है। कपास के क्षेत्रफल में २.२ प्रतिशत की कमी हुई, किन्तु कुल पैदावार में २.३ प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्योंकि मौसम अनुकूल रहा और कपास के क्षेत्रफल और कुल पैदावार के आंकड़े क्रमशः १,०४,७१५ एकड़ और प्रत्येक ३९२ पौन्ड वाली ४५,००० गांठें हैं।
---	---

सरकारी फार्म इस वर्ष वसागिक फार्मों की कुल पैदावार बढ़कर २३.४ मन प्रति एकड़ हो गई।

अधिक अन्न गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी अन्न उत्पादन को प्राथमिकता दी गई उपजाओ और जितना संभव हो सकता था उतना अधिक अन्न उत्पादन करने के लिए प्रत्येक आन्दोलन प्रकार के प्रयास किये गये। बांध बनाने, भूमि को चौरस करने, नक्शे तैयार करने,

बागबानी
सम्बन्धी
विकास तथा
वृक्षारोपण
आन्दोलन

कृषि विभाग के बागवानी उप-विभाग की सामान्य कार्यवाहियों के अतिरिक्त फल के पेड़ों के अलावा जलाने की लकड़ी, चारा और इमारती लकड़ी के पेड़ों के लगाने के उद्देश्य से एक वृहद् वृक्षारोपण आन्दोलन चलाया गया। इस वर्ष कुल २२,३६,८६६ पेड़ लगाये गये, जबकि गत वर्ष केवल १४,८८,२४० पेड़ लगाये गये थे।

इस वर्ष लगभग १६,८८३ एकड़ क्षेत्र में नए फल के बाग लगाये गये और पुराने फल के बाग के ८,६०१ एकड़ क्षेत्र को फिर से नई तरह लगाया गया। प्रत्येक १० एकड़ की १० केन्द्रीय पौधशालाये और पहाड़ों में ६ छोटी पौधशालाये और मैदानों में ७ जिला पौधशालाये नई योजना के अनुसार चालू की गई, जिससे काश्तकारों को देने के लिये विद्वसनीय पौधे पैदा किये जा सकें। केन्द्रीय पौधशालाओ में ३,५७,०१८ पौधे उगाये गये और वहां से २,२५,८०६ पौधे बाटे गये और पहाड़ों की पौधशालाओ से ११,००० पौधे बाटे गये।

दो नई अन्वेषणशालाये अर्थात् एक मैदानी फलो (सहारनपुर में) और दूसरी वनस्पतियो (लखनऊ में) के लिये उपयोगी कार्य करती रही।

पौधा संरक्षण
सेवा

टिडिडियों को, जिनके आने की सूचना सभी ५१ जिलों से मिली थी, मारने की कार्यवाहियाँ, जिसमें कांडो को मारने की गम्भीर समस्या भी शामिल है, जारी रही। जनवरी-अप्रैल के बीच की अवधि में लगभग १,३३४ एकड़ अतिरिक्त क्षेत्रफल में ये कार्यवाहियाँ की गईं और लगभग ४७६ मन टिडिडियाँ मारी गईं। मई और वर्ष समाप्ति की अवधि में पौधा संरक्षण कर्मचारी २० से अधिक जिलों में १४० समीपवर्ती क्षेत्रों में गये और अन्य सरकारी कर्मचारियों की सहायता से नियन्त्रण कार्यवाहियों का सगठन किया। लगभग १,३८० मन और ५० बोरे टिडिडियाँ नष्ट की गईं। १९५१ ई० में २५ जिलों में ४४,१७६ आम के पेड़ों में आम के पतंगों को मारने के विचार से ०.२५ प्रतिशत डी० डी० टी० छिड़का गया। जहाँ कहीं पहले डी० डी० टी० नहीं छिड़का गया था उन जिलों में चार आने प्रति पेड़ के हिसाब से लिया गया। गेहूँ, जौ, धान और ज्वार के बीजों से पैदा होने वाले रोग की रोकथाम के लिये पौधा संरक्षण सेवा हॉल ही के अनुसंधानों में फायदा उठाती रही और १७ जिलों में तीन आने तीन पाई से लेकर पाँच आने तीन पाई प्रतिमन के हिसाब से विभिन्न प्रकार के ४,६२० मन बीजों की रासायनिक जाँच की। चूहों के ७०,६८१ बिलों में आर० सी० एन० गैस छिड़की गई और १९५०-५१ ई० में चूहों के १३,७१४ बिलों को विषले कुत्तों द्वारा परिष्कृत किया गया और १९५१ ई० में अप्रैल से सितम्बर के भीतर ५,१८४ बिलों को गैस छिड़क कर परिमार्जित किया गया और ८७३ को विषले कुत्तों से परिष्कृत किया गया। राज्य भर में सरसों के युका (मस्टर्ड एफिस), ऊन पर लगने वाले यूका (अल एफिस), आड़ू की पत्तियों में घुंघरालापन लाने वाले यूका (फीच लीफ कालिंग एफिस), लाल-कहूँ के गोबरैलों (रेड पम्पकिन बीटल), सिर्गाई पर लगने वाले गोबरैलो, पहाड़ों पर फलदार पेड़ों पर लगने वाली लाहकैना (एक प्रकार की काई जो चट्टानों पर उगती है), सेव की पड़ों की स्टेम ब्राउन, स्टेम ब्लैक, कालर रौट और पिंक रोगों, गन्ने के पायरिला और रेड रौट रोगों, बैंगन के अकुरो और फलों को भेदने वाले तथा अन्य प्रकार के कीड़े और पौधों के रोगों को रोकने के भी उपाय किये गये।

आलोच्य वर्ष में कृषि विभाग का कार्य-क्षेत्र ३,६०० गाँवों में बढ़ाया गया और प्रदर्शनों के ३,००,००० नियत लक्ष्य में से २,३२,२४४ प्रदर्शन किये गये।

कार्य-क्षेत्र का प्रसार तथा प्रदर्शन

ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाने की योजना के अन्तर्गत जिस ७,७४३ एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रस्ताव किया गया था उसमें से १,२०४ एकड़ भूमि में खरीफ फसल और १,१४६ एकड़ भूमि में रबी की फसलें बोई गईं और कुल ७,१३३ मून की पैदावार हुई। जिस भूमि को भूमि कटने से रोकने की योजना के अन्तर्गत संरक्षित करना था उसमें पेड़ लगाये गये, जिसमें से १०,४५७ पेड़ सुरक्षित रह पाये। २८० संरक्षित भूमि के विभिन्न टुकड़ों में खरीफ फसल बोई गई और उसमें ६४४ मन पैदावार हुई।

ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाना और भूमि-संरक्षण

इस राज्य में जूट की खेती के लिये लक्ष्य के रूप में नियत क्षेत्र मार्च सन् १९५१ ई० में फिर से बढ़ाकर १,००,००० एकड़ कर दिया गया, लेकिन ६३,१२३ एकड़ से अधिक भूमि में बीज न बोया जा सका। इसमें से लगभग २५,२१८ एकड़ भूमि को अवर्षण इत्यादि के कारण हानि पहुँची। इस योजना के अनुसार, जो इस वर्ष तीन अन्य जिलों में भी लागू कर दी गई थी, १६ चुने हुए जिलों के ७० केन्द्रों में काम हो रहा था। यह अनुमान लगाया गया था कि ५,००,००० मन से ऊपर जूट का रेशा प्राप्त हो सकेगा।

जूट विकास

गत वर्ष आरम्भ की गई योजना के अनुसार जिसके अधीन भारत सरकार इस बात पर राजी हो गई थी कि जितने एकड़ भूमि में कपास की खेती की जावेगी उसके आधार पर वह खाद्यान्न देगी, ६३,१६७ एकड़ भूमि में (२४ जिलों में) कपास बोई गई, जबकि गत वर्ष केवल १६,६७७ एकड़ भूमि में बोई गई थी। काश्तकारों के बीज की आवश्यकता की पूर्ति के लिये १०,१०७ मन कपास का बीज, जिसमें से १,०६० मन अच्छे किस्म का बीज था, वितरित किया गया। कपास की फसल को अन्य फसलों के साथ मिलाकर बोने का प्रोत्साहित करने के लिये लगभग ४४४ मन कपास का बीज बिना मूल्य वितरित किया गया। उतने अतिरिक्त एकड़ भूमि के सम्बन्ध में जिसमें नहर के पानी से सिंचाई करके कपास उत्पन्न की गई थी, सरकार ने प्रति एकड़ सिंचाई कर के बराबर धनराशि राज्य सहायता के रूप में प्रदान की।

कपास विकास

सदा की भांति अनुसंधान कार्य विभाग के विभिन्न कार्यों में प्रमुख रहा। यह कार्य खेतों और प्रयोगशालाओं दोनों ही जगहों में किया गया। शाहजहाँपुर में गन्ना अनुसंधान संचालक (Director of Sugarcane Research) और कानपुर में कृषि रसायन शास्त्री (Agricultural Chemist) पौधों के रोगों के चिकित्सक (Plant Pathologist), कीटशास्त्रज्ञ (Entomologist) और रबी की फसल तथा तिलहन के लिये दो आर्थिक वनस्पतिज्ञ (Economic Botanist) के पर्यवेक्षण और पथ-प्रदर्शन में अनुसंधान कार्य किये गये। प्रदर्शन नगिना, जिला बिजनौर में सहायक आर्थिक वनस्पतिज्ञ (Assistant Economic Botanist) ने धान के सम्बन्ध में और बुलन्दशहर के सहायक आर्थिक वनस्पतिज्ञ (Assistant Economic Botanist) ने कपास में अनुसंधान कार्य किये। फलों और शाक भाजियों से संबद्ध अनुसंधान कार्य उद्यानकरण के उप-संचालक (Deputy Director of Horticulture)

कृषि सम्बन्धी अनुसंधान

के अधीन था। लखनऊ में शस्य जीवन प्रक्रिया विज्ञान सेक्शन (Crop Physiology Section), शस्य दैहिकी विद् (Crop Physiologist) के अधीन था।

शुद्ध बीज की वृद्धि की नई रीति

वैज्ञानिक ढंग से तैयार किये लकड़ी के बने हुए सस्ते बीज बोने के औजारों (Wooden Dibblers) द्वारा किये गये प्रयोग सफल सिद्ध होने पर इन औजारों का प्रयोग करने के तरीके के प्रदर्शन की व्यवस्था हर जिले में की गई, ताकि गाँव वालों को इस बात के लिये तैयार किया जा सके कि वे इस नये तरीके को अपना कर अच्छे बीज की वृद्धि करे तथा अपने गोदाम को बढ़ाये और इस प्रकार विभाग से अच्छे बीज की मांग को घटावे। ये औजार (dibbler) बीज बोने के उपकरण के रूप में काम में लाये जाते हैं और जब उनकी सहायता से गेहूं बोया जाता है तो एक एकड़ भूमि के लिये केवल ६ सेर बीज ही पर्याप्त हो जाता है तथा उपज भी लगभग उतनी ही होती है जितनी कि सामान्य तादाद यानी ४०-५० सेर गेहूं प्रति एकड़ भूमि में बोने पर होती है।

शिक्षा

कानपुर के कृषि कालेज (Agricultural College) और बुलन्दशहर गोरखपुर चिरगांव, (झांसी) और हवालबाग (अलमोड़ा) के कृषि स्कूल (Agricultural Schools) दोनों ही कृषि की सैद्धांतिक और व्यावहारिक शिक्षा देते रहे।

कृषि स्कूलों (Agricultural Schools) के पाठ्यक्रम में इस ढंग से परिवर्तन करने का प्रयास किया गया जिससे कि अधिक व्यावहारिक किसान तैयार हो सकें और प्रत्येक छात्र को अनाज पैदा करने के लिये दी गई भूमि में १/२० एकड़ से १/५ एकड़ तक की वृद्धि हो सके। साल की समाप्ति के समय कृषि कालेज तथा स्कूलों (Agriculture Colleges and Schools) को अपनी-अपनी तहसीलों में कृषि की वृद्धि के कार्य का उत्तरदायी बनाये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था। अमेरिका के लैंड ग्रान्ट कालेजों (Land Grant Colleges) के आधार पर इस राज्य में एक ग्राम्य विद्वद्विद्यालय (Rural University) स्थापित करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन था।

२८-कृषि इंजीनियरिंग

पिछले वर्ष की भांति कृषि इंजीनियरिंग विभाग की मुख्य कार्यवृत्तियों का उद्देश्य अन्न उत्पादन को बढ़ाना था। इनका संबंध निम्नलिखित से था :-

सिंचाई के छोटे-मोटे निर्माण-कार्य जैसे (१) पक्के कुओं की मरम्मत या निर्माण, वेधन द्वारा पक्के कुओं का सुधार, रहटों (Persian wheels) का लगाना, टच बवेलों का बनाना, पम्प से पानी खींचने वाली मशीनों का लगाना और नालियों, झीलों और तालाबों पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकने वाली पम्पिंग मशीनों का लगाना; (२) कारखानों का निर्माण, औजार बनाना और कृषि औजार संबंधी अनुसंधान कक्षा; (३) जोती जाने योग्य बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना तथा यंत्रों द्वारा खेती करना; (४) पानी के निकास की नालियों का सुधार करके पानी से भरे हुए क्षेत्रों को कृषि योग्य बनाना और (५) बुन्देलखण्ड में कण्टूर-बन्धियों का निर्माण।

सिंचाई
सम्बन्धी
निर्माण-कार्य

राज्य सहायता द्वारा पक्के कुओं के निर्माण योजना के अनुसार इस वर्ष १२,५८७ पक्के कुओं का निर्माण कार्य पूरा किया गया। कृषकों को नियंत्रित दर से इमारती सामान दिया गया और साथ ही उनको बिना ब्याज की उतनी तकावी दी गई जोकि कुओं की वास्तविक लागत के १/३ भाग के बराबर थी।

तथापि वर्तमान वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए इस वर्ष राज्य-सहायता संबंधी पिछले साल के नियमों में संशोधन किये गये । इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि वित्तीय सहायता के अधीन कुल नियत धनराशि में वृद्धि नहीं की जा सकती है, राज्य-सहायता देने की दर में कमी कर देने का निश्चय किया गया, जिससे कि अधिक से अधिक कुएं खोदे जा सकें और अधिक किसानों को लाभ पहुंच सके । विभिन्न क्षेत्रों में पानी की सतह, निर्माण-कार्य की लागत, कृषकों की आर्थिक स्थिति, प्रार्थना-पत्रों की संख्या, जो कुएं पूरे बन चुके हैं उनकी संख्या और विभिन्न जिलों की तुलनात्मक आवश्यकताएं आदि जैसी बातों को देखते हुए सरकार ने उन जिलों में जहाँ कृषक गरीब हैं और निर्माण-कार्य की लागत अधिक है, राज्य-सहायता घटाकर ४०० रु० प्रति कुएं की दर से और राज्य के बाकी जिलों में २५० रु० प्रति कुएं की दर से कर दी है ।

७३६ बेकार पड़े हुए कुओं को फिर से ठीक किया गया, जिसके लिए सम्बन्धित व्यक्तियों को नियंत्रित दर पर सामान दिया गया । इसके अतिरिक्त ३,६२२ पक्के कुओं का वेधन इस विचार से किया गया कि उनमें पानी ज्यादा हो जाय और वे स्थायी रूप से बराबर पानी दे सकें । इस प्रयोजन के लिए नियंत्रित दर से पाइप, छल्ला इत्यादि दिया गया और कुएं वेधन की लागत की ५० प्रतिशत तक धनराशि बिना ब्याज तकावी के रूप में दी गई । इन निर्माण-कार्यों के लिए बिलकुल राज्य-सहायता नहीं दी गई, किन्तु इस संबंध में सरकार ने जो उपरिबध्य किया था वह कृषकों के लिए रियायत के रूप में छोड़ दिया गया । इसी प्रकार की सुविधायें ३,६२२ पक्के कुओं में रहूट लगाने के संबंध में दी गईं । रहूट तैयार करने के लिए निर्माताओं और कृषकों को लोहा और इस्पात भी नियंत्रित दर से दिया गया ।

कृषि इंजीनियरिंग विभाग निजी तौर पर फार्म रखने वालों और यंत्रों द्वारा खेती करने वाले अथवा पशुपालन संबंधी फार्मों का काम करने वाले विभिन्न सरकारी विभागों के लिए बिजली के कुएं निर्माण करने का कार्य कर रहा । ट्यूबवेलों की लागत की १/३ धनराशि तक बिना ब्याज तकावी के रूप में दी गई । नियमानुसार राज्य-सहायता नहीं की जा सकती थी, किन्तु जहाँ किसी जिले में पक्के कुओं के बदले सहकारी सिंचाई समितियों के लिए ट्यूबवेल बनाये गये, सरकार ने ट्यूबवेल की लागत का १/३ भाग, जो प्रति ट्यूबवेल अधिक से अधिक ५,००० रु० तक था, उस अनुदान में भी स्वीकृत किया जो पक्के कुओं के लिए राज्य-सहायता के रूप में देने के लिए निश्चित था । इस योजना के अधीन मेरठ और इटावा जिलों में ट्यूबवेल बनाने का काम पूरा किया गया । इस वर्ष इस विभाग ने कुल १०२ ट्यूबवेल बनाये और वर्ष के अन्त में ६१ ट्यूबवेलों का निर्माण किया जा रहा था । बिजली से चलने वाले दो रिगों (Rigs) से जो पहिले ही यंत्रों द्वारा वेध कर ट्यूबवेल बनाने के लिए प्राप्त किये गये थे, इलाहाबाद, इटावा और बस्ती जिलों में, जहाँ मिट्टी की परतें खराब थीं और हाथ से खोदने वाले हथियारों में काम करना कठिन था, कई ट्यूबवेलों को बनाने में सुविधा मिल गई ।

एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकने वाले पम्प से पानी खींचने वाले स्थिर यंत्रों की योजना के संबंध में काफी सफलता मिली । इस वर्ष १०७ स्थिर-यंत्र ज्यादातर पूर्वी जिलों में, जहाँ बारिश बिलकुल नहीं हुई और सूखा पड़ गया था, सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था करने के विचार से लगाये गये । ये स्थिर-यंत्र २४,३६१ घंटे चले और इनसे लगभग ६,५०० एकड़ भूमि को फायदा पहुंचा । घंटों के हिसाब से सिंचाई महसूल लिया जाता रहा । सरकार

ने प्रति घंटा १ रु० ८ आना की दर से राज्य सहायता के रूप में दिया और कुषकों को प्रति घंटा २ रु० ८ आना की दर से भुगतान करना पड़ा।

वर्कशाप

आलोच्य वर्ष में बरेली के सेन्ट्रल वर्कशाप और मेरठ, झांसी तथा लखनऊ के जोनल (Zonal) वर्कशापों को उपयुक्त साज-सामान से सुसज्जित किया गया। तथापि झांसी और मेरठ की वर्कशापों में बिजली नहीं लगाई जा सकी, क्योंकि पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं थी। वर्कशापों में ट्रैक्टरों की सफाई की जाने लगी, ट्रैक्टरों, औजारों, परिवहन की गाड़ियों तथा कृषि सम्बन्धी यंत्रों की मरम्मत और औजार तथा ट्रैक्टरों के कल-पुरजे तैयार होने लगे। उन वर्कशापों में लोहा ढालने का काम, मशीन शाप वर्क और धातु का काम भी होने लगा। लगभग २०० ट्रैक्टरों की मरम्मत की गई तथा उनकी सफाई की गई और बलों द्वारा खींचे जाने वाले औजार, पाइपों के लिए सांकेट, कृषि कार्य के लिये छत्रे इत्यादि बहुत बड़े परिमाण में तैयार किये गये।

इन बड़े-बड़े वर्कशापों के अतिरिक्त १० ग्रामीण वर्कशापों को भी इस वर्ष सुसज्जित किया गया। इनमें छोटे-मोटे मरम्मत के काम किये जाने लगे और छोटे-छोटे ऐसे छत्रे तैयार किये जाने लगे जिनकी बेधन किया से तैयार होने वाले कुओ के संबन्ध में आवश्यकता थी। इनमें से कुछ वर्कशापों में कारीगरों को कृषि संबन्धी औजारों की मरम्मत करने और तेल से चलने वाले इजिनों तथा अन्य छोटे स्थिर-यंत्रों (प्लान्टो) को चलाने और उनको अच्छी हालत में बनाये रखने की ट्रेनिंग देने का काम भी प्रारम्भ किया गया।

गवेषणा

गवेषणा शाखा में छोटी मशीनों के उपयुक्त डिजाइन तैयार करने के प्रयोग किये जाते रहे। इंडियन सेन्ट्रल जूट कमेटी, कलकत्ता के सेक्रेटरी के विस्तृत विवरण के अनुसार जूट डिलिंग की पहली मशीन का समनुविधान (design) तैयार किया गया और वह मशीन इस वर्ष बनाई गई। इस मशीन की जाँच इंडियन सेन्ट्रल जूट कमेटी के कार्यालय और जूट एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के बैरकपुर स्थल पर की गई और परिणाम अच्छे निकले। मशीन को कम मूल्य पर तैयार करने की सम्भावना की जाँच की जा रही है।

वाटर-लिफ्टों (Water Lifts) में सुधार के लिए दक्ष टेकनिशियनों को सहायता दी गई। उन्हें आवश्यक निर्देश दिये गये और नियंत्रित दर पर उन्हें सामान देने की व्यवस्था की गई।

औजारों को प्रमापित करने के विचार से इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट में स्थापित टेस्टिंग स्टेशन (Testing Station) में बलों से चलाये जाने वाले औजारों की जाँच की गई और आवश्यक प्रमाण-पत्र दिये गये तथा जहाँ आवश्यक प्रतीत हुआ सुधार संबंधी सुझाव भी दिये गये।

ऐसे उपयुक्त फर्मों को, जिनके पास सुसज्जित वर्कशाप थे, खेती के उन्नत औजारों को तैयार करने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। इन फर्मों के वर्कशापों का निरीक्षण किया गया और निर्दिष्ट ढंग के औजारों को तैयार करने की उनकी क्षमता तथा सामर्थ्य की जाँच की गई। उन्हें उन्नत प्रकार के कृषि संबन्धी औजार तैयार करने के लिए लोहा और इस्पात आवश्यक परिमाण में दिया गया। ये औजार कुषकों के हाथ बेचने के लिये बनाये जायेंगे और सरकार उनकी अधिकतम कीमत नियत करेगी।

इस वर्ष भी ट्रैक्टरों की मदद से भूमि तोड़ी गई और उसके बाद ही खेती शुरू की गई। तराई और काशीपुर में भारत सरकार के बहुत से ट्रैक्टरों द्वारा भूमि तोड़ देने के बाद ही खेती करने के अधिकतर कालर (crawler) ट्रैक्टर हैं। पहिले की तरह काम में लाये गये। तराई और भाबर तथा इटावा

भूमि को खेती योग्य बनाना और यंत्रों द्वारा खेती

और लखीमपुर खीरी में नई भूमि को तोड़ने में भी इन ट्रैक्टरों का उपयोग किया गया। पहिरेदार किस्म के ट्रैक्टरों को अधिकतर यंत्रों द्वारा खेती के लिए और कृषि संबंधी मशीनों, जलाने के तेल इत्यादि को लाने-लेजाने के लिए प्रयोग में लाया गया। कृषि इंजीनियरिंग विभाग ने कृषकों को ठेके पर सुविधायें देने की व्यवस्था भी की थी। यह निश्चय किया गया कि जिलों को एक निश्चित संख्या में ट्रैक्टर उस समय दिये जायें जब कि किये जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में प्रस्ताव वास्तव में परिपक्व हो जायें। पहले की उस योजना को, जिसके अधीन कुछ जिलों में यंत्रों द्वारा खेती करने के उद्देश्य से जिला मैजिस्ट्रेट की देखरेख में ट्रैक्टरों के यूनिट दे दिये गये थे, परिणाम अच्छे न मिलने से छोड़ देनी पड़ी। नई योजना के अधीन ट्रैक्टर द्वारा जुताई के लिये जमीन जहाँ तक संभव हो सके १०० या इससे अधिक एकड़ के ब्लाकों में छाँटी जानी थी। उन दशाओं में भी ट्रैक्टरों की व्यवस्था की जानी थी जबकि एक बहुत बड़ी संख्या में एक दूसरे से मिले हुए छोटे-छोटे ब्लाक हों, किन्तु जिनका क्षेत्रफल १०० एकड़ से कम हो। इन सेवाओं के करन में विभाग का जितना व्यय होता वह पेशगी लिया जाने वाला था। किन्तु ऐसी दशाओं में जबकि किसान इन व्ययों को तुरन्त देने में असमर्थ होते थे कांवी ऋण, जिसे पश्चात्तवर्ती ३ बड़ी फसलों में से तीन किस्तों में वसूल किया जा सकता था, स्वीकृत किए गए। उन कृषकों को जो अपने-अपने ट्रैक्टर रखने के लिये उत्सुक थे, उन जिलों में जहाँ कि यह माँग ठीक समझी गई, ट्रैक्टर के कुल मूल्य की ५० प्रतिशत धनराशि को, जो १०,००० रु० से अधिक नहीं हो सकती थी, तकावी ऋण के रूप में देने की सुविधायें दी गयीं।

सब मिलाकर १३,०६९ एकड़ बन्जर भूमि तोड़ी गई। ७,७२५ एकड़ खेती की जाने वाली भूमि में हल चलाये गए और ४८,८५६ एकड़ भूमि में हेंगा (सरावन) चलाया गया।

बाहर से सामान भगाने के लाइसेंस सम्बन्धी प्रतिबन्धों के कारण ट्रैक्टरों के मरम्मत के लिये फुटकर पुर्जे प्राप्त करने और माँग किये जाने पर खेती के काम के लिये ट्रैक्टरों को तुरन्त उपलब्ध करने में कठिनाई होती रही। ट्रेनिंग-प्राप्त औद्योगिक कर्मचारियों की वैभागीक वर्कशापों में कमी के कारण और बिजली के न मिलने आदि जैसी अन्य बातों से भी कठिनाइयाँ हुयीं।

पानी के निकास की बहुत सी नालियों की योजना के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल की गई। इस वर्ष ७४ योजनाएँ निष्पादित की जा रही थीं। वर्ष के अन्त तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्य की काफी प्रगति हो चुकी थी, जिससे लगभग ६३,६०० एकड़ के क्षेत्रफल को लाभ पहुंचेगा।

पानी के निकास की नालियों में सुधार

कैन्टूर बन्धियों से सम्बन्धित कार्य बहुत काफी बढ़ गया था। बन्धियों के निर्माण कार्य में काफी प्रगति हुई। वे इस प्रकार बनाई जा रही हैं कि झांसी, इलाहाबाद, बाँदा और हमीरपुर का लगभग १६,२१४ एकड़ क्षेत्र पानी में डूब जाय।

बन्देलखण्ड में कैन्टूर बांधियाँ

२६-सिंचाई

मानसून में वर्षा कम होने के कारण अगहनी धान रोपने के सम्बन्ध में नहर के पानी की अधिक माँग हुई। मानसून के जल्दी खत्म हो जाने और जाड़े में वर्षा न होने के कारण रबी की फसल को पानी नहीं मिल सका और इसलिये वर्ष के अन्त तक पानी की अधिक माँग बनी रही। नदियों में कम

सामान्य

पानी रहने के कारण मांग पूरी करने में काफी कठिनाई हुई और कुछ स्थानों में नहरों तथा बिजली के कुंओं से जो पानी मिला वह पर्याप्त नहीं था।

आलोच्य वर्ष से ६६,६५,४७० एकड़ (१६५०-५१ ई० में रबी के ४१,३७,४७२ एकड़ और १६५१ ई० में खरीफ के २८,२७,९९८ एकड़) क्षेत्र में सिंचाई हुई, जबकि पिछले वर्ष ६०,१७,६७३ एकड़ क्षेत्र में सिंचाई हुई थी। सिंचाई का क्षेत्र बढ़ जाने का कुछ कारण तो यह था कि मानसून नहीं आया और अधिकतर यह कि उपलब्ध पानी का वितरण मितव्ययता और वैज्ञानिक आधार पर किया गया। यह तखमीना लगाया गया कि वर्ष में नहर और राज्य के बिजली के कुंओं की सहायता से सींची गयी जितनी फसले पकीं उनका मूल्य कुल १६० करोड़ रु० था और सम्बन्धित किसानों पर सिंचाई कर लगने से ५.४०८ करोड़ रु० राजस्व की प्राप्ति हुई।

चालू नहरें
और बिजली
के कुंए

वर्ष के अन्त में २६,०७३ मील नालियाँ चालू थी, जिनमें से १,२८८ मील नालियाँ आलोच्य वर्ष में बनायी गयी थी। कलेंडर वर्ष के अन्त में २,३५१ सरकारी बिजली के कुंए चालू थे, जिनसे १०.५४ लाख एकड़ क्षेत्र की सिंचाई की गई। इनमें से १३७ बिजली के कुंए साल के दौरान में बनकर तैयार हो गये और उनमें बिजली लगाई गयी।

निर्माण कार्य
जो पूरे हो
गये थे या जो
हो रहे थे

नई नालियों का निर्माण और गंगा तथा जमुना नहरों का विस्तार करने वाली अन्य नालियों का निर्माण कार्य होता रहा। गंगा नहर की पानी की निकासी की क्षमता ८,००० से १०,५०० क्यूसेक्स तक बढ़ाने के लिये सरकार ने १५ लाख रु० की तखमीनी लागत की एक योजना स्वीकृत की और यह कार्य अक्टूबर, १६५१ ई० में नहरबन्दी के समय प्रारम्भ किया गया। सोलानी पानी की नाली की सतह को कम करने और उसकी बगल की दीवारों को ऊँचा उठाने के फलस्वरूप गंगा नहर में अधिक पानी भेजना और ६१,००० एकड़ अतिरिक्त रबी क्षेत्र को सींचना संभव हो सका। धरौनी रेगुलेटर के फाटको को जो कि अत्यन्त पुराने हो गये थे बदल कर नये फाटक लगाने की एक योजना ३,५७,६४४ रु० की तखमीनी लागत पर स्वीकृत की गयी। नहरबन्दी के समय नये फाटकों में सिलप्लेट और साइड गूल लगाये गये। कनखल नगर की रक्षा के लिये गंगा नदी में बाँध बनाने का कार्य जारी रहा और लगभग ७.५ लाख रु० के व्यय पर वह जून, १६५१ ई० में पूरा हो गया।

राज्य के पश्चिमी जिलों में विभिन्न योजनाओं के अधीन बिजली के कुंओं का निर्माण कार्य जारी रहा और वर्ष के अन्त तक ६३७ बिजली के कुंओं को चालू किया गया।

बुन्देलखण्ड में ललितपुर, सपरार और कबरायू झील योजनाओं के सम्बन्ध में जो निर्माण कार्य पहले से हो रहा था वह पूरा हो गया, सिवाय बाढ़ के पानी की निकासी के लिये प्रबन्ध करने और जल मार्ग बनाने के। सिंचाई के प्रयोजनों के लिये ललितपुर तथा सपरार बाँधों पर एकत्रित पानी का बँटवारा तथा घसान नहर तन्त्र में उपयोग किया गया। रंगवान बाँध (बाँवा जिले में) और बेलन नहर योजना (इलाहाबाद जिले में) के निर्माण कार्य में अच्छी प्रगति रही। नई योजना, जिसके अधीन ३५० मील नयी नालियाँ और बेतवा नहर प्रणाली के आधार पर पानी के विस्तार की अन्ध नालियाँ बनायी जाने वाली थीं और जिसका निर्माण कार्य पहले से ही हाथ में ले लिया गया था, लगभग पूर्ण हो गया था।

झांसी, हमीरपुर, बाँवा, इलाहाबाद और मिर्जापुर जिले में भी कई बाँधियाँ बनाई गयीं और चन्द्रप्रभा, अहौरा, माटातिला तथा अर्जुन योजनाओं का, जिसके द्वारा लगभग ४ लाख एकड़ क्षेत्रफल को सिंचाई की संभावना थी, निर्माण कार्य हाथ में ले लिया गया।

गोरखपुर, बस्ती और देवरिया जिलों में १०० बिजली के कुंओं का निर्माण कार्य होता रहा और वर्ष के अन्त तक ६० बिजली के कुंओं को चालू किया गया। आजमगढ़ जिले में ४ पाताल तोड़ कुंए यह मालूम करने के लिए कि पूर्वी जिलों में जहाँ कि अगले १५ वर्षों में कई हजार बिजली के कुंए गलाने का प्रस्ताव था, किस प्रकार के बिजली के कुंए अत्यन्त उपयुक्त सिद्ध होंगे, बनाये गये।

सिंचाई की ११२ मील छोटी नालियों में से जिनका अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल और देहरी-गढ़वाल जिलों के अविकसित क्षेत्रों में निर्माण हो रहा था, ६३ मील नालियाँ पूरी की गयीं और वर्ष में सिंचाई के लिये उनको खोल दिया गया। उक्त योजना, जिसके अधीन निर्माण कार्य किया जा रहा था, के पूरी हो जाने पर २५० मील और नयी नालियाँ तैयार हो जायेंगी और उनसे प्रति वर्ष २०,००० एकड़ क्षेत्र को सिंचाई होगी।

राज्य के केन्द्रीय रीजन में सारदा नहर तन्त्र प्रतापगढ़ और दरियाबाद शाखाओं को सम्मिलित करते हुए २,००० मील नयी नालियाँ और पानी के विस्तार की अन्य नालियों को बनाकर सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार के लिये प्रयत्न किये गये। वर्ष के अन्त में चालू कुल १,४७५ मील नयी नालियाँ थीं। जहाँ कहीं उपलब्ध हो नदियों के अतिरिक्त पानी का उपयोग करने के अभिप्राय से प्रमुख सारदा नहर और उसकी शाखाओं की २,००० क्यूसेक्स क्षमता बढ़ाने के लिये ३६ लाख रु० की तखमीनी लागत पर सरकार ने एक योजना स्वीकार की और निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। शाहजहाँपुर, खीरी, सीतापुर, फैजाबाद और गोंडा जिलों में ३४० नये बिजली के कुंओं का निर्माण कार्य में, जिसे एसोसियेटेड ट्यूब-वैल्स लिमिटेड को सौंप दिया गया था संतोषजनक प्रगति रही।

३०-बिजली

विद्युत् शाखा, जो फरवरी, १९५० ई० में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सिंचाई शाखा से अलग कर दी गई थी, १ जनवरी, १९५१ ई० से चीफ इंजीनियर के चार्ज में रख दी गई। इस वर्ष सारदा जल विद्युत् सर्किल में ऊरल लाइनों के निर्माण तथा खातिमा में विद्युत् शक्ति के उत्पादन कार्य की देखरेख करने के प्रयोजन से दो नए डिवीजनों के बनाने की स्वीकृति दी गई इस प्रकार विद्युत् शाखा में कुल १४ डिवीजन और ३३ सब-डिवीजन हो गये।

इस वर्ष विभाग द्वारा लगभग एक करोड़ रुपये की लागत के बड़े निर्माण कार्य किये गये। इस वर्ष के अनुमानित राजस्व की धनराशि १,१४,५०,००० रु० थी। विद्युत् शाखा द्वारा प्रारम्भ किये गये विभिन्न निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में कुछ विस्तृत विवरण नीचे दिये गये हैं:—

(१) हरदुआगंज स्टीम स्टेशन का विस्तार—इस वर्ष ३ पुराने डब्ल्यू० आई० एफ० ब्वायलरों के लगाए जाने का काम जारी रहा।

(२) मुहम्मदपुर बिजलीघर—१ नम्बर की मशीन के सम्बन्ध में निर्माण कार्य चलता रहा और पूरा किया गया और फरवरी के महीने में व्यवसाय सम्बन्धी बिजली की सप्लाई करने के प्रयोजन से मशीन चालू की गई। वर्ष के अन्त में ग्रिड में लगाई गई मशीन की विद्युत् उत्पादन करने की क्षमता ३,१०० किलोवाट थी। बिजलीघर से वर्तमान रुड़की, मुजफ्फरनगर की ३७.५ के० बी० लाइन तक लगभग आधा मील लम्बी एक अस्थायी ३७.५ के० बी० लाइन का निर्माण किया गया जिसमें उत्पादित

सामान्य

गंगा जल-
विद्युत् सर्किल

विद्युत् शक्ति का उपयोग करने के प्रयोजन से बनाया गया एक ४,००० के० वी० ए० ११/३७.५ के० वी० ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। नम्बर २ और ३ की मशीन के सम्बन्ध में निर्माण कार्य चालू था। अक्टूबर के महीने में गंगा की नहर बन्द कर दी गई और नहरों की विशेष रूप से मरम्मत की गई।

(३) रामपुर बिजलीघर—एक नये ब्वायलर के लगाए जाने के सम्बन्ध में नींव तैयार की गई और यह अनुमान किया गया कि इससे रामपुर बिजलीघर की विद्युत् उत्पादक क्षमता ६०० किलोवाट और बढ़ जायेगी और नये ब्वायलर के सम्बन्ध में निर्माण स्थल पर ९८ प्रतिशत सज्जा पहुंच गई।

(४) मोहम्मदपुर सलवा ६६ के० वी० डबल सर्किट लाइन—वर्ष के अन्त में वह (बिजली की) लाइन जिसकी मोहम्मदपुर बिजलीघर द्वारा सप्लाई की जाने वाली विद्युत् शक्ति को उपयोग करने के प्रयोजन से बनाये जाने की आवश्यकता थी, वस्तुतः बन कर तैयार हो गई।

(५) मुमेरा, चन्दौसी और मुरादाबाद के सब-स्टेशनों के बीच की ६६ के० वी० की डबल सर्किट लाइन—इस लाइन पर नाप-जोख का काम हाथ में लिया गया, जो मुहम्मदपुर सलवा ६६ के० वी० डबल सर्किट लाइन के साथ-साथ गंगा प्रिड में प्रमुख दूरप्रेषण लाइनों के निर्माण कार्य का ऐसा भाग होगा जो प्रथम दौर में बनाने के लिये निश्चित किया गया है। दूरप्रेषण लाइन के लिये उपयोगी सामान का उत्पादन किया जा रहा था।

(६) राज्य के ६१६ ट्यूब-वैलों में बिजली लगाया जाना—इस सम्बन्ध में निर्माण कार्य वस्तुतः समाप्त हो गया था और अधिकांश कुंओं में बिजली लगाई गई।

(७) साल बल्ला का बदला जाना—राज्य के ट्यूब-वैलों में ११ के० वी० लाइनों के साल बल्ला के खंभों को हटाकर उनके स्थान पर इस्पात के खंभे लगाने का काम वस्तुतः पूरा हो गया था। इस वर्ष लगभग ८४ मील तक लगे हुए साल बल्लों को बदला गया।

(८) चित्तौरा और निरगजनी के सब-स्टेशनों का परिवर्द्धन—चित्तौरा और निरगजनी के मुख्य ६६ के० वी० के सब-स्टेशनों के परिवर्द्धन का काम पूरा हो गया था। अनुज्ञप्त क्षेत्रों में बिजली के उपभोक्ताओं पर होने वाले प्रतिबन्ध जारी रहे, किन्तु इस वर्ष मुहम्मदपुर के बिजलीघर से भी विद्युत् शक्ति के उपलब्ध होने के कारण ट्यूब-वैलों की बारी नियत करने का काम पहले की अपेक्षा कम हो गया। जनता को घरेलू प्रयोजनों के लिये एक बड़ी संख्या में अस्थायी रूप से बिजली के कनेक्शन देने की स्वीकृति दी गई।

सारदा जल
विद्युत् सर्किल

(१) खातिमा बिजलीघर—इस बिजलीघर में नम्बर १, २ और ३ की मशीनों में ड्राफ्ट ट्यूब लाइनरों के बनाने का काम पूरा हो गया था।

(२) सारदा जल-विद्युत् की दूरप्रेषण तथा रूपांतरण लाइनें—इस वर्ष विभाग द्वारा ६६ के० वी० सिगल सर्किट फीडरों का निर्माण कार्य जारी रखा गया। सेक्शन और नम्बर के फीडर (क्रमशः १८ और ७४ मील की लम्बाई के) शाहजहाँपुर मोहम्मदी और नेरी-सीतापुर-लखनऊ सेक्शन में टावरों बनाने का काम पूरा किया गया और शाहजहाँपुर, हरदोई सेक्शन में (नम्बर १ के फीडर में ४१ मील तक) स्टब लगाने का काम पूरा किया गया। लखनऊ के निकट गोमती नदी के खादर सेक्शन में पैसाइश की गई और इस बाढ़प्रस्त क्षेत्र में (जिसकी लम्बाई लगभग ६ मील है) टावरों के निर्माण के प्रयोजन से नीचे तैयार की गई और आवश्यक सामग्री की व्यवस्था की गई। ८८ के० वी० के बरेली-हल्द्वानी फीडर पर बहेड़ी तक (३० मील की दूरी तक)

लखीमपुर खीरी और बिसवाँ के म्यूनिसिपल बोर्डों को सड़क की रोशनी के लिये बिजली के सप्लाई की प्रयोजन से ११ के० बी० लाइनों का निर्माण किया गया और कम तनाव वाले विद्युत प्रसारक तार लगाए गये। इस कार्य में लगभग ५० मील लम्बी ११ के० बी० में लाइन बनाई गई और लगभग १५ मील की दूरी तक कम तनाव वाले विद्युत प्रसारक तार लगाए गए। डिस्पोजल से खरीदे गए दो डीजेल इंजनों की मरम्मत की गई और उक्त बिजली की सप्लाई के प्रयोजन से वे सीतापुर के अस्थायी बिजलीघर में लगा दिये गए।

लखीमपुर
खीरी तथा
बिसवाँ के
उपनगरों में
बिजली की
सप्लाई

इस वर्ष गोरखपुर के बिजलीघर में ६०० किलोवाट का एक दूसरा सेट लगाया गया और चालू किया गया। ४०० किलोवाट के एक और सेट लगाये जाने के लिये नींव तैयार की गई।

गोरखपुर
के राजकीय
ट्यूब-वेलों में
बिजली लगाने
की योजना

• देवरिया, मुंडेराबाजार, खलीलाबाद और बस्ती के उपनगरों में औद्योगिक तथा घरेलू प्रयोजनों के लिये बहुत से बिजली के कनेक्शन दिये गये और राज्य के बहुत से ट्यूब-वेलों में बिजली लगाई गई और बहुत सी रूरल लाइनों का निर्माण किया गया। देवरिया, खलीलाबाद और बस्ती के रेलवे स्टेशनों में भी बिजली दी गई। राप्ती नदी के पुल के टावरों का विस्तार किया गया और कन्डक्टर तथा अर्थवायर की ऊँचाई ७ १/२ फीट और बढ़ा दी गई।

केवल यही नहीं कि इस कारोबार (अन्डरटेकिंग) से होने वाली बिजली की सप्लाई संतोषजनक रूप से जारी रखी गई बल्कि दैनिक सप्लाई के घंटों को भी बढ़ाकर १४ से १८ कर दिया गया। वर्ष के अन्त में नित्य प्रति २४ घंटे बिजली की सप्लाई को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक २० किलोवाट सेट भी लगाया जा रहा था।

आजमगढ़
एलेक्ट्रिक
सप्लाई
अन्डरटेकिंग

सोहवल स्टीम स्टेशन में ब्वायलर से युक्त १,००० किलोवाट के दो टर्बो सेट लगाये गये और चालू किये गये और सोहवल से फँजाबाद तक ११ के० बी० के दोहरे फीडर का निर्माण कार्य पूरा किया गया और इससे बिजली लगाई गई। इसी प्रकार ३०० के० बी० ए० की क्षमता के फतेगंज सब-स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा किया गया और चालू किया गया। रूपांतरण (ट्रांसफार्मरों) के बदले जाने के सम्बन्ध में भी कार्य किया गया।

सोहवल स्टीम
स्टेशन तथा
फँजाबाद की
विद्युत सप्लाई
योजना

राज्य में बिजली सप्लाई करने के ४४ कारखाने थे जो कि बिजली लगे हुए ११६ नगरों की आवश्यकता पूरी करने रहे।

अन्य कारखाने

बिजली के इंस्पेक्टर ने लगभग २,००० बिजली लगी हुई इमारतों का निरीक्षण किया और ४,३३,६३१ रु० की लागत के निर्माण कार्यों का सम्पादन किया। बिजली के ठेकेदारों को कुल ६४ लाइसेंस जारी किये गये, जबकि इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर और वायरमैन की परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या क्रमशः ४ और ४५ थी। बिजली के झटके लगने से ४० घातक और ४६ साधारण दुर्घटनाएँ हुयी। अधिकतर दुर्घटनाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में हुई। इनका कारण ग्रामीणों का खंभों आदि पर चढ़ना बताया जाता है। बिजली की सप्लाई स्थिति में सुधार हो जाने के कारण सरकार ने आगरा-इलाहाबाद (ए० सी० सप्लाई) और झाँसी के नगरों में विद्युत शक्ति के वितरण और सप्लाई पर से नियन्त्रण हटा दिया था और अन्य नगरों में कुछ निर्धारित शर्तों पर प्राधिकृत लाइसेंसदारों को अपने आप बिजली के कनेक्शन दे देने की अनुमति दी गई। बाराबंकी, उन्नाव, हल्द्वानी और अल्मोड़ा के नगरों में पहले ही से ५० पी० एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) ऐक्ट, १९४७ ई० लागू नहीं था।

कानपुर
बिजली
सप्लाई
प्रशासन

आलोच्य वर्ष में कानपुर बिजली सप्लाई प्रशासन के बिजली उत्पादन और आय में वृद्धि होती रही। उत्पादन में वृद्धि होने का अधिकतर कारण यह था कि पिछले कुछ वर्षों से इसके विद्यमान स्थिर-यंत्र के सुचारु संचालन के लिए जो अनुसंधान किये गये उनमें सफलता मिली। स्थिर-यंत्र को पहिले जो अधिकतम क्षमता ३१,००० किलोवाट मान ली गई थी वह बढ़कर ३७,००० किलोवाट हो गई। इस पर केवल उतना ही व्यय हुआ जितना कि साधारणतः उसकी मरम्मत और रखरखाव पर होता।

प्रशासन ने एक बहुत बड़ी संख्या में नये विद्युत भार (लोड) देना स्वीकार किया और उपभोक्ताओं की संख्या २३,१५२ से बढ़कर २३,६२१ हो गई। दिये गये लोड का परिमाण ८८,२५० किलोवाट से बढ़कर ६३,३०७ किलोवाट हो गया, तथापि यह संभव न हो सका कि अतिरिक्त बिजली की मांग को पूरा किया जा सके। अतएव १५,००० किलोवाट के विद्युत् प्रसार योजना पर परिर्वर्द्धित वेग से कार्य करने के लिए प्रत्येक प्रयास किये गये। वर्ष के अन्त में नया व्वायलर करीब करीब पूरा हो रहा था।

श्रम संबंधी मामलों की ओर निरन्तर ध्यान दिया गया और यह कोशिश की गई कि कोई ऐसी बात पैदा न हो जिसकी मजदूर शिकायत करें।

३१-वन

सड़कों के
किनारे के
छायापथ
और नहरों
के किनारे
वृक्षारोपण

सड़कों के किनारे के छायापथों के संरक्षण तथा नहरों के किनारे पेड़ लगाने पर विशेष ध्यान दिया गया। यह देखा गया कि तन अधिकारियों को इतने अधिक व्यय और कष्ट के साथ लगाए पेड़ को क्षति से बचाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था और कुछ जिलों में गांव वाले उनको बुरी तरह से काट-छाट ले जाते थे। कोई भी ऐसा विशेष अधिनियम नहीं था जिसके अनुसार उक्त छायापथों तथा वृक्षों को क्षति पहुंचाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कोई सख्त कार्रवाई की जा सकती। इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ ई० के उपबंध उन पर लागू नहीं होते थे। अतएव आलोच्य वर्ष में विधान मंडल द्वारा भारतीय वन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५१ ई० पास किया गया जिससे कि सरकार सड़कों के किनारे के छायापथों तथा नहरों के किनारे के पेड़ों के संबंध में इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ ई० के उपयुक्त उपबंधों का प्रयोग कर सके।

लव्हेना के
निजी (p 1-
vate) वन

संयुक्त प्रान्तीय निजी जंगल संरक्षण अधिनियम, १९४८ ई० (यू० पी० प्राइवेट फारेस्ट्स ऐक्ट, १९४८ ई०) के अनुसार निजी (प्राइवेट) जंगल के लव्हेना ब्लाक को अधिकृत (vested) वन के रूप में घोषित किया गया। उक्त अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के संबंध में यह वहा के लिप्प किया गया था, जहाँ वृक्ष अधिक संख्या में काटे जा रहे थे।

भूमि-प्रबंधक
सकिल

भूमि-प्रबंधक सकिल, जो १९४५ ई० में बनाया गया था और जिसे नदी के कटावों पर नियंत्रण करने, नदी की तराई, बेकार तथा अन्य बंजर भूमि में खेती करने, रेलवे की भूमि, नहरों के किनारों, सड़कों के किनारे के छायापथों और नजूल की भूमि जैसी राज्य की भूमि में पेड़ लगाने और सुरक्षित ईंधन तथा चारा की व्यवस्था करने का काम सौंपा गया था, का काम जारी रहा।

१९५० ई० के अंत तक विभिन्न प्रयोजनों के लिए कुल ६५,५८३ एकड़ भूमि प्राप्त की गई। आलोच्य वर्ष में कोई नई भूमि नहीं प्राप्त की गई, क्योंकि यह निर्णय किया गया था कि जितनी भूमि प्राप्त की जा चुकी है उसी को विकसित किया जाय।

इस वर्ष ६७ एकड़ निजी भूमि और १५ एकड़ छावनी की भूमि के अतिरिक्त लगभग ८० मील लम्बे छायापथों पर ११० मील लम्बे नहरों के किनारों पर और १७ एकड़ रेलवे की भूमि पर नए पेड़ लगाए गए अथवा बीज बोए गए।

नहरों के किनारों पर ६ १/२ मील तक शहदूत के पेड़ लगाए गए और उसका परिणाम उत्साहवर्द्धक था।

भूमि-प्रबन्धक बोर्ड का चतुर्थ अधिवेशन लखनऊ में २२ अप्रैल, १९५१ ई० में हुआ। बोर्ड ने राज्य के लिए उपयुक्त एक भूमि संरक्षण अधिनियम (Soil Conservation Act) के बनाये जाने की आवश्यकता पर विचार किया। इस प्रश्न पर विचार करने तथा बोर्ड के आगामी अधिवेशन पर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रयोजन से एक उप-समिति नियुक्त की गई।

पश्चिमी अफ़मोड़ा, पीलीभीत तथा दक्षिणी दोआब फारेस्ट डिवीजनों से संबंधित योजनाओं का काम पूरा किया गया और चकराता डिवीजन की योजना का कार्य चल रहा था। इस वर्ष गोरखपुर और नैनीताल के फारेस्ट डिवीजनों से संबंधित योजना का काम भी हाथ में ले लिया गया था।

इस वर्ष सरकार ने भूतपूर्व बनारस रियासत के वनों में वन-बंदोबस्त संबंधी कार्य प्रारम्भ करने का निश्चय किया। इसके अतिरिक्त यह भी निश्चय किया कि (१) सुरक्षित वन घोषित किए जाने वाले क्षेत्रों में से मालगुजारी वाले गांवों के आबादी तथा खेती किए जाने वाले क्षेत्र निकाल दिए जाने चाहिए, (२) यदि सुरक्षित वन में मातहतदारों, स्वामियों या माफीदारों का कोई भूमि-खंड हो तो आवश्यकतानुसार उक्त व्यक्तियों के अधिकार खरीद लिए जाने चाहिए या लैंड एक्वीजिशन ऐक्ट के अधीन भूमि प्राप्त कर लेनी चाहिए।

जंगली हाथियों से होने वाली हानि को रोकने और तराई तथा भाबर के सरकारी आस्वानों की फसलों को हानि से बचाने के लिये प्रभावपूर्ण कार्रवाइयों की गई। उड़ीसा सरकार के एक पदाधिकारी को, जिसे खेदा कार्य के संबंध में बहुत काफ़ी अनुभव था, सेवाएं भी प्राप्त की गई।

वनों से कुल २,०७,००० मन रेजिन इकट्ठा किया गया। पिछले वर्षों में कभी भी इसकी इतनी प्राप्ति नहीं हुई थी। इंडियन टर्पेन्टाइन एंड रोजिन कंपनी लिमिटेड, कलटबर्कगंज इसका मुख्य ग्राहक था। लगभग १२,००० मन लीसा नीलाम की गई और थोड़ी सी कुमायूँ टर्पेन्टाइन एंड रोजिन फैक्टरी, सोमेश्वर को भी सप्लाई की गई।

अन्य राज्यों की भांति उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग को भी भारत सरकार ने यह परामर्श दिया कि वह अपने सुरक्षित तथा संरक्षित वनों में लकड़ का उत्पादन करे। यह इस उद्देश्य से किया गया कि हमारा देश जो संसार भर में पैदा की जाने वाली कुल लाख में से ६० प्रतिशत लाख का उत्पादन करता है इस संबंध में कृत्रिम (synthetic) लाख सप्लाई करने वाले अन्य देशों की प्रतियोगिता में कमजोर न रहे। इसके अनुसार दूधी के फारेस्ट डिवीजन में लाख का उत्पादन एक बड़े पैमाने पर होता रहा और इसी प्रकार से बनारस के फारेस्ट डिवीजन में भी काम प्रारम्भ किया गया। लगभग २,५०० पलास के पेड़ों में कच्ची लाख लगाई गई जिसका फल संतोषजनक रहा।

इमारती लकड़ों के लाने ले जाने तथा मूल्य पर कोई नियन्त्रण न था। इमारती लकड़ों के ढेरों (coupes) को आम नीलाम के द्वारा बेचने के अतिरिक्त औद्योगिक महत्व की कुछ विविध इमारती लकड़ियाँ जैसे सेमल, हलदू, बौरण, कजू, तून और गुटेल सदा की भांति निजी इकरारनामों के अधीन बेची गईं। आलोच्य वर्ष में विभिन्न रेलवे कंपनियों को १,७८,५०० साल ट्रंक-स्लीपर, ७१,३०० चीर ट्रंक-स्लीपर और ५८,१०० घनफिट विशेष माप के साल स्लीपर सप्लाई किए गए।

भूमि-प्रबन्धक बोर्ड

कार्य योजना

वनों की पैमा-इश, सीमा-निर्धारण तथा बन्दोबस्त

खेदा कार्य

लीसा

लाख

इमारती लकड़ी

ईंधन नियंत्रण १९५१ ई० में वर्ष भर ईंधन की लकड़ी के मूल्य तथा लाने ले जाने पर नियंत्रण बना रहा और वनों से राज्य के २५ नगरों को नियंत्रित दरों पर ईंधन की लकड़ी सप्लाई की गई। उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली के सैनिक विभाग को और चीनी मिलों तथा अन्य कई छोटे औद्योगिक कारखानों को भी सस्ती ईंधन की लकड़ी सप्लाई की गई। कुल जितनी ईंधन की लकड़ी सप्लाई की गई उसका विवरण नीचे दिया हुआ है :-

(क) असेनिक (सिविल) जनसंख्या, सैनिक तथा

छोटे उद्योग

४३,८६,४०० मन

• (ख) चीनी मिल

६,४१,४०० मन

बहराइच में सहायता कार्य

जिला बहराइच में घोर दुष्काल (अन्न संकट) की स्थिति में पीड़ितों की सहायता करने के विचार से वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण की योजना पर कार्य प्रारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत बहुत से श्रमिकों को काम मिल गया।

राजस्थान के अकाल पीड़ित क्षेत्रों को सहायता

चारे की कमी की स्थिति में राजस्थान सरकार की सहायता करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे इस राज्य से ४ लाख मन सूखी घास सप्लाई करने का निश्चय किया।

पुनर्वासन

पाकिस्तान से आये हुए जिला रावलपिंडी के विस्थापित कृषकों तथा हरिजनों को बसाने और सहारनपुर तथा मुजफ्फरनगर के जिलों में बाढ़ द्वारा नष्ट किए गए गावों को फिर से बसाने के प्रयोजन से सहारनपुर वन डिवीजन के पथर्री ब्लॉक में २,५०० एकड़ क्षेत्रफल की भूमि दी गई।

वन पंचायतें

३१ मार्च, १९५१ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में कुमायू में लगभग २६६ वर्गमील भूमि में १,०६८ पंचायतें काम कर रही थीं। उसके बाद किसी नई पंचायत की स्थापना नहीं की गई, क्योंकि यह निश्चित किया गया था कि वर्तमान संगठन को ही अधिक सुव्यवस्थित रूप से चलाया जाय। विभिन्न पंचायतों द्वारा किए जाने वाले जनोपयोगी काम में पाठशालों की इमारत का बनवाया जाना, ग्राम मार्गों का सुधार, जलाशयों का निर्माण इत्यादि सम्मिलित था।

वित्तीय स्थिति

१९५०-५१ के वित्तीय वर्ष में वन-विभाग के राजस्व में २,३१,४७,००० रु० की बचत हुई और १९५१-५२ में उसके लगभग २,२४,५६,००० रु० होने की आशा की जाती थी।

३२-उद्योग-धंधे

उद्योग-धंधों के लिये टेक्निकल कर्मचारियों की प्रशिक्षण संस्थाएँ

सरकार, राज्य के उद्योग-धंधों को पूर्ववत् तथासंभव सभी प्रकार की सहायता देती रही। उद्योग विभाग की विभिन्न वैभागीक योजनाएँ, जो विशेषतः कुटीर उद्योगों के विकास में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई थीं, चालू रहीं।

इस वर्ष उत्तर प्रदेश में २४ सरकारी टेक्निकल (technical) तथा औद्योगिक संस्थाएँ थीं। इनमें कानपुर का हार्कोर्ट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट टेक्नालॉजिकल खोज का केन्द्र बना रहा और जो साधारण खोज संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करने के अतिरिक्त आंखल टेक्नालॉजी में प्रशिक्षण देता रहा। पूर्व की भांति सूती कपड़ों के उद्योग के संबंध में प्रशिक्षण देने के निमित्त ७ संस्थाएँ थीं, एक कानपुर का केन्द्रीय टेक्स्टाइल इंस्टीट्यूट था जिसमें कताई, बुनाई, रंगाई और छपाई का एक चार वर्ष का पाठ्यक्रम था। सेन्दल वीविंग

इन्स्टीट्यूट, बनारस में करघे की बुनाई के संबंध में ऐसी ही शिक्षा दी जाती थी। अन्य ५ माडल वीविंग स्कूल थे, जहाँ मुख्यतया कारीगरी की प्रशिक्षण दिया जाता था। लखनऊ, झांसी और गोरखपुर के ३ टेक्निकल इंस्टीट्यूट मिर्कैनिकल तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण देते रहे। इसके अतिरिक्त २ आकूपेशनल और ४ पालीटेक्निक इंस्टीट्यूट थे। ५ इंस्टीट्यूट लकड़ी के काम तथा बड़ईगरी में और अन्य स्कूल चमड़े के काम, चमड़ा कमाने तथा धातु के काम में प्रशिक्षण देते रहे। इसके अतिरिक्त गाजीपुर में एक टेक्निकल स्कूल था और लखनऊ में एक आर्ट्स और क्राफ्ट्स स्कूल था। टेक्निकल तथा औद्योगिक संस्थाओं से संलग्न भारत सरकार के प्रशिक्षण केन्द्रों में विस्थापित व्यक्तियों, हस्त्रिजो तथा राजनैतिक पीड़ितों को प्रशिक्षण दिया गया और विस्थापित छात्रों को भी विशेष सुविधायें दी गईं।

• इन संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या १,३६५ थी। विभिन्न छात्रों की संस्था के विद्यार्थियों की प्रति विद्यार्थी ७५ रु० से १५० रु० तक मूल्य के भारत सरकारी ११ छात्रवृत्तियाँ और प्रति विद्यार्थी १५० रु० प्रतिमास के मूल्य के उत्तर प्रदेश अनुसंधान समिति की १० छात्रवृत्तियाँ दी गईं। धनवाद के इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइन्स, बंगलौर के इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइन्स और बम्बई के जे० जे० आर्ट्स स्कूल में अध्ययन करने वाले उत्तर प्रदेश के उपयुक्त तथा निर्धन विद्यार्थियों को अपने आंशिक व्यय को पूरा करने के लिए पहले से जो प्रति विद्यार्थी ५० रु० प्रति मास का छात्रवेतन दिया जाता था वह जारी रखा गया। उत्तर प्रदेश के ऐसे विद्यार्थियों को जिनकी उच्च टेक्निकल तथा वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा हो १ प्रतिशत के नाम-मात्र के ब्याज पर ऋण देने के लिए एक लाख रुपए की धनराशि अलग निकाल कर रख दी गई।

टेक्निकल इंस्टीट्यूटों की पुनर्संगठन समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार के पास भेजी। वर्ष के अंत में रिपोर्ट विचाराधीन थी।

५२ टेक्निकल तथा औद्योगिक संस्थाओं को, जिनका प्रबंध निजी तौर से तथा स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है, कुल १,४३,४४६ रु० के सहायक अनुदान दिये गये।

वर्ष में जिन महत्वपूर्ण खोज सम्बंधी समस्याओं के संबंध में कार्यवाहियाँ की गईं उनका संबंध निम्नलिखित से था :—

• (१) फ्यूजेल आयल से अलकोहल से प्राप्य ग्लैस्टिडाइजर्स संश्लिष्ट रसायनों (synthetic chemicals) इत्यादि का तैयार किया जाना।

(२) सल्फरलमाइड (sulphalamide) तथा सल्फे-पिरिडी (sulphapyridine) का तैयार किया जाना।

(३) फौटोग्राफी का काम।

(४) इंडियन वेजिटेबुल आयल के नॉन-ग्लिसरीडाइड (non-glyceride) अवयव।

(५) अर्द्ध-व्यावसायिक आधार पर झुंडी की खली से ऐक्टिवेटेड कार्बन का तैयार किया जाना।

(६) ऐन्टी-आक्सीडेंट्स का अध्ययन करने के प्रयोजन से सर्कारी पर्य का लगाया जाना।

छात्रों की भर्ती, छात्र-वृत्तियाँ, छात्रवेतन इत्यादि

टेक्निकल इंस्टीट्यूटों की पुनर्संगठन समिति

सहायक अनुदान

अनुसंधान

(७) कलाबत्तू रौलर का बनाया जाना ।

(८) चमड़े का तल्ला काटने वाली मशीन का बनाया जाना ।

(९) हैंडमिल का बनाया जाना ।

(१०) सोडियम जिकेट में सेलूलोज का घुलना और उस सेलूलोज के घोल का सूती उद्योगों में फिनिशिंग करने के लिए प्रयोग करना ।

(११) ऊनी कपड़े के लिये उन्नत प्रकार की मिलिंग मशीन ।

(१२) बिजली से चलने वाले कर्घों में वार्ष प्रोटेक्शन ।

(१३) फेस हाइड मार्किंग ।

उद्योग-धन्धों
को अन्य
सहायता

वर्ष से कोयला और कोक की सप्लाई में काफी उन्नति हुई । भारत सरकार ने भी २८ बैगन कोयला इस उद्देश्य से और बांटा जिससे राज्य के ऐसे सभी उद्योगों के पास जो ब्राड-गेज के रेलवे स्टेशनों पर स्थित थे कोयले के रिजर्व तैयार हो जाय ।

मैटीरियल रिसोर्सेज कमेटी ने कारखानों तथा वर्कशापों के निर्माण के लिये बांटने के प्रयोजन से उद्योग विभाग के अधिकार में १,५०० टन इस्पात, ३,००० बैगन सीमेंट और ५०० बैगन स्लैक कोयला रख दिया । सीमेंट के सम्बन्ध में कारखानों की मांगें पूर्ण रूप से पूरी की गई । वर्ष के पूर्वार्द्ध में पाइप की जो मात्राये बांटी गई वे संतोषजनक रही, परन्तु वर्ष के उत्तरार्द्ध में पाइप की सारी मांगें पूरी न की जा सकी क्योंकि राज्य के पाइपों को कोटे में सहसा कटौती कर दी गई थी ।

भारत सरकार ने राज्य के कुटीर तथा छोटे पैमाने वाले उद्योगों को बांटने के लिये ४०० टन इस्पात का एक विशेष कोटा दिया, किन्तु बाद में इसे काट कर २६४ टन प्रति तिमाही कर दिया गया । अलीगढ़ के ताले, मेरठ के कैंची, चाकू इत्यादि बनाने वालों और साइकिल के हिस्से, चौर-फाड़ के यन्त्र, बिजली का सामान बनाने वालों को परमिट दिये गये ।

उत्तर प्रदेश के तेल विशेषज्ञ के परामर्श पर, भारत सरकार ने खाने योग्य तेल इत्यादि को पैक करने के लिये टीन के डिब्बे बनाने के प्रयोजन से रजिस्टर्ड निर्माताओं को तेल के मिलों में सप्लाई करने के लिये टीन की प्लेटें दी ।

राज्य सरकार के उद्योग विभाग ने तेल की विभिन्न मिलों को सरसों के तेल के यातायात के लिये टैंक बैगन दिये । ये ५ बैगनों तेल-विशेषज्ञ के परामर्श पर उद्योग विभाग के उन बैगन समूहों में से दी गयी थीं जिन्हें कलकत्ता के ईस्ट इंडियन रेलवे के चीफ आपरोटिंग सुपरिन्टेंडेंट ने उनके सुपुर्द किया था । बैगनों की संख्या नियत करते समय प्रत्येक मिल की पेरने की क्षमता का ध्यान रखा गया ।

औद्योगिक प्रयोजनों के लिये अपेक्षित पेट्रोल, मिनरल आयल, टरपेन्टाइन, रासायनिक पदार्थ, लिक्वोरिन, वायर सिलिकन शीटें, डीजेल आयल, मिट्टी का तेल, सूत, कपड़ा, भूमि इत्यादि के मुक्त क्रिये जन्मे के सम्बन्ध में भी सिफारिशें की गईं । उद्योग विभाग ने औद्योगिक कारोबार की आयात की हुई अपेक्षित वस्तुओं को प्रमाणित करना जारी रखा ।

पूर्व की भक्ति विकास टेक्नोलॉजी उपविभाग ने कांच तथा मिट्टी के उद्योग-धन्धों की उनकी दिन-प्रति-दिन की समस्याओं में सहायता की । वैश्लेषिक नियन्त्रण और कच्चे साल के परीक्षण, उत्पादन के विकास, नियन्त्रण यन्त्रों के प्रयोग तथा एकत्रीकरण सम्बन्धी कार्रवाइयों की तरफ काफी ध्यान दिया गया ।

राज्य में १२३ पढ़ाई की कक्षाएँ चल रही थीं, जिनमें शिल्प सम्बन्धी विभिन्न कलाओं में प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जिनमें बुनाई, रंगाई तथा छपाई, मोजे बनाना, चमड़ा कमाना तथा चमड़े का काम, दर्जांगीरी, मिट्टी के बर्तन बनाना, बढ़ईगीरी, लकड़ी के खिलौने बनाना इत्यादि काम सम्मिलित थे। १,१२,५२१ रु० के मूल्य का सामान तैयार किया गया और प्रशिक्षण पाने वाले व्यक्तियों की सहकारी समितियों की संख्या बढ़कर ५९ हो गई। पढ़ाई की कक्षाओं ने बहुत सी महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों तथा मेलों में भाग लिया और उन्होंने स्टोर्स पर्चेज सेक्शन द्वारा सरकारी विभागों को १,४३,७१० रु० ६ आना ३ पाई से अधिक मूल्य का सामान सप्लाई किया।

९,१७६ सूत कातने वाले को प्रशिक्षण दिया गया और विभिन्न उत्पादन केन्द्रों में ९५० मन सूत तैयार किया गया। किसान आश्रम के सरकारी उत्पादन केन्द्र में लगभग १४,२६३ गज कपड़ा तैयार किया गया। इस वर्ष बुनाई सिखाने वाली ६ कक्षाओं ने भी काम किया और बुनाई में प्रशिक्षण दिया। देहात के बुनकरों के लिये प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्रों में कुल १,७०,४०० रु० के मूल्य का सूत तैयार किया गया। वर्ष में ९ सहायता-प्राप्त चरखा उत्पादन केन्द्रों ने खादी केन्द्रों को चरखे के सेट सप्लाई करने के सम्बन्ध में काम किया। पिछले वर्ष के खादी के उत्पादन के आधार पर श्री गांधी आश्रम तथा अन्य खादी संघों को राज्य-सहायता प्रदान की गई। नए खादी संघों को अनुदान भी दिये गये।

इस आशय के आदेश, कि राज्य के चिकित्सालयों तथा औषधालयों की बिछौने की चादरे, ड्राशीट चादरे (drawsheets), तकियों के गिलाफ, धोतियाँ, एप्रन और सरकारी कार्यालयों, सरकारी निवास-स्थानों और रेस्ट हाउसेज में काम आने वाले पायजामे, पदें, मँजपोश, तौलिये, सजाने के कपड़े, झाड़न और बस्ते जैसी वस्तुएँ केवल खादी की बनी हो, लागू रहे। इससे खादी संघों को अपने स्टॉक निकालने में सहायता मिली।

आलोच्य वर्ष में ९ उत्पादन केन्द्रों में कच्चे द्वारा उत्पादन कार्य किया गया और २,५६,५५० रु० के मूल्य का ८,१८,३६० गज कपड़ा करघे द्वारा तैयार किया गया। लगभग २,००० बुनकर काम पर लगाए गये और उन्हें २१४ लाख रु० मजदूरी के रूप में दिया गया। १५० नई डिजाइनें जारी की गईं।

बुनकरों की ६९२ सहकारी समितियों ने, जिनमें ९३ लाख सदस्य थे, करघा उद्योग के विकास के लिये कार्य किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार का ३३.८२ लाख गज कपड़ा तैयार किया।

रेशम के कीड़े पालने की योजना देहरादून में डोईवाला और प्रिमतनगर में चलती रही, जहाँ रेशम के कीड़े पालने और शहतूत के पेड़ लगाने के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देना जारी रखा गया। उन व्यक्तियों को, जिन्हें रेशम के कीड़े पालने के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया गया था, छात्र-वैतन भी दिया गया। तीन विद्यार्थियों को रेशम उद्योग में प्रशिक्षण प्राप्त करने के निमित्त मैसूर और पश्चिमी बंगाल भेजा गया और केन्द्रीय सिल्क बोर्ड द्वारा दिये गये अनुदानों में से प्रत्येक को १०० रु० प्रति मास का छात्र-वैतन दिया गया। लगभग ६०४ पौन्ड १२ औन्स रेशम के कोवे (cocoons) तैयार किये गये।

५९ नई डिजाइनें चालू की गईं और लखनऊ के पुराने चिकन उद्योग के पुनर्जीवन तथा विकास से सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत ४३,११२ रु० ५ आना

वैभागिक
योजनाएं
(१) पढ़ाई
की कक्षाएं

(२) खादी
विकास

(३) करघा
पर बुनाई

(४) करघा
के बुनकरों
की सहकारी
समितियाँ

(५) रेशम
उत्पादन

(६) चिकन
उद्योग

के मूल्य का माल तैयार किया गया। इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य यह था कि निर्धन मजदूरों को शोषण से बचाया जाय तथा उन्हें काम दिया जाय।

(७) ऊन योजना

अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल और देहरी के जिलों में ऊन योजना चाल रही। पूर्व की भाति वाणिज्य सम्बन्धी उत्पादन सहकारी समितियों का काम था। टेक्निकल मामलों में सलाह देने, समितियों के गोदामों तक कच्चे माल के निःशुल्क परिवहन के रूप में वित्तीय सहायता देने, सहकारी समितियों को कच्चा माल उधार दिलवाने और समितियों तथा व्यक्तियों को उन्नत उपकरण और औजार दिलाने तथा तैयार माल के विक्रम में सहायता देने के लिये उद्योग विभाग जिम्मेदार था। - उन्हें ४,५५२ रु० की लागत के रासायनिक पदार्थ तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं भी सप्लाई की गईं। लगभग ३१४ मन सूत तैयार किया गया। नजीबाबाद की ब्लैन्केट फिनिशिंग फैक्ट्री से कुटीर उद्योगों में काम करने वालों द्वारा किये गये कम्बलों को धोने, माड़ लगाने तथा उन्हें अन्तिम रूप से तैयार करने का काम चालू रहा। चूंकि कारखाने को चालू रखने के लिये स्थानीय उत्पादन पर्याप्त न था, इस लिये उद्योग के पथ-प्रदर्शन में सरकारी संस्थाओं को सप्लाई करने तथा जनता में विक्रय के लिये कम्बल बनान और उन्हें पूर्ण रूप से तैयार करने का निश्चय किया गया।

(८) रंगाई तथा अन्तिम रूप देने (Finishing) का कारखाना

मऊ में रंगाई तथा अन्तिम रूप देने के सरकारी कारखाने (Government Dyeing & Finishing Factory) ने अनुसंधान विभाग में तैयार किये गये उन्नत उपकरणों तथा नई डिजाइनों का प्रदर्शन जारी रखा। इस कारखाने में २७,००० गज स्टैंडर्ड (standard) कपड़ा तैयार किया गया।

(९) तन्तु उद्योग

०१९५१ ई० में भी हारकोर्ट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में विभिन्न स्थानीय तंतुओं जैसे पटसन, पीला रामबांस इत्यादि पर प्रयोग किये गये। प्रारम्भिक प्रयोगों से यह पता चला कि जूट के स्थान पर अलसी के रेशों का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है और यदि ये ५०:५० के आधार पर जूट में मिलाये जायें तो इससे अच्छे बोरे बनाये जा सकते हैं। तदनुसार गोंडा और बस्ती के जिलों में अलसी की सूखी घास इकट्ठा करने से सम्बन्धित योजना के काम को जारी रखने और इससे तन्तु बनाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में स्वीकृति दी गई। इस वर्ष उक्त दोनों जिलों में लगभग २,३९७ मन अलसी का डंठल इकट्ठा किया गया और उसके रेश तैयार किये गये। मजदूर तन्तु तैयार करने के लिये उक्त संस्था में एक छोटी सी पस्पेडर (paspader) मशीन भी लगाई गई।

(१०) हाथ से कागज बनाने की योजना

७ विद्यार्थियों को हाथ से कागज बनाने की कला तथा कागज की लुग्दी के काम में ट्रेनिंग दी गई। फाइल कैंडक तथा फाइल कवर बनाने के लिये फाइल कवर के कागज के ५,००० तख्ते तैयार किये गये। इस वर्ष औसतन ६०० फाइल कवर प्रति मास के हिसाब से इलाहाबाद के सरकारी छापखाने को दिये गए और ३,२७५ फाइल कवर, ३,१५० कैंडक और १७५ फिल्टर पेपर पैकेट सरकारी कार्यालयों को सप्लाई किये गये। काल्पी केन्द्र में ३,७४८ पौन्ड लुग्दी तैयार की गई, जिसमें से २,७०७ पौन्ड स्थानीय कारीगरों को फिल्टर तथा ब्लॉटिंग पेपर तैयार करने के लिये बेची गई और शेष इस केन्द्र द्वारा स्वयं उपयोग में लाई गई।

(११) गुड़ योजना

गुड़ योजना ४० जिलों में ६,००० गांवों में चली। ४५ गन्ना उत्पादकों को उन्नत प्रकार के गुड़ तैयार करने के सम्बन्ध में स्थानीय अवैतनिक कार्यकर्ताओं के रूप में ट्रेनिंग दी गई। १६,१६६ उन्नत किस्म की भट्ठियाँ बनाई गईं और २,७६,६६० रु० के ७५३ उन्नत किस्म के कोल्हू तथा ३२६ रस उबालने के

का हे प्रयोग म लाए गये । इटावा की गवर्नमेंट कार्बन फैक्ट्री में ६१३ ह० ४ आना के मूल्य का लगभग ३६,४५० पौन्ड कार्बन तैयार किया गया ।

इस वर्ष कुटीर तेल उद्योग योजना प्रयोगात्मक तथा प्रदर्शनात्मक रूप में कार्य करती रही । ग्रामीण क्षेत्र में उन्नत वर्धा तेल घानियों को चालू करने के प्रयत्न होते रहे । इन घानियों को बनाने में १६ बड़इयो को ट्रेनिंग दी गई और १२,८०० ह० का माल तैयार किया गया । राज्य में आयोजित विभिन्न प्रदर्शनियों में प्रदर्शन किए गए ।

(१२) कुटीर, तेल उद्योग योजना

एसेंशल आयल तथा इत्र उद्योग योजना के अन्तर्गत, जो १९४८ ई० में स्वीकृत की गई थी, कानपुर के हारकोर्ट बटलर टेक्नीलॉजिकल इंस्टीट्यूट में और प्रयोग किए गए । पिपरमिंट के पौधे लगाये गये और उससे निकाला गया तेल काफी लोकप्रिय हुआ । बहुत से इत्र तथा तम्बाकू के व्यापारियों ने अपनी चीजें बनाने में सेन्थल के स्थान पर इसका प्रयोग किया । जिन विशुद्ध पौधों में कपूर पाया जाता है, उनकी खेती रामपुर और लखीमपुर-खीरी में निजी रूप से की गई । फूलों की पैदावार पर विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के प्रभाव को जाँच करने के उद्देश्य से कानपुर के इंस्टीट्यूट में भी प्रयोग किये गये । इन प्रयोगों में अमोनियम सल्फेट, सल्फर फास्फेट, नाइट्र और पशुशाला की खाद को मिलाकर या अलग अलग उपयोग किया गया ।

(१३) एसें-शल आयल तथा इत्र

राज्य सरकार द्वारा गुट प्रोडक्ट्स आर्डर, १९४८ ई० जारी रखा गया । चूंकि भारत सरकार न मुख्यतः देश में शकर की कमी के कारण अगस्त, १९५० ई० से नये लाइसेंस देना बन्द कर दिया था, अतः नये लाइसेंस किसी को भी नहीं दिये गये । इस वर्ष लाइसेंस की फीस से कुल १६,०५५ ह० की आमदनी हुई और कारखानों में जो वस्तुएं फलों से तैयार की गई उनका मूल्य लगभग १६,५५,००० ह० था ।

(१४) फलों से तैयार की जानेवाली वस्तुएं

१९५१-५२ के वर्ष में १६ और परिवारों ने खुरजा के गवर्नमेंट पाटरी डबेलपमेंट सेन्टर से लाभ उठाया, जो कि प्रयोग में आने वाले मिट्टी के बर्तन तथा अन्य प्रकार की वस्तुएं तैयार करने के लिये स्थानीय कारीगरों को संगठित करने के उद्देश्य से खोला गया था ।

(१५) मिट्टी के बर्तनों की योजना

उन्होंने लगभग १,१६,६६४ ह० का कच्चा माल खरीदा और लगभग २,४१,३६० ह० की वस्तुएं तैयार कीं । इस वर्ष इस योजना से शीर्षक 'वाणिज्य सबन्धी क्रियाओं' के अन्तर्गत लगभग ८,८०० ह० का लाभ हुआ ।

इस योजना के अन्तर्गत खुरजा के कुटीर-उद्योग में काम करने वालों को उन्नत प्रकार की शिल्प कला की शिक्षा देना जारी रखा गया और इसके परिणाम-स्वरूप जो वस्तुएं उन्होंने बनाई उनमें चाय के सेट, होटल के सॉदे और बन-बूटेदार चीनी के बर्तन, रासायनिक पदार्थों के बर्तन, हल्की तश्तरियाँ इत्यादि सम्मिलित हैं ।

बनारस और खुरजा केन्द्रों में लगभग २० व्यक्तियों को आभूषण के काम की सुन्दर काँच की गुरियाँ बनाने की ट्रेनिंग दी गई । सफल उम्मीदवारों को सज्जा तथा सामान के रूप में अनुदान दिये गये, ताकि उन्हें स्वतन्त्र कारीगर के रूप में काम शुरू करने में आसानी हो । इन कारीगरों के कारखाने विभिन्न आकार तथा रंग की गुरियाँ, कान के बुन्दे, टाप्स, नकली मोती इत्यादि तैयार करते रहे ।

(१६) काँच की गुरियाँ

इस वर्ष मुरादाबाद में जो योजना पक्की कलाई के बर्तनों के प्रसिद्ध उद्योग को सुरक्षित तथा पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई थी, चालू रही और १९५० ई० में खोले गए सरकारी कारखाने में ६८ प्रतिशत टिन और २ प्रतिशत शीशा मिली हुई पक्की कलाई से वस्तुएं तैयार करने की व्यवस्था जारी रखी गई ।

(१७) लौह रहित (non-ferrous) धातु योजना

कच्ची कलई से वस्तुएं तैयार करने के काम को रोकने के लिए तथा खरीदने वालों को वस्तुएं खरीदने में सहायता देने के उद्देश्य से सरकारी केन्द्र में अन्य निमाताओं द्वारा तैयार की गई वस्तुओं पर कलई करने तथा उनकी किस्म बन्दी करने के संबंध में प्रबंध किया गया। साथ ही कारीगरों को विभिन्न उद्योगों में ट्रेनिंग देने के प्रयोजन से सुविधायें दी गईं।

(१८) पाइ-
लेट वर्क-
शॉप योजना कुर्वाड़ तथा इटावा में पाइलेट वर्कशॉप योजना के अन्तर्गत, जो लोहारी-
फिटिंग, टीन का काम, ढलाई जैसे इंजीनियरिंग के व्यवसायों में ग्रामीण कारीगरों के घरों पर ही ट्रेनिंग में सुविधाएं देने तथा उन्हें विभिन्न कृषि यंत्रों तथा घरेलू उपयोग की हार्डवेयर की अन्य वस्तुओं को तैयार करने में सहायता देने के उद्देश्य से चालू की गई थी, काम चलता रहा। कारखानों में प्रारम्भिक उत्पादन कार्य के संबंध में ट्रेनिंग दी गई।

(१९) ऋण १९४७-४८ के वर्ष में ऋणों और अनुदानों की योजना, जो छोटे पैमाने वाले तथा कुटीर-उद्योगों के विकास के लिए टेक्निकल योग्यता-प्राप्त व्यक्तियों को उचित व्याज की दर पर निःशुल्क अनुदानों तथा ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता देने के अभिप्राय से प्रारम्भ की गई थी, इस वर्ष चालू रही। इस वर्ष विभिन्न व्यक्तियों को कुल २,०४,७०० रु० के ऋण और २९,५५० रु० के अनुदान दिए गए।

(२०) किस्म-
बन्दी योजना इस वर्ष किस्मबन्दी योजना, जो कुटीर उद्योगों में तैयार की गई वस्तुओं की किस्म पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से चालू की गई थी, आगरा के जूता उद्योग, करघे से बुने हुए कपड़े, अलीगढ़ के ताला उद्योग तथा फर्रुखाबाद के छपाई उद्योग पर भी लागू की गई। जो फर्म इस योजना में सम्मिलित हुईं और जिन्होंने निर्धारित किस्म की वस्तुएं तैयार करना स्वीकार किया, उनकी संख्या ३० थी। जूता उद्योग में निर्धारित किस्मों का ३,५५५.२३ रु० ७ आना का माल तैयार किया गया। लगभग ८४,२६६ रु० का फर्रुखाबाद की छपाई का लगभग २१,५०,६८३ वर्ग गज कपड़ा तैयार किया गया और उस पर किस्म की छाप लगाई गई। इसके अतिरिक्त लगभग १४,२६,०१३ रु० के १७,८२,६०५ गज करघे पर बुने हुए कपड़े पर और बहुत से अलीगढ़ के तालों पर किस्म की छाप लगाई गई। विदेशी खरीदने वालों के ऐसे बहुत से पत्र प्राप्त हुए जिनमें उन्होंने इस योजना के अंतर्गत किए जाने वाले उपयोगी कार्य की प्रशंसा की।

(२१) गवर्न-
मेंट यू० पी० हेन्डीक्राफ्ट्स कुटीर उद्योगों की तैयार की हुई वस्तुओं के लिए विक्रय एजेंसी के रूप में कार्य करता रहा। इसने नई डिजाइनें प्रचलित करने के लिए एक व्यापारिक प्रदर्शन-गृह के रूप में भी काम किया। आलोच्य वर्ष में कुल लगभग ८,७२,७३४ रु० की बिक्री हुई। इस संगठन ने भारत तथा इसके बाहर होने वाली विभिन्न प्रदर्शनियों में भाग लिया। विदेशों में कुटीर उद्योगों द्वारा तैयार किए हुए सामान की बिक्री बढ़ाने के लिए जोरदार प्रयत्न किए गए।

(२२) विस्था-
पित - उद्योग विभाग द्वारा विस्थापित व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दी तथा अन्य प्रकार की सुविधायें दी गईं। कुटीर उद्योग की बहुत सी मशीनों, जो जापान से मंगाई गई थीं और लखनऊ की बन्द डिहाइड्रेशन फैक्टरी में लवाई गई थीं, के संचालन के काम में विस्थापितों को ट्रेनिंग दी गई। विस्थापित व्यक्तियों को नियोजित सामान दिलाने के संबंध में सहायता की गई और बहुत से मामलों में विदेशों से कुछ विशिष्ट किस्म का माल मंगवाने के संबंध में सिफारिशें की गईं।

मेरठ के खेलकूद के सामान के उद्योग में लगे हुये, विस्थापित औद्योगिक व्यक्तियों के उपयोग के लिये सूत तथा कपड़े की सप्लाई प्राप्त की गई। उद्योग, जिसको स्यालकोट के निर्माताओं तथा श्रमिकों ने सरकारी सहायता से स्थापित किया था, उन्नति करता रहा।

गत वर्ष की भांति उद्योग-विभाग के स्टोर्स पंचेज शाखा ने विशेष प्रकार के स्थिर-यंत्र और मशीनों तथा अन्य सज्जा, जिसमें ट्रैक्टर, जमीन खोदने वाले उपकरण, शल्य चिकित्सा संबंधी औजार इत्यादि सम्मिलित थे और जिनकी विभिन्न सरकारी विभागों की आवश्यकता थी, की बहुत बड़ी खरीद का प्रबन्ध किया। रुपये के अवमूल्यन तथा उसके फलस्वरूप वैदेशिक विनिमय को सुरक्षित रखने की आवश्यकता के कारण खरीद को देश की फर्मों द्वारा अधिकृत स्टोर्स तथा सुलभ मुद्रा क्षेत्र में प्राप्त होने वाले सामानों तक ही सीमित करना पड़ा। सरकारी विभागों द्वारा उत्पादित सामानों के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाता रहा।

स्टोर की खरीद

गवर्नमेंट सीमेन्ट फैक्टरी के लिए यूनाइटेड किंगडम से मंगाए गये कुल कल-गुर्जों में से लगभग दो-तिहाई कल-गुर्जा प्राप्त हो चुके हैं और वर्ष समाप्त होने पर इस फैक्टरी को खड़ा कर देने का प्रबन्ध किया जा रहा था। इस स्थल पर सिविल इंजिनियरिंग निर्माण-कार्य, जिसका तखमीना लगभग ६० लाख रुपया लगाया गया था, किया जा रहा था, किन्तु अनुसूची में दिये गये कार्यक्रम के अनुसार निर्माण कार्य आगे न बढ़ाया जा सका, क्योंकि सरकारी सीमेन्ट परामर्शदाता, श्री शिथार को, जो कि इस योजना के लिए सिविल इंजीनियरिंग के खाके बनाने का कार्य करते थे, मृत्यु हो गई थी और एक ठेकेदार निर्माण-कार्य को कार्यक्रम के अनुसार पूरा न कर सका। इस ठेकेदार का ठेका भी समाप्त कर देना पड़ा।

गवर्नमेंट सीमेन्ट फैक्टरी, निजापुर

वर्ष भर पत्थर का चूना खोदने का काम मजदूरों ने अपने हाथ से किया और कच्चे सामान का स्टोक एकत्र किया गया।

चुनार से राबर्ट्सगंज तक जिस रेलवे लाइन को बनाने का प्रस्ताव किया गया था उस पर काम हो रहा था और दिसम्बर, १९५३ ई० तक इस काम को पूरा करने का निश्चय किया गया। रेलवे लाइन बनाने का कार्य समाप्त होते ही यह आशा की जाती है कि इस फैक्टरी में काम होने लग जायगा। यह आशा की जाती है कि १९५४ ई० के मध्य तक, जबकि फैक्टरी में उत्पादन प्रारम्भ होने का अनुसूची में उल्लेख किया गया है, फैक्टरी की इमारतें तैयार हो जायंगी और मशीनें ठीक से लगा दी जायंगी।

गवर्नमेंट प्रिंसीजन इन्स्ट्रुमेंट्स फैक्टरी में वाटर-मीटर तैयार करने का कार्य होता रहा। वर्ष के अन्त में २,००० से भी अधिक मीटर बिक्री के लिए तैयार थे और लगभग इन्ने ही मीटरों के जोड़े जाने का काम किया जा रहा था। तथापि वाटर-मीटरों की बिक्री साधारण हुई। केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों को वाटर-मीटर सप्लाई करने के लिए भारत सरकार ने इस फैक्टरी को निश्चित दरों पर ठेका दिया।

गवर्नमेंट प्रिंसीजन इन्स्ट्रुमेंट्स फैक्टरी, लखनऊ

इस फैक्टरी में १०० स्थानीय रेडियो-सेटों के भी जोड़ने का काम किया गया और अणुवीक्षण यंत्रों (microscopes) को तैयार करने के संबंध में प्रयोग जारी रखे गये।

कुल ६,८२,८०० रुपये व्यय हुए। इसमें वह धनराशि भी सम्मिलित है, जो यंत्रों को मोल लेने में और भवन-निर्माण के संबंध में व्यय हुई।

नवम्बर-दिसम्बर, १९५१ ई० में तीन कला विशेषज्ञ (टेकनीशियन्स) उनके साथ किये गये ठेके की अवधि समाप्त होने पर नौकरी से पृथक् किये गये । शेष तीन जर्मन कला विशेषज्ञों की नियुक्ति की अवधि २८ फरवरी, १९५३ ई० तक के लिए बढ़ा दी गई ।

पिछले वर्ष की भांति गवर्नमेंट वर्कशॉप, रुड़की की मुख्य कार्यवाही सारदा हाइडल डिवाजन के लिए ६६ के० बी० ट्रांसमिशन मीनारों का निर्माण करना था, जिसका ठेका १९४९ ई० में ७,५०,००० रु० की लागत पर लिया गया था । ११ के० बी० टावर के निर्माण के लिए एक नये ठेके का प्रश्न विचाराधीन था ।

इस वर्कशॉप में ईस्ट पंजाब रेलवे का, जो अब नार्दन रेलवे कहलाती है, और सरकार के विभिन्न विभागों का काम काफी मात्रा में हुआ ।

३३—खान और पत्थर की खानें

देहरादून का चूने का पत्थर मुख्य खनिज या धातु (मेजर मिनरल) मानी जाय या साधारण धातु (माइनर मिनरल), इस प्रश्न पर इस वर्ष भारत सरकार का निर्णय प्राप्त हुआ । यह निर्णय किया गया कि यह चूने का पत्थर मुख्य खनिज पदार्थ समझा जाय ताकि मिनरल कन्शेन्स रूल्स, १९४९ ई० में निर्धारित शर्तों और उपबन्धों के अनुसार दिये जाने वाले खान खोदने के पट्टों के अधीन इन खनिज पदार्थों का उपयोग हो सके । इसी बीच अस्थायी अनुज्ञा पत्रों (परमिट्स) के आधार पर, जो अनुभवी खान खोदने वालों को दिये गये, देहरादून की चूने की खानों से चूना निकालने का काम इस उद्देश्य से होता रहा कि चीनी और कागज की मिलों को लगातार इसकी सप्लाई हो सके ।

३४—श्रम

कामबंदी,
हड़तालें,
तालाबन्दियाँ
इत्यादि

जिन विभिन्न कारणों अर्थात् उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल न मिलने, तैयार माल (स्टॉक) के इकट्ठा हो जाने, वित्तीय कठिनाइयों और बहुत सी दशाओं में मशीनों के बिगड़ जाने तथा बराबर बिजली न मिल पाने से पिछले वर्ष व्यापार की जो मंदी रही थी, वही पूरे १९५१ ई० में भी बनी रही । पिछले वर्षों की तरह बहुत से उद्योगों में कामबंदी, तालाबन्दियों, छटनी, हड़तालें तथा बैठकियों का कारण एक बड़ी हद तक यही सब बाते थी । ८१ बार कारखाने बंद रहे और ७७१ बैठकियाँ हुईं, जिनके कारण क्रमशः ८,५४९ और १,३७,४५५ मजदूर बेकार हो गये । इस वर्ष छटनी के कारण २,५७३ मजदूर काम से हटा दिये गये ।

राज्य की तेल की मिलें तैयार किये गये माल के इकट्ठा हो जाने तथा कच्चे ताल की सप्लाई में कठिनाई होने के कारण बहुत दिनों तक बंद रहीं । मजदूर नेताओं के एक दल के द्वारा चीनी उद्योग में हड़ताल कराने का आयोजन किया गया, किन्तु स्थिति को सम्भालने के लिये तात्कालिक कार्रवाई की गई जिससे हड़ताल असफल हो गई । एक सप्ताह के भीतर ही चीनी की मिलों में फिर से साधारण रूप से काम होने लगा ।

इस वर्ष कुल १०५ हड़तालें हुईं, जिनमें ७४,४६२ मजदूरों ने भाग लिया और कुल ३,०५,७९२ काम के दिनों का हर्ज हुआ, जबकि पिछले वर्ष ६० हड़तालें हुईं थीं, जिनमें ४६,४८९ मजदूरों ने भाग लिया था और २,२९,१४९ काम के दिनों का हर्ज हुआ था । हड़तालों की संख्या में वृद्धि चीनी की मिलों और स्थानीय निकायों के कारखानों की हड़तालों के कारण हुई है ।

ट्रेड यूनियन

उत्तर प्रदेश के डिप्टी लेबर कमिश्नर इंडियन ट्रेड यूनियन्स ऐक्ट के अधीन ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार की हैसियत से काम करते रहे । १०१

यूनियनों की रजिस्ट्री रद्द कर दी गई और १०६ नई यूनियनों की रजिस्ट्री की गई। ३१ मार्च, १९५१ ई० को रजिस्ट्री की गई यूनियनों की कुल संख्या ५५८ थी, जबकि ३१ मार्च, १९५० ई० को ५५३ थी।

कर्मकरो या उनकी यूनियनों से प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या २,४३० थी, जबकि १९५० ई० में २,४०८ थी। शिकायतें

इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स (अपिलेट ट्रिब्यूनल) ऐक्ट, १९५० ई० के प्रचलित होने और उसके अधीन भारत सरकार द्वारा लेबर अपिलेट ट्रिब्यूनल आफ इंडिया के निर्माण के फलस्वरूप राज्य सरकार ने १५ मार्च, १९५१ ई० के आदेश द्वारा अपनी समझौता तथा निर्णयन संस्थाओं का पुनर्संगठन किया। प्रादेशिक समझौता बोर्डों (रीजनल कंसीलियेशन बोर्ड्स) के स्थान पर समझौता बोर्ड (कंसीलियेशन बोर्ड) बन गया और औद्योगिक न्यायालयों के स्थान पर इलाहाबाद में एक औद्योगिक ट्रिब्यूनल बन गया, जिसका काम बड़े बड़े झगड़ों का फैसला करना था। इनके बन जान पर समझौता बोर्डों के पास १,९५० मामले और औद्योगिक ट्रिब्यूनल के पास १९ मामले भेज गये, जिनमें से उन्होंने ने क्रमशः १,५८६ और १३ मामलों का फैसला किया।

समझौता
तथा निर्णयन
(Adjudication) संस्था

उत्तर प्रदेश में काम करने वाले ३३ स्थायी श्रम-कल्याण केन्द्रों के अतिरिक्त इस वर्ष शक्कर के उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की भलाई के लिये चार मौसमी केन्द्र खोले गये और चाय के खेतों में काम करने वाले मजदूरों के फायदे के लिये सेन्ट्रल टी बोर्ड के १०,००० रुपये के एक अनुदान की सहायता से देहरादून में तीन नये केन्द्र खोले गये।

श्रम-कल्याण

ये केन्द्र कर्मकरों और उनके कुटुम्ब वालों को चिकित्सा सहायता तथा आमोद-प्रमोद और शिक्षा संबंधी सुविधायें मुफ्त देते रहे।

कानपुर में क्षयरोग का एक विज्ञानिक, जिसमें १०० एम० ई० एक्सरे के प्लांट तथा अन्य सज्जा की व्यवस्था थी, एक पी० एम० एस० द्वितीय अफसर के अधीन कार्य करता रहा।

मिनिसम वेजेज ऐक्ट, १९४८ ई० के अधीन इस अधिनियम की अनुसूची के भाग १ में वर्णित कारबारों के संबंध में मजदूरियों की न्यूनतम दरे नियत करने के प्रस्ताव प्रकाशित किये गये थे। उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विक्रय निधि विधेयक, जो १९५० ई० में पारित किया गया था, अधिनियम बन गया और प्रचलित किया गया। इस अधिनियम के अधीन एक हाउसिंग बोर्ड और परामर्शदात्री समिति बनाई गई और कर्मकरों के लिये क्वार्टरों के निर्माण की योजना में भाग लेने वाले ६७ शक्कर के कारखानों को उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि से ३९ लाख रुपये की एक धनराशि नियत की गई। यह निश्चय किया गया कि इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये यथासंभव सभी सुविधायें दी जायें। भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित एप्लाइज प्राविडेंट फंड्स आडिनेन्स, १९५१ ई० को चलाने के उद्देश्य से जांच की गई। सबसे पहिले कानपुर क्षेत्र में एम्प्लाइज स्टेट इश्योरेन्स ऐक्ट, १९४८ ई० को प्रचलित करने के लिये प्रारम्भिक कर्तव्य-वाहियों की गई। भारत सरकार के प्लान्टेशन्स लेबर ऐक्ट, १९५१ ई० के संबंध में जांच-पड़ताल का काम भी आरम्भ किया गया। एम्प्लायमेंट एक्सचेंजों के द्वारा छटनी किये गये तथा आकस्मिक रूप से काम करने वाले कर्मकरो की रजिस्ट्री तथा उनकी कानपुर के कपड़े और चमड़े

श्रम संबंधी
अन्य कार्य-
वाहियाँ

के कारखानों में लगाने की जो मूल योजना १९५० ई० में कानपुर में आरम्भ की गई थी वह जारी रखी गई ।

जांच-पड़ताल

जून, १९५१ ई० के अंत तक झांसी, गाजियाबाद और इलाहाबाद में पारिवारिक आय-व्ययक के संबंध में जांच-पड़ताल पूरी कर ली गई थी । कानपुर के जूही क्षेत्र में उद्योगों में काम करने वालों के द्वारा दिये जाने वाले मकानों के बड़े हुये किराये के संबंध में इस वर्ष जांच-पड़ताल की व्यवस्था की गई और नगर के भालटोली क्षेत्र में कर्मकरों के अहातों का भी निरीक्षण किया गया ।

उद्योगों में काम करने वालों में शराबखोरी की प्रवृत्ति या न्यूनाधिकता के संबंध में भी जांच की गई ।

कृषि के कारबार के संबंध में (मिनिमम वेजेज ऐक्ट, १९४८ ई० के अधीन) मजदूरों की न्यूनतम दरें नियत करने के लिये जांच-पड़ताल करने तथा उस संबंध में सरकार को सलाह देने के लिये परामर्शदात्री समिति सरकार ने बनायी । उसने भी इस वर्ष जांच-पड़ताल किया ।

आंकड़े तथा अनुसंधान

सूदा की भाति लेबर कमिशनर के कार्यालय के आंकड़ा उपविभाग ने रहन-सहन व्यय संबंधी आंकड़ों, फुटकर मूल्य, औद्योगिक झगड़ों, दुर्घटनाओं, श्रम-कल्याण, अनुपस्थिति का शिकायतों, इत्यादि के संबंध में आंकड़े एकत्र किये और संकलित किये । जांच करने वाले अमले का विकेन्द्रीकरण हो गया और कानपुर रीजन को छोड़ कर, जहां कि दो जांच करने वाले रहे गये, प्रत्येक रीजन में एक जांच करने वाला रख दिया गया ।

अनुसंधान उपविभाग महत्वपूर्ण विषयों पर टिप्पणियां और स्मृति-पत्र तैयार करता रहा और रोगी तथा सरकारी और निजी संगठनों के लिये सूचनाये एकत्रित करके उन्हें देता रहा ।

कारखानों, व्यायलर्स इत्यादि का निरीक्षण

वर्ष के उत्तरार्द्ध में फैक्टरी निरीक्षकों (फैक्टरीज इंस्पेक्टोरेट) में पांच और निरीक्षकों (इंस्पेक्टरों) की नियुक्ति की गई । फैक्टरीज ऐक्ट, एम्प्लायमेंट आफ चिल्ड्रेन ऐक्ट, पेमेंट आफ वेजज ऐक्ट, यू० पी०, मैटरनिटी बेनिफिट ऐक्ट के अधीन निरीक्षकों ने कुल ४,३८९ निरीक्षण किये । इस वर्ष कुल ५,९९९ दुर्घटनाये हुईं, जिनमें से २९ घातक सिद्ध हुईं, जबकि १९५० ई० में ७,११३ घटनाये हुईं, जिनमें से ३४ घातक सिद्ध हुईं ।

इस वर्ष इंस्पेक्टोरेट को भवन निर्माण की स्वीकृति के लिये ७१७ नक्शे प्राप्त हुये, जबकि पिछले वर्ष ३७४ नक्शे प्राप्त हुये थे । इनमें से ४९ कैन्टीन, विश्राम कमरों तथा सायबानों के लिये थे । शेष कारखानों की इमारतों के संबंधमें थे ।

व्यायलर्स निरीक्षकों (इंस्पेक्टोरेट) ने २,३९५ निरीक्षण किये, जिनमें से ८३२ जल-बिजली के (हाइड्रोलिक) और ३३ भाग संबंधी परीक्षण (स्टीम टेस्ट्स) थे ।

३० वीं शाप्स एंड कर्मशायल इस्टेब्लिशमेंट्स ऐक्ट, १९४७ ई० लखनऊ, मुरादाबाद और झांसी के रेलवे नोटिफाइड एरियाओं में प्रचलित किया गया । इस अधिनियम के अधीन डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर और पूरे समय वाले १३ निरीक्षकों (इंस्पेक्टरों) ने कुल ३९,९१५ मुआयने किये, जबकि १९५० ई० में ३६,८७४ मुआयने किये गये थे ।

यू० पी० फैक्टरीज क्लस, १९५० ई० के लागू होने के बाद कारखानों को लाइसेंस देने और उनकी रजिस्ट्री करने के संबंध में उपबंध १ अप्रैल १९५१ ई० से प्रचलित किये गये। इस वर्ष कुल १,०४० कारखानों को लाइसेंस दिये गये। इनमें से ८६ कारखानों की हाल ही में रजिस्ट्री की गई।

उत्तर प्रदेश के श्रम कमिशनर इंडस्ट्रियल एम्प्लायमेंट (स्टैंडिंग आर्डर्स) स्थायी आदेश ऐक्ट, १९४६ ई० के अन्तर्गत प्रमाणित करने वाले अधिकारी (Certifying Officer) के पद पर बने रहे। पहली जनवरी को ऐसी औद्योगिक स्थापनाओं की संख्या ४१२ थी जिनके संबंध में स्थायी आदेश प्रमाणित किये जा चुके थे (इनमें ३८ शक्कर के कारखाने थे जिनके संबंध में यू० पी० इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ ई० के अधीन स्थायी आदेश बाद में प्रचलित किये गये थे)। वर्ष के अन्त में ऐसी स्थापनाओं की संख्या ५०६ थी।

श्रम कमिशनर के कार्यालय का प्रकाशन उप-विभाग अंग्रेजी में मासिक प्रकाशन "लेबर बुलेटिन" और हिन्दी में "साप्ताहिक श्रमजीवी" प्रकाशित करता रहा और समझौता तथा निर्णयन संस्था और श्रम विभाग की महत्वपूर्ण प्रगति तथा कार्यवाहियों के प्रचार का कार्य जारी रखा गया।

३५—सहकारी आन्दोलन

१९५०-५१ (जुलाई, १९५०-जून, १९५१) के सहकारी कार्य के वर्ष में मुख्यतः उस प्रगति को स्थिर करने की कार्यवाहियाँ की गईं, जो पिछले वर्षों में सहकारिता के क्षेत्र में प्राप्त हुई थीं। १९४७ ई० से अनुसरण की गई नीति के अनुसार सहकारी संस्थाओं ने मेम्बरो की न केवल ऋण संबंधी आवश्यकताओं की ओर ही ध्यान दिया, बल्कि उनके अर्थिक जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर ध्यान दिया। सब बातों को देखते हुये सहकारी समितियों की वित्तीय स्थिति बहुत संतोषजनक थी और उनका 'ग्रोन्ड' कैपिटल उनके कुल 'वर्किंग' कैपिटल के एक-तिहाई से अधिक था।

आलोच्य वर्ष के अन्त में राज्य में सभी प्रकार की ३५,००० वित्तीय स्थिति सहकारी संस्थाएँ थीं और इनके २८ लाख मेम्बर थे। इनमें यू० पी० कोऑपरेटिव बैंक, यू० पी० कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एन्ड मार्केटिंग फेडरेशन, यू० पी० केन यूनियन्स फेडरेशन, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एन्ड बैंकिंग यूनियन्स, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फेडरेशन्स, डेवलपमेंट एन्ड मार्केटिंग यूनियन्स, केन यूनियन्स, एग्रिकल्चरल मल्टीपरपज एन्ड अवर क्रेडिट सोसाइटीज, नान-एग्रिकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, कन्जूमर्स सोसाइटीज, घी सोसाइटीज, टेक्सटाइल सोसाइटीज, कन्सासिडेशन ऑफ होल्डिंग्स सोसाइटीज, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज, लैन्ड कालोनाइजेशन सोसाइटीज और हार्जसिंग सोसाइटीज सम्मिलित हैं।

समितियों का 'वर्किंग' कैपिटल लगभग २३ करोड़ रुपये था, जबकि पिछले वर्ष १८ करोड़ रुपये था और 'ग्रोन्ड' कैपिटल ७.८२ करोड़ रुपये था। मेम्बरो द्वारा भुगतान किया गया 'शेयर' कैपिटल चार करोड़ रुपये था और सुरक्षित तथा अन्य कोष ३.५ करोड़ रुपये से अधिक था।

राज्य में महत्वपूर्ण सहकारी समितियों की वित्तीय स्थिति इस प्रकार थी:-
(रुपये लाखों में दिये गये हैं)

समितियाँ	समितियों की संख्या	सदस्यो की संख्या	वर्किंग कैपिटल	ओव्ड कैपिटल	ग्रेयर कैपिटल	मुनाफा
यू० पी० कोआपरेटिव बैंक	१	६२७	३२९.११	४०.०९	३१.६५	१.९७
यू० पी० डेवलपमेंट एन्ड मार्केटिंग फेडरेशन	१	८०	४४५.६३	६२.५७	२.३१	१.१७
यू० पी० केन, यूनियन्स फेडरेशन	१	१०१	२.५९	१.६४	१.६६	१.६६
कोआपरेटिव बैंक्स एन्ड बैंकिंग यूनियन्स	६६	२४,५७५	३०२.२५	८०.५४	४९.३६	४.७१
एग्रिकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज (जिनमें बहुधनी, सम्मितिया सम्मिलित हैं)	२६,३९०	८,५०,२९२	३८४.९४	२१४.६७	१३०.२९	१३.७९
डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फेडरेशन्स	५०	२६,५३७	१००.९१	३४.९१	१५.६५	१७.०५
डेवलपमेंट एन्ड मार्केटिंग फेडरेशन्स	१,५९७	१,५७,८८५	१२८.८७	६९.७५	५०.२५	२२.७३
मिलक यूनियन्स	६	३६८	१०.७८	५.१८	४.४	०.८
केन यूनियन्स	१०५	११,७१,४३७	२२३.३२	१३६.७३	४२.२०	१४.५२
नान-एग्रिकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज	६४९	८१,५६४	११७.३८	५०.८३	३७.२३	२.४८
कंजमर्स सोसाइटीज	५०८	३,०१,५३०	९६.६५	४१.२३	२८.०७	१३.०८
टैक्सटाइल्स यूनियन्स	३९	१०,४२९	२३.२०	११.३६	४.६२	१.५३
टैक्सटाइल सोसाइटीज	५८१	६९,१३८	१३.२४	९.९०	७.२७	५.६
हाउसिंग सोसाइटीज	१६७	१०,७९७	३४.११	११.४६	१०.८५	५.६
लन्ड कालोनाइजेशन सोसाइटीज	६७	३,८६२	३६.७३	७.७२	७.०	३.२

सहकारी सस्थाओं ने इस वर्ष कुल लगभग २६ करोड़ रुपये कर्ज दिये और वर्ष के अन्त में ऋण के लिये लगभग १३ करोड़ रुपये रह गया था, जबकि पिछले वर्ष यह धनराशि क्रमशः १८ १/२ करोड़ रुपये और ६ करोड़ रुपये थी। ऋणों के विवरण, जिनका अधिक भाग उत्पादन के प्रयोजन के लिये दिया गया था, और ऋणों के विवरण, जो वसूल नहीं हुये थे, नीचे दिये जाते हैं—

सहकारिता
के आधार
पर ऋण

ऋण जो वर्ष के अन्त
तक वसूल नहीं
हुये थे

	रु० (लाखों में)	रु० (लाखों में)
यू० पी० कोऑपरेटिव बैंक ..	८७८.४६	१६०.६५
सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक और बैंकिंग यूनियन्स ..	३१४.४५	१६०.६७
एप्रिकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज ..	२२८.२५	२६२.८६
नान-एप्रिकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज ..	५४.७१	६७.७०
अन्य कर्ज न देने वाली समितियाँ—		
(क) सेन्ट्रल ..	१,१३६.२६	३८३.६७
(ख) एप्रिकल्चरल प्राइमरी ..	३०.२५	४१.६६
(ग) नान-एप्रिकल्चरल प्राइमरी ..	६.४४	६.७५
केन यूनियन्स ..	२३३.०८	१३६.००
योग ..	२,३८४.६०	१,२८६.२६

सहकारी उपभोक्ता समितियाँ, यू० पी० क्रय-विक्रय संघ, जिला सहकारी विकास संघों, विकास तथा क्रय-विक्रय यूनियनों और कर्ज देने वाली बहुत सी समितियों ने नियंत्रित वस्तुओं के वितरण करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। यू० पी० क्रय-विक्रय संघ (U P. Marketing Federation) ३२ जिलों में मिल के बने कपड़ों के थोक व्यापारी के रूप में काम करता रहा और उसने मोटे तौर पर राज्य के लिये नियत कींटे का एक-तिहाई भाग आयात किया। संघ ने लगभग ६ १/२ करोड़ रुपये के मूल्य के कपड़े खरीदे और लगभग ४ करोड़ रुपये की बिक्री की। संघ ने जिला विकास संघों की बिक्री के लिये २ १/२ करोड़ रुपये से अधिक का स्टॉक दिया। जिला विकास संघों और विकास तथा क्रय-विक्रय यूनियनों ने क्रमशः ८ करोड़ और ४ करोड़ रुपये के मूल्य के कपड़े, शक्कर, नमक, मिट्टी का तेल, सीमेंट, सूत, रासायनिक खाद, बिस्किट के सामान इत्यादि बाँटे। पिछले वर्ष के ये आँकड़े क्रमशः ४ करोड़ और ६ करोड़ रुपये थे। बहुवर्षी सहकारी समितियों ने ३०.५ लाख रुपये मूल्य

आवश्यक
वस्तुओं का
वितरण

की आवश्यक वस्तुएं बेचीं। सहकारी उपभोक्ता समितियों ने ग्रामीण क्षेत्रों को १,७०० राशन की दूकानों में काम किया और १० लाख कार्ड-गृहीताओं को नियंत्रित खाद्यान्न बेचा। उनकी मासिक बिक्री का औसत १ १/२ करोड़ रुपया था।

बीज,, खाद
इत्यादि की
सप्लाई

सहकारी समितियों द्वारा चालित बीज-गोदामों की संख्या ६५५ थी। इनमें वे ५६७ गोदाम भी सम्मिलित हैं, जो कृषि विभाग ने १९४८ ई० में हस्तांतरित किया था। १९५०-५१ में निम्नलिखित परिमाण में बीज दिये गये और वसूल किये गये :-

	खरीफ	रबी
	मन	मन
वितरण	२,२०,३५४	६,७७,५५६
सिचाई की मांग	२,७५,५६८	१२,२१,६५५
गल्ले की वसूली	२,२०,५२८	११,७०,१०६
वसूली का औसत	८०.०%	६५.८%

विशेष रूप से पूर्वी जिलों में मौसम खराब होने से खरीफ की फसल बरबाद हो जाने के बावजूद वसूली अच्छी हुई। शुद्ध बीज वितरित करने के प्रयत्न किये गये और उसमें सफलता मिली, जिसके फलस्वरूप १९४६-५० ई० में पैदा किये गये "ए" वर्ग के बीजों का लगभग २.४७ लाख मन परिमाण बढ़कर १९५०-५१ ई० में ३.७१ लाख मन हो गया।

सहकारी समितियों ने ६,८३३ खेती के औजारों के अतिरिक्त १०,८५० मन से अधिक खली, ११,०१४ मन सनई और ४,७७२.६१ टन खाद वितरित किया। समितियों के मेम्बरों ने १० लाख मन से अधिक मिलवा खाद तैयार किया और उसे अपने-अपने खेतों में छोड़ा।

सिचाई की
सुविधायें

सहकारी समितियों ने मेरठ जिला में चालीस ट्यूबवेल बनावाये और लगभग ५०,००० एकड़ नयी भूमि में सिचाई करने में सहायता प्रदान की। इटावा जिला में तीन नये ट्यूब-वेल बनाये गये। मुरादाबाद और बदायूँ जिलों में सहकारी समितियों ने १० ट्यूब-वेलों से पानी वितरित करने का काम आरम्भ किया। आलोच्य वर्ष में कुल लगभग २,००० पक्के कुएं, १५० बांधियाँ और १५० तालाब बनाये गये।

दूध और
दूध से इनी
अन्य वस्तुओं
की सप्लाई

लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, मेरठ और हलद्वानी में काम करने वाली दूध यूनियनों ने लगभग १.२६ लाख मन दूध का काम किया, जबकि १९४६-५० में यह मात्रा १.०२ लाख मन थी। शहर के ग्राहकों को दूध की सप्लाई की मात्रा लगभग ७५,००० मन से बढ़कर १,०६,००० मन हो गई। गांव की उन समितियों की संख्या, जो यूनियनों को दूध सप्लाई करती थीं, १९४६-५० की ३०० से बढ़कर १९५०-५१ में ३८४ हो गई। लखनऊ यूनियन के पास एक पैस्चुराइजिंग प्लांट था जो इलाहाबाद और बनारस यूनियनों के अहाता में दो और प्लांट लगाने लिये राज्य सरकार ने यूनियनों को वित्तीय सहायता दी। दूध यूनियनों को १९५०-५१ में १.२२ लाख रुपये के आवर्तक अनुदान स्वीकृत हुए थे, जबकि १९४६-५० में ३.३७ लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे। उन्नत प्रकार

द्वारा पशुओं की खरीद के लिये १-५० लाख रुपये बेसुदी तकावी के रूप में भी स्वीकृत किया गया।

घी-विक्रय समितियों और यूनियनों ने लगभग एक दर्जन जिलों में काम किया। उन्होंने लगभग ११ लाख रुपये के मूल्य के घी का काम किया, जबकि पिछले वर्ष यह धनराशि ६ लाख रुपये थी।

उत्तर प्रदेश में सहकारी आधार पर क्रय-विक्रय के कार्यों में ईख के क्रय-विक्रय का कार्य ठीक रहा। उन समितियों ने, जो कोन कमिश्नर के प्रशासकीय नियन्त्रण में रहें, आलोच्य वर्ष में २५ १/२ करोड़ रुपये से अधिक की १४ १/२ करोड़ मन ईख शहकर के कारखानों को दिया। सप्लाई पर कमीशन से इन समितियों को कुल ६० लाख रुपये की आय हुई।

पहिले की तरह करधा उद्योग, चमड़े के काम और चपड़ा बनाने के कुछ महत्वपूर्ण उद्योग सहकारी आधार पर चलाये जाते रहे। आलोच्य वर्ष में औद्योगिक सहकारी समितियों का कार्य वर्ष भर आमतौर पर सन्तोषजनक रहा।

लाख विकास का कार्य मुख्यतः दूधो (जिला मिर्जापुर) क्षेत्र में ही होता रहा। वह अस्थायी प्रबन्ध, जिसके अन्तर्गत विधमगंज शैलाक फेक्टरी का प्रबन्ध और लाख एकत्र करने का काम सहकारी समितियों और एक सहकारी यूनियन के बनते तक यू० पी० मार्केटिंग फडरेशन न अपने हाथ में ले लिया था, जारी रहा।

१९५०-५१ में मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर और फतेहपुर जिलों में चक्रबन्दी का काम आरम्भ किया गया और ४३,००० भूखंडों वाली १६,५३७ एकड़ भूमि की ३,००० चक़ों में चक्रबन्दी की गई। सहकारी समितियों द्वारा जिस कुल क्षेत्र की चक्रबन्दी की गई वह ३० जून, १९५१ ई० को १.६७ लाख एकड़ था। बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर जिलों में जोतों की चक्रबन्दी का काम विशेषरूप से हुआ।

१७ जिलों में काम करने वाली सहकारिता के आधार पर खेती करने वाली ३२ समितियाँ अब भी प्रयोगात्मक अवस्था में थीं, परन्तु उन्हें काफी प्रोत्साहन मिला। यह आशा की जाती थी कि निकट भविष्य में और अधिक भूमि में सहकारिता के आधार पर खेती की जा सकेगी।

३० जून, १९५१ ई० को ६७ भूमि उपनिवेश समितियाँ थीं और उनके ३,८६२ मेम्बर थे। इनमें से ३४ में विस्थापित व्यक्ति १४ में भूतपूर्व सैनिक और १६ में राजनैतिक पीड़ित थे। प्रत्येक समिति के संगठन कार्य के लिए एक ऐसे गाँव को मूल यूनिट बनाया गया था, जिसमें १,००० से १,५०० तक एकड़ नई भूमि तोड़ी गई हो और जो बलाकों में नये बसने वालों के परिवारों को दी गई हो। बसने वालों ने व्यक्तिगत रूप से अपने-अपने भूखंडों में खेती की, परन्तु यह आशा की जाती थी कि अन्ततः खेती का कुल काम सहकारिता के आधार पर किया जायगा। आलोच्य वर्ष में सहकारी समितियों का काम यह था कि वह मेम्बरों को ऋण दें, उनकी बाँज, खाद और खेती के औजार सप्लाई करें और उनकी पदावार की उचित बिक्री के लिये प्रबन्ध करें। १९५०-५१ में मेम्बरों को १४ लाख रुपये ऋण दिए गए और व के अन्त में कुल २७ लाख रुपये वसूल नहीं हुआ था।

फेक्टरियों की ईख की सप्लाई

औद्योगिक सहकारी समितियाँ

लाख की खेती

जोतों की चक्रबन्दी

सहकारिता के आधार पर खेती

उपनिवेश समितियाँ

भवन निर्माण

भवन निर्माण सहकारी समितियों की संख्या १६७ थी और उनके कुल मेम्बरों की संख्या १०,८०० थी। समितियों ने आमतौर पर मकानों के बनाने में वित्तीय सहायता दी और भूमि प्राप्त करने, नक्शा बनाने और भवन निर्माण सामग्री भी प्राप्त करने में सहायता दी। लगभग १५४ एकड़ भूमि प्राप्त की गई और इन समितियों के द्वारा लगभग ४०० मकान बनाये गये। इतनी कम संख्या में मकान इसलिये बन सके कि भवन निर्माण सामग्री के मूल्य बढे हुए थे और उपयुक्त स्थान तथा भवन निर्माण सामग्री मिलने में कठिनाई थी और सस्ते दरों पर अधिक दिनों के लिये ऋण नहीं मिलता था। भवन निर्माण सहकारी समितियों ने १९५०-५१ में ५ लाख रुपया ऋण दिया और वर्ष के अन्त में ६.५६ लाख रुपया वसूल नहीं हुआ था।

**विशेष कार्य-
वाहियाँ**

अपनी साधारण कार्यवाहियों के अतिरिक्त यू० पी० मार्केटिंग फेडरेशन ने ५४ ट्रक अपने पास इसलिये रक्खे कि राज्य की सहकारी समितियों को उनके समान लाने-लेजाने में सहायता मिल सके। फेडरेशन की अन्य विशेष कार्य-वाहियों में हिन्दी टाइपराइटरों की बिक्री करना, शिकोहाबाद में घी के वर्गीकरण वाले स्टेशन का प्रबन्ध और जड़ी-बूटियों के विकास तथा उनकी क्रय-विक्रय सम्बन्धी कार्यवाहियाँ सम्मिलित थी। आलोच्य वर्ष में फेडरेशन ने ३५,८१७ रुपया का घी बेचा और शिकोहाबाद के घी ग्रेडिंग स्टेशन ने १०,५७० मन घी का वर्गीकरण किया और उसकी २३,३२५ रुपया फीस ली। अम्नोड़ और ननीताल जिलों में जड़ी-बूटियाँ और जंगल की अन्य पैदावार एकत्र करने का कार्य जारी रहा और आलोच्य वर्ष में १०,००० रुपये की जड़ी-बूटियाँ बेची गईं। फेडरेशन राज्य के २३ जिलों के लिये नाहान फाउन्ड्री (पूर्वी पंजाब) का सोल एजेंट हो गया। शेष जिलों के लिये फेडरेशन ने फाउन्ड्री के एजेंट के रूप में कार्य किया।

३६—गन्ना विकास

गन्ने की फसल अच्छी हुई और उत्तर प्रदेश में गन्ने के अत्यधिक विकास की पंचवर्षीय योजना में, जिसका अभी तीसरा वर्ष चल रहा था, और अधिक प्रगति हुई। इस कार्य का सम्पादन ३८ समितियों द्वारा किया गया, जिनके केन्द्र चीनी मिलों के बहिर्द्वार पर स्थित थे। प्रत्येक समिति का कार्यक्षेत्र, जो प्रारम्भ में २,००० एकड़ था और बाद में धीरे-धीरे बढाया गया था, आलोच्य वर्ष के अन्त तक ४,००० एकड़ हो गया था। इस वर्ष ३० लाख मन उन्नत, अधिक उत्पादक और रोगमुक्त किस्मों के गन्ने के बीज का वितरण किया गया और सिंचाई की सुविधाएँ और अधिक बढा दी गयीं। १,००० से अधिक कुएँ खोदे गये और २७१ कुएँ गलाये गये। इसके अतिरिक्त १५० तालाब खोदे गये या अधिक गहरे किये गये, ११३ पंपिंग प्लांट स्थापित किये गये। पक्के कुओं के लिये २२० वाटर-लिफ्टों की व्यवस्था की गई और लगभग ६४२ मील गूलों की सफाई की गई। हरी खाद के लिये ५,३५४ मन सनई के बीज के अतिरिक्त ३५,२२४ मन खली, १,७९,६२१ मन उर्वरक और २,२५,४५९ मन मिश्रित उर्वरक गन्ने की काश्त करने वालों को बाटा गया। लगभग ४,६३२ लाख मन देहाती मिलवा खाद, ९.४० लाख मन मिल वाली मिलवा खाद भी तैयार की गई। पैदावार बढाने के उद्देश्य से खेती के उन्नत ढंगों का प्रदर्शन करने के प्रयोजन से किसानों के खेतों में १३,९७२ अर्द्ध-क्षेत्रीय प्रदर्शनों का प्रबन्ध किया गया।

वर्षा के ठीक से न होने तथा कई स्थानों में सूखा पडने के कारण बीमारियों का जोर अपेक्षाकृत अधिक रहा। २३,४३३ एकड़ के क्षेत्रफल में रेड राट

(red rot), पाइरिला, कंडआ (smut), बिल्ट और स्टैम्बोरर की बीमारियों का जोर था, किन्तु रासायनिक प्रक्रिया द्वारा निकाई करके झाड़-पतवार साफ करके और ५ प्रतिशत गमेक्सीन (gammexyne) छिड़क करके २२,२३८ एकड़ भूमि पर सफलता पूर्वक रोगों की रोकथाम की गई। इन निरोधक कार्यों में लगभग १०,५६३ रु० की धनराशि व्यय की गई।

शक्कर की वसूली में भी कुछ वृद्धि हुई और वह बढ़कर ९.८१ प्रतिशत हो गई, जबकि पिछले वर्ष की वसूली ९.६३ प्रतिशत ही थी। १६.५७ करोड़ मन की कुल सप्लाई में १४.५८ करोड़ मन गन्ने की सप्लाई अर्थात् कुल परिमाण का लगभग ८८ प्रतिशत गन्ना समितियों ने की।

आलोच्य वर्ष में गन्ना सहकारी यूनियनों की संख्या इस प्रदेश में १०५ थी। इन यूनियनों का कार्य-क्षेत्र २६,८४० गांवों में ११.५४ लाख एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में था और ११,६९,९०८ व्यक्ति उनके सदस्य थे तथा १,५३७ सदस्य-समितियां थीं। १९५० ई० में उनका कार्य क्षेत्र ९.९४ लाख एकड़ (२५,८७३ गांवों) में था और ११,०५,१७३ व्यक्ति सदस्य थे तथा समिति-सदस्यों की संख्या १,४८२ थी। यूनियनों की कार्य-सम्पादन पूंजी गत वर्ष १.९५ करोड़ रु० से बढ़कर २.२३ करोड़ रु० हो गयी, जबकि सुरक्षित तथा अन्य-निधि ८९६५ लाख रु० से बढ़कर ९४५३ लाख रु० हो गई। पास की पूंजी भी १.२४ करोड़ से बढ़कर १.३७ करोड़ रु० हो गयी। वर्ष के अन्त में यूनियनों के पास चुकता की गयी अंशक पूंजी ४२.२० लाख रु० थी जो गत वर्ष की पूंजी से ७.९३ लाख रु० अधिक थी। उत्पादक प्रयोजनों के लिये सदस्यों को २.३३ करोड़ रु० का अग्र-ऋण दिया गया। २.१८ करोड़ रु० की वसूलियां हुईं। अपने सदस्यों की सामाजिक तथा आर्थिक दशा सुधारने में भी समितियों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया।

उत्तर प्रदेश गन्ना संघ, जो यूनियनों द्वारा बनाया गया था और १९४९ ई० में जिसकी रजिस्ट्री हुई थी तथा जिसने यूनियनों की कार्यवाहियों का एकीकरण करने तथा उनके कार्यों में सामंजस्य लाने में पहले ही उपयोगी कार्य किया था, सफलतापूर्वक कार्य करता रहा। वर्ष में इस संघ ने लगभग ६०.०० लाख रु० मूल्य की खाद, उर्वरक और कृषि सम्बन्धी औजारों के केन्द्रीय-कृत क्रय तथा सप्लाई का कार्य किया। इस संघ ने विभिन्न कामों, रजिस्टरों तथा अन्य कागजातों के सम्बन्ध में आत्म-निर्भरता के आधार पर सदस्य यूनियनों की आवश्यकताओं पूर्ण करने के लिये एक निजी छापाखाना की भी स्थापना की।

गन्ने का मूल्य पहले १ रु० १० आना प्रति मन के हिसाब से निर्धारित किया गया था, परन्तु गन्ने की सप्लाई में वृद्धि करने के उद्देश्य से बाद में इसे पूर्व तिथि से ही बढ़ाकर १ रु० १२ आना प्रति मन कर दिया गया। कैक्टरियों ने कुल जितने मन गन्ना पैरा था वह १९५० ई० के १४.३७ करोड़ मन की अपेक्षा आलोच्य वर्ष में बढ़कर १६.५७ करोड़ मन हो गया और उत्पादित शक्कर में भी २२.८४९ लाख मन की वृद्धि हुई।

३७—ग्राम सुधार

महिला हितकारी योजना, जो कि १९४९ ई० में पुनःसंगठित की गई तथा महिला हितकारी संचालक (Director) के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में रखी गई थी, इस राज्य के १२ जिलों में अर्थात् आजमगढ़, बहराइच, बस्ती, महिला हितकारी योजना (१) सामान्य

देवरिया, देहरादून, इटावा, फैजाबाद, गोरखपुर, हमीरपुर, लखनऊ, मथुरा और रायबरेली के लगभग १५० गावों में चालू की गई। माताओं और स्कूल जाने से पूर्व के बच्चों को उपदेश देने, (२) माताओं और नये पैदा हुए शिशुओं के कल्याण और (३) आर्थिक हित पर जोर दिया जाता रहा।

उक्त १२ जिलों में से प्रत्येक जिले के ३ से ५ तक के केन्द्रों में सकेन्द्रित प्रयत्न (concentrated efforts) उस कर्मचारिवर्ग द्वारा किये गये, जिस में प्रत्येक के लिये तीन ग्राम-सेविकाएँ—एक प्रौढ तथा पूर्व स्कूल शिक्षा तथा शारीरिक-संवर्धन में प्रशिक्षित (trained), दूसरी धात्री कार्य (midwifery) और तीसरी दस्तकारी में प्रशिक्षित थी—रखी गईं।

- (२) लखनऊ महिला हितकारी योजना के अधीन कार्य करने के लिये ग्राम-सेविकाओं में नया प्रशिक्षण केन्द्र ई० में खोला गया था। बीस ग्राम-सेविकाओं का एक समुदाय (batch) (Training Centre) एक व्यापक पाठ्यचर्या (comprehensive syllabus) के अनुसार ५ महीने की ट्रेनिंग पा रहा था जबकि वर्ष समाप्त हो गया। उनके पाठ्यक्रम (course) में दस्तकारी की ट्रेनिंग, जिससे कि माताओं और बच्चों का हित होने की संभावना है, तथा स्कूल जाने से पूर्व के बच्चों को ठीक ढंग पर रखने एवं उसे शिक्षा देने और गांव की महिलाओं का दृष्टिकोण बढ़ाने की ट्रेनिंग सम्मिलित की गई थी।

- (३) जच्चा-बच्चा सम्बन्धी प्रशिक्षण केन्द्र से, जो कि १९५० ई० में लखनऊ में स्थापित किया गया था, इस वर्ष २१ सफल उम्मीदवारों का एक समुदाय भेजा गया। वे इससे पूर्व स्वास्थ्य विभाग की ओर से संचालित सिल्वर जुबली हेल्थ स्कूल (Silver Jubilee Health School) में एक वर्ष ट्रेनिंग पा चुके थे। उन्होंने कुछ अन्य शिक्षा संस्थाओं में जिन विषयों की ट्रेनिंग प्राप्त की उनमें बच्चों के पालन-पोषण के अतिरिक्त चिकित्सा सम्बन्धी तथा जच्चा-बच्चा सम्बन्धी विषय सम्मिलित थे। स्वच्छता, स्वास्थ्य विज्ञान तथा ग्राम-सुधार से सम्बन्धित अन्य विषयों पर लेक्चर देने की व्यवस्था भी की गई थी। ट्रेनिंग पाने वालों के लिये यह आवश्यक था कि वे घरेलू कार्य (domestic work) भी करें, जिससे कि वे गांव की परिस्थितियों में काम करने के लिये अधिक उपयुक्त हो सकें। ट्रेनिंग समाप्त हो जाने पर सफल होने वाली ग्राम-सेविकाओं को साधारण रीति-रिवाज के अनुसार मेटरनिटी बाक्स (जच्चा-बच्चा के काम आने वाले बक्से) दिये गये और महिला हितकारी केन्द्रों (Women's Welfare Centres) को पास्त-पड़ोस में वितरण करने के लिये ६० प्राथमिक सहायता सम्बन्धी औषधियों की पेटियाँ फिर दी गईं, जिनमें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के छोटे-मोटे रोगों के लिये कुछ आवश्यक आयुर्वेदिक तथा एलोपैथिक दवायें थी। ट्रेनिंग पाई हुई ग्राम-सेविकाओं ने जच्चा-बच्चा सम्बन्धी मामलों को देखते समय नियमानुसार इस बात पर ज़ोर दिया कि स्थानीय दाइयाँ उनके साथ रहे, क्योंकि स्थानीय दाइयों को ट्रेनिंग देना उनके कार्यक्रम का एक भाग था।

- ४) आर्थिक हित इत्यादि गांव की महिलाओं का और अधिक आर्थिक हित करने के उद्देश्य से महिला हितकारी केन्द्रों के अधीन समुदाय केन्द्रों (Community Centres) में घरेलू दस्तकारी (Home Crafts) सिखाने का कार्य होता रहा। इनमें कताई, कूड़ाई (needle work), बुनाई (knitting), खिलौने बनाना, फल परिरक्षण (fruit preservation) तथा अन्य कुटीर उद्योग सम्मिलित थे। उद्योग विभाग द्वारा दिये गये लगभग एक सौ चरखे देहरादून जिले में चलाये जा रहे थे। पूरे तौर पर तैयार

बनाने का पारिश्रमिक (remuneration) गांव की महिलाओं को मिला। एटा जिले में यह देखा गया कि कोई भी महिला, जो कि इस काम में प्रति दिन दो घंटा समय दे, १८ से २० रु० तक मासिक कमा सकती है। कुछ उत्पादित वस्तुओं की बिक्री का प्रबन्ध सहकारी यूनियनों की देख-रेख में चलाई जाने वाली दुकानों द्वारा किया गया।

चार ग्राम-सेविकायें गर्वर्नमेंट सेन्ट्रल वीविंग इन्स्टीट्यूट, बनारस में कांच की गुरिया बनाने की ट्रेनिंग पाने के लिये भरती की गई। जिला आर्गेनाइजरो तथा ग्राम-सेविकाओं को कृषि विभाग द्वारा संचालित कक्षाओं में फल परिरक्षण (fruit preservation) तथा मुरब्बा, अचार और चटनी बनाने की भी ट्रेनिंग दी गई। महिलाओं और बच्चों में ग्राम तथा अन्तर-ग्राम प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिये सरकार ने १२ जिलों को ५०० रु० स्वीकृत किया था।

महिला हितकारी केन्द्रों के लिये यह निश्चित किया गया कि वे खाद के गड्ढे और पानी सोखने वाले गड्ढे (सोकेज पिट्स) तैयार करने, साक्षरता, दस्तकारी, पौष्टिक पदार्थ और स्वास्थ्य बढ़ाने तथा महामारी और हीनात्र रोगों (deficiency diseases) की रोक-थाम करने के लिये किस मात्रा में कार्य करें। यद्यपि ग्रामीण महिलाओं की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इस प्रकार के कार्यों में उनके भाग लेने में सामान्य रूप से बाधक रही, फिर भी जिलों से इस सम्बन्ध में उत्साह बढ़ाने वाली रिपोर्टें प्राप्त हुईं।

केवल समुदाय केन्द्र वाले गांवों में ही नहीं अति आसपास के गांवों में भी (५) प्राप्त यह देखा गया कि लोगों ने योजना के सम्बन्ध में काफी दिलचस्पी ली है और इस हुए परिणाम योजना का कार्यक्षेत्र बढ़ाने के संबंध में बहुत से लोगों की प्रार्थनाएं आईं। इसका स्पष्ट कारण इसके पूर्व प्राप्त हुए परिणाम थे। निम्नलिखित आंकड़े इस बात को प्रदर्शित करेंगे कि महिला हितकारी योजना के अन्तर्गत कितना लाभ-प्रद कार्य हुआ—

(१) महिला हितकारी केन्द्रों में ग्राम-सेविकाओं द्वारा औषधियों की पेटियों की सहायता से इलाज किये गये रोगियों की संख्या .. २२,४९७

(२) ग्राम-सेविकाओं द्वारा रोगमुक्त किये गये रोगियों की संख्या .. १२,७२४

(३) बालुबारी कक्षाओं में शिक्षा पाय हुए विद्यार्थियों की संख्या .. ६,३१३

(४) घरेलू दस्तकारी (Home Crafts) में ट्रेनिंग पाई हुई महिलाओं की संख्या .. २,३२०

(५) साक्षर बनाई गई महिलाओं की संख्या .. १,४५६

(६) जच्चा-बच्चा संबंधी जिन मामलों की देख-रेख की गई उनकी संख्या .. १९२

ग्रामीण क्षेत्रों में जिला प्लानिंग समितियों द्वारा पंचायतघरों और बीज गोदामों की इमारतें बनवाने तथा उनकी मरम्मत कराने के लिये सरकार ने ३०,००० रु० की धनराशि स्वीकृत की थी। इस अनुदान की सहायता से आलोच्य वर्ष में ३३९ पंचायतघर और ६६ बीज गोदामों का निर्माण किया गया। जिला प्लानिंग समिति, मेरठ ने ७१९ आदेश-गृह बनवाये, जवकि

इमारतों का निर्माण

मुजफ्फरनगर और शाहजहापुर ने सबसे अधिक पशुशालाओं का (क्रमशः १९९ और ६३७) निर्माण किया। आलोच्य वर्ष के आकड़े इस प्रकार हैं :—

(१) निर्माण किये गये बीज गोदामों तथा पंचायतघरों की संख्या	६६
(२) निर्माण किये गये पंचायतघरों की संख्या	.. ३३९
(३) बनाये गये आदर्शगृहों की संख्या	. १,२०१
(४) निर्माण किये गये पशुशालाओं की संख्या	.. ९४५

यातायात

यातायात सबधी कार्य बहुत कम हो गये थे और वे विकास ब्लकों में स्थित गांवों में पुलियां और गन्दे पानी के निकास की नालियां बनाने तक ही सीमित रहे। इमारती सामान की कमी होते हुए भी कुछ जिल्लों ने फीडर सड़कों आदि को सुधारने के काम में बहुत दिलचस्पी ली और इस सबध में जो व्यय हुआ उसकी पूर्ति सरकार तथा जनता ने अंशदान के आधार पर की।

सरकारी अंशदान की धनराशि १८,०२० रु० १२ आना के लगभग थी, जब कि गांव वालों ने जो अंशदान नगद तथा वस्तुओं के रूप में दिया वह लगभग ७३,७०६ रु० १ आना था। सम्पूर्ण धनराशि में से ६९,०४८ रु० १३ आना केवल गांव के यातायात (communications) की उन्नति पर व्यय किया गया। लगभग ५,७८२ नालियों, ३,०२६ पुलियों, ६ बंधियों और ७९,३४७ गज कच्ची सड़कों का निर्माण किया गया।

पानी की सप्लाई

सरकार ने पानी की सप्लाई की उन्नति के लिए भी ३ लाख रुपए की धनराशि दी। लगभग २,९७५ नए कुएं खोदे गए और २,३०३ पुराने कुओं की मरम्मत अंशदान के आधार पर की गई। नए बनवाए गये तालाबों की संख्या ६ थी। इसके अतिरिक्त २० पुराने तालाबों की मरम्मत आलोच्य वर्ष में की गई। हरिजनो के उपयोग के लिए भी लगभग २१४ कुएं बनाए गए, जिनके लिए सरकार ने ९३,९४५ रु० ९ आना का अंशदान दिया, जब कि सार्वजनिक-अंशदान १,२५,६०३ रु० ८ आना ६ पाई था।

ओलेम्पिक खेल

गांव वालों के शारीरिक-गठन सबधी स्तर (standard of physique) को ऊँचा करने के लिए कुछ जिलों में ओलेम्पिक खेलों का आयोजन किया गया और लगभग १,६३४ गांव तथा ३०८ अन्तर्ग्राम खेल प्रतियोगिताएं (Inter-Village Tournaments) आयोजित की गईं। इस सबध में सरकार ने लगभग २४,००० रुपए स्वीकृत किए थे।

प्रदर्शनियां (Exhibitions)

विकास-सुधार कार्यों से संबंधित प्रदर्शनियों के लिए विभिन्न जिलों को ७,५०० रु० दिए गए थे। विकास-मंडलों (Development Courts) संगठित किए गए और विकास-ब्लकों (Development-Blocks) के भीतर ग्रामीण-क्षेत्रों से एकत्र की गई प्रदर्शनों की वस्तुएं (Exhibits) इन प्रदर्शनियों में प्रदर्शित की गईं। कुछ स्थानों पर महिला हितकारी कर्मचारियों द्वारा अनाज की श्रेणी में न आने वाले खाद्य-पदार्थों की प्रदर्शनियों का आयोजन भी किया गया। इस वर्ष आयोजित प्रदर्शनियों की कुल संख्या ४० थी।

३८—नियोजन

पुनर्संगठित नियोजन विभाग का

सदर मुकामी और जिलों में नियोजन तथा विकास विभाग, जिसका १९५० ई० में पुनर्संगठन किया गया था, आलोच्य वर्ष में अपना कार्य करते रहे। राज्य नियोजन समिति ने राज्य के लिए जो द्वि-वर्षीय तथा पञ्च-वर्षीय योजनाएँ

नवम्बर में हुई और उसने उनमें उपयुक्त संशोधन करने का सुझाव दिया। वर्ष के अन्त में ये सुझाव सरकार के विचारार्थीन थे।

जिला नियोजन समितियों ने, नियोजन विभाग द्वारा तैयार की गई योजना जिला स्तर के अनुसार कार्य किया। जिलों के स्तर पर जो योजना बनाई गई, उसकी पर नियोजन मूल्य-मूल्य विशेषताये नीचे दी जाती हैं :-

(१) ग्राम्य योजनाएँ स्वावलम्बन के आधार पर निष्पादित की जानी चाहिए। लोगों को अधिकतम अपेक्षित कोष और साधनों की व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए और सरकार केवल उन्हें यूनियनों को, जिनका अश्वदान अत्यधिक रहेगा, उनके प्रयासों को भान्यता देने के हेतु थोड़ी-बहुत प्रतीक सहायता देगी। (इसका उद्देश्य लोगों में अस्मविश्वास पैदा करना तथा उनके सामाजिक जीवन में अनुराग और मंत्री भाव उत्पन्न करना है।)

(२) सरकारी और गैरसरकारी संस्थाओं तथा कार्यकर्ताओं के मध्य समन्वय पैदा करने का ध्यान सर्वप्रथम रखना चाहिए। (वास्तव में विभिन्न संस्थाओं, जैसे राज्य नियोजन बोर्ड, जिला नियोजन समितियाँ और ब्लाक समितियाँ, जिन्हें नियोजन के संबंध में स्थापित किया गया था, इस प्रकार बनाई गई थीं कि उनमें ऐसा समन्वय स्थापित हो जाय और साथ ही ऐसे भी उपाय किये गये जिनसे विभिन्न विभागों और स्थानीय निकायों तथा गाँव पञ्चायतों में समन्वय स्थापित हो सके।)

(३) गावों के लिए कृषि, पशु-पालन, सहकारी, ग्राम्य-स्वच्छता तथा आरोग्य विज्ञान और पञ्चायत कार्यों में ट्रेनिंग प्राप्त बहुधन्वी कार्यकर्ताओं को तैयार करना है।

अपेक्षित कार्य-कर्ताओं की संस्था तैयार करने के लिए एक ठोस उपाय यह है कि इन विषयों से संबंधित विभागों को एक सूत्र में मिला दिया जाय और इन्हें जिला नियोजन अधिकारी के, जो कि जिले में अपने पद की हैसियत से जिला नियोजन समिति के सेक्रेटरी का कार्य करते हैं और जिनके अधिकार में हरिजन सहायक तथा प्रांतीय रक्षक दल का काम तथा उसका प्रख्यापन भी है, प्रशासकीय नियंत्रण में रख दिया जाय। ५० प्रतिशत जिलों में, जहाँ उपयुक्त इमारतें उपलब्ध थीं, इन विभागों के कार्यालयों को एक ही इमारत में रखा गया। इस दिशा में सफलता का एक और कारण यह था कि भिन्न-भिन्न स्तरों पर कार्य करने के लिए कार्यकर्ताओं को मिश्रित कार्यों की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई।

नियोजन का मुख्य यूनिट, अर्थात् विकास ब्लाक के पञ्चायती अदालत के, जिसके अधिकार-क्षेत्र में आम तौर से १० से १५ तक गाँव थे, समक्ष बना दिया गया। इस वर्ष ऐसे ८,००० ब्लाक थे जो तीन वर्गों में रखे गये थे। 'ए' वर्ग के ब्लाकों में कृषि की ट्रेनिंग प्राप्त सुपरवाइजर रखे गये थे और वर्ग 'बी' में सहकारिता की ट्रेनिंग पाय हुए सुपरवाइजर। 'सी' वर्ग में ट्रेनिंग प्राप्त कर्मचारी नहीं थे। प्रथम दो प्रकार के ब्लाकों में, जिनकी सख्या कुल संख्या की लगभग २५ प्रतिशत थी, यह फायदे थे कि उनमें या उनके समीप के बीज गोदामों से उन्नत प्रकार के बीज सप्लाई हो सकते थे। 'ए' और 'बी' ब्लाकों को निम्न

सुविधाओं प्राप्त थी। अतएव उन्हें सलाह दी गई थी कि वे विशेषतः कृषि क्षेत्र में प्रगढ़ रूप से कार्य करें।

जिला और
ब्लाक
नियोजन
समितियाँ

जिला नियोजन समिति का मुख्य कार्य यथा-संभव सरकार द्वारा मोटे तौर पर दिये गये नमूने और रूप-रेखा के आधार पर स्थानीय आवश्यकताओं और साधनों का समुचित ध्यान रखते हुए जिलों के लिए योजना तैयार करना रहा। इन समितियों में जिला मैजिस्ट्रेट अध्यक्ष के रूप में, जिला बोर्ड का अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में तथा जिला नियोजन अधिकारी सेक्रेटरी के रूप में और प्रत्येक तहसील से गाँव सभाओं का एक प्रतिनिधि, जिले की सहकारी संस्थाओं के पाँच प्रतिनिधि, स्थानीय निकायों के पाँच तक प्रतिनिधि, सरकार द्वारा मनोनीत उद्योग तथा श्रम के तीन प्रतिनिधि और सरकारी विभागों के जिला प्रतिनिधि सदस्य के रूप में काम करते हैं। विभिन्न ब्लाकों से संबंधित कार्यों का कार्यक्रम सबसे पहिले ब्लाक नियोजन समितियों द्वारा, जो केवल राय-बरेली को छोड़कर सब जिलों में बनाई गई थीं और जिनमें प्रत्येक दशा में सब गाँव-सभाओं के प्रधान और उप-प्रधान और सहकारी समितियों और ब्लाक में सम्मिलित यूनियनों के सरपच हैं, तैयार होना था। कुछ जिलों में आवश्यक आंकड़े एकत्र करने के लिए ब्लाक समितियों के लिए विसृत प्रस्तावली जारी की गई, किन्तु इस कार्य-विधि में विलम्ब तथा कठिनाइयों के कारण बहुत सी जिला नियोजन समितियों ने, उनको दी गई रूपरेखा के आधार पर, अपने जिले के लिए स्वयं योजनाएं बनाई और आम तौर पर उस रूपरेखा में दिये गये लक्ष्यों के अनुसार ही काम किया।

कई जिलों में ये ब्लाक समितियाँ, जिन्हें नियोजन विभाग में मूल रूप से महत्वपूर्ण समझा जाता है, सक्रिय नहीं प्रतीत हुईं। कई जगहों पर उन समितियों को ब्लाक सम्मेलनों का आयोजन करके अथवा उनकी सहायता के लिए समितियाँ बनाकर शक्तिशाली बनाने के प्रयास किये गये। गाँव सभाओं के सेक्रेटरियों को, जो कि ब्लाक नियोजन समितियों के भी सेक्रेटरी थे और जिनसे यह आशा की जाती थी कि वे ग्राम योजना के निष्पादन में महत्वपूर्ण भाग लेंगे, उपयुक्त ट्रेनिंग देने के लिए प्रबन्ध किया गया।

जिलों में
कार्य-क्रम

इस कार्यक्रम में कई विषय थे, जिनमें सड़कों और इमारतों का निर्माण या सुधार करना, ग्रँव की स्वच्छता तथा स्वास्थ्य-विज्ञान, पशुपालन सम्बन्धी कार्य, शिक्षा तथा मनोरंजन, कृषि तथा बागदानी, सहकारी तथा कुटीर-उद्योग सम्मिलित हैं। १९५१ ई० में राज्य में इन कार्यवाहियों की प्रगति सम्बन्धी कुछ आंकड़े निम्न विवरण-पत्र में दिये जाते हैं :-

क्रम- संख्या	कार्यक्रम का विषय	१९५१-५२ का लक्ष्य		३१ दिसम्बर, १९५१ ई० तक की प्रगति
		संबंधित जिलों की संख्या	नियत कार्य का परिमाण	
१	२	३	४	५
१	पञ्चायतघरों का निर्माण	५७	२,२३३ पञ्चायतघरों का निर्माण करना	७५४ घरों का निर्माण हुआ।
२	कच्चे मकानों को पक्का बनाना	३०	५३,७२० कच्चे मकानों को पक्का बनाना	२२,२८७ कच्चे मकानों को पक्का बनाया गया।
३	अन्तर्ग्राम सड़कों का सुधार	३४	१६,४७८ मील लम्बी सड़कों का सुधार करना	३,३४३ मील लम्बी सड़कों का सुधार किया गया।
४	कूड़े-करकट के गड्डे बनाना (सोकेज पिट्स)	१३	५४,०३९ गड्डे तैयार करना	२५,०५२ गड्डे तैयार हुए।
५	पीने के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था— (१) नये कुओं का निर्माण (२) पुराने कुओं की मरम्मत	१२ २०	३,९१४ नये कुएं खोदना २०,३२० पुराने कुओं की मरम्मत	४,०२४ नये कुएं खोदे गये। ६,८१५ पुराने कुओं की मरम्मत की गई।
६	पशुओं को सूइयां लगाना	१६,४०,४१७ पशुओं को सूइयां लगाई गई।
७	पशुओं को बधिया करना	१,३९,१५९ पशुओं को बधिया किया गया।
८	प्रौढ-साक्षरता आन्दोलन	३०	११,२२,४७२ प्रौढ को साक्षर बनाना	४३,११९ प्रौढों को साक्षर बनाया गया।

क्रम- संख्या	कार्य-क्रम का विषय	१९५१-५२ का लक्ष्य		३१ दिसम्बर, १९५१ ई० तक की प्रगति	
		संबंधित जिलों की संख्या	नियत कार्य का परिमाण		
१	२	३	४	५	
१०	पुस्तकालयों और वाचनालयों की स्थापना खेल के मैदानों की व्यवस्था	३२ ३०	५,०५२ की स्थापना करना ४,८७६ खेल के मैदानों की व्यवस्था करना	३,५१५ की स्थापना की गई। २,२९९ मैदानों की व्यवस्था की गई।	
११	फलों के उद्यान लगाना	२३	८,२१५ एकड़ भूमि में उद्यान लगाना	४,३९७ एकड़ भूमि में उद्यान लगाया गया।	
१२	मिलवा खाद (compost) के गड्डे तैयार करना	३१	१७,०६६ गड्डे तैयार करना	३,५८८१० गड्डे तैयार किये गये।	
१३	यूरिनल डिजर्वेशन बेड्स तैयार करना	२२	१०,३४,५६० बेड्स बनाना	३३,७२४ तैयार किये गये।	
१४	खाइयों के नमूनों के मूत्रालय	१४	२,९९२ मूत्रालय बनाना	३,०२० मूत्रालय बनये गये।	
१५	रके हुए पानी से भरे हुए क्षेत्रों को खेती योग्य बनाना	२०	२९,०५१ एकड़ भूमि को खेती योग्य बनाना	७,५६० एकड़ भूमि को खेती योग्य बनया गया।	
१६	तालबो को गहरा करना	१५	९,११९ तालबों को गहरा करना	१,९८४ तालबों को गहरा किया गया।	
१७	बन्धियों का निर्माण	८	१,३७६ बन्धियों का बनाया जाना	२,०५५ बन्धिया बनाई गई।	
१८	पाताल तोड़ कुओं का कार्यक्रम - (१) नये कुएं खोदना (२) पुराने कुओं की मरम्मत	३० २४	२०,३५६ नये पाताल तोड़ कुओं का खोदना १५,२७६ पुराने कुओं की मरम्मत करना	६,८०० कुएं खोदे गये। ३,६६३ कुओं की मरम्मत की गई।	
१९	कुएं बेधना	२५	४,०२४ कुओं का बेधन करना	१,९९१ कुएं बेधे गये।	
२०	कुछ योग्य बंजर भूमि को जोतने योग्य बनाकर विस्तार करना	१९	८८,१५७ एकड़ भूमि को जोताई करना	६६,५८१ एकड़ भूमि जोती गई।	

वर्ष के अन्त में समग्र ग्राम सेवा के आधार पर गावों को संगठित करने के लिये अपेक्षित कार्य कर्त्ताओं के शिक्षण के लिये प्रादेशिक शिक्षण केन्द्र योजना छः गाँधी आश्रमों में चालू थी। इसके अतिरिक्त इटावा और गोरखपुर के पाइलेट प्रोजेक्ट के संबन्ध में राज्य में क्षेत्र विकास कार्य-कर्त्ताओं और ग्राम्य-कार्यकर्त्ताओं की ट्रेनिंग के लिए दो केन्द्र और पूर्वी जिलों के लिए क्षेत्र विकास कार्यकर्त्ताओं के अग्रिम शिक्षण के लिए गाजीपुर में एक केन्द्र था।

इस वर्ष विभिन्न विभागों से लिये गये कर्मचारियों को, जिन्हें जिला नियोजन अधिकारियों के नियंत्रण में रखा गया था, और उन उम्मीदवारों को जो गाँव पञ्चायत के सेक्रेटरी हो सकेंगे, आवश्यक शिक्षण देने की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आश्रम योजना को पुनर्संगठित करने का प्रश्न हाथ में लिया गया। इसकी वास्तविक कार्यविधि का पुनरावलोकन किया गया और दो केन्द्रों में कक्षाओं को बन्द कर देन और इस शिक्षण को केवल चार ही प्रादेशिक शिक्षण केन्द्रों में सीमित रखने का निश्चय किया गया। इनमें से प्रत्येक केन्द्र में पञ्चायतराज के कार्य की ट्रेनिंग देने के लिए एक अतिरिक्त इन्सपेक्टर रखा गया, क्योंकि ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यकर्त्ता को पञ्चायत कार्य प्रणाली का ज्ञान होना आवश्यक है। इस वर्ष प्रान्तीय रक्षा दल के पुनर्संगठित होने से इसके कर्मचारियों को भी ग्राम-हितकारी कार्यक्रम की ट्रेनिंग देना आवश्यक हो गया और उन दो केन्द्रों से मुक्त किय गये इन्सपेक्टरों का, जहाँ शिक्षण बन्द कर दिया गया था, उपयोग प्रादेशिक कार्यकर्त्ताओं तथा दल के अन्य कर्मचारियों को कृषि, पशु-पालन, सहकारिता और पञ्चायत राज कार्य की ट्रेनिंग देने के लिए किया गया। गाँव पंचायतों के सेक्रेटरियों के पदों के लिए चुने गये उम्मीदवारों के संबन्ध में यह निश्चित किया गया कि पास-पड़ोस के चार या पाँच जिलों के उम्मीदवारों को उनके समीपवर्ती आश्रमों में ट्रेनिंग के लिए एक साथ भेजा जाय।

आलोच्य वर्ष में प्रारम्भ होने पर प्रादेशिक केन्द्रों में पाँचवाँ जत्था (बैच) ट्रेनिंग पा रहा था। इस जत्थे में १२५ उम्मीदवार थे और इनमें से १२१ परीक्षा में सफल रहे। छठे बैच की ट्रेनिंग जिसमें १२० उम्मीदवार थे और जिन्हें गाँव पंचायतों के सेक्रेटरियों के पद के लिए छाँटा गया था, योजना पुनर्संगठित करने के पश्चात् प्रारम्भ की गई।

बहुत से जिलों में अल्पकालीन शिक्षण शिविर (ट्रेनिंग कैंप) खोले गये और गाँव सभाओं के सेक्रेटरियों को विभिन्न विभागों की कार्यवाहियों की व्यावसायिक ट्रेनिंग दी गई।

कई कृषि तथा सहकारी सुपरवाइजरों, प्रान्तीय रक्षक दल के जोन (zone) कार्यकर्त्ताओं, पशुपालन विभाग के स्टेशनमेंटों को इस प्रकार की मिश्रित ट्रेनिंग दी गई। लखनऊ जिले में समस्त क्षेत्रीय कर्मचारिवर्ग की, जिसमें इन्सपेक्टर भी सम्मिलित हैं, ट्रेनिंग पूरी हो गई थी और इन्सपेक्टरों को, जिन्हें सहकारी, कृषि और पंचायत राज इन्सपेक्टरों की हैसियत से काम करना था, नियोजन इन्सपेक्टरों के रूप में नियुक्त किया गया। कुछ और जिलों जैसे बनारस, बेहराइन, इलाहाबाद, फैजाबाद, मेरठ और जालौन में भी इसी प्रकार के प्रयोग किय गये।

१९५० ई० में गाजीपुर में जो संस्था गाँव स्तर पर कार्यकर्त्ताओं को हर प्रकार के काम की ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी, वह जारी रही। नया सत्र फर्स्ट इयर क्लास में ४५ और सेकंड इयर क्लास में ३५ छात्रों से प्रारम्भ हुआ। व्यावहारिक ट्रेनिंग देने के लिए इस संस्था में जहाँ एक कृषि फार्म, एक दुग्धशाला, एक शाक-सब्जी का उद्यान, एक

गाजीपुर
ट्रेनिंग संस्था
(इन्स्टीट्यूट)

उद्योग कुटी और एक प्रयोगशाला था, पर्याप्त सुविधाये दी गई। इस वर्ष इस फार्म से १०,००० रु० का लाभ हुआ। दुग्धशाला में १४ गायें और भैंसें थीं। इस वर्ष ६ गंगातीरी गायों को भी लाकर इस दुग्धशाला में रखा गया। दूध और छात्रों द्वारा दूध से बनाये गये पदार्थ छात्रों तथा कर्मचारियों के सदस्यों को बेचा गया। छात्रों ने अपने उपभोग के लिये स्वयं शाक सब्जी पैदा की। और डस्टर, तौलिये, चादरे, मेज-पोश, इत्यादि के लिये सूत काते और उन्हें बुना और उन वस्तुओं को उन्होंने तथा सरकार के विभिन्न विभागों ने खरीदा। इस वर्ष तैयार किया गया गुड़ और तेल छात्रों और जनता को बेचा गया।

ध्यावहारिक उत्थान कार्य के प्रयोजन के लिये दस मील की परिधि के भीतर के गाँव छाँटे गये और उनमें छात्र सप्ताह में दो बार गये। छात्रों ने मल-मूत्र को इकट्ठा करने के लिये गड्डे बनाये, गन्दे पानी की नालियों तथा गलियों को साफ किया और प्रौढ़ शिक्षा की कक्षाएँ प्रारम्भ कीं।

शिक्षात्मक दौरे के सम्बन्ध में छात्र महेवा और लखना (जिला इटावा), भदत (गोरखपुर), किछा (नैनीताल), कानपुर एग्रीकल्चरल कालेज तथा रिसर्च स्टेशन, नैनी एग्रीकल्चरल इन्स्टीट्यूट (इलाहाबाद), दयालबाग इन्स्टीट्यूट (आगरा), बुलन्दशहर तथा गोरखपुर के एग्रीकल्चरल स्कूलों और लखनऊ सहकारी यूनियनों में गये।

पाइलेट
प्रोजेक्ट
(क) इटावा

१९४८ ई० में इटावा में प्रारम्भ की गई पाइलेट विकास योजना के सफल कार्यकाल का द्वितीय वर्ष समाप्त हुआ। वहाँ जो प्रगति हुई उससे सरकार इस कार्यवाही को १०० और गाँवों में फैलाने के लिये प्रोत्साहित हुई और इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत गाँवों की संख्या २०० हो गई। कृषि (जिसमें सिंचाई, उद्यान-विद्या, कृषि इन्जीनियरिंग और पौधा संरक्षण सम्मिलित हैं) पशुपालन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक शिक्षा, महिलाओं की भलाई, सहकारी और पञ्चायत-कार्य और सड़कों और इमारतों के सुधार से सम्बन्धित कार्यों में भी संतोषजनक प्रगति रही।

कृषि के सम्बन्ध में भी इटावा अग्रणी रहा। उन्नत प्रकार के बीजों, उन्नत खाद (जिसमें सनई तथा मूँग तथा मूँग टाईप, “१” के साथ हरी खाद तथा अमोनियम सल्फेट, रेडो की खली और सुपर फास्फेट जैसे उर्वरक भी सम्मिलित हैं) और उन्नत ढंग का कृषि सम्बन्धी अभ्यास, अर्थात् कतार में बीज बोने, गर्मी के मौसम में खेती करने तथा मिट्टी ठीक करने से उपज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कुछ आँकड़े नीचे दिये जाते हैं :-

फसल		प्रति एकड़ अधिकतम उपज (१९४१-४२)			प्रति एकड़ औसत उपज		
		मन	सेर	छटाक	मन	सेर	छटाक
गेहूँ	...	४२	२३	३	२२	२५	६
आलू	...	३८६	३२	१५	२१०	३७	०
मटर ‘टी’ १६३०	...	३१	१२	१३	२४	२	१
गन्ना (खाद डालना पुरा ‘किया गया’)	...	७२	३५	९ (गुड़)	५२	२४	०
जौ ‘टी’ २५१	...	३३	२५	३	१७	१८	१
चना ‘टी’ ८७	...	२४	३८	१३	१६	३०	१

(असामयिक और कम वर्षा के कारण मक्का सम्बन्धी कार्यक्रम का अनुसरण
न किया जा सका।)

कपास और धान के काम की अभी जाँच की जा रही है और उसका प्रदर्शन किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण गेहूँ के क्षेत्र में पिछले वर्ष की भाँति पी-५६१ नामक गेहूँ को उन्नत किस्म बोई गई। इसके अतिरिक्त अन्य जिलों तथा इटावा के अन्य क्षेत्रों में १५,००० सन उन्नत किस्म का बीज दिया गया। अन्य प्रकार के उन्नत बीजों में जैसे मटर १६३, चना 'टी' ८७, जौ "सी" २५१ तथा 'एन० पी०' १२ की कई गुना वृद्धि की गई और मिट्टी को उलटने के लिये हल, 'कल्टिवेटर' डेकी, (श्रृंखर), सोड ड्रिल, रोपर, उन्नत किस्म की हंसिया इत्यादि जैसे उन्नत औजार लोकप्रिय बनाये गये।

तीन ट्यूबवेल और चार पाताल तोड़ कुंए, जिनसे प्रतिवर्ष १,५०० एकड़ भूमि सींचे जाने की आशा की जाती है, बनाये गये और सहकारिता के आधार पर इनका खर्चा चलाया गया। यमुना नदी के कछार क्षेत्रों में पाताल तोड़ कुंओं के लिये उपयुक्त भूमि का पता चलने से नदियों से पम्पों द्वारा पानी निकालने की योजना स्थगित की गई। केनाल लिफ्ट, बिजली से खींचे जाने वाले सेट तथा हाथ से चलाये जाने वाले पानी के लिफ्टों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करके जाँच-पड़ताल की गई।

महेवा में कृषि सम्बन्धी औजारों की मरम्मत करने, साधारण प्रकार के औजार तैयार करवाने और इन व्यवसायों में स्थानीय प्रतिभाशाली व्यक्तियों को ट्रेनिंग देने के लिये जो देहाती कारखाना खोला गया था उसमें उपयोगी कार्य होता रहा। यह देखा गया कि प्रोजेक्ट क्षेत्र में यह कारखाना तीव्रगति से जन-प्रिय होता जा रहा है।

लगभग १,१२,८०० शाक-भाजी के छोटे पौधे, ४२ पौंड शाक-भाजी के बीज, १,१०० फलों के पौधे और ४,१०० इमारती लकड़ियों के पौध किसानों को लागत मूल्य पर बचे गये।

सबसे घातक पशु महामारियों, अर्थात् हैमोरेजिक सेप्टीसेमिया और रेन्डरपेस्ट को समूल मिटाने के कार्य-क्रम को रोग-निरोधक (प्रोफिलैक्टिक) सूइयाँ जगाकर जारी रखा गया और क्रमशः २४,०२६ और ८,८८५ पशुओं को वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन के पथ-प्रदर्शन के अनुसार काम करने वाले ग्राम-स्तर के कार्यकर्त्ताओं ने इन रोगों से बचाने के लिये सूइयाँ लगाईं। (रिन्डरपेस्ट से बचने के लिये लगाई गई सूइयों की संख्या कम थी, क्योंकि जिन पशुओं को पहले ही सूइयाँ लगाई गई थी वे तीन साल तक के लिये इस बीमारी से मुक्त हो चुके थे)। इस वर्ष हैमोरेजिक सेप्टीसेमिया के रोगग्रस्त मामले नगण्य थे और रिन्डरपेस्ट तो करीब-करीब नहीं के बारबर रह गया था।

अभिजात (pedigree) पशुओं की सप्लाई, कृत्रिम गर्भाधान और बधिया करने के फलस्वरूप पशुओं की नस्ल को उन्नत करने के कार्य में नियमित प्रगति हुई। हिसार से ५७ गाये लाई गई और ५४३ पशु कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र में गायित किये गये। बधिया किये गये पशुओं की संख्या ७५४ थी और सामान्य रोग से बीड़ित ३,४३४ पशुओं का गाँव-स्तर के कार्यकर्त्ताओं ने उपचार किया और इसके अतिरिक्त ४२,०७६ पशुओं का पशु चिकित्सालयों में उपचार किया गया।

सफेद घरेलू मुर्गे (४७ मुर्गे और ७७ मुर्गियाँ) गाँव वालों को दिये गये और ७ तालाबों में मछलियाँ रखी गयी।

जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में चेचक-निरोधक अनुविद्ध टीके का कार्य ग्राम-स्तर कार्यकर्त्ताओं द्वारा हाथ में लिया गया और हैजा तथा स्कैबीज की रोक-थाम

पास-पड़ोस के सफाई के कार्य में सुचारु करने के लिये सफाई सम्बन्धी निर्माणकार्य, जैसे मल-मूत्र, मलवा खाद के गड्डे इत्यादि द्वारा प्रोत्साहन मिला और ११ गाँवों में यह कार्य किया गया।

शिक्षा के क्षेत्र में भी ग्रामीणों ने उत्साह दिखलाया। बकेवार और अरहे-पुर के गाँव वालों ने अपने ही प्रयासों से दो नये हायर सेकेंडरी स्कूल खोल। प्रथम संस्था को जो अंशदान दिया गया वह बढ़कर ६०,००० रु० से अधिक था। यह संस्था जो जनता विद्यालय के नाम प्रसिद्ध है, एक अपूर्व संस्था थी, जिसमें ऐसे प्रबन्ध किये गये थे जिनके द्वारा छात्र स्कूल के पढाई के समय किये गये आभ्यासिक कार्य द्वारा कमाई कर सके। ग्रामीणों ने ४ नये मिडिल स्कूल और ११ प्राइमरी पाठशालायें चालू की और इनकी इमारतों के लिये लगभग १ लाख रुपये की सम्पूर्ण लागत की व्यवस्था की।

४१ प्रौढ साक्षरता और सामाजिक शिक्षा की कक्षाये चालू की गयीं और ४८० प्रौढ साक्षर बनाये गये। २८ कम्यूनिटी सेन्टर, जिनका सम्बन्ध महेवा के केन्द्रिय वाचनालय से था, इस वर्ष चालू रहे। 'मन्दिर से' नामक एक पाक्षिक समाचार-पत्र के लगभग १,००० ग्राहक थे।

५,००० से अधिक ग्रामीणों को योजना क्षेत्र के अन्दर तथा बाहर भी विभिन्न स्थानों में दृश्यावलोकन के लिये ल जाया गया। वार्षिक किसान मेला, जिसमें १५,००० से अधिक लोग सम्मिलित हुए, बहुत सफल सिद्ध हुआ। ग्राम्य नाटक समितियों ने २३ नाटक और १२४ एकांकी नाटकों का आयोजन किया और सिनेमा प्रोजेक्टर की सहायता से ६१ फिल्म दिखलाये गये।

लखना के शिक्षण शिबिर में ४५ ग्राम्य-स्तर कार्यकर्त्ताओं और ४७ पन्चायत सेक्टरियों को—३५ उत्तर प्रदेश और १२ अन्य राज्यों के लिये—ट्रेनिंग दी गई। इस शिबिर में ट्रेनिंग देकर ४० पन्चायत सेक्टरियों और १० प्रान्तीय रक्षक दल आर्गनाइजरी को बहु-धन्धी ग्राम्य-स्तर कार्यकर्त्ता बनाया गया। प्रोजेक्ट क्षेत्र में समस्त सहकारी यूनियनों को अपने ईंट के भट्टे थे और वे ग्रामीणों को बीज, खाद, औजार, कपड़ा तथा अन्य उपभोग्य सामग्रियों तथा दवाइयों भी सप्लाई करते थे। इस वर्ष कुल विक्रय धन ५,१८,१०० रु० था और शुद्ध लाभ की धनराशि ४२,८३६ रु० १२ आना थी। सहकारी यूनियनों के पारा पानी खींचने के सेट, सौंड ड्रिल (बीज बोने का यन्त्र विशेष), डकी (थूँसर) थे और वे गाँव वालों को किराये पर देते थे। ईंटों के भट्टों से पक्के मकानों, स्कूलों, पुलियों, सामाजिक जीवन केन्द्रों (कम्यूनिटी सेन्टर) और अन्य कई जनोपयोगी योजनाओं को प्रोत्साहन मिला।

४० गाँवों में गाँव वालों ने अपनी स्वेच्छा से किये गये श्रम द्वारा लगभग ५१ १/२ मील कच्ची ग्राम्य सड़कें, जिस में पुलियाँ भी थी, बनाई।

महिला हितकारी कार्यक्रम, जिसमें प्रौढ शिक्षा, छोटे बच्चों की कक्षाएँ, घरेलू दस्तकारी और प्रसूत-सेवा की ट्रेनिंग सम्मिलित थी, अभी प्रयोगात्मक स्थिति में था। किन्तु इस कार्य-क्रम के लिये ग्रामीणों में पर्याप्त उत्साह था।

प्रोजेक्ट के प्रथम यूनियट के २४ ग्रामस्तर के कार्यकर्त्ताओं ने सहकारी सुपरवाइजरों, पशु-चिकित्सा के स्टाफमैनो, पन्चायत सेक्टरियों और सहायक कृषि इन्स्पेक्टरों के कार्यभार को सभाला।

पूर्वी जिलों के लिये चार प्रोजेक्टों का कार्य इटावा प्रोजेक्ट के कार्य से कुछ हद तक भिन्न था। इटावा में यह योजना सम्बन्धी कार्य ठोस ब्लाकों अर्थात् एक

ऐसा प्रतीत हुआ कि इन क्षेत्रों के, जहाँ कि योजना सम्बन्धी क्षेत्रीय कर्म श्रमिकों के लोग सावधानी से काम करेंगे, मध्य जो गाँव छूट गये हैं, वहाँ के लोगों को यह देखने का अवकाश मिलेगा कि उनके पास-पड़ोस में विकास के क्या कार्य हुए हैं और वे कृषि सम्बन्धी ऐसे तथा अन्य प्रचलित कार्यों को अपनायेंगे जो उन्हें अच्छे लगेंगे। इससे अधिक बड़े क्षेत्र में काम हो सकेगा। साथ ही यह आशा की जाती है कि इस प्रयोग से व्यय की प्रत्येक मद को अधिक लाभ होगा।

गोरखपुर में योजना का क्षेत्र दो जिलों (गोरखपुर और देवरिया) में था और इसमें ११२ गाँव थे और १,३२,६७७ जनसंख्या थी और इसका क्षेत्रफल ८६,४०० एकड़ था, जिसमें से ७२,८०० एकड़ भूमि में खेती की जा रही थी। बीच-बीच में स्थान छोड़कर (interstitial spaces) इस योजना में गाँवों की संख्या २०५ थी।

आजमगढ़ जिले के ८१ गाँवों में, जो घोसी के चारों ओर ५ मील की परिधि के भीतर थे, यह योजना चालू थी और इनकी जनसंख्या लगभग ३४,००० थी। इस योजना में १२,००० एकड़ भूमि थी, जिसमें से १३,३०० एकड़ भूमि में खेती की जा रही थी। बलिया में यह योजना १६० गाँवों के लिये थी और इनकी जनसंख्या ५०,३०० थी और इनका क्षेत्रफल लगभग ४५,००० एकड़ था। गाजीपुर में ७५ गाँवों में यह कार्य प्रारम्भ किया गया।

पूर्वी जिलों की योजनाओं में कृषि करने की ओर मुख्य ध्यान दिया गया। इस वर्ष गोरखपुर में गेहूँ और धान के सम्बन्ध में १,४०० और गन्ने के सम्बन्ध में ६०० प्रदर्शन किये गये। 'एन २२' नामक पहिले बोये जाने वाले धान के बारे में यह मालूम हुआ कि स्थानीय किस्म के धान की अपेक्षा इस धान की उपज प्रति एकड़ ७० सेर के हिसाब से अधिक है और ३,००० एकड़ भूमि में यह पैदा किया गया।

इस फसल का कुल अतिरिक्त मूल्य ८४,००० रु० था। गेहूँ और जौ की अतिरिक्त उपज क्रमशः २,१७५ और १,००० मन थी, जिसका मूल्य लगभग ५०,००० रुपये था। उन्नत किस्म के गन्ने की उपज, जो कि प्रदर्शन प्लाटों पर पैदा की गई और जिनका क्षेत्रफल ३५० एकड़ था, नियंत्रित प्लाटों से प्राप्त उपज से प्रति एकड़ २७५ मन अधिक थी और इससे लगभग १,६७,००० रु० की और अधिक आय हुई।

आजमगढ़ में मुख्य फसल चावल की थी, जिसके ७५५ किस्म प्रदर्शन के लिए रखे गये, तथापि वर्षा की कमी के कारण अपेक्षित परिणाम लब्ध नहीं हुए। बलिया और गाजीपुर की स्थिति सब तरह से करीब करीब एक ही सी रही।

गोरखपुर में तबाही के आधार पर ६६ गाँवों को सफ़ाई करके के अतिरिक्त योजना क्षेत्र में काश्तकारों को अश्वदान के आधार पर २१ हरियाना साड़ दिये गये। इस क्षेत्र में स्थानीय नमूने को उन्नत करने के लिए याकशायर नर सुअर और १३ बारबरी हिरण भी लाये गये। बहुत से जानवरों को हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया तथा रिडरपस्ट को रोकने के लिये रोग निरोधक सूइयाँ लगाई गईं। आजमगढ़ में ८ हरियाना सांड तथा २ मुर्रा भैंसें सफ़ाई की गईं और महापौरी के रोगों से बचने के लिए जानवरों को ४,५०० सूइयाँ लगाई गईं। गाजीपुर और बलिया में नर-बछड़ों को बधिया करने और पशुओं को सूइयाँ लगाने का काम किया गया।

का छिड़काव करवाया और १५० ऐसे घरों में पैसे देकर छिड़काव किया गया। आजमगढ़ के पांच गाँवों में मलेरिया-निरोधक उपाय किये गये और इसी प्रकार जन-प्रिय सिद्ध हुए। बलिया और गाजीपुर में पैल्यूडिन की गोलियाँ व्यापक रूप से बांटी गईं।

प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में १,२०९ प्रौढ़ गोरखपुर में और ६०० आजमगढ़ में भर्ती किये गये। बलिया में २० अध्यापकों के शिक्षण के लिए एक शिविर खोला गया और फलतः ये अध्यापक सामाजिक शिक्षा देने के लिए विभिन्न केन्द्रों में रखे गये।

गोरखपुर में हरिजनो के लिए मकान बनवाने का प्रयास किया गया और वहाँ ३२ मकान बनवाये गये। इस क्षेत्र में ३ मील अन्तर्ग्राम्य सड़के और ३ पुलियाँ बनवाई गई थी और इनके अतिरिक्त एक बन्धी तथा ३५० बीघी भूमि को सींचने के लिए सिंचाई की नालियाँ बनाई गईं।

कुमायूँ
विकास बोर्ड

इस बात को देखते हुए कि सब जिलों में, जिसमें कुमायूँ डिवीजन के जिले भी सम्मिलित हैं, जिला नियोजन बोर्ड स्थापित हो चुके हैं, कुमायूँ विकास बोर्ड को बनाये रखने की अब कोई आवश्यकता नहीं समझी गई। तथापि ऐसा प्रतीत हुआ कि समय समय पर जिला नियोजन अफसरों और नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल तथा टोहरी (गढ़वाल) से चुने गये गैरसरकारी लोगों की बैठके बुलाना वांछनीय होगा, ताकि अन्य बातों के साथ साथ पर्वतीय जिलों की एक ही तरह की समस्याओं पर वाद-विवाद करना सुविधाजनक हो सके और इन मामलों में राय देने के लिए तदर्थ समिति बनाने में सुविधा हो सके।

कुमायूँ डिवीजन तथा टोहरी (गढ़वाल) के जिलों में विकास-कार्य के लिए २५,००० रु० की धनराशि निश्चित की गई थी।

टूरिस्ट
ब्यूरो

इस वर्ष टूरिस्ट ब्यूरो की कार्यवाहियाँ सरगम रहीं। देश के समस्त भागों से और बाह्य देशों से टूरिस्टों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापनों, पोस्टरों तथा अन्य प्रकार के साहित्य द्वारा प्रत्यक्ष आयोजित किया गया। भारत के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों, पुस्तकालयों, भोजनालयों, क्लबों और अन्य सार्वजनिक स्थानों और विदेशी दूतावासों में पोस्टर लगाये गये। इस ब्यूरो ने रेलगाड़ी तथा बसों में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कम्पार्टमेंटों में यात्रा करने वाले ४०० टूरिस्टों के लिए स्थान सुरक्षित करने का प्रबन्ध किया। टूरिस्टों की सुविधा के लिए अवध और तिरहुत रेलवे का एक बुकिंग आफिस नैनीताल में खोलने का भी प्रबन्ध किया गया। पर्वतीय जिलों में विभिन्न रमणीक स्थानों को देखने के लिए टूरिस्टों को प्रोत्साहन देने के निमित्त गैर-सरकारी एजेन्सियों को ५,००० रुपये की धनराशि राज्य सहायता के रूप में स्वीकृत की गई।

शारीरिक
संवर्द्धन परि-
षद् (काउंसिल
आफ फिजि-
कल कल्चर)

१ अप्रैल, १९५१ ई० से उत्तर प्रदेश के शारीरिक संवर्द्धन परिषद् (काउंसिल आफ फिजिकल कल्चर) को शिक्षा विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण से हटाकर नियोजन विभाग के अधीन कर दिया गया। शारीरिक संवर्द्धन योजना १४ जिलों, अर्थात् आगरा, इलाहाबाद, बनारस, बरेली, देहरादून, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, नैनीताल और मुरादाबाद में चालू नहीं। इनमें से प्रत्येक जिले में इस वर्ष कार्य की देख-भाल के लिए शारीरिक संवर्द्धन का एक अधीक्षक नियुक्त किया गया। इस योजना में जितने कर्मचारी काम कर रहे थे, उनमें एक महिला टेकनिकल असिस्टेंट और शारीरिक संवर्द्धन के लिये एक महिला जिला अधीक्षक (सुपरिन्टेन्डेंट) भी सम्मिलित हैं, जिनको अन्ततः उत्तर प्रदेश सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार

के तालाबो (Swimming Pools) के रख-रखाव के लिए ५,००० रु० और जलक्रीड़ा सम्बन्धी शिक्षा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के १३ बाढ़-ग्रस्त जिलों में आवश्यक सज्जा देने के लिए १२,३५० रु० की धनराशि भी सम्मिलित है।

योगिक आसनों पर पोस्टरों, सिनेमा स्लाइडों और शारीरिक संवर्द्धन और व्यायाम के संबंध में फिल्मों द्वारा "स्वस्थ रहो" दैनिक कार्यक्रम का समुचित प्रस्थापन किया गया। इलाहाबाद के तरुण कार्यालय को ५०० रु० की राज्य-सहायता इसलिए दी गई कि विभिन्न शारीरिक संवर्द्धन संबंधी विषयों पर मैगज़ीन और पुस्तकें प्रकाशित की जायें।

शारीरिक संवर्द्धन के जिला अधीक्षकों के इस वर्ष लखनऊ में दो सम्मेलन हुए, जिनमें से एक में मुख्य मंत्री ने भाषण किया। इस सम्मेलन में जो कार्यक्रम अपनाया गया उसकी पूरा करने के लिए जिलों में शिशु-प्रदर्शन, सर्वोत्तम शारीरिक प्रतियोगितायें और अन्तर्गाम्य, अन्तर्माहल्ला तथा अन्तर्कार्यालय टूर्नामेंट आयोजित किये गये। प्रान्तीय रक्षक दल के जोन के कार्यकर्ताओं को प्रान्तीय रक्षा दल के सदर मुकाम में शारीरिक संवर्द्धन कार्यवाहियों के शिक्षण के लिए एक अल्पकालीन पाठ्यक्रम संचालित किया गया। जिला नियोजन अधिकारियों द्वारा आयोजित विभिन्न शिविरो में शारीरिक संवर्द्धन की भी ट्रेनिंग दी गई।

३६—उपनिवेशन

पिछले वर्षों में आरम्भ की गई बहुत सी उपनिवेशन योजनायें चालू रखी गईं। इन योजनाओं के संबंध में होने वाला व्यय १९५१ ई० में कुल मिला कर १,११,७८,०२२ रु० था। १५,२१,९२० रु० उधार के रूप में भी दिया गया।

गंगा खादर में इस वर्ष ६४ विस्थापित परिवारों, राजनैतिक पीड़ितों के ९१ परिवारों तथा २ स्थानीय किसानों को खेत दिये गये और दी हुई भूमि का कुल क्षेत्रफल १,५७० एकड़ था। इसके अतिरिक्त ५ एकड़ भूमि ताड़ गुड़-योजना के संबंध में ताड़ और खजूर की किस्में उगाने के लिये दी गईं।

स्वास्थ्य सम्बन्धी उपाय—मलेरिया-निरोधक उपाय ६६ गांवों में, जिनमें नये बसाये हुये तथा पुराने दोनों प्रकार के गांव सम्मिलित हैं, काम में लाये गये। घरो तथा पशुशालाओं में, जिनका कुल क्षेत्रफल २,८२,८१,५५१ वर्ग फुट था, डी० डी० टी० का छिड़काव किया गया और मलेरिया से होने वाली घटनाओं की संख्या घटकर ३,६२ प्रतिशत हो गई। सूक्ष्म परीक्षा से ज्ञात हुआ कि कीटाणु ले जाने वाले मच्छरों की संख्या घट रही थी। लगभग ३,५०,००० पैलूडीन की टिकियां रोग दूर करने तथा आरोग्य करने के लिये मुफ्त बांटी गईं। २० रोगी, शय्याओं का एक अस्पताल लगभग पूरा हो चुका था जब कि वर्ष समाप्त हो गया।

सहकारी समितियां—सहकारी उपभोक्ता स्टोर (Co-operative Consumers Stores) तथा महिला औद्योगिक समिति का कार्य संतोषपूर्ण ढंग से होता रहा। इस वर्ष दो नई सहकारी समितियां बनाई गईं और सहकारी समितियों के एक संघ (Federation) का संगठन भी, जिस सहकारी समिति विकास यूनियन कहते हैं, सभी बसने वालों के हित के लिये किया गया। यह निश्चय किया गया कि यह यूनियन कृषि सम्बन्धी साधनों, गृह सम्बन्धी समस्याओं, बसने वालों की आर्थिक आवश्यकताओं, शिक्षा तथा सफाई जैसे कार्यों को करे और समितियों के सदस्यों की ओर से मोल लेने और बचने तथा बीज बांटने का कार्य भी करे।

डेरी (दुग्धशाला) फार्म—राजकीय फार्म और डेरी फार्म, जिनका कुल क्षेत्रफल १,५०० एकड़ था, एक साथ मिला दिये गये। वर्ष के अन्त में डेरी उप-विभाग

संख्या १० थी और एक आधुनिक स्थिरयंत्र (modern plant) लगाने का कार्य, जिससे प्रति घंटा २२० गैलन तक दूध कृमि मारकर शुद्ध किया जा सकता था, पूरा ही होने वाला था।

जंगल लगाना—जंगल लगाने की योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले निर्माण कार्य में, जिसका उद्देश्य खोलाओं पर होने वाली क्षति को रोकना था, और अधिक प्रगति हुई। इस वर्ष लगभग १,२०० एकड़ क्षेत्र में जंगल लगाये गये और लगे हुये पौधों की संख्या लगभग १२,००,००० थी। प्रति मील लगभग २६० पौधे सड़क के किनारे भी लगाये गये।

यातायात—खटौली से हस्तिनापुर तक ट्राम लाइन का विस्तार करने के कार्य में प्रगति हुई। भवाना से हस्तिनापुर तक एक नई सड़क का प्रारंभिकरण करने का प्रस्ताव किया गया और मेनलाइन तथा खादर* के बीच यातायात निरंतर बनाये रखने की व्यवस्था करने के लिये बूढ़ी गंगा पर पुल बनाने का कार्य पूरा किया गया।

सिंचाई—सिंचाई के प्रयोजनों के लिये २२ ट्यूबवेल और पीने के पानी की पूर्ति के लिये ६ कुंवों का निर्माण कार्य पूरा किया गया और उन्हे हस्तिनापुर के बिजलीघर से मिलाने के लिये ट्रांसमिशन (दूरप्रण) लाइन बनाई जा रही थी।

केन्द्रीय नगर—हस्तिनापुर नगर विकास बोर्ड की संरक्षता में हस्तिनापुर में एक केन्द्रीय नगर स्थापित किया जा रहा है। हस्तिनापुर के प्रस्तावित नगर की भीतरी सड़कों का विस्तार किया गया और एक प्राइमरी स्कूल का भी निर्माण किया गया। एक बस स्टैंड की व्यवस्था की गई और बसने वाले लोगों के लिये लगभग ५०० क्वाटर बन चुके थे या वर्ष के अन्त तक बन रहे थे। भीतरी भाग में बिजली लगाने का कार्य भी हाथ में लिया गया और जल-कल निर्माण कार्य प्रणाली को केन्द्रित करने के लिये एक ट्यूब वेल लगाया गया।

नैनीताल तराई

नैनीताल तराई में लगभग ८,२०० एकड़ क्षेत्र की भूमि कृषि योग्य बनाई गई और स्वीकृत वर्गों, जिनमें राजनैतिक पीड़ित, विस्थापित व्यक्ति, कृषि स्नातक (ग्रेजुएट) तथा कृषि डिप्लॉमा रखने वाले और भूमि न रखने वाले व्यक्ति सम्मिलित हैं, के ५६६ परिवार वहाँ की भूमि पर बसाये गये। २७ नये गांव बसाये गये और कुछ पुराने गांवों का जीर्णोद्धार किया गया।

यातायात—रुहरपुर से बाजपुर और नगला तक लगभग ३५ मील सड़क पक्की की गई और विभिन्न गांवों और फार्मों को मिलाने के लिये ४० मील भीतरी सड़कों का विस्तार किया गया।

सिंचाई—१९५१ के अन्त तक १६ ट्यूबवेल और आर्टीजनल वेल (पाताल तोड़ कुएं) लगाये जा चुके थे और कुछ गांवों में बिजली लग चुकी थी। लगभग ८ मील की दूरी तक जंगली जानवरों को घुसने न देने की लिये बाड़ लगाई गई थी।

डैरी (दुग्ध शाला) और राजकीय फार्म आदि—डैरी फार्म उपनिवेशन क्षेत्र तथा हल्द्वानी, काठगोदाम, ज्योलीकोट और नैनीताल नगरों को कृमि रहित शुद्ध दूध पहुंचाता रहा। राजकीय फार्म के संपूर्ण १६,००,००० एकड़ में जोताई की गई और ऊष्ण प्रदेशीय (tropical) फलों का १,००० एकड़ बाग लगाया जा रहा था। वर्ष के अन्त तक लगभग २०० एकड़ क्षेत्र में फलों के पेड़ लगाये गये।

ई टोक भट्ठों तथा दूसरे गड़दों को मछली के तालाबों में परिवर्तित करके मत्स्य-पालन का कार्य आरम्भ किया गया। उपयुक्त प्रकार की छोटी मछलियाँ (fingerlings) रखी गयीं।

कटाव को रोकने के लिये जलस्रोत (stream) के दोनों ओर १०० गज जंगल की पट्टी में पौधे लगाने और उपनिवेश के लिये ईंधन तथा लकड़ी की व्यवस्था करने के कार्य में प्रगति हुई। जंगल तथा चरागाहों के लिये सुरक्षित क्षेत्र काफी बड़ा था।

सहकारी समितियाँ—इस क्षेत्र में ७६ सहकारी समितियाँ मौजूद थीं और कृषि सम्बन्धी स्टोक तथा औजार मेल लाने एवं घर बनवाने के लिये उन्हें रकबा उधार दिया गया। कुछ समितियाँ अच्छा कार्य करती रहीं किन्तु अन्य समितियों में अनुभव की कमी और उनके सदस्यों में एकता की कमी पाई गई।

स्वास्थ्य सम्बन्धी उपाय—इस क्षेत्र के लोगों का स्वास्थ्य प्रायः सन्तोषजनक रहा। मलेरिया निरोधक युनिट ने जो कार्य किया उसके फलस्वरूप मलेरिया से होने वाली घटनायें नगण्य रही। प्लीहा की सूची (spleen index) जो कि आपरेशन के आरम्भ में ७० से १०० प्रतिशत तक बढ़ी हुई थी अब लगभग १० प्रतिशत थी और परजीवि संचार की सूची (parasite index) ५-२० प्रतिशत से घटकर (ऋतु के अनुसार) १.४ प्रतिशत हो गई थी।

सिंचाई—लगभग ३० ट्यूब वेल लगाये गये और उनमें से ८ ट्यूब वेल आर्टिजन कुये सिद्ध हुए। इसके अतिरिक्त और कुएं बनाने के कार्य में प्रगति हुई और लगभग ४० मील दूरप्रेषण (ट्रांसमिशन) लाइन का कार्य पूरा किया गया।

जूट और गन्ने की खेती—इस क्षेत्र में बसे हुए पूर्वी बंगाल के जूट उगाने वाले तीन सौ विस्थापित परिवारों ने १९५२ में जूट की खेती करने के पूर्व इस वर्ष अपनी धान की फसल पैदा की।

गन्ने की खेती के उन क्षेत्रों में, जो उसके लिये विशेष रूप से उपयुक्त थे, जोरो की प्रगति हुई। उपनिवेशन क्षेत्र के बाहरी और भीतरी भागों में किसी प्रकार ३०,००,००० मन से कम गन्ना नहीं उगाया गया। शक्कर मिलों के लिये इतना अधिक गन्ना उपयोग में लाना कठिन था, अतः यह निश्चय किया गया कि बाजपुर में एक दूसरा शक्कर का कारखाना खोला जाय।

केन्द्रीय नगर—हदरपुर नगर को वैज्ञानिक ढंग पर लाने की योजना आरम्भ की गई और एक प्रशासक नियुक्त किया गया। यह निश्चय किया गया कि विकास का व्यय प्लानों को बचने के फलस्वरूप प्राप्त निधि (२ १/२ लाख रुपया) से पूरा किया जाय। आय का ३० प्रतिशत सरकार को देना था और २० रोगीशय्या का एक अस्पताल, अन्य वस्तुओं के साथ साथ आधुनिक, सर्जरी के औजारों तथा साधनों, एक एक्सरे मशीन (plant) तथा एक आपरेशन गृह से सुसज्जित खोला गया और उनकी नींव का पत्थर भारत के प्रधान मंत्री द्वारा रक्खा गया। एक ग्रामीण हाई स्कूल भी, जिसमें ४०० विद्यार्थी पढ़ सकते थे और जिसमें विद्यार्थियों को कृषि की व्यावहारिक शिक्षा देने के लिये २५० एकड़ का एक फार्म प्राप्त करने वालों के लाभ के लिये स्थापित किया गया। इस क्षेत्र में बहुत से छोटे उद्योग-धंधे स्थापित हुये और एक बाजार केन्द्र बन रहा था।

इस वर्ष काशीपुर में लगभग ३,१०० एकड़ भूमि कृषि योग्य बनाई गई और वह ५०० विस्थापित व्यक्तियों के परिवारों, ६२ राजनीतिक पीड़ितों, १०० भूतपूर्व सैनिकों, ४ कृषि स्नातकों (ग्रेजुएटों) और डिप्लोमा रखने वालों और ३७ भूमिहीन मजदूरों को बांटी गई। वर्ष के अन्त तक ७

काशीपुर

गांव स्थापित हो चुके थे और कई अन्य गांव स्थापित होने वाले थे । बसने वालों के लिये ८०४ एक कमरे वाले घर थे और उनकी शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ५ प्राइमरी स्कूल था ।

यातायात—बाजपुर से काशीपुर तक और जसपुर तक लगभग ३२ मील नई सड़कें पक्की की गईं । घेला के पूर्व में काशीपुर से सीधे हेमपुर फार्म तक एक बिल्कुल नई सड़क भी पक्की की गई ।

सिंचाई—वर्ष में लगभग ६ इंच बरस बरस बनाकर सिंचाई की सुविधाये दी गई ।

सहकारी समितियाँ—कृषि सामग्री (स्टोक) और औजार मोल लेने तथा घरो के निर्माण के लिये लगभग १८ समितियों को वित्तीय सहायता दी गई । भारत सरकार के पुनर्वास मंत्रालय (Ministry of Rehabilitation) से प्राप्त कर्जों से विस्थापित व्यक्तियों को प्रति परिवार १,७८२ रु० के हिसाब से सहायता मिली ।

आलोच्य वर्ष में बसने वालों ने ७ सहकारी समितियाँ बनाईं ।

जंगल लगाना—नैनीताल तराई की भोंति जलस्रोत (stream) और सड़कों के किनारे और दूसरे स्थानों के छोटे टुकड़ों में जंगल लगाने का काम ईंधन तथा लकड़ी के सुरक्षित स्टोको की व्यवस्था करने के उद्देश्य से आरम्भ किया गया ।

मलेरिया निरोधक उपाय—भारतीय खाद्य तथा अनुसंधान संस्था (Research Institute) और उत्तर प्रदेश सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त मलेरिया निरोधक यूनिट ने लगभग २३० वर्ग मील में प्रगाढ़ रूप से मलेरिया निरोधक कार्य आरम्भ किये । पैलूडोन की ४,५०,००० टिकियाँ बांटी गईं । इससे मलेरिया की घटनाओं में काफी कमी पाई गई ।

विद्युत् व्यवस्था (Electrification), एक बिजलीघर जिसकी कुल समाई ६०० किलोवाट थी और जिसका उद्देश्य ट्यूबवेलों को बिजली पहुंचाना और घरेलू तथा औद्योगिक प्रयोजनों के लिये बिजली की व्यवस्था करना था, पूरा किया गया । काशीपुर नगर में भी विद्युत् व्यवस्था का कार्य निर्धारित समय के भीतर किया गया ।

झुनागिरि

सरकार कृषि ओर से झुनागिरि के ३१८ एकड़ क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाये गये और दूसरे १२० एकड़ में सीढ़ीनुमा खेत बनाने का कार्य सरकार द्वारा दिये हुये कर्जों की सहायता से बसने वालों ने किया । सरकार द्वारा स्वीकृत २०० एकड़ बाग लगाने की योजना के अन्तर्गत इस वर्ष १५ एकड़ क्षेत्र में फलों के पेड़ लगाये गये । लगभग ५२० एकड़ भूमि विभिन्न वर्गों के बसने वालों को बांटी गई और १३२ क्वार्टर बसने वालों ने प्राप्त हुये कर्जों की सहायता से निर्मित किये । उत्तर प्रदेश युद्धोत्तर सेवा पुनर्निर्माण निधि न्यास (U P. Post-War Services Reconstruction Fund Trust) से प्राप्त निधियों से एक स्कूल इमारत का निर्माण किया गया और पीने के पानी की पूर्ति के लिये ५० पी० गवर्नमेंट स्टोरेज टैंकों (उत्तर प्रदेश सरकार जल संग्रह तालाबों) का निर्माण हो रहा था ।

पुल का ४ मील रास्ता बनाने का कार्य पूरा किया गया और दूसरे ७ मील का निर्माण कार्य हो रहा था । इस क्षेत्र में सहकारी समितियों और उपभोक्ता सहकारी भण्डार (Store) का कार्य संतोषजनक रहा ।

मनूनगर के ५,००० एकड़ उपनिवेश में बसे हुये भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों की संख्या १९५१ के अन्त में १३२ थी। बसने वालों के १९६ क्वार्टर थे और रुद्रपुर-काशीपुर से मनूनगर तक एक पक्की सड़क का निर्माण हो रहा था। इस वर्ष तीन ट्यूब-वेल भी लगाये गये।

मनूनगर
(रामपुर
जिला)

भरसार की सिम्पुल इस्टेट (जिसका क्षेत्रफल ५०० एकड़ और जो पौड़ी के पश्चिम २४ मील पर स्थित है) जो कि प्रारम्भ में गढ़वाली भूत-पूर्व सैनिकों की बस्ती के सम्बन्ध में प्रयुक्त किये जाने के लिये थी, निकट भविष्य में लगाये जाने वाले सरकारी बाग के प्रयोजनों के लिये ले ली गई।

भरसार

लगभग २०,००० एकड़ भूमि कृषि योग्य बनाने की अफजलगढ़ योजना के सम्बन्ध में भी संतोषजनक प्रगति हुई। यह निश्चय किया गया कि १२,५०० एकड़ में खेती की जाय और शेष का एक भाग पुराने निवासियों के पास रहने दिया जाय और दूसरा भाग लकड़ी और चारे के रखैल (reserve) स्थान के काम में लाया जाय। लगभग २० क्वार्टर बनाये गये और यातायात के साधनों के सुधार के लिये कार्यवाही की गई। इस सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया कि भारत सरकार से प्राप्त की हुई निधियों की सहायता से जसपुर सड़क रेहार होती हुई अफजलगढ़ तक पक्की कर दी जाय और कालागढ़ अफजलगढ़ और अफजलगढ़-शेरकोट सड़क सेक्शनों का निर्माण कार्य इस वर्ष हाथ में लिया गया।

अफजलगढ़

उपनिवेशन विभाग में विभिन्न प्रकार की उपयोगी मशीनें, जो कि बिक्री सग्रहागारों (Disposals Depots) में उपलब्ध थीं, खरीदवाने के लिये एक लाइजन्स अफसर (सहकारिता अधिकारी) (बिक्री व्यवस्था) पूर्ववत् बना रहा। सड़क बनाने तथा मिट्टी बराबर करने के बहुत से औजार पूर्ति तथा बिक्री व्यवस्था के डाइरेक्टर जनरल, भारत सरकार से प्राप्त किये गये और वे तराई प्रदेश में यातायात के साधनों की उन्नति के सम्बन्ध में प्रयोग में लाने के लिये प्लानिंग तथा कांस्ट्रक्शन डिवीजन (इपक्रमण तथा निर्माण डिवीजन) तराई के इन्जीनियरिंग इंजीनियर को सप्लाई किये गये। उसी प्रकार दो अस्पताल यूनिट भी, जो कि सब प्रकार पूर्ण थे गंगा खावर और नैनीताल तराई में स्थापित अस्पतालों के लिये प्राप्त किये गये। उपकरण तथा स्थिर यंत्रों (tools and plants) के विशेष सेटों, जैसे यू० एस० के इचलन टूल सेट (Echelon tool sets) के अतिरिक्त कारखाने के काम की विभिन्न प्रकार की मशीनें भी मोल ली गईं।

बिक्री व्यव-
स्थालयों से
मोल ली
गई वस्तुएं

कांस उन्मूलन योजना (Kans Eradication Scheme) के अन्तर्गत झांसी जिले की सहरीनी तहसील में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के यूनिट की सहायता से पूर्ववत् कार्य किया गया। यह योजना इस क्षेत्र में बड़ी ही सर्वप्रिय थी और ट्रैक्टर से जोतने का मूल्य पिछले वर्ष के ३६ रु० ५ आना से बढ़कर ५२ रु० हो जाने पर भी कांस होने वाली भूमि के जोतने के सम्बन्ध में यूनिट की सहायता के लिये आवेदन-पत्र अधिकांश गांवों के किसानों से प्राप्त हुये। लगभग ६,००० एकड़ के सम्पूर्ण क्षेत्र में यूनिट ने जोताई करने का काम हाथ में लिया।

कांस उन्मूलन
योजना

यह कार्य २ जनवरी, १९५१ ई० को आरम्भ हुआ और ३१ मई को समाप्त हो गया और लगभग ६,३३४ एकड़ कांस जमने वाली भूमि, जिस में २,१२६ एकड़ बंजर भूमि सम्मिलित है, जोती गई। वर्ष के अन्त तक

ट्रक्टर की सहायता से जोती गई काँस जमने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल २७,४५४ एकड़ था।

इस वर्ष ट्रैक्टर से जोती हुई भूमि के ४०१ एकड़ में तीन नई सहकारी कृषिकर्म (Farming) समितियों का संगठन किया गया। इन सहकारी फार्मों में ट्रैक्टर का मूल्य केवल ३५ रु० प्रति एकड़ लगाया गया। काँस जमने वाली सम्पूर्ण भूमि किसानों की थी और ट्रैक्टर से जोतने के पश्चात् उन्हें लौटा दी गई। उन्होंने अनुसरण कार्य अपने निजी बैलो की सहायता से किया। इतना करने पर भी अभाग्यवश वर्षा के जल्दी हो जाने के कारण ऋतु रबी फसल के अनुकूल नहीं रही और २३६ एकड़ में बोवाई न की जा सकी। सब मिलाकर फसले पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खराब थी। फसलें और १६५१ ई० में जोती हुई भूमि की अतिरिक्त पैदावार केवल २०,१३३ मन के लगभग थी। वर्ष में ट्रैक्टर से जोते हुये सम्पूर्ण क्षेत्र की अतिरिक्त पैदावार लगभग ८२,३६२ मन थी।

४०—सार्वजनिक निर्माण कार्य

सड़के और पुल सड़क और भवन निर्माण सम्बन्धी सरकारी कार्यवाहियों में वित्तीय संकट के कारण बराबर बाधा पड़नी रही। फिर भी सड़क निर्माण कार्यक्रम (चरण १) के अग्रे निर्माण कार्यों के लिये १ करोड़ रुपये नियत करना तथा राज्य की पक्की सड़कों का और अधिक विस्तार करना सम्भव हुआ।

आलोच्य वर्ष के अन्त तक सार्वजनिक निर्माण विभाग की देखरेख में ८,४४२ मील लम्बी पक्की और ६,२२३ मील कच्ची सड़कें थीं जबकि १६४६ ई० में जब पंच-वर्षीय कार्यक्रम हाथ में लिया गया था, क्रमशः ४,७०० और ७५० मील लम्बी सड़कें थी। पक्की सड़कों में २,३५२ मील लम्बी स्थानीय निकायों की पक्की सड़कें भी शामिल हैं जिन्हें फिर से बनाया गया था। आलोच्य वर्ष में कुल २०० मील लम्बी सड़कों का निर्माण किया गया। फतेहपुर-चमोली सड़क पर पूर्विय नायर पुल और गोरखपुर-देवरिया सड़क पर फरेन लोहे का पुल, बदायूँ जिले में सौत नदी का पुल और पीलीभीत जिले में खेलरा पुल का निर्माण कार्य पूरा किया गया। कुछ दूसरे पुलों का काम भी शुरू किया गया, जैसे मेरठ-बरेली सड़क पर बाइगूल और भाकरा पुलों का निर्माण कार्य।

भवन

कुछ छोटे और बड़े भवनों का निर्माण कार्य भी पूरा किया गया। बड़ी इमारतों में प्रिंटिंग प्रेस की इमारत पूरी की गई, नया कॉन्सिलर्स रेजिडेंस का निर्माण कार्य समाप्त हुआ और लखनऊ के महात्मा गान्धी अस्पताल का विस्तार किया गया। मिर्जापुर में प्रस्तावित सरकारी सीमेन्ट फैक्टरी के निर्माण का कार्य चालू किया गया और उसमें बहुत सी नई इमारतें तैयार की गईं। विस्थापित व्यक्तियों के वास्ते इमारतें बनाने के लिये ५०.५ लाख रुपये खर्च करने का निश्चय किया गया और जब वर्ष समाप्त हुआ उस समय ४०० दुकानों के अतिरिक्त ४,००० 'सी' टाइप के और ३०० 'ए' टाइप के क्वार्टरों का निर्माण कार्य या तो पूरा हो गया था या हो रहा था।

गवेषणा

गवेषणाशाला में, जो भारत भर में अत्यन्त प्रकार की एक सुसज्जित प्रयोगशाला है, सीमेन्ट, चूना, ईंट, मिट्टी जैसी चीजों का परीक्षा कार्य होता रहा और यहाँ अन्य बातों के साथ-साथ पक्की सड़कों की उपयुक्तता, मिट्टी की मिलावट, स्थिरता पर वर्गीकरण के प्रभाव, इमारत के निर्माण में इस्पात के स्थान पर बाँस के उपयोग तथा मिट्टी के बने

घरों की स्थिरता की सम्भाव्यता की जाँच करने के उद्देश्य से प्रयोग किये गये।

४१—परिवहन

वित्तीय कठिनाई के कारण आलोच्य वर्ष में रोडवेज की गाड़ियाँ नये रास्तों पर प्रायः नहीं चलाई गईं। चलते वाली वर्तमान गाड़ियों को बनाये रखने तथा वर्कशाप के सगठन में सुधार करने की ओर विशेषरूप से ध्यान दिया गया। यू० पी० स्टेट रोडट्रान्सपोर्ट ऐक्ट, १९५०, १० फरवरी, १९५१ से प्रचलित किया गया।

वर्तमान गाड़ियाँ संतोषजनक रूप से चलती रही। वर्ष के अन्त में उन मार्गों की संख्या, जिनपर मोटरगाड़ियाँ चलती थीं, २४२ थी और ये गाड़ियाँ विभिन्न रोजनों में कुल ४,६६५ १/२ मील चलीं। कुल १,८७४ गाड़ियाँ थीं जिनमें १,३२४ बसें थीं, ४४६ ट्रकें थी और ५० टैक्सियाँ थी। इनके अतिरिक्त देखरेख तथा वर्कशाप के कामों के लिये पिकअप, स्टाफ कारे, ब्रेक डाउन लारियाँ इत्यादि थी। काम पर लगे हुये आदमियों की कुल संख्या ७,५३२ थी जिनमें से कार्यालय के अमले में १,८०५, ट्रैफिक के अमले में ४,२६० और वर्कशाप के अमले में १,४३७ आदमी काम करते थे।

आलोच्य वर्ष में नगर में चलने वाली बसें लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस और बरेली में चली और नगर के निकटवर्ती स्थानों में चलने वाली बसें देहरादून, मथुरा और फतेहगढ़ में चलीं।

परिवहन विभाग ने सवारियों को विभिन्न प्रकार के आराम की सुविधायें पहुंचाने के लिये सब कुछ किया। इनमें पानी पीने का प्रबन्ध, सवारियों के लिये शेड, महिलाओं के लिये टिकट खरीदने की अलग लिडकी, पेखाना, पेशाबघर, बेञ्च, पखे इत्यादि का प्रबन्ध सम्मिलित है। पिछले वर्ष की तरह बहुत से बस-स्टेशनों पर सवारियों के सामान लाने-ले जाने के लिये मजदूरों की व्यवस्था की गई। नियत कार्यक्रम के अनुसार समय से बसें चलती रहीं और इस प्रयत्न में काफी सफलता रही कि गाड़ियाँ ठीक समय पर छूटें। टिकटघरों में शिकायत की किताबें बराबर रखी रहती थीं और उनमें की गई प्रविष्टियों से शिकायतों को दूर करने में प्राधिकारियों को कुछ सहायता भी मिली।

अप्रैल से सितम्बर, १९५१ तक रोडवेज ने पूंजे पर व्यञ्ज, टूटफूट क्षति के व्यय, रख-रखाव के सुरक्षित कोष तथा मुख्य कार्यालय के कुल व्यय को पूरा करने के बाद शुद्ध राजस्व के रूप में १८,१५,८६० रु० २ आ० ४ पा० कमाया।

लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, अगगरा, मेरठ, बरेली तथा कुमायूं रोजनों के ३७ स्थानों के वर्कशाप के निर्माण का पहिला कार्य पूरा किया गया। इसकी एक सूची आगे दी जाती है।

१-रोडवेज संगठन
(क) सामान्य

(ख) मार्गों की संख्या जिन पर मोटरगाड़ियाँ चलती थीं

(ग) सिटी बस सर्विसे

(घ) सवारियों के लिये आराम की सुविधायें

(ङ) आय

(२) वर्कशाप का सगठन
(क) निर्माण तथा सेज

लखनऊ

इलाहाबाद

कानपुर

- १—चारबाग
- २—ओलिवर रोड
- ३—टेढ़ी कोठी
- ४—सीतापुर
- ५—उन्नाव

- १—अलबर्ट रोड
- २—जौरी रोड
- ३—मिर्जापुर

- १—कालपी रोड
- २—चुन्नीगंज
- ३—फतेहगढ़
- ४—फतेहपुर
- ५—इटावा
- ६—महोबा

. आगरा

मेरठ

बरेली

- १—खालियर रोड
- २—मथुरा
- ३—अलीगढ़
- ४—हाथरस
- ५—एटा
- ६—शिकोहाबाद

- १—मेरठ
- २—सहारनपुर
- ३—हरद्वार
- ४—देहरादून

- १—बरेली
- २—शाहजहाँपुर
- ३—मुरादाबाद
- ४—बिजनौर

गोरखपुर

कुमायूँ

- १—गोरखपुर
- २—आजमगढ़
- ३—बस्ती
- ४—गोडा
- ५—देवरिया
- ६—मुल्तानपुर

- १—काठगोदाम
- २—कोटद्वारा
- ३—रानीखेत

कानपुर का सेन्ट्रल वर्कशाप गाड़ियों की बड़ी-बड़ी मरम्मत करता रहा जिनमे इन्जनों और बटरियों को फिर से अच्छी हालत में लाना सम्मिलित था। गाड़ियों को धूल से बचाने, उनके डिजाइनों को उन्नत करन तथा उनकी बाड़ी बनान के सम्बन्ध म अच्छा काम किया गया।

प्राप्य धनराशि से जो अपरुडेट मशीनरी खरीद कर सेन्ट्रल वर्कशाप और रीजनल वर्कशापों में लगान का जो काम किया जा सकता था वह हाथ में लिया गया।

(ख) टेक्निकल कर्मचारिगर्ग की कमी की कठिन समस्या अब भी बनी रही। सेन्ट्रल वर्कशाप मे टेक्निकल शिक्षण योजना आरम्भ करके इसका एक दीर्घकालीन हल निकालने का प्रयत्न किया गया। वर्ष के अन्त में बीस टेक्निशियन आटोमोबाइल इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग ले रहे थे। पुलिस विभाग के १२ मिक्ैनिक भी ट्रेनिंग पा रहे थे।

(ग) गाड़ियों और कल-पुर्जों के आलोच्य वर्ष मे मूल्यों के और बढ जाने के फलस्वरूप गाड़ियों और उनके कल-पुर्जों को प्राप्त करने में कठिनाई हुई। बहरहाल किराये वही थे जो १९४९ में थे।

(घ) श्रम

वर्ष भर श्रमिकों के साथ सम्बन्ध संतोषजनक रहे। श्रमिकों के हितों के लिये कार्यवाहियों—जैसे कैंटीन तथा मनोरंजन केन्द्र खोलना—की ओर विशेषरूप से ध्यान दिया गया। बस पर चलने वाले अमले के कुछ श्रेणी के लोगों को यूनिकार्ड

की व्यवस्था की गई और मेले के सिलसिले में विशेषरूप से कठिन कार्य करने वाले कर्मचारियों को विशेष भत्ते तथा मानदेय दिये गये। उन ड्राइवरों को जिन्होंने अपनी गाड़ियों को अच्छी दशा में रख कर इन्जनों, टायरों और बटरियों से अच्छा काम लिया, इनाम भी दिये गये। १९५१-५२ में कुल लगभग १०,००० रुपया इनाम से दिया गया।

एक मोटर वेहिकल्स अफसर ने, जिसकी सहायता चार टेक्निकल इन्स्पेक्टर करते थे, सरकार के विभिन्न विभागों की मोटर गाड़ियों का सामयिक निरीक्षण किया। निरीक्षण की गई गाड़ियों की कुल संख्या १,६७३ थी जिनमें से ६८७ अच्छी हालत में थीं, ५७६ चालू हालत में थीं, परन्तु उनमें कुछ छोटो-मोटी मरम्मत की आवश्यकता थी, ३२४ खराब हालत में थी और ८६ गाड़ियाँ ऐसी थीं जिनकी मरम्मत कफायत के साथ नहीं की जा सकती थी।

(३) वैभागीक
गाड़ियों का
निरीक्षण

प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी अपने-अपने रीजनों में बराबर काम करते रहे। आम तौर पर प्रादेशिक परिवहन अफसरों के अधीन ड्राइवरों को लाइसेन्स देने तथा मोटरगाड़ियों की रजिस्ट्री करने और उन पर कर लगाने के कार्य को केन्द्रित करने का प्रयोग सतोषजनक रहा। राज्य में जिन मोटरगाड़ियों की रजिस्ट्री की गई उनकी संख्या ६,२६९ थी। जनवरी से लेकर दिसम्बर, १९५१ तक ७,४६७ ड्राइवरों के लाइसेन्स दिये गये और ३८,९३१ लाइसेन्सों का नवीकरण हुआ। १,७१६ भारी परिवहन गाड़ियों के सम्बन्ध में उनके फिट होने के प्रमाणपत्र दिये गये और १३,००० गाड़ियों के सम्बन्ध में उनके फिट होने के प्रमाणपत्र नये किये गये। ऐसे दस मामलों में इस प्रकार के प्रमाणपत्र रद्द कर दिये गये और १,२७० मामलों में ऐसे प्रमाणपत्र स्थगित कर दिये गये। निजी तौर पर रखी गई जनसेवा गाड़ियों की संख्या ९,६४३ थी इनमें से २,५७३ स्टेज गाड़ियाँ थीं, ४,४५४ पब्लिक कैरियर थी, २,०८२ प्राइवेट कैरियर थीं, ४७३ कंटेनर कैरिजेज थीं और ६१ लाश ढोने वाली गाड़ियाँ थीं। ये गाड़ियाँ राज्य परिवहन प्राधिकारी या सम्बन्धित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये परमिटों पर चलती रही।

(४) प्रादेशिक -
परिवहन
प्राधिकारी
तथा इन्स-
पेक्टर

मोटर वेहिकल्स ऐक्ट ऐन्ड रूलस के उपबन्धों का उल्लंघन करने के अपराध में एफोर्समेंट स्क्वाड ने ९,५४५ मुकदमे चलाये। जितने मुकदमे चलाये गये उनमें ७,६२५ मुकदमों में सजा हुई और १२३ मुकदमों में रिहाई का हुक्म हुआ।

(५) एफोर्स-
मेंट

पावर अल्कोहल उद्योग के हित में उत्तर प्रदेश में सितम्बर, १९५१ तक पेट्रोल की राशनिंग जारी रही। मई और जून के महीनों को छोड़ कर वर्ष भर पेट्रोल की सप्लाई संतोषजनक रही।

(६) पेट्रोल
राशनिंग
और पावर
अल्कोहल

लखनऊ का हिन्द फ्लाईंग क्लब और उसका इलाहाबाद तथा कानपुर में स्थित केन्द्र 'ए-१' और '२' बी लाइसेंसों के लिये बराबर पायलेटों को ट्रेन्ड करता रहा। इस क्लब के तत्वावधान में कानपुर में एक आल इंडिया एयर रैली हुई जिसमें उड़ान का प्रदर्शन देने के लिये समस्त देश के फ्लाईंग क्लबों ने भाग लिया और इस रैली के द्वारा विभिन्न क्लबों में प्रतियोगिता की अच्छी भावना जागृत हुई। भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस क्लब को काफी वित्तीय सहायता दी। वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के लिये राज्य सरकार ने कुल ५ लाख रुपया दिया।

(७) सिविल
एविएशन

खाद्य

(१) सामान्य
स्थिति और
स्टाक

अल्पाहार योजना (Austerity Provisioning scheme) और पूर्वी जिलों में अन्य प्रकार से सहायता देने के साधनों के विस्तार के कारण आलोच्य वर्ष में राज्य सरकार के राशनिंग सम्बन्धी वायदों में और अधिक वृद्धि हुई। इसके विपरीत खाद्यान्नों को राज्य में ही खरीद कर पर्याप्त परिमाण में प्राप्त करने की सम्भावना विभिन्न कारणों से बहुत कम हो गई। गत वर्ष बाढ़ों और बहुत दिनों तक सूखा पड़ने के कारण फसलों को अधिक हानि हुई थी। १९५१ ई० की रबी फसल को भारी हानि पहुंची, क्योंकि वर्षा की कमी के कारण बुवाई में काफी देर हो गई थी। भारत सरकार ने अगस्त, १९५० ई० में चने पर से नियन्त्रण उठा लिया जिससे कठिनाइयां बढ़ गईं, क्योंकि उससे रबी की ५० प्रतिशत खरीदारियां पूरी हो जाती थी। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक हो गया कि बाहर से बड़े परिमाणों में अनाज मंगाया जाय। राज्य में गेहूं और अन्य अनाजों की आवश्यकताये क्रमशः ३,०६,००० टन और १,३२,५०० टन थी। फिर भी अन्त में उत्तर प्रदेश की सरकार ने भारत सरकार को इस बात पर राजी कर लिया कि चने पर फिर से नियन्त्रण लगा दिया जाये। यह बात १० मई, १९५१ ई० को तय हुई और उसके फल-स्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार ५३,२९८ टन चना प्राप्त कर सकी। इस प्रकार मोटा अनाज भी अधिक प्राप्त हो गया और राज को भारत सरकार के बसिक प्लान के अधीन केवल २,३४,९४६ टन गेहूं और लगभग ३४,६६५ टन मोटा अनाज बाहर से मंगाना पड़ा।

प्रत्येक प्रकार से यह कोशिश की गई कि चावल की कुटाई में बचत हो सके। भारत सरकार के परामर्श से राज्य सरकार ने धान से चावल निकालने के लिये शेल्डर (sheller) प्रकार की मिलों को लगाने के लिये प्रोत्साहन दिया और राज्य में चावल निकालने के (हॉलिंग) मशीनों में पेंडी सेपरेटरो को बिना लगाये सभी खास खरीदारों के केन्द्रों में धान से भूसी अलग करके चावल निकालने के काम (हॉलिंग) को रोका। यद्यपि पेंडी सेपरेटरो के लगाने की लागत अधिक थी फिर भी यही एक तरीका था जिसके द्वारा चावल निकालने की प्रक्रिया में टूटे-फूटे चावलों और कनियों का प्रतिशत कम किया जा सकता था और सार्वजनिक हित के लिये ऐसा करना आवश्यक था। कठिनाई को दूर करने के लिये केवल उन्हीं छोटी-छोटी मिलों को, जो साधारण केन्द्रों में उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करती थी, काम करने की आज्ञा दी गई।

अधिक से अधिक ३ प्रतिशत से ५ प्रतिशत तक चावल पर पालिश करने के सम्बन्ध में भी प्रतिबन्ध लगाया गया जिसका उद्देश्य यह था कि चावल के स्वाद को नष्ट किये बिना ही उसकी पौष्टिक शक्ति बढ जाये। चावल की मिलों के लिये यह आवश्यक था कि वे अपने पास चावल पर पालिश करने के उस स्टैंडर्ड नमूने रखें।

• आवास गृहों के अहातों में अनाज उगाने के काम को प्रोत्साहन देने के लिये यू० पी० फूड प्रोग्राम राशनिंग आर्डर में यह सशोधन किया गया कि राशन कार्ड रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने आवास गृह के अहाते में उगाये हुए खाद्यान्नों को अपने उपयोग के लिये अपने पास रख सकता है यदि उसके अहाते का क्षेत्रफल एक एकड़ से कम हो। इस उपज का परिमाण राशन कार्ड के आधार पर उसे मिलाने वाले खाद्यान्न के परिमाण में से नही काटा जायगा।

यदि अहात का क्षेत्रफल एक एकड़ से अधिक होगा, तो एक एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की पैदावार अनुपात के अनुसार ही उत्पादक के राशन कार्ड से मिलने वाले खाद्यान्न में से काट ली जायगी।

१ जनवरी, १९५१ ई० को सरकार के पास निम्नलिखित खाद्यान्न थे :—

		टन
गेहूं	...	५७,९००
चावल	..	४०,७००
अन्य खाद्यान्न	...	२१,३००
योग	...	१,१९,९००

इस वर्ष गेहूं, जौ और इनके मिश्रण की सरकारी खरीद शीघ्र ही प्रारम्भ हो गई। मई, १९५१ ई० में चने की खरीद उस समय प्रारम्भ की गई जब उस पर फिर से नियन्त्रण लगा दिया गया था। पिछले वर्ष की भांति सभी खरीद वसूली के एकाधिकार प्रणाली के अनुसार की गई। सभी अधिक अन्न वाले क्षेत्रों का और कमी वाल क्षेत्रों में स्थित अधिक अन्न वाले स्थानों (पाकटों) का गल्ला बाहर जाने से रोक दिया गया और खरीद के बिज्ञापित केन्द्रों में व्यापारियों में से नियुक्त किये गये एजेंटों द्वारा खरीदारिया की गई। खरीद के केन्द्रों को बढ़ा दिया गया ताकि बाजार किसानों के और भी पास हो जायें और बड़े-बड़े फार्मों के मालिकों से सीधे ही अनाज खरीदने के लिये विशेष प्रबन्ध किये गये। यदि किसी फार्म के मालिक ने एक ट्रक भर या उससे अधिक अन्न बचना चाहा तो वह अन्न उस किसान के दरवाजे पर ही उससे ले लिया गया। सरकारी खरीद के केन्द्रों पर आये हुए सभी खाद्यान्नों की खरीद के लिये नियुक्त एजेंटों द्वारा ही सरकार की ओर से नियत दरो और किस्मों के अनुसार मोल ले लिया गया। खरीदारी के केन्द्रों में किसी अन्य एजेंटों को खरीद के लिये आज्ञा नहीं दी गई और अनधिकृत रूप से खाद्यान्नों को ले जाने को रोकने के लिये किसी भी व्यक्ति को खरीदारी के केन्द्र से २ १/२ मिन से अधिक खाद्यान्न ले जाने की आज्ञा नहीं दी गई। पूर्ववत् खरीदारी के उन केन्द्रों में जहाँ राशनिंग व्यवस्था नहीं थी, स्थानीय जनता के उपयोग के लिये सरकार द्वारा मोल लिये हुए खाद्यान्नों में से विवस्त्र फुटकर एजेंटियों द्वारा नियुक्त दरो पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न दिये गये। फुटकर वितरण पर भी कड़ी निगाह रखी गयी।

गेहूं की वसूली १४ ह० से १६ ह० प्रतिमन की दर से और जौ की क्रमशः १२ ह० और ११ ह० प्रतिमन की दर से की गई। इस वर्ष रबी के खाद्यान्नों की कुल खरीद इस प्रकार हुई:—

		टन
गेहूं	...	१,९८,३५२
चना	...	५३,३९८
जौ	...	५१,१८०
मिश्रित अनाज	...	५,११८
योग	...	३,०७,९४८

(२) रबी की वसूली

- (३) खरीफ वसूली की एकाधिकार प्रणाली के अन्तर्गत चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का की सरकारी खरीद अक्टूबर के अन्त में प्रारम्भ हुई। खरीफ के अनाजों विशेष रूप से चावल में कम वर्षा होने और सूखा के कारण हकावटें हुईं। पूर्वी जिलों में कोई भी वसूली नहीं हुई, क्योंकि उन जिलों में सबसे अधिक हानि हुई थी और वहाँ खाद्यान्नों की बहुत भारी कमी थी। नैपाल राज्य से भी चावल प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि नैपाल राज्य की सीमा के बाहर भारत को चावल भेजने पर लगाई गई रोक अभी तक लागू थी। फिर भी शुरू से ही अधिक से अधिक वसूलयाबी करने के लिये प्रबल प्रयत्न किये गये और धान की खरीदारी भी की गई। वसूलयाबी का काम करने वालों नान-गजटेड कर्मचारियों को उनके विशेष काम के लिये रूपयों के उभययुक्त पारितोषिक देने के वायदे किये गये।

- (४) आयात खरीफ की फसलों के अनाजों की वसूली करने के मूल्य की दरें निम्नलिखित और निर्यात थीं :—

			प्रतिमन	रु० आ० पा०
चावल प्रथम श्रेणी	२९	० ०
चावल द्वितीय श्रेणी	२१	४ ०
चावल तृतीय श्रेणी	१८	८ ०
चावल चतुर्थ श्रेणी	१४	८ ०
चावल पंचम श्रेणी	१२	० ०
बाजरा	११	० ०
ज्वार	१०	० ०
मक्का	१०	० ०

१९५१ ई० में खरीफ के खाद्यान्नों की कुल खरीद इस प्रकार हुई :—

			टन
चावल	१,१५,३७०
ज्वार	३०,२४७
बाजरा	३५,७१०
मक्का	६,४२५
योग	१,८७,७७९

भारत सरकार के बेसिक प्लान के अधीन इस राज्य को २,३४,९४६ टन गेहूं और ३४,६६५ टन मोटा अनाज प्राप्त हुआ।

“अधिक चावल बचाओ” आन्दोलन के फलस्वरूप राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा नियत किये गये ० भाग के अनुसार ३०,९४८ टन चावल बचाकर अन्य राज्यों और प्रशासनों को भेज सकी। भारत सरकार के आज्ञा-नुसार राज्य सरकार ने कुछ अन्य राज्यों और प्रशासनों को, जिन्हें बीज की आवश्यकता थी, बीज के लिये गेहूं, मक्का, बाजरा और ज्वार भी भेजी। इन बीजों के बदले भारत सरकार ने राज्य सरकार को आयात का गेहूं और, बाजरा दिया। यद्यपि राज्य सरकार को जिन दरों पर आयात के खाद्यान्न प्राप्त हुए, उसके द्वारा दिये गये बीज की दरों की अपेक्षा ऊंची थी फिर भी राज्य सरकार ने “अधिक अन्न उपजाओ” योजनाओं की सहाय्य के

उद्देश्य से अन्य प्रशासनों को ३,३२४ टन गेहूं के बीज और कुछ मात्राओं में मक्का, बाजरा और ज्वार दिया। राज्य सरकार ने भारत सरकार की आज्ञा के अनुसार १०,६७६ टन मोटा अनाज भी, जिसमें बीज के लिये दिया हुआ परिमाण भी सम्मिलित है, निर्यात किया।

गत वर्ष के अन्त तक ६२ नगरों में राशनिंग की व्यवस्था थी जिनमें से ५४ नगरों में पूर्ण राशनिंग और शेष नगरों में अंशतः राशनिंग थी। आलोच्य वर्ष में मसूरी, लैन्सडाउन और पौड़ी में पूर्ण राशनिंग के स्थान पर आंशिक राशनिंग की व्यवस्था की गई। इस प्रकार आंशिक राशनिंग वाले नगरों की संख्या बढ़कर ११ हो गई और पूर्ण राशनिंग वाले नगरों की संख्या घटकर ५१ रह गई। वर्ष के अन्त में पूर्ण राशनिंग वाले नगरों की जनसंख्या ६८,९४,२७३ थी और आंशिक राशनिंग वाले नगरों की जन संख्या ४,३६,६२५ थी। राशनिंग व्यवस्था के अधीन खाद्यान्न पाने वाली कुल जनसंख्या ७३,३४,१९८ थी।

(५) राशनिंग

जिन क्षेत्रों में अनाज की कमी बनी रही उन्हें छोड़ कर अन्य स्थानों में अप्रैल-मई में जबकि रबी की फसले कटकर आने लगी थी, अल्पाहार योजना बन्द कर दी गई। इस वर्ष वर्षा न होने के कारण राज्य के पूर्वी जिलों में अल्पाहार योजना को फिर से चलाने की आवश्यकता पड़ गई। इस योजना के अधीन ३१ दिसम्बर, १९५१ ई० तक प्रत्येक जिले में बांटे गये खाद्यान्नों का परिमाण और अन्य सहायता पाने वाले व्यक्तियों की संख्या निम्नांकित थी :-

(६) अल्पा-
हार योजना

जिले का नाम	सहायता-प्राप्त जन-संख्या	३१ दिसम्बर, १९५१ ई० तक वितरित खाद्यान्नों का परिमाण (मैनों में)
१ बस्ती	१२,८४,७४१	५८,९६२
२ बनारस	४०,०७३	१०,५७६
३ गाजीपुर	३,३३,१२६	४९,८३२
४ देवरिया	५,३७,७४९	७२,९७७
५ आजमगढ़	८,२८,१८१	१,०९,२२४
६ बलिया	६१,०३०	२४,९२४
७ गोरखपुर	८,९३,७१६	२१,६०,५६७
८ गोडा	३,००,०००	२९,४१५
९ जौनपुर	१,१०,४६८	३८,२४४
१० मिर्जापुर	२,३१,९२०	५०,३९२
११ बहराइच	अंक अप्राप्त	१,८७५
योग	४६,२२,००४	५,९६,६८८

(७) पर्वतीय क्षेत्रों में अन्न की व्यवस्था करने की योजना

नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल और टहरी-गढ़वाल के जिलों में पर्वतीय क्षेत्रों में अन्न की व्यवस्था करने की योजना लागू रही। इस योजना के अधीन २,५०,००० व्यक्तियों को अन्न की सहायता दी गई और खाद्यान्न की कुल खपत ९२० टन (२४,८४० मन) प्रति मास रही।

(८) मूल्य

१ फरवरी, १९५१ ई० से अस्थायी रूप से मैदा का फुटकर मूल्य १ सेर ४ छटांक प्रति रुपया से घटा कर १ सेर ३ छटांक प्रति रुपया कर दिया गया। १५ अप्रैल से १ सेर ४ छटांक प्रति रुपये की पुरानी दर फिर से कर दी गई।

मिलो (ज्वार) के समान आयात किया गया मोटे अनाज को जनवरी से राशनिंग के अन्नो में मिला दिया गया। इस अन्न के थोक और फुटकर मूल्य क्रमशः १० रुपये ३ आने १० पाई प्रतिमन और ३ सेर १२ छटांक प्रति रुपया कर दिया गया।

चने की वसुली का मूल्य १० रुपया प्रतिमन से बढ़ाकर १२ रुपये प्रतिमन कर देने के कारण उसके बेचने की दरों में भी संशोधन कर दिया गया और उन्हें १२ रु० १२ आने १० पाई प्रतिमन (थोक) और ३ सेर प्रति रुपया (फुटकर) रखा गया।

१६ जुलाई से चने के दाने (दला हुआ चना) की बिक्री की दरें १३ रु० १५ आ० ५ पाई प्रतिमन (थोक) और २ सेर १२ छटांक प्रति रुपया (फुटकर) निर्धारित की गई।

अक्टूबर, १९५१ ई० से चने की दाल की दरों का संशोधन किया गया और उन्हें १४ रु० १५ आने ९ पाई प्रतिमन (थोक) और २ सेर ९ छटांक प्रति रुपया (फुटकर) निर्धारित किया गया।

(९) राशन की सीमाय

साधारण और आगमेटेड (बढ़ाई हुई मात्रा वाले) यूनिटों के सम्बन्ध में १६ नवम्बर, १९५० से गृह की व्यक्तिगत सामुदायिक (Group) सीमाओं और सभी खाद्यान्नों की कुल सीमाओं में जो कमी की गई थी, वह १ जनवरी, १९५१ ई० से 'साधारण' यूनिट को ६ छटांक और 'आगमेटेड' (बढ़ाई हुई मात्रा वाल) यूनिट को ८ छटांक अन्न देकर पूरी कर दी गई। फिर भी भारत सरकार के निदेशों के अधीन व्यक्तिगत और सामुदायिक यूनिटों के लिये गेहूं और मोटे अनाज में १ फरवरी से फिर कमी करनी पड़ी। 'साधारण' और 'आगमेटेड' (बढ़ाई हुई मात्रा) के सम्बन्ध में क्रमशः ६ छटांक और ८ छटांक के स्थान पर ४ १/२ छटांक और ६ १/२ छटांक अन्न प्रतिदिन दिया जाने लगा। १६ फरवरी, १९५१ ई० से 'आगमेटेड' (बढ़ाई हुई मात्रा वाल) यूनिटों को फिर उतना ही राशन दिया जान लगा और जनवरी, १९५० ई० में जिस हिसाब से राशन दिया जाता था वह फिर से लागू कर दिया गया। १६ जून, १९५१ ई० से 'साधारण' उपभोक्ताओं के लिये कुल राशन की मात्रा ६ छटांक प्रतिदिन कर दी गई। १ फरवरी से १५ जून तक फैक्टरियों में अधिक मेहनत करने वाले मजदूरों और शिक्षक संस्थाओं के छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को ६ छटांक प्रति यूनिट प्रति दिन के हिसाब से अन्न दिया जाने लगा। ऐसी यूनिटों को 'एनलाइव्ड यूनिट' कहा गया।

चन को फिर से राशनिंग में ले लिया गया और १ जून से उसे राशन की इकानों में इस प्रकार बेचा गया कि "साधारण यूनिटों" पर प्रतिदिन १/२ छटांक प्रति यूनिट की दर है और "आगमेटेड यूनिटों" पर प्रतिदिन २ छटांक प्रति यूनिट की दर से मिलने लगा।

अगस्त से पर्वतीय क्षेत्रों में अन्न व्यवस्था भोजन के अधीन प्रति व्यक्ति के लिये प्रति दिन राशन के कुल खाद्यान्न की मात्रा ४ छटांक निर्धारित कर दी

गयी। अल्पाहार योजना (Austerity Provisioning Scheme) के अधीन कुल ३ छटांक राशन का अन्न दिये जाने की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

१६ सितम्बर से पश्चिमी जिलों के "साधारण" उपभोक्ताओं के लिये चावल की मात्रा घटाकर प्रतिदिन प्रति यूनिट $1\frac{1}{2}$ छटांक कर दी गई। १६ अक्तूबर से पूर्वी और पहाड़ी जिलों में 'साधारण' उपभोक्ताओं के लिये प्रति यूनिट प्रति दिन दिये जाने वाले २ छटांक चावल को कम करके $1\frac{1}{2}$ छटांक कर दिया गया। इस कमी को पूरा करने के लिये सारे राज्य में गेहूं और आटा नम्बर १ के राशन की मात्रा $1\frac{1}{2}$ छटांक बढ़ा दी गई।

अगस्त के महीने में रात्रानिग व्यवस्था वाले नगरों (रेग्युलेटेड टाउन) में जाली और "मरे हुए" व्यक्तियों (घोस्ट) राशन कार्डों की जांच करने के लिये एक विशेष आन्दोलन किया गया। आन्दोलन के परिणामों का संक्षिप्त विश्लेषण नीचे दिया जाता है :—

(१०) राशन कार्डों की जांच के लिये विशेष आन्दोलन

(१) उपयोग में न लाये जाने वाले राशन कार्डों की संख्या जिन्हें निकाल दिया गया	७०,४७०
(२) उपयोग में न लाये गये और बढ़े हुए यूनिटों की संख्या			२,७४,४५९
(३) झूठे और जाली यूनिटों की संख्या जिन्हें निकाल दिया गया	...		३,०१,३२५
(४) सरकारी खाद्यान्नों की अनुमानित मासिक बचत			२,८५८ मट

खाद्यान्न के लिये उचित गोदामों की व्यवस्था करने की समस्या पर विशेष ध्यान दिया गया। १९५१ ई० के प्रारम्भ में राज्य सरकार के पास विभिन्न स्थानों में १,३४६ खतियां थी, जिनमें लगभग $7\frac{1}{2}$ लाख मन अनाज रखा जा सकता था और कानपुर के रेग्युलेटेड टाउन में एक पक्का गोदाम था। इस वर्ष के दौरान में खीरी और बदायूं में कई खतियों का निर्माण प्रारम्भ किया गया। मूल युद्धोत्तर पुनर्निर्माण योजना के अनुसार, जिसके अधीन ४०० खतियां बनाने की योजना बनाई गयी थी, कोच, उरई और औरध्या में से प्रत्येक में पचास-पचास खतियां और बरेली तथा शाहजहांपुर में प्रत्येक में पचास-पचास गोदाम बनाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही थी, परन्तु सरकार को १९४६ ई० के प्रारम्भ में अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के शुरू करने के कारण यह निर्माण कार्य स्थगित करना पड़ा। यू० पी० (टेम्पोरेरी) रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ ई० की, जिसके द्वारा खाद्यान्नों का संग्रह करने के लिये स्थान प्राप्त करने और इस प्रकार प्राप्त किये गये स्थानों के बदले प्रतिकर की धनराशियां निश्चित करने की व्यवस्था की गई थी, अवधि बढ़ा दी गई। यू० पी० स्टोरेज रिक्वीजीशन (कंटीन्यूयेन्स आफ पावर) ऐक्ट, १९४९ ई० के द्वारा इस ऐक्ट की अवधि ३१ दिसम्बर, १९५१ ई० तक प्रहिले ही बढ़ा दी गई थी, किन्तु इससे स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अतएव इस ऐक्ट की अवधि एक वर्ष के लिये और बढ़ा दी गई।

(११) गोदाम

भारत सरकार ने अक्तूबर, १९५० ई० में शक्कर पर जो सिलेक्टिव कंट्रोल लगाया था वह इस आलोच्य वर्ष भी लागू रहा। भारत सरकार ने ईख पैदा करने वालों और शकर बनाने वालों, दोनों को प्रोत्साहित करने के लिये गन्ने का न्यूनतम मूल्य १ रुपया १० आना प्रतिमन से बढ़ाकर १ रुपया १२ आना प्रति मन

शक्कर और गुड़

कर दिया और राज्य के पश्चिमी और पूर्वी भागों की फैक्टरियों द्वारा बनाई हुई एफ० ए० ब्यू० शकर (ई-२७ ग्रेड) के एक्स फैक्टरी मूल्य क्रमशः ३० रु० ८ आना प्रति मन और ३२ रु० प्रति मन कर दिया। ग्रेड के अनुसार मूल्यों का अन्तर ज्यों का त्यों बना रहा। प्रत्येक फैक्टरी के लिये शकर उत्पादन का अधिकतम परिमाण निश्चित कर दिया गया और इस निश्चित किये गये परिमाण से अधिक बनाई गई शकर को खुले बाजार में बेचने की आज्ञा उत्पादकों के लिये दे दी गई।

शकर के अधिकतम निश्चित परिमाणों में फैक्टरियों से भारत सरकार को जितनी शकर मिलती रही, उसी में से वह इस राज्य को शकर देती रही। इस राज्य के ५१ जिलों के लिये नियत किया गया और तत्सम्बन्धी जिलाधीशों द्वारा मनोनीत की गई विश्वस्त एजेंसियों द्वारा निर्धारित मूल्य पर यथोचित रूप से शकर वितरित की गई। इस राज्य में “न कोई लाभ और न कोई हानि” के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में फैक्टरियों से प्राप्त शकर के परिमाण का हिसाब लगाकर शकर के थोक और फुटकर मूल्य समान रूप में निर्धारित किये गये। फिर भी राज्य सरकार के लिये ऐसा प्रशासन-कर, जो ऐसे कुल निर्धारित मूल्य (पूल प्राइस) पर चार आने प्रतिमन से अधिक न हो, वसूल करने की अनुमति दी गई। बेसिक पूल एक्स-फैक्टरी मूल्य ३१ रु० ८ आना प्रति मन निर्धारित किया गया, जिससे ३ आने १० पाई प्रति मन ही प्रशासकीय कर के रूप में बच सका। अधिकतम फुटकर मूल्य १३ आने ९ पाई प्रति सेर निर्धारित किया गया और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को पहले की तरह यह आदेश दिया गया कि वे तदनुसार ही थोक और फुटकर मूल्यों को निर्धारित करें और देहाती तथा पर्वतीय क्षेत्रों के मूल्यों के अन्तर ज्यों के त्यों बनाये रखें। १९५१ ई० के वर्ष के लिये आम जनता, लाइसेंस प्राप्त फल संरक्षण कर्ताओं (फ्रूट प्रोजरक्स), हलवाईयों, कन्फेक्शनरों, बिस्कुट बनाने वालों और उद्वासित हलवाईयों के लिये और जन्माष्टमी, दशहरा, दीवाली और क्रिसमस जैसे त्योहारों के अवसरों पर अतिरिक्त शकर के रूप में देने के लिये इस राज्य की सरकार के लिये १,३४,०८१,९१ टन शकर का कोटा नियत किया गया, किन्तु वर्ष के उत्तरार्ध में भारत सरकार ने इस राज्य के शकर के कोटा को बढ़ा दिया और तदनुसार जिलों के कोटे भी बढ़ा दिये गये। स्थिति सामान्यतः संतोषजनक हो गई और दानेदार शकर खुले बाजार में मिलने लगी, यद्यपि खुले बाजार में उसका मूल्य नियन्त्रित मूल्य की अपेक्षा अधिक रहा। गुड़ और खाडसाले शकर के मूल्यों के नियन्त्रण वर्ष भर ज्यों के त्यों बन रहे। वर्ष के उत्तरार्ध में इन वस्तुओं की सप्लाई करने की स्थिति अधिक अच्छी रही। १९५१ ई० की समाप्ति के कुछ पूर्व आरम्भ होने वाले सीजन में दानेदार शकर के उत्पादन में अधिक वृद्धि होने की संभावना प्रतीत होने लगी थी, जिसके कारण यह आशा की गई कि अगले वर्ष भी सम्पूर्ण राज्य में शकर की स्थिति अधिक अच्छी रहेगी।

वनस्पति धी

भारत सरकार की ओर से राज्य सरकार ने वनस्पति धी की किस्म और कीमत के सम्बन्ध में नियन्त्रण लागू रखा। यह नियन्त्रण डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों, स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारियों (हेल्थ अफसरों) और सप्लाई अधिकारियों द्वारा किया गया और भारत के वनस्पति धी के नियंत्रक अधिकारी (बेलीटेबिल आयल प्रोडक्ट कंट्रोलर) की नवीनतम आज्ञाओं में यह उल्लेख किया गया कि सम्बन्धित अधिकारियों को वनस्पति धी के थोक व्यापारियों के मुहुरबन्द पात्रों और फुटकर दूकानदारों

के खुले पात्रों में से नमूने के तौर पर ३ पौन्ड बनस्पति घी उसकी किस्म की जाँच करने के लिये निकालना चाहिए और यदि नमूने में कोई मिलावट पाई जाय तो बनस्पति घी के बनाने वाले थोक या फुटकर विक्रेता, जैसी भी दशा हो, के विरुद्ध मुकद्दमा चलाया जाय। इन आज्ञाओं को कड़ाई से लागू किया गया और बनस्पति घी के मूल्यों पर भी सावधानी से निगाह रखी गई, जिससे कि यह सुनिश्चित हो जाय कि भारत के बनस्पति घी के निर्यातक (बेजिटेबिल आयल प्रोडक्ट्स कंट्रोलर) द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये मूल्यों पर ही उसकी बिक्री की जाती है।

सूती वस्त्र

इस वर्ष के प्रारम्भ में कपड़े का व्यापार संकटापन्न अवस्था में था, क्योंकि उस समय कपड़ की अत्यधिक कमी थी जो अधिकांशतः कपड़े के उत्पादन में कमी, कपड़े के अत्यधिक निर्यात और नियन्त्रित दरों पर कपास न मिलने के कारण हुई।

इस स्थिति पर काबू पाने के लिये भारत सरकार ने मार्च, १९५१ ई० से यह प्रतिबन्ध लगा दिया कि कपड़े के कुल उत्पादन का ४० प्रतिशत तक ही कपड़ा बाहर भेजा जाय। उसके बाद ही उत्पादन पर नियन्त्रण लगा दिया गया और मिलों को यह आदेश दिया गया कि वे धोतियों और साड़ियों के बचाने के लिये ४८" से ५८" रीड-स्पेस वाले ५० प्रतिशत करघों (Looms) का प्रयोग करे। इन करघों में से ३० प्रतिशत की धोतियों के बनाने में आवश्यकता हुई। छपाई और रंगाई पर भी प्रतिबन्ध लगाये गये और किसी भी मिल को किसी भी महीने में अपने उत्पादन के १० प्रतिशत से अधिक माल के छापने और रंगने की अनुमति नहीं थी, जब तक कि किसी अन्य आधार पर उसे ऐसा करने की अनुमति दे दी गई हो। इसके साथ ही यह भी प्रयत्न किये गये कि नियन्त्रित दर पर मिलों को कपास मिल सके। अप्रैल, मई, जून और जुलाई, १९५१ ई० के नियत कोटे का परिमाण और घटाकर उत्पादन का १० प्रतिशत तक ही कर दिया गया। बाद में अगस्त के बाद से वह कोटा बढ़ाकर उत्पादन का २५ प्रतिशत कर दिया गया। जून, १९५१ ई० से मिलों का "अनियन्त्रित बिक्री (free sale)" का कोटा जो उत्पादन का ३३ १/३ प्रतिशत निर्धारित किया गया था, घटाकर २० प्रतिशत कर दिया गया।

राज्य सरकार ने कपड़े की बिक्री को उचित रूप से नियमित करने के लिये कार्टर्वाई की। खाद्यान्न के राशन कार्डों के आधार पर उपभोक्ताओं को कपड़े के वितरण की विधि प्रारम्भ की गई और जिन नगरों में खाद्यान्न के नियन्त्रण की व्यवस्था नहीं थी वहाँ (नान-रेग्युलेटेड टाउन) कपड़ा मोल लेने के लिये शहर के राशन कार्डों को वैध कर दिया गया। होटलों में रहने वालों और विद्यार्थियों के लिये भी कपड़ा देने की व्यवस्था की गई। यू० पी० मार्केटिंग फेडरेशन की ८७ उचित मूल्य पर बिक्री करने वाली दुकानें (Fair Price Shops) और मिलों के ६१ विशेष फुटकर बिक्री के डिपो (स्पेशल मिल डिटेल डिपो) उपभोक्ताओं में कपड़े का वितरण करने के लिये खोले गये। वितरण के लिये दिये गये कपड़े पर लाभ का अंश भी निश्चित कर दिया गया। विवाहों और कपड़ के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित कपड़े के विशेष परमिटों की व्यवस्था की गई।

देहाती क्षेत्रों में भी कपड़े के वितरण को नियमित कर दिया गया और जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर के महीनों में देहाती क्षेत्रों में कपड़े की सप्लाई की मात्रा में कुछ वृद्धि कर दी गयी। "अन्न वसूली योजना" के सम्बन्ध में कपड़े की ३,५०० गाँवों के बॉटने की व्यवस्था की गई।

इस स्थिति का सामना करने के लिये किये गये विभिन्न उपायों का सम्मिलित प्रभाव यह हुआ कि साधारण उपभोक्ताओं को अधिक कपड़ा मिलने लगा। फिर भी उत्कृष्ट (फाइन) और अत्युत्कृष्ट (सुपर फाइन) किस्मों के कपड़ों के मूल्य जो अमेरिका, मिश्र और सूडान की रूई के मूल्यों के अधीन थे, बढ़े चढ़े रहे। पिछले चार महीनों के मूल्यों की अपेक्षा अप्रैल से सितम्बर, १९५१ ई० तक के अत्युत्कृष्ट कपड़ों के मूल्य लगभग ३३ प्रतिशत से ३५ प्रतिशत तक अधिक रहे। स्वाभाविक रूप से माध्यम (मीडियम) और मोटे कपड़ों की मांग अधिक रही और अप्रैल से सितम्बर, १९५१ ई० तक के उत्कृष्ट (फाइन) और अत्युत्कृष्ट (सुपर फाइन) कपड़ों के स्टॉक को बेचना कठिन हो गया। इसलिये व्यापारियों को ऐसी सुविधाये दी गई, जिससे कि वे अपने पास एकत्रित कपड़ों के स्टॉक को बेच सकें। अस्थायी रूप से इस राज्य के एक जिले से दूसरे जिले में कपड़ा लाने के जाने की आज्ञा दे दी गई और कई प्रकार के कपड़ों पर से राशन संबंधी प्रतिबंध उठा लिये गये।

सूत के संबंध में ऐसी कार्रवाई की गई कि प्राप्त माल का अधिकांश बुनकरों (Weavers) को मिल सके। यह तैयार हुआ कि ऐसे कपड़ा बनाने वालों का सूत देना बंद कर दिया जाय, जो ३१ दिसम्बर, १९४६ ई० से पहले यह व्यापार नहीं करते थे या जिन्हें पहिले नियमित रूप से सूत का कोटा नहीं मिलता था। फिर भी उद्वासित व्यक्तियों को ऐसी फैक्ट्रियों को, जो ३१ दिसम्बर, १९५० ई० को विद्यमान थी, सूत की सप्लाई करने के लिये मान्यता प्रदान की गई।

बुनकरों को उनके मंडलों और सहकारी समितियों के द्वारा सूत बांटा गया। हाथ से छपाई और रंगाई करने वालों को भी कपड़ा सप्लाई करने की व्यवस्था की गई।

भवन निर्माण
सामग्री
(लोहा,
इस्पात,
सीमेंट और
कोयले का
चूरा)

वर्ष के आरम्भ में नियंत्रित भवन-निर्माण-सामग्री की स्थिति संतोषजनक रही। पिछले कुछ महीनों में कोयले के चूरे की सप्लाई में निरंतर प्रगति बनी रही।^{१०} इससे यह समझा गया कि भविष्य में भी स्थिति ऐसी ही सुगम बनी रहेगी और इसके फलस्वरूप ईंटों पर से नियंत्रण हटा लिया गया। लोहे, इस्पात, सीमेंट और कोयले की खानों से मिलन वाले कोयले के चूरे पर भी नियंत्रण पूर्ववत् बना रहा।

१९५१ ई० की दूसरी तिमाही से अर्थात् अप्रैल से स्थिति क्रमशः बिगड़ने लगी।^{११} मुख्यतः वैगनों की कमी के कारण कोयले के चूरे की सप्लाई संबंधी स्थिति विशेष रूप से बिगड़ी हुई पाई गई और जुलाई के महीने में इस राज्य को कुल केवल १०२ वैगन कोयले का चूरा मिला, जब कि मासिक कोटा २,५१२ वैगन का था। इस वर्ष की प्राप्तियों का परिमाण केवल १३,४६४ वैगन रहा, जबकि कुल नियत किया गया परिमाण (टोटल अलाटमेंट) ३०,१४४ वैगन था। स्वभावतः इसका प्रभाव ईंटों के प्रचलित बाजार भाव पर पड़ा जो कमी के स्थानों में फिर बढ़ गया।

कुल मिलाकर सीमेंट की सप्लाई उतनी कम नहीं रही जितनी कि कोयले के चूरे की। २,४१,२३८ टन माल की कुल प्राप्तियां हुईं, यद्यपि भारत सरकार ने इस राज्य के लिये २,६४,००० टन का कोटा इस वर्ष भर के लिये नियत किया था, फिर भी जो परिमाण नियत किया गया वह प्राप्त नहीं था। राज्य का कोटा जो अप्रैल, १९५१ ई० से पूर्व प्रतिमास लगभग ३१,००० टन का होता था, अप्रैल में कम कर के प्रतिमास २३,००० टन कर दिया गया और जुलाई में तो

और भी अधिक घटाकर १६,००० टन कर दिया गया। फिर भी जनता की सप्लाई पर उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि सरकारी विभागों की सप्लाई पर, जो महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के लिये अपेक्षित थी। सरकारी विभागों को भेजे जाने वाले माल में विशेषतः कमी रही क्योंकि सीमट के कुछ कारखाने अपने उत्पादन के एक निश्चित अनुपात से अधिक माल विशेष सरकारी दरों पर देना नहीं चाहते थे और उन्होंने माल रोक लिया।

जो ० सी० शीट, पाइप और काटेदूर तार जैसी कुछ विशेष वगों की चीजों को छोड़कर, जिनकी सप्लाई बहुत कम रही, इस पूरे वर्ष में लोहे और इस्पात की स्थिति बराबर संतोषजनक बनी रही। इस राज्य के लिये लोहे और इस्पात का कुल कोटा ५२,५५२ टन नियत किया गया था। किन्तु उसे कुल ४६,८०९ टन ही माल मिला। जिन मालों की सप्लाई प्रचुर मात्रा में थी और जो माल (स्टाक) रखने वालों के पास बहुत जमा हो गये थे उनकी निर्वाधि बिक्री के लिये प्रान्तीय लोहे तथा इस्पात के नियंत्रक (Provincial and Steel Controller) समय-समय पर आज्ञा देते रहे। गांवों में लोहारों के काम के लिये लोहारों को नियंत्रित साधनों से लोहा और इस्पात देने के प्रयोजन से बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, फैजाबाद, सुलतानपुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी के सान जिलों में एक योजना प्रयोग के रूप में चलाई गई।

आलोच्य वर्ष में ढलाई-घरों के लिये कच्चे लोहे (पिग-आइरन) का कोटा और इस्पात तैयार करने वाले उद्योगों के लिये लोहे और इस्पात का कोटा राज्य सरकार के नियंत्रण में संक्रामित कर दिया गया। भारत सरकार ने कच्चे और पक्के लोहे तथा इस्पात के कोटे सीधे ही इस राज्य के ढलाई-घरों और इस्पात तैयार करने के उद्योगों के लिये नियत करने के बजाय इन चीजों के कोटी को, राज्य के प्राधिकारियों द्वारा वितरित किए जाने के लिये, इस राज्य सरकार के अधिकार में दे दिया। केवल कुछ बड़े बड़े ढलाई-घर और विशिष्ट उद्योग ही, जिनमें सौ से अधिक श्रमिक काम करते थे, भारत सरकार की सूची में बने रहे।

१९५१ ई० में इस राज्य में नमक की सप्लाई साभर, खारगोदा, धरंगधर, नमक बम्बई और कलकता से होती रही। भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय योजना (Zonal Schemes) के अंतर्गत इस राज्य को प्रति मास दिये गये २,८५३ मीटर-टोन वैनलों के कुल कोटे में से १,५५३ वैनलों की प्रतिमास सामूहिक सप्लाई साभर से होनी थी। इस वर्ष के लिये नियत किये गये कुल कोटे की तुलना में कुल २२,६९७ वैनन प्राप्त हुए। वर्ष के प्रारम्भ में प्राप्तियां अत्यंत असंतोषप्रद थीं। जनवरी से मार्च तक की अवधि के नियत परिमाणों (allocation) तथा प्राप्तियों के संबंध में नीचे दिये हुए अंकों से पता चलता है कि प्राप्तियां कितनी कम थीं :

मास	नियत परिमाण	प्राप्ति
जनवरी ..	२,७०५	१,५२८
फरवरी ...	२,७०५	१,४०४
मार्च ...	२,७०५	१,६२०

नमक की सप्लाई प्राप्त करने में मुख्य कठिनाई निकासी के स्थान पर नमक की कमी नहीं थी वरन् परिवहन की कमी थी। यह कहा जाता था कि पश्चिमी तट के बन्दरगाहों से खाद्यान्नों को अधिक मात्रा में भेजने के कारण रेल के मार्ग पर आवागमन बहुत अधिक था और वगने उपलब्ध नहीं थीं। मुख्यतः सांभर झील से जो अवध-तिरहुत-रेलवे के जिलों में नमक की सप्लाई का प्रधान साधन था, नमक की सप्लाई न हो सकने के कारण इन जिलों में मार्च के महीने में वस्तुतः नमक की कमी हो गई। किसी सीमा तक इसकी पूर्ति कलकत्ते से ब्राड-गेज-रेलवे पर स्थित स्थानों को और फिर वहाँ से अवध-तिरहुत रेलवे के अभीष्ट स्थानों को विशेष सप्लाइयाँ पहुंचाने का प्रबंध करके की गई। इस प्रकार के विशेष प्रबंधों के अनुसार एक गाड़ी नमक पर्वतीय जिलों में उपयोग के लिए गढ़वाल को विशेषरूप से भेजा गया था।

सांभर से ३४ विशेष गाड़ियों (रेक्स) के भेजने आदि के संबंध में भारत सरकार के निर्माण कार्य, उत्पादन तथा सप्लाई के मंत्रालय से व्यवस्था की गई थी। कुछ कठिनाइयों के होते हुए भी उक्त प्रबंध सफलता से हो गया और कमी को पूरा करने का प्रयत्न किया गया। अपर्याप्त वर्षा तथा सांभर में कम उत्पादन के परिणामस्वरूप वर्ष के बाद के छः महीनों में नई कठिनाइयाँ उपस्थित हो गईं। नमक के नियंत्रक को इस साधन से मिलने वाले नमक की सप्लाई में तुरंत और काफी सीमा तक कमी करनी पड़ी। जिन जिलों को सांभर से नमक मिलना बंद हो गया था उनके लिये दूसरे साधन से नमक की सप्लाई की व्यवस्था करने में कुछ समय लगा। सांभर का नमक अन्य सब नमकों की अपक्षा सस्ता होने के कारण आयात करने वाले और उपभोक्ता दोनों ही अधिक महंगे नमक की सप्लाई प्राप्त करने के लिये उत्सुक नहीं थे। अक्तूबर और नवम्बर विशेष कठिनाई के महीने थे। दिसम्बर में तो स्थिति काफी संभल गई क्योंकि उस महीने में २,८५३ वगनों के नियत परिमाण की तुलना में कुल २,५१४ वगन मिल गई।

मिट्टी का तेल

वर्ष के आरम्भ में मिट्टी के तेल की सप्लाई संतोषजनक रही और १९५० ई० के बाद के ६ महीनों में स्थिति में जो सुधार हुआ था वह भलीभांति बना रहा। जनवरी, फरवरी और मार्च, १९५१ ई० की प्राप्तियाँ १९४१ ई० की ३,६०,००० टन प्रति मास की तुलना में लगभग ५,५०,००० टन प्रति मास थी। ईरान के राजनैतिक परिवर्तनों के फलस्वरूप, जिससे एंग्लो ईरानियन आयल कंपनी के निर्यात पर प्रभाव पड़ा, सप्लाइयो में सामान्यतः कमी हो जाने के कारण मार्च के बाद स्थिति बिगड़ गई। बम्बई से अधिक मात्रा में खाद्यान्नों के आने के कारण रेल द्वारा माल लाने जाने की कठिनाइयो और वगनों की कमी से कुछ क्षेत्रों में स्थिति और अधिक जटिल हो गई और झांसी, जालौन, बाँदा तथा हमीरपुर के जिलों में और अवध-तिरहुत रेल मार्ग से सम्बद्ध अन्य स्थानों में विशेष कमी बनी रही। ईरान से भिन्न देशों की मिट्टी के तेल की कंपनियों से तेल का आयात होने पर और बुंदेलखंड के जिलों के लिये वगने मिल जाने पर वर्ष के अंत में स्थिति सुधर गई। कुछ कंपनियों ने ब्राड-गेज के स्थानों से मोटर-गेज के जिलों को सप्लाई भेजने की व्यवस्था की। सप्लाई की अस्थिरता के कारण इस वर्ष मिट्टी के तेल के मूल्य और वितरण पर नियंत्रण बना रहा।

इंधन

राज्य के प्रमुख नगर क्षेत्रों में घरेलू इंधन की सप्लाई की समस्या पहले जसी ही कठिन बनी रही। जमींदारों के निजी जंगलों से पड़ों के गिराने पर प्रतिबंध के कारण नगरों में मिलने वाले इंधन की मात्रा में कमी हो गई। पत्थर के जलान के कोयले की सप्लाई, जो घरेलू इंधन के विकल्प के रूप में काम में लाया जाते हैं अनिश्चित और अनियमित थी।

नियंत्रित जगलो से मिलने वाले ईंधन में भी सहसा कमी हो गई । १९४६-५० ई० की १,१६,०७,००० मन की तथा १९५०-५१ ई० की ८०,३६,००० मन की उपलब्ध मात्रा की तुलना में १९५१-५२ में केवल ५५,००,००० मन की उपलब्धि रही । दूसरी ओर नागरिक जनता की ही नहीं, अपितु सेना तथा उद्योगों की भी माँग बढ़ी-चढ़ी रही । सबसे भारी माँग शकर मिलों की थी जिसके लिये कुल सप्लाई का ६० प्रतिशत से भी अधिक भाग अपेक्षित था । इसलिए उपलब्ध स्टॉक को पूर्णरूप से राशनिंग करनी पड़ी और वैगनों की व्यवस्था के आधार पर सभी उपभोक्ताओं के लिये बराबर-बराबर वितरण किया गया । नियंत्रित ईंधन की लकड़ी की सप्लाई, जिन नगर-क्षेत्रों में की जाती थी, उनकी संख्या २० से बढ़ कर २५ हो गई ।

• नियंत्रण की मुख्य विशेषताएं (क) मूल बनो की ईंधन की लकड़ों का रेल तक ढुलाई-व्यय मिलाकर, मूल्य-निर्धारण, (ख) राशनिंग के अधीन वितरण-योजना के अनुसार मूल बन के स्टेशनों से माल ले जाने पर नियमन और (ग) माल पहुंचने के स्थानों पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों द्वारा माल के मूल्य पर नियंत्रण और उसका वितरण । विध्य प्रदेश के कुछ अंतर्क्षेत्रों का उत्तर प्रदेश में विलयन हो जाने से नियंत्रण के क्षेत्र का विस्तार हो गया । इस वर्ष नागर-क्षेत्रों में वितरण के नियंत्रण को पुनर्संगठित करने के लिये भी कार्यवाहियाँ की गईं । दो यू० पी० फारेस्ट प्रोड्यूस (मूवमेंट ऐंड प्राइस) कंट्रोल आर्डर, १९५१ ई० से जो दो यू० पी० फारेस्ट प्रोड्यूस (मूवमेंट ऐंड प्राइस) कंट्रोल आर्डर, १९४५ ई० तथा यू० पी० फायरवुड ऐंड चारकोल (मूवमेंट) कंट्रोल आर्डर, १९४५ ई० के स्थान पर प्रवृत्त किया गया, पिछली आज्ञाओं के दोष दूर हो गये और उसमें और कुछ ऐसे नये उपबंधों का समावेश किया गया जो नियंत्रण को कार्यान्विष्ट करने में आवश्यक समझ गये ।

उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण ऐक्ट, १९५० ई० जो कुछ प्रकार की आयात की हुई औषधियों के मूल्य तथा वितरण पर नियंत्रण करने वाले यू० पी० ड्रग्स (कंट्रोल) ऑर्डिनेंस, १९४६ ई० के स्थान पर प्रवृत्त किया गया था, १९५१ ई० के उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण (संशोधन और अधिकार को जारी रखने का) अधिनियम द्वारा १९५१ ई० में भी लागू रखा गया । भारत सरकार के निदेशों के अनुसार नियंत्रण कार्यान्वित किया गया । भारत सरकार औषधियों की सप्लाई स्वतंत्र रूप से व्यापार के साधारण साधनों द्वारा होने देना चाहती थी, किन्तु इसके साथ ही वह इस बात को भी सुनिश्चित कर देना चाहती थी कि उसके द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य की सीमा से अधिक मूल्य न बढ़ने पाये । अधिकतम मूल्य से अधिक मूल्य पर दुर्प्राप्य भण्डों के बेचे जाने के संबंध में समय-समय पर शिकायत आती रही और स्टॉकिस्टों से द्रव्यों का पालन कराने के लिये कठोर कार्यवाहियों की गईं । कानपुर के तीन प्रमुख स्टॉकिस्टों को निवारक निरोध अधिनियम के अधीन यह सुनिश्चित करने के लिये गिरफ्तार रखा गया कि वे व्यापार के ऐसे ढंगों को काम में न ला सकें, जो नियंत्रण आज्ञाओं के प्रतिकूल हों । इसका प्रवर्तन इस बात से सामंजस्य कठिन हो गया था कि उपभोक्ताओं में बहुत कम व्यक्ति पुलिस या जिला नियंत्रण प्रशासन (District Control Administration) में शिकायत करते थे ।

औषधियाँ

पूरे १९५१ के वर्ष में भारत सरकार का सप्लाई ऐंड प्राइसेज आफ गुड्स ऐक्ट, १९५० ई० लागू रहा । इस अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के अधिकारों के रूप में काम किया और प्रस्तुत वर्ष में उन्हें अनेक प्रकार के मालों पर, जिनमें औद्योगिक उत्पादन के लिये उपयोगी कच्चा माल भी सम्मिलित था, लागू किया । ड्रग्स कंट्रोल ऐक्ट की भांति सप्लाई

उपभोक्ताओं संबंधी माल

एण्ड प्र.इसेज आफ गुड्स ऐक्ट में केवल अधिकतम मूल्य के प्रवर्तन के संबंध में व्यवस्था की गई थी। फिर यह देखने में आया कि अधिकांश मामलों में नियंत्रित माल के मूल्य अधिकतम मूल्य से काफी कम रहे।

मकान के
किराये और
उसके उठाने
पर नियंत्रण

रहने के स्थान के नियंत्रण को, जिनमें मकान के किराये और उसे किराये पर उठाने का नियमन होता है, जारी रखना इसलिये आवश्यक हो गया कि नगरों में जनसंख्या तो बराबर बढ़ती गई; किन्तु उसी अनुपात से प्रा.प्य निवास-गृहों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई। यू० पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट एण्ड एविकेशन ऐक्ट के सशोधन से, जिनके अनुसार १ जनवरी, १९५१ ई० के बाद बने हुए भवनों को इस अधिनियम के अधिक्षेत्र से निकाल दिया गया, नए भवनों के निर्माण में किसी हद तक प्रोत्साहन मिला, किन्तु उसके पूर्ण प्रभाव का अनुभव नहीं किया जा सका। मुख्यतः मुद्राबाजार की तेजी तथा अपने निजी निवास के लिए घर बनवाने वालों की अपने-अपने मकान बनवाना शुरू करने की असमर्थता के कारण निर्माण कार्य की गति उतनी तेज नहीं रही जितनी कि उसकी आशा थी। यह भी देखने में आया कि जो व्यक्ति व्यापारिक आधार पर मकान बनवा सकते थे वे भी ऐसा करने के लिये उत्सुक नहीं थे। इसका कारण अंशतः तो यह था कि उन्होंने व्यापार के अन्य क्षेत्रों में रुपया लगाना अधिक लाभप्रद समझा और अंशतः यह कि यद्यपि नए भवनों पर किराए तथा किराये पर उठाने के संबंध में तो नियंत्रण लागू नहीं होंगे तो भी सरकारी मांगों से मुक्त न हो सकेंगे।

प्रस्तुत वर्ष में इस संबंध में एक विशेष बात यह हुई कि कंट्रोल आफ रेन्ट एण्ड एविकेशन ऐक्ट के अधीन मुकद्दमें बहुत बढ़ गये। प्रायः सभी वर्ग के व्यक्तियों में जैसे किरायेदार, उप-किरायेदार और मकान के स्वामी उक्त अधिनियम के अधीन स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा दी गई आज्ञाओं का विरोध करने और उनके विरुद्ध मामलों को कोर्टों के न्यायालयों में ले जाने की प्रवृत्ति पाई गई। इस मुकद्दमेबाजी का अधिकांश भाग उक्त अधिनियम की धारा ७ तथा ७-क के अधीन था।

अधिनियम की धारा ३ का भी कार्यान्वित किया जाना कुछ कठिन प्रतीत हुआ। मकान मालिकों की यह शिकायतें थी कि उन्हें उन किरायेदारों को अपने मकानों से निकालने की अनुमति जल्दी नहीं दी जाती, जिन्हें वे अपने मकानों में रखना नहीं चाहते। इसके विपरीत किरायेदारों की यह शिकायतें थीं कि उक्त अनुमति बहुत स्वतंत्रता से दी जाती है। कई स्थानों पर मकान मालिकों की यह प्रवृत्ति भी देखी गई कि वे पानी तथा बिजली काटने की कार्रवाई करके अधिनियम के उपबंधों की उपेक्षा करते थे। किरायेदावों के संघों की ओर से बड़ी सख्या में निवेदन-पत्र प्राप्त हुए जिनमें उन्होंने उक्त अधिनियम में ऐसे नए उपबंधों का समावेश करने के सुझाव रखे थे, जिससे कि वे मकान मालिकों की ओर से किए जाने वाले उक्त कार्यों से बच सकें। मकान के स्वामियों और किरायेदारों के विरोधी दावों को निपटाने और अधिनियम की विभिन्न धाराओं में पाई गई कमी को दूर करने के लिये किराये तथा किराये पर मकान उठाने के नियंत्रण संबंधी संपूर्ण विषय नियंत्रण जांच समिति (कंट्रोल इक्वायरी कमेटी) के पास निर्णय के लिये भेज दिया गया। समिति ने प्रभावित जनता के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को बुलाया और अधिनियम के अधीन होने वाली कार्रवाई की जांच करने के प्रयोजन से विभिन्न स्थानों के दौरे भी किए। वर्ष की समाप्ति पर समिति की रिपोर्ट तैयार हो रही थी।

नये सविधान के अधीन छवनी (कैन्टूनमेंट) के क्षेत्र में किराये तथा किराये पर मकान उठाने के नियंत्रण का विनियमन केन्द्रीय सरकार का विषय हो जाने के कारण उक्त क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किया जाने वाला नियंत्रण

बंद कर दिया गया। किंतु छावनी के क्षेत्रों के संबंध में केन्द्रीय सरकार का कोई उपयुक्त अधिनियम न होने के कारण मकानों का किराया बहुत बढ़ गया और मकान के स्वामियों द्वारा की जाने वाली बेदखलियों की संख्या में भी वृद्धि हो गई। अंत में केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श पर वर्ष की समाप्ति के समय इस राज्य के अधिनियम के आधार पर छावनी के क्षेत्रों में किरायेदारों की सुरक्षा प्रदान करने के लिये विधान बनाने के संबंध में कार्यवाही की।

१९५१ ई० में यू० पी० कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविकेशन ऐक्ट के अतिरिक्त यू० पी० (टेम्पोरेरी) एकमोडेशन रिक्वीजिशन ऐक्ट तथा यू० पी० (टेम्पोरेरी) स्टोरेज रिक्वीजिशन ऐक्ट नामक दो अन्य अधिनियम भी लागू रहे। इन दोनों अधिनियमों को कार्यान्वित करने में सामान्यतः इस नीति का अनुसरण किया गया कि जहाँ तक हो सके कम से कम स्थान (एकमोडेशन) की माँग की जाय और विशेषतः ऐसी माँग उसी समय की जाय जब वह नितरित अनिवार्य हो।

१९५१ ई० में नियंत्रण संबंधी आज्ञाओं के उल्लंघन के ४,८५१ मामले प्रवर्तन निपटाये गये। इनमें से ३,६५३ मामले में दंड दिया गया और १,१९८ में अभियुक्त मुक्त किये गये। अधिकांश अभियोग उन व्यक्तियों के विरुद्ध थे जो या तो विनियंत्रित वस्तुओं को चोरी से ले गए थे या जिन्होंने ऐसा करने का प्रयत्न किया था या जिन्होंने चोर-बाजारी के मूल्य पर माल बेचा था।

प्रस्तुत वर्ष में प्रवर्तक दलों ने विभिन्न नियंत्रण आज्ञाओं के उल्लंघन के संबंध में १,३०६ मामले पकड़े। इनमें से ५५२ सूती कपड़े के मामले थे। उन्होंने १,६५७ व्यक्तियों को बंदी किया और लगभग ५,३९,५६६ रु० की लागत का माल पकड़ा।

खाद्य तथा रसद विभाग से अवांछनीय व्यक्तियों (तत्वों) को निकाल देने का भी प्रयास किया गया। बदनामी, भ्रष्टाचार इत्यादि के संबंध में विभागों द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप जनवरी, १९५१ ई० से दिसम्बर, १९५१ ई० तक १४९ व्यक्ति नौकरी से निकाले गये या हटा दिये गये। ३२ व्यक्तियों को अन्य प्रकार से दंड दिया गया और ४ व्यक्तियों ने त्याग-पत्र दिए।

विभिन्न प्रचलित नियंत्रणों के प्रशासन की जाँच करने तथा उनको चलाने के संबंध में सुधारों का सुझाव देने के लिये १९५० ई० के अंत में सरकार द्वारा नियुक्त की गई नियंत्रण जाँच समिति बराबर अपना काम करती रही और उसने अपनी कई बैठकें की। उसने सूती कपड़े के वितरण और खाद्यपदार्थों की वसूली के संबंध में सरकार के पास अपनी अंतरिम सिफारिशें भेजीं। नियंत्रण जाँच समिति की उपसमितियों ने जिलों में नियंत्रण के प्रचालन के संबंध में इस राज्य के विभिन्न जिलों में दौरे किये जिससे कि वे जाँच समिति को अपने प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त जानकारी से अवगत करा सके। समिति ने अपनी उपसमितियों की रिपोर्टों पर विचार किया, किन्तु वह अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप न दे सकी, क्योंकि उसके अधिकतर सदस्य वर्ष के अंतिम भाग में साधारण निर्वाचन संबंधी कार्य में व्यस्त रहे।

नियंत्रण जाँच
समिति

४३--सहायता तथा पुनर्वास

राज्य सरकार के समक्ष विस्थापित व्यक्तियों की समस्या एक मुख्य प्रश्न बना रहा। ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या ४ १/२ लाख से भी अधिक थी जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति पर बहुत अधिक भार पड़ा।

सहायता शिविर

फिर भी सरकार द्वारा विस्थापित व्यक्तियों के प्रगतिशील पुनर्वास कार्य के फलस्वरूप सहायता शिविरों की संख्या ११ से घटकर ६ हो गई। शिविरों की आबादी भी १६,३८१ से घटकर १३,५०८ रह गई। मुफ्त में भोजन का दिया जाना केवल आश्रम तथा इन्फर्मरी मेरठ और मथुरा गृह के १७६ व्यक्तियों तक ही सीमित था। देहरादून में प्रेमनगर शिविर को विस्थापित व्यक्तियों का नगर के रूप में बदल देने के कार्य में काफी प्रगति हुई और वर्ष के समाप्त होने पर यह कार्य लगभग पूरा होने को था। म्युनिसिपल बोर्ड के प्रशासन की सुविधा के हेतु सहारनपुर वही दो बस्तियों को शीघ्रातिशीघ्र म्युनिसिपल बोर्ड को सौंप दिये जान तथा विस्थापित व्यक्तियों के निवास के लिये ज्योंही कोई अन्य स्थान प्राप्त होता है, आई० ई० एम० ई० लाइस, शाहजहांपुर में शेष बचे हुए बैरको (Barracks) को जिनमें विस्थापित व्यक्ति रहते हैं, फौजी अधिकारियों को वापिस लौटा देने का प्रस्ताव विचार-धीन था।

आश्रम और इन्फर्मरी

शासन संबंधी कारणों से ऋषिकेश स्थित इन्फर्मरी (आश्रय गृह) शरणार्थी महिला उद्योग मन्दिर के महिला गृह (Women's Home) की शाखा बनाये जाने के हेतु ९ सितम्बर को मेरठ बदल दिया गया था। भारत सरकार के आज्ञानुसार दरभंगा कंसिल, इलाहाबाद स्थित महिला गृह (Women's Home) १० सितम्बर को बन्द कर दिया गया और वहाँ के निवासियों को फिरोजपुर (पंजाब) मेरठ और मथुरा के आश्रमों में भेज दिया गया। इन आश्रमों के निवासियों को निःशुल्क रहने का स्थान तथा भोजन के अतिरिक्त लाभप्रद व्यापारों में व्यावसायिक ट्रेनिंग भी दी गई। इन आश्रमों और आश्रय गृहों (इन्फर्मरी) में प्रत्येक व्यक्ति पर २५ रु० प्रति मास की दर से व्यय हुआ।

एसी महिलाओं के लिये जिन्होंने गृहों में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर ली थी और जो इन संस्थाओं से स्वतन्त्र होकर आजीविका कमाने की इच्छुक थीं, २५० रु० के ३३ पुनर्वास सम्बन्धी अनुदान स्वीकृत किये गये थे। इन अनुदानों का तात्पर्य उन्हें कपड़ा सिलने या दूसरी छोटी-छोटी मशीनों तथा वस्तुओं को खरीदने में सहायता देने से था, ताकि वे छोटे-मोटे व्यापार व व्यवसाय स्थापित कर सकें।

नकद भत्ते

१४ विस्थापित व्यक्तियों को उनकी आजीविका के लिये नकद भत्ता दिया गया।

चिकित्सा सम्बन्धी सहायता

यू० पी० के निराश्रित विस्थापित व्यक्तियों की चिकित्सा सम्बन्धी सहायता के हेतु भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृत २५,००० रु० का तदर्थ अनुदान विस्थापित व्यक्तियों के लिये भुवाली सेनिटोरियम में निःशुल्क पलंग (Beds) दिलाने व सुरक्षित कराने में व्यय हुआ। ऐसे पलंगों (Beds) की संख्या १८ थी। राज्य के चिकित्सा सम्बन्धी अधिकारियों को यह भी नीति थी कि विस्थापित व्यक्तियों में क्षय-रोग के संकेत रोगियों को असुरक्षित निःशुल्क पलंगों (Beds) पर, यदि ऐसे स्थान (Beds) प्राप्त हैं, पलंग दिलाये जायें। इसके अतिरिक्त विस्थापित व्यक्तियों के लिए राज्य की सामान्य जनता की भांति सरकारी अस्पतालों व औषधालयों में निःशुल्क दवाइयां तथा चिकित्सा सुलभ थी।

मेरठ तथा मथुरा में स्थित महिला गृहों के व्यावसायिक केन्द्र, जो अब तक अलग-अलग माने गये थे, इन गृहों के अखंड भाग बनाये जाने के लिये पुनःसंगठित किये गये। नौ अन्य केन्द्रों—लखनऊ, बनारस, आगरा, मुरादाबाद, चम्बौसी, सहारनपुर, हरद्वार, गाजियाबाद और कानपुर—में भी व्यावसायिक ट्रेनिंग दी जाने लगी। इन केन्द्रों में ट्रेनिंग पान वालों की संख्या ७०० थी। जब कि स्वीकृत संख्या ५५० थी। २५० शिक्षार्थी ट्रेनिंग पूरी कर रहे थे। बरेली स्थित ट्रेनिंग तथा उत्पादन केन्द्र की तरह के केन्द्र उन योग्य निजी संस्थाओं को, जो आवश्यक योग्यता और साधनों से युक्त समाजसेवकों की हों तथा जो उन्हें सरकार से प्राप्त कुछ अनुवर्तक अनुदान की सहायता से चलाने के इच्छुक हों, हस्तारित किये जाने का प्रश्न विचाराधीन था।

(१) बापू इण्डस्ट्रियल होम, देहरादून—वर्ष के अन्त में देहरादून स्थित बापू इण्डस्ट्रियल होम (Bapu Industrial Home) में १८० शिक्षार्थी थे। इस राज्य सरकार ने १९४९ में पश्चिमी पाकिस्तान से आई हुई विस्थापित महिलाओं और बालिकाओं को उन्नत व्यावसायिक और टेक्निकल ट्रेनिंग देने के लिये स्थापित किया था। इस संस्था में अब तक ३८९ महिलाएं और बालिकाएं ट्रेनिंग ले चुकी हैं। ट्रेनिंग के समय शिक्षार्थियों को २५ ह० मासिक छात्र-वैतन दिया गया।

शिबिर के बाहर रहने वाली महिलाओं के लिये ट्रेनिंग तथा उत्पादन केन्द्र

उन्नत व्यावसायिक और टेक्निकल ट्रेनिंग

(२) इण्डस्ट्रियल होम चुनारगढ़ (जिला मिर्जापुर)—चुनारगढ़ इण्डस्ट्रियल होम (Industrial home) में प्रौढ़ व्यक्तियों को उन्नत व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा देने का प्रबन्ध सुयोग्य शिक्षकों से युक्त सर्वांगीण, औद्योगिक विभाग में किया गया। पूर्वी पाकिस्तान से आई हुई निराश्रित विस्थापित महिलाओं के लिये १९५० के अन्त में स्थापित ८०० व्यक्तियों के लिये स्वीकृत गृह में ३०० बालिग, १० और १५ साल के बीच की उम्र के १५९ लड़के, ५ और १० साल के बीच की उम्र के २५० बच्चे और ५ साल तक की उम्र के १०० शिशु रहते थे। बालिग शिक्षार्थियों को निःशुल्क ट्रेनिंग, मकान, चिकित्सा तथा अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति पर २५ ह० प्रति मास की छात्र-वृत्ति भी दी गई। गृह के अन्य निवासियों के प्रति भी आवश्यक ध्यान दिया गया। अल्पवयस्क ट्रेनिंग तथा उत्पादन विभाग में जाते थे और ५ और १० साल के बीच की उम्र के बच्चों को गृह में खोली गई प्राइमरी पाठशाला में शिक्षा दी जाती थी। ५ साल से कम उम्र के शिशुओं की देख-रेख एक सुयोग्य नर्स द्वारा शिशुआलय में होती थी। १२ ह० प्रतिमास की दर से भोजन का भत्ता बच्चों के लिए उनकी उम्र का विचार न करते हुए दिया गया। उन्हें बे-किराया रहने का स्थान, चिकित्सा इत्यादि भी दी गई। वर्ष के अन्तिम दिनों में चुनारगढ़ गृह की संख्या ५० प्रतिशत बढ़ाये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था।

केन्द्रीय सरकार और पश्चिमी बंगाल की सरकार के सुझाव पर उत्तर प्रदेश की सरकार न वृन्दावन, इलाहाबाद और बनारस में पाकिस्तान से आई हुई बड़ी विस्थापित महिलाओं के लिये तीन विशेष गृह (कुल मिला कर ४०० व्यक्तियों के स्थान के लिये) स्थापित करने की स्वीकृति दी। इन गृहों में प्रति व्यक्ति २५ ह० प्रति मास की दर से व्यय किया जाने को था।

पूर्वी पाकिस्तान से आई हुई बड़ी विस्थापित महिलाओं के लिये विशेष गृह

विस्थापित व्यक्तियों को जो पुनर्वास सम्बन्धी सुविधायें प्रदान की गईं वे निम्नलिखित हैं :—

पुनर्वास सम्बन्धी कार्यवाहियाँ

शिक्षा, व्यावसायिक तथा टेक्निकल ट्रेनिंग, रोजगार व पुनर्वास (व्यापार, उद्योग, खेती इत्यादि में) और ऋण व अन्य सुविधायें (जैसे विद्युत् शक्ति, लोहा तथा दीन, चीनी इत्यादि का दिया जाना।)

(क) शिक्षा विस्थापित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता देने की योजना में भारत सरकार ने पुनः जुलाई में संशोधन किया। यद्यपि पुस्तक और लेखन-सामग्री खरीदन के लिये प्रति विद्यार्थी ५ रु० की नकद सहायता केवल प्राइमरी कक्षा के विद्यार्थियों को ही दी जा सकती थी, परन्तु जुलाई तक जारी योजना के अनुसार प्राइमरी कक्षा के सब विद्यार्थियों और कक्षा ६ से लेकर १० तक के सब योग्य छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जा सकती थी। कुछ शर्तों पर हाई स्कूल से ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियों को भी छात्र-वेतन मिल सकता था। संशोधित योजना के अनुसार भी प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षा निःशुल्क रही लेकिन नकद अनुदान ५० प्रतिशत विद्यार्थियों के लिये ही सीमित रहा। फिर भी किसी भी विद्यार्थी को जिसके पिता या अभिभावक की आय १०० रु० प्रति मास से अधिक हो यह सहायता नहीं मिल सकती थी। निःशुल्क शिक्षा और पुस्तक-खरीदन के लिये नकद अनुदान ६ से लेकर ८ तक की कक्षाओं के ५० प्रतिशत छात्रों और कक्षा ९ तथा १० के ४० प्रतिशत छात्रों को ही स्वीकृत हो सकता था। फिर भी निःशुल्क शिक्षा तथा नकद अनुदान का दिया जाना विद्यार्थियों के पिता या अभिभावक की आय पर निर्भर था। कक्षा ६ से लेकर ८ तक के छात्रों के सम्बन्ध में आय की सीमा १०० रु० थी जबकि कक्षा ९ और १० के छात्रों के लिये १५० रु० थी। हाई स्कूल से ऊपर की कक्षाओं के लिये छात्र-वेतन प्राप्त कर सकने का स्तर कुछ नीचा कर दिया गया। टेक्नोलॉजिकल (Technological) और व्यावसायिक पाठ्यक्रम में, जिनके लिये सहायता दी जा सकती थी, कुछ और विषय सम्मिलित कर दिये गये। पहली बार उन पोस्ट ग्रेजुएट (Post Graduate) विद्यार्थियों के लिये भी छात्र-वेतन का प्रबन्ध किया गया जो डिग्री (Degree) परीक्षा में कुल अंकों का ६० प्रतिशत प्राप्त किये हों। इस वर्ष ९,८६,४३२ रु० निःशुल्क शिक्षा व नकद सहायता के रूप में क्रमशः २१,११६ छात्रों और २५,१३१ विद्यार्थियों को दिये गये, और १,२८,६०० रु० का छात्र-वेतन ४२६ छात्रों को दिया गया। ऐसे विद्यार्थियों को ऋण भी दिया जा सकता था जिन्हें पहले भी ऋण मिला हो और जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिये छात्र-वेतन के बदले ऋण लेना चाहते हो। इस वर्ष ऐसे १४ विस्थापित विद्यार्थियों को १८,६३० रु० का ऋण दिया गया।

(ख) व्याव-
सायिक और
टेक्निकल
(Technical) ट्रेनिंग
श्रम मन्त्रालय (भारत सरकार) के टेक्निकल ट्रेनिंग केन्द्रों में ५०३ विस्थापित व्यक्तियों और राज्य की कुछ फैक्टरियों (Factories) और वर्कशॉप (Workshop) में ५०० व्यक्तियों की ऐपरेन्टिस (Apprentice) की ट्रेनिंग देने की योजनायें जारी रखी गईं। श्रम मन्त्रालय के केन्द्रों में गैर-सैनिकों (Civilians) के लिये निर्धारित किये गये स्थानों में भी विस्थापित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी गई। उनको कैलिको छापने, रंगने और चमकाने, काटने तथा सिलने और छांटने तथा खेल-कूद के सामान तैयार करने की व्यावसायिक ट्रेनिंग की सुविधाएं प्रदान करने के प्रयोजन से भारत सरकार ने ९६ अतिरिक्त सीटों की स्वीकृति दी थी। भारत सरकार ने १०० विस्थापित व्यक्तियों को राज और कारीगरी की ट्रेनिंग देने की योजना भी स्वीकार की। इस योजना के चालू होने से उत्तर प्रदेश में श्रम मन्त्रालय के केन्द्रों में कुल ३,३६२ विस्थापित व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी गई और वर्ष समाप्त होने पर ३९९ व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी।

वह योजना, जिसके अनुसार सरकारी शिविरो में ट्रेनिंग तथा उत्पादन केन्द्र विस्थापित व्यक्तियों के लाभ के लिये खोले गये थे, चालू रही। फिर थोड़े से केन्द्र बंद कर दिये गये और हस्तिनापुर, मोदीनगर और नैनी के उप-नगरों में तीन नये केन्द्र खोले गये। दिसम्बर के अंत तक इन केन्द्रों में कुल मिलाकर ४,५६५ व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। दिसम्बर के अंत तक डालीगंज

लखनऊ के ट्रेनिंग तथा उत्पादन केन्द्र में, जो जापानी यंत्रों से सुसज्जित था, ४८ विस्थापित व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी गई और ८४ को ट्रेनिंग दी जा रही थी। मई में रामपुर के ट्रेनिंग तथा कार्यकारी केन्द्र को भारत सरकार से राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और वर्ष के अंत तक ४७ विस्थापित व्यक्ति उसमें ट्रेनिंग पा रहे थे। राज्य सरकार के अधीन ट्रेनिंग योजना के अनुसार पहिले पहल अप्रैल से प्रत्येक शिक्षार्थी को ३० ६० मासिक छात्र-वैतन देने की व्यवस्था की गई थी। टेनिकल शिक्षार्थियों को ऋण देने के लिये कुटीर उद्योगों के डाइरेक्टर को २ लाख रुपये की धनराशि नियत की गई।

विस्थापित व्यक्तियों को नौकरी की सुविधाएँ देने के लिये आयु और शिक्षा संबंधी योग्यताओं के प्रतिबंध में ढिलाई देने के निमित्त सरकारी आदेश प्रचलित रखे गये और समस्त वैभागीक अध्यक्षों इत्यादि पर यह जोर दिया गया कि जिन खाली जगहों की भर्ती सीधे की जाती है उनकी सूचना रोजगार दिलाने के दफ्तरो (इम्प्लायमेंट एक्सचेंज) को दी जानी चाहिये ताकि उपयुक्त विस्थापित व्यक्ति वंचित न रह जाय। रेलवे में वर्ग ४ की खाली जगहों के लिये भी, जिनकी सूचना रेलवे प्राधिकारियों ने दी थी, विशेष चुनाव किये गये पुनर्वास तथा नियोजन डाइरेक्टरेट विस्थापित व्यक्तियों को काम दिलाने का प्रयत्न करता रहा। वर्ष के अंत तक २१,१७९ विस्थापित व्यक्तियों को सरकारी तथा गैर-सरकारी नौकरियाँ दिलाई गईं।

(ग) नौकरी

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विस्थापित डाक्टरों, वैद्यों और हकीमों के पुनर्वास की योजना चालू रखी गई और १९५१ ई० में इस योजना के अनुसार १७ डाक्टरों, ११ वैद्यों तथा हकीमों को सहायता मिल रही थी। सरकार जिन चिकित्सकों को जिस अवधि के लिये राज-सहायता देने को राजी हुई थी उनमें से अधिकतर चिकित्सकों के संबंध में यह आशा की जाती थी कि १९५२ ई० के अंत तक यह अवधि समाप्त हो जायगी और तत्पश्चात् वे स्वावलम्बी हो जायेंगे।

(घ) डाक्टरों, वैद्यों इत्यादि को फिर से बसाना

इस वर्ष ४,५०० परिवारों को व्यवसाय, व्यापार, पेशे और उद्योग में फिर से लगने की सुविधाएँ प्रदान करने के लिये २६,४५,००० ६० का ऋण दिया गया और २८,७४,५४० ६० की धनराशि इसलिये ऋण के रूप में दी गई जिससे विस्थापित व्यक्तियों के १,९२१ परिवार खेती-बाड़ी के काम में फिर से लग जायें। इनके अतिरिक्त पुनर्वास वित्त प्रशासन ने ३१ दिसम्बर तक ७४,३२,९०० ६० की धनराशि ऋण के रूप में दी। यह आशा की जाती थी कि पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत २२,४५० परिवार राज्य सरकार से लिये गये १,३०,२९,००० ६० ऋण और २५,००० परिवार बिना राज्य सहायता के ३१ मार्च, १९५२ ई० तक व्यापार, व्यवसाय और उद्योग में लग जायेंगे। इसके अतिरिक्त यह भी आशा की जाती थी कि मार्च, १९५२ ई० के अंत तक ४,९५० परिवार सरकारी ऋणों से (कुल मिलाकर ४२,५२,५०० ६०) जो कि भारत सरकार के कोष से प्राप्त हुये थे, उपनिवेशन तथा अन्य क्षेत्रों में खेती के काम में लग जायेंगे।

(ङ) ऋण तथा अन्य सुविधाएँ

ऋणों के अतिरिक्त इस वर्ष उपनिवेशन क्षेत्रों में बसने वाले ४,९५० परिवारों में से २,९०० परिवारों को बसाने में एक करोड़ से अधिक रुपया व्यय हुआ। इस व्यय का एक अंश यानी २० लाख रुपया भारत सरकार ने दिया। विस्थापित व्यक्तियों को राज्य के विभिन्न जिलों में उद्योग-धंधे चलाएँ के लिये २,६०० हार्स पावर से अधिक बिजली, इसमें नैनी और गोविन्दपुरी को दी गई बिजली शामिल नहीं है, दी गई। विस्थापित फ़ैब्रीकेटर्स (अनिर्माताओं) को उनके काम के लिये लोहा और इस्पात का ८०० टन का कोटा बढ़ाकर १,००० टन कर दिया गया।

डालीगंज, लखनऊ की डिहाइड्रेशन फैक्टरी के एक भाग को छोड़ कर, जिसका ट्रेनिंग तथा उत्पादन केन्द्र के रूप में उपयोग किया जा रहा था, आगरा, फर्रुखाबाद तथा लखनऊ की डिहाइड्रेशन फैक्ट्रियाँ, जिन्हें यू० पी० सरकार ने भारत सरकार से ले लिया था, योग्य विस्थापित व्यक्तियों को पट्टे पर दी गई। पुनर्वास समस्या को विशेष रूप से हल करने के विचार से राज्य सरकार पूर्वी बंगाल के जूट की खेती करने वाले ५०० परिवारों को किछा उपनिवेश क्षेत्र (जिला नैनीताल) में फिर से बसाने के लिये राजी हो गई। इस वर्ष इनमें से ३०० परिवार इस राज्य में पहुँच गये और उसको फिर से बसाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की गई।

मकान
इत्यादि

सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों के लिये क्रमशः ६,७१८ और ३,००० मकान और स्टाल बनवाये। यह आशा की गई थी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग का १९५१-५२ का कार्यक्रम समाप्त होने पर मकानों की संख्या बढ़कर ९,४२३ हो जायगी। १९५१-५२ के सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यक्रम में ५०० दुकानों का निर्माण-कार्य भी सम्मिलित था। विस्थापित व्यक्तियों की सहायता गृह निर्माण समितियों, स्थानीय निकायों और प्राइवेट एजेंसियों ने राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से ३,२२१ मकान और १,५९८ दुकानें लगाई। वर्ष के अंत तक सरकार ने इन संस्थाओं को कुल १,४०,५३,१६९ रु० ऋण दिया जिसमें १९५१-५२ में दिया गया २४,३६,१६७ रुपये भी शामिल हैं। इस वर्ष मेरठ और लखनऊ में निजी संस्थाओं के जरिये सरकार की कुल वित्तीय सहायता द्वारा मकानों के बनवाने की योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया।

उपनगर

गोविन्दपुरी, नैनी और हस्तिनापुर के इन तीन उपनगरों का निर्माण-कार्य जारी रहा और देहरादून में रेस कोर्स कालोनी का विकास कार्य प्रारम्भ किया गया और भू-खंडों का परिच्छेद किया गया।

(१) गोविन्द-
पुरी

मेरठ जिले में मोदीनगर के समीप गोविन्दपुरी के निर्माण का काम, जो विस्थापित व्यक्तियों के ५०० परिवारों को बसाने और उन्हें कारोबार तथा उद्योग में लगाने के लिये आरम्भ किया गया था, काफी तेजी से चलता रहा। आलोच्य वर्ष के अंत तक ९२२ मकान, ४ बंगले, ३६ दुकानें और १४ औद्योगिक कारखाने बनाये गये। २७ में से लगभग १९ पार्टियों के लिये, जिन्हें विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना के लिये भू-खंड दिये गये थे, कारखानों की इमारतों का निर्माण-कार्य भी पूरा किया गया और वर्ष समाप्त होने पर बाकी पार्टियों का काम हो रहा था।

(२) नैनी

इलाहाबाद के निकट नैनी में २५० एकड़ भूमि को ६ लाख रुपये की लागत से एक औद्योगिक उपनगर बनाने के विकास संबंधी कार्य की प्रगति सतोषजनक रही। इस उपनगर के पूरे होने पर यह आशा की जाती है कि विस्थापित व्यक्तियों के २०० परिवारों के आवास गृहों के अतिरिक्त ११७ कारखानों और वर्कशॉपों की व्यवस्था हो सकेगी। कारखानों और वर्कशॉपों के लिये सुरक्षित कुछ प्लॉटों में १७० व्यक्तियों ने निर्माण-कार्य प्रारम्भ कर दिया। उस उपनगर में उद्योगों के लिये बिजली और कच्चे माल की सप्लाई के लिये तथा शेष आवासगृह बनाने के योग्य प्लॉटों (लगभग ९०) को भी पट्टे पर देने के लिए व्यवस्था की गई।

(३) हस्तिना-
पुर

हस्तिनापुर उपनगर का काम जारी रहा जिसमें बाहर के १,००० परिवार और १,५०० राज्य के परिवारों यानी लगभग २,००० परिवारों के बसाने की व्यवस्था की गई है और इस नगर में गंगा खादर के क्षेत्र में रहने वाले किसानों के दैनिक जीवन और कृषि के लिये आवश्यक चीजों के वितरण और निर्माण तथा कृषि उपज की सफाई और इकट्ठा करने के काम मुख्य रूप से किये जायेंगे। वर्ष में इस उपनगर में एक बिजलीघर बनाया गया।

भारत सरकार न इस राज्य मे कस्टोडियन के संगठन पर होने वाले व्ययों के निमित्त ४२६ लाख रुपये का अशदान दिया जिसके लिये १९५१-५२ ई० के बजट मे ८,९०,८०० रु० की व्यवस्था कर दी गई थी। शेष व्यय की पूर्ति निष्क्रान्त सम्पत्ति की आय के दस प्रतिशत से की गई।

भारत सरकार ने निष्क्रान्त सम्पत्ति की खोज के लिये भी एक विशेष अमले की स्वीकृति दी। इन कर्मचारियो न लगभग १२,००० सम्पत्तियो का पता लगाया।

वर्ष के दौरान में यू० पी० सरकार ने उन मुसलमानो को सम्पत्ति वापस दिलाने के ४८२ प्रमाणपत्र जारी किये जो फरवरी, १९५० से मई, १९५० ई० तक इस राज्य से पश्चिमी पाकिस्तान को चले गये थे और बाद मे सरकार द्वारा चलाये गये बैचो मे फिर लौट आये। भारत-पाकिस्तान समझौता के अनुसार भारत सरकार ने इस मामले में किये गये निर्णय के अधीन उन मुसलमानो के नाम प्रमाण-पत्र जारी किये जो समझौता के अनुसार 'निष्क्रान्त सम्पत्ति' को फिर से लेने के अधिकारी थे। अधिकांश लौटने वाले व्यक्तियो को, जो यहाँ से जा चुके थे, कठिनाइयो को देखते हुए फिर से वापस की जाने वाली सम्पत्ति के लिये प्रत्येक आवेदन-पत्र पर लगाई गई १० रुपये की कोर्ट फीस वसूल नहीं हुई। कुछ ऐसी वैधानिक कार्यवाहियो को, जिनसे निष्क्रान्त सम्पत्ति के शीघ्र लौटाने मे बाधा पड़ती थी, हटा दिया गया।

आलोच्य वर्ष मे भारत सरकार ने अपना ध्यान निष्क्रान्त सम्पत्ति के विभाजन की समस्या की ओर भी दिया। सम्मिलित और बंधक सम्पत्ति में निष्क्रान्त और गैर-निष्क्रान्त सम्पत्ति दोनों ही सम्मिलित पाई गईं। सम्मिलित सम्पत्तियों में निष्क्रान्त और गैर-निष्क्रान्त सम्पत्ति अलग अलग करना ही उचित समझा गया ताकि विस्थापित व्यक्तियों को अर्द्ध स्थायी रूप से बाँटने योग्य सम्पत्ति का ठीक ठीक पता लग सके और यह भी महसूस किया गया कि बंधक गृहीताओं के बंधक सम्पत्ति बेचने के अधिकारों को अनिश्चित समय तक रोकना संभव नहीं था, इसलिये केन्द्रीय सरकार ने नवम्बर में इवेक्वी इन्टेरेस्ट सेपरेशन ऐक्ट, १९५१ ई० पारित किया। इस ऐक्ट के अधीन एक ऐसे अफसर की नियुक्ति की गई जिसने उत्तर प्रदेश मे निष्क्रान्त सम्पत्ति के विभाजन का काम शुरू किया।

भारत में जो निष्क्रान्त सम्पत्ति शेष रह गई थी उसमें से विस्थापित व्यक्तियो को प्रतिकर देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने इस राज्य के नागर क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में निष्क्रान्त सम्पत्ति के मूल्यांकन के लिये एक योजना बनाई। वर्ष में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों मे इस योजना के अधीन काम किया गया और सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा कई स्थानों पर इमारतों आदि का मूल्यांकन किया गया।

विस्थापित व्यक्तियों को भरण-पोषण भत्ता की भुगतान करने के प्रयोजन से ८ लाख रुपये की धनराशि निष्क्रान्त सम्पत्ति के कस्टोडियन के व्यक्तिगत खाते से भारत के निष्क्रान्त सम्पत्ति के कस्टोडियन जनरल के व्यक्तिगत खाते को संक्रमित कर दी गई।

डिस्पलेसर्स (डेट्स ऐजडस्टमेंट) ऐक्ट, १९५१ ई० ७ नवम्बर की प्रेसिडेंट द्वारा स्वीकृत किया गया और केन्द्रीय सरकार ने १० दिसम्बर, १९५१ ई० से उस ऐक्ट को उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया। इस ऐक्ट का यह उद्देश्य

निष्क्रान्त सम्पत्ति (क) बजट

(ख) निष्क्रान्त सम्पत्ति की खोज

(ग) सम्पत्ति वापस दिलाने के प्रमाण-पत्र

(घ) निष्क्रान्त सम्पत्ति का विभाजन

(ङ) निष्क्रान्त सम्पत्ति और विस्थापित व्यक्ति

डिस्पलेसर्स (डेट्स ऐजडस्टमेंट) ऐक्ट, १९५१ ई०

था कि विस्थापित व्यक्तियों के पहली बार जाने के समय पर समस्त आर्थिक उत्तरदायित्वों को भुगतान को उसकी (क) 'भुगतान करने की क्षमता' और (ख) प्रतिकर जो उसकी पश्चिमी पाकिस्तान में छोड़ी गई अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में दिया जाय, से पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करना था।

इस ऐक्ट के लागू होने के एक वर्ष की अवधि में इस ऐक्ट द्वारा विस्थापित ऋणियों (debtors) को अपने दाताओं (Creditors) से ऋणों को कम कराने के लिये आवेदन-पत्र देने का अधिकार मिला। इस प्रयोजन के लिये पहले से जाने वालों के समस्त दायित्वों को संग्रहीत किया गया, किन्तु यह विशेष प्रकार का प्रतिबन्ध था कि इस कानून के अधीन जो व्यक्ति सहायता प्राप्त करने के लिये प्रार्थी होंगे, उन पर दिवालियेपन का दोष नहीं लागू होगा। विस्थापित व्यक्तियों को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं में कुछ सहायताएं इस प्रकार हैं, यथा १५ अगस्त, १९४७ ई० के पश्चात् व्याज का कम करना, गिरफ्तारी या सम्पत्ति को कुर्को से मुक्त कर देना, पहिले से जाने वालों के उत्तरदायित्वों के सम्बन्ध में भरण-पोषण सम्बन्धी भत्ते में कमी करना, सम्मिलित ऋणों के सम्बन्ध में उत्तरदायित्वों का विभाजन पहिले ही से निर्णय की गई डिग्रियों को दुहराना, ताकि नये विधान आदि के अनुसार उनका भुगतान हो सके।

इस ऐक्ट की धारा ४ के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को काम में लाकर सरकार ने सभी सिविल जजों और जहाँ सिविल जज नहीं थे वहाँ डिस्ट्रिक्ट जजों को इसलिये नियुक्त की कि वे ट्रिब्यूनल के रूप में अपने-अपने अधिकार-क्षेत्रों में इस ऐक्ट के अधीन प्रदत्त अधिकारों को काम में ला सकें। इस ऐक्ट ने ऋणों को निश्चित करने और कई अपीलें तथा रिवीजनों में होने वाली देर को दूर करने के सम्बन्ध में कार्यविधि को अधिक सरल बनाने की व्यवस्था की।

इस ऐक्ट ने डिस्प्लेस्ड पर्सन्स इन्स्टीट्यूशन आफ सूट्स ऐक्ट, १९४८ ई० और डिस्प्लेस्ड पर्सन्स लीगल प्रोसीडिंग्स ऐक्ट, १९४९ ई० को निर्वीत किया।

**निष्क्रमण-
थियों के दावे**

वर्ष में भारत सरकार के केन्द्रीय दावा संगठन (Central Claims Organisation) से तसदीक के लिये राजकीय दावा संगठन (State Claims Organisation) द्वारा भेजे गये ८७४ दावे आये जो प्रावीडेन्ट फण्ड तनख्वाह के बकायें, छुट्टियों के वेतन, जमानत की धनराशियाँ और सरकारी कर्मचारियों, पहले की रियासतों के कर्मचारियों तथा स्थानीय निकायों के उन कर्मचारियों की पेंशनो के बारे में थे, जो पाकिस्तान चले गये थे। राजकीय दावा संगठन (State Claims Organisation) ने उतनी ही अवधि में २,४३६ दावों की तसदीक की और उन्हें भारत सरकार को लौटा दिया।

**विस्थापित
व्यक्तियों
क दाव**

उन विस्थापित व्यक्तियों के मामले, जिन्होंने पाकिस्तान में छूटी हुई अपनी चल सम्पत्ति को फिर से वापस पाने के लिये आवेदनपत्र दिये थे, पाकिस्तान स्थित भारत के हाई कमिश्नर या पाकिस्तान के उन प्रांतों के चीफ सेक्रेटरियों के हाथ में दिये गये जिनसे वे चल कर इस राज्य में आये थे। नवंबर, १९५० ई० का चल सम्पत्ति का समझौता पाकिस्तान में कार्यान्वित नहीं हुआ, अतएव इन मामलों को तय करने में अधिक सफलता प्राप्त न हुई। फलस्वरूप इनमें से अधिकांश मामलों की रिपोर्टें भारत सरकार को की गईं, ताकि वह कोई उचित कार्यवाही करे।

**निष्क्रमण-
थियों के सेवा
अभिलेख
(सर्विस
रेकार्ड्स)**

पाकिस्तान की प्रान्तीय सरकारों के पास से निष्क्रमणार्थी सरकारी थियों के सेवा नौकरों के सेवा अभिलेखों इत्यादि के हस्तान्तरण करने की प्रार्थनाएं आईं और उन्हें सम्बन्धी प्रशासकीय विभाग के पास इस अनुदेश के साथ भेज दी गईं कि वे सीधे स्वयं इनको सबन्धित सरकारों के पास भेज दें। वर्ष में कई मामलों के सम्बन्ध में सेवा अभिलेख सप्लाई किये गये।

अध्याय ५—सरकारी राजस्व तथा वित्त

४४—केंद्रीय राजस्व

उत्तर प्रदेश में आय कर देने वालों की कुल संख्या १,०१,४६२ थी। १९५१-५२ ई० में इस सम्बन्ध में शुद्ध वसूलियाँ ६,१७,१९,०६४ रु० हुईं। विभिन्न वसूलियों के व्योरे ये हैं :—

	रु०
आय-कर ...	४,४८,१३,५६२
घारा १८-क के अन्तर्गत वसूलियाँ ..	२,१५,६८,८०६
निगम-कर ...	१,०३,८६,६१३
उच्च आय-कर ...	६५,६६,६४२
सरचार्ज ...	३१,६६,२५३
अधिक लाभ-कर ...	५,६७,००१
व्यापार लाभ-कर ..	५,४६,४२३
पूँजी लाभ-कर ...	१,१६,७३६
विविध ...	८,६१,०२५
योग ...	६,१७,१९,०६४

४५—राज्य का राजस्व

१९५०-५१ ई० के मूल बजट में ५,२२६ लाख रु० राजस्व प्राप्ति और ५,२२१ लाख रु० राजस्व व्यय का तखमीना लगाया गया था, जिसका तात्पर्य यह था कि ५ लाख रु० की छोटी बचत हुई। वष की वास्तविक कार्यावाहियों से भी इस बात का पता चलता है कि ५ लाख रु० राजस्व की बचत हुई, यद्यपि प्राप्तियाँ और व्यय दोनों घटकर क्रमशः ५,१८९ लाख रु० और ५,१८४ लाख रु० हो गये।

५,१८९ लाख रु० की वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ ५,२२६ लाख रु० मूल तखमीने की तुलना में ३७ लाख रु० कम हो गयीं। एक जल्लेखनीय बात यह थी कि 'अन्य कर तथा महसूल' के अन्तर्गत ९८ लाख रु० की कमी हो गयी, जो मुख्यतया गन्ना कर तथा आय कर की कमी के कारण हुई थी। ३८ लाख रु० की अन्य महत्वपूर्ण कमी 'कृषि' के अन्तर्गत हुई। 'पशु चिकित्सा' के अन्तर्गत ३६ लाख रु० की कमी हो गयी, क्योंकि पहिले रजतनी आशा की गयी थी उसकी अपेक्षा कम क्षेत्र में खेती की गई

१९५०-५१
ई० का बजट
तथा उसके
वास्तविक
आंकड़े

राजस्व
प्राप्तियाँ

श्रीर उन कुछ फार्मों में, जहाँ सिचाई की सुविधाये नहीं हैं, मौसम प्रतिकूल होने के कारण फसले अच्छी नहीं हुई। "विविध विभाग" के अंतर्गत १९ लाख २० कीजो कमी हुई थी उसका मुख्य कारण यह था कि सरकारी बस सेवाओं से अपेक्षाकृत कम आय हुई। असामान्य प्रतियोगी में ३६ लाख २० की कमी का प्रधान कारण यह था कि "अधिक अन्न उपजाओ" योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार को जिस राज्य सहायता को मूल बजट में सम्मिलित किया गया था, वह प्राप्त नहीं हुई। दूसरी ओर कृषि आयकर से अधिक प्राप्तियों तथा भारत सरकार से प्राप्त उच्चतर आयकर भाग के फलस्वरूप "आयकर" के अंतर्गत २० लाख २० की वृद्धि हुई। "भू-राजस्व" के अधीन भी ४१ लाख २० की वृद्धि हुई, जो प्रधानतया विलीनी-कृत रियासतों में स्थित सरकारी आस्थानों से अतिरिक्त आय के कारण और अशतः मालगुजारी की अच्छी वसूली के कारण हुई। अफीम और देशी स्प्रिट की ऊँची नीलामों बोलियों तथा देशी स्प्रिट पर बड़े हुये महसूल एवं मदिरा स्प्रिट और देशी शराब से अधिक प्राप्तियों के कारण राज्य आबकारी में ७० लाख २० की वृद्धि हुई। गेर-अदालती स्टाम्प की बिक्री से प्राप्तियाँ और न्याय शल्क स्टाम्प की बिक्री के कारण 'स्टाम्प' के अंतर्गत १२ लाख २० की वृद्धि हुई। वन प्राप्तियों में २६ लाख २० की वृद्धि हुई, क्योंकि इमारती लकड़ी तथा अन्य वन उपज की अधिक माँग होने के फलस्वरूप उनसे प्राप्तियों की धनराशि बढ़ गई। प्रारम्भिक पाठशालाओं में अधिक भर्तियों से अधिक प्राप्तियों और परीक्षार्थियों की संख्या में वृद्धि के कारण 'शिक्षा' के अंतर्गत १५ लाख २० की वृद्धि हुई। "नागरिक निर्माण कार्यों" के अंतर्गत भी १७ लाख २० की वृद्धि हुई।

राजस्व व्यय

१९५०-५१ ई० में ५,२२१ लाख २० के मूल तखमीने की तुलना में वास्तविक व्यय ३७ लाख २० कम हुआ। २७ लाख २० की सबसे बड़ी कमी 'शिक्षा' के अंतर्गत हुई, क्योंकि नयी पाठशालाओं में पूरे कर्मचारिवर्ग की नियुक्ति नहीं की गयी। समस्त सरकारी प्रारम्भिक पाठशालाओं को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को हस्तान्तरित कर दिया गया और प्रारम्भिक पाठशालाओं के भवन निर्माण के संबंध में धनराशि का पूरा पूरा उपयोग नहीं किया गया। "सिचाई संबंधी निर्माण कार्यों" पर २३ लाख २० की कमी हुई, जिसका प्रधान कारण यह था कि खाद्य उत्पादन योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार की राज्य सहायता बजट में समायोजित नहीं की गई। सिचाई संबंधी व्यय के अंतर्गत भी २३ लाख २० की बचत हुई। "विविध" शीर्षक के अंतर्गत वास्तविक आंकड़ों में २० लाख २० की कमी हुई, क्योंकि विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर कम व्यय हुआ और अन्तर्देशी के लिये व्यवस्था की गई धनराशि तथा शक्कर अनुसंधान और श्रम गृह कोष के हेतु संकमित की गई धनराशि एवं भूतपूर्व सैनिकों की प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिये, केन्द्रीय सरकार को अंशदान के रूप में दी जाने वाली धनराशि का पूरा पूरा उपयोग नहीं किया गया। "कृषि" के अंतर्गत १८ लाख २० की बचत प्रधानतया इस कारण हुई कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन यूनिटें देर से आईं और उनके कुये गलाने तथा अन्य अर्थ व्यवस्थाओं पर कम व्यय हुआ। "सावजनिक स्वास्थ्य" के अंतर्गत व्यय में १६ लाख २० की कमी हुई, जिसका प्रधान कारण यह था कि बहुत से जच्चा-बच्चा तथा शिशु हितकारी केन्द्र काम नहीं कर रहे थे। राज्य कर्मचारी बीमा योजना को कार्यान्वित करने में विलम्ब और कोई भीषण महामारी का प्रकोप नहीं हुआ। दूसरी ओर "सामान्य

प्रशासन" के अन्तर्गत व्यय में २३ लाख ६० की वृद्धि हुई। इसका प्रधान कारण यह था कि बड़ी हुई दरों पर महंगाई भत्ते के लिये पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। जमींदारी विनाश कोष की वसूलियों के लिये अधिक कर्मचारिवर्ग की नियुक्ति की गयी और पंचायत सेज्जेरियो के वेतन के भुगतान के लिये गांव सभाओं को सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गयी। विविध विभाग के अन्तर्गत व्यय में ३६ लाख ६० की वृद्धि हुई, क्योंकि पेट्रोल, फुटकर पुर्जों तथा अन्य सहायक पुर्जों का मूल्य और परिवहन विभाग के रीजनल हेडक्वार्टरों के फुटकर पुर्जों के स्टॉक को बढ़ाने के संबंध में किया गया व्यय बढ़ गया।

पूँजी-व्यय ९४५ लाख ६० हुआ, जबकि मूल तखमीने में १,१४८ लाख ६० की व्यवस्था की गयी थी। बजट के मूल तखमीने में सप्लाई योजनाओं के लिये १०७ लाख ६० के शुद्ध व्यय की व्यवस्था की गयी थी, किन्तु वास्तव में इन योजनाओं को कार्यान्वित करने पर ३५० लाख ६० की शुद्ध आय हुई और इसी कारण व्यय में ४६६ लाख ६० की कमी हुई। विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर पूँजी व्यय १९३ लाख ६० कम हो गया, जिसका प्रधान कारण यह था कि इन योजनाओं को वित्त पोषित करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने छोटे छोटे ऋण दिये थे और भवन निर्माण संबंधी प्रयोजनों के लिये स्टॉक की अधिक से अधिक सामग्रियां जारी की थी। "औद्योगिक विकास" के अन्तर्गत ३८ लाख ६० की कमी हुई, जिसका मुख्य कारण यह था कि बिहार में उर्वरक के कारखाने की स्थापना के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने ९० लाख ६० के अंशदान की जो व्यवस्था की थी उसका उपयोग नहीं किया गया। "जल-विद्युत् निर्माण कार्य" पर व्यय में ५८ लाख ६० की कमी हुई। इन कमियों को तुलना में ४०० लाख ६० की वृद्धि इस कारण हुई कि यह धनराशि प्रारंभिक कोष को संक्रमित कर दी गयी, जिसके लिये मूल बजट में कोई व्यवस्था नहीं थी। "सिंचाई संबंधी निर्माण कार्य" के अन्तर्गत व्यय में ५४ लाख ६० की और "कृषि सुधार तथा अनुसंधान" के अन्तर्गत व्यय में ४९ लाख ६० की भी वृद्धियां हुई। "सिंचाई संबंधी निर्माण कार्य" के अन्तर्गत व्यय में वृद्धि केवल इस बात से हुई कि "अधिक अन्न उपजाओ" योजनाओं के निष्पादन में शीघ्रता की गयी और "कृषि सुधार तथा अनुसंधान" के अन्तर्गत व्यय में वृद्धि का कारण यह था कि बीज और उर्वरक अधिक मात्रा में खरीद गये और वेधन क्रियाओं के संबंध में वसूलियां कम हुईं।

१९५१-५२ ई० के बजट में ६,१२६ लाख ६० के राजस्व और ६,१५१ लाख ६० के व्यय का अनुमान लगाया गया था, जिसका तात्पर्य यह था कि २५ लाख ६० का घाटा हुआ। १९५०-५१ ई० के तखमीनों की तुलना में १९५१-५२ ई० की अनुमानित राजस्व प्राप्तियों में ९२० लाख ६० की और अनुमानित राजस्व व्यय में ९२९ लाख ६० की वृद्धि हुई।

संभावित जमींदारी विनाश के कारण "भू-राजस्व" के अन्तर्गत ६७९ लाख ६० की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। यह सभावना थी कि "पंचायत निर्वाचन" से प्राप्तियों में ७० लाख ६० की वृद्धि होगी। इस बात की आशा की जाती थी कि १९५०-५१ ई० तथा १९५१-५२ ई० में भूमि-व्यवस्था कमिश्नर की स्थापना का व्यय, जिसमें ५० लाख ६० की वृद्धि हुई थी, जमींदारी विनाश कोष से संक्रमित धनराशि द्वारा पूरा हो जायगा। इस बात का अनुमान लगाया गया था कि केन्द्रीय सड़क कोष से आय की धनराशि में ७७ लाख ६० की वृद्धि होगी। वन प्राप्तियों के तखमीने में भी ३२ लाख ६० की वृद्धि हुई। दूसरी ओर इस बात की आशा की जाती थी

पूँजी-व्यय

१९५१-
५२ ई०
का बजट

कि आय कर सबधी विभाज्य धनराशि में राज्य भाग के फलस्वरूप जो प्राप्तियां होगी उनमें ५२ लाख २० की कमी हो जायगी । ऐसा अनुमान था कि नहरों के निर्माण कार्य के व्यय में वृद्धि के फलस्वरूप कृषि संबंधी प्राप्तिओं में २० लाख २० की शुद्ध कमी होगी । यह भी तखमीना लगाया गया था कि खाद्य उत्पादन योजना के लिये केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता में ३७ लाख २० की कमी हो जायगी । व्यय पक्ष में सर्वविशिष्ट वृद्धि जमींदारी विनाश कोष में ४४३ लाख २० संक्रमित करने के कारण हुई, क्योंकि जमींदारी विनाश के फलस्वरूप अतिरिक्त आय होने की आशा थी । ६८ लाख २० की अन्य वृद्धि उस व्यवस्था के कारण हुई, जो स्थानीय दरो के पुनर्भुगतान के सबध में डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को अंशदान देने के लिये की गयी थी । स्थानीय निकायों के कमचारियों को देय महगाई भत्ते के संबंध में स्थानीय निकायों को जो अंशदान देना सरकार के जिम्मे था, उसके लिये २३ लाख २० की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हुई ।

निर्वाचन व्यय के सबध में राज्य सरकार को जो खर्च करना पड़ा उसमें भी ४४ लाख २० की वृद्धि हुई । जमींदारों को देय प्रतिकर निर्धारण के संबंध में प्रबंध करने और भूमिधरो से सीधे राजस्व वसूल करने के कारण व्यय में १५० लाख २० की वृद्धि हुई ।

इस वर्ष की कृषि विकास सम्बन्धी कामों तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों की मरम्मत पर व्यय कम हुआ ।

१९५१-५२
लिये
त

१९५१-५२ के संशोधित तखमीनों में प्राप्तियां घटकर ५,६६५ लाख २० तक और व्यय ५,७०६ लाख २० तक पहुंच गया, जिससे ४१ लाख २० की कमी प्रकट हुई, जिसकी पूर्ति राजस्व सुरक्षित कोष (Re newe Reserve Fund) से एक समान धनराशि संक्रमित करके की गई । प्राप्तिओं में संभावित कमी मुख्यतया भूमि के लगान की वसूलियों की मंद के कारण हुई, जो वास्तविक तखमीनों के प्रत्याशित १,४०७ लाख २० के विपरीत घटकर ७३५ लाख २० हो गई, क्योंकि आशा के प्रतिकूल प्रस्तुत वर्ष में जमींदारी विनाश अधिनियम के उपबन्ध निहित न हो सके । फार्म की उपज से प्राप्तिओं में कमी अंशतः वर्षा के न होने और अंशतः सिंचाई की सुविधाओं के अपर्याप्त होने के कारण हुई । ग्राम सभाओं तथा पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के स्थगित हो जाने के कारण प्राप्तिओं में बहुत कमी हुई । मनोनयन-पत्रों इत्यादि के विक्रय से होने वाली आय वास्तविक तखमीने में प्रत्याशित ७२ लाख २० के स्थान पर घटकर एक लाख २० हो गई । न्यून प्राप्तिओं का सतुलन विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत होने वाली वृद्धियों से किया गया । भारत सरकार आय-कर में से राज्य को जो भाग देती है, उसमें १४१ लाख २० की वृद्धि हुई, जबकि आवश्यकता की प्राप्तिओं में राज्य सरकार द्वारा देशी स्परिट, शराब इत्यादि पर अधिक कर लगाये जाने के कारण ३१ लाख २० की वृद्धि हुई । "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन के सम्बन्ध में अधिक नहरों के निर्माण हो जाने के कारण उत्पादक नहरों तथा ट्यूबवेलों से ५८ लाख २० की वृद्धि हुई । व्यय में सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत १३७ लाख २० की तखमीनी बज्रत हुई । यह बचत मुख्यतया इस कारण हुई कि जमींदारी विनष्ट अधिनियम के अधीन निहित आज्ञा के अनुसार प्रतिकर सूची तैयार करने तथा काइतकारों से सीधे लगान वसूल करने के लिये जो अमला रखा जान वाला था, वह नहीं रखा गया । जमींदारी विनाश कोष में संक्रमित करने के अभिप्राय से ४४३ लाख २० की व्यवस्था और

डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को स्थानीय दरो का भुगतान करने के अभिप्राय से ६८ लाख रु० की एक अन्य व्यवस्था का उपयोग नहीं किया जा सका, क्योंकि प्रस्तुत वर्ष में जमींदारी विनाश अधिनियम, जिसके वर्ष में लागू होने की आशा थी, लागू न हो सका। पुलिस व्यय में १९ लाख रु० की कमी हुई, जिसका मुख्य कारण तीन प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस के बटालियनों का व्यय था, जिनकी तीन मास के लिये विशेष कार्य के लिये भारत सरकार न मागा था और उसने उनका उस अवधि का व्यय भी बर्दाश्त किया। इन कमियों के विपरीत 'असाधारण व्यय' के अधीन व्यय में वृद्धि हुई। इसका कारण यह था कि राजस्व से अन्न क्रय योजनाओं के अधीन हुई हानियों के एक भाग को पूरा करने के लिये १०० लाख रु० संक्रमित किया गया। भारत सरकार से लिये गये ऋणों की बढ़ती हुई सभ्या का अपाकरण (liquidation) करने के प्रयोजन से संशोधित तखमीन में अधिक धनराशि की व्यवस्था भी की गई थी।

पूँजी-व्यय में कमी हुई। मूल तखमीने के १,६७९ लाख रुपये से घट कर संशोधित तखमीने में यह १,५३८ लाख रु० हो गया। इस कमी का मुख्य कारण यह था कि राज्य सरकार ने असोनियम सल्फट फबटरी, सिन्धरी के पूँजी व्यय के लिये मूल तखमीने में जो ९० लाख रुपया की व्यवस्था की थी, उसका उपयोग नहीं किया गया तथा सीमेन्ट फबटरी प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में इमारत, सड़क इत्यादि के बनाने के व्यय में बचत हुई। पत्थर की खानों के यन्त्रीकरण का स्थगित हो जाना भी संशोधित तखमीने में थोड़ी बचत का कारण है। कुछ सड़कों और इमारतों के निर्माण में जितनी धनराशि का अनुमान था, उससे ३२ लाख रु० कम व्यय होने की आशा थी। पूँजी व्यय का यह तखमीना, जो विस्थापित व्यक्तियों के मकानों तथा दूकानों के निर्माण के लिये था, उसमें १९ लाख रु० की कमी हुई। शोरदा जलविद्युत् तथा पथरी प्रोजेक्ट के व्यय में ३६ लाख रु० की बचत और सिचाई की विभिन्न नई योजनाओं के सम्बन्ध में १० लाख रु० की बचत इस कारण होने की सम्भावना थी कि निर्माण कार्य में प्रगति कम थी और बाहर से मंगाये गये स्थिर यन्त्रों तथा मशीनों के प्राप्त होने में जितनी आशा थी, उससे अधिक विलम्ब हुआ। दूसरी ओर 'अन्न सप्लाई योजना' के व्यय के तखमीने में १२५ लाख रु० की वृद्धि हुई। जिसका मुख्य कारण यह था कि रबी की फसल नष्ट हो जाने तथा बड़भत्र में सूखा पड़ जाने के कारण अधिक परिमाण में अन्न खरीदा गया।

पूँजी-व्यय

बजट के तखमीने में ४०० लाख रु० के अंकित मूल्य के एक स्थायी ऋण लिए जाने की व्यवस्था की गई थी, किन्तु केवल २०३ लाख रु० का ऋण लिया जा सका। प्रारम्भ में ऋण सम्बन्धी ५०० लाख रु० के ट्रेजरी बिलों को जारी करने का विचार था, किन्तु उनकी आवश्यकता नहीं समझी गई और इस लिये ट्रेजरी बिल नहीं जारी किये गये।

सार्वजनिक
ऋण

'अन्न सप्लाई योजना' व्यापार से संबंधित सभी योजनाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रही, आलोच्य वर्ष में अधिक जनसंख्या वाले नगरों में पूर्ण राशनग बना रही, किन्तु व्यापक मूल्य के कारण चावल की फसल खराब हो गई, जिससे अन्न की उगाही में पर्याप्त कमी हुई और साथ ही सूखा वाले क्षेत्रों में अन्त्याहार योजना के लागू किए जाने के कारण अधिक अन्न की आवश्यकता हुई। स्वभावतः कुछ राज्य के अन्दर खरीद करके और कुछ आयात द्वारा पर्याप्त मात्रा में अन्न का स्टॉक रखना पड़ा। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष आयात किये गये गेहूँ की दर अधिक ऊँची रही।

सरकारी
व्यापार
योजना

जबकि भारत सरकार ने कानपुर और लखनऊ के औद्योगिक क्षेत्रों की खपत के लिए ९५,००० टन गेहूँ १३ ह० १४ आ० प्रति मन की दर से सप्लाई किया, उसने शेष राज्यों की खपत के लिए बाकी गेहूँ अधिक ऊंची दर पर अर्थात् १८ ह० ६ आ० प्रतिमन के हिसाब से दिया। बोरो का मूल्य भी अधिक चढ़ गया।

इस वर्ष सम्पूर्ण व्यय ४,१३९.५३ लाख ह० हुआ। राज्य से देश के अन्य कमी वाले क्षेत्रों को माल भजा गया। खाद्यान्नों, बोरो इत्यादि की बिक्री से होने वाली प्राप्तियों का तखमीना ३,६१५.७९ लाख ह० था। अतः इस वर्ष उक्त योजना के अंतर्गत होने वाली शुद्ध कमी का तखमीना ५२३.७४ लाख ह० लगाया गया था, क्योंकि शुद्ध दायित्व में से १ करोड़ ह० राजस्व के नामे लिखे जाने के कारण तखमीना ४२३.७ लाख ह० कम हो गया था।

विनियोग लेख

उत्तर प्रदेश सरकार के १९४८-४९ ई० के विनियोग लेखे तथा १९५० ई० की लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्यपाल महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये भारत के कम्प्ट्रोलर तथा आडिटर जनरल से १५ मार्च, १९५१ ई० को प्राप्त हुई। इस प्रकाशन में लेखा परीक्षा अनुसंधान के फलस्वरूप आवश्यक समझी जाने वाली टीका-टिप्पणियों तथा महत्वपूर्ण पर्यवेक्षण के साथ १९४८-४९ ई० के कुल व्यय के परीक्षित लेखे, चाहे वे प्रत्येक अनुदान के भिन्न विनियोग लेखे के रूप में मतदेय या प्रभूत रहे हों, सम्मिलित थे। इस खंड में लेखा परीक्षा प्राधिकारियों की वे टीकाएँ व टिप्पणियाँ भी सम्मिलित थीं जो उन्होंने व्यापार उत्पादन और हानि तथा लाभ सम्बन्धी सभी लेखों और सरकारी वाणिज्य एवं अर्द्ध-वाणिज्य सम्बन्धी व्यवसायों के हेतु रखी जाने वाली रोकड़ बहियों पर दी थी।

वित्त लेखे

सरकार के १९४८-४९ ई० के वित्त लेखे और उन पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्यपाल महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये कम्प्ट्रोलर तथा आडिटर जनरल से १९ मार्च, १९५१ ई० को प्राप्त हुई। इस संकलन में सरकार की १९४८-४९ ई० की प्राप्तियाँ (Receipts) और व्यय के लेखों के साथ-साथ विभिन्न लेखों और दूसरे जांच के लिये आय हुये आकड़ों से प्रकट होने वाले वित्तीय परिणामों पर एक रिपोर्ट भी दी गई है, अर्थात् राजस्व और पूँजी के लेखे सरकारी ऋण के लेखे और राज्य सरकार के देने और पावने का विवरण दिया गया है। यह लेखा विनियोग लेखों के पूरक के रूप में है।

राज्यपाल महोदय के आदेशों के अधीन १९४८-४९ ई० के विनियोग तथा वित्तीय लेखे और उन पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट विधान सभा तथा विधान परिषद के समक्ष क्रमशः २१ तथा २७ मार्च, १९५१ ई० को प्रस्तुत की गई।

सावजनिक लेखा समिति

वैभागीक अफसरों द्वारा प्रस्तुत की गई साक्षियों की दृष्टि से सरकार के विनियोग लेखों पर विचार करने के लिये उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यविधि के नियमों के अधीन बनाई गई १९५०-५१ ई० की सार्वजनिक लेखा समिति ने १९४८-४९ ई० के विनियोग लेखों तथा सम्बन्धित लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर मार्च, १९५१ ई० में की गई बैठकों में विचार किया। समिति की सिफारिशें एक रिपोर्ट में दर्ज हैं, जिस पर २८ सितम्बर, १९५१ ई० को विचार करने के बाद विधान सभा ने उसे मान लिया।

यू० पी० वेतन समिति द्वारा अभिस्तावित (सिफारिश किये गये) उन वेतन-क्रमों के संबंध में, जिन्हें बहुत से मामलों में गतवर्ष कार्यान्वित किया जा चुका है, वर्ष समाप्त होने तक कुछ प्रयोजीयान स्टेटमेंट स्वीकृत होने को रह गये थे। अतएव संशोधित वेतन-क्रमों को चुनने के लिये कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं की जा सकी।

वेतनों में संशोधन

कार्यविधियों के विचाराधीन रहन की अवधि में मुअत्तली

सहायक नियम १९९ में संशोधन किया गया और यह निर्धारित किया गया था कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध गिरफ्तारी अथवा आपराधिक दोषारोपण की कार्यवाही की जा रही हो तो उसे मुअत्तल समझा जायगा और उसे हिरासत, रोक लेने अथवा कैद में रहन की अवधि के लिये केवल निर्वाह भत्ता दिया जायगा। यह भी निर्धारित किया गया था कि ऐसे सरकारी कर्मचारी की उस अवधि में, जिसमें उसे वास्तव में हिरासत में न रखा गया हो या कैद न किया हो, मुअत्तली के लिए विशेष आदेश जारी किये जाने चाहिए, यदि उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों या की गई कार्यवाहियों का उसके सरकारी नौकर होने की हैसियत से संबंध हो या सरकारी कर्मचारी की हैसियत से उसके कर्तव्य पालन करने में इससे कठिनाई पैदा होने की सम्भावना हो अथवा वह नैतिक पतन का शोका हो।

यह निर्णय किया गया कि राज्य सरकार के उन अफसरों को, जो सीनियर आई० ए० एस० या आई० पी० एस० वेतन-क्रम में हैं या स्थानापन्न रूप से पदों पर नियुक्त हैं, मंहगाई भत्ता दिया जायगा। तथापि यह स्पष्ट किया गया कि उन्हें इस अवधि के लिये वह निजी वेतन नहीं दिया जायगा, जो उन्हें छोटे पदों पर रहन-सहन व्यय के रूप में मिला करता था।

आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० अफसरों को मंहगाई भत्ता

पहाड़ तथा जाड़े के दिनों का भत्ता लेने के बारे में नीचे दिये गये सिद्धान्त निर्धारित किये गये थे—

पहाड़ - का तथा जाड़े के दिनों का भत्ता

(क) वे सरकारी नौकर, जो इस भत्ते को पा रहे हैं वे अपने पदों पर काम करने की अवधि में फसते रहेंगे और उस समय तक जब तक कि निर्धारित वेतन सीमा के अनुसार उन्हें ये भत्ते मिलने की अनुमति हो।

(ख) नये पदों पर नियुक्त व्यक्तियों तथा पुराने पदों पर नये भर्तों किये गये व्यक्तियों को उन भत्तों के अतिरिक्त, जो नीचे खंड (ग) में दिये गये हैं, इन भत्तों में से कोई भत्ता पाने का अधिकार न होगा।

(ग) उन सरकारी नौकरों को, जिन्हें इन भत्तों में से कोई भी एक भत्ता मिलता रहा हो, ऐसी जगह जहां अब तक यह भत्ता मिल सकता हो, समान पद पर स्थानान्तरित होने पर या ऐसी जगह उच्च पद पर उस पद से अवनति के पद पर जाने पर उस दर से भत्ता मिल सकेगा जिसके कि मिलने के अधिकारी हो, किन्तु इसके साथ वेतन सीमा का ध्यान रखा जायगा जहां तक भत्ता मिल सकता है।

४६—मुद्रांक (स्टाम्प)

माल बोर्ड उत्तर प्रदेश का मुद्रांक (स्टाम्प) विभाग मुद्रांक (स्टाम्प) शुल्क और न्यायालय शुल्क (कोर्ट फीस) से प्राप्त होने वाले राजस्व को नियन्त्रित करता रहा।

सामान्य

चूंकि हाल के वर्षों में सरकारी कार्यालयों की संख्या अधिक बढ़ गई थी और मुद्रांक (स्टाम्प) तथा रजिस्ट्रेशन का निरीक्षण कार्यालय समस्त

कार्यालयों का निरीक्षण करने में असमर्थ था, इसलिये सरकार न सरकारी तथा स्थानीय निकायों के कार्यालयों में शुल्क तथा कर की जाँच करने के लिये दो विशेष मुद्रांक अधिकारियों की नियुक्ति की। उक्त अधिकारियों ने १ मार्च, १९५१ ई० से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया।

मुद्रांक (स्टाम्प) शुल्क तथा न्यायालय फीस को सुगमांक में करने का प्रस्ताव, जिससे रुपया के विषम भाग चार आने (अर्थात् चार आने, आठ आने, बारह आने और एक रु०) के सुगमांक में हो जाय, सरकार के विचारार्थ था। इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह था कि विभिन्न अंकित मूल्य के सामान्य तथा न्यायालय फीस मुद्रांकों की छपाई में बचत हो जाय और उनके ज़ारी करने तथा लेख्यों पर प्रयोग करने के सम्बन्ध में अफसरों का कार्य भी सरल हो जाय।

प्राप्तियाँ
और व्यय

मुद्रांकों से प्राप्त कुल राजस्व १९५०-५१ ई० के २,३१,३१,६०० रु० से घटकर १९५१-५२ ई० में २,२५,००,००० रु० हो गया। यह कमी मुख्यतया जमीन्दारी विनाश योजना के कारण पचायती अदालतों की स्थापना के फलस्वरूप, जहाँ इस प्रकार के प्रार्थना-पत्रों पर कोई न्यायालय फीस नहीं लगती, दीवानी तथा फौजदारी अदालतों में की जाने वाली शिकायतों तथा अन्य विविध प्रार्थना-पत्रों की संख्या में कमी और माल अदालतों में विभिन्न प्रकार के मुकदमों के रुक जाने के कारण हुई।

कुल व्यय १९५०-५१ ई० के ४,५१,७०० रु० से कम होकर १९५१-५२ ई० में ४,४६,३०० रु० हो गया। अलोच्य वर्ष में जालसाजी तथा गबन के कोई मामले नहीं हुए।

कमियाँ तथा
उगाहियाँ

निरीक्षकों द्वारा बताई गई कुल कमी २,५३,३३२ रु० की हुई।

४७—आबकारी

आबकारी
राजस्व

कलेन्डर वर्ष १९५१ ई० में सम्पूर्ण आबकारी राजस्व का तखमीना ६४३.६४ लाख रु० लगाया गया था, जब कि गत वर्ष सम्पूर्ण वास्तविक आय का तखमीना ६६३.२० लाख रु० था। आय में यह अनुमानित कमी चूने क्षेत्रों में देशी शराब पर महसूल बढ़ जाने के फलस्वरूप, मादक वस्तुओं के सेवन में कमी, अफीम के निर्गम मूल्य में वृद्धि, अफीम के सीमित निर्गमन तथा दुकानों पर घटिया किस्म का गोंजा सप्लाई किये जाने के कारण हुई।

खपत १९५० ई० के ८,४०,८४७ गैलन की तुलना में आलोच्य वर्ष में
(क) देशी ६,२२,६०२ गैलन देशी शराब की खपत हुई और १९५० ई० (गत वर्ष) के १८,६५१ सेर अफीम की तुलना में आलोच्य वर्ष में १४,६०१ सेर
(ख) अफीम अफीम की खपत हुई। १९५० ई० के १,४६,५०१ सेर की तुलना में आलोच्य वर्ष में १,५३,५७३ सेर भांग की खपत हुई और गोंज की खपत १९५० ई० में ६,५५४ सेर की तुलना में इस वर्ष ५,५६८ सेर हुई।
(ग) भांग
(घ) गोंजा

ताड़ी राजस्व

ताड़ी से प्राप्त होने वाला राजस्व २१.५ लाख रु० से बढ़ कर २२.२ लाख रु० हो गया। इस धनराशि में से १५.६ लाख रु० वृक्ष कर और अनुज्ञप्ति शुल्कों से प्राप्त हुआ और ६.३ लाख रु० 'अन्य प्राप्तियों' से, जबकि १९५० ई० में इन शीर्षकों के अन्तर्गत क्रमशः १५.० लाख रु० और ६.५ लाख रुपया प्राप्त हुआ था। यह वृद्धि मुख्यतया नीलाम के समय अच्छी प्रतियोगिता तथा अच्छे नियन्त्रण के कारण हुई।

नीरा बेचने के लिये लखनऊ में प्रयोगात्मक आधार पर एक दूकान खोली गई और यह प्रस्ताव था कि यदि यह दूकान सर्वप्रिय सिद्ध हो तो ऐसी दूकानें आगे चल कर अन्य क्षेत्रों में भी खोली जायें।

नीरा

आलोच्य वर्ष में एक्साइज डेन्जरस ड्रग्स तथा ओपीयम ऐक्टों के अधीन कुल ८,३१६ मामले पकड़े गये, जबकि १९५० ई० में ऐसे मामलों की संख्या १०,५९२ थी। १,४८४ मामले नाजायज तौर पर शराब बनाने के थे, जबकि विगत वर्ष इस प्रकार के मामलों की संख्या २,१११ थी। आलोच्य वर्ष में शराब सम्बन्धी अन्य अपराधों की संख्या १,४२५ थी, जबकि पिछले वर्ष उनकी संख्या १,८६० थी। • भाँग और गांजा से सम्बन्धित मुकदमों की संख्या १,५७३ और अफीम से सम्बन्धित मुकदमों की संख्या ७८५ थी, जबकि १९५० ई० में ऐसे मुकदमों की संख्या क्रमशः १,९८१ और १,५४० थी। लाइसेन्सदारी द्वारा लाइसेन्स की शर्तों के तोड़ने के १,५८४ बड़े और १,४११ छोटे मामले पकड़े गये और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया।

आबकारी
सम्बन्धी
अपराध

नेपाल से चोरी से चरस ले आने और हाथू चरस, जोकि कुमायूँ डिवीजन के पर्वतीय क्षेत्रों में तैयार की जाने वाली एक देशी चरस है, के व्यापक उपयोग के कारण राज्य के पश्चिमी और उत्तरी-पश्चिमी जिलों में चरस के आबकारी सम्बन्धी अपराधों की संख्या बढ़ गई। आलोच्य वर्ष में ५ मन से अधिक गैरकानूनी चरस उन जिलों में पकड़ी गई, जहाँ नशा-बन्दी लागू नहीं है। बिहार राज्य में गांजा के महसूल में कमी हो जाने के फलस्वरूप उस राज्य तथा नेपाल से चोरी से गांजा ले आने के कारण अधिकारियों को चिन्ता बनी रही और इसको रोकने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया गया। १९५० ई० में नियुक्त विशेष कर्मचारिवर्ग समस्त प्रमुख घटनास्थलों पर इस प्रकार के उत्पात को दूर करने के लिये अपनी सारी शक्ति लगा दी और विधिवत् नियुक्त कर्मचारिवर्ग को आबकारी सम्बन्धी अपराधों पर नियन्त्रण रखने के हेतु अधिक शक्तिशाली उपाय करने के लिये प्रोत्साहित किया गया। इसके अतिरिक्त डाक तथा रेलवे पार्सलों के जरिये बिहार से चोरी से गांजा ले आने को रोकने के लिये डाक तथा रेलवे के अधिकारियों तथा बिहार के समीपवर्ती जिलों के आबकारी सम्बन्धी कर्मचारिवर्ग का सहयोग प्राप्त किया गया। इन उपायों के फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में उत्तर प्रदेश में ८० मन गैरकानूनी गांजा पकड़ गया। ३१ मार्च, १९५० ई० तक अफीम खाने को रोकने के लिये भारत सरकार की नीति के अनुसार लाइसेन्स प्राप्त विक्रेताओं को जो विनियमित आधार पर अफीम का कोढ़ा दिया गया, उससे पोस्ता के खेतिहरों को चोरी से बेचने के लिये अफीम रोक रखने की काफी लालच पैदा हो गया। इसके फलस्वरूप कच्ची अफीम से सम्बन्धित अपराध में वृद्धि हुई और उन जिलों में, जहाँ पोस्ता की खेती होती है, मूल स्थान से इस उत्पात को दूर करने के लिये अतिरिक्त कर्मचारिवर्ग की नियुक्ति करनी पड़ी। वर्ष में ७ मन से अधिक गैरकानूनी अफीम पकड़ी गई। कोकीन को चोरी से ले आने के मामले कम रहे।

चालक मद्यसार तैयार करने की एक नयी भट्ठी (सड़द्वारनगर में) चालू की गयी और पेय मद्यसार तैयार करने की दो भट्ठियाँ, जिनका चलना गत वर्ष स्थगित हो गया था, आलोच्य वर्ष में फिर से काम करने लगी। ३९५० ई० में राज्य में पेय मद्यसार तैयार करने वाली ५ और चालक मद्यसार तैयार करने वाली ११ भट्ठियाँ थी। यह तखसीना लगाया गया था कि यदि चालक

चालक मद्य-
सार (पावश
अलकोहल)

मद्यसार की भट्टियाँ आदर्शपूर्ण परिस्थितियों से कार्य करती रहे तो उनकी कुल उत्पादक क्षमता १०७.१ लाख गैलन प्रति वर्ष होगी। चालक मद्यसार तैयार करने की प्रक्रिया में उप-उत्पादन के रूप में लगभग २० प्रतिशत हल्की स्प्रिट की गुंजाइश रख देने पर भी निकट भविष्य में लगभग ८२ लाख गैलन चालक मद्यसार के वार्षिक उत्पादन की आशा की गई थी, यदि शीरा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता रहा। पेट्रोल के साथ सम्मिश्रण के लिये उपलब्ध चालक मद्यसार की सप्लाई में दृढ़ि हो जाने के फलस्वरूप इस बात की आशा की गई थी कि पेट्रोल में काफी बचत हो जायगी और साथ-साथ वैदेशिक विनिमय की भी बचत हो जायगी। चालक मद्यसार के कुल उत्पादन का तखमीना (हल्की स्प्रिट को छोड़ कर) १९५१ ई० में ४६.४७ लाख गैलन लगाया गया था, जबकि विगत वर्ष में ३८.९९ लाख गैलन का तखमीना लगाया गया था।

नये क्षेत्रों में चालक मद्यसार पेट्रोल सम्मिश्रण योजना के विस्तार में पर्याप्त प्रगति हुई। ऐसी डिपो की सख्या जहाँ सम्मिश्रण की कार्यवाहियाँ की जाती थीं ४२ थी, जबकि १९५० ई० में उनकी सख्या १६ थी। ये डिपो रामपुर जिले तथा मुरादाबाद जिले के एक भाग को छोड़ कर समस्त राज्य में अपना माल भूजते थे। वर्ष में इस डिपो का सबसे बड़ा ग्राहक दिल्ली राज्य था, जिसकी चालक मद्यसार की मांग १.८ लाख गैलन प्रतिमास थी।

**आबकारी
नियन्त्रण
प्रयोगशाला**

१९५० ई० में कानपुर में स्थापित आबकारी नियन्त्रण प्रयोगशाला ने बहुत उपयोगी कार्य किया। चालक मद्यसार तथा पेय मद्यसार तैयार करने वाली भट्टियों को प्राविधिक सम्मति देने के अतिरिक्त इस प्रयोगशाला ने वैभाषिक पदाधिकारियों को मद्यसार टेक्नोलोजी में उच्च प्रशिक्षण दिया।

शीरा]

भट्टियों को नियमित रूप से सप्लाई करने के उद्देश्य से शीरे की बिक्री पर, जो मद्यसार उत्पादन के लिये एक प्रमुख कच्ची सामग्री है, नियन्त्रण जारी रहा। आबकारी कमिश्नर ने, जो १९५० ई० में इंडियन शुगर सिंडीकेट के स्वगत अपाकृत हो जाने के समय से ही शीरा के नियन्त्रण के रूप में कार्य कर रहे थे, शीरा के वितरण और निस्तारण पर वर्ष भर नियन्त्रण रखा। सरकार को शीरे की बिक्री से होने वाली आय शुगर एन्ड अलकोहल इंडस्ट्री लेबर वेलफेयर हाउसिंग एन्ड रिसर्च फंड के खाते में पूर्ववत् जमा कर दी गई।

४८--बिक्री-कर

वर्ष में संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर ऐक्ट तथा नियमों में कुछ परिवर्तन किये गये। भारत के संविधान के अनुच्छेद २८६ के उपबन्धों का समावेश करते हुए उक्त ऐक्ट में एकनयी धारा (धारा २७) बढ़ा दी गई।

बिक्री कर से मुक्त होने की अधिकतम फ्रीस को ५०० रु० से बढ़ाकर १,००० रु० कर देने के सम्बन्ध में जो सशोधन किया गया था, उसे १ अप्रैल, १९५१ ई० से लागू किया गया। हार्थ के बुने हुए रेशम, कृत्रिम रेशम, लिनन या फ्लैक्स या इनमें से किसी कपड़े के सम्मिश्रण के बने और कपास अथवा ऊन के कपड़े को १ जुलाई, १९५१ ई० से बिना कोई शर्त बिक्री कर से मुक्त कर दिया गया और मशीन से निर्मित उसी प्रकार के कपड़े के कर का उत्तरदायित्व उसी तारीख से फुटकर बिक्रेता के बिक्री स्थल

से हटाकर निर्माता या आयातकर्ता के बिक्री स्थल पर कर दिया गया।
रेशम, कृत्रिम रेशम और कच्चे सूत पर भी ६ पाई प्रति रुपया की दर से निर्माता
अथवा आयातकर्ता के बिक्री स्थल पर कर लगा दिया गया।

वर्ष में लगभग ४०,५०० व्यवसायों ने कर अदा किया। उनमें से
२१,५४१ (५३ प्रतिशत) व्यवसायियों ने अपना नाम रजिस्टर करवाया।
फीस देने पर ७,७१८ व्यवसायियों को क्रूर-मुक्त प्रमाण-पत्र दिये गये और
४,५९१ कमीशन एजेंटों को लाइसेंस दिये गये।

१९५०-५१ ई० के वित्तीय वर्ष में बिक्री कर ऐक्ट के अधीन ४९३
लाख रु० की प्राप्ति हुई, जबकि १९४९-५० ई० के वित्तीय वर्ष में
६१२ लाख रु० की प्राप्ति हुई थी। प्राप्ति में यह कमी सबसे अधिक
कपास के कपड़े (१७९ लाख रुपये से १४९ लाख रु०); चमड़े के सामान
(११९ लाख से १०८ लाख रु०); शक्कर (६७ लाख रु० से ३४ लाख रु०);
वनस्पति तेल (२३ लाख रु० से १२ लाख रु०) और पीतल के बर्तनों (१४
लाख रु० से ११ लाख रु०) के सम्बन्ध में हुई। ये वस्तुएँ राज्य के निर्यात
व्यापार में प्रमुख स्थान रखती हैं। प्राप्ति में कमी का कारण यह था कि
भारत के संविधान के अनुच्छेद २८६ के खंड (१) के अधीन, जो १९५०-
५१ ई० में वर्ष भर प्रचलित रहा, अन्य राज्यों के उपभोग के निमित्त निर्यात की
जाने वाली वस्तुओं पर कर नहीं लगाया जा सकता था।

यह अनुमान लगाया गया था कि १९५१-५२ ई० में लगभग ४६०
लाख रु० (१९५०-५१ ई० की प्राप्ति की अपेक्षा लगभग ३३ लाख रुपया
कम) की प्राप्ति होगी। प्राप्ति में कमी की संभावना प्रधानतया
इस कारण की गई कि भारत के संविधान के अनुच्छेद २८६ का जो खंड
(२) १ अप्रैल, १९५१ ई० से लागू किया गया था, उसके अधीन ऐसी दशा में
किसी भी सामान के क्रय या विक्रय पर किसी भी राज्य को कर लगाना
निषेध था, जबकि क्रय या विक्रय अन्तर-राज्य व्यापार या व्यवसाय के सम्बन्ध
में होता हो।

चन्द्रौसी के बिक्री कर के सब सकिल आफिस को प्रशासन में कठिनाइयाँ
होने के कारण — १ अप्रैल से तोड़ दिया गया।

अध्याय ६—जन-स्वास्थ्य, पशुपालन तथा मत्स्य-पालन

• ४९—सार्वजनिक स्वास्थ्य

वर्ष के दौरान में देहरादून, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर, महामारी
झज्झाबाद, हमीरपुर, बाँदा, बनारस, मिर्जापुर, जौनपुर, गोरखपुर, देवरिया,
बस्ती, आजमगढ़, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, खीरी, फैजाबाद,
गोंडा, बहराइच, मुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी के जिलों से प्लेग की
रिपोर्टें मिलीं। इस रोग का सबसे अधिक प्रकोप मार्च के महीने में हुआ। जून
के महीने में यह रोग कम हुआ और थम गया, परन्तु सितम्बर के महीने में यह
फिर प्रारम्भ हो गया और वर्ष के अन्त तक जारी रहा।

१२,०८,१६१ से अधिक प्लेग के टीके लगाये गये। झज्झाबाद, गोरखपुर,
बस्ती, गोंडा, हरदोई, कानपुर, मिर्जापुर और सीतापुर के जिलों में प्लेग के

११ अस्थायी अस्पताल खोले गये जिनमें मरीजों के लिये १३४ पलंगों की व्यवस्था की गई।

कई जिलों के उन क्षेत्रों में जहाँ महामारी थी, वर्ष भर चूहों को नष्ट करने के लिये उन्हें जाल में फसा कर या चारे के द्वारा या साइनों गैस के द्वारा नष्ट करके उनके विरुद्ध आन्दोलन चलाया गया। डी० डी० टी० का चूहों के बिलों में तथा घरों में छिड़काव करके पिस्तुओं को नष्ट करने का प्रयत्न किया गया।

बहुत से जिलों से चेचक की बीमारी की रिपोर्टें मिलीं जोकि वर्षभर बनी रही। सर्वदा की भांति अप्रैल मास में सबसे अधिक व्यक्ति चेचक से ग्रस्त हुए। मुरतदी के साथ टीके लगाये गये। एपिडेमिक डिजीजेज ऐक्ट के अनुसार अनिवार्य रूप से टीका लगाने के आदेश को भी उन सभी स्थानों में कार्यान्वित करना पड़ा जहाँ उसकी आवश्यकता थी।

हैजा की बीमारी की रिपोर्टें सबसे पहले मार्च के महीने में बहराइच और जौनपुर के जिलों से मिली। यह बीमारी साधारण रूप से नवम्बर के अन्त तक रही और उसके बाद पूर्णरूप से समाप्त हो गयी। ६,८१,३८७ से ऊपर हैजे के टीके लगाये गये।

राज्य में होने वाले वार्षिक मेले और त्योहार बिना किसी महामारी के प्रकोप से समाप्त हो गये।

गोंडा जिले के देवी पाटन के मेले में, बहराइच के संयद सालार मेले और अयोध्या के रामनवमी तथा सावन में झुला के मेलों के सम्बन्ध में प्रवेश के लिये अनिवार्य रूप से हैजे का टीका लगाने की शर्त लागू की गई। यह उपाय सफल रहा, क्योंकि किसी मेले में हैजे की बीमारी नहीं हुई।

हैजा-निरोधक वैक्सीन

इस वर्ष ३३,७६,८०० खुराक हैजा-निरोधक वैक्सीन तैयार की गई, जबकि पिछले वर्ष ३०,३८,५४४ खुराक ही तैयार की गई थी।

मलेरिया

सहारनपुर, शाहजहाँपुर और खीरी के जिलों के अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों में न्यूनाधिक रूप से महामारी के रूप में मलेरिया फैलने की रिपोर्टें मिलीं। अन्य जिलों में मलेरिया की दशाये साधारण रही। इन जिलों में उदारता से पेल्ड्रीन की गोलियाँ बाँटी गयीं।

कुछ स्थानों में मलेरिया से सम्बन्धित बातों की जाँच और निरीक्षण किया गया और प्रत्येक दशा में आवश्यक सफाईशर्तें की गयीं। इस वर्ष निम्नलिखित मलेरिया-नियंत्रक यूनिटों ने काम किया :—

(१) २ प्रान्तीय यूनिटें—एक झाँसी जिले में ललितपुर स्थान पर और दूसरी बिजनौर जिले में नगीना स्थान पर;

(२) नैनीताल तराई के किछा क्षेत्र और मेरठ जिले के गंगाखान्द में उपनिवेशन योजना के सम्बन्ध में यूनिटें स्थापित की गयीं;

(३) विश्व स्वास्थ्य सस्था (डब्ल्यू० एच० ओ० यू० एन० आई० सी० ई० एफ०) के संस्वावधान में नैनीताल तराई के लिये मलेरिया कंट्रोल डिमान्स्ट्रेशन की एक टीम काम करने लगी;

(४) एक यूनिट, जिसकी स्थापना जिला नैनीताल के लोहिया हेड नामक स्थान पर शारदा जल-विद्युत के निर्माण के सम्बन्ध में की गई थी;

(५) एक मलेरिया-निरोधक यूनिट, जिसका व्यय आई० सी० एम० आर० और इस राज्य ने मिलकर वहन किया और जो काशीपुर, जिला नैनीताल के उपनिवेशन क्षेत्र में कार्य करती रही।

राज्य के पूर्वी जिलों में काला आजार के १० यूनिट जिनके साथ सचल काला आजार औषधालयों की व्यवस्था की गई थी, पडताल और परिचर्या का कार्य करते रहे।

वर्ष के दौरान में बी० सी० जी० के टीके लगाने वाली ६ टीमों ने काम किया बी० सी० और बनारस, फिरोजाबाद, कानपुर, मेरठ, शाहजहाँपुर, झांसी, मथुरा, रामपुर, जी० के टीके अलगाव, फंजाबाद, टोंडा, हाथरस, सहारनपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, उन्नाव, हापुड़, इटावा और रुड़की के टाउनो तथा देहरी-गढ़वाल, कानपुर, अलीगढ़, और मेरठ के देहाती क्षेत्रों में काम हुआ। प्रत्येक टीम में ६ विशेषज्ञों (टेक्नीशियन्स) को लेकर रखकर उनकी शक्ति इसलिये बढ़ा दी गई ताकि बड़ पैमाने पर काम हो सके। ६,५१,१०० से अधिक व्यक्तियों की जाँच की गई और उनमें से १,६९,२६० व्यक्तियों को टीके लगाये गये।

ट्यूबरक्यूलोसिस सीलों की बिक्री का आन्दोलन, जो जनता को ट्यूबरक्यूलोसिस शिक्षा देने के उद्देश्य से कुछ वर्षों से अन्य देशों में और अक्टूबर, १९५० ई० से भारत में प्रारम्भ किया गया था, जारी रहा। इस आन्दोलन का मुख्य काम यह था कि व्यक्तिगत रूप से मनुष्यों से भेंट की जाय और उनसे एक आने की कीमत वाली सीलों के मोल लेने का आप्रह करने के साथ-साथ उन्हें ट्यूबरक्यूलोसिस से सम्बन्धित अन्य उपयोगी सूचना भी दे दी जाय। उत्तर प्रदेश में इस आन्दोलन के द्वारा १९५०-५१ ई० में २,३६,४०० रु० इकट्ठे किये गये और यह तथ्य हुआ कि पहिले में सरकार ने जो व्यवस्था की है उसके अतिरिक्त स्थानीय ट्यूबरक्यूलोसिस-निरोधक योजना की उन्नति के लिये यह एकत्रित धनराशि वितरित की जाय।

शय की सीलों
(ट्यूबर-
क्यूलोसिस
सील्स)

समस्त म्युनिसिपैलिटियों और नोटीफाइड और टाउन एरियाओं में प्रिवेन्शन आफ फूड एडल्ट्रेशन ऐक्ट लागू था। पब्लिक एनालिस्ट को २३,२०० खाद्य के नमूने प्राप्त हुए, जिसमें से ५,१०० नमूनों में मिलावट पाई गई। दूध में ४५.४ प्रतिशत की सबसे अधिक मिलावट रही जिसके बाद आटा और दालों में (३५.६ प्रतिशत) मिलावट पाई गई।

भोजन तथा
औषधियों
में मिलावट

औषधियों के बनाने और बेचने पर कठोर देखभाल रखी गयी।

जिन निर्माणकर्ताओं की औषधियों का स्टैन्डर्ड निम्नकोटि का पाया गया उनकी औषधियों को स्टैन्डर्ड तक लाने के लिये अवसर दिया गया। यदि कभी अन्य राज्यों या विदेशी औषधि निर्माणकर्ता की निम्न कोटि की स्टैन्डर्ड की औषधियाँ यू० पी० में बेची जाती थी। तब अन्य राज्यों और भारत सरकार के ड्रग्स कन्ट्रोलर का इस बात पर ध्यान आकर्षित किया गया जिन औषधियों में अंशतः आयुर्वेदिक और अंशतः एलोपैथिक के अंश पाये जाते थे उन् पेटेन्ट और प्रोप्राइटरी औषधियों के निर्माण करने वालों को यू० पी० ड्रग्स क्लब के अधीन लाइसेंस लेना आवश्यक था। आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक इन्जेक्शनों के निर्माण करने वालों को भी बायोलॉजिकल (जीव विज्ञान) सम्बन्धी वस्तुओं के तैयार करने से सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस लेना आवश्यक था। नैकली दवाइयों के व्यापार पर रोक थाम की गई और प्राण-रक्षक मुख्य औषधियों पर नियन्त्रण जारी रखा गया।

रासायनिक विश्लेषण के लिये आये हुए पानी, खाद्यपदार्थ, कीटाणुनाशक वस्तुओं तथा व्यापार चलाने वाली चीजों इत्यादि के ३१२ नमूनों और वेक्टीरिया सम्बन्धी विश्लेषण के लिये आये हुये १,६१४ नमूनों का विश्लेषण किया गया। म्युनिसिपल पानी सप्लाय की शुद्धता पर नियन्त्रण पूर्ववत् जारी रहा।

जल और खाने
की चीजों
आदि का
विश्लेषण

पोषक तत्व

मेरठ, मुजफ्फरनगर, बलिया, फर्रुखाबाद, उन्नाव और गाजीपुर जिलों के देहाती क्षेत्रों में स्कूल के बच्चों को पोषित करने वाले तत्वों की जांच की गई। २३ स्कूलों के २,४४० से अधिक लड़कों की जांच की गई। उनमें से लगभग ३.३ प्रतिशत अधिक अच्छी स्वास्थ्य और ५३.३ प्रतिशत लगभग अच्छे स्वास्थ्य के पाये गये। शेष में ३७.३ प्रतिशत लड़कों का स्वास्थ्य खराब और ६.१ प्रतिशत लड़कों का स्वास्थ्य बहुत ही खराब था। साधारण रूप से विटामिन 'ए' की कमी पाई गई। कानपुर स्थित फैक्टरियों में भी इसी प्रकार की जांच की गई और वहाँ भी ऐसे ही फल प्राप्त हुए।

जनता को पोषकतत्वों के सम्बंध में शिक्षा देने के लिये विभिन्न प्रकार की पुस्तिकाएँ लिखी गयी, जिनमें स्कूल के बच्चों के लिये एक विशेष पुस्तिका थी और इससे सम्बन्धित बड़े बड़े इशतहार बाँटे गये और प्रदर्शनियो की गयी। यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेन एमरजेंसी फन्ड द्वारा उत्तर प्रदेश के १२ वर्ष से छोटे अपर्याप्त और संतुलित पोषक तत्वों को खाने वाले बच्चों तथा गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं को ४,६०,००० पौन्ड स्किम मिल्क पाउडर वितरित किया गया। प्रतिदिन विभिन्न स्थानों पर लगभग ३०,००० लाभार्थियों को दूध बाँटा गया, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक को फिर से बनाया गया ८ औन्स स्किम मिल्क मिला, जिसमें ४० ग्राम स्किम मिल्क का पाउडर सम्मिलित था।

लखनऊ शहर के प्राइमरी स्कूलों में राज्य सरकार से वित्तपोषित दूध योजना को जारी रखा गया। इस योजना के अर्धीन नाममात्र का मूल्य २ आने प्रति सेर विद्यार्थी को ८ औंस दूध दिया गया। म्युनिसिपल बोर्ड ने उक्त लड़कों के लिये भुगतान किया जो इतना धन भी चुकाने में असमर्थ थे। कई हायर सेकेंडरी स्कूलों और कालेजों में श्रुत के अनुसार चुने हुए चावल, अंकुरित चने, दूध या फलों की सप्लाई चालू की गई।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा (यू० पी० पब्लिक हेल्थ सर्विस) के एक अधिकारी को पोषक तत्व सम्बन्धी विषय के अध्ययन के लिये यूनाइटेड किंगडम भेजा गया था।

स्कूल के बच्चों की परीक्षा

पूर्ववत् ढंग से स्कूल के बच्चों के स्वास्थ्य की परीक्षा जारी रही। ऐंग्लो हिन्दुस्तानी स्कूलों में विस्तृत रूप से स्वास्थ्य की परीक्षा ली गई। १४ बड़े बड़े नगरों के स्कूल क्लिनिकों में छात्रों के इलाज की व्यवस्था की गई।

औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान

स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारियों (मेडिकल अफसर आफ हेल्थ) ने अपने अपने क्षेत्रों में कारखानों के इन्स्पेक्टरों का काम किया और चिकित्सा तथा सफाई सम्बन्धी मामलों में सलाह दी।

जनवरी, १९५१ ई० में नियुक्त किये गये औद्योगिक हाइजीन अफसर ने १४७ से अधिक फैक्टरियों की जांच की और विभिन्न काम में लगे हुए २,२०० से अधिक मजदूरों की शारीरिक जांच की गई। कानपुर स्थित चमड़े की कमाई और स्टैल् मोड़ने के कारखाने, मिर्जापुर के चपड़े के उद्योग और मुरादाबाद के धातु पर पालिश करने वाले कारखानों में काम करने वालों की विशेष रूप से स्वास्थ्य और कार्य सम्बन्धी दशाओं की जांच की गई। स्वास्थ्य और रक्षा को प्रभावित करने वाली दशाओं और परिस्थितियों के सुधार के लिये सिफारिशें की गईं और जहाँ कहीं भी आवश्यकता हुई वहाँ पेशे के रोगों और क्षति की ओर ध्यान दिया गया। भोजन देने के प्रबन्ध में भी सुधार करने का सुझाव दिया गया।

लोगों की स्वास्थ्य-शिक्षा का आयोजन पूर्व की भांति सचित्र पोस्टरों के प्रदर्शनों, प्रदर्शिनियों, मैजिक लैटर्न के साथ दिये जाने वाले भाषणों तथा सिनेमा चित्रों की सहायता से किया गया था। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने क्षय रोग के कारण और उस रोग को फैलाने वाली परिस्थितियों के विवेचनार्थ जो ट्रेलर के रूप में फिल्म तैयार की थी, उसे सिनेमाघरों में दिखाया गया। क्षय रोग से सम्बन्धित ४,६०० से अधिक पुस्तिकायें स्कूलों के जूनियर रेडक्रास ग्रुपों में बाँटी गईं।

१,५४,६०० से अधिक बच्चों को जूनियर रेड क्रॉस के सदस्यों के रूप में भर्ती किया गया और लगभग २,२०० बच्चे प्राथमिक चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विज्ञान के मेकेजी स्कूल कोर्स पढ़ने लगे।

५,८०० से अधिक व्यक्तियों ने फर्स्ट एंड होम नर्सिंग और अन्य सेंट्रल ज्ञान एम्बुलेंस एसोसियेशन के विषयों में ट्रेनिंग प्राप्त की। कई जिलों के रोडवेज के कर्मचारियों ने भी फर्स्ट एंड होम ट्रेनिंग प्राप्त की। प्लानिंग इन्सपेक्टरों और अन्य विभिन्न कार्यकर्ताओं, जिनमें महिला हितकारी केन्द्रों की कार्य करने वाली स्त्रियाँ भी सम्मिलित हैं, को जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों पर भाषण दिये गये।

प्रतापगढ़ जिले की स्वास्थ्य सम्बन्धी यूनिट में रोगों से बचने के उपाय और सामाजिक स्वास्थ्य विज्ञान के सबध में प्रगाढ़ रूप से काम होता रहा। इस यूनिट के एक कमरे में संग्रहालय और मैदान में प्रदर्शन क्षेत्र का कार्य चलता रहा और दूरी से १०वीं कक्षाओं के स्कूल के बच्चों के लिये विशेषरूप से स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा का आन्दोलन चलाया गया। पोषक तत्वों, महामारी और छुआछूत की बीमारियों, वैयक्तिक स्वास्थ्य विज्ञान और सामान्य सफाई पर भाषण दिये गये और प्रदर्शनों का भी संगठन किया गया। लगभग १,५०० लड़के और लड़कियों ने इस पाठ्यक्रम को पढ़ा और सामान्य स्वास्थ्य की आवश्यकताओं के विषय में प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त किया। बड़ी-बड़ी तीन प्रदर्शिनियाँ लगई गईं और ५ गावों में संडास (Bored Hole Latrines), पशुशालायें, सोकेज पिट और स्वच्छ कुयें बनवाये गये। स्वास्थ्य संबंधी यूनिट ने निवास अथवा गृह संबंधी धात्री-सेवा के लिये स्वास्थ्य निरीक्षकों की देख-भाल में चार जच्चा-बच्चा केन्द्र और धात्रियों (midwives) की देख-भाल में आठ जच्चा-बच्चा केन्द्र खोले। इन केन्द्रों में क्लिनिकें भी रखी गईं, जहाँ देहाती दाइयों को भी ट्रेनिंग दी गई। प्रसव से पूर्व स्त्रियों को रजिस्टर किया गया और प्रसूति-काल में देख-भाल की गई। प्रसव के पश्चात् स्त्रियों और शिशुओं की भी देख-भाल पर अधिक जोर दिया गया। जिन देहाती क्षेत्रों में आनेजाने की सुविधा कम थी वहाँ के कुल २,६५४ जन्म सम्बन्धी मामलों में से १,५३८ मामलों की देख-भाल हुई। उस क्षेत्र के ६० प्रतिशत बच्चों को चेचक से बचाया गया।

स्वास्थ्य-
शिक्षा

प्रतापगढ़
स्वास्थ्य
यूनिट

उन क्षेत्रों के लिये जो अब तक देहरी और बनारस रियासतों में थे, आठ नये जच्चा-बच्चा और शिशु कल्याण केन्द्र स्वीकृत हुये। पूर्व से स्वीकृति पाये हुये लगभग २०० सरकारी केन्द्रों ने वर्ष भर उत्तर प्रदेश के शेष भाग में काम किया। जो केन्द्र अस्पतालों और औषधालयों के निकट स्थित थे उनको धात्रियों के काम और असाधारण मामलों की देखरेख के लिये अस्पतालों और औषधालयों से सम्बद्ध कर दिया गया।

जच्चा-बच्चा
तथा शिशु-
कल्याण

ग्रामीण जच्चा-बच्चा केन्द्रों की लगभग २५० देशी दाइयों को ट्रेनिंग दी गई। यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रेन एमरजेंसी फंड ने इस राज्य को जच्चा-बच्चा तथा शिशु स्वास्थ्य सम्बन्धी सज्जा और जच्चा-बच्चा के लिये उपयोगी बक्स दिये और उनका बड़े-बड़े केन्द्रों में प्रयोग हुआ।

संतति नियोजन

इंडियन रेडक्रास सोसाइटी की उत्तर प्रदेश की शाखा ने मार्च, १९५१ ई० में संतति नियोजन के संबंध में सलाह देने का निश्चय किया। प्रारम्भ में यह काम केवल लखनऊ में ही सीमित रहा, परन्तु बाद में इस काम को शुरू करने के लिये इस संगठन ने बाहर के २४ अस्पतालों को सहायता प्रदान की। इस संबंध में राज्य सरकार ने रेडक्रास को १०,००० रु० का एक प्रतीक अनुदान दिया।

लखनऊ नगर के विभिन्न भागों (सेक्टरों) में स्त्रियों को सलाह देने के लिये क्लीनिकों का संगठन किया गया और योग्य डाक्टरों ने मुफ्त सलाह दी। बाद में पुरुषों को भी सलाह देने के लिये दो सुसज्जित क्लीनिक संगठित किये गये। इन क्लीनिकों में केवल लागत के मूल्य पर जनता को साहित्य और अन्य सामान मिलता था। सलाह देने के संबंध में माँ की आयु और स्वास्थ्य तथा उससे उत्पन्न बच्चों और उनमें से जीवित पैदा किये गये बच्चे और जीवित बच्चों की संख्या का ध्यान रखा गया। जुलाई, १९५१ ई० से, जब काम प्रारम्भ हुआ, दिसम्बर तक इन क्लीनिकों में १,००० व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति आये और उन्होंने सलाह ली।

स्वास्थ्य निरीक्षकों और घात्रियों ने भी अपने-अपने क्षेत्र में इसका प्रचार किया और बड़े-बड़े कार्यालयों तथा संस्थाओं में वहाँ काम करने वालों के लाभ के लिये भाषणों की व्यवस्था की गई।

यह तय हुआ कि उत्तर प्रदेश के दो अन्य बड़े शहरों में भी लखनऊ के आधार पर काम का विस्तार किया जाय। फिर भी यह माना गया कि इस संबंध में देहाती क्षेत्रों की जनता को शिक्षित करने पर जन-संख्या में प्रभावशील कमी हो सकती। यह बात भी स्पष्ट थी कि ऐसे क्षेत्रों के लिये एक विभिन्न उपाय की आवश्यकता होगी। तदनुसार सरकार ने लखनऊ विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र और मानवीय-सम्बन्ध स्थापित कराने वाले विभाग (Department of Sociology and Human Relationship) को गाँवों में संभव तरीकों पर काम करने के उपाय खोजने के लिये एक अनुदान दिया।

शहर के कूड़ा-करकट से मिलवा खाद बनाना

शहर के कूड़ा-करकट से कृषि योग्य मिलवा खाद बनाने की योजना जारी रही और २३ नए मिलवा खाद के केन्द्र खोले गये। वर्ष भर में ३,३८,४०० टन मिलवा खाद तैयार की गई, जबकि गत वर्ष ३,१४,४१४ टन खाद तैयार हुई थी। कुल खाद का ६४ प्रतिशत से अधिक भाग बच दिया गया।

प्रारम्भिक विभिन्न कठिनाइयों के कारण कानपुर में एक छोटे पमाने पर बूचड़ाने के कूड़े-करकट से खून की खाद तैयार करने का काम प्रारम्भ किया जा सका। यह खाद काफी लाभप्रद प्रमाणित हुई और हापड़ जैसे दूर स्थानों से किसान इसको ७ रुपये प्रतिमन की दर से खरीदने के लिये आये।

५० राजकीय हेल्थ बोर्ड

१९५१ ई० में राजकीय हेल्थ बोर्ड की दो बैठकें हुईं। बोर्ड को छोटे-छोटे स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के लिये सहायिक अनुदान के रूप में ४,६०,००० रु० की धनराशि निर्यत की गई। इसके लिये नियत धनराशि का पूर्णरूप से उपयोग हुआ और बोर्ड ने पानी सप्लाई के सुधार, गन्दे पानी के निकास की नालियों, गोशत के बाज़ारों और कौलघरों (Slaughter Houses) तथा सफाई से संबंधित विभिन्न मदों में अनुदान स्वीकृत किये। प्रत्येक मामले में साधनों और परिस्थितियों के अनुसार स्थानीय चर्चों की व्यवस्था करने को भी कहा गया। कुछ विशेष मामलों में जैसे हरिजनों के लिये कुओं के बनाने में

बोर्ड ने स्थानीय निकायों द्वारा तैयार की गई स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की छानबीन की और इस बात की सिफारिश की कि ऋण के रूप में कुल लागत की कितनी धनराशि अनुदान के रूप में और कितनी ऋण के रूप में दी जाय। आलोच्य वर्ष में कई बड़ी योजनाओं की छानबीन की गई। स्वास्थ्य विभाग संबंधी प्रशासन से संबंधित नीति के कुछ मामले भी बोर्ड को सलाह के लिये भेजे गये।

राजकीय हेल्थ कौन्सिल की भी दो बैठकें हुईं। अन्य मामले जिन पर राज्य स्वास्थ्य कौन्सिल ने विचार किया वे ये हैं :—

राज्य में अस्पतालों का प्रान्तीयकरण, बायोलाजिकल तथा पदार्थों के निर्माण का स्तरीकरण, वैश्व और हकीमों द्वारा सल्फा औषधियों (Sulpha Drugs), पेन्सिलीन और स्ट्रेप्टोमाइसीन का दिया जाना, औषधि अनुसंधान, निष्पन्न और एकीकरण करने के लिये राज्य द्वारा एक संगठन, नर्सिंग के लिये एक पाठ्यक्रम और डाक्टरों के लिये एक अल्बर्टाईन अनिवार्य सैनिक शिक्षा के पाठ्य-क्रमों की व्यवस्था करना।

५१—चिकित्सा-सुविधायें

(क) पल्लौपैथिक प्रणाली

इस वर्ष राज्य में चिकित्सा-सुविधायें बढ़ाने की सरकारी योजनाओं के संबंध में और अधिक प्रगति हुई।

ग्रामीण जनता में और अधिक लोगों को चिकित्सा संबंधी सहायता देने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से १७ नये अस्पताल खोलने की स्वीकृति दी गई। इस वर्ष ८८ राज्य सहायता प्राप्त एलोपैथिक अस्पताल भी चालू रहे यद्यपि इसी प्रकार चिकित्सकों को राज्य सहायता देकर चिकित्सा सहायता बढ़ाने की योजना पूरी तरह कार्यान्वित न हो सकी, क्योंकि चिकित्सक गांवों में बसने के लिये अन्यमनस्क थे। १९५१-५२ ई० में केवल २० यूनिटों में काम हुआ, जबकि ८२ यूनिटों की स्वीकृति मिली थी। उस योजना को, जिसे १९४८ ई० में ग्रामीण क्षेत्रों में बसने के लिये इच्छुक विस्थापित चिकित्सकों को राज्य सहायता देने के निमित्त अस्थायी रूप से प्रारम्भ किया गया था, छोड़ देना पड़ा।

जिला परामर्शदात्री समितियों के बनाने का काम, जो १९५० ई० में इसलिये प्रारम्भ किया गया था कि ग्रामीण चिकित्सा यूनिट ठीक से काम करें, पूरा किया गया।

बलरामपुर राज के सात अस्पतालों का प्रान्तीयकरण किया गया और इस प्रकार प्रान्तीयकरण किये गये कुल अस्पतालों की संख्या १६ हो गई।

भवन निर्माण संबंधी कार्यक्रम की ओर भी समुचित ध्यान दिया गया। देहरादून में अस्पताल की इमारतें काफी बड़ा दी गईं और युद्धोत्तर पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत कम्पाउण्डों के लिये जो ९० क्वार्टर बनाने का प्रस्ताव किया गया था उनमें से ५९ क्वार्टर १९५१ ई० के अंत तक बनाकर पूरे किये गये।

बनारस के किंग एडवर्ड सप्तम अस्पताल की विस्तृत रूप से मरम्मत की गई और बरेली के मस्तिष्क रोगों के अस्पताल के वार्ड नं० ४ और ९ का पुनर्निर्माण किया गया और इन पर क्रमशः १,८४,००० और १,५३,५०० रु० खर्च हुए। मेडिकल कालेज, लखनऊ के विस्तार, रायबरेली और देवरिया में नये अस्पताल, पी० एल० शर्मा अस्पताल, मेरठ में सुधार और आगरा मेडिकल कालेज में पलश लैट्रिन बनाने के काम होते रहे। डाक पाथर (जिला देहरादून) में टी० बी०

गांवों में
चिकित्सा
संबंधी सहा-
यता

अस्पतालों में
सुधार

सैनोटोरियम के भवन में परिवर्तन और परिवर्द्धन का काम और बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में व्याधिकीय प्रयोगशाला (पैथेल जिकल लैबोरेटरी) का निर्माण कार्य हाथ में लिया गया ।

परिचारक
सेवा
Nursing
Services

नर्सों की कुछ कमी होते हुये भी रोगियों के लाभ के लिये चालू परिचारक सेवा योजना (Nursing Services Scheme) संतोषजनक रूप से चलती रही । फिर भी यह देखा गया कि कुछ अच्छी शिक्षित और प्रतिष्ठित परिवारों की लड़कियां परिचारक-वृत्ति (नर्सिंग प्रोफेशन) के लिये आने लगीं और यह आशा की गई कि इससे ट्रेनिंग पाई हुई नर्सों की कमी की समस्या हल हो जायगी ।

सेंट्रल मेडिकल
स्टोर्स डिपो

सदा की भांति आकस्मिक मांगपत्र मिलने पर सेंट्रल मेडिकल स्टोर्स डिपो राज्य में स्थित अस्पतालों और औषधालयों को भेषज और औषधियां सफाई करता था । लगभग २५ लाख रुपये की लागत पर अस्पतालों के साज-सामान की व्यवस्था, जिसमें फ्लूक्चर टेबुल, हाइड्रोलिक आपरेशन टेबुल, अल्ट्रावाइलेट और इनफ्रारेड यंत्र, शैडोलेस लैम्प शामिल हैं, विभिन्न अस्पतालों के लिये की गई । ६ अस्पतालों में पुरानी एक्स-रे मशीनों के बदले नई मशीनें लगाई गईं ।

शुल्क
विश्वजालय
Pay Clinic
महिलाओं
की चिकित्सा
सहायता

राज्य के कुछ महत्वपूर्ण जिला अस्पतालों में जो शुल्क विश्वजालय (Pay Clinic) स्थापित किये गये वे चालू रहे । उनको अधिक जन-प्रिय बनाने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

इस वर्ष महिलाओं के लिये उत्तर प्रदेश में राजकीय अस्पतालों की संख्या बढ़कर १०४ हो गई ।

महिलाओं के लिये जो नए राजकीय अस्पताल भी खोले गये और रतिज रोगों के उपचार तथा अन्य प्रयोजनों के लिये गैर-सरकारी महिला औषधालयों के लिये कुल मिलाकर ४२,००० रु० के अनुदान स्वीकार किये गये ।

माताओं की स्वास्थ्य-रक्षा तथा और अधिक स्वस्थ सन्तान की उत्पत्ति करने के विचार से लखनऊ में एक प्लान्ड पेरेंटहुड स्कीम चालू की गई । इस योजना के अधीन माता-पिता, पति या पत्नी को निःशुल्क यह राय दी जाती थी कि बच्चे किस क्रम से पैदा किये जायें । कृत्रिम उपायों से सन्तानोत्पत्ति रोकने की वस्तुये कम कीमत पर जनता को मिलने लगी ।

चक्षु-चिकित्सा
के लिये
सहायता

गांधी आई हास्पिटल, अलीगढ़; गांधी मेमोरियल एंड एसोसियेटेड हास्पिटल, लखनऊ; एस० एन० हास्पिटल, आगरा; सीतापुर आई हास्पिटल; शिक्षक आई हास्पिटल तथा खैराबाद आई हास्पिटल ने राज्य में चक्षु संबंधी चिकित्सा सहायता का काम किया । इस प्रकार का काम करने के लिये कई जिलों में चक्षु संबंधी चिकित्सा सहायता संस्थाओं का संगठन किया गया । १९५१-५२ ई० में चक्षु संबंधी चिकित्सा सहायता-कार्य के लिये सरकार ने ५०,००० रु० का अनुदान दिया, जबकि पिछले वर्ष ३०,००० रु० दिया गया था । देहरादून में जौनसार-बाबर के पिछड़ हुए भागो और कुमायूं डिवीजन में चक्षु संबंधी चिकित्सा सहायता का कार्य चलान के लिये विशेष अनुदान दिये गये । अलीगढ़ के गांधी आई हास्पिटल में आई बैंक की कार्यवाहियां यथावत् चालू रही ।

क्षय रोग-

क्षय रोग से पीड़ित व्यक्तियों के उपचार के लिये अधिकतर सुविधाओं की व्यवस्था करने के निमित्त एक ऐसा क्षय रोगियों का सैनोटोरियम डाक पाथर, देहरादून में स्थापित किया गया, जिसमें ८८ विस्तर है । किंग एडवर्ड सप्तम

सैनिटोरियम, भुवाली में रोगियों को रखने की निरन्तर बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के उद्देश्य से भुवाली के बिल्कुल पास भूमियाधर में, इसी सैनिटोरियम से संयोजित एक और उप-सैनिटोरियम खोला गया। लाला लाजपतराय हास्पिटल, कानपुर में क्षय रोगियों के लिये २२ चारपाई वाला एक वार्ड खोला गया। टी० बी० सील्स के विक्रय से प्राप्त धन में से कुल मिलाकर १,८६,००० रु० का अनुदान राज्य के क्षयरोग विरुजालयों (क्लीनिक्स) के पुनर्संगठन और अतिरिक्त विरुजालयों की स्थापना के लिये दिया गया।

इस वर्ष राज्य में १५ कुष्ठ रोग चिकित्सालय थे जिनमें कुल १,१७४ रोगियों के रहने का प्रबंध था। गोरखपुर जिले में, गोरखपुर जोन में, जिसमें गोरखपुर, गोडा, बहराइच और देबरिया जिले शामिल हैं, १९५० ई० में जो कुष्ठ-निराधक यूनिट खोला गया था उसने कुष्ठ रोग का सर्वे करने और संक्रामित रोगियों को चुन-चुन कर निकटतम केन्द्र में उपचार के लिये भेजने का काम बराबर संतोषजनक ढंग से किया।

कुष्ठ रोग

आलोच्य वर्ष में चकराता (जिला देहरादून) और दूधी (जिला मिर्जापुर) दोनो ही में रतिज रोग विरुजालय स्थापित किये गये।

रतिज रोग

कार्यक्रम के अनुसार मेडिकल लाइसेंसियेटों की पदोन्नति करने के लिये १५ लाइसेंसियेटों को, जिनमें १९ निजी तौर पर चिकित्सा करने वाले डाक्टर भी शामिल थे और जो स्थानीय बोर्डों में नौकर थे, सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा और मेडिकल कालेज, लखनऊ में एम०बी०, बी०एस० का द्विवर्षीय संक्षिप्त पाठ्यक्रम पूरा करने के लिये भर्ती किया गया। १९५१ ई० में सात सर्विस डाक्टरों का एक जत्था उच्च शिक्षा के लिये विदेश भेजा गया और इसी वर्ष सात डाक्टर विदेशों में उच्च शिक्षा समाप्ति के बाद वापस लौट आये। जो तीन डाक्टर पिछले वर्ष भेजे गये थे वे अपने अध्ययन में लगे रहे। काउन्टेस आफ डफरिन फंड, यू० पी० की प्रान्तीय समिति चिकित्सा छात्राओं को छात्र-वेतन देती रही। इस वर्ष छात्र-वेतन पाने वाली छात्राओं की कुल संख्या १० थी।

चिकित्सा
संबंधी शिक्षा

दो मात्रिकाओं और एक सिस्टर ने कालेज आफ नर्सिंग, नई दिल्ली में प्रशासन संबंधी पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न किया। एक सिस्टर ने इसी संस्था में सिस्टर ट्यूटर का पाठ्यक्रम पूरा किया। प्रशासकीय पाठ्यक्रम के लिये दो मात्रिकाएँ और सिस्टर ट्यूटर के पाठ्यक्रम के लिये एक सिस्टर देहली कालेज में भेज दी गई।

कानपुर में नर्सों की प्रारम्भिक शिक्षा के लिये सेन्ट्रल स्कूल की इमारत का निर्माण पूरा हो गया था, किन्तु वर्ष समाप्त होने तक उसमें शौचालय, पानी और बिजली के प्रबंध का कार्य शेष रह गया था।

राजकीय अस्पतालों में काम करने वाली मात्रिकाओं में से एक एन० सी० ई० एफ० फेलोशिप के अंतर्गत तैनात की गयी। यह फेलोशिप अस्पताल प्रशासन के स्नातकोत्तर ट्रेनिंग तथा विशेष रूप से नर्सिंग ट्रेनिंग के लिये वर्ल्ड हेल्थ आगनाइजेशन द्वारा प्रदान की गई है।

आलोच्य वर्ष मे यू० पी० स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने निम्नलिखित परीक्षाये लीं:—

क्र०-सं०	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या
१	डिप्लोमा प्राप्त नर्स	९७
२	प्रमाण-पत्र प्राप्त नर्स	२९
३	डिप्लोमा प्राप्त मात्रिकाएं	६४
४	प्रमाण-पत्र प्राप्त मात्रिकाएं	५२
५	हेल्थ विजिटर्स	५
६	कम्पाउन्डर और ड्रेसर्स सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन (भाग २)	३६

किंग एडवर्ड सप्तम सैन्टोरियम, भुवाली के सुपरिन्टेण्डेंट को किश्चियन मेडिकल कालेज हास्पिटल, वेल्डोर के औरस विभाग (Thoracic Deptt) में उस अस्पताल में की जाने वाली औरस शल्य चिकित्सा की कला का ज्ञान प्राप्त करने के निमित्त दो महीने के लिये भेजा गया। वेल्डोर से वापस आने पर भुवाली सैन्टोरियम में औरस शल्य चिकित्सा आरंभ कर दी गई। यह भी निश्चय किया गया कि १ जनवरी, १९५२ ई० से औरस शल्य चिकित्सा के २ साल का पाठ्यक्रम पूरा करने के लिये एक पी० एम० एस० (प्रथम) अफसर को किश्चियन मेडिकल कालेज हास्पिटल, वेल्डोर भेजा जाय।

एक पी० एम० एस० (प्रथम) अफसर देहली विश्वविद्यालय के डी० टी० डी० का पाठ्यक्रम पूरा करके लौटा है और आलोच्य वर्ष में दो अन्य अफसर इसी पाठ्यक्रम के लिये भेजे गये।

लखनऊ विश्वविद्यालय की संरक्षता में दन्त चिकित्सा की शिक्षा देने के लिये लखनऊ में एक डेंटल कालेज खोला गया। डेंटल कालेज और अस्पताल की इमारतों की बनान का खाका और तखमीना अंतिम रूप से तैयार किया गया और इस वर्ष इस कार्य का अधिकतर भाग पूरा हो चुका है।

शिशु-जन्म पूर्व
संबंधी और
शिशु हित-
कारी केन्द्र

सन् १९४४ ई० में एस० एन० मेडिकल कालेज, आगरा में धात्री विज्ञान और स्त्री चिकित्सा में चिकित्सा छात्रों को ट्रेनिंग देने के लिये श्री शिशु-जन्म पूर्व संबंधी और शिशु हितकारी केन्द्र खोले गये थे, वे उपयोगी कार्य करते रहे।

(ख) देशी चिकित्सा-प्रणाली

सामीन्य

इस वर्ष इस राज्य में ५१४ राजकीय औषधालय अर्थात् ४३३ आयुर्वेदिक और ८१ यूनानी औषधालय चलते रहे। इनमें से ६७ आयुर्वेदिक और ३ यूनानी औषधालय कुछ रियासतों और अन्तर्क्षेत्रों के उत्तर प्रदेश में विलीन होने के फल-स्वरूप प्रबंध में ले लिये गये। इनके अतिरिक्त जिला बोर्ड गांवों में २१९ आयुर्वेदिक और ९० यूनानी औषधालयों को, जहाँ उनके ही नियंत्रण में थे, चलाते और उनका खर्च देते रहे। नागरिक क्षेत्रों में म्यूनिसिपल बोर्डों ने १५ आयुर्वेदिक और १२ यूनानी औषधालयों को चलाया और तत्सम्बन्धी खर्च किया। जिला बोर्डों के राज्य सहायता प्राप्त औषधालयों की संख्या ७७ (६० आयुर्वेदिक और १७ यूनानी) थी और राज्य सहायता पाने वाले चिकित्सकों (प्रेक्टिशनर्स) की संख्या २८ (१८ आयुर्वेदिक और १० यूनानी) थी। इनमें ११ राज्य सहायता पाने वाले उद्वासित चिकित्सक शामिल नहीं हैं।

सरकारी और वित्तीय सहायता पाने वाले औषधालयों का समय-समय पर निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिये किया गया था कि उनका काम ठीक चलता रहे। २० आयुर्वेदिक और ४ यूनानी राजकीय औषधालय, जो उपयुक्त स्थानों पर और अच्छे मकानों में नहीं थे, अच्छी जगहों पर ले जाये गये और उनके लिये अच्छे मकानों की व्यवस्था की गई। २५१ राजकीय औषधालयों के लिये किराये पर समुचित इमारतों की व्यवस्था की गई। सरकारी औषधालयों में आवश्यक सज्जा और फर्नीचर और राजकीय औषधि निर्माणशाला में तैयार की गई असली औषधियाँ पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करके उनकी दशा में सुधार किया गया। कई औषधालयों को चिकित्सकों के उपयोग के लिये उपयोगी चिकित्सा संबंधी पुस्तकें प्रदान की गई।

उपसंचालक (आयुर्वेद) के कार्यालय में एक ऐसे पुस्तकालय की स्थापना के कार्य में प्रगति की गई जो आधुनिक चिकित्सा संबंधी और वैज्ञानिक पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं (जर्नल्स) से सुसज्जित हो।

स्टेचुटेरी संस्था के रूप में बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन का अपने जीवन का यह पांचवां वर्ष है। आलोच्य वर्ष में बोर्ड की तीन आम बैठकें हुईं। विभिन्न परामर्शदात्री समितियों की भी, जिनका संबंध रजिस्ट्रेशन, शिक्षा और वित्त से है, बैठकें हुईं। २,७२८ वेंचो और ५१५ हकीमों की रजिस्ट्री की गई और बोर्ड की आयुर्वेदिक और यूनानी परीक्षाओं में ९९१ परीक्षार्थी बैठे। इनमें से ७४४ परीक्षार्थी सफल हुये। निम्नलिखित संस्थाओं का सबंध-विच्छेद किया गया और बंद किये गये:—

बोर्ड आफ
इंडियन मेडि-
सिन, उत्तर
प्रदेश

लेखराम आयुर्वेदिक कालेज, दौरली, मेरठ। आयुर्वेदिक विद्यालय, पचपोखरा, फरेंखाबाद। गांधी आयुर्वेदिक विद्यालय, हरदोई। मम्ब-उल-तिब्ब कालेज, लखनऊ। राज्य सहायता प्राप्त (स्टेट एडेड) यूनानी मेडिकल कालेज, लखनऊ। तिब्बिया कालेज, सहारनपुर। जगदम्बा आयुर्वेदिक विद्यालय, बनारस। नरेन्द्र विद्यामन्दिर, किरौली, आगरा। वृजभूषण सरस्वती आयुर्वेदिक विद्यालय, कानपुर। द्विवेदी आयुर्वेद विद्यालय, कानपुर।

मध्यभारत गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कालेज, ग्वालियर को बोर्ड से संलग्न किया गया। एक्सपर्ट कमेटी ने बी० आई० एम० एस० सहायक वृद्ध, गृह स्वास्थ्य विशारद और सहायक हकीमों के पाठ्यक्रम के लिये, जो पाठ्य विषयावली बनाई थी, उसीका बोर्ड ने सशोधन किया और यह निश्चय किया गया कि आगामी सत्र से उसे चलाया जाय। योग्यता के आधार पर २६ छात्रवृत्तियाँ और निर्धन और योग्य छात्रों की, जिनमें छात्राये भी थी, छात्रवृत्तियाँ दी गईं। छात्रवृत्तियों में कुल ४,६५० रु० की धनराशि दी गई। बोर्ड ने ३६,२०० रु० का सरकारी अनुदान ११ आयुर्वेदिक और यूनानी कालिजों से सबधित अस्पतालों, २६ सार्वजनिक औषधालयों और ३६ आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सकों में बांट दिया। १,५०० रु० की धनराशि रायपुरी, चुनार (जिला मिर्जापुर) के श्री हकीम दलजीत सिंह को एक आयुर्वेदिक कोष के प्रकाशन के लिये दिया गया।

धन की कमी होते हुये भी सरकार ने विश्वविद्यालय को और संलग्न कालेजों को कालेजों को भी आर्थिक सहायता देने में गत वर्ष की अपेक्षा अधिक उदारता अनुदान दिखलाई। १३ आयुर्वेदिक और यूनानी कालेजों के लिये ३,८८,३५७ रु० का कुल सहायक अनदान स्वीकृत किया गया।

- विकास कार्य** माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने उनके द्वारा व्यय करने के लिये निर्धारित की गई धनराशि में से कुल २५,००० रु० के सहायक अनुदान का वितरण आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के विकास के लिये योग्य संस्थाओं और व्यक्तियों में किया।
- मैनुअल की तैयारी** सरकार ने एक ऐसे मैनुअल को तैयार करने के लिये, जो विभाग के नियमों और विनियमों का सग्रह हो, एक विशेष कार्याधिकारी को नियुक्त करने की स्वीकृति दी। आलोच्य वर्ष में उन्न संबंध में कार्य की प्रगति होती रही।
- माघ मेला और अन्य मेलों में कार्य** प्रयाग में माघ मेला क्षेत्र में एक अस्थायी आयुर्वेदिक यूनिट की स्थापना की गई। इस यूनिट में लगभग ७,००० रोगियों की चिकित्सा हुई। रामनवमी और अन्य मेलों में सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य करने के लिये लगभग १०० वैद्य और हकीम भी नियुक्त किये गये।
- भेषज-संहिता समिति** भेषज-संहिता समिति की दो बैठकें हुईं और आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियों की एक प्रमाणिक भेषज संहिता तैयार करने से संबंधित विभिन्न बातों पर विचार-विमर्श किया गया। एक प्रश्नावली जारी की गई और इस देश के भिन्न-भिन्न भागों में लगभग २५० प्रख्यात वैद्यों और हकीमों में उसे इसलिये बांटा गया कि इस समस्या के टेक्निकल पहलुओं पर उनकी राय मालूम हो सके। जो उत्तर प्राप्त हुए हैं उनको इस वर्ष की समाप्ति तक सकलित किया जाता रहा और साथ ही उनकी जाच-पड़ताल भी होती रही। आयुर्वेदिक मिश्रणों पर तीन सौ निबन्धों का भी संकलन किया गया। ख्यातिप्राप्त आयुर्वेदिक और यूनानी फार्मसियों से अपने यहां तैयार की गई प्रमाणिक औषधियों और औषधि तत्वों के नमूनों को भजने के लिये अनुरोध किया गया।
- राजकीय औषधि निर्माणशाला** लखनऊ की स्टेट फार्मसी आफ आयुर्वेदिक ऐंड यूनानी मेडिसिन्स (आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियों की राजकीय निर्माणशाला) ने ५१४ राजकीय औषधालयों और गांवों के लिये ५,३०० औषधि पेटियों के लिये विशुद्ध आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों को तैयार करने और देने के कार्य को हाथ में लिया और उसे पूरा किया। उन क्षेत्रों में जहां औषधियों की कमी थी गांवों के लिये औषधि पेटियों में फिर से दवाइयां भरकर गांव पंचायतों के चार्ज में रख दी गईं। रिपोर्टों से यह पता चला कि इन पेटियों की औषधियों का उपयोग करके गांवों के लोगों ने बहुत लाभ उठाया।
- भूमि-दान** निम्नलिखित स्थानों में जनता ने राजकीय औषधालय खोलने के लिये उदारता से भूमि और इमारतें दान में दी :—
- चन्दौसी (जिला अलीगढ़)।
 - गोकुलपुरा (जिला आजमगढ़)।
 - पौजानिया (जिला बिजनौर)।
 - पौनगला (जिला बरेली)।
 - खिरसू (जिला गढ़वाल)।
 - देवाल (जिला गढ़वाल)।
 - करदहा (जिला उन्नाव)।
- ५२-पशु-पालन
- पशु-चिकित्सा** इस वर्ष राज्य में २२८ पशु चिकित्सालय थे, इनमें से २१ अस्पतालों संबंधी सहा-का प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा और शेष का स्थानीय निकायों द्वारा होता था। यथा वर्ष के अंत में विभाग में १९८ वेटरिनरी असिस्टेंट सर्जन और ६९४ स्टाकमैन काम कर रहे थे। वेटरिनरी अस्पतालों में और उनके बाहर

९,८६,००० मवेशियों का इलाज किया गया और १,२२,००० ऐसे मवेशियों को औषधि सप्लाई की गयी, जो वास्तव में अस्पतालों में नहीं लाये गये थे ।

विभिन्न संक्रामक रोगों, जैसे रिन्डरपेस्ट, हेमोरेजिक सेप्टीसीमिया, ब्लैक क्वार्टर इत्यादि से बचाने के लिये २६,३६,००० मवेशियों को सूइयाँ लगाई गयी । अन्य विकास विभागों के संयोजित फील्ड कार्यक्रमों की फील्ड ट्रेनिंग के लिये प्रबंध किये गये । विशेष संदेशवाहकों द्वारा बायोलाजिकल प्रोडक्ट्स की सप्लाई और जिला हेडक्वार्टर्स में कोल्ड स्टोरेज संबंधी सुविधाओं से सीरा और वेक्सिन की शीघ्र सप्लाई एवं संक्रामक रोगों के नियंत्रण में पर्याप्त सहायता मिली । सचल पशु-चिकित्सा यूनिट को मेरठ भेज दिया गया और उस जिले में पशुओं की प्रगाढ़ रूप से नस्लकशी करने में इस यूनिट से काफी लाभ हुआ । इंडियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च तथा राज्य सरकार द्वारा आधे आधे पर संयुक्त रूप से वित्तपोषित योजना के अधीन नवम्बर, १९५१ ई० में एक असिस्टेंट डिजीज कंट्रोल ऑफिसर (भेड़ और बकरियाँ) की नियुक्ति की गयी । विभिन्न मुर्गी-पालन रोगों, जैसे रानीखेत रोग, फाउल पाक्स और फाउल होल्स को रोकने के लिये वर्ष में लगभग ३४,६५९ चिड़ियों को सूइया लगायी गयी ।

वर्ष में बायोलाजिकल प्रोडक्ट सेक्शन का विस्तार हो रहा था । वर्ष में फील्ड कर्मचारियों को निम्नलिखित परिमाण में बायोलाजिकल प्रोडक्ट (अंशतः इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट से प्राप्त) सप्लाई किये गये :—

	खुराक
(१) एंटी-रिन्डरपेस्ट सीरम (साधारण)	२,२८,१५०
(२) एंटी-रिन्डरपेस्ट सीरम (विशेष)	६,४५०
(३) एच० एस० सीरम ..	५९,५००
(४) एन्थरेक्स सीरम ...	२४,८००
(५) ब्लैक क्वार्टर सीरम ...	३२,४००
(६) रिन्डरपेस्ट गोट टिशू वॉरस (डेसीकटेड)	१०,६१,७००
(७) एच० एस० कम्पोजिट वैक्सिन ...	२५,७२,७५०

देशी स्टॉक के स्तर को ऊँचा करने के लिये स्वीकृत स्तर के साँड़ तैयार करने के उद्देश्य से राज्य में प्रचारार्थ स्वीकृत किये गये विभिन्न नस्ल के विशुद्ध आधारभूत स्टॉक का रख-रखाव राज्य पशुधन-नस्लकशी फार्मों में किया जाता रहा ।

१९५१ ई० में राज्य फार्मों में रक्खा गया स्टॉक निम्नलिखित था :—

क्रम संख्या	नस्ल	पशुओं की संख्या
१	साहीवाल ..	२८७
२	सिन्धी ..	४५
३	हरियाना ..	६१०
४	केनकेथा ..	७९
५	गंगतरी ...	१५१
६	थरपारकर ...	६७
७	पवार ..	१३७
८	खरगढ़ ...	१६२
९	मुर्गा ..	७९५
१०	भदवारी ..	७९
११	तराई की भैंसे ..	३०

रोग-निरो-
धक ला

बायोला-
जिकल
प्रोडक्ट

पशु-संवर्द्धन

सरकार ने कालसी (देहरादून जिले) में एक ऐसे पशु-नस्लकशी तथा दुग्धशाला फार्म की स्थापना के लिये स्वीकृति दी, जिसमें सिंधी गायें और मुर्रा भैंसें रक्खी जायें। यह आशा की गयी कि राज्य के पर्वतीय जिलों के लिये जिस पशु-नस्लकशी फार्म की आवश्यकता बहुत दिनों से प्रतीत हो रही थी उसकी पूर्ति इस प्रस्तावित योजना से हो जायगी।

निजी स्थाओं द्वारा विशुद्ध नस्ल के सांड तैयार करने के लिये प्रोत्साहन देने की योजनायें चालू रही। विशुद्ध नस्ल के साहीवाल पशुओं के पालन-पोषण के लिये बेंती (प्रतापगढ़ जिले) के पशु फार्म के मालिक को ३६,००० रु० की एक आवर्तक राज्य-सहायता दी गयी और विशुद्ध नस्ल के सिंधी सांड उत्पन्न करने के लिये एग्रीकल्चरल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद के साथ जो प्रबन्ध किये गये थे वे इस वर्ष भी जारी रहे। जनता को दूध सप्लाई करने के अतिरिक्त विशुद्ध नस्ल के हरियाना सांड उत्पन्न करने के लिये स्वीकृत गौशालाओं में हरियाना पशुओं का पालन-पोषण होता रहा।

राज्य में विशुद्ध नस्ल के सांडों की कमी दूर करने के लिये पंजाब, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली, विभिन्न सैनिक दुग्धशाला फार्मों और केन्द्रीय सरकार के अन्य कारोबार से २२८ सांड और ७५ भैंसे खरीदे गये। आलोच्य वर्ष में राज्य में विभिन्न मांगपत्र भोजनवालों को ३० रु० प्रति सांड के नाममात्र के अंशदान पर लगभग ९०० विशुद्ध नस्ल के सांड दिये गये।

‘प्रमुख ग्राम’ योजना मेरठ जिले के ७५ चुने हुए गांवों में संतोषजनक रूप से चालू रही। उक्त योजना के अधीन १९५१ ई० में विशुद्ध नस्ल के ११ सांड और विशुद्ध नस्ल के ३ मुर्रा भैंसे सप्लाई किये गये। छाता (मथुरा जिले) में पाइलट ‘प्रमुख ग्राम’ योजना के अधीन, जिसे इंडियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की वित्तीय सहायता से १९५० ई० में प्रारम्भ किया गया था और जो कौंसिल द्वारा वित्त-पोषित प्राचीन पशु सम्बर्द्धन योजना का पुनर्संगठित रूप थी, कृत्रिम रूप से गर्भाधान कराने के केन्द्र पर ४ सांडों का पालन-पोषण किया गया और योजना में सम्मिलित निकटवर्ती गांवों को २९ सांड सप्लाई किये गये।

‘प्रमुख गांव’ योजना के संबंध में, जो पशु सुधार आंदोलन को तेजी और जोर से चलाने के लिये उत्कृष्ट प्रणाली समझी जाती थी, भारत सरकार ने सहायता दी और प्रत्येक ब्लाक में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र के साथ १४ अतिरिक्त ‘प्रमुख ग्राम’ ब्लाकों की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता दी गयी। वर्ष में इन केन्द्रों के लिये सज्जा तथा औजार खरीदे गये, आवश्यक कर्मचारियों को उपयुक्त ट्रेनिंग दी गयी और समस्त अन्य प्रारम्भिक कार्य पूरे किये गये।

लखनऊ (भदरक), मेरठ, देवरिया, इटावा (महोबा) और गाजीपुर के कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र संतोषजनक रूप से कार्य करते रहे और जनप्रिय हो गये। गाजियाबाद (मेरठ जिले) में भी एक कृत्रिम गर्भाधान उप-केन्द्र की स्थापना की गयी। इसके अतिरिक्त बाबूगढ़ (मेरठ), भरारी (झांसी), माधुरीकुंड (मथुरा) और बेंती (प्रतापगढ़) फार्मों में चार कृत्रिम गर्भाधान-केन्द्र चल रहे थे।

विभाग के लिये नियंत्रण में केवल दो सरकारी दुग्धशालायें थी अर्थात् लखनऊ की भदरक-दुग्धशाला और अलीगढ़ का केन्द्रीय दुग्धशाला फार्म।

दुग्धशाला विकास - भदरक दुग्धशाला इंडियन सेन्ट्रल सुगरकेन रिसर्च स्टेशन, भदरक के भू-गृहादि में यथावत् स्थित रही, किन्तु इसे चक-गजेरिया के यंत्रिकृत राज्य फार्म (१) सरकारी में स्थापित करने का प्रबन्ध किया जा रहा था। भदरक दुग्धशाला में अच्छे प्रकार का दूध निकलता रहा तथा दूध की अच्छे प्रकार की अन्य चीजें भी बनती

रहीं और इन सब की माँग बढ़ गयी। इस दुग्धशाला में प्रतिदिन के दूध के उत्पादन का औसत लगभग ४३ १/२ मन था। नस्लकशी का एक कार्यक्रम तैयार किया गया, जिसका उद्देश्य यह था कि जिस अवधि में भैंसें और गाय गाभिन नहीं रहतीं और दूध नहीं देती, उस अवधि में भी वे नियमित रूप से गाभिन रहें और दूध देने लगें, जिससे दूध का उत्पादन और उसकी सप्लाई वर्ष भर समान रूप से होती रहे।

इस उद्देश्य से कि भविष्य में कम से कम क्षति हो, मितव्ययता के कड़े उपाय किये गये, जिससे १९५० ई० में २,९२,१८८ रु० १४ आना ४ पाई का जो नुकसान हुआ था, वह घट कर १९५१ ई० में १,१२,९८२ रु० २ आना ८ पाई हो गया। इस बात की आशा की गयी कि चक-गंजेरिया में दुग्धशाला के जाने और पर्याप्त परिमाण में फार्म में तैयार किया गया हरा चारा प्राप्त करने के लिये बड़ी हुई सुविधाओं से कारोबार को स्वयं वित्तपोषित करना अन्ततोगत्वा सम्भव हो जायगा। अलीगढ़ के केन्द्रीय दुग्धशाला फार्म का प्रबन्ध उसके डेनिश मैनेजर, श्री ई० जी० वोरम के हाथ में पूर्ववत् बना रहा और उसमें तैयार की जाने वाली चीजों को केवल उत्तर प्रदेश में ही जनप्रिय बनाने के लिये नहीं बरन् बाहर और भारत यूनिन की अन्य प्रमुख बाजारों में भी जनप्रिय बनाने के लिये प्रयत्न किये गये।

आलोच्य वर्ष में केन्द्रीय दुग्धशाला फार्म में लगभग १,५७,१०९ पौंड मक्खन, २,२५,६६३ पौंड दूध और १,५२,६३३ पौंड घी निकाला गया और ३,१२,८४५ पौंड सुअरबाड़े से प्राप्त होने वाली चीजे तैयार की गयी। यह घी विशेषकर इस राज्य में जनप्रिय था, क्योंकि निजी संस्थाओं द्वारा विशुद्ध घी प्राप्त करने में कठिनाइयाँ पड़ती थी।

सुअर के मांस की फेक्ट्री देश में विभिन्न बाजारों की आवश्यकता पूरी करने के लिये सुअर का मांस, हेम, पोरक, सासेज तथा लार्ड (सुअर की चर्बी) तैयार करती रही। दुग्धशाला ने जनता के लिये दुग्धशाला संबंधी उपकरण भी तैयार किये।

निजी दुग्धशालाओं में प्रतिदिन के दूध के उत्पादन का औसत १५ मन था। निजी दुग्धशालाओं को तकावी बॉटने के लिये आलोच्य वर्ष के बजट में ७५,००० रु० को एक छोटी व्यवस्था की गयी। विभिन्न प्रयोजनों, जैसे दुधारू भवेशियों या दुग्धशाला संबंधी उपकरणों की खरीद, शेडों के निर्माण इत्यादि के लिये तकावी ऋण के अनुदान के संबंध में बहुत से प्रार्थना-पत्र आय और उन पर विचार किया जा रहा था, जबकि वर्ष समाप्त हो गया।

(२) निजी
दुग्धशालाएँ

स्वीकृत गौशालाओं को दूध की सप्लाई बढ़ाने के निमित्त और स्वीकृत स्तर के सॉड तैयार करने के लिये १९४८ ई०, १९४९ ई० और १९५० ई० में जो २४६ हरियाना गायें सप्लाई की गयी थी, उनका रख-रखाव होता रहा। इन गौशालाओं में प्रतिदिन के दूध के उत्पादन का औसत ४५ मन था। विभाग ने गौशालाओं द्वारा तैयार किये गये ४ चुने हुये विशुद्ध नस्ल के सॉड उनके बाजारु भाव के दो-तिहाई मूल्य पर खरीदा।

गौशालाओं
का विकास

बड़ापचपेड़ा (पीलीभीत), गढमुक्तेश्वर (मेरठ) और इमौलिया (जालौन) में निजी गौशालाओं द्वारा खोले गये कन्सेन्ट्रेशनी कैम्पों (समाहार, शिविरों) का रख-रखाव होता रहा। बड़ापचपेड़ा और गाजियाबाद में दूध न देने वाले भवेशियों के लिये जो पशु-रक्षक केन्द्र (सालवेज सेन्टर) खोले गये थे, वे भी कार्य करते रहे।

घोड़ों और
खच्चरो की
नस्लकशी

मेरठ, अलीगढ़, बुलन्दशहर और मुजफ्फरनगर के जिलों से जिन सरकारी सॉड-घोड़ों (बीजाश्वों) को हस्तान्तरित कर दिया गया था, उनका रख-रखाव मथुरा, मैनपुरी, बिजनौर, इटावा, सहारनपुर, एटा और कानपुर के नये चुने हुये जिलों में किया गया। १९५० ई० में कृषि से जो पाँच काठियावाड़ी घोड़ियाँ और दो काठियावाड़ी सॉड-घोड़े (बीजाश्व) खरीदे गये थे, उनका रख-रखाव मुरादाबाद के सॉड-घोड़ों (बीजाश्वों) के डिपो में किया गया। यह निर्णय किया गया कि इन घोड़ियों से जो बल्लू पदा हो उनको राज्य के पूर्वी जिलों में देशी घोड़ों का स्तर ऊँचा उठाने के लिये उपयोग किया जाय और जो बल्लू पदा हों उनका नस्लकशी का स्टाक बढ़ाने के लिये उपयोग किया जाय। लखनऊ में काठियावाड़ी स्टाक के लिये उपयुक्त अस्तबल का निर्माण करने के निमित्त भी प्रबन्ध हाथ में ले लिया गया।

आलोच्य वर्ष में राज्य में ४३ सॉड-घोड़ों (बीजाश्वों) और ८ सॉड-गर्दहों (बीज गर्दभों) का रख-रखाव किया गया।

भेड़ों की
नस्लकशी

पूर्व की भाँति फुलाही (इलाहाबाद), रतनपुर (फतेहपुर), भुलावन (गोरखपुर) और शिवपुर (बनारस) में सरकारी सॉड-भेड़ों केन्द्रों का रख-रखाव होता रहा। भेड़ों पर परजीवियों का नियंत्रण करने के लिये भेड़ों के बाल काटने और उनको धोने तथा नहलाने, उनको श्रेणीबद्ध करने इत्यादि के संबंध में इन केन्द्रों में गाँववालों में प्रदर्शन किये गये। विशुद्ध नस्ल के सफेद बिकानेरी सॉड-भेड़ों की श्रेणीबद्ध संतति से, जिसका रख-रखाव विभाग ने इन केन्द्रों में किया था, उत्पादित उनमें उसके प्रकार तथा परिमाण दोनों की दृष्टि से पर्याप्त सुधार दिखाई दिया। फुलाही में जहाँ श्रेणीबद्ध भेड़ों की पाँचवी पीढ़ी थी, संतति में वस्तुतः विशुद्ध नस्ल की सफेद बिकानेरी भेड़ों के समस्त गुण पाये गये। निकटवर्ती क्षेत्रों की स्थानीय भेड़ों का सुधार करने के लिये विभाग ने इस क्षेत्र से चुनी हुई श्रेणी के २३ सॉड-भेड़े खरीदे। एक विशुद्ध नस्ल के सफेद बिकानेरी सॉड-भेड़ा सहित विशुद्ध नस्ल की ५० सफेद बिकानेरी भेड़ियों के जिस गल्ले को मथुरा जिले में एक निजी नस्लकशी करने वाले को आधी कीमत पर दे दिया गया था, वर्ष में उसका भी रख-रखाव किया गया।

उरई (जालौन), ग्वालदम और पीपलकोटी (गढ़वाल) के भेड़-नस्लकशी फार्मों और भरारी (झासी), माधुरीकुंड (मथुरा), बाबूगढ़ (मेरठ) तथा दुग्धशाला प्रदर्शन फार्म, मथुरा की भेड़-नस्लकशी की युनितों की कार्यवाहियाँ जारी रहीं। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय भेड़ों का सुधार करने के लिये विशुद्ध नस्ल के रामपुर विशेर सॉड-भेड़े पंदा करने के उद्देश्य से ग्वालदम तथा पीपलकोटी के भेड़ के फार्मों में रामपुर विशेर भेड़ियाँ रखी गयीं, जब तक कि यहाँ की जलवायु के अनुकूल बनाये गये मैरिनो सॉड-भेड़े न तैयार हो जाय। संयुक्त-राष्ट्र से विशुद्ध नस्ल की १० मैरिनो भेड़ियाँ और विशुद्ध नस्ल के ६ मैरिनो सॉड-भेड़ों के आयात का प्रबन्ध किया जा रहा था।

विभाग ने १९५१ ई० में नस्लकशी करने वाले ग्रामीणों को ५६० प्रति सॉड भेड़ा के सामान्य अंशदान पर विशुद्ध नस्ल के १५५ सॉड-भेड़े बाँटे।

बकरियों की
नस्लकशी

इटावा जिले के चाकर नगर क्षेत्र में जमुनाफरी बकरियों और बकरीयों के रख-रखाव के लिये राज्य सहायता देने की योजना जारी रही। इस योजना के अधीन वर्ष में १६५ बकरियों और ३० बकरीयों के रख-रखाव के लिये राज्य सहायता दी गयी। यह योजना लाभप्रद सिद्ध हुई और क्षेत्र में अच्छे प्रकार के कुछ मवेशी पैदा किये गये। प्रति बकरी ने प्रति दिन ६ सेर दूध दिया। अटा, उरई और माधुरीकुंड के फार्मों तथा केन्द्रीय दुग्धशाला

अलीगढ़ में जमुनापारी बकरियों की युनिटों का भी रख-रखाव किया गया। केन्द्रीय दुग्धशाला फार्म की जमुनापारी बकरियों को अन्तर्गतत्वा दुग्धशाला प्रदर्शन फार्म, मथुरा को स्थानान्तरित कर दिया गया, क्योंकि केन्द्रीय दुग्धशाला फार्म में, जोकि एक व्यावसायिक युनिट था, जिन परिस्थितियों में पालन-पोषण होता था, वे इन बकरियों के लिये अनुकूल नहीं मिद्ध हुई।

बारबरी बकरियों का युनिट दुग्धशाला प्रदर्शन फार्म, मथुरा में भलौभांति उन्नति नहीं कर सका और इसलिये उसे मिशन फार्म, एटा को पुनः स्थानान्तरित कर दिया गया। राज्य ने विभिन्न माँगपत्र भेजनेवालों को ५ रु० प्रति बकरे के नाममात्र के अंशदान पर शुद्ध नस्ल के ७६ जमुनापारी और शुद्ध नस्ल के ६ बारबरी बकरे सप्लाई किया।

अलीगढ़ का केन्द्रीय दुग्धशाला फार्म, जहाँ कि देश का सबसे अच्छा और बड़ा सुअरबाड़ा था, राज्य में देशी सुअरों की नस्ल सुधारने के लिये सॉड-सुअरों की सप्लाई करता रहा। १० रु० प्रति सुअर के हिसाब से नाममात्र की धनराशि लेकर निजी रूप से सुअरों की नस्लकशी करने वालों को इस फार्म के शुद्ध नस्ल के मिडिल ह्वाइट यार्कशायर नर-सुअर दिये गये। आलोच्य वर्ष के अंत में राज्य में १३३ सुअर बाड़े-में नस्लकशी के प्रयोजन के लिये रखे गये थे।

सुअरों की
नस्लकशी

६,४६० बड़ी और मुर्गियों २,०७२ मुर्गी के बच्चों के अतिरिक्त ३८,४५० से अधिक अंडे, जिनसे बच्चे पैदा हो सकते थे, राज्य में नव स्थापित विकास ब्लाकों और राज्य सहायता प्राप्त मुर्गी फार्मों को दिये गये। इसके अतिरिक्त ५१,४५६ अंडे और १,५५८ चिड़ियाँ उपभोग के प्रयोजनों के लिये बेची गयी।

मुर्गियों की
नस्लकशी

वर्ष में खाल उतारने वाले चार गश्ती दलों ने दो शहरी क्षेत्रों में और दो ग्रामीण क्षेत्रों में हाइड डेवलपमेंट अफसर के प्रयत्नप्रदर्शन में कार्य किया। दलों ने १०६ ग्रामीण खाल निकालने वालों को और १०६ कसाइयों को क्रमशः स्वभावतः मृत्यु को प्राप्त और बध किये गये जानवरों की खाल उतारने की कला में ट्रेनिंग दी। खाल उतारने के सुधरे तरीकों का प्रयोग करने के लिये प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ट्रेनिंग प्राप्त खाल उतारने वालों को खाल उतारने के अच्छे किस्म के १२२ औजार और केनियाँ किस्म के लकड़ी के ७० ढाँचे दिये गये और जो खाले बहुत अच्छे तरीके से निकाली गयी थी उनके लिये ८२६ रु० १० आ० के पारितोषिक बाँटे गये।

खाल उतारने
के धंधे का
विकास

विभाग के एक पदाधिकारी संयुक्त राष्ट्र में मुर्गीपालन की ट्रेनिंग के लिये अध्ययन अवकाश पर रहे। पशु चिकित्सा के एक असिस्टेंट सर्जन को पशु चिकित्सा विज्ञान में उच्च ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिये मनीला में फिलीपाइन्स के विश्वविद्यालय में भेज दिया गया। विभाग के योग्य कर्मचारियों को इन्डियन वेटरिनरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट द्वारा संचालित पोस्ट-ग्रेजुएट तथा एडवान्स पाठ्यक्रम पूरा करने के लिये भेज दिया गया। पशु चिकित्सा अस्पतालों में जो बिना ट्रेनिंग प्राप्त कम्पाउन्डर काम कर रहे थे उनके लाभार्थ मरादाबौद में कम्पाउन्डरों की ट्रेनिंग के लिये पाठ्यक्रम खोले गये। १५ उम्मीदवारों ने राज्य मुर्गीपालन फार्मों में ६ सप्ताह की नियमित व्यावहारिक ट्रेनिंग पाठ्यक्रम पूरा किया और पशु चिकित्सा, कृषि तथा अन्य संस्थाओं से विद्यार्थियों के लिये प्रदर्शनों तथा अल्पकालीन ट्रेनिंग का भी आयोजन किया गया।

कर्मचारियों
की ट्रेनिंग

एक दिन की कई पशु संबंधी जिला प्रदर्शनियाँ और प्रादेशिक प्रदर्शनियाँ की गयीं और विभिन्न श्रेणी के प्रदर्शनों के लिये कई पारितोषिक

प्रचार, मेले

में आगरा में की गयी। विभाग ने “आप की सेवा में पशु-पालन तथा मत्स्यपालन विभाग” की वैभागिक बुलेटिन का हिन्दी रूपान्तर निकाला। जनता में फील्ड कर्मचारि वर्ग के जरिये विशेष कर प्रदर्शनों में विभिन्न वैभागिक पक्षों तथा बुलेटिनों की प्रतियाँ बाँटी गयी।

मथुरा स्थित शिक्षण, अनुसंधान और प्रदर्शन संस्था

मथुरा स्थित उत्तर प्रदेश पशुचिकित्सा विज्ञान कालेज और पशुधन अनुसंधानशाला तथा जिला दुग्धशाला प्रदर्शन फार्म के अस्तित्व का यह पाँचवा वर्ष था। इस कालेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या १७४ थी। इस कालेज के ग्रेजुएटों को प्राप्त वेतन-क्रम १२०-२५० रु० से बढ़ाकर २००-३५० रु० कर दिया गया और यह अनुभव किया गया कि भविष्य में इस संस्था में भर्ती के लिये अधिक उम्मीदवार आयेंगे। यह कालेज आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध रहा और गो-सेवकों तथा स्टाफ़ मेंनों को पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विज्ञान में शिक्षण देने के अतिरिक्त पशु चिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन (बी० बी० एस० सी० और ए० एच०) की बी० ए० डिग्री के लिये विद्यार्थी तैयार करता रहा। आलोच्य वर्ष में इस कालेज से १६ विद्यार्थियों का पहला समूह निकला।

कोठारी पशु चिकित्सालय जो नवम्बर, १९४६ ई० में आधुनिक साज-सामान के साथ, जिसमें एक्स-रे का सुविधायें भी सम्मिलित हैं, खोला गया था और भी जनप्रिय बन गया।

पशुधन अनुसंधानशाला के पशु प्रजनन, पशु पोषण तथा रोग और घातक महामारियों के उपविभाग पशुधन की उन्नति के विभिन्न पहलुओं से संबंधित महत्व की तात्कालिक समस्याओं को हल करते रहे। पशु प्रजनन उपविभाग ने पशु चिकित्सा के २१ असिस्टेंट सर्जनों और पशु पालन विभाग के ३३ स्टाफ़मेंनों को कृत्रिम गर्भाधान की प्रविधि में भी शिक्षण दिया।

मथुरा स्थित जिला दुग्धशाला प्रदर्शन फार्म ने विकास संबंधी कार्यवाहियाँ करते रहने के अतिरिक्त छात्रों तथा कर्मचारि वर्ग के लिये शिक्षा तथा अनुसंधान संबंधी आवश्यक सुविधाओं की भी व्यवस्था की। विकास संबंधी कार्यवाहियों में निम्नलिखित बातें सम्मिलित थी —

(१) नस्लकशी के प्रयोजनों के लिये स्वीकृत स्तर के साँड-बकरे, साँड-भेड़ें, भुगीं, बतख इत्यादि सप्लाय करना और (२) ताजा और शुद्ध दूध पैदा करना और उसे जिला सहकारी संघ के जरिये मथुरा की जनता को बेचना।

यंत्रोक्त सरकारी फार्म

वर्षात वर्ष की भाँति पशुपालन विभाग के निबंधन में १२ यंत्रोक्त सरकारी फार्म थे। लगभग कुल १२,००० एकड़ भूमि में खेती की गयी।

आलोच्य वर्ष कृषि की दृष्टि से बहुत खराब रहा। अपर्याप्त वर्षा होने के कारण खरीफ़ की फसल की बहुत अधिक क्षति पहुँची और रबी की फसल भी न तो ठीक तरह से बोई जा सकी और न भलीभाँति जम ही सकी।

इन फार्मों ने किसानों को कृषि विभाग के जरिये बाँटने के लिये अच्छे किस्म के बीज पैदा करने के संबंध में सहायता दी और अच्छी नस्ल के पशुधन पालन के लिये प्रमुख साधन के रूप में भी सेवायें की। खाद की अनुकूलतम मात्रा और ड्राईफार्मिंग की सबसे उपयुक्त प्रणालियों का पता लगाने के विचार से प्रयोग किये गये।

असर भूमि को तोड़ कर खेती योग्य बनाने के संबंध में भी कुछ कार्य किया गया। इन फार्मों के कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों ने गाँवों के संरक्षित

समूहों में पशुधन सुधार की "प्रमुख गाँव" योजना में भी आवश्यक सहयोग दिया ।

जिस समय फार्मों की यंत्रीकरण योजना के अधीन लाया गया, उस समय विभिन्न फार्मों में पशुओं और भैंसों की कुल संख्या ४,५१७ थी, जबकि उनकी कुल संख्या १ जुलाई, १९४८ ई० को २,३११ थी । इन पशुओं में हरियाना, सिंधी, पन्वार, खैरीगढ़, केनकाथम, थरपारकर, साहीवाल और गंगातेरी मवेशी और तराई मुर्रा तथा भदवारी भैंसों थीं । भरारी, बाबूगढ़ और माधुरीकुंड फार्मों में बढ़ती हुई भेड़ कम करने के उद्देश्य से आर्लोच्य वर्ष में कुछ मवेशी सैदपुर, निबलेट और अंदेशनगर फार्मों को स्थानान्तरित कर दिये गये । सभी सिंधी गायों को माधुरीकुंड फार्म से दुग्धशाला प्रदर्शन फार्म, मथुरा को स्थानान्तरित कर दिया गया । मूनाव कर नस्तकशी करके जमुनापारी बकरियाँ और बीकानरी भेड़ें रखने तथा भेड़ों और बकरियों की स्थानीय नस्ल में सुधार करने के लिये शहर के पास-पड़ोस में वितरण करने के वास्ते यहाँ की जलवायु के आदी बनाये गये साँड-भेड़ और बकरे उत्पन्न करने के उद्देश्य से भेड़ों और बकरियों के गल्ले (सब मिलाकर ८१५ मवेशी) का भी बाबूगढ़, भरारी और माधुरीकुंड के फार्मों में रख-रखाव किया गया ।

मुर्गियों, ह्वाइट लेगहार्न, ब्लैक माइनोर्का और रोड आइलैंड की लाल मुर्गी, बतख इत्यादि चिड़ियों का रख-रखाव बाबूगढ़, भरारी और मंझरा फार्मों में किया गया । मुर्गी, बतख इत्यादि चिड़ियों की कुल संख्या ५,४२१ थी ।

इन यंत्रीकृत सरकारी फार्मों ने जुलाई, १९४८ ई० से १९५०-५१ ई० के अन्त तक ३२१ साँड और १४३ साँड-भेड़े बाँटे और १५,८०८ मन दूध, ५१,७३७ अंडों तथा १५० भेड़ों की बिक्री की । इस अवधि में बैची अथवा बाँटी गयी मुर्गी, बतख इत्यादि चिड़ियों की संख्या ३,५३३ थी ।

हरा चारा पैदा करने के संबंध में पशु-पालन बोर्ड की सिफारिशों पूर्ण रूप से कार्यान्वित की गयी । निम्नलिखित तालिका में यह दिखाया गया है कि विभिन्न फार्मों में कितने एकड़ क्षेत्र में हरा चारा पैदा किया गया और कितने एकड़ क्षेत्र में चरागाह था :—

क्रम-संख्या	फार्म का नाम	कुल क्षेत्र	कुल क्षेत्र, जिसमें खेती की गयी	क्षेत्र, जिसमें हरा चारा बोया गया	क्षेत्र, जिसमें चरागाह था
		एकड़	एकड़	एकड़	एकड़
१	बाबूगढ़	८५६	८५०	५८६	२००
२	भरारी	२,१२५	६००	३८३	१,०००
३	माधुरीकुंड	१,३६६	८५०	५१७	५००
४	हेमपुर	५,२३५	३३,३००	७६	१,२००
५	मंझरा	६५०	७००	९६.७	२५०
६	आराजी लाइन्स	१,०३०	५००	२०३	०
७	अंदेशनगर	१,१४४	६००	१३५	१५०
८	सैदपुर	१,००४	६००	२१७	५००
९	निबलेट	६०२	२५०	१६५	५००

५३—मत्स्य-पालन

तालाबों में वर्ष में २०,१७६.६ एकड़ क्षेत्र के १,६३८ तालाबों की पैमाइश की गयी और मत्स्य संवर्द्धन के प्रयोजन के लिये तालाब मालिकों से समझौते के आधार पर ३८१२ एकड़ क्षेत्र के २३५ तालाब प्राप्त किये गये। १५३.६ एकड़ क्षेत्र के १६२ तालाबों की सफाई की गयी। ३०८.२ एकड़ क्षेत्र के २५२ तालाबों में मछलियों का स्टॉक रखा गया और १७३२ एकड़ क्षेत्र के १२२ तालाबों को फिर से भरा गया।

रिसर्च स्टेशन ने मत्स्य उत्पादन के लिये समझौते के आधार पर लगभग २३२ एकड़ का पानी भी लिया और १०२ एकड़ के पानी में १,८७,०६६ छोटी मछलियों का स्टॉक रखा गया। इसके अतिरिक्त शारदा नहर की प्रतापगढ़ विस्तार शाखा में १७,५७५ छोटी मछलियों का स्टॉक रखा गया।

मिरर कार्प की छोटी मछलियाँ और १६४७ ई० में भुवाली हैचरी में नये सिरे से रखी गयी तेजी से बढ़ने वाली विदेशी मछलियाँ उपलब्ध थीं और ये हवालबाग तथा बैजनाथ तालाबों में रखी गयी। यह निर्णय किया गया कि उन्हें अन्ततोगत्वा प्रदेश के चूने हुये तालाबों में नये सिरे से रखा जाय। मिरर कार्प को नये सिरे से रखने के लिये नौकुचिया ताल के ६ छोटे तालाबों में से प्रत्येक को अलग करने के लिये पत्थर की एक पतली दीवाल बनायी गयी।

टोहरी-गढवाल में काल्देयानी ट्राउट हैचरी, जो अब तक वन विभाग के नियंत्रण में थी, मत्स्य पालन विभाग को हस्तान्तरित कर दी गयी, जिससे कि मत्स्य-पालन विभाग राज्य के कुमायूँ तथा अन्य पर्वतीय भागों में ट्राउट मछलियों को ऊँचे स्तर पर उत्पन्न करने में समर्थ हो सके।

अनुसंधान

लखनऊ की केन्द्रीय मत्स्य-पालन अनुसंधान प्रयोगशाला और रामपुर, बनारस, भुवाली और मिर्जापुर में नव-स्थापित अनुसंधान के ४ सब-स्टेशनों में यह ज्ञात करने के लिये प्रत्येकटाणिक अध्ययन और भौतिक तथा रासायनिक विश्लेषण जारी रहे कि किन उत्कृष्ट वातावरणों में मछलियों की अनुकूल-तम वृद्धि हो सकती है। जिनो में मछलियों के वितरण के अध्ययन की सुविधा के लिये प्रत्येक केन्द्र में एक म्यूजियम की स्थापना की गयी और अधिक संख्या में स्थानीय मछलियाँ इकट्ठा की गयीं। तालाबों की ज्वरता बढ़ाने के उद्देश्य से खाद संबंधी प्रयोग किये गये और लाने, ले जाने तथा तालाबों में रखने पर फाई तथा छोटी मछलियों के जीवित रहन, मछलियों के बचे हुये भाग से भोजन तैयार करने से संबंधित समस्याएँ परीक्षाधीन थीं। १ अप्रैल, १९५१ ई० से २४ उम्मीदवारों को व्यावहारिक मत्स्य-पालन में ट्रेनिंग दी गयी।

सामाजिक और आर्थिक कार्य

इलाहाबाद में गंगा रोक मछुओं की एक सहकारी समिति उत्तर प्रदेश सहकारी विभाग द्वारा रजिस्टर्ड की गयी और उपयुक्त उप-विधियाँ बनाई गयीं।

अध्याय ७—शिक्षा तथा कला

५४—शिक्षा

१९५१ ई० में शिक्षा की प्रायः सभी दिशाओं में महत्वपूर्ण प्रगति हुई।

उत्तर प्रदेश की ८६ नगरपालिकाओं में ६ से ११ वर्ष तक की आयु के लड़कों के लिये प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क थी। २४ नवनिर्मित नगरपालिकाओं में अनिवार्य शिक्षा को लागू करने के सम्बन्ध में प्रारंभिक कार्यवाहियों की गई।

प्रारंभिक
(Primary)
शिक्षा

२६ डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के ३५७ ग्रामीण क्षेत्रों के लड़कों के लिए प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य थी। १९५१ ई० में इस योजना के अंतर्गत नए क्षेत्र सम्मिलित नहीं किए जा सके। २३ सैचुरेटेड (saturated) जिलों में से सभी में अनिवार्य शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध थीं, यद्यपि उन जिलों में प्रारंभिक शिक्षा अब तक अनिवार्य नहीं की गई थी।

तीन नगरपालिकाओं में प्रारंभिक शिक्षा पहले से अनिवार्य थी, उनके अतिरिक्त आलोच्य वर्ष में ७ और नगरपालिकाओं में लड़कियों के लिए अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की गई। इस प्रकार यह योजना १० नगरपालिकाओं में चल रही थी। इस वर्ष इसमें २ ग्रामीण क्षेत्र सम्मिलित किए गए।

जुलाई, १९४८ ई० से पिछले वर्ष तक प्रारंभिक शिक्षा योजना के अंतर्गत जो सरकारी प्रारंभिक स्कूल खोले गए थे नवम्बर, १९५० ई० में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधिकार में दे दिए गए। १९५१ ई० में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सिपुर्वंगी में ५५० नए स्कूल खोले गए।

वर्ष के अन्त में प्रारंभिक स्कूलों की कुल संख्या ३२००० थी, अध्यापकों की संख्या ७०,००० से अधिक थी और लड़कों की संख्या ८ लाख से भी अधिक हो गई।

ट्रेनिंग के सचल दस्ते (squads), जिनकी संख्या ५० थी, रामपुर के अतिरिक्त अन्य सभी जिलों में कार्य करते रहे और तेजी से बढ़ते हुए प्रारंभिक स्कूलों को नार्मल स्कूलों के ट्रैन्ड अध्यापक सप्लाई करने के काम में हाथ बंटाया। १९५१ ई० में कुल ११,५७० अध्यापकों को एच० टी० सी० तथा जे० टी० सी० (J.T.C.) की ट्रेनिंग दी गई।

जुलाई, १९५० ई० में जूनियर हाई स्कूलों में नई आठवीं कक्षा खोली गई। नई योजना के अंतर्गत, जिसमें उभयनिष्ठ पाठ्य-विषय (common syllabus) की व्यवस्था की गई थी, १९५१ ई० में पहले बैच में जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा दी। ऐसे विद्यार्थियों की कुल संख्या, जो कोर्स पूरा कर रहे थे, लगभग एक लाख थी।

जूनियर हाई
स्कूल इत्यादि

१९५१ ई० में ११२ अन्य स्कूलों में सामान्य विज्ञान की कक्षाएं खोली गईं। इस प्रकार ऐसे स्कूलों की कुल संख्या, जिनमें सामान्य विज्ञान की शिक्षा की सुविधाएं थी, ३३७ तक पहुंच गई। सरकार ने सज्जा तथा उपकरणों की खरीद के लिए १,१२,००० रु० उपस्कर (फर्नीचर) की खरीद के लिए ६३,००० रु० और सामान्य विज्ञान के अध्यापकों के वेतन के लिए १,३०,००० रु० की स्वीकृति दी।

७ सरकारी नार्मल स्कूलों, लड़कियों के १२ जूनियर हाई स्कूलों और लड़कों के १५ सरकारी माडल स्कूलों में भी इस विषय की कक्षाएं खोली गईं। सरकार ने इस विषय में ५०,००० रु० का अनावर्तक व्यय किया और ऐसी प्रत्येक शिक्षा संस्था के लिए इस विषय के एक अंश तक की व्यवस्था की।

सभी नार्मल स्कूलों में एक अनिवार्य विषय के रूप में कृषि की कक्षाएं खोली गईं। लड़कियों के नार्मल स्कूलों में कृषि के स्थान पर गृहविज्ञान (House Craft) की शिक्षा दी गई।

उच्च माध्यमिक स्कूल (हायर सेकेंडरी स्कूल)

१९५१ ई० में उच्च माध्यमिक शिक्षा में विशेष प्रगति हुई। लड़कों की १६८ और लड़कियों की १० शिक्षा संस्थाओं में ११वीं कक्षा खोली गई। जिन शिक्षा संस्थाओं में इंटरमीडिएट की कक्षाएं थी और जिनमें नहीं थीं उनकी संख्या क्रमशः ५०६ और १,००० थी।

जो विद्यार्थी यू० पी० बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट (कृषि तथा वाणिज्य में इंटरमीडिएट की परीक्षा को सम्मिलित करके) की परीक्षा में बैठे थे उनकी संख्या क्रमशः १,१०,५५१ और ४१,१०६ थी। इन अंकों में उन विद्यार्थियों की संख्या नहीं सम्मिलित है, जो बनारस और अलीगढ़ के विश्वविद्यालयों तथा प्रयाग महिला विद्यापीठ जैसी अन्य संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली समकक्ष परीक्षाओं में बैठे थे।

सरकारी शिक्षा संस्थाओं ने उन विषयों के पढ़ाने में अधिक जोर दिया जो गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाएं अधिक खर्च के कारण पढ़ाने में असमर्थ थीं। अतएव पिथौरागढ़, मैनपुरी, फतेहपुर, फतेहगढ़, हमीरपुर और रायबरेली के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूलों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित की, पीलीभीत और देहरी में जीव विज्ञान (बायोलॉजी) की, पीलीभीत में कृषि की और इलाहाबाद के लड़कियों के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूलों में वर्ग 'ग' के विषयों की ११ वीं कक्षाएं खोली गईं। इलाहाबाद के सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल में औद्योगिक रसायन तथा कुम्हारी विद्या (Ceramics) पढ़ाने और बनारस में औद्योगिक रसायन के पढ़ाने की व्यवस्था की गई। इन विषयों के पढ़ाई पर क्रमशः ३३,६०० रु० और २३,५०० रु० के आवर्त्तक तथा अनावर्त्तक सरकारी व्यय होने का अनुमान लगाया गया था और सरकार ने उक्त प्रयोजन से गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं को अनुदान (आवर्त्तक और अनावर्त्तक) दिए।

विश्वविद्यालयों की शिक्षा

आलोच्य वर्ष में उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा कालेजों की डिग्री तथा पोस्ट-ग्रेजुएट कक्षाओं के विद्यार्थियों की कुल संख्या २६,८२९ थी, जबकि पिछले वर्ष वह केवल २४,१४१ थी। इससे २३.५ प्रतिशत की वृद्धि का पता चलता है। यह वृद्धि विश्वविद्यालय के सभी विभागों में हुई, केवल कृषि विभाग इसका अपवाद रहा, जिसमें उक्त संख्या ६४५ में घटकर ६२५ रह गई। इस संख्या में आर्ट्स विभाग में २८.८ प्रतिशत की, विज्ञान विभाग में २५.८ की, वाणिज्य विभाग में १७ प्रतिशत की और विधि (Law) विभाग में ८.३ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

उन क्षेत्रों में जहाँ सन्तोषप्रद व्यवस्था नहीं की गई थी जगता के लिए उच्च शिक्षा सुगम कर दी गई। सरकार ने नैनीताल तथा ज्ञानपुर (बनारस) में डिग्री कालेज खोले। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बी० एस-सी० डिग्री की शिक्षा प्रदान करने के प्रयोजन से कायस्थ पाठशाला के प्रबंध में चौधरी महोदय प्रसाद कालेज नामक एक नयी शिक्षा संस्था खोली गयी। आलोच्य वर्ष में इसकी बी० एस-सी० प्रथम वर्ष की कक्षा में ६० विद्यार्थी थे। उरई के डी० ए० बी० कालेज, हापड़ के सरस्वती विद्यालय कालेज, फाजिल्हाद के साकेत महाविद्यालय कालेज, नैनीताल के स्टेट डिग्री कालेज और ज्ञानपुर (बनारस) के बी० एच० कालेज, आगरा

डिग्री कालेजों को उनके सामने अंकित विषयों में शिक्षा के लिए सम्बद्ध किया गया :—

(१) वीमेन्स ट्रेनिंग कालेज, दयालबाग	} बी० ए० की डिग्री के लिए
(२) बराहसेनी कालेज, अलीगढ़	
(३) महाराणा प्रताप कालेज, गोरखपुर	
(४) कारोनेशन हिन्दू कालेज, मुरादाबाद	बी० एस-सी० की डिग्री के लिए
(५) राधास्वामी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा	} बी० टी० डिग्री के लिए
(६) डी० ए० वी० कालेज, देहरादून	

पूर्व की भांति शासकीय आज्ञाओं के अनुसार इलाहाबाद और लखनऊ के विश्वविद्यालयों तथा डिग्री कालेजों के १० प्रतिशत विद्यार्थियों की फीस माफ कर दी गई और १५ प्रतिशत विद्यार्थियों की फीस आधी कर दी गई। इसके अतिरिक्त परिगणित जाति के विद्यार्थियों की फीस माफ कर दी गई। विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में विभिन्न साधनों से नाना प्रकार की छात्रवृत्तियाँ भी उपलब्ध थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय प्रदेशों में कुछ अधिक छात्रवृत्तियाँ देने के अतिरिक्त डिग्री की कक्षाओं के बहुत से विद्यार्थियों को २० ह० प्रतिमास की और पोस्ट-ग्रेजुएट कक्षाओं के विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी ३० ह० की छात्रवृत्तियाँ दीं। राज्य के पश्चिमी भाग के कालेजों के बहुत से विस्थापित विद्यार्थी सरकार की ओर से छात्रवृत्तियाँ पा रहे थे। परिगणित जाति के विद्यार्थी केन्द्रीय तथा राज्य सरकार दोनों ही से १६ ह० और २० ह० से लेकर ४० ह०, ५० ह० और ५५ ह० प्रतिमास तक की छात्रवृत्तियाँ पा रहे थे। जुलाई, १९५१ ई० से सरकार ने इलाहाबाद और लखनऊ के विश्वविद्यालयों और आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों के निर्धन तथा प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ तथा पुस्तकों के अनुदान दे रही है। इन छात्रवृत्तियों की सख्या इस प्रकार से है :—

इलाहाबाद विश्वविद्यालय	६०
लखनऊ विश्वविद्यालय	६०
आगरा विश्वविद्यालय	८०
			<hr/> २००

छात्रवृत्तियों का मूल्य वर्ष में १० मास तक १०० ह० प्रतिमास से अधिक न होना चाहिए। इस काम के लिये १,५०,००० ह० का अनुदान दिया गया।

चूँकि सरकार इमारतों के सम्बन्ध में अनुदान देने में बिल्कुल असमर्थ थी, नई इमारतों का निर्माण बहुत सीमित रहा। इसके अतिरिक्त भवन निर्माण सामग्री 'अधिक अन्न उपज्ञाओं' योजना सम्बन्धी निर्माण-कार्यों के लिये सुरक्षित रखी गयी थी। इस वर्ष विश्वविद्यालयों तथा कालेजों ने अपने तिज्जी कोष तथा पूर्ववर्ती अनुदानों से रुपया बचाकर कुछ निर्माण कार्य किया।

वैज्ञानिक अनुसंधान समिति की सिफारिश पर सरकार ने विश्वविद्यालयों तथा डिग्री कालेजों के अनुसंधान-कार्य के लिये कुल १,२७,४५० ह० का अनुदान दिये। विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त विभिन्न टेक्निकल तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं के अनुसंधान कार्य के लिये भी ५२,२३६ ह० तक के अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान समिति

उत्तर प्रदेश की विश्वविद्यालय अनुदान समिति ने बहुत सी बातों के सम्बन्ध सिफारिशों कीं जिनमें से कुछ, जिनके सम्बन्ध में सरकार ने स्वीकृति प्रदान की, वे ये हैं :— विज्ञान की शिक्षा तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ अतिरिक्त अध्यापकों के पदों, जिसमें भू-गर्भ शास्त्र के अध्यापक का पद भी सम्मिलित है, के लिये प्रस्तुत व्यवस्था का विस्तार करना। सरकार ने प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों की योग्यता को बढ़ाने की आवश्यकता को, जिसके सम्बन्ध में समिति ने अपनी सम्मति प्रकट की थी, स्वीकार कर लिया और इन बातों की देखभाल करने के प्रयोजन से एक डिप्टी डाइरेक्टर आफ ट्रेनिंग की नियुक्ति की।

ग्रौढ़ शिक्षा

सम्पूर्ण राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के १,३१७ सरकारी पुस्तकालयों (जिनमें से ४० महिलाओं के लिये) और ३,६०० वाचनालयों का सरकार द्वारा रखरखाव किया गया और इन संस्थाओं के लिये पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा सामयिक पत्रों की खरीद के प्रयोजन से ७५,००० रु० की व्यवस्था की गई। पुस्तकालयों तथा वाचनालयों ने ग्रामीण क्षेत्रों में ज्ञान की वृद्धि में योग देने तथा उन व्यक्तियों को, जिनके पास इसके अतिरिक्त पढ़ने का कोई अन्य साधन न था, पुनः पढ़ना, लिखना भूल जाने से बचाकर पठनीय सामग्री की व्यवस्था की।

शिक्षा सम्बन्धी फिल्म बनाने के लिये एक फिल्म विभाग चलाया जा रहा था। जनता को दिखाने और ग्रामीण क्षेत्रों में तथा मेला इत्यादि में प्रचार करने के लिये ५ सिनेमा गाड़ियाँ थीं, जिनमें प्रोजेक्टर, रेडियो सेट, लाउडस्पीकर इत्यादि लगे हुए थे। ५ सिनेमा वान थी, जो प्रोजेक्टरों इत्यादि से सुसज्जित थी।

अस्वस्थ तथा अशक्त बच्चों की शिक्षा

राज्य में अस्तिष्ठक तथा शरीर से अस्वस्थ बच्चों के लिये कुल १२ स्कूल चल रहे थे। नवम्बर, १९५१ ई० में सरकार ने बरेली में एक नया स्कूल खोला। इलाहाबाद, लखनऊ, अलीगढ़, बर्नारस और मेनपुरी में सरकारी शिक्षा संस्थाओं का काम चालू था।

सैनिक शिक्षा

यू० पी० एजुकेशन कोर और नेशनल कैंडेट कोर दोनों का काम सुचारु रूप से चल रहा। १९५१ ई० में १८ शहरों में इंटरमीडियेट की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य सैनिक शिक्षा योजना चल रही थी। यह योजना १९४८ ई० में ११ शहरों में नवयुवकों की स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐसे कार्यों में भाग लेने का अवसर देने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई थी, जिससे विशेषतया आत्म-विश्वास, विचार की स्वतन्त्रता, स्वभाव की सरलता, आत्मसंयम, अनुशासन, टीम में मिलकर काम करने की भावना तथा सहिष्णुता जैसे व्यक्तियों को ऊँचा उठाने के गुणों को प्राप्त करने में सहायक हो। इस वर्ष यह किसी अन्य नये शहर में नहीं चालू की गई।

इस वर्ष नैनीताल के शिक्षकों के प्रशिक्षण शिविर में १३४ नये शिक्षकों को अनिवार्य सैनिक ट्रेनिंग दी गई, जबकि पिछले वर्ष फैजाबाद में ८० शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई थी। जिन कालेजों में सैनिक शिक्षा दी जाती थी उनकी कुल संख्या ६० से बढ़ाकर १६४ हो गई और प्रशिक्षण पाने वाले कैंडेटों की कुल संख्या २६,४५० थी, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या २२,००० थी। प्रत्येक नगर में नेशनल कैंडेट कोर के विशेष प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया गया।

प्रत्येक केन्द्र पर जिले की प्रतियोगिताओं तथा साप्ताहिक शिविरों का आयोजन किया गया और सर्वश्रेष्ठ कैंडेटों को पारितोषिक वितरण किया

राज्य के नवयुवकों की तृतीय रैली लखनऊ में १५ और १६ दिसम्बर १९५१ ई० को हुई और १६ दिसम्बर को १,०५० कैंडेटों ने परेड में भाग लिया। भारत सरकार के गृह मंत्री डाक्टर कलश नाथ काटजू ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। उन्होंने कैंडेटों के एक सामूहिक व्यायाम प्रशिक्षण प्रदर्शन को भी देखा और विभिन्न यूनिटों को पारिवर्तनिक वितरण किये। इसमें एक बात जो विशेष थी, वह यह थी कि परेड के समय सभी कैंडेटों के पास सर्विस राइफिलें थीं और एक कैंडेट द्वारा सम्पूर्ण परेड करायी गयी थी।

जिलों से प्राप्त होने वाली रिपोर्टों से यह प्रकट हुआ कि यह योजना लोक-प्रिय हो रही थी और जिन शिक्षा संस्थाओं में यह चालू थी उनके सामान्य अनुशासन में सुधार हुआ।

• शिक्षा अधिकारियों का ध्यान नैतिक शिक्षा की ओर भी गया। हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट शिक्षा बोर्ड ने इसका शिक्षा संस्थाओं में बिना परीक्षा के एक अनिवार्य विषय के रूप में चालू किया जाना स्वीकार कर लिया और राज्य में नैतिक शिक्षा के सम्बन्ध में उपयुक्त साहित्य रचना का कार्य प्रारम्भ किया गया। यह अनुभव किया गया कि शिक्षकों द्वारा अच्छा आदर्श प्रस्तुत किया जाना, इस विषय में शिक्षा देने का एक बहुत प्रभावशाली साधन होगा और इस विषय के सम्बन्ध में सैद्धांतिक ज्ञान की अपेक्षा क्रियात्मक ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण है।

कांस्ट्रक्टिव ट्रेनिंग कालेज, जो इलाहाबाद में विभिन्न इमारतों में (जिनमें से कुछ किराये की थी) स्थित था, १९५१ ई० में लखनऊ में स्थानांतरित किया गया और इसके विस्तार को सुगम करने के लिये इसे एक उपयुक्त सरकारी इमारत में स्थापित किया गया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, लखनऊ में, जहाँ इसकी ट्रेनिंग पाने वाले विद्यार्थी प्रैक्टिस करते थे, औद्योगिक रसायन, कृषि, पुस्तक कला (Book Craft), धातुकला और कताई तथा बुनाई के काम की शिक्षा नवी कक्षा में प्रारम्भ की गई। इस कालेज में ग्रेजुएट और अन्डर ग्रेजुएट दोनों प्रकार के अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जाती थी। १९५१ ई० में कृषि, कुम्हारी विद्या (सेरामिक्स) औद्योगिक रसायन, पुस्तक-कला, धातुकला और कताई तथा बुनाई की कक्षाओं में कुल ५३ नये विद्यार्थी ट्रेनिंग के लिये भर्ती किये गये।

कांस्ट्रक्टिव
ट्रेनिंग कालेज

इलाहाबाद का मनोविज्ञान का ब्यूरो मनोविज्ञान के सम्बन्ध में नियमित रूप से पथ-प्रदर्शन करता रहा। ५ प्रदेशों में से प्रत्येक में एक मनोविज्ञान का शिक्षा केन्द्र खोलने के उद्देश्य से ५ मनोवैज्ञानिकों तथा ५ सहायक मनोवैज्ञानिकों को उच्च-मनोविज्ञान की सैद्धांतिक तथा क्रियात्मक दोनों प्रकार की प्रगाढ़ रूप से ट्रेनिंग दी गई।

मनोविज्ञान
का ब्यूरो

अनुसंधान सम्बन्धित कार्य, जिसमें मनोवैज्ञानिक जाँच तथा खेलों द्वारा चिकित्सा (Play Therapy) सम्मिलित है, जारी रखा गया। अनुसंधान सम्बन्धी ६ पत्र प्रकाशित किये गये और भारत की दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना और बम्बई की उसी प्रकार की शिक्षा संस्थाओं और बाहर की शिक्षा संस्थाओं से सम्बन्ध स्थापित किया गया और घनिष्ठता बढ़ाई गई।

इलाहाबाद के पेडागोगिकल इन्स्टीट्यूट ने जूनियर हाई स्कूलों के हिन्दी, गणित, भूगोल, सामान्य विज्ञान तथा अंग्रेजी के अध्यापकों के लिये पुस्तकें (Handbooks) तैयार कीं। गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं

सेन्ट्रल पेडागा-
गिकल
इन्स्टीट्यूट

इस शिक्षा संस्थाने १९५१ ई० में निम्नलिखित पत्र प्रकाशित किये :—

- (१) प्राइमरी स्कूलों का पाठ्यक्रम ।
- (२) लड़कों द्वारा नक्शों का अध्ययन ।
- (३) विज्ञान का अध्यापन ।
- (४) इलाहाबाद के स्कूलों में छठी कक्षा की व्यवस्था ।
- (५) बेमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम का आलेख्य ।
- (६) प्राइमरी शिक्षा की केन्द्रीय समस्या—अनेक कक्षाओं की शिक्षा ।
- (७) इतिहास की शिक्षा के सम्बन्ध में अध्यापकों के लिये एक (हैंड-बुक) पुस्तक ।

शारीरिक-
संवर्द्धन
कालेज

इलाहाबाद का शारीरिक शिक्षा का कालेज शिक्षकों को (पुरुषों और महिलाओं दोनों को) शारीरिक शिक्षा की ट्रेनिंग देना जारी रखेगा और यह राज्य में अपने किस्म की एक ही सरकारी शिक्षा संस्था थी। १९५१ ई० में शिक्षार्थियों की संख्या ६६ थी (जिसमें ५४ पुरुष और १२ महिलाएँ थी) ।

महिलाओं के
गृह विज्ञान
तथा कला
का कालेज

इलाहाबाद का गृह विज्ञान तथा कला का कालेज, जो १९४३ ई० में गृह विज्ञान की अध्यापिकाओं को ट्रेनिंग देने के प्रयोजन से स्थापित किया गया था, संतोषजनक ढंग से कार्य करता रहा। इस वर्ष जिन शिक्षार्थियों ने 'प्रमाण-पत्र' सम्बन्धी पाठ्य विषय (Course) लिया था उनकी संख्या ११५ थी और जिन्होंने डिप्लोमा सम्बन्धी पाठ्य विषय लिया था उनकी संख्या १७ थी ।

नर्सरी ट्रेनिंग
कालेज

नर्सरी ट्रेनिंग कालेज ने (जिसमें अध्यापन के अभ्यास के लिये एक नर्सरी स्कूल सम्बद्ध था) अध्यापकों को इस उद्देश्य से ट्रेनिंग देना जारी रखा कि वे छोटे बच्चों में अपने विचार प्रकट करने की क्षमता तथा व्यक्तित्व का विकास करने की दृष्टि से उन्हें शिक्षा देने में विशेष रूप से समर्थ हों और समुचित योग्यता के अध्यापकों को तैयार करके बच्चों की एक अधिक प्रभावपूर्ण शिक्षा प्रणाली का तैयार किया जाना जारी रखा ।

पूर्व की भांति 'शिक्षा' नामक त्रैमासिक पत्र शिक्षा विभाग से प्रकाशित होता रहा और यह शिक्षा सम्बन्धी अनुसंधान के तथा विभाग द्वारा किये गये कार्यों के प्रकाशन में उपयोगी था ।

पुस्तकों के
लिये पारि-
तोषिक

हिन्दी में, जो केवल राष्ट्र भाषा ही नहीं थी अपितु उत्तर प्रदेश में शिक्षा का माध्यम थी, अच्छी पुस्तकों की रचना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ३१ लेखकों को विभिन्न विषयों पर अच्छी पुस्तकें लिखने के लिये कुल २५,७०० रु० की धनराशि के पारितोषिक वितरण किये गए ।

अध्यापकों के
लिए सुविधाएँ

गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों की दशाओं में सुधार करने और सम्बन्धित अमले के मेम्बरो के एक स्कूल से दूसरे स्कूल में अव्यवस्थित रूप से जाने को रोकने के उद्देश्य से सरकार उनके लिये कुछ शासकीय वेतनक्रम पहले ही से निर्धारित कर चुकी थी। १९५१ ई० में अध्यापकों को जो और सहायता दी गई यह यह थी कि जो अध्यापक बहुत वर्षों से अध्यापन कार्य कर रहे थे उनके वेतन में एक या दो अग्रिम वेतन-वृद्धि की गई, जैसे १० साल की सेवा पर एक वेतन-वृद्धि । शिक्षा विभाग के लिये एक क्षय रोग चिकित्सालय की योजना भी प्रारम्भ की गई और उन अध्यापकों तथा उनके आश्रितों के लिये, जो दुर्भाग्यवश क्षय रोग से ग्रस्त हो जाय, सेनी-कोरियम में चिकित्सा की व्यवस्था करने के प्रयोजन से योजना को आगे बढ़ाया गया । लोगों के उदारतापूर्वक सहायता दी और १५ लाख रु० से अधिक

इस वर्ष की एक महत्वपूर्ण घटना दिसम्बर मास की लखनऊ की अंतर्राष्ट्रीय खिलौना प्रदर्शनी थी जो शिक्षा को अधिक आकर्षक बनाने की योजना में स्फूर्ति पैदा करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। इसमें भारत के सभी भागों से तथा बाहर के कई देशों से मंगाये गये खिलौनों का प्रदर्शन किया गया था। इस प्रदर्शनी को बहुत से शिक्षा विशेषज्ञों तथा जनता ने देखा। खिलौनों की प्रदर्शनी से केवल मनोरंजन ही नहीं हुआ, बल्कि खिलौना का शिक्षा सम्बन्धी विशेष मूल्य तथा कला श्रौद्ध खिल के द्वारा अभिव्यक्ति का महत्व प्रकट हुआ। इसके अतिरिक्त इसने भारत के खिलौना बनाने वालों को भी स्फूर्ति प्रदान किया।

अन्तर्राष्ट्रीय
खिलौना
प्रदर्शनी
(International
Toys Ex-
hibition)

• ५५—रुडकी विश्वविद्यालय

मई, १९५१ ई० में जो प्रवेशिका परीक्षा ली गई थी उसके परीक्षकाल के परिणामस्वरूप इंजीनियरिंग में (सिविल में ३५, बिजली में १९ और मेकेनिकल इंजीनियरिंग में १८) ७२, ओवरसियरी में ७० और नक्शा-नर्वशी (ड्रफ्टमैन) की कक्षा में १२ प्रविष्ट किये गये। हिन्द एशिया, बर्मा और पूर्वी अफ्रीका से भी इंजीनियरी कक्षा में ५ विद्यार्थी भर्ती किये गये। जो तीन विद्यार्थी असफल रहे उन्हें फिर से पाठ्यक्रम पढ़ने को कहा गया। प्रवेशिका परीक्षा में कोई भी महिला उम्मीदवार नहीं बैठे। विश्व-विद्यालय का सत्र १७ अक्टूबर से प्रारम्भ हुआ।

प्रवेश

१९५२-५३ ई० में विभिन्न विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्रों में से सार्वजनिक निर्माण कार्य, भू-सूचन और बिजली विभाग की ट्रेनिंग के लिये चुने गये २६ इंजीनियर छात्रों को छात्र वृत्ति देने की सरकार ने स्वीकृति दी। इस वर्ष मेकेनिकल इंजीनियरिंग (रेफीजरेशन), इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग (कांक्रिट टेकनालाजी) के अल्पकालीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये। छुट्टियों में प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के छात्रों को विश्वविद्यालय में व्यावहारिक ट्रेनिंग देने की प्रथा जारी रखी गई। विश्वविद्यालय में ऐसे सिनेमा की व्यवस्था करके, जिसमें शिक्षात्मक और मनोरंजक फिल्म दिखाये जाते थे, मनोविनोद की सुविधाओं में सुधार किया गया।

छात्र-वृत्ति,
ट्रेनिंग और
अन्य कार्य-
वाहियाँ

विद्यार्थियों के अनुशासन और स्वास्थ्य की ओर समुचित ध्यान दिया गया।

सिविल इंजीनियरिंग सेक्शन में स्वायत्त (soil) इंजीनियरिंग लेबोरेटरी (प्रयोगशाला), कंक्रीट लेबोरेटरी और हाइड्रालिक्स लेबोरेटरी, मेकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्शन में रेफीजरेशन लेबोरेटरी, सीनयर टेकनालाजिकल लेबोरेटरी, कम्प्यूनिकेशन लेबोरेटरी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेक्शन में मेजरमेंट लेबोरेटरी साल भर चालू रही। प्रयोगशालाओं की आधुनिक ढंग से सुसज्जित करने के लिए बहुत सा साज-सामान प्राप्त हुआ और उसे यथास्थान ठीक कर दिया गया।

प्रयोगशालाएं

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेबोरेटरी के लिए एक पृथक ब्लॉक, जिसके बन जाने से सिविल और मेकेनिकल इंजीनियरिंग विभागों में स्थान की संकीर्णता दूर होकर उसके विस्तार की गुंजायश हो जायगी, बनाने की व्यवस्था करने के संबंध में जो योजना बनाई जा रही थी, उसमें वर्ष के अन्त में काफी प्रगति हो चुकी थी।

१९५१ ई० में विकास और नियोजन समितियाँ भी सिंडीकेट को राय देने के लिए बनाई गईं ।

विश्वविद्यालय के नियम और विनियम बनाने का काम सिंडीकेट की पाण्डुलेख उपसमिति को सौंपा गया और सिंडीकेट ने इसकी रिपोर्ट पर विचार किया और इसे प्रवर समिति के पास भेज दिया ।

इस वर्ष प्रोफेसरों और लेक्चररों का वेतनक्रम बढ़ाया गया ।

उप-कुलपति (वाइस-चांसलर), डॉक्टर सी० ए० हार्ट को भारत सरकार का प्रतिनिधि बनाकर अगस्त में ब्रसेल्स में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय जियोडेटिक (Geodetic) तथा जियोफिजिकल (Geophysical) की ८ वीं सामान्य बैठक में और सितम्बर में लन्दन में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय भूगर्भ अनुसंधान सम्मेलन में भाग लेने के लिये भेजा गया ।

वीक्षान्त समारोह के पुराने हाल को नये नमूने पर बनाया गया, जिससे अब उसमें ६०० व्यक्तियों को बैठने के लिए व्यवस्था हो गई है, जबकि पहिले उसमें केवल ६५० के लिए ही स्थान था ।

सेन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की इमारत के लिए काउंसिल आफ साइंटिफिक ऐण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च को १० एकड़ का एक भू-खण्ड (प्लॉट) दिया गया और इमारत का निर्माण कार्य हो रहा है ।

५६—साहित्यिक प्रकाशन

१९५१ ई० में जो प्रकाशन शिक्षा विभाग को प्राप्त हुए, उनकी कुल संख्या १,३२६ थी, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या १,०२६ थी । इस वर्ष के प्रकाशन में भी सबसे अधिक संख्या हिन्दी पुस्तकों (६११) की रही । शेष पुस्तकों में से १८३ पुस्तकें विभिन्न भाषाओं में लिखी हुई, १३२ अंग्रेजी की, ४८ उर्दू की, २२ संस्कृत की, बंगाली और गुजराती प्रत्येक की दो-दो और १ अरबी की थी । १० पत्रिकाओं में से प्रत्येक कई भाषाओं तथा अंग्रेजी में लिखी हुई और ५ हिन्दी की पत्रिकाएं थीं । पद्य के प्रकाशनों की संख्या सबसे अधिक अर्थात् २४७ थी । अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाशित पुस्तकों की संख्या इस प्रकार थी :—

धर्म	१७०
साहित्य	१११
शिक्षा	१०२
उपन्यास	१०२
नाटक	४८
इतिहास	४८
विधि	४१
भूगोल	३६
गणित	३१
राजनीति	२६
जीवन-चरित्र (जिसमें संस्मरण सम्मिलित है)	२६
नागरिक शास्त्र	२६
विज्ञान (जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, पशु-विज्ञान, वनस्पति विज्ञान इत्यादि सम्मिलित है)	२२

सभी विषयों में नई पुस्तकें आईं। हिन्दी, उर्दू और बंगाल की पुस्तकें अत्यधिक जनप्रिय रही। उपन्यास, इतिहास, समाज-शास्त्र और दर्शन की पुस्तकों का सबसे अधिक पठन किया गया।

५८--सूचना और प्रख्यापन

सामान्य

सूचना डायरेक्टरेट पहले की तरह लोगों को सरकार की नीतियों, कार्यवाहियों और योजनाओं के सम्बन्ध में सूचना देता रहा और सरकार को भी इस बात से अवगत कराता रहा कि विभिन्न विभागों में उसने जो कार्यवाहियों की, उनके बारे में जनमत क्या था और उसकी प्रतिक्रियाएँ क्या थी।

अगस्त के महीने से सूचना विभाग के सचिव ने सूचना सचालक के रूप में भी कार्य किया। डायरेक्टरेट की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष में उसको पुनर्संगठित करने के प्रश्न पर विचार किया गया।

फिल्म प्रख्यापन यूनिटों द्वारा आयोजित प्रकाशन, जिनमें पत्र-पत्रिकाएँ, पत्रिकाएँ आदि, प्रेस नोट, प्रेस को भेजे गये समाचार, फिल्म और फोटोग्राफ, रेडियो तथा व्याख्यान सम्मिलित हैं, प्रख्यापन के मुख्य साधन बने रहे। सूचनात्मक पत्रिका और लेखों को और अधिक छपाने के लिये प्रभावपूर्ण कार्यवाहियाँ की गयीं।

सरकारी प्रकाशन, जिनमें से बहुतों का मूल्य रखा गया, डायरेक्टरेट के सूचना ब्यूरो द्वारा जारी रखे गये। समूह्य प्रकाशनों की व्यावसायिक आधार पर बेचने के लिये विगत वर्ष जो निर्णय किया गया था, उसके अनुसार ब्यूरो को १ अप्रैल, १९५१ ई० से व्यावसायिक कारोबार घोषित कर दिया गया।

पत्र-पत्रिकाएँ

वर्ष के आरम्भ से "यू० पी० इन्फार्मेशन" तथा "इत्तेलात" को उनके आकार में बिना कोई परिवर्तन किये हुए ४८ पृष्ठ के मासिक समाचार-पत्रों में परिवर्तित कर दिया गया। हिन्दी "समाचार" और "नवयुग" को भी, जिसके साथ हिन्दी मासिक "हूल" मिला लिया गया था, बन्द कर दिये गये और इनके स्थान पर "उत्तर प्रदेश पंचायती राज्य" एक नया हिन्दी पाक्षिक निकाला गया, जो आकार तथा विस्तार में अपेक्षाकृत बहुत अधिक था। प्रत्येक पक्ष में इस नये पत्र की जितनी प्रतियाँ निकाली जाती थीं, उनकी संख्या ४०,००० थी। कुछ व्यक्तियों को छोड़कर इस पत्र को उत्तर प्रदेश में सभी गाँव सभाएँ और बहुत सी पंचायती अदालतें मूल्य देकर खरीदती थीं। "यू० पी० इन्फार्मेशन" तथा "इत्तेलात" के इस प्रकार के क्रमशः ४५० और २२२ ग्राहक थे। वर्ष में प्रकाशित "यू० पी० इन्फार्मेशन" की प्रतियों की कुल संख्या ३४,८२६ थी और "इत्तेलात" की ३६,४५३ थी। इन तीनों पत्रों ने स्वतन्त्रता दिवस, गाँधी जयंती तथा जनतन्त्र दिवस के अवसर पर विशेषांक निकाले।

पत्र, पुस्तिकाएँ आदि

पत्र, पुस्तिकाएँ आदि के नियमित विवरण तथा प्रकाशन के लिये एक सुस्पष्ट कार्यक्रम बनाया गया और डायरेक्टरेट तथा सचिवालय के विभिन्न विभागों के बीच अधिक सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से विभागों के साथ सम्पर्क बनाये रखने और पत्रियों के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त करने का कार्य पत्रकारों की एक टीम को सौंपा गया। वर्ष में इस प्रबन्ध के अधीन बहुत सी समूह्य पत्रिकाएँ और पुस्तिकाएँ प्रकाशित की गयीं। पत्रियों का मूल्य इतना कम रखा गया कि प्रत्येक व्यक्ति उसे आसानी से खरीद सके। समूह्य प्रकाशनों के अतिरिक्त निःशुल्क वितरण के लिये सरकारी कार्यवाहियों से

संबंधित पत्रिया निकाली गईं। इनमें निम्नलिखित ग्रन्थ-मालायें भी सम्मिलित थी :—

- (१) उत्तर प्रदेश में (हिंदी)।
- (२) उत्तर प्रदेश में (उर्दू)।
- (३) प्रोग्रेसिव उत्तर प्रदेश (अंग्रेजी)।
- (४) प्रगतिशील उत्तर प्रदेश (हिंदी)।
- (५) यू० पी० सरकारों की राष्ट्रपर (उर्दू)।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पत्रों की जितनी प्रतियाँ प्रकाशित करके निःशुल्क बाँटी गयीं उनकी कुल संख्या लगभग ११ लाख थी।

डायरेक्टरेट की तीनों पत्रिकाओं में प्रकाशन विज्ञापनों से १९५१ ई० के फेब्रुअरी वर्ष में २,९६१ रु० की आय हुई। पत्र-पत्रिकाओं को मिलाकर समस्त समूह्य प्रकाशनों से कुल १,६६,२९३ रु० (सुगमार्क) की आय हुई।

आय

प्रेसों को सरकारी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में सूचना देने के अभिप्राय से विभिन्न समाचार-पत्रों और नियतकालिक पत्रिकाओं के लिये ६०० से अधिक प्रेस नोट और अन्य आइटम जारी किये गये। साप्ताहिक संवाद-पत्र जारी रहा और इस प्रकार के ५१ संवाद-पत्र, जिनमें विभिन्न सरकारी विभागों की कार्यवाहियों का वर्णन था, प्रकाशन के लिये दिये गये। राज्य में समाचार-पत्रों को सरकारी दफ्तरों के दयाल्यगनो, रेडियो भाषणों के अतिरिक्त कई विशेष लेख भी भेजे गये।

समाचार-
पत्रों द्वारा
प्रस्थापन

डायरेक्टरेट के फोटोग्राफिक सेक्शन ने राष्ट्र-निर्माण के सम्बन्ध में सरकार की विभिन्न कार्यवाहियों का फोटोग्राफ लिया और प्रेस को ५,००० से अधिक फोटोग्राफ दिये गये। सरकारी पत्र-पत्रिकाओं में भी कई फोटोग्राफों का उपयोग किया गया।

फोटोग्राफ
द्वारा प्रस्था-
पन

राज्य में १९५१ ई० में ५२ फील्ड पब्लिसिटी यूनिटों ने कार्य किया। इनमें से ५१ यूनिटें जिलों के हेडक्वार्टरों पर तैनात की गयीं और एक यूनिट डायरेक्टरेट के हेडक्वार्टर पर तैनात की गयी। कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, आगरा और लखनऊ के पाँच बड़े बड़े शहरों में से प्रत्येक शहर के जिला सूचना अधिकारियों के अतिरिक्त एक अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी भी था। जुलाई, १९५१ ई० में जिला सूचना अधिकारियों और अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारियों के १४ पद खाली थे, क्योंकि इन पदों के आधिकार्य अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया था। इन खाली जगहों को चुनाव समिति, जिसके अध्यक्ष विधान सभा के सदस्य, श्री कमलापति त्रिपाठी थे, द्वारा चुनावों के आधार पर भर दिया गया।

फील्ड पब्लि-
सिटी

प्रस्थापन सम्बन्धी कार्यवाहियों में संयोजन के विचार से, जिलों में स्थापित जिला प्रस्थापन समितियों और कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, आगरा और लखनऊ नगरों में बनायी गयी नगर प्रस्थापन समितियों द्वारा फील्ड प्रस्थापन कार्य में पहले गैर-सरकारी व्यक्तियों की राय मान्य समझी जाती थी, किन्तु यह देखा गया कि ये समितियाँ ठीक तरह कार्य नहीं कर रही थी और इनमें से एक समिति जिले में जो काम करती थी, वही काम अधिकतर दूसरी समिति भी करती थी। १९५० ई० के अन्त में सूचना विभाग से सम्बद्ध स्थायी समिति ने प्रणाली में उपयुक्त परिवर्तन के लिये सुझाव दिये और १९५१-५२ ई० के वित्तीय वर्ष में जिला तथा नगर प्रस्थापन समितियों को तोड़ दिया गया। उनके स्थान पर जिला मैजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता में जिला

नियोजन सभितियों बनायी गयी। जिला नियोजन समितियों को प्रख्यापन कार्य के लिये ६०० रु० से लेकर ६०० रु० तक की धनराशि दी गयी, जैसी कि जिला प्रख्यापन समितियों के लिये दी जाती थी।

जिलों तथा
मेलों में
प्रख्यापन
कार्य

फील्ड प्रख्यापन यूनिट्स सरकारी कार्यवाहियों पर व्याख्यान आयोजित करती रहीं और जिले में अन्य प्रख्यापन कार्य भी करती रहीं। इन यूनिटों ने टिडिडियों को नष्ट करने, कृषि संरक्षण, महिला हितकारी योजना, साम्प्रदायिक शांति अपराधशील जातिधों के उत्थान, वयस्क जनो के प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षण, जमीन्दारी विज्ञान कोष की वसूली, जन-गणना इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया। कार्तिकी पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न जिलों में आयोजित गंगा के मेलों तथा विभिन्न अन्य मेलों में दीर्घयात्रियों को जनता के सुधारार्थ सरकार द्वारा किये गये विभिन्न उपायों के लाभ से अवगत करने के लिये प्रगट रूप से प्रख्यापन किये गये। निम्नलिखित मेलों में प्रख्यापन कार्य किये गये:—

गढमुक्तेश्वर (मेरठ), ददरी (बलिया); ककोरा (बदायूँ); अनुपशहर (बलन्दशहर); राजघाट (बलन्दशहर); बिठूर (कानपुर); अयोध्या (फैजाबाद); डलमऊ (रायबरेली); गंज (बिजनौर); टिगरी (मुरादाबाद); शिवराजपुर (फतेहपुर); परियारघाट (उन्नाव); नानमऊ (उन्नाव); गोवर्धननाथ (हमीरपुर); धाईघाट (शाहजहाँपुर); सिवो रामपुर (फर्रुखाबाद); मकनपुर (कानपुर); लकड़मन्डी घाट (गोडा) और चोचकपुर (गाजीपुर)।

मोटर गाडियाँ
तथा पब्लिक
ऐडरेस
एक्विपमेंट सेट

हरदोई तथा बिजनौर जिले को छोड़कर वर्ष समाप्त होने के समय समस्त जिलों के पास प्रख्यापन कार्य के लिये मोटर गाडियाँ थीं। हरदोई तथा बिजनौर जिले की दो मोटर गाडियों की कानपुर के सेन्ट्रल वर्कशॉप में भारी मरम्मत की जा रही थी।

डायरेक्टरेट के पास २२ पिक-अप (जिनमें से एक बेकार थी), १० लैन्ड रोवर और २६ वान थी। २० मोटर गाडियाँ नवम्बर, १९५१ ई० में स्वीकृत की गयी थीं और १८ शेबरेलेट पिक-अप और २ इन्टर नेशनल पिक-अप नवम्बर, १९५१ ई० में खरीदी गयी थी। जो पिक-अप और लैन्ड रोवर १९४६ ई० में खरीदी गयी थीं और अधिक इस्तेमाल के कारण टूट-फूट गयी थीं, उनकी मरम्मत रोडवेज वर्कशॉप में की गयी।

रामपुर और टेहरी-गढ़वाल के अतिरिक्त प्रत्येक जिले को एक पब्लिक ऐडरेस, इक्विपमेंट सेट दिया गया, किन्तु इनमें से बहुत से सेट पुराने थे और उनकी जगह नये सेट देने पड़े। सब मिलाकर १९५१ ई० में ४६,५०४ रु० १४ आ० की कुल लागत पर आधुनिक प्रकार के २३ नये सेट खरीदे गये।

सिनेमा की
यूनिटें

वर्ष के अन्त में २३ जिलों के पास १६ मिलीमीटर की साउन्ड यूनिटें थी, किन्तु प्रत्येक सेट से दो सम्मेलनवाली जिलों में कार्य लिया गया। अलमोड़ा जिले के पास १६ मिलीमीटर का एक साइलेंट प्रोजेक्टर था। नियोजन विभाग को इटावा पाइलेट प्रोजेक्ट स्कूल के सम्बन्ध में १६ मिलीमीटर का एक साउन्ड प्रोजेक्टर दिया गया। १० जिलों के पास कुछ समय तक ३५ मिलीमीटर के प्रोजेक्टर थे, परन्तु बहुत भारी होने की वजह से इन्हें अक्टूबर-नवम्बर, १९५१ ई० में वापस ले लिया गया (किन्तु इटावा जिले में ३५ मिलीमीटर का प्रोजेक्टर रहने दिया गया और वहाँ इसके अतिरिक्त १६ मिलीमीटर का भी एक सेट था)। आगामी वित्तीय वर्ष में १६ मिलीमीटर की ३० सिनेमा मशीनों के खरीदने का निर्णय किया गया।

“मच्छरों का उत्पात” फिल्म की तीन प्रतियाँ, “लोक तन्त्रप्रवर्तन” फिल्म की ६ प्रतियाँ और “समुदाय”, “शिशु” तथा “माँ” फिल्मों की एक एक प्रतियाँ भारत सरकार से खरीदी गयीं और इन फिल्मों को उन जिलों में दिखाया गया, जहाँ १६ मिलीमीटर की मशीनें थीं। “अपराध निरोधक अधिकारी” (भाग १, २, ३ और ४) की एक अन्य फिल्म इंग्लैन्ड से खरीदी गयी। भारत सरकार से जो फिल्में मिलीं, उन्हें जिला सूचना अधिकारियों के पास भेज दिया गया, ताकि वे उन फिल्मों को अपने जिलों में बारी-बारी दिखायें। सब मिलाकर १६ मिलीमीटर आकार की ७० फिल्में भारत सरकार से प्राप्त हुईं और १२ फिल्में खरीदी गयीं।

जनता के लाभ के लिये डायरेक्टरेट द्वारा चलायी गयी सामूहिक रूप से रेडियो सुनने की योजना जनप्रिय सिद्ध हुई और ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो सेट लगाने के लिये कई माँग आयीं। चूँकि अधिकांश गाँवों में बिजली नहीं थी, इसलिये बैटरी द्वारा चालित रेडियो सेटों की अधिक माँग हुई। इस माँग को पूरा करने के अभिप्राय से डायरेक्टरेट ने बैटरी द्वारा चालित सेटों को ग्रामीण क्षेत्रों में बाँटने के लिये इकट्ठा करने के सम्बन्ध में लखनऊ की सरकारों, सूक्ष्म यन्त्र फैक्ट्री से प्रबन्ध किया। इसके अतिरिक्त वर्ष में विभिन्न जिलों में लगभग ८० रेडियो सेट लगाये गये और उनमें से अधिकांश रेडियो सेट न लौटाये जाने वाले ग्रंथदान के आधार पर उधार दे दिये गये। प्रारम्भ में ग्रंथदान की धनराशि २०० रु० प्रति सेट निर्धारित की गयी थी, परन्तु बाद में उसे घटाकर १२५ रु० प्रति सेट कर दिया गया।

सरकार को उसकी नीतियों और कार्यवाहियों की प्रतिक्रिया तथा जनमत से अवगत कराने के लिये बहुत से समाचार-पत्रों और नियतकालिक पत्रिकाओं की परीक्षा की गयी और लगभग ७८,००० कॉपी सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गयी। कई मामलों में सम्बन्धित समाचार-पत्रों का ध्यान झूठे रिपोर्टों की ओर आकर्षित किया गया और उनसे इस प्रकार की रिपोर्टों का खंडन करने या उनको सही-सही छापने का अनुरोध किया गया। सरकारी सदस्यों की सूचना के लिये समाचार-पत्रों की प्रमुख विषयों पर आलोचनाओं के साप्ताहिक तथा पाक्षिक रिव्यू भी तैयार किये गये।

उत्तर प्रदेश प्रेस परामर्शदात्री समिति, जो १९४९ ई० में नौ वर्ष के लिये फिर से बनायी गयी थी, का कार्यकाल ३१ मार्च, १९५१ ई० को समाप्त हो गया। समिति का कार्यकाल ३१ मार्च, १९५१ ई० से ६ महीने के लिये और बढ़ा दिया गया और इसके बाद उसके फिर से बनाये जाने का प्रश्न विचाराधीन था। समिति को जिन बातों का निर्देश किया गया था, सरकार ने उनके सम्बन्ध में समिति के सुझावों को साधारणतया स्वीकार कर लिया। सरकार और समिति के सम्बन्ध वर्ष भर अच्छे बने रहे।

आलोच्य वर्ष में सरकार ने किसी भी समाचार-पत्र के विरुद्ध जमानत माँगने और/अथवा जब्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की, किन्तु रामपुर के उर्बू साप्ताहिक “आजाद” और आगरा के हिन्दी दैनिक “सैनिक” का नाम वार-वार अश्लील बातों को प्रकाशित करने के कारण “दुर्नामावलि” में दर्ज कर दिया गया, ताकि उनको अदालतों नोटिसें जारी की जा सकें। उर्बू साप्ताहिक “आजाद” को एक आपत्तिजनक लेख प्रकाशित करने के लिये चेतावनी दी गयी। आगरा के “सैनिक” का नाम प्रेस परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों पर अन्ततोगत्वा ‘सद्नामावलि’ में फिर से दर्ज कर लिया गया।

सामूहिक रूप से रेडियो सुनने की योजना

समाचार पत्रों की छानबीन

उत्तर प्रदेश प्रेस परामर्शदात्री समिति

समाचार-पत्रों के विरुद्ध कार्यवाही

अध्याय ८—विविध

५६—स्थानीय स्वशासन इंजीनियरिंग

इस वर्ष जन-स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग का नाम बदल कर स्थानीय स्वशासन इंजीनियरिंग विभाग रखा गया। स्थानीय निकायों ने उन अधिकारियों से, जो उनके लिये उपलब्ध किये गये थे, बहुत सी योजनाओं को प्रारम्भ किया। इसके फलस्वरूप विभाग की कार्यवाहियों में काफी वृद्धि हुई। को की कमी के कारण इन योजनाओं का कार्यान्वित किया जाना स्थगित कर दिया गया था।

विभाग ने ५३ जल सप्लाई योजनाओं (१४०.८४ लाख रु० की लागत की, जो बड़ी तथा पुनर्रसगठित योजनाएँ हैं), ६०.८२ लाख रु० की लागत की २१ पानी निकास की योजनाओं, २३.३० लाख रु० की लागत की ४ बिजली सप्लाई योजनाओं और १३.१३ लाख रु० की लागत के ३ स्वास्थ्य-कार्य हाथ में लिया। इसके अतिरिक्त ४० जल सप्लाई सम्बन्धी, सविस्तर योजनाएं, १२ जल सप्लाई सम्बन्धी संशोधित तखमीनें, १४ पानी के निकास की योजनाएं, ४ पानी के निकास के संशोधित तखमीनें, १३ बिजली सप्लाई तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाएं, उक्त निर्माण कार्यों से सम्बन्धित एक संशोधित तखमीना और १७ लागत के पूर्वानुमान (जिसके लिये २६६.१२ लाख रु० की धनराशि अपेक्षित थी) तैयार किये गये और स्थानीय निकायों को भेजे गये।

विभाग के पथ-प्रदर्शन में कानपुर में पानी के सप्लाई के विस्तार की त्रैवार्षिक योजना, जिसमें २२.५ लाख रु० का व्यय होगा तैयार की गई। इस सम्बन्ध में पाइप लाइन को आर्डिनेंस फैक्ट्री तक बढ़ाने के प्रयोजन से सरकार ने कानपुर विकास बोर्ड को ५ लाख रु० का ऋण दिया। विभाग ने जल सप्लाई को चकेरी हवाई अड्डे के क्षेत्र तक बढ़ाने के सम्बन्ध में होने वाली लागत का एक पूर्वानुमान तैयार किया और उसी प्रकार से उसे कानपुर के गोविन्दगढ़ तक बढ़ाने के सम्बन्ध में पैमाइश की। कानपुर विकास बोर्ड को कानपुर गलीज उपयोग योजना के पहिले दौर के सम्बन्ध में विभाग के एक अफसर की सेवाएँ अर्पित की गयी थी। इस योजना को कानपुर विकास बोर्ड ने पूरा किया, इसके कार्यान्वित होने के फलस्वरूप वर्ष के अन्त तक ३८० एकड़ भूमि में खेती की गयी थी।

स्थानीय स्वशासन इंजीनियरिंग विभाग द्वारा किये गये कुछ अधिक महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों का विवरण नीचे दिया हुआ है :—

सम्पादित
निर्माण-कार्य

(१) जल सप्लाई—जिला गढ़वाल में रतुरा, डूंगरी तथा कांडई नामक तीन गाँवों में तथा जिला सहारनपुर के कस्बा ज्वालापुर में जल सप्लाई योजनाओं का काम पूरा किया गया।

राबर्ट संगंज (जिला भिर्जापुर) की जल सप्लाई योजना के काम में भी काफी प्रगति हुई। इस वर्ष फिल्डेशन प्लान्ट न आ सका और इसके कारण इस निर्माण कार्य के सम्बन्ध में कुछ अस्थायी प्रबन्ध करने की आवश्यकता हुई। देहरादून में बंदलमेढ की दोहरी लाइन बनाने का काम पूरा किया गया। इसी प्रकार मछोदरी तथा सिकरौल (बनारस) ट्यूबवैल्स के परम्पिंग स्टेशनों का निर्माण कार्य और लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट तथा सेन्ट्रल जेल में जल सप्लाई का प्रबन्ध पूरा किया गया। रुड़की, झासी, हरदोई, बाँदा, अल्मोड़ा, आगरा

था इलाहाबाद की औद्योगिक बस्ती नैनी (इलाहाबाद) की अनेक योजनाएं गति के विभिन्न स्तर पर थीं। जल की सप्लाई को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के कुछ नगरों में ६० टयबवेलों का निर्माण कार्य चलता रहा। इनमें से २५ बनकर तयार हो गये और सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारियों के सुपुर्ण कर दिये गये थे।

(२) बिजली लगाने की योजनाएं—उत्थाव में जहां एक बिजलीघर का निर्माण किया गया था और मई, १९५० ई० में चालू किया गया था सब-स्टेशनों में तो २०० किलोवाट के और दो १०० किलोवाट के ट्रान्सफार्मर लगाये गये और २४ घंटे बिजली देने का काम प्रारम्भ किया गया। वर्ष के अन्त में अल्मोडा में बिजली-घर की सज्जा परिपूर्ण की जा रही थी। नगर में घरेलू तथा औद्योगिक प्रयोजनों के लिये बिजली दिन के १६ घंटे तक दी जाती थी। हलद्वानी में अधिकांश निर्माण पूरा हो गया था और नगर को २४ घंटे बिजली दी जाती थी।

(३) पानी के निकास की योजनाएं—वर्ष के अन्त में अमरोहा में लगभग ४४ प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका था। हाथरस में पानी के निकास की योजना दो भागों में विभाजित कर दी गयी थी। वर्ष के दौरान में पहला भाग लगभग पूरा हो गया था। उत्तरा खंड के तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिये गरम पानी नासक स्थान पर एक यात्री शाला बनाने का काम भी पूरा हो गया था।

६०—स्थानीय कोष लेखे

स्थानीय कोष लेखा परीक्षा विभाग ने कुल ३,०६१ लेखों को जाँचा, जबकि पिछले वर्ष २,८२७ ही लेखे जाँचे गये थे। इसके अतिरिक्त म्युनिसिपल तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के लेखों में सम्मिलित किये गये अनेक धर्मदाय ट्रस्ट कोष भी थे। कुल लेखों में से २,३८३ लेखों की लेखा-परीक्षा निःशुल्क की गयी।

गजपेट अफसरों द्वारा किये गये निरीक्षणों की संख्या पिछले वर्ष की १,१८१ से बढ़कर इस वर्ष १,३७५ हो गयी। इनके अतिरिक्त अधिकांश निरीक्षण रेजि कार्यालयों में सम्बद्ध लेखा परीक्षकों द्वारा किये गये।

समस्त स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं तथा कोषों की कुल आय और व्यय जिनकी जाच-पड़ताल की गई क्रमशः २०,४०,६६,००० रु० और २०,६९,९२,००० रु० थे, जबकि पिछले वर्ष २०,४१,१७,३०० रु० और १८,१३,२३,२०० रु० थे। कुल व्यय में २ १/२ करोड़ रुपये से अधिक वृद्धि हुई।

स्थानीय निकायों की सामान्यतः वित्तीय दशा संतोषजनक नहीं थी। ७३ बोर्ड अपने व्यय को अपनी वार्षिक आय के अनुसार सीमित नहीं रख सके और २३ बोर्डों के वायित्व उनकी पूंजी से बहुत अधिक बढ़ गये। अधिकांश बोर्डों को अपनी बचत की धनराशि का सहारा लेना पड़ा। लेखों के देखने से यह स्पष्ट है कि बोर्डों को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिये अपने व्यय में कमी करने के अतिरिक्त बकाया की वसूलियों के मामले में कड़ाई बर्तनी पड़ेगी और चुगी तथा सीमांत कर के कर्मचारिबर्ग के कार्य पर कड़ी देख-रेख एवं जांच करनी पड़ेगी। लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर भलीभांति ध्यान नहीं दिया जाता रहा और लेखा परीक्षा की खास खास आपत्तियों को दूर करने में अधिकतर बिलम्ब किया गया।

जहां तक डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का सम्बन्ध है, ३५ बोर्डों के लेखों की दशा या

निरीक्षण

आय और व्यय जिनकी जाच-पड़ताल हो चुकी है

स्थानीय निकायों में लेखों का वित्तीय तथा सामान्य दशा

के समान डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की वित्तीय स्थिति पर, सामान्यतः उनके कर्मचारियों के संशोधित बतन-क्रम के लागू हो जाने के फलस्वरूप बुरा प्रभाव पड़ा। कुछ बोर्डों ने तो अपने व्यय को पूरा करने के लिये सरकार से अल्प-कालीन ऋण की मांग की। वाजिब छूट उदारतापूर्वक दी गयी और करों की बसूली के सम्बन्ध में, जिनका बकाया प्रतिवर्ष बढ़ रहा था, सख्त कानूनी कार्यवाहियाँ नहीं की गयी। अधिकांश बोर्डों ने पिछली लेखा परीक्षा आपत्तियों पर ध्यान नहीं दिया।

गबन तथा
जालसाजी
के मामले

गबन तथा दुरुपयोग के मामलों में अधिक वृद्धि हुई ; देख-रेख में असावधानी तथा नियमों के न पालन किये जाने के कारण ध्वंसहरण हुए। लेखों की हालत के लगातार बिगड़ने का प्रमुख कारण यह था कि अपराधियों के साथ सख्ती नहीं बरती गयी।

* लेखा परीक्षा के समय इटावा, अतरौली, तिलहर, मिर्जापुर, मुराब्बाबाद, मसूरी, कासगंज, गाजीपुर, मुजफ्फरनगर, आगरा, बनारस भदोही, हरद्वार, इलाहाबाद, कोसी और लखनऊ की म्युनिसिपैलिटियों और इलाहाबाद, आगरा, बाराबंकी, इटावा, एटा, देवरिया, फर्रुखाबाद, मिर्जापुर, उन्नाव, सीतापुर, बरेली, आजमगढ़, जौनपुर तथा नैनीताल के डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में गबन तथा दुरुपयोग के फलस्वरूप हानियाँ पाई गयीं। लखनऊ म्युनिसिपैलिटी में लगभग १ लाख रुपये के गबन का पता लगाया गया और इलाहाबाद तथा आगरा के डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में पूर्वोक्त कोष लेखा में भारी गबन के मामले पकड़े गये। मिथिला तथा नौमसूर और अहमौरा की नोटिफाइड एरिया में और इलाहाबाद, बरेली, हरदोई, झाँसी तथा गाजीपुर की टाउन एरिया में भी गबन के मामले हुए। देवरिया और गोंडा में कोर्ट आफ वाईस लेख में व्ययहरण पाये गये।

विशेष लेखा
परीक्षा

* अतरौली, कानपुर तथा चन्दौसी के म्युनिसिपल बोर्डों, बनारस के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, के० डी० ई० एम० इन्टरमीडियेट कालेज, बरेली, सेन्ट एन्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर, गांधी मेमोरियल एन्ड एसोसियेटेड हास्पिटल, लखनऊ, बनारस के एलेक्शन आफिस तथा कलेक्टोरेट के लेखों की भी विशेष लेखा परीक्षाएँ की गयीं।

पाकिस्तान
को प्रव्रजन
करने वाले
स्थानीय नि-
कायों के
कर्मचारियों
के दावे

लेखा-पालों
की परीक्षा

पाकिस्तान उपनिवेश तथा भारत संघ के बीच समझौता हो जाने के फलस्वरूप स्थानीय निकायों के उन भूतपूर्व कर्मचारियों के दावों के सत्यापन के अधिकांश मामलों की जांच की गयी, जिन्होंने पाकिस्तान को प्रव्रजन किया था और संघ सरकार की समय समय पर उनके परिणाम भेजे गये। यह आशा की गयी थी कि समस्त दावों का सत्यापन १९५२ ई० के प्रारम्भ में ही पूरा हो जायगा।

म्युनिसिपल तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लेखा-पालों की परीक्षाएँ पूर्व की भाँति दिसम्बर में हुईं। किन्तु परीक्षाफल बहुत ही असन्तोषजनक रहा : म्युनिसिपल बोर्ड लेखापाल की परीक्षा में २७ उम्मीदवारों में से केवल दो उम्मीदवार सफल हुए और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लेखापाल की परीक्षा में २४ उम्मीदवारों में से ६ उम्मीदवार सफल हुए।

६१-निरीक्षण कार्यालय

ऑलोच्य वर्ष में विलीनीकृत राज्यों में सरकारी कार्यालयों के अतिरिक्त दीवानी अदालत के ३०० कार्यालय निरीक्षण कार्यालय की अधिकार सीमा में रखे गये।

विगत वर्षों की भांति निरीक्षण कार्यालय प्रमुख रूप से विभागाध्यक्षकों को उनके अधीनस्थ विभागों की कार्यविधि के नियमों को बनाने तथा उनमें संशोधन करने के सम्बन्ध में परामर्श एवं सहायता देता रहा। उक्त कार्यालय विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्य को सँस्र बनाने के उपाय बतलाने, कार्यालय की कार्यविधि में दोषों को दूर करने और सरकारी कार्यालयों में जनता के मामलों का निपटारा करने के सम्बन्ध में और अधिक क्षमता लाने पर विशेष ध्यान देता रहा।

वर्ष में ७५७ कार्यालयों का निरीक्षण किया गया और कर्मचारिवर्ग के सम्बन्ध में ६७ मामलों की विशेषरूप से जांच की गयी। निरीक्षण कार्यालय ने माल बोर्ड, डिवीजनों के कमिश्नरों, भूमि-व्यवस्था कमिश्नर, इत्यादि के बीच कर्मचारिवर्ग का फिर से बंटवारा करने के सम्बन्ध में सहायता प्रदान की, जो कतिपय कार्यालयों के कार्यों के पुनर्संगठन की दृष्टि से आवश्यक हो गया था और कार्यालय के विभिन्न मनुअलों में भी आगे पारिणामिक संशोधन करने में सहायता दी।

६२—उत्तर प्रदेश तथा बिहार का शुगर कमीशन

पहले की भांति उत्तर प्रदेश तथा बिहार के शुगर कमीशन ने चीनी तथा गन्ने के मूल्य और चीनी मिलों के वर्तमान स्थिर यन्त्रों (plants) में परिवर्तन तथा परिवर्द्धन से सम्बन्धित सभी मामलों में सरकार को परामर्श दिया।

१९५०-५१ के गन्ना पेरने के मौसम में अनेक समस्याएँ उपस्थित हुईं। देश में चीनी का अभाव था। गुड़ और खंडसारी के मूल्य अधिक ऊँचे थे और यह समझा जाता था कि इन वस्तुओं के बनाये जाने से अधिक मात्रा में गन्ने की खपत होगी। दानेदार शकर की कमी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार दोनों इस बात की इच्छुक थीं कि शकर का उत्पादन अधिक से अधिक मात्रा में किया जाय। यह तभी संभव हो सकता था जबकि उद्योग को कोई प्रलोभन दिया जाय। अतएव भारत सरकार ने यह उद्घोषित किया कि पिछले वर्ष तैयार की गई शकर से १०७ प्रतिशत से अधिक जितनी शकर तैयार की जायगी उसे चीनी मिलें खुले बाजार में बेच सकती हैं। इस सुविधा के दिये जाने से अभीष्ट फल की प्राप्ति हुई और बाजार में गुड़ तथा खंडसारी शकर के मूल्य चढ़े होने पर भी दानेदार शकर का उत्पादन १९५०-५१ के पेराई के मौसम में १९४९-५० के ४,६७,२०३ टन से बढ़कर ५,९३,३३७ टन हो गया।

चीनी उत्पादन के बढ़ाने के उपाय

इस मौसम के लिये गन्ने का न्यूनतम मूल्य भारत सरकार द्वारा १ रु० १२ आ० प्रति मन की दर से निर्धारित किया गया था और उस पर अबबाब (Cess) ३ आना प्रति मन के हिसाब से लागू रखा गया। पिछले वर्षों के विपरीत इस वर्ष शकर का मूल्य प्रादेशिक आधार पर निर्धारित किया गया और उक्त प्रयोजन से राज्य को पश्चिमी तथा पूर्वी दो भागों में विभाजित कर दिया गया। पश्चिमी प्रदेश के चीनी के मिलों में जो शकर तैयार की गई उस पर मिल के बाहर ३० रु० ८ आ० प्रतिमन की दर से निर्धारित किया गया जबकि पूर्वी प्रदेश के चीनी के मिलों में तैयार की गई शकर का मूल्य ३२ रु० प्रति मन की दर से निर्धारित किया गया। इन मूल्यों के निर्धारित करने में दोनों प्रदेशों में शकर के उत्पादन पर होने वाली लागत का समुचित रूप से ध्यान रखा गया था।

चीनी का मूल्य

शक्कर उद्योग
का विकास

राज्य में विशेषतः राज्य के पूर्वी जिलों में शक्कर उद्योग के सुवृद्ध करने का प्रश्न कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार के विचाराधीन है। इस उद्देश्य से विविध भविष्य में इस उद्योग के संबंध में किस प्रकार से योजनाये बनाई जायें और इसका विकास किया जाय मार्च, १९५१ ई० में राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में शक्कर उद्योग की जाँच पड़ताल करने तथा इसके विकास के लिये उपयुक्त सिफारिश करने के प्रयोजन से एक समिति नियुक्त की गई जिसमें तत्संबंधी विभिन्न हित सम्मिलित थे। वर्ष समाप्त होने के पूर्व सरकार को समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई और समिति जिन निष्कर्षों पर पहुंची थी सरकार प्रायः उन सबसे सहमत थी। विशेषतः जिन बातों से सरकार सहमत थी, वे ये हैं:-

(१) पूर्वी जिलों में कारखानों के अत्यधिक इकट्ठे होने के कारण इस क्षेत्र के कारखानों को पर्याप्त मात्रा में गन्ना नहीं सप्लाई हो पाता है। उद्योग के हित में यह आवश्यक है कि इन जिलों के कुछ कारखानों को राज्य के अन्दर अधिक उपयुक्त स्थानों में हटा दिया जाय।

(२) शक्कर उद्योग को जिन बढ़ती हुई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उसमें प्रति एकड़ गन्ने की उपज का कम होना सबसे मुख्य कठिनाई है और यह उपज की कमी तथा गन्ने की कम सप्लाई सिंचाई की सुविधा विशेष कर पूर्वी जिलों में कम होने के कारण है और यह उर्वरकों की सप्लाई में कठिनाई तथा यातायात की कमी के कारण है।

समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के संबंध में सरकार द्वारा कार्यवाहियों की गईं और यह प्रस्ताव किया गया कि प्रदेश में चीनी उद्योग के विकास तथा सुधार के प्रयोजन से आगामी पाँच वर्षों के लिये एक योजना बनाई जाय।

१९५१-५२ के मौसम में भारत सरकार द्वारा गन्ने का न्यूनतम मूल्य १ रु० १२० प्रति मन की दर से निर्धारित किया गया और उस पर लगने वाला अवकाश (Cess) ३ आ० प्रति मन की दर से ही लागू रहा। पश्चिमी रोजन (प्रदेश) की मिलों में तैयार की जाने वाली शक्कर का मिल के बाहर मूल्य ३० रु० ८ आ० प्रति मन की दर से और पूर्वी रोजन (प्रदेश) की मिलों में तैयार की जाने वाली शक्कर का मूल्य ३१ रु० ८ आ० प्रति मन की दर से निर्धारित किया गया। जहाँ तक १९५१-५२ की पेराई के मौसम का संबंध है शक्कर के वितरण पर किए जाने वाले आंशिक अथवा विशिष्ट नियंत्रण में उदारता बरती गई। केन्द्रीय सरकार ने यह निश्चित किया कि १९४८-४९ और १९४९-५० के मौसमों में होने वाली प्रत्येक मिल से तैयार किये जाने वाले औसत परिमाण मिल के मूल कोटे के रूप में निर्धारित किये जायेंगे और प्रत्येक मिल के मूल कोटे से अधिक उपज का आधा भाग खुले बाजार में बेचा जायगा और आधा भाग मूल कोटे के साथ नियंत्रित मूल्य पर वितरण किये जाने के लिये सुरक्षित रखा जायगा। यह भी निश्चित किया गया कि आवश्यकता पड़ने पर सप्लाई को बराबर बनाए रखने तथा मूल्य में अनुचित वृद्धि को रोकने के प्रयोजन से समस्त चीनी मिलों के उत्पादन का अधिक से अधिक ५ प्रतिशत तक मुक्त की जानी चाहिए। कारखानों से बाहर नियंत्रण के बेचने के लिए इस प्रकार मुक्त किया गया कुल परिमाण का उस कोटे में समाधान कर लिया जायगा जिसे पेराई के मौसम के बाद उस कारखाने को खुले बाजार में बेचने का अधिकार होगा।

इस नीति का उद्देश्य यह था कि डाक्टरों के बड़े हुए उत्पादन को शीघ्र अधिक प्रोत्साहन दिया जाय।

६३—मुद्रण तथा लेखन सामग्री

सरकार के प्राय सभी विभागों के कामों में वृद्धि होने के कारण छपाई के काम में भी लगातार वृद्धि होती गई। सरकारी छापखाने ने, जिसने अपने हाथ में काम का बहुत बड़ा भाग लिया था, अपनी पूरी शक्ति भर काम किया। श्रम जाँच समिति की सिफारिशों के अनुसार सरकारी छापखाने में ठेके पर काम करने (पीस वर्क) के स्थान पर नियत समय में काम करना (टास्क सिस्टम) की प्रणाली चलाई गई।

प्रशिक्षण, लेखन में नये सरकारी छापखाने की मुख्य इमारत का निर्माण कार्य पूरा हो गया और यूनाइटेड किंगडम से मंगाई गई अन्य मशीनों के आने तथा लगाये जाने की प्रतीक्षा की जा रही थी। वाशिंगटन में स्थित कॉंग्रेसनल प्रेस के आधार पर छापखाने में विधान मंडल की कार्यवाहियों की छपाई के लिए एक आत्म-निर्भर यूनिट की अलग व्यवस्था कर दी गई।

१९५०-५१ ई० के वित्तीय वर्ष में सरकार के विभिन्न विभागों को लगभग ४५,००,००० रु० की लागत की लेखन-सामग्री सप्लाई की गई।

६४—अर्थ तथा संख्या

अर्थ तथा संख्या विभाग ने पूर्व की भांति कृषि तथा उद्योग संबंधी वस्तुओं और दैनिक उपयोग की वस्तुओं और पदार्थों तथा उनसे मिलने वाली वस्तुओं के मूल्यों के आँकड़ों की एकत्र तथा संकलित किया। मूल्यों की सूचियाँ तैयार की गईं और उनके आधार पर मूल्यों के चढ़ाव-उत्तार के संबंध में समीक्षाएं तैयार की गईं।

मूल्यों के
आँकड़े

एक हाल के आधारवर्ष के आँकड़ों के आधार पर कृषि संबंधी वस्तुओं के थोक मूल्यों की तथा उसी प्रकार की अन्य वस्तुओं की सूचियों के इंडेक्स का काम हाथ में लिया गया। एक हाल के आधारवर्ष के आँकड़ों के आधार पर औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों की सूचियाँ तथा औद्योगिक उत्पादन के आँकड़े तैयार करने का भी प्रयत्न किया गया।

उत्तर प्रदेश के बाह्य व्यापार की प्रवृत्ति को समझने के विचार से विभाग ने राज्य के शुद्ध निर्यात के आँकड़े तैयार करने का काम हाथ में लिया, जिसमें राज्य की शुद्ध निर्यात के रूप में भजी जाने वाली कुछ विशेष वस्तुओं के पृथक पृथक तथा सामूहिक रूप से परिमाणों के अंतर देखलाय गये। यह निश्चित किया गया था कि इन सूचियों को विभाग द्वारा निकाली जाने वाली आँकड़ों के मासिक बुलेटिन में प्रकाशित किया जाय।

व्यापारिक
आँकड़े

कृषि की उपज और तत्संबंधी मूल्यों के आँकड़े तैयार करने का काम कृषि उपज के परिमाण तथा मूल्य की विभिन्नता को निर्धारित करने के काम को सुकर बनाने के प्रयोजन से हाथ में लिया गया। यह निश्चित किया गया है कि इन्हें भी आँकड़ों के मासिक बुलेटिन में प्रकाशित कर दिया जाय।

कृषि की
उपज और
तत्सम्बन्धी
मूल्यों के
आँकड़े

आलोच्य वर्ष इस राज्य में इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स ऐक्ट, १९४२ ई० के लागू होने का छठवाँ वर्ष था। कारखानों से जो आँकड़े संग्रह किए गए थे उनसे उनकी पुँजी की व्यवस्था, काम पर लगाये गये श्रमिकों की संख्या,

औद्योगिक
आँकड़े

उपयोग किए गए कच्चे माल तथा ईंधन और तैयार किए जाने वाले माल के परिमाण तथा मूल्य का पता चलता है।

प्रकाशन

आँकड़ों की मासिक बुलेटिन का नियमित रूप से निकलना जारी रहा। इस वर्ष विभाग द्वारा जो अन्य बुलेटिन् निकाली गईं वे ये हैं—(१) 'प्रोथ आफ फॅक्ट्रीज इन यू० पी० एंड नीड फार देयर प्लान्ड डेवलपमेन्ट', (२) 'टु वर्ड्स ए बेटर एकानमी और (३) 'ए गाइड टु करेन्ट आफीशियल स्टेटिस्टिकल पब्लिकेशन्स'।

जाँच और
अनुसंधान

(१) पारिवारिक बजट की जाँच—इस राज्य के १५ चुने हुए नगरों में संग्रह किए गए पत्रकारों के पारिवारिक व्यय संबंधी आँकड़ों को संकलित करने का काम पूरा किया गया। अध्यापन, वकालत और चिकित्सा संबंधी तीन अन्य पेशों के संबंध में उसी प्रकार के आँकड़े पहले ही संग्रह किए जा चुके थे।

(२) फसलों को पैदा करने में होने वाली लागत के संबंध में जाँच—इस संबंध में संग्रह किए गये आँकड़ों के संबंध में तालिका तैयार की जा रही थी। 'हमारा किसान क्या खाता है?' शीर्षक के अंतर्गत एक टिप्पणी प्रकाशित की गई, जिसकी ओर बहुत से लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ। सहकारी तथा यन्त्रीकृत कृषि के अनुसार खती करने में होने वाली लागत की तुलना—त्मक समीक्षा करने के उद्देश्य से तीन नए गाँवों में जाँच-पड़ताल जारी रखी गई।

(३) गाँव संबंधी जाँच—अधिकांश आँकड़े जो वर्ष के अन्त में इस जाँच के अंतर्गत संग्रह किए गए थे वे रिपोर्ट तैयार करने के प्रारम्भिक कार्य के रूप में संकलित किए जा चुके थे और उनके संबंध में तालिका बनाई जा चुकी थी।

(४) मजदूरी के संबंध में जाँच—गाँवों और शहरों में मजदूरी के संबंध में जो जाँच की गई थी उसकी रिपोर्ट तैयार करने का काम पूरा किया गया।

(५) रुई संबंधी आँकड़े—३१ अगस्त, १९५१ ई० को व्यापारियों के पास रुई का जितना स्टॉक था उसके आँकड़े यू० पी० काटन स्टेटिस्टिक्स ऐक्ट, १९४७ ई० के अधीन प्राप्त किए गए और सब आँकड़ों का एक संकलित विवरण—पत्राइडियन सेन्ट्रल काटन कमेटी, बम्बई को भेजा गया।

(६) जिला आर्थिक जाँच—जिला आर्थिक जाँच के संबंध में राज्य के सभी जिलों से आँकड़े एकत्र करने तथा उन्हें अंतिम रूप से संकलित करने के उद्देश्य से उनकी छानबीन करने का काम जारी रहा।

(७) राज्य की राष्ट्रीय आय—१९४६-४७ ई० से १९४९-५० ई० तक की चार वर्षों की अवधि के लिए राज्य में प्रति व्यक्ति आय का तख्तीना लगाया गया।

लगभग ५०० गाँवों में नमूने के तौर पर जाँच-पड़ताल करके राज्य के गाँवों से होने वाली आय का तख्तीना लगाने के लिए एक योजना तैयार की गई। इच्छानुकूल नमूने के आधार पर गाँव चुने गए और नमूने के प्रत्येक गाँव में परिवारों की पूर्णरूप से गणना की गई। प्रत्येक परिवार से उसके पेशे, कुटीर उद्योग इत्यादि के संबंध में विवरण एकत्र किए गए। नमूने के परिवार चुने गये और एक पाइलट जाँच-पड़ताल का काम प्रारंभ किया गया।

(८) नौकरों संबंधी आँकड़े—राज्य सरकार तथा अन्य सार्वजनिक निकायों द्वारा दी गई नौकरियों के संबंध में तख्तीना तैयार करने के लिए प्रयत्न किया गया। प्रारम्भ में राज्य कर्मचारियों के संबंध में उनके वेतनों की श्रेणियों के अनुसार हर-छह महीने बाद आँकड़े तैयार किए गए और इन अस्थायी आँकड़ों को आँकड़ों की बुलैटिन (बुलैटिन आफ स्टेटिस्टिक्स) में प्रकाशित किया गया।

६५—एडमिनिस्ट्रेटर जनरल तथा आफिशल ट्रस्टी, यू० पी० का कार्यालय

एडमिनिस्ट्रेटर जनरल और आफिशल ट्रस्टी के प्रशासन के अधीन २३ ट्रस्ट और २४० रियासतें थी और इनसे लगभग ३०,००० रुपये की आमदनी थी। कुल विक्रय-वस्तु लगभग १२ लाख रुपये था।

हाई कोर्ट द्वारा लेटर्स आफ एडमिनिस्ट्रेशन स्वीकृत करने के कारण बहुत मो रियासतें प्रशासन के अंतर्गत आ गईं और अन्य रियासतें उत्तराधिकारियों तथा रिक्थसाधकों (executors) के प्रार्थना पर और एडमिनिस्ट्रेटर जनरल एक्ट की धारा २५ के कारण प्रशासन के अंतर्गत आ गईं।

२,००० रुपये की मालियत तक के प्रशासन तथा उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र देने के अधिकार का प्रयोग करके एडमिनिस्ट्रेटर जनरल तथा आफिशल ट्रस्टी ने इस वर्ष ३५ प्रमाण-पत्र स्वीकृत किये।

विभाग के राजस्व में काफी वृद्धि हुई। बहुत से बाँवों का फैसला किया गया और उनका भुगतान किया गया। कुछ रियासतों को, जिनके कोई उत्तराधिकारी नहीं थे या जिनके उत्तराधिकारियों का पता नहीं लगाया जा सका, सरकार ने जूट कर लिया।